

***The Union Budget,2025-2026(concluded)**

श्री अखिलेश यादव (कन्नौज) : धन्यवाद सभापति महोदय । मैं आपको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे केन्द्रीय बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं अपनी बात को अपने विपक्ष के साथियों की बात से जोड़ते हुए, इस बजट के विरोध में खड़ा हुआ हूँ ।

सभापति महोदय, यह बजट टारगेटेड बजट है, यह बजट फोकस्ड बजट है । यह टारगेटेड और फोकस्ड बजट उन लोगों के लिए है जो बहुत संपन्न हैं, बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनके लिए यह बजट बना है । भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन मुझे इसमें कोई रोडमैप दिखायी नहीं देता है ।

14.11 hrs

(Shri Dilip Saikia in the Chair)

इसलिए रोडमैप दिखायी नहीं देता है कि जैसे ही बजट आया, हम लोगों ने तस्वीरें देखी हैं और जो तस्वीरों में दिख रहा है कि हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां हैं । सभापति महोदय, दस बजट इस देश के लिए क्या इसीलिए बनाए गए थे कि जब 11वां बजट आएगा तो पूरा देश और पूरी दुनिया यह देखेगी कि भारत के लोग हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भारत लौटाए गए?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधान मंत्री जी अमेरिका जा रहे हैं । पिछली बार हीरा लेकर गए थे, इस बार सोने की जंजीर लेकर जाइएगा । जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए । सभापति महोदय, हो सके तो कुछ महिलाओं और बच्चों को अपने साथ तो नहीं, लेकिन किसी ओर जहाज में साथ लेते आइएगा । वह जहाज भी तो भारत का ही होगा । इतना हक तो उनका बनता ही है कि दूसरों की ... ****** के शिकार कुछ लोग बाइजजत लौट सकें । वैसे सवाल यह भी है कि आपके रहते ऐसी ... ****** कैसे फल-फूल रही है? सभापति महोदय, इस ... ***** से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कहीं के लोग हैं तो वे गुजरात के लोग हैं । क्या यही हमारे विकसित भारत की तस्वीर है? ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं । अनपार्लियामेंटरी वर्ड को आपको थोड़ा सोच-समझकर बोलना चाहिए ।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : ? *****वर्ड को रिकॉर्ड से हटा दीजिए ।

? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव : सभापति महोदय, एक दूसरी तस्वीर भी हम लोगों ने देखी है । महाकुम्भ, जिसके बारे में 144 साल बाद, ऐसा एक *******प्रचार किया गया । सभापति महोदय, ये साइंटिस्ट हैं या एस्ट्रोनॉमर हैं और एस्ट्रोनॉमी समझते हैं । ? (व्यवधान)

डॉ. निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : सर, यह आस्था का सवाल है और मेरा इस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है?

डॉ. निशिकान्त दुबे : सभापति महोदय, संविधान के आर्टिकल्स 25, 26, 27 और 28 कहते हैं कि आप किसी भी रिलिजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते हैं। ? (व्यवधान) ये लोग एंटी हिन्दू हैं। ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I got the point. I will see the proceedings.

? (Interruptions)

माननीय सभापति : आप लोग बैठ जाइए। मैं देख लूंगा।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग बैठ जाइए और माननीय नेता जी को बोलने दीजिए।

? (व्यवधान)

वस्त्र मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): सर, यह आस्था का सवाल है और इसको रिकॉर्ड से हटाया जाए। ? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव : सभापति महोदय, वह महाकुम्भ की तस्वीर ? (व्यवधान) आप स्नान करके नहीं आए हैं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : ऐसा कोई भी शब्द, जो आस्था के विरुद्ध बोला गया है, उसे रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा।

? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव : आप कुंभ में स्नान करके नहीं आए हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप स्नान नहीं करके आए हैं। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मैंने रिकॉर्ड से निकालने के लिए बोल दिया है।

? (व्यवधान)

माननीय सभापति : उसे हटा दिया जाएगा।

? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव : सभापति महोदय, इन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया है। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आप चेयर को एड्रेस कीजिए। वहां देखकर बात मत कीजिए।

? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव : अगर फोटो आई होती तो मैं जैकेट वाली भी फोटो देख लेता। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : शायद, आपने आपकी कोई गलत फोटो देख ली है।

? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव : सभापति महोदय, हमने विकसित भारत की जो दूसरी तस्वीर देखी, वह तस्वीर न केवल हम लोगों को दुख पहुंचाती है, बल्कि उन तमाम सनातनी लोगों को, सनातन को स्वीकार करने वाले लोगों को भी दुख पहुंचाती है।

लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे और ऐसा पहली बार हुआ होगा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। वहां पर दो-दो मुख्य मंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे भी जाम रुक जाए। इसके साथ-साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वे व्यवस्था नहीं बना सकते तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों ने अपील की कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आएँ और लोगों को सुविधा दें। यह बात तब आई है, जब लोग दुख, तकलीफ और परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। ? (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जिस स्नान के लिए प्रधान मंत्री गए हों, देश की राष्ट्रपति गई हों, उप राष्ट्रपति गए हों, मंत्री गए हों तो क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी? आप वहां पर ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से न निकले, सब के सब वहीं पर रुक जाएं। आप आगे नहीं जा सकते हैं, दर्शन नहीं कर सकते हैं। क्या यह सच्चाई नहीं है?

सभापति महोदय, सारे बॉर्डर सील हुए हैं। चांद पर पहुंचने का क्या फायदा, जब आपको जमीन की समस्याएं न दिखती हों? जमीन की समस्याएं न दिखती हों और मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि वह ड्रोन कहां पर है? डिजिटल इंडिया की जो बात कही गई थी, वह कहां है? ये लोग इस बात की अभी तक डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है और कितने लोग वहां पर खो गए हैं।

सभापति महोदय, यहां पर विज्ञापन और कार्टूनों की काफी चर्चा हो रही थी। मुझे याद है कि एक दिन मैंने अखबार देखा। वह अंग्रेजी का अखबार था और मैं समझता हूँ कि सभी माननीय सदस्यों ने उस अखबार को जरूर देखा होगा। उसके फ्रंट पेज पर एक विज्ञापन था। उस विज्ञापन की जो तस्वीर थी, उसमें एक जानवर था। मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन शायद वह एक गधा रहा होगा। वह जेल के अंदर था। मेरा मन नहीं माना और मैंने उसी दिन सरकार को जगाने के लिए लिखा और मैं आज सरकार के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि डिजिटल इंडिया करते-करते साइबर क्राइम, साइबर लूट और डिजिटल अरेस्ट कितना बढ़ गया है तथा जो विज्ञापन दिया था, इस जानकारी के बाद वह विज्ञापन दोबारा अखबार में नहीं आया। मैं उस विज्ञापन की तस्वीर नहीं

दिखा सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री जी उस विज्ञापन के बारे में जानते होंगे और उन्होंने देखा होगा। जो विज्ञापन दिया, जनता का भारतीय रिजर्व बैंक से यह सवाल है कि वह अपने ऐसे विज्ञापनों में किसको चित्रित कर रहे हैं और क्यों तथा वह कहां से आया है? क्या यह कोई प्रतिकात्मक चित्रण है? यदि हाँ तो वह जानवर किसका प्रतीक है? क्या उस सिस्टम का, जिसके कंधे पर स्वच्छ और सुरक्षित बैंकिंग की नैतिक जिम्मेदारी है या उस मंत्रालय का, जिसको सुरक्षित बैंकिंग का दायित्व निभाना चाहिए? अगर यह चित्रण जनता को दिखाना चाह रहा है कि यह बहुत अनैतिक है, तो जनता इसके लिए मानहानि का दावा भी कर सकती है।

अगर आरबीआई यही दिखाना चाह रहा है तो अपने खाताधारकों के प्रति बैंक की ऐसी नकरात्मक रवैया न केवल आपत्तिजनक है, बल्कि घोर निंदनीय भी है। आरबीआई ऐसे विज्ञापनों से नहीं बल्कि अपने सिस्टम को चुस्त-दुरुस्त करके व बैंकिंग साक्षरता, बैंकिंग सजगता और जागरूकता अभियान चलाकर जनता को सचेत और सावधान करे। जब भी हम लोग मोबाइल खोलते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई आवाज सुनाई देती है।

सभापति महोदय, क्या डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से लाखों-लाख रुपया नहीं लूट जा रहा है? आखिरकार उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो बजट दिया गया है, बजट में जो बातें निकल करके आ रही हैं, बजट में पीडीए के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं है। जो लोग अपने जीडीपी की न जाने कितनी कहानियां बताते थे, आज जीडीपी रेट क्यों कम होती चली जा रही है? क्यों जीडीपी 6.4% के आसपास पहुंच गई है? न केवल जीडीपी बल्कि आज अगर हम 87 रुपए से ही एक डॉलर ले सकते हैं। कभी डॉलर के मुकाबले रुपए को नीचे गिरने की कहानी कहीं किसी से जोड़ दी गई थी। आज सोचिए कितने रुपए हम इकट्ठे करते हैं, तब हमें एक डॉलर मिलता है? क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है? इस ग्रोथ रेट के कम होने का कारण जो मुझे समझ में आता है, वह इन्वेस्टमेंट की कमी और कंजम्प्शन की कमी है। यह देश की आर्थिक विकास की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और यही नहीं जो भेदभाव बढ़ता चला जा रहा है, जो खाई पैदा होती जा रही है, इन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि खाई कितनी है। मुट्ठी भर लोगों के पास पूरे देश की संपदा पहुंच गई। जो ज्यादा लोग हैं, वे गरीब हैं। आपको जीवन यापन के लिए 80 करोड़ लोगों को राशन बांटना पड़ रहा है। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर है? दुनिया में हम पर-कैपिटा इनकम में कहां खड़े हैं?

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहेंगे कि जिन परिवारों को आप राशन दे रहे हैं, उन परिवारों की पर-कैपिटा इनकम क्या है? अगर विकसित भारत की तस्वीर लेकर यह सरकार चलना चाहती है तो सभापति महोदय सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह देखे कि जो 80 करोड़ लोग राशन पा रहे हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है।

सरकार का एक बहुत प्रिय काम है। वह इतना प्रिय है कि उसका नाम बदल करके इज्जत घर कर दिया गया है। मुझे याद है की एक छत्तीसगढ़ में बुजुर्ग मां ने बकरी बेचकर अपना शौचालय बनाया था। जब उन्होंने बकरी बेचने के बाद शौचालय बनाया तो देश के प्रधानमंत्री जी ने उनका सम्मान किया। आखिरकार सवाल यह है कि उन्हें बकरी क्यों बेचनी पड़ गई? इसका मतलब यह है कि आपकी बनाई हुई स्कीम्स जमीन पर नहीं पहुंच रही हैं, उनके लिए पर्याप्त पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। आखिरकार पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा है? यह तो सरकार की जिम्मेदारी है।

सभापति महोदय, जो शौचालय बनाए गए हैं उनमें से किसी में पानी नहीं पहुंचता है। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर बनेगी?

सभापति महोदय, हम लोग डबल इंजन, डबल इंजन बहुत सुनते थे और अब इस बजट में दो इंजन और बढ़ गए हैं। सभापति महोदय, यह बजट चार इंजन वाला है। ऐसा लगता है कि एक के बाद एक इंजन खराब हो गया होगा, इसलिए इन्हें चार इंजन लगाने पड़े। ये चार इंजन की बात करके जनता को धोखा दे रहे हैं। जब हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं, तो वहां पर डबल इंजन की सरकार चल रही है, वह डबल ब्लंडर कर रही है। हमें उनके डबल ब्लंडर देखने को मिल रहे हैं।

महोदय, यह चार इंजन की सरकार है, सबसे पहला इंजन हमारे किसानों और कृषि का है। दस साल गुजरने का गुजरने के बाद भी, इतने बजट आने के बाद भी आज तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। तमाम माननीय सदस्य अपने क्षेत्रों और फसलों की समस्याओं को लेकर सवाल खड़ा करते हैं। कई किसान नेता अभी-भी आंदोलन कर रहे हैं, अभी-भी आंदोलन चल रहा है। इस सरकार के पास, जो विकसित भारत का सपना दिखा रही है, अभी तक किसान की दोगुनी कैसे हो, कोई रोडमैप नहीं है। अगर कोई रोडमैप रहा हो तो हमें बता दें।

महोदय, हजारों किसानों की जान चली गई कि एमएसपी को कानूनी गारंटी मिले, लेकिन आज भी वह गारंटी नहीं मिल पा रही है। क्या यही विकसित भारत होगा जिसमें किसान को एमएसपी नहीं मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं मिलेगी? जो किसान की दोगुनी आय का सपना ले रहे थे, उन्होंने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन उनकी कही हुई बातों को सही जगह नहीं पहुंचा पा रहे हैं।

14.26 hrs

(Hon. Speaker in the Chair)

महोदय, दलहन, तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए जिस मिशन की घोषणा की गई थी, क्या वह मिशन पूरा हुआ है? अभी तक हम लोग तिलहन इंपोर्ट कर रहे हैं। दलहन और तिलहन के बारे में पहले बजट से कहा जा रहा है, लेकिन आज भी हम लोगों को इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। इसका परिणाम यह है कि हम अपने किसानों को जिस तरह का लाभ देना चाहते हैं वह नहीं दे पा रहे हैं।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना 100 पिछड़े जिलों के लिए घोषित हुई है, लेकिन इसके लिए कोई बजट नहीं दिया गया है। फल और सब्जी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में योजना बनाई जाएगी। क्या यही चार इंजन वाला बजट है? फल और सब्जी के लिए बाद में बजट बनाया जाएगा, बाद में बजट घोषित होगा। पॉलिसी क्या होगी, यह बाद में तय होगा। कृषि क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए अधिक धन की आवश्यकता है, लेकिन इस बजट में यह नहीं दिखाई दे रहा है। कृषि क्षेत्र में कार्यबल 46 प्रतिशत है लेकिन जीडीपी में इसका योगदान केवल 18 परसेंट है, जो किसानों की खराब आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, अभी हमारा किसान गरीब है।

महोदय, मुझे याद है फसल बीमा योजना को लेकर के न जाने कितना प्रचार किया गया। सच्चाई यह है कि जब क्लेम करने की बात आती है तो आंकड़े बताते हैं कि हम अभी भी 3 परसेंट से ऊपर नहीं पहुंच पाए हैं। किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहा है। क्या विकसित भारत की यही तस्वीर होगी कि लाखों लाख किसान आत्महत्या कर लें? अब तो सुना है कि ये आंकड़े भी आना बंद हो गए हैं। हमें किसान के ऊपर कर्ज और कर्ज के ऊपर कर्ज नहीं बढ़ाना है, जिस तरीके से आप बड़े-बड़े उद्योगपतियों का ध्यान रखते हैं और उनका समय-समय पर कर्ज माफ करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि उसी तरह से हमारे देश के किसानों का भी कर्ज माफ होना चाहिए, उनको कर्ज से मुक्ति दिलानी चाहिए।

महोदय, अगर क्लाइमेट चेंज की बात होगी तो सबसे पहले अगर किसी पर असर पड़ेगा, सबसे पहले प्रभावित अगर कोई होगा तो हमारा किसान होगा। उसके लिए क्या आपके पास रोड मैप है? यहां बहुत से माननीय सदस्यों कहा है कि जीएसटी को लेकर के न जाने क्या-क्या रूल सरकार बनाती है। सरकार जीएसटी में लगातार व्यापारियों को उलझा रही है, जब तक जीएसटी के बारे में व्यापारी समझ पाता है तब तक जीएसटी के तरीके को बदल दिए जाते हैं। अभी भी किसानों के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उन पर कम से कम 12 से 18 परसेंट जीएसटी लिया जा रहा है। अगर यह सरकार विकसित भारत का सपना देख रही है तो सभी के सभी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, जो हमारे किसान इस्तेमाल करते हैं, उनमें जीरो जीएसटी होना चाहिए।

महोदय, सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लाई है। भंडारण की सुविधा किसको मिल रही है? भंडारण को लेकर भी सरकार का कोई रोडमैप जरूर होना चाहिए। यह कैसी अर्थव्यवस्था है? जहां पर अर्थव्यवस्था को तो हम तीसरे नंबर पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन नौकरी और रोजगार उसके पास नहीं है। ग्रोथ है, ग्रोथ बताना चाहते हैं, लेकिन रोजगार और नौकरी नहीं है। इनके मैन्युफैक्चरिंग के जो तमाम मिशनस थे, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन ? जब तक इनवैस्टमेंट का वातावरण नहीं सुधरेगा, तब तक इनवैस्टमेंट नहीं हो सकता है। हमारा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन आगे नहीं बढ़ सकता है।

इन्होंने दूसरा इंजन बताया है ? एमएसएमई। एमएसएमई को लेकर बहुत चिंता व्यक्त की। बजट भाषण में एमएसएमई सेक्टर को विकास का द्वितीय इंजन बताया गया, जो सही है, परंतु एमएसएमई के विकास के लिए बजट में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। भारत में एमएसएमई 11 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है और इसमें सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। हमारी जो माइक्रो यूनिट्स हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं है। उनको विशेष मदद के लिए कोई प्रावधान न पहले किया गया, न इस बजट में किया गया है। मैं केवल यूपी के बारे में कहना चाहता हूं। यूपी में लगभग 96 लाख एमएसएमईज हैं, लेकिन केवल 14 लाख पंजीकृत हैं। पूरे देश में एमएसएमईज 6 करोड़ हैं, एमएसएमईज के विपरीत केवल एक करोड़ पंजीकृत हैं। अगर यूपी में केवल 96 लाख एमएसएमईज हैं, 6 करोड़ पूरे देश में हैं, पंजीकृत केवल 14 लाख और एक करोड़ हैं तो इसका मतलब यह है कि ज्यादातर एमएसएमई सेक्टर को सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। मुझे उम्मीद है कि एमएसएमईज को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार जागरूक होगी और अपनी डबल इंजन सरकार जहां-जहां चल रही हैं, उनको जगाने का भी काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक समय ऐसा भी था कि जब लोग बजट के आने पर खुश होते थे, क्योंकि बजट नई उम्मीद जगाता था, देश और जनता को आगे की ओर ले जाता था। लेकिन भाजपा सरकार के बजट में न देश के विकास के लिए कुछ होता है, न

जनता की तरक्की के लिए कुछ होता है। बजट मायूसी लेकर नहीं आना चाहिए। बजट देश का आर्थिक मानचित्र होता है। वह दर्शाता है कि किस तरह पूरे देश का संतुलित मतलब हर राज्य का बराबर विकास हो। जो भी राज्य या क्षेत्र भौगोलिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणों से पिछड़ गया है, उसके लिए कैसे प्रावधान किए जाएं, जो कि वे भी मुख्यधारा से जुड़ सकें। वर्तमान में बैलेंस डेवलपमेंट की नीति पिछड़ती जा रही है। मैंने कई मौकों पर कहा है और आज फिर दोहरा रहा हूं कि सच्चा विकास वही होता है, जो भेदभाव मिटाता है। अच्छा बजट हर दिशा में किसी भी देश के विकास का रास्ता तैयार करता है। इन्हीं अर्थों में बजट लोकतांत्रिक होता है, जो समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी होता है। यह सबसे आखिरी व्यक्ति को ताकत देकर उसे आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ता है। यह बजट होता है। मैं तो कहूंगा कि?

‘मिट जाए अमीरी-गरीबी के बीच की वह सब खाई
जिसमें भेदभाव और गैर बराबरी की जड़ है जमायी।’

बजट के अंदर उसके लिए हमेशा एक दिल धड़कना चाहिए, जो आज भी भूख के सूचकांक के आंकड़े बनाकर देश के दिखावटी विकास के सच का भंडा फोड़ कर रहा है।

भूख मिटे, महंगाई घटे? यही बजट का सबसे बड़ा नारा होना चाहिए। निर्बल को सबल बनाना, निराशा को आशा में बदलना ही बजट का मानवीय पहलू होना चाहिए। बजट का सबसे बड़ा सिद्धांत कमजोर के प्रति हमदर्दी होना चाहिए। बजट बनाने की सोच किसी या कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंसानियत के नजरिये की बुनियाद होनी चाहिए। यदि बजट के आने से निर्बल सबल बनता है, तो समझो कि बजट अपने उद्देश्यों से सफल हुआ है, नहीं तो उसे असफल ही माना जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, रोटी की भूख किसानों को विश्वास में लेकर ही मिटाई जा सकती है। मैंने पहले भी कहा और फिर उन बातों को दोहराता हूं। किसानों को फसल के सही दाम दिलवाना, बीज, खाद और पानी के इंतजाम करना, आवारा पशुओं से उनकी फसलों को बचाना चाहिए।

मैं आवारा पशुओं के बारे में इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री जी आये थे, उन्होंने कहा था कि हमने एक रोडमैप बनाया है। आप सरकार बनवा दीजिए, इस काम में दो हफ्ते लगेंगे। एक भी जानवर सड़कों पर दिखाई नहीं देगा और किसानों की जान नहीं जाएगी, न ही खेतों में फसलों की बर्बादी होगी।

महोदय, उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्यगण, चाहे वे इधर के हों या उधर के हों, वे जानते होंगे कि इस तकलीफ और परेशानी से किसान अभी तक उबर नहीं पाया है। आज भी खेतों को उसे चारदीवारी से घेरकर या तारों से जोड़कर चलना पड़ रहा है।

फसलों को बचाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस मामले में जुमलेबाजी और झूठे वायदे अच्छे नहीं। आँकड़े बताते हैं कि देश में बहुत-से ऐसे कारोबार हो रहे हैं, जो बढ़ते चले जा रहे हैं। कई उद्योगपति उद्योगों से कई गुना लाभ उठा रहे हैं, कई विदेशी कम्पनियाँ इस धन्धे में अरबों रुपए कमा रही हैं, लेकिन आलू के किसान इस लाभ से वंचित हैं।

महोदय, जहाँ बिहार के लिए मखाना बोर्ड बना है, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मखाने का ध्यान रखना। जिस तरह से, पोपकॉर्न में मीठे और नमकीन के कारण जीएसटी में हेर-फेर हो गया है, कहीं आपके मखाने में भी मीठे का जीएसटी अलग हो और नमकीन का जीएसटी अलग हो और गुड़ वाले का अलग हो, कहीं ये वैसा ही न करें।

आज किसान का आन्दोलित होना सरकार की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकार और किसान के बीच भरोसे के बिना भूख नहीं मिटाई जा सकती। समय पर बीज, खाद आदि का मिलना, कृषि ऋणों को माफ किया जाना, एमएसपी दिलवाना सरकार का दायित्व है। वह इससे बच नहीं सकती। किसानों के हिस्से में काले कानून नहीं, बल्कि सतरंगी भविष्य आना चाहिए। यह सरकार काले कानून लाकर हमारे किसानों को अपमानित करना चाहती है।

वहीं हमारे मानव संसाधन के लिए स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है। चिकित्सा स्वास्थ्य में सुधार होना बेहद जरूरी है। आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि हर शरीर को पोषक आहार मिले, कार्य की दशाएं अच्छी हों, वर्क-लाइफ बैलेंस सही हो, जिससे मानसिक रूप से भी लोग स्वस्थ रहें। इसके अलावा, पर्यावरण को भी अब स्वास्थ्य के बड़े कार्य के रूप में लेना होगा। एन्वायरमेंट को अब हेल्थ फैक्टर के रूप में देखना होगा। हर तरह के प्रदूषण को रोकना होगा। हरियाली बढ़ानी होगी। इसके साथ ही, एक और बात अहम है। वह यह है कि हर तरफ नकारात्मकता और नफरत के प्रचार से इंसान के अन्दर निगेटिविटी आती है। इससे आपस का विश्वास और सौहार्द टूटता है, जिसके परिणामस्वरूप इमोशनल सपोर्ट सिस्टम फेल होने लगता है। फेक न्यूज लोगों को मानसिक रूप से धीरे-धीरे बीमार बना रही है, इसे हर हाल में रोकना होगा।

महोदय, इसमें विपक्ष से ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी है क्योंकि कई मौके पर हम लोग देखते हैं कि सरकार अपने-आप का जितना प्रचार करना चाहती है, उससे ज्यादा दूसरों को कैसे बदनाम किया जाए, उसके लिए प्रचार करती है। इसलिए शायद सरकार की बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इससे देश के मानव संसाधन में जानबूझकर जो आपसी अविश्वास बढ़ाया जा रहा है और समाज में सौहार्द को भी जानबूझकर घटाया जा रहा है ताकि कुछ लोग अपनी सियासी रोटियाँ सेंक सकें, इसके लिए सख्त कानून लाना चाहिए।

एक तरफ सरकार लोगों को सही इलाज नहीं दे पा रही है, दूसरी तरफ जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर भी टैक्स लग रहे हैं। सरकार मुनाफा कमाने के लिए नहीं बनती है, बल्कि जनता के कल्याण के लिए बनती है। यह बात कुछ लोगों को याद रखनी चाहिए।

महोदय, अगर काम है भी, तो उसके सही दाम नहीं मिल रहे हैं। अगर यह बात एक पढ़े-लिखे युवा के लिए सही है, तो एक मजदूर भी दिन भर कमतोड़ मेहनत तो करता है, लेकिन वह मजदूरी में उतने पैसे नहीं पाता है कि वह अपना और अपनों के पेट भर सके। आज जब देश की अधिकांश आबादी युवा है, ऊर्जा से भरी हुई है, वह कुछ करना चाहती है, ऐसे में सरकार को सिर्फ यह करना है कि वह देश में कारोबारी वातावरण और व्यावसायिक वातावरण का निर्माण करे। वह लोगों के टैलेंट को पहचाने। उसकी

सच में स्किल मैपिंग करे ताकि युवाओं को उनकी प्रतिभा के अनुसार काम और रोज़गार मिल सके । इससे युवाओं को देश के निर्माण में अपना योगदान करने का मौका मिल सके ।

महोदय, जब से यह सरकार बनी है, तब से महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है । महंगाई कहां पहुंच गई है, यह सरकार को बेहतर पता है, उनके पास आकलन है ।

अध्यक्ष महोदय, महंगाई एक ऐसी समस्या बनकर उभरी है, जिसने हर कौर को भारी बना दिया है । जिस तरह सत्ता में बैठे हुए लोग राजनीतिक चंदे के नाम पर कंपनियों से उगाही कर रहे हैं, दरअसल वह भी दामों के बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है । सरकार ने मुनाफाखोरी की लगाम खोल दी है । मुनाफाखोर छुट्टा बैल हो गए हैं । आजाद भारत के इतिहास में नोटबंदी और जीएसटी दो सबसे बड़े आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि सबसे बड़े आर्थिक विकार बनकर उभरे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि नोटबंदी के समय बैंक की लाइन में एक गर्भवती मां लगी थी । जिस बच्चे ने जन्म लिया, उसका नाम हम लोगों ने खजांची रखा है । अब वह काफी बड़ा हो गया है, साइकिल भी चला लेता है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहूंगा कि आप कम से कम उसको ही गोद ले लें । ? (व्यवधान) मैं चाहूंगा कि आप उसको गोद ले लीजिए । जब आप उसे गोद ले लेंगे, तो उसका नाम भी आप अपने हिसाब से रख पाएंगे । किसी भी आर्थिक सुधार का लक्ष्य यह होता है कि आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चल सकें और आसान हों, जिससे अर्थव्यवस्था दिन दोगुनी, रात चौगुनी तरक्की करे, लेकिन इन सुधारों के आने के बाद से अर्थव्यवस्था की गति कछुए की चाल जैसी हो गई है । इसका प्रमाण है कंपनियों की ग्रोथ का कम होना, उनकी बिक्री का घट जाना, यहां तक कि फास्ट मूविंग कन्ज्यूमर गुड्स भी दो परसेंट से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ।

इसका सीधा मतलब यह है कि लोगों के पास पैसों की किल्लत हो गई है और वे रोजमर्रा की जरूरतों तक पर खर्च नहीं करना चाहते हैं । ऐसे में उनकी बचत कहां से होगी? जब बचत नहीं होगी, तो लोग क्या खाएंगे और क्या बाजार में लगाएंगे? लोगों में भविष्य को लेकर इतनी अनिश्चितता और चिंता है कि वे अपने जमा पैसे अपने पास ही रखना चाहते हैं । इसलिए, व्यापार में बढ़ोत्तरी नहीं हो पा रही है । बैंकों में भारी किल्लत है । पूंजी का निर्माण नहीं हो पा रहा है और लोग निवेश के लिए आगे नहीं आ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था, जो कि ? इनवेस्टमेंट मीट? का आयोजन था । 40 लाख करोड़ रुपए का एमओयू हुआ । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप घूमकर उत्तर प्रदेश पर ही आ जाते हैं ।

? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि जो अपने आपको डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, वे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए क्या सहयोग कर रहे हैं? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आत्मनिर्भरता की बात करते हुए भी हमारा शेयर बाजार विदेशी निवेशकों पर निर्भर करने लगा है। जब वे पैसे लगा देते हैं, तो शेयर बाजार में उछाल आ जाता है, नहीं तो उसे धड़ाम होते देर नहीं लगती है। एक-एक दिन में हमारे निवेशकों का लाखों-करोड़ों रुपयों का नुकसान हो जाता है। इसका एक बड़ा शिकार हमारी युवा पीढ़ी भी हो रही है, जो देखा-देखी पैसे तो लगा देती है, लेकिन शेयर की खरीद-फरोख्त से पैसा कमाने वाले बिचौलियों की गहरी चाल को समझ नहीं पाती है। यह खेल बंद होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि यह खेल बंद हो।

सेबी को अपना काम निष्पक्ष रूप से करना चाहिए और अर्थव्यवस्था की निगरानी व्यवस्था सच्ची नियत के साथ सजग और सचेत होनी चाहिए। इनसिक्योरिटीज़ सिक्योरिटी मार्केट से बाहर होनी चाहिए। आज जिस तरह विदेशी निवेशक धीरे-धीरे भारतीय बाजार से अपना पैसा बाहर निकाल रहे हैं, यह दर्शाता है कि हमारी अर्थव्यवस्था से अब उनका भरोसा उठ गया है। उन्हें दूसरे देशों से अधिक लाभ कमाने की उम्मीद है, इसलिए वे अपना पैसा यहां से निकालकर दूसरे देशों में लगा रहे हैं। उनकी वजह से हमारा शेयर मार्केट हिचकोले खा रहा है।

माननीय अध्यक्ष : आपने अपना भाषण कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख दिया।

? (व्यवधान)

श्री अखिलेश यादव : अध्यक्ष महोदय, चूंकि बजट चार इंजन का था, इसलिए बड़ा भाषण लिखकर लाया, कोई बात छूटे न और सरकार तक हर बात पहुंच जाए। ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अगर ग्यारहवें बजट में चार इंजन लगाने पड़ें, तो कहां विकसित भारत बन रहा है? जीएसटी को भ्रष्टाचार से मुक्त करना होगा, व्यापारियों के प्रति विश्वास जताना होगा। यदि टैक्स की व्यवस्था और दर सही होगी, तो सब आसानी से टैक्स भर देंगे। हाई टैक्स रेट दरअसल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इससे राजस्व की हानि होती है। लोग सच में काम, कारोबार करना चाहते हैं, वे कर की चोरी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए, टैक्स की रेट को तार्किक बनाने और टैक्स सिस्टम को ईजी करने से ही अर्थव्यवस्था में गति आएगी। निवेश के लिए पूरी दुनिया वापस हमारे देश की ओर देखेगी।

महोदय, मैं अर्थव्यवस्था के संबंध में एक गंभीर मुद्दा बताना चाहता हूँ। एक बहुत गंभीर मामला पलायन का है। पलायन के मामले में एक बहुत बड़ा विरोधाभास हमारी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है। एक तरफ सबसे अमीर वे लोग हैं, जो अपनी पूँजी का निवेश करते हैं और दूसरी तरफ सबसे गरीब वे लोग हैं, जिनके पास अपना श्रम निवेश करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसे हजारों अरबपति बाहर के देशों में ज्यादा उम्मीद देखते हुए अपनी पूँजी लेकर देश छोड़कर जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सबसे गरीब लोग हैं, वे राज्यों के असंतुलित विकास की वजह से अपने राज्यों से पलायन कर रहे हैं। इस महा समस्या का सबसे बड़ा शिकार हमारा उत्तर प्रदेश है। जहाँ नौकरी और अवसरों की भारी कमी है। जहाँ विकास टीवी, अखबारों, होर्डिंग्स में तो दिखता

है, लेकिन जमीन पर नहीं दिखता है। जब पूँजी और श्रम के निवेश के लिए आंतरिक वातावरण बनेगा तभी सच्चा विकास होगा, बजट अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा, अर्थव्यवस्था लाभ के लोभ से मुक्त होगी और बजट एक लोकतांत्रिक देश के जनकल्याण की सही दिशा में आगे बढ़ेगा।

महोदय, बजट विकास में तेजी लाने का मतलब यह है कि पिछले 11 सालों में भाजपा ने विकास के लिए कछुए की चाल चली है। जब उन्होंने समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए संकल्प लिया तो यह बात खुली कि अब तक समावेशी नहीं, बल्कि विशेषी विकास हुआ है मतलब कुछ लोग बेहताशा आगे बढ़ गए हैं और बाकी नीचे की ओर जा रहे हैं। निजी क्षेत्र के निवेश में नई जान डालने की बात का अर्थ यह निकलता है कि भाजपा राज में निजी क्षेत्र बेजान हो गया है। नोटबंदी और जीएसटी सुधार नहीं, बेकार साबित हुआ है। परिवारों के मनोभाव में उल्लास भरने की बात स्वीकार कर रही हैं, लेकिन लोगों ने मुस्कुराना बंद कर दिया है। अच्छे दिन न अब तक इनके राज में आये हैं और न आने वाले समय में आएंगे। भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने की बात का मतलब है कि मध्यम वर्ग के हाथ खाली हैं। आज आप आयकर की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने तो बहुत पहले ही इस बात की माँग की थी कि कम से कम 12 लाख रुपये तक की आय को कर से माफ किया जाए। यह बहुत पहले से समाजवादियों की माँग रही है। जब वित्त मंत्री जी ने कहा कि हम सब मिलकर अधिक सम्पन्नता लाने और विश्व में अपना स्थान बनाने और अपने राष्ट्र की अनन्त क्षमता को बढ़ाने के लिए अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो उनका असली मतलब यह था कि वे बस चल रहे हैं। आपकी यह यात्रा निरर्थक है। अगर 11 साल बाद भी मंजिल का अता-पता नहीं है तो महोदय यह कौन सी यात्रा है?

आपने कहा कि हमारे सामने प्रतिकूल भू-राजनैतिक परिस्थितियाँ हैं तो सरकार यह बताए कि आपने उन प्रतिकूल परिस्थितियों को क्यों बनने दिया? हमारे संबंध पड़ोसियों से क्यों खराब हुए? हमारी सीमाएं क्यों असुरक्षित हुईं? हम अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने में क्यों कामयाब नहीं हुए हैं? जब आपने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है तो आप यह क्यों भूल गए कि हमारा रुपया आपके शासनकाल में सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया है। सबका विकास का आपका नारा सबका विनाश में कैसे बदल गया है, क्योंकि जब रुपया नीचे जाँगा तो विनाश का ही रास्ता खुलेगा। बड़े से लेकर छोटे उद्योग धंधे, दुकानदारी सब चौपट क्यों हो गए हैं? मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया ये सब नाकामी की किताब के चैप्टर कैसे बन गए हैं? सवाल यह है कि कैसे व्यापार, कारोबार केवल कुछ लोगों के हाथ में ही सिमट गया है और बाकी सब का काम-धाम क्यों मिट गया?

महोदय, हम भी मानते हैं कि कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है, बल्कि देश उसके लोगों से है, लेकिन आप लोग यह बात सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। जनता आपके लिए बस नारे का विषय है। आप कहती हैं कि हमारे लिए विकसित भारत में शामिल हैं, गरीबी से मुक्ति, शत-प्रतिशत अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, शत-प्रतिशत कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों से शत-प्रतिशत महिलाएँ और देश को फूड बास्केट ऑफ दी वर्ल्ड बनाने वाले किसान। अगर यह आपका लक्ष्य है, तो क्या आपके राज में अमीरी-गरीबी की खाई नहीं बढ़ी है?

आप देखिए कि भूख के इंडेक्स में हम कहां आ पहुंचे हैं। क्या स्कूली शिक्षा का बजट कम नहीं किया गया? क्या स्वास्थ्य सेवाएं महंगी नहीं हुई? यहां तक कि आपने स्वास्थ्य बीमा पर भी टैक्स लगा दिया। आपने योग्य लोगों को बेरोजगारी के अंधेरे में धकेल दिया है और आपके बड़े-बड़े नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि कमी नौकरी की नहीं है, बल्कि योग्यता की है। हमारी युवा पीढ़ी को हताश-निराश करने का पाप आप लोगों ने किया है। कुशल कारीगर के नाम पर आपने युवाओं को डिलीवरी पर्सन बनाकर छोड़ दिया है। आपके राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े ज्यादा हुए हैं। ऐसे असुरक्षित माहौल में आप कैसे आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी की बात कर सकते हैं। आपके मंत्रिमंडल में ही महिलाओं की कितनी भागीदारी है, यह आपसे अच्छा और कौन जानता होगा। रही बात फूड बास्केट ऑफ दि वर्ल्ड बनाने की, तो पहले आपसे आग्रह है कि पहले आप लोगों की थाली भर दीजिए और ऐसे हवा हवाई जुमले कम उछालिए।

अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को खत्म करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बजट में जिन क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार की बात कही गई, उनमें कराधान तब तक सफल नहीं होगा, जब तक उसे सरल, पारदर्शी और ईमानदारी से नहीं बनाया जाएगा। जब तक विद्युत क्षेत्र को निजी हाथों में सौंपकर मनमानी वसूली से रोका नहीं जाएगा, तब तक सुधार संभव नहीं है। जब तक शहरी विकास के नाम पर कुछ धनवानों के हाथ में जमीनें कोड़ियों के दाम पर बेचने का काम खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक सुधार संभव नहीं है। खनन के नाम पर जब तक जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों के परम्परागत अधिकार से खिलवाड़ किया जाएगा, तब तक सुधार संभव नहीं है। जब तक वित्तीय क्षेत्र और विनिमय सुधार की निष्पक्ष कोशिश नहीं की जाएगी, तब तक सुधार संभव नहीं है। मैं अंत में यह बात कहना चाहूंगा ?

?असली तरक्की है वही,

जो हर फर्क मिटाती है,

जो हर तरफ खुशहाली के गुलशन खिलाती है ?

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का विरोध करता हूं। यह रोड मैप कहीं नहीं दिखाता है जिससे कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने।

श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा) : राधे-राधे।

अध्यक्ष जी, वर्ष 2025-26 के बजट पर सदन में चर्चा हो रही है। इस विषय में मुझे भी भाग लेने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूं। मैं सबसे पहले कहना चाहती हूं कि दिल्ली में जो जीत हुई है, उसके लिए मैं अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देती हूं।

अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी मोदी जी की सरकार में नारी शक्ति का प्रतीक तो हैं ही, इसके साथ ग्लोबल लेवल पर भी वे आज भारत की नारी शक्ति को गौरव के साथ रिप्रेजेंट कर रही हैं। एक महिला सांसद होने के नाते मुझे उन पर बहुत गर्व है। निर्मला जी का यह लगातार आठवां बजट है, जो कि एक रिकार्ड है। उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई देती हूं। भारत आज दुनिया का सबसे तेज गति से विकसित होता हुआ देश है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के

मार्गदर्शन में वित्त मंत्री निर्मला जी जिस प्रकार हर संकट काल में, कठिन परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था को टॉप पर लेकर आई हैं, उसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत बधाई देती हूँ और इतना ही कहना चाहती हूँ कि ?जलाने वाले जलाते ही हैं चराग आखिर, ये क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की !?

अध्यक्ष जी, महाकुंभ के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से सांसद हूँ जहाँ प्रयाग राज में भारत की महान सांस्कृतिक परम्परा का महाकुंभ चल रहा है। इस महाकुंभ में भाग लेने के लिए देश-विदेश से करोड़ों लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं। मुझे भी यहाँ स्नान करने का अवसर मिला। मैं विश्व के इस सबसे बड़े धार्मिक और अध्यात्मिक समागम प्रयाग राज महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्य नाथ जी का कोटि-कोटि अभिनंदन करती हूँ।

I have witnessed everything is perfectly all right there. Yes, I have seen it. I have been there.

अध्यक्ष महोदय, सरकार के तीसरे कार्यकाल में तीन गुणा तेज गति से काम हो रहा है। सौभाग्य से, मथुरा के सांसद के रूप में मेरा भी यह तीसरा कार्यकाल है और मथुरा में भी तीन गुणा तेज गति से जो काम हो रहा है, उसके लिए मैं मोदी जी और योगी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उनका मुझे हर समय सहयोग मिलता रहता है।

अध्यक्ष महोदय, मोदी जी की सरकार में आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है। इन निर्णयों में गरीब, वंचित, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है।

महोदय, बजट पर अब तक हमारी पार्टी के कई माननीय सांसदों ने अपने विचार रखे हैं कि बजट घोषणाएं किस प्रकार देश की जनता के लिए हितकारी हैं। सभी लोगों ने इसके बारे में विस्तार से बताया है। उन्हीं बातों को मैं दोहराना नहीं चाहूंगी। मैं उन सभी बातों का समर्थन करती हूँ।

अध्यक्ष जी, बजट के कुछ प्वायंट्स हैं, जिनके बारे में मैं कहना चाहूंगी। वित्त मंत्री जी ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, उन्होंने 70 प्रतिशत महिलाओं का आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए कदम उठाने की बात की है। मैं देश की अपनी नारी शक्ति से यही कहना चाहूंगी -

तुम्हारे हौसले अधूरे हैं, उड़ान बाकी है,

यह तो सिर्फ थोड़ा है, आसमान बाकी है,

नाम तेरा भी होगा, काम तेरा भी होगा,

अभी तो तुम्हारी पहचान बाकी है।

महोदय, अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो अगले पाँच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिकरिंग लैब्स की स्थापना और भारत नेट परियोजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी एक बहुत

ही अच्छा कदम है।

हेल्थ सेक्टर में कैंसर की 36 दवाएं पूरी तरह से ड्यूटी-फ्री कर दी गयी हैं। अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेन्टर्स स्थापित करने की सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।? (व्यवधान)

यूथ सेक्टर में, बजट में देश के युवाओं के लिए, उनके स्टार्ट-अप्स के लिए लोन सीमा को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, टैक्स के संबंध में इस बजट में एक हिस्टॉरिकल और पॉपुलर घोषणा की गयी है, जिससे पूरे देश के मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास के बीच खुशी की लहर दौड़ रही है। इनकम टैक्स में अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी छूट की घोषणा की गयी है। इससे देश के मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को बहुत राहत मिली है। इस निर्णय के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के प्रति देश के करोड़ों मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास लोगों की ओर से आभार व्यक्त करती हूं।

This year's Budget reflects most sincerely the thought process of our hon. Prime Minister, Modi ji whose singular aim is to give the Indian population an Amrit Kaal for years to come. The wealth creators to the economy are also not looked down upon as filthy rich. 'Tax the rich and feed the poor' slogan has been completely erased.

महोदय, हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में पहली बार एतिहासिक वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट सम्मिट यानी 'वेक्स' का आयोजन हुआ। यह नए भारत की पहचान है। कला और फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधि होने के नाते मुझे भी इस सम्मिट में प्रधान मंत्री जी के साथ पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला, इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में अपने सुझाव रखने का अवसर मिला था। इसके लिए मैं हमारे प्रधान मंत्री जी और आई. एण्ड बी. मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूं।

15.00 hrs

अध्यक्ष महोदय, हमारी महान आध्यात्मिक परंपरा और संस्कृति में यमुना मइया का आध्यात्मिक महत्व है और मथुरा-वृंदावन की पहचान व जीवन-रेखा है। पिछले एक दशक से यमुना की सफाई और स्वच्छता के लिए मैंने बहुत मेहनत की, हर जगह जा कर बहुत कुछ बातें कहीं और कभी-कभी तो ऐसे बोलना पड़ता था कि हाँ यमुना शुद्ध हो जाएगी। जितना हो सके हम लोगों ने मथुरा-वृंदावन में जितने नाले वगैरह हैं, उनको बंद करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम लोग कामयाब नहीं रहे, क्योंकि यमुना में अशुद्ध जल दिल्ली से आ रहा था। उस वक्त दिल्ली में दूसरी पार्टी राज कर रही थी, तो हम कुछ कर नहीं सके। हम अपने बृजवासियों को इतना ही कहते रहे कि सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आज उम्मीद की किरण आई है। आठ फरवरी को दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाषण का शुभारंभ ही जय यमुना मइया से किया। उन्होंने यमुना नदी को दिल्ली की पहचान बनाने की बात की। यह मोदी जी की गारंटी है, मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी

है। मेरे संसदीय क्षेत्र में लोग इसे लेकर बहुत ही खुश हैं। इतने खुश हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। यमुना अब स्वच्छ हो जाएगी, बृजवासियों को अब स्वच्छ यमुना का जल पीने को मिलेगा, आचमन करने को मिलेगा, नहाने को मिलेगा, साधु-संत, श्रद्धालु एवं पर्यटक आदि सभी लोग बहुत ही खुश हैं। यह इतनी खुशी की बात है कि अब मैं बृजवासियों के बीच में सिर ऊंचा कर के चल सकती हूँ। इतना मुझे भी विश्वास है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का यह बजट ऐतिहासिक है और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाला है। भारत को विश्व का आर्थिक, सांस्कृतिक केंद्र बनाने वाला है। प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व में 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लिए एकता के सूत्र में बंध कर आगे चल पड़े हैं, इस संकल्प के साथ ही कि

वतन के जाँ निसार हैं, वतन के काम आएंगे।

हम इस जमीं को एक रोज़ आसमां बनाएंगे ?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मेरा आपसे आग्रह है कि माननीय वित्त मंत्री जी पांच बजे इस बजट पर अपना जवाब देंगी। सभी दलों के सदस्य अपने दल के अन्य सदस्यों को अगर बोलने का समय देंगे तो उचित रहेगा। इसलिए अपने-अपने दल में कम समय में अपनी बात को कह दें, तीन या पांच मिनट में कह दें, नहीं तो आपके दल के अन्य सदस्यों का ही बोलने का अवसर नहीं आएगा, यह मेरा आपसे आग्रह है।

डॉ. श्रीकांत शिंदे।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ? (व्यवधान)

15.03 hrs

(Shri Dilip Saikia in the Chair)

महोदय, सबसे पहले अखिलेश जी ने जो बातें कुंभ के ऊपर कही कि 144 बाद यह महाकुंभ आया है। यह ? * है। ? (व्यवधान) आपने यह कहा है। ? (व्यवधान) मैं तो पंडित नहीं हूँ। मैं युवा हूँ और मेरे जैसे अनेक युवा इस महाकुंभ में स्नान करने जा रहे हैं। यह आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, इसलिए आज तक मुझे लगता है कि 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ में गए हैं। करोड़ों लोग आस्था और श्रद्धा के साथ महाकुंभ में गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर अखिलेश जी हिन्दू के विरोध में, महाकुंभ के विरोध में अगर नहीं बोलेंगे। ? (व्यवधान) आपने शुरुआत ही विरोध से किया। ? (व्यवधान) आपको स्नान तो करना ही पड़ेगा। अखिलेश जी, डुबकी तो लगाना ही पड़ेगा। वहां पर कुछ लोग डर से डुबकी लगा कर आए हैं। जिस तरीके से आज लोग साथ में आ रहे हैं, लेकिन आपने हमेशा हिन्दू धर्म का विरोध किया। यह मैं केवल आपको नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि पूरे विपक्ष को बोल रहा हूँ। ? (व्यवधान) हिन्दुओं का विरोध, श्रद्धा का विरोध करने का काम इन्होंने हमेशा ही किया है। आज देश की जनता एकत्रित रूप से वहां आ रही है। इसलिए, मोदी जी के नेतृत्व में पूरी बहुमत के साथ यह सरकार बनी है। ? (व्यवधान)

आप लोग 100 भी नहीं पार कर पाए, 99 पर अटक गए।? (व्यवधान) मेरी पार्टी शिव सेना और हमारे नेता एकनाथ शिंदे जी की तरफ से मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। इस बजट ने हर वर्ग को कुछ न कुछ देने का काम किया है। इस बजट ने डुअल रिकॉर्ड सेट किया है। पहला रिकॉर्ड है कि एनडीए सरकार का यह 11वां बजट है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड है कि निर्मला सीतारमण जी भारत की पहली फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर हैं और उन्होंने आठवां बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है। वह हमारे देश की रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। अभी वह वित्त मंत्री है। उनके कार्यकाल में देश समृद्ध भी हुआ है और सुरक्षित भी हुआ है। अगर हम मोदी जी को टीम इंडिया का कप्तान कहते हैं तो आज टीम इंडिया का विनिंग ऑल राउंडर निर्मला सीतारमण जी को कह सकते हैं। वर्ष 2014 में कांग्रेस ने हमें एक पैरालाइज्ड इकोनॉमी दी थी। उस समय हमारा बजट 17 लाख 94 करोड़ रुपये था। आज सरकार का बजट 50 लाख 65 हजार करोड़ रुपये का है। इसमें 39 लाख 44 हजार करोड़ रुपये का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और 11 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसका मतलब है कि तीसरे कार्यकाल में तीन गुना अधिक बजट, तीन गुना अधिक विकास और तीन गुना स्पीड से विकास इस देश में हो रहा है।

यह बजट कितना महत्वपूर्ण है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसे मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा-

किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं का बजट आया है,

मिडिल क्लास के लिए खुशियाँ लाया है।

बारह लाख रुपये तक अब टैक्स नहीं लगेगा,

हर घर में खुशियों का दीप जलेगा।

मध्यम वर्ग का अब होगा उत्थान,

उनकी मेहनत को मिला है पूरा सम्मान।

युवाओं को मिलेगा काम, गरीबों को मिलेगा अपना पक्का मकान,

बजट ने रखा है समाज के हर वर्ग का पूरा ध्यान,

और विपक्ष हो गया है परेशान।

इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा अब होगा पूरे देश में,

सड़क, पुल और मेट्रो बनेंगे हर प्रदेश में,

वंदे भारत और बुलेट ट्रेन से भी महाराष्ट्र को भी नई रफ्तार मिलेगी,

उबल इंजन की गाड़ी अब तीन गुना तेजी से चलेगी ।

महोदय, मैं वर्ष 2020 का वह समय याद करता हूं, जब वित्त मंत्री जी मुंबई में एक फंक्शन में आई थी । तब के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं बजट के बारे कुछ नहीं समझता हूं, फिस्कल डेफिसिट नहीं समझता हूं । वह कहते थे कि मुझे बजट के दूसरे दिन जो कहना होता है, उसे मैं पहले ही दिन एक टिप्पणी बना कर रख देता हूं । यह बजट आने के पहले होता है । मुझे लगता है कि वैसी ही हालत इस बार विपक्ष की हुई थी । विपक्ष ने पुराने डायलॉग्स रटे हुए थे । उन्होंने इसकी प्रैक्टिस की हुई थी । बजट आने के बाद पूरी तरीके से चेकमेट करने का काम निर्मला सीतारमण जी ने विपक्ष को किया । जब हम बाहर मकर द्वार पर गए, तो वहां पर विपक्ष के एक भी सांसद बाइट देते हुए नहीं दिखे ।

अब ये क्या कहेंगे, क्योंकि बजट में इतना कुछ दे चुके हैं तो अब विपक्ष क्या आलोचना करेगा? मैं सही परिस्थिति बता रहा हूं । मुझे लगता है कि विपक्ष के कुछ साथी खुद के लिए भी सोचते होंगे कि उनको कुछ टैक्स रिलीफ मिला है या नहीं । यह जो बजट दिया गया है, वह भले ही विपक्ष की समझ में न आए, लेकिन देश की आम जनता की समझ में जरूर आ गया है । कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक मिडिल क्लास के हर वर्ग में खुशी की लहर इस बजट के कारण है ।

मैंने इस सदन में पहले भी बताया है कि हमारी सरकार स्कैम्स के लिए जानी जाती है और कांग्रेस की जो सरकार थी, वह स्कैम्स के लिए आज भी जानी जाती है - स्कैम्स और स्कैम्स । विपक्ष वाले बोलते थे कि दस सालों में क्या किया? विपक्ष के कुछ नेता एआई पर भी बात कर रहे थे । वर्ष 2014 से 2024 तक इस सरकार ने किस-किस क्षेत्र में क्या-क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा । ? (व्यवधान) आपको वह भी बताऊंगा ।

?ए? फॉर एयरपोर्ट्स, वर्ष 2014 में 74 एयरपोर्ट्स थे, जो 2024 में 197 एयरपोर्ट्स हो गए । ?बी? फॉर ब्रॉडबैंड, तब कनेक्शन्स 6 करोड़ थे और आज 94 करोड़ ब्रॉडबैंड्स कनेक्शन्स हैं । ?सी? फॉर कोल प्रोडक्शन 56 मीट्रिक टन था, आज 997 मीट्रिक टन है । ?डी? फॉर डिफेंस बजट 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये था और आज 6 लाख 81 हजार करोड़ रुपये है । ?ई? फॉर इथेनॉल का ब्लेंडिंग पर्सेंट जो पहले केवल 1.53 पर्सेंट था, वह आज 15 पर्सेंट है । इसके कारण हमारे देश का फॉरेन एक्सचेंज भी बच रहा है । ?एफ? फॉर एफडीआई, जो 305 बिलियन डॉलर था, वह आज 596 बिलियन डॉलर है । ?जी? फॉर जीडीपी पर-कैपिटा, जो पहले साढ़े 3 हजार डॉलर्स थी, आज 6 हजार डॉलर्स से भी ज्यादा जीडीपी पर-कैपिटा है । ?एच? फॉर हाईवेज की संख्या 91 थाउजेंड किलोमीटर थी, जबकि आज डेढ़ लाख किलोमीटर से अधिक हाईवेज भारत में बन चुके हैं । ?आई? फॉर इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में हमारा देश पहले 81 रैंक पर था, जो अब 39 रैंक पर है । आधे से ज्यादा हमारी रैंकिंग नजदीक आ चुकी है । आप रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं । इनोवेशन में स्टार्ट अप भी आते हैं । पहले स्टार्ट अप सिर्फ 340 थे, जबकि आज डेढ़ लाख स्टार्ट अप इस देश में हैं और सबसे ज्यादा स्टार्ट अप हमारे महाराष्ट्र में हैं । महाराष्ट्र बहुत बड़ा प्रदेश है । ?(व्यवधान)

दिल्ली चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं । मैं एनडीए को एक ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देता हूं और विपक्ष को भी ऐतिहासिक हार के लिए बधाई देता हूं । विपक्ष के लोग कहते थे कि एनडीए इस जन्म में राम मन्दिर नहीं बना पाएगा, धारा 370 नहीं हटा पाएगा

और कुछ लोग कह रहे थे कि मोदी जी इस जन्म में आम आदमी पार्टी को हरा नहीं पाएंगे। इन दस सालों में राम मन्दिर भी बन गया, धारा 370 भी हट गई और दिल्ली में सरकार भी बन गई। इस जन्म में ही यूनीफॉर्म सिविल कोड भी इस देश में आया। जो व्यक्ति अपने आपको पीएम इन वेटिंग समझते थे, नई दिल्ली की जनता ने उनका टिकट ही काट दिया। नई दिल्ली में इतने सालों तक एक परिवार रहा। अपने घर में खाता खोलने के लिए इतने सालों तक परिश्रम, वेटिंग और आने वाले समय में और वेटिंग करनी पड़ेगी। कुछ लोग यहां पर ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं कि फर्जी वोटर जोड़ दिए गए। मैं उनको बताना चाहूंगा, we gave people economic growth, and people blessed us with electoral growth. इसलिए इतना पूर्ण बहुमत भारत में, महाराष्ट्र में हमें मिला और आज दिल्ली में भी है। पिछले दस वर्षों में सिर्फ इकोनॉमिक इंडीकेटर्स ही नहीं, इलेक्टोरल इंडीकेटर्स पर भी हमने रिकार्ड्स स्थापित किए हैं। वर्ष 2014 में एनडीए की सरकार सिर्फ 7 राज्यों में थी और कांग्रेस की सरकार 13 राज्यों में है। वर्ष 2025 में एनडीए की सरकार 21 राज्यों में है और कांग्रेस की सरकार सिर्फ 4 राज्यों में बची है।

आप लोगों ने लोक सभा चुनाव के समय बेइमानी की, लोक सभा के टाइम आपने लोगों को फंसाने का काम किया, लोगों को गुमराह किया इसलिए कुछ वोट आप लोगों को मिल गए। लेकिन लोगों को आप हमेशा गुमराह नहीं कर पाए, उसका नतीजा दिल्ली इलेक्शन हो, महाराष्ट्र इलेक्शन में आपको दिखाई दिया।

माननीय सभापति : शिंदे जी, आप इधर देखकर बोलिए।

? (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : हम लोग अखिलेश जी का भाषण पूरे ध्यान से सुना। आज इंडी गठबंधन एक क्रिकेट टीम की तरह है। इसमें कांग्रेस नाम का एक बैट्समैन है, जो हरेक को रन आउट कराने में लगा है। हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सत्य कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी नहीं, ... * है। कांग्रेस पार्टी भारतीय राजनीति का एक ... * है, जिसके ऊपर हाथ रख दे वह भष्म हो जाता है, उसका उदाहरण महाराष्ट्र में है। ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I will check. If there is any unparliamentary word. I will check.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : महोदय, मैंने कोई असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यही ... * आने वाले समय में खुद के सिर पर हाथ रखने वाला है। हमारे महाराष्ट्र में उदाहरण देखिए, यूबीटी की मशाल को बुझा दिया, घड़ी के सिम्बल पर सबसे ज्यादा विधायक चुन कर आते थे, आज उनकी परिस्थिति क्या हो गई है। जिन्होंने हिन्दुत्व छोड़ा, आइडियोलॉजी के साथ कंप्रोमाइज किया, आज उनके साथ क्या परिस्थिति हो गई है, आप महाराष्ट्र में आकर देख लीजिए।

राहुल जी इस सदन में चीन के एक प्रवक्ता की तरह लग रहे थे। उनकी अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां बता रहे थे और मेक इन इंडिया को फेल्योर बता रहे थे। ? (व्यवधान) जब आप मेक इन इंडिया को गाली देते हो तो सिर्फ इस सरकार को गाली नहीं देते हो, हर मजदूर को देते हो, हर इंजीनियर को गाली देते हो, हर साइंटिस्ट को गाली देते हो, हर डॉक्टर को गाली देते हो। आज मेक

इन इंडिया इनके प्रयासों की वजह से सफल हुआ है। जब उनके सामने भारत की उपलब्धियां राष्ट्रपति जी के एड्रेस के माध्यम से बतायी जा रही थी तो वह कह रहे थे कि यह बोरिंग है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अपमानजनक बात कुछ नहीं होगा। उनको देश से माफी मांगनी होगी, मैं विपक्ष को कहना चाहूंगा, In congress years, India was known as a third world country, today it is soon becoming the third largest economy in the world. यह हमारे शासन और कांग्रेस के शासन में फर्क है। जो लोग फेलियर की बात करते हैं, जहां-जहां इनकी सरकारें बची हैं, वहां पर ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा।

कर्नाटक में सरकार ने 5 गारंटी दिखाकर वोट लिए, लेकिन आज कर्नाटक को 48 हजार करोड़ रुपये का उधार लेना पड़ रहा है। दूसरा हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश में 18 नवम्बर, 2024 को हिमाचल भवन की जब्ती के आदेश हाई कोर्ट ने दिए। चूंकि कांग्रेस सरकार 150 करोड़ रुपये के हाइड्रो पावर परियोजना का भुगतान नहीं कर पाई। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का हाल फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर वाला हो गया है, जिसकी प्रॉपर्टी अटैच करने की जरूरत पड़ गई है। उधर हिमाचल प्रदेश सरकार में समोसा स्कैम पर सीआईडी इन्क्वायरी चल रही है। तेलंगाना में भी 10 महीनों में इन्होंने 50 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। कल हमारे विपक्ष के साथी कुछ आंकड़े बता रहे थे। ? (व्यवधान) अरे, सुन लीजिए, ज्यादा नहीं बोलूंगा। ? (व्यवधान) नॉन स्टॉप कमेंट्री ये सब लोग कर रहे हैं। ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Do not disturb, please.

? (Interruptions)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : कल विपक्ष की एक साथी आंकड़े देकर कुछ बता रही थीं कि हम सब जो यहां बैठे हैं, हर किसी पर एक कर्ज है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि यह कर्ज क्यों है? कैसे हुआ? जब इनकी सरकार थी, तो जनता को इन्होंने बैंक समझ लिया था और उस बैंक को 10 साल तक इन्होंने लूटने का काम किया। वर्ष 1971 में आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन वर्ष 2014 आते-आते आपने बैंकों की ऐसी कर दी, कि यूपीए और एनपीए ज्यादा सुनाई दे रहा था और हमने 10 सालों में इन सभी बैंकों को एनपीए से बाहर निकालकर और संरक्षित करने का काम किया। आज इन बैंकों के माध्यम से पूरे देश में लोगों को सुविधा मिल रही है।

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : इनकम टैक्स अमेंडमेंट ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया एक मिनट में कम्प्लीट कीजिए।

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE: Give me five minutes, Sir.

HON. CHAIRPERSON: No. Your time is already over.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट भी हमने लाया है। पहले इनकम टैक्स टेररिज्म हुआ करता था, आज इनकम टैक्स कम्प्लायंस है। यह 10 साल की जर्नी हमने की है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। वर्ष 2014 से पहले 1 लाख 70 हजार 518 करोड़ रुपये के ऑयल बॉन्ड्स जारी किए गए, लेकिन उस समय की सरकार ने इसे चुकाने की कोई चिंता नहीं की। वर्ष 2014 से 2022 के बीच उसी ऑयल बॉन्ड के लिए 42 हजार 223 करोड़ रुपये प्रिंसिपल अमाउंट चुकाने हेतु ब्याज के रूप में 80 हजार करोड़ रुपये सरकार को देने पड़े। वर्ष 2022 से 2024 के बीच 42 हजार करोड़ रुपये और 22 हजार करोड़ रुपये ब्याज के रूप में चुकाने पड़े। यानी कांग्रेस सरकार की दरियादिली का बिल आज आम आदमी चुका रहा है। कांग्रेस ने इस देश के आम आदमी, किसान को कर्जदार बनाया। उसके बाद कांग्रेस बोलती है कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मुझे लगता है कि किसानों की कर्जमाफी में भी इन्होंने घोटाला किया, क्योंकि सी एंड एजी की एक रिपोर्ट इस सदन में रखी गई थी कि- ?in several cases, the ineligible farmers were given benefit while the deserving ones were left out.? जिसको कर्ज देना था ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप प्लीज समाप्त कीजिए।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : जिसको कर्ज देना था, उसे नहीं दिया और जब अनुराग जी इनको स्कैम्स्टर्स कहते हैं, तो इनको दुख होता है। इन्होंने नैनो यूरिया और कॉटन बैग की कल बात की। ये वे लोग हैं, जिन्होंने कोरोना जैसी आपदा में भी भ्रष्टाचार का अवसर नहीं छोड़ा। जो बॉडी बैग 6 सौ रुपये में मिल रहा था, 6 हजार रुपये में खरीदने का काम इन्होंने किया। खिचड़ी में घोटाला करने का काम इन्होंने किया। सीडब्ल्यूजी में रिकॉर्ड घोटाला करने का काम इन्होंने किया। इनके खुद के मंत्री टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की जगह अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वसूली कर रहे थे और जेल भी गए। इस बात को किसी ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है।

HON. CHAIRPERSON: Okay Shinde ji, please conclude.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : सर, मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा।

HON. CHAIRPERSON: Your time is over.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : इसीलिए इस न्यायालय ने आदेश दिया और उनको जेल में भेजा। मैं यहां पर महाराष्ट्र की बात करूंगा।

महोदय, ये पूछ रहे थे कि इस बजट में महाराष्ट्र को क्या मिला है। मैं यहां पर बताऊंगा कि इस बजट में महाराष्ट्र को क्या-क्या मिला है। महाराष्ट्र को वधावन पोर्ट के माध्यम से 76,000 करोड़ रुपये मिले हैं, जो हमारे महाराष्ट्र में 12 लाख रोजगार का निर्माण करेगा। टैक्स प्रोसीड्स के माध्यम से महाराष्ट्र को 90,000 करोड़ रुपये मिले हैं। महाराष्ट्र को एमवाईटीपी-थ्री प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत 1,400 करोड़ रुपये मिले हैं। पुणे मेट्रो के लिए 837 करोड़ रुपये मिले हैं। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रोड के लिए 4,300 करोड़ रुपये मिले हैं। (व्यवधान) मुंबई मेट्रो के लिए 1,600 करोड़ रुपये, रूरल ट्रांसपोर्ट इम्प्रूवमेंट के लिए 683 करोड़

रुपये तथा इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत 652 करोड़ रुपये मिले हैं। रेलवे सेक्टर में सबसे ज्यादा फायदा महाराष्ट्र को हुआ है, हमें रेलवे में 23,778 करोड़ रुपये मिले हैं।?(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : महोदय, आज गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावित एरिया में भी विकास की बात हो रही है।?(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please conclude in a sentence.

Now, I will call another hon. Member.

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : महोदय, हमारी डबल इंजन सरकार में गढ़चिरौली जैसे नक्सल प्रभावित इलाके को भी देश की मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो रही है तथा आज गढ़चिरौली में जिंदल स्टील जैसा एक लाख करोड़ रुपये का स्टील पावर प्लांट लग रहा है, जिससे हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी। मैं इसके लिए तब के वहां के मुख्यमंत्री तथा गार्जियन मंत्री एकनाथ शिंदे जी को खूब-खूब धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। आज उसको आगे बढ़ाने का काम बीजेपी के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस जी कर रहे हैं। मैं कुछ पंक्तियां बोलकर अपना भाषण समाप्त करूंगा।?(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, जो भी माननीय सदस्य बजट 2025-26 पर लिखित भाषण देना चाहते हैं, वे सभा पटल पर अपने भाषण की प्रति रख सकते हैं। इसकी अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI SALENG A. SANGMA (TURA): Thank you, Mr. Chairperson, Sir.

Mr. Chairperson, Sir, after the presentation of the Budget by the hon. Finance Minister, it was unfortunate to see the citizens of India shackled, chained, and brought as prisoners from the USA. How do we expect that this Budget will be so beautiful? We should learn from the past. They have been expressing their praises about this Budget as well as the previous Budget. But how do we expect when thousands of Indians are being pushed back from the other country, chained and shackled? It is a shame for us. If the Budget is so good, why are our own citizens fleeing from our own India to get better jobs in other countries? Is it not fair enough to see what actual issues are happening within our country?

HON. CHAIRPERSON: The hon. Minister of External Affairs has given a statement in the Parliament.

? (Interruptions)

SHRI SALENG A. SANGMA: No, Sir, I am talking about the Budget. ? (*Interruptions*) I am coming to the Budget. ? (*Interruptions*) It is because this Budget reflects? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: No, you must go through that statement also.

SHRI SALENG A. SANGMA: If the Budget is so good, then our own people would not have left, risked their lives to go to other country illegally. Just imagine, illegally going there, and then, being shackled and chained, and then, pushed back to our own country. Just imagine, how and why are they risking their lives? It is because we cannot provide them a good job/good employment and good environment. That is why, they are running away from our country.

Mr. Chairperson, Sir, a lot of questions have been asked by our Parliamentarians. Do we have to take unflinching realism to take such answers? This Government's methodology and the purpose of defining the financial Budget to planning future seem to have drifted away steadily from the realism. The Budget seems to have boxed in a dysfunctional manner. Therefore, I would like to focus on a few areas.

There was a quote by our Father of the Nation, and I quote:

?If we want to teach real peace in this world, we should start educating children.?

This is a famous quote by our Father of the Nation, Mahatma Gandhi.

Mr. Chairperson, Sir, now, I talk about education. The Right to Education has totally collapsed under the SSA. No amount of funding can revive it because it is completely destroyed. A complete overhaul by giving funds to the district, block level and at village level is the only solution. New restructured institutions and policy is the only option.

Mr. Chairman Sir, when we come to the North-East Region, the Budget 2025 does not reflect substantial increase in the allocation specifically to the education needs in the region. The North-East including Meghalaya, Assam, Arunachal Pradesh face higher school dropout rates due to socio-economic factors.

The neglect of the Government in education is evident in the decrease in education spending dropping from 2.57 per cent to 2.51 per cent of the GDP which greatly strays away from the recommended Government spending on education to be at least six per cent of GDP (NEP, 2020).

Mr. Chairperson, Sir, we have seen the Budget fell short of addressing key problems despite announcing grand plans. If we fail to make announcements with substantial funds, particularly for areas such as agriculture, education and urban development, then we will not grow.

Now, when you look at the scholarship for the minorities and for those who reach matriculation, it has been cut down by 40 per cent, bringing down the fund to Rs. 197.50 crore. The scholarship for students after matriculation faced an even steeper cut, dropping by nearly 64 per cent to Rs. 731.39 crore. The merit-based scholarship has decreased to Rs. 7.34 crore. In addition, the National Fellowship and Scholarship for higher education has decreased to Rs. 7.34 crore.

Mr. Chairperson, Sir, we talk about the Budget cut. This Budget cut will only increase the spending in other areas. This is only for certain rich people. Yesterday, our Parliamentarians have spoken about this particular Budget whereas the poor tend to spend every single rupee that he has earned. Now, the poor does not have a saving at all. MGNREGS and other sorts of wages and GST have not been compromised by this Government.

So, I would like to urge if there is any chance, if they can amend this area where our poor people, our BPL people can be looked into.

With these few words, Mr. Chairperson, Sir, I resume my seat.

श्री राजेश रंजन (पूर्णिमा) : सभापति महोदय, धन्यवाद । जब सशक्त भारत की बात आती है तो लगभग पौने तीन-चार सालों से किसान धरने पर बैठे हैं । किसानों की मौतें हुई हैं, आत्महत्या हुई हैं । एक तरफ किसान हैं, तो दूसरी तरफ मणिपुर है । पूरे देश में नीट से लेकर सभी तरह के एग्जामिनेशन पेपर्स लीक आउट हैं और लगातार बच्चों पर जुल्म हो रहा है, बच्चों पर केस हो रहे हैं । जो आईएस बनेंगे और देश का निर्माण करेंगे, उनके पेपर लीक आउट हो रहे हैं । आजाद हिंदुस्तान के बाद हमारे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब हम इस देश के इन सारे मुद्दों के बारे में सोचते हैं, तब मुझे लगता है कि एक तरफ अमेरिका है, जिस पर इतने सारे सवाल आ गए हैं और दूसरी तरफ महाकुंभ है । आजाद हिंदुस्तान के बाद नेहरू जी के समय में जब मात्र 848 करोड़ रुपये का बजट था, तब नेहरू जी ने जिन बातों का उल्लेख किया था, उसके बाद लगातार हर 12 सालों के बाद महाकुंभ आता है । आज इतने सशक्त प्रधानमंत्री हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश किसी राज्य के ताकतवर लोग कर रहे हैं या सनातन के प्रति इनका सम्मान नहीं है?

सशक्त भारत की बात आती है तो हमारा कोई भी पड़ोसी देश रास्ता देने को तैयार नहीं है, हमारे साथ व्यापार करने को तैयार नहीं है । जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वियतनाम और ताइवान इत्यादि सब चीन के साथ जा चुके हैं । भुटान के सारे मंत्री चीन में

बैठे रहते हैं। हमारा पड़ोसी देश हम से बिल्कुल अलग है। About 23 million people are leaving India every year. 11 बार बजट पेश हुआ है। About eight to nine lakh professionals like CA are under the threat of possible brain drain. There is no relaxation on tax for those 30 per cent people who file their ITRs under the old tax regime. वर्ष 2024 में भारत पर विदेशी कर्ज लगभग आठ अरब डॉलर है। लगभग 1 लाख 96 हजार करोड़ रुपये का कर्ज हमारे ऊपर है। क्या यह कर्ज भारत चुका सकता है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस हिन्दुस्तान में तीन चीजों पर कभी मूल्यांकन नहीं हुआ है। एक है, जितने मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद हैं। अगर हम मंदिर की बात करें और गुरुद्वारे, चर्च और मस्जिद को छोड़ दें तो साढ़े तीन से चार लाख करोड़ रुपये मंदिर डिपोजिट है। गुरुद्वारे अलग हैं, बाकी अलग हैं। हमारे ऊपर जो कर्ज है, क्या उस पैसे पर हमारा वित्त मंत्री जी कोई निगरानी नहीं रखते हैं? क्या उस पैसे पर कोई टैक्स की बात नहीं आती है? क्या हम दो दिन का खाना खिलाकर पूरी फ्रीडम दे देंगे। दूसरी तरफ, इस हिन्दुस्तान में जितने बाबा लोग हैं, किसी के पास दो हजार करोड़ का है, किसी के पास दस हजार करोड़ रुपये का है। उन लोगों ने फंडिंग रेज़ की है। मैं सब बाबा का नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि सभापति महोदय, आप भी समझते हैं कि हिन्दुस्तान में फकीरी और अमीरी दोनों में मजा है। जिस तरीके से बाबा लोगों ने इस देश को एनजीओ के माध्यम से, एनजीओ के पास भी लगभग 33 लाख करोड़ रुपये हैं, ऐसा क्या कारण है कि एनजीओज़ पर किसी प्रकार के टैक्स नहीं लगते हैं। उनको लूटने की फ्रीडम है, उस पर हमारा अंकुश नहीं है। दूसरा है, सीएसआर फंड है। बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, हमारी ही सरकारी कंपनियां हैं, वे सीएसआर फंड का क्या करती हैं? उसको कहां लगाती हैं, किसको देती हैं, किस एमपी से बात करके लगाती हैं?

मेरा कहना है कि नोटबंदी के बाद 16.99 लाख करोड़ रुपये के डिमोनेटाइजेशन का मामला था। उसके पहले 35.99 लाख करोड़ रुपये का मामला था। आज भी 35.99 लाख करोड़ रुपये का है। कितने लोग उस समय मरे?

मैं हेल्थ और एजुकेशन पर आता हूँ। इस बजट में हेल्थ पर, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई पर आप जीएसटी ले रहे हैं। 28 फीसदी जीएसटी सीमेंट पर है। आपने एजुकेशन पर जीएसटी लगाया हुआ है। पेन, पेंसिल, कलम, दवात और किताब पर जीएसटी लगाया हुआ है। क्या बच्चे पढ़ पाएंगे?

सभापति जी, भ्रष्टाचार और गरीबी के समाधान पर कभी इस सदन में हम चर्चा सही तरीके से नहीं करते हैं। उसका समाधान कैसे होगा? जीएसटी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। सबसे ज्यादा जीएसटी की मार छोटे व्यापारियों पर है। अगर मैंने एक लाख करोड़ रुपये का टेंडर लिया और उस टेंडर को छुपाकर 50 हजार करोड़ रुपये कर लेते हैं तो हम जीएसटी की चोरी कर रहे हैं। जीएसटी एक बड़ा अभिशाप है, वरदान नहीं है। वह इस कंट्री के मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा बोझ है। आपने किचन आइटम्स पर जीएसटी लगायी हुई है। आपने हेल्थ पर जीएसटी लगायी हुई है।

सभापति महोदय, मैं सिर्फ अपनी एक बात करके अपना भाषण समाप्त करूंगा। बिलो पावर्टी लाइन में जितने भी गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, उनमें से दसवीं क्लास में जाते-जाते लगभग 72 से 78 परसेंट बच्चे ड्रॉप

आउट हो जाते हैं। उसके बाद बाहरवीं तक जाते-जाते 58 परसेंट ड्रॉप आउट हो जाते हैं। वे पढ़ नहीं पाते हैं और हम कोचिंग के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाते हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि बिहार में बार-बार मखाना की चर्चा होती है। मखाना, दुनिया में सबसे ज्यादा मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्णिया और कटिहार में होता है। उससे ज्यादा कहीं पर भी नहीं होता है। सीमांचल कोसी मिथिला का एक भाग मधुबनी है। यहां बार-बार मखाने की बात आती है, लेकिन मखाने की प्रोसेसिंग के बारे में कोई नहीं जानता है। हमने मखाना फैक्ट्री की बात की। हमने मखाने के प्रोडक्शन की बात की। हमने बाजार की बात की। हमने 10 फैक्ट्री के लिए कहा तो आप उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। हम कोसी की बात नहीं कर रहे हैं।

सभापति महोदय, उसके तीन हिस्से नदी से जुड़े हुए हैं। भीम नगर बैराज हो या फरक्का बैराज हो, वहां गंगा है, कमला है, महानंदा एक्सप्रेस वे है और गंडक है तो हम तीनों हिस्सों से बाढ़ से प्रभावित हैं। आप हर बजट में कोसी कैनाल लेकर आते हैं। आप हर बजट में एक ही बात को कहते हैं।

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात को समाप्त कीजिए।

श्री राजेश रंजन : सर, मुझे एक मिनट दे दीजिए। मैं अंत में आप से यह बात कहना चाहता हूँ कि हाई डैम बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात स्मार्ट सिटी की है। पूर्णिया की चर्चा थी। कटिहार की चर्चा थी। तीसरी बात मेट्रो की थी। पूर्णिया और कटिहार मेट्रो की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ? (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका समय समाप्त हो गया है। अब आप बैठ जाइए।

? (व्यवधान)

ADV. FRANCIS GEORGE (KOTTAYAM): Sir, the Finance Minister in her Budget Speech again mentioned about the importance of agriculture sector. She said that it is the first engine of our economy.

In the last Budget also, she said that the Government should take care of our *annadatas*. She also quoted the lines of poet Apparao: 'A country is not just its soil, a country is its people?' She has announced about ten programs for the agriculture sector, out of which one is about this Makhana Board in Bihar. That is okay. But, I would like to politely ask the Finance Minister about the demands of the farmers of this country. The farmers of the country are on strike. They are demanding, as we all know, MSP, Minimum Support Price at the rate of C2+50 per cent as recommended by the National Commission on Farmers. That is the average weighted cost of production plus 50 per cent above that cost of production. This should be made binding on the Government by an enactment in Parliament. They

are also demanding waiver of debt, and pension. But, the budget is totally mum on all these three aspects.

As the Finance Minister is from the South, she knows the nutritional and medicinal value of jackfruit. We have no quarrel about giving a Makhana Board to Bihar. But, she totally forgot jackfruit, that is a staple fruit of the South, which is very nutritional, and also it has got medicinal values. I would request the Finance Minister to announce a Jackfruit Board also in her reply.

Sir, human-animal conflict is increasing in the country, especially, in the Western Ghat areas. In Kerala, in the last six years, there have been 60,000 cases reported of man-animal conflict. More than 1,000 people have died, more than 8,000 people had been injured, and the loss of crops is uncountable. This problem has to be addressed on a mission-mode by the Government. But, the Budget is totally silent on this.

The next point is about waiver of debts. NCRB, the National Crime Records Bureau has reported that from 2014 to 2022, more than one lakh farmers have committed suicide due to debt burden. The total farm debts in commercial banks, cooperative banks, and RRBs amount to only Rs. 1,42,610 crore out of more than one crore accounts in these three sets of banks, whereas the tax cuts for corporates alone comes to Rs. 4,53,329 crore, let alone the write offs.

So, the farmers are demanding pension for the farm workers too but the Budget is mum on all these demands.

Sir, the Budget announced in July, 2024 talked about the job and internship opportunities for 4.1 crore youths. The outlay was Rs. 2 lakh crore. The Periodic Labour Force Survey says that in 2023-24, the youth unemployment for those in the age bracket of 15 to 29 years has gone up to 10.2 per cent. Among graduates, it is 13 per cent. The wages are falling.

Sir, in respect of Jal Jeevan Mission and PM Awas Yojana, the amount has been slashed in this Budget. Talking about the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme, there is a cut of Rs. 3,654 crore in this year's Budget. This is the budgeted capital welfare expenditure, and this will affect investment and consumption in rural areas.

Sir, the Government is gloating about the income tax cut. Only 2.8 crore individuals paid tax in 2023-24 out of the 7.5 crore people filing returns. The relief will go to only 2.8 crore who form 22 per cent of our salaried class. The revenue foregone is Rs. 1 lakh crore. Instead of this, if a cut of similar rate on indirect taxes like excise duties on fuel and Central GST rates on mass consumption goods had been done, it would have given relief to the entire working class. But that was not done.

Sir, now, I come to the National Rural Employment Guarantee Scheme. ? (*Interruptions*) Let me complete, Sir. Please allow me one or two minutes.

Sir, the daily wage rate as per the Ministry's dashboard is Rs. 252.31 in 2024-25. The national floor level minimum wage for agricultural labour is Rs. 452. What was needed was a hike in the NREGA wages and an increase in rural development outlays.

Sir, the after-tax profit to GDP ratio of NIFTY 500 companies rose from 2.1 per cent in 2021 to 4.8 per cent in 2023-2024 due to a deep corporate tax cut in 2019. But it did not translate to high investment or employment generation.

Sir, I am concluding by raising certain Kerala-specific issues. Kerala has demanded a special fund of Rs. 1,000 crore to mitigate human-animal conflict, which is almost a daily occurrence in Kerala. A special fund of Rs. 1,000 crore was asked for paddy procurement as the farmers are not getting their funds from the procuring agency and they have to seek loans. A special fund should be there to ensure that the rubber farmers get Rs. 300 per kg for the rubber. Rubber is a strategic crop. Every year, thousands of crores are coming to the kitty of the Central Government out of this rubber import duty. So, if a portion of it can be given to the rubber farmers, we can increase the production of rubber. That will avoid this massive import of rubber and consequently lead to the fall in prices of natural rubber. So, I request the Finance Minister to make an announcement regarding this in her reply.

Sir, I had specifically asked for the Vembanad Lake restoration programme. It is a pristine ecological system in Kerala which is dying. So, I had asked for a special project to restore Vembanad Lake, but the Finance Minister did not say anything about it. Due to paucity of time, I am not going into the details of that.

Sir, GST has also been imposed on the traditional snacks of Kerala. There has to be a lower uniform tax rate for the entire MSME food sector.

HON. CHAIRPERSON: Okay, please conclude now.

ADV. FRANCIS GEORGE: Sir, the advance ruling mechanism of GST is not functioning in Kerala properly. There is GST on ready-made Khadi garments. There are 28 khadi and village industries in Kerala which generate employment. They give rural employment. Many are on the verge of closure due to this imposition of GST on readymade Khadi garments. So, I request the hon. Finance Minister to withdraw that.

Thank you.

SHRI YADUVEER WADIYAR (MYSORE): Thank you, Hon. Chairperson, Sir, for giving me this opportunity. I rise to support this Budget of 2025-26. I would use this occasion to congratulate the hon. Prime Minister and the hon. Finance Minister. I understand that it is her eighth Budget, and congratulations are in order for this record.

Viksit Bharat of 2047 is the first time a leader in democratic India has laid the foundation for a long-term vision and has initiated a structured approach for an economically developed Bharat. This year's Budget adds strong building blocks towards executing the ideas within the noble vision of the Prime Minister representing the continued commitment of the Government to work towards the aspirations of 140 crore Indians and looks to ensure their happiness and welfare. The last 10 years of successive Modi Governments have laid a strong foundation for Viksit Bharat, and this Budget builds on that foundation by adding strong pillars to support the grand edifice of this noble vision.

Given the limited time, I would like to focus mostly on my State and all of the key policy shifts that will benefit my State of Karnataka. The National Action Plan on Toys especially benefits States such as mine. Between Bangalore and Mysore, the district of Channarayana is a well-known toy-making centre and the district of Koppal as well is a well-known toy-making centre. Both of these places will be abundantly benefited. Given the huge impetus and the full push given on the National Action Plan for Toys, I am sure that the heritage, that is, toy-making will be conserved and furthermore made attractive for the modern audience.

Sir, aside from that, the Gyan Bharatam Mission will be a boon for cities such as my own in Mysore, which have an abundant treasure of manuscripts and need urgent conservation as well. I am sure that this heritage being preserved and accessible to one and all will be another boon that this Budget will bring along.

This investment also highlights the key aspect of Viksit Bharat. Never before has such an impetus been given to preserving, conserving, and most importantly taking pride in our Bharatiya heritage. Viksit Bharat pays homage to the aspirations of Bharat from its civilizational roots all the way to its modern aspirations to be a world leader in AI, deep tech and cyber security. In particular, the modified UDAAN scheme as well looks to benefit many of the smaller, tier-II and tier-III cities in Karnataka as well. I am also very happy to learn that a special airstrip will be given to Kushalnagar, which is within my own constituency of Mysore and Kodagu. Kodagu has not a very strong connectivity, and so this airstrip will benefit tremendously in ensuring that a very vital and agricultural district gets the needed impetus. It needs to ensure better pricing for their agricultural goods.

Sir, many schemes, of course, will be benefited by a complete transformation in the tax sphere. The positive transformation in our tax landscape will play a pivotal role in nation building, and this decade of tax reforms is perhaps one of the least underappreciated aspects of the Modi-led Governments. From 2014 onwards, the tax slabs have seen continuous improvements from Rs.2.5 lakh exemption to Rs.12 lakh exemption in this current Budget. We have been witness to a paradigm shift in the functioning of our Income Tax Department. Gone are the days of the Income Tax Department being an enforcer; rather, today's IT Department has been repositioned as an infrastructure to assist the taxpayer in services and understanding Government policy. So, the codifying of rights and duties of the taxpayer, the recognition of our taxes being utilised for nation-building have all contributed positively, and the contribution of direct taxes to total tax revenue has also been steadily increasing as compared to the indirect taxes.

Another big investment for my State of Karnataka has come in the railway infrastructure. An additional allocation of Rs.7,564 crore in the Budget to our railways, which is one of the highest ever railway allocations, is a big boost in connectivity for our State. A total of 61 railway stations are being upgraded with Rs.1,981 crore. The addition of two new Namo Bharat trains is very much a welcome development. Additionally, Bangalore Metro is also getting an allocation of Rs.1717 crore, all of which will

benefit both Bangalore in terms of its traffic woes as well as alleviate many of the issues that Bangalore faces.

Sir, sadly, over the last two years since the Congress-led Government has come to Karnataka, the progress that has been seen in the rest of the country which is going on with the Prime Minister's noble vision, has been in stark contrast with our current State's Government's policy. Instead of adopting better fiscal management and people-friendly policies, the State Government continues to misrepresent facts and present half-truths to point a finger at the Central Government to cover the Congress-led Government's inability to manage their own economic affairs. So, our constant accusation is that the taxes due to our State of Karnataka are not being given commensurate to what the other States are receiving in the north. This cannot be farther from the truth.

The tax devolution for Karnataka in 2004-2014 was Rs. 81,795 crore with the UPA-led Governments. That has jumped 250 per cent to Rs. 2,85,455 crore in the current Modi-led Governments. The grant-in-aid during the UPA Governments was Rs. 60,779 crore. That has jumped to Rs. 2,08,832 crore or rather a 243 per cent increase in the Modi-led Governments. The increase in tax devolution and grant-in-aid has been multi-fold. Despite this, the current Government continues to lay the blame on the Central Government to cover their bad fiscal management.

Their leadership is best represented by a quote from Mahatma Gandhi's autobiography: "But you can wake a man only if he is really asleep. No effort that you will make will produce any effect upon him if he is merely pretending to sleep." The State Government is pretending to sleep as we lose out on the 15th Finance Commission grants because they are unable to conduct local body elections. They continue to pretend to sleep when salaries for our workers, our school teachers, and our doctors are not being paid. Key central projects, including in my own constituency, like the Mysore-Kushalnagar railway line, which is required for Kodagu, have not been given due to the State's mismanagement of fiscal policy. Also, there is the Awas 2.0, which is for urban bodies, where the Modi Government has promised houses for all urban backward communities and for those who are economically weaker. While 29 other States have been signatories, the current Congress State has not been a signatory and this has been a very bad development and is not helping us in implementing the policies. All of this has been a bad picture for our State Government and such bad administration is a blight on development. We must urge the citizens of

our State to look past this misrepresentation and hold the State Government responsible for the injustice they have put upon the people. ? (*Interruptions*)

माननीय सभापति : डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन जी ।

पास में बैठे हुए लोग ज्यादा बोलते हैं कि और समय दीजिए ।

DR. PRABHA MALLIKARJUN (DAVANAGERE): Hon. Chairperson, Sir, thank you for allowing me to speak on the Union Budget.

I rise today not just as a critic of this Budget but as a concerned citizen and a Member of Parliament representing Karnataka's Davanagere Lok Sabha constituency. I stand to contest what the incumbent Government promises of its failed Viksit Bharat dream. They say, 'सबका साथ सबका विकास' । The reality reads more like कुछ का साथ, चुनिंदा कॉर्पोरेट का विकास ।

This Government boasts of economic growth. Let me put out some shivering facts to the ears of our Treasury Benches. The hon. Finance Minister says, 'She has heard the voice of the middle class', while rolling out changes in tax slabs. Let us be aware that only 6.68 per cent of India's population filed income tax returns in fiscal year 2023-24. India's population is around 142 crores. Which middle class is the Finance Minister talking about? What relief are you offering to the poor who live with less than Rs. 100 a day? The graduate unemployment rate stands at 29.1 per cent, which is the highest in recent history. In general, the unemployment rate had even peaked to 9.2 per cent in June 2024. Since 2014, real wage growth has been abysmal. Agricultural labourers' wages increased by just 0.8 per cent, non-agricultural workers by 0.2 per cent, and construction workers faced negative wage growth. The number of billionaires has surged to 200 with the wealth rising 41 per cent in 2024. The top one per cent now control more than 40 per cent of India's wealth, which is the highest inequality since the British rule. The public sector banks have written off Rs. 9.90 lakh crore in bad loans to corporates in the past five years. Is this Viksit Bharat? The household debt is at a record 39 per cent of GDP. A hundred million promised manufacturing jobs never materialised. Twenty-four lakh SME units have shut down since 2015-16. Communal violence is at its peak. Has the Government uttered a single word on the need for secularism and brotherhood? This is the state of Viksit Bharat we are living in. *Vikas* of Viksit Bharat is completely

lost and nowhere to be seen. The gross injustice the NDA Government has done to India cannot be washed off even if they take a dip in the holy Kumbh Mela.

16.00 hrs

Our farmers are struggling with the NABARD allocation being slashed by 58 per cent and the cooperative banks being crippled. This is forcing lakhs of farmers to go into the private money-lenders' hands. Meanwhile, the Government remains silent on legally guaranteeing MSP, leaving the farmers vulnerable to exploitation.

Let me now turn to what I call this Government's 'triple talaq' on rural India, their systematic dismantling of MGNREGA, NABARD and our Self-Help Groups.

As a doctor, I present the latest chapter of this Government's healthcare horror story. The Finance Minister has allocated Rs. 99,858 crore for healthcare in the Financial Year 2025-2026. Let me give you the real prognosis. The current medical inflation rate in India is 14 per cent, which is highest among the Asian countries, including China. We have a 79.5 per cent shortfall of specialists, and the doctors are working over 36 hours in shifts.

Let us talk about priorities. India's healthcare spending stands at just two per cent of GDP. For a nation aiming to become a developed economy by 2047, how can we dream of a Viksit Bharat when lakhs of people still go bankrupt over hospital bills? Even the PPP model is suffering with no governance structure and zero ownership. It has become nothing more than publicity, propaganda and photography.

As a medical professional, I can tell you that this is not universal healthcare. It is universal health scare. ? (*Interruptions*)

Sir, please give two minutes more. Article 1 of our Constitution describes India as a Union of States. The idea of cooperative federalism is being systematically eroded by this Government.

Karnataka is among the top contributors to the national economy. Karnataka contributes Rs. 4.3 lakh crore in taxes, yet it receives only 13 paise for every one rupee given. Yet, the Centre happily distributes funds elsewhere to serve its political interest.

Despite these betrayals, Karnataka continues to lead by example allocating Rs. 52,000 crore for the welfare schemes. Even the UNGA President, Philemon Yang has hailed Karnataka's guarantee schemes for empowering women, endorsing them as models for global adoption in future UN workshops.

When injustice becomes law, resistance becomes our duty. This Budget exposes the Government's neglect, widening inequality, and failure to address the nation's pressing crisis. Deception cannot replace real governance, and empty rhetoric will not mask the hardships faced by millions. If accountability is ignored today, the consequences will be unavoidable tomorrow.

I would like to end my speech by quoting the great Kannada poet, Sarvagna that expresses the plight of Karnataka State at the hands of the Centre -- if rain falls on the rock, the rock will not absorb the water.

Jai Hind! Jai Karnataka! Jai Samvidhan!

***m16 श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील (सांगली) :** माननीय सभापति जी, वर्ष 2025-26 के बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

मैं अर्थ मंत्री जी को आठवीं बार बजट पेश करने की उपलब्धि पर भी बधाई देता हूँ । While we welcome the few positive announcements, I regretfully state that for a record five Budgets in a row they failed to mention the State of Maharashtra in the Budget Speech.

उन्होंने वर्ष 2021 में नाशिक का उल्लेख किया था, जब वहाँ मेट्रो की घोषणा की गई थी । लेकिन पिछले 10 वर्षों में मेरे संसदीय क्षेत्र सांगली या पश्चिमी महाराष्ट्र का नाम एक बार लेने का रिकॉर्ड अर्थ मंत्री जी ने कायम रखा है । देश के जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन का एक-चौथाई हिस्सा यानी, 24 per cent contribution comes from Maharashtra.

I have already said that Maharashtra contributes 37 per cent to tax and 14 per cent to the GDP. Apparently, many people say that GVA is a better economic figure. सर, महाराष्ट्र 37 परसेंट कंट्रीब्यूट करता है और सिर्फ 6 परसेंट इसे वापस मिलता है । लोगों को अपेक्षा थी, इन्होंने पिछले साल महाराष्ट्र में सरकार बनायी है । लोक सभा में इन्हें वोट नहीं मिले, इसलिए शायद पिछले साल इन्होंने बजट में कुछ नहीं दिया था । लेकिन इस बार के चुनाव में, हाइएस्ट स्ट्राइक रेट से, महाराष्ट्र की जनता ने 132 विधायक भाजपा को दिए । स्वाभाविक है कि लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बजट में उनको कुछ तो मिलेगा । सांगली जैसे शहर में स्मार्ट सिटी का इंकलूजन करना, महाराष्ट्र में नये एयरपोर्ट्स का निर्माण करना, एआईबीपी और पीएमजीएसवाई में सिंचाई के लिए पैसे देना, महाराष्ट्र के लिए नये आईआईटीज और आईआईएमज खोलना, एमएसपी को लीगलाइज करना, महंगाई को सीमित रखना, ईपीएस पेंशन योजना के तहत सात हजार रुपए देना, भूमिहीन किसानों को

पीएमकेएसवाई में लाना, फर्टिलाइजर और सीड्स पर से जीएसटी हटाना, मनरेगा में न्यूनतम आय 400 रुपए करना, आशा वर्कर्स की आय बढ़ाना आदि ऐसे बहुत-से डिमांड्स थे।

किसानों का कर्जा माफ करना भी एक डिमांड थी। किसानों का कर्जा माफ करने की बीजेपी ने चुनाव के पहले घोषणा तो कर दी।

सर, लोग कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं हैं। जो कर्जा चुका सकते हैं, अब वे भी नहीं चुका रहे, क्योंकि उन्होंने यह घोषणा सुन ली है कि कर्जा माफ होने वाला है। महाराष्ट्र की ग्रामीण व्यवस्था इस वजह से पूरी तरह वेंटिलेटर पर चली गई है। कोई कर्ज नहीं भर रहा है, कर्ज मिल भी नहीं रहा है।

सर, क्या बजट में इस बारे में कुछ भी बोलना सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी या नहीं? मराठी में एक कहावत है ? ?बाप दाखव नाही तर श्राद्ध घाल?। इसका मतलब यह है, या तो सरकार कर्जा माफ करे, वरना ये कबूल कर लें कि इनसे कर्जा माफ नहीं होगा, यह इलेक्शन में बस एक जुमलेबाजी इन्होंने की थी। मैं बजट की दो-तीन अनाउंसमेंट्स के बारे में बात करता हूँ। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। 12 लाख तक एग्जेंप्शन की बात हुई थी। सात करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं।

What was the basis for coming up with the exemption scheme which elevates 35 per cent of the tax-filing population? जो लोग पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स फाइल करते हैं, उनके लिए एक रुपए का बेनिफिट इन्होंने इस बजट में नहीं अनाउंस किया। What is the hidden agenda behind making people shift from the old regime to the new regime? By removing the old regime, you are giving a short-term gain and the result will be a long-term loss. What is the reason then for discouraging people from savings, buying houses, and buying insurance? The Government needs to explain that.

They are targeting Rs. 14 lakh crore collection from personal income tax alone. Therefore, they are proposing to collect 35 per cent more tax from individuals than from the entire corporate world. अडानी, अंबानी, रिलायंस, बिरला सब मिलाकर लोगों से 35 फीसदी ज्यादा इनकम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। The personal income tax they are expecting is 25 per cent higher than the entire GST collection in India. आप लोग मिडिल क्लास पर और कितना बोझ डालोगे?

इन्होंने किसानों के कर्ज के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी को तीन लाख रुपए से पांच लाख रुपए बढ़ाया है। मैंने पूरे बजट को पढ़ा है। कहीं भी इसका एडिशनल प्रोविजन नहीं दिख रहा है। Is this actually an announcement just to please people? जिसे ? फील-गुड? वाला बोलते हैं या सच्चाई में इन्होंने कुछ किया है? एक्स्ट्रा कर्जा लेने के लिए कितने लोग पात्र हैं? 50-60 हजार रुपए

एकड़ के ऊपर कर्जा ही नहीं मिलता है। पांच लाख रुपए का कर्जा लेने के लिए दस-दस एकड़ जमीन लेनी पड़ती है, लोगों के पास दस एकड़ जमीन नहीं है।

इन्होंने कस्टम ड्यूटी रिडक्शन की बात की है। कस्टम ड्यूटी रिडक्शन में इन्होंने इतनी चालाकी की है कि कस्टम ड्यूटी उतार दी और एग्रीकल्चर सैस लगा दिया। यानी, जो सेंट्रल पूल का पैसा था, जो स्टेट्स को जाता था, वह निकालकर इन्होंने सेंट्रल पूल में खुद के लिए बढ़ा दिया। They are stealing the funds from the States by doing this.

पिछले बजट में भी इन्होंने डाला था कि न्यू स्कीम्ज के लिए 60,000 करोड़ रुपए देंगे। अब वापस इस बजट में डाला है कि न्यू स्कीम्ज के लिए 60,000 करोड़ रुपए देंगे। ये कौन सी स्कीम्ज हैं, यह तो बताया नहीं? रिवाइज्ड एस्टिमेट्स में बताया कि न्यू स्कीम्ज में आठ ? नौ हजार रुपए का खर्चा भी हो गया, लेकिन ये कौन सी न्यू स्कीम्ज हैं? मेरी बात ऑलमोस्ट खत्म हो गई है।

16.07 hrs (Dr. Kakoli Ghosh Dastidar *in the Chair*)

मैडम, यह सब दिखावा है। ये दिखाते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। पुराने जमाने में निकम्मे लड़के की शादी करने के लिए होनहार लड़के की फोटो दिखाकर शादी करवा देते थे, बाद में पता चलता था कि शादी किससे हुई है। महाराष्ट्र के चुनाव में कुछ यही हुआ है। इलेक्शन से पहले एकनाथ शिंदे जी का चेहरा दिखाकर रिजल्ट ले लिया, जीत गए, लेकिन जीत के बाद कोई और ही घोड़ी पर चढ़ गया। यह ऐसा हुआ मैंन ऑफ दि मैच को इन्होंने ट्वेल्थ मैन बना दिया और ट्वेल्थ मैन अब कैप्टन बनकर सरकार चला रहा है।

The provision for education is not there. I would ask them to talk about women empowerment. The nation talks about it. मेरे लोक सभा क्षेत्र सांगली के जत तालुका के करजगी गांव में एक सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसका खून कर दिया गया। Have we not failed this girl as a society? Have you all not failed? Where is the provision for security? There is so much I want to talk about but I understand the time is limited.

Thank you.

श्री लुम्बा राम (जालौर) : मैं केन्द्रीय बजट 2025-26 पर अपने विचार रखने के लिए समय दिए जाने पर आपका आभार और धन्यवाद करता हूँ।

वित्त मंत्री महोदया द्वारा 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया है, बकि वर्ष 2012-13 में यह केवल 13 लाख करोड़ रुपए था। इस बजट के माध्यम से देश और दुनिया के समक्ष एक मजबूत, श्रेष्ठ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की विस्तृत रूप-रेखा को रखा गया है। भारत की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों में, मोदी सरकार के विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है।

इस बजट में देश के युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति समेत देश के गरीब, पिछड़े और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं।

इस शरण के लिए मैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी का हार्दिक आभार व धन्यवाद देता हूँ। कृषि क्षेत्र के लिए लाख 37 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कर देश के अन्नदाताओं को बड़े पैमाने पर सशक्त बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया गया है, साथ ही दलहन के क्षेत्र, मिशन की शुरुआत एक सराहनीय कदम है। किसान क्रेडिट की लिमिट 3 लाख से 5 लाख कर दिया है यह किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में मजबूत कदम है।

इनकम टैक्स में 12 लाख की छुट देकर हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग का पुरा ध्यान रखा है इस बजट में। सूक्ष्म एवं वात के लिए ऋण सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया है, जिससे अगले 5 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा

स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपये तक, आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 2 क्षेत्रों में पर के लिए गारंटी शुल्क को घटाकर 1 प्रतिशत किया गया, जोकि देश के युवाओं को इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। रोगियों, विशेषकर कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने 36 जीवनरक्षक औषधियों को मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) से पूर्ण छूट वाली औषधियों की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव किया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 4 लाख करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है, जोकि वर्ष 2013-44 में 37 हजार करोड़ी रुपए था। अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी, अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य है। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 1.1 लाख यूजी और पीजी मेडिकल शिक्षा सीटें जोड़ी हैं, जिसमें इस दौरान 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जो काम कांग्रेस सरकार पिछले 60 वर्षों में नहीं कर पाई थी, वो काम मोदी सरकार ने केवल 10 वर्षों के भीतर ही कर दिखाए। 2014 में देश में 16 IIT थे, जो अब 23 हो गई है, 13 IIM थे, जो अब 21 हो गए हैं, हमारी सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 2025-26 में रेल मंत्रालय के लिए 2 लाख 65 हजार करोड़ रुपय है, जिसका उपयोग रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण, अपग्रेडेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेल लाइनों के दोहरीकरण और अन्य बुनियादी ढांचे के कार्यों में किया जाएगा। असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10 हजार 440 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। वर्ष 2013-14 में रेलवे का बजटीय आवंटन केवल 63 हजार करोड़ रुपए था। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए 74 हजार करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है, इसमें करीब 90 प्रतिशत राशि जल जीवन मिशन के लिए खर्च की जाएगी और इस योजना का वर्ष 2028 तक विस्तार किया जाएगा। जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और रखरखाव के लिए कुल परिव्यय में भी वृद्धि की गई है।

अगले 10 वर्ष में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लाने-ले-जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा भी की गई है। पर्वतीय, आकांक्षी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी निर्माण किया जाएगा। 2014 तक भारत में 74 हवाई अड्डे थे, अब 160 हवाई अड्डे हैं। एयरपोर्ट की संख्या में वृद्धि से रोजगार के नए अवसर भी खुले हैं। देश को खतरों से सुरक्षित रखने और कक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इस बजट हेतु 6 लाख 81 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी की गई है। 2013-14 में देश का रक्षा बजट 2 लाख 3 हजार करोड़ रुपये था, जिसमें पिछले 10 दौरान ऐतिहासिक वृद्धि देखने को मिली है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय का बजटीय आवंटन 2013-14 में लगभग 31,130 करोड़ रुपये था, जोकि वर्ष 2025-26 में 2 लाख 87 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का हो गया है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई मार्च 2014 में 91,287 किलोमीटर से 1.6 गुना बढ़कर वर्तमान में 1,46,145 किलोमीटर हो गई है। अप्रैल 2014 से बजटीय आवंटन में वृद्धि के साथ, सड़कों की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। 4 लेन और उससे अधिक के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई 2014 में 18,371 किलोमीटर से 2.5 गुना से अधिक बढ़कर 46,720 किलोमीटर हो गई है।

माननीया वित्त मंत्री महोदया द्वारा पेश किया गया यह बजट नए भारत की नई उम्मीदों को साकार करने वाला है। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही देश का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा। कांग्रेस के शासन काल में हम दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, जबकि माननीय प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में केवल पिछले 10 वर्षों के दौरान दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं और जल्द ही दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम होगा।

मेरे संसदीय क्षेत्र की प्रमुख मांग है जिसे इस बजट वर्ष में पुरा करने की आवश्यकता है

नीति आयोग के आकांक्षी जिला के सूची में शामिल सिरोही जिला केन्द्र को बागरा से रूपगंज लगभग 72 कि०मी० नई रेलवे मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता है।

- सिरोही आकांक्षी जिला को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत हिंडन हवाई अड्डा से मानपुर हवाई अड्डा तक वायु सेवा प्रारंभ करने की आवश्यकता है।

आकांक्षी जिला सिरोही में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत गुलाबगंज से माउट आबू के लिए 23 कि०मी० लम्बी ऐलिवेटेड सड़क का निर्माण करवाने की आवश्यकता है।

सूखा प्रभावित क्षेत्र रा सिरोही को माही एवं कडाणा बांध का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

मैं, वित्त मंत्री महोदया को इस ऐतिहासिक, साहसिक और दूरगामी लक्ष्यों को साधने वाले बजट के लिए धन्यवाद देता हूँ।

SHRI KOTA SRINIVASA POOJARY (UDUPI CHIKMAGALUR): I would like to express my views on the Union Budget 2025-26. Many Indians look at annual budgets only for relief in direct and indirect tax regimes that benefits the middle class. Finance Minister Nirmala Sitharaman did not disappoint them this

time. For years, the FM endured criticism for failing to increase the income tax exemption rate substantially. This year, she announced that incomes up to Rs. 12 lakh would be exempt from income tax as against Rs. 7 lakh until now, answering the call of the country's middle class. This development has been widely applauded.

In the short term, the decision is clearly a sound one, especially because more money in the hands of the middle class means more spending. This will catalyse more production and create jobs. Last year, the consumer products market saw a decline in profits. Consumption items like oils and pulses as well as daily-use products like soaps and shampoos saw a decline in sales. The reasons for this need detailed study. But, on the face of it, it appears that one reason could be the exponential growth of the gig economy. Ordering food through delivery aggregators like Swiggy and Zomato rather than cooking at home or visiting one of the mushrooming beauty parlours rather than spending on shampoos and other beauty products have become rampant in the middle class.

Globally, the manufacturing industry is a major job provider. But the sector remained an Achilles' heel for India. Thanks to the efforts of the Narendra Modi government, growth in the sector has picked up in recent years. According to the Annual Survey of Industries (ASI) data, the sector experienced 7.5 per cent growth in FY 2023, taking the number of employed in it to 18.5 million. Any slowdown in the sector would create a challenge to the country's ever-growing employable population. India is a country with a massive population of the young. The millions of young people entering the workforce put enormous stress on governments on the job front. As shortages in the traditional jobs sector continue to plague the economy, a large number of youths are in the newly emerging gig sector. Estimates suggest that the gig sector is the fastest growing in India, providing employment to around 10 million people today. ASSOCHAM analysts predict that this figure is growing at a compounded rate of 17 per cent, while Niti Aayog is projecting that it will cross 23.5 million by 2029-30.

There is no clear definition of gig work. It is broadly understood as a work arrangement that is non-permanent, outside the traditional definition of employer and employee. The FM seems to have followed the traditional logic that increased tax exemption rates will place excess money in the hands of India's primary consuming class - the middle class and that will increase domestic consumption. More spending means more tax revenue, more manufacturing and more jobs. But this time, the minister has paid

attention to the gig sector too. There has been a long-standing demand from labour organisations for insurance cover for gig workers. Heeding those, Sitharaman has announced several social security measures like coverage under the PM Jan Arogya Yojana, aiming to provide health protection to over 10 million gig workers. She may have to keep in mind, though, that leading companies in the gig sector already have certain welfare measures in place for their workers. At a time when digitisation and AI threaten to take away jobs, securing capital inflows into the manufacturing sector remains India's biggest challenge. In the last few years, the government has used the infrastructure spending route to boost employment, which continued in this year's budget. It may be a temporary reprieve, but the real answer is to catalyse a greater inflow of domestic and foreign capital into industries with greater employment potential. So far, only the defence manufacturing industry has shown promising growth. Now, the government wants to encourage other labour-intensive sectors like shipbuilding. Although India depends on oceans for almost 95 per cent of its exports and imports, its share in the global shipping industry remains minuscule. By granting industry status to shipbuilding, the FM has opened doors for potential growth in the sector.

The most important reform, however, is for regulatory institutions. In a successful economy, regulatory institutions play the role of facilitators. Instead, in India, overzealous regulators made the country less attractive to foreign capital. Recognizing this bottleneck, the FM has cautioned that the regulators "must keep up with technological innovations and global policy developments". She promised "a light touch regulatory framework" based on "principles and trust", and announced the constitution of a high-level committee with the objective of building a "modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century".

Another far-reaching announcement was of the Jan Vishwas Bill 2.0. In 2023, through a similar bill, the government decriminalised more than 180 legal provisions in various departments under different ministries. With a view to further enhancing the ease of doing business, the minister announced the decriminalisation of another 100 provisions in various laws.

With these words, I conclude.

DR. K. SUDHAKAR (CHIKKBALLAPUR):

I would like to place my views on Budget 2025-26.

First of all, I would like to congratulate our Hon'ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman Ji for presenting a comprehensive and pragmatic Union Budget 2025-26 that focuses on sustaining economic growth through strategic investments in infrastructure, innovation, and human capital while ensuring fiscal consolidation and enhancing welfare for all citizens.

The NDA Government led by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji is into its 12th year. The Government has won three back-to-back mandates.

But still, the Government has its ears to the ground and finger on the pulse of the common man.

In a big relief to salaried middle-class people, the budget has announced that annual income of up to Rs 12 lakh will be exempt from I-T under the new income tax regime.

This decision shows how sensitive and responsive the Government is to the needs and aspirations of the common man.

No government in the history of independent India has done as much as PM Modi Govt. has done for the welfare and empowerment of poor, women, youth and farmers of this country.

It is unfortunate that it sounds boring to the opposition leaders when Hon'ble President read out the transformative effects of the Government's welfare schemes.

It may sound like a laundry list for the opposition leaders, but those schemes have changed the lives of crores of people across the country

Be it building toilets under Swachh Bharat, be it providing 5kg food grains under Garib Kalyan Yojana, be it providing LPG gas connection under Ujwala, be it providing 5 lakh health insurance under Ayushman Bharat yojana, be it building a house under PM Awas Yojana, be it providing tap water connection to every house Jal Jeevan Mission all these schemes which sound like a boring laundry list for opposition leaders have literally changed the lives of crores of people across the country.

This boring laundry list has pulled 25 crore people out of the poverty.

The opposition leader spoke about Make in India,

I must say the opposition leaders have come a long way from ridiculing the logo of Make in India to finally acknowledging the need for Make in India and the efforts of the government.

Make in India, which was launched on September 25, 2014, aims at making the country a hub for global manufacturing.

The government has undertaken various initiatives to make India an attractive destination for foreign investment and has taken several steps to promote ease of doing business.

There is no magic wand to increase manufacturing growth in any country.

Infact we lost the manufacturing bus long ago due to the policies of successive Congress Governments.

I will come to what Modi Govt has achieved in Make in India a bit later.

First let us understand the root cause of this problem.

The Congress party takes credit for the 1991 economic reforms for opening up the Indian economy.

But who closed the Indian economy in the first place? Will the Congress party also take the blame for closing the economy for the first four decades after independence and giving way for license raj which ruined the Indian economy?

As part of 1991 economic reforms, the government reduced import duties on all IT hardware purportedly to facilitate software promotion and growth on a globally competitive basis using imported hardware.

However, by 1994 our fledgling civilian IT hardware industry folded up.

During those days, IT hardware far more technologically sophisticated than the commercial hardware being imported by our software companies was being manufactured by Indian defence, atomic energy and space agencies and even exported to other developing countries such as Brazil, Malaysia, and Indonesia.

But, the then government failed to take note of this.

The 1991 reforms also dealt a body blow to the indigenous optic fibre telecommunication systems industry, a project begun by the Department of Electronics (DoE) in 1986 with the setting up of the public sector utility, Optel.

This was mainly because of the reduction in import duty on fibre from 40% to 10%. With this, large quantities of optic fibre began to be imported. This move affected the domestic industries very badly.

In 1990-91, there were at least a dozen electronics corporations producing a range of high-tech radio communication equipment, industrial electronics and control and instrumentation equipment worth annually around Rs.6,000 crore.

However, the reduction in customs duties from 60% to 30% overall, which led to a glut of imports, forced many of these corporations to halt production and become import agents, a phenomenon repeated in the key solar photovoltaic industry.

Reforms also led to large-scale import of cell-phone handsets that could have been easily produced here had a policy of phased manufacture been adopted. As a result, the entire market for such handsets was met by unnecessary imports from Day One in 2005-06. In 2013-14 cell-phone imports totalled Rs.35,000 crore.

Also, by 2000, foreign brands grabbed 80% of the television sets market, from a situation where 10 local companies catered almost fully to the demand. Six of the 10 indigenous television makers have folded up, with a ripple effect on the electronic components sector.

This industry was led by Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL). Up until 1998-1999 this industry was doing very well.

However, from the next year onwards, four Chinese power plant equipment manufacturers began to seriously erode BHEL's market.

This erosion was despite the quality and technical reliability of the Chinese equipment being considerably inferior to BHEL's products.

Besides, the United States, home to General Electric and Westinghouse, had already imposed penal anti-dumping duties on Chinese power plant equipment. Yet, the Indian government merely watched as BHEL lost 30 per cent market share by 2014.

Despite few positive gains, the reforms have largely led to de-industrialization.

Products that we were manufacturing in the 1990s are being imported in 1995.

The negative impact this de-industrialization has had on employment and on our economy is gigantic.

Now let me come to what Make in India has achieved.

Manufacturing sector's growth cannot happen in isolation.

For the manufacturing industry to flourish, we need mainly four things:

1. Skilled workforce
2. World class infrastructure
3. Ease of doing business
4. Supportive policies

Initiatives like Skill India, PM Gati Shakti, National Logistics Mission, reforms like GST, UPI, policies like Startup India, PLI schemes have all played in creating a conducive atmosphere for manufacturing.

India made remarkable progress in improving its business environment, climbing from 142nd in 2014 to 63rd in the World Bank's Doing Business Report (DBR) 2020, published in October 2019 before its discontinuation.

This 79-rank jump over five years reflects the government's sustained efforts to simplify regulations, reduce bureaucratic hurdles, and create a more business-friendly environment, significantly boosting

investor confidence and supporting the objectives of the Make in India initiative.

The success of the Make in India initiative has been significantly bolstered by record-breaking Foreign Direct Investment (FDI) inflows, driven by the simplification of FDI rules and improvements in ease of doing business.

India now ranks among the top 100 nations in the Ease of Doing Business (EoDB) index.

FDI inflows have steadily risen, starting from \$45.14 billion in 2014-15 to a record \$84.83 billion in 2021-22.

Between April 2014 and March 2024, India attracted \$667.41 billion in FDI, representing nearly 67% of the total FDI received over the last 24 years.

In FY 2023-24, total FDI inflows amounted to \$70.95 billion, with equity inflows reaching \$44.42 billion, underscoring India's growing appeal as a global investment destination.

While we all have a lot to achieve in Make in India, we have come a long way.

Powered by indigenously produced vaccines, India not only achieved COVID-19 vaccination coverage in record time but also became a major exporter of much-needed life-saving vaccines to many developing and underdeveloped countries across the world. India supplies nearly 60% of the world's vaccines, meaning every second vaccine globally is proudly made in India.

Vande Bharat Trains, India's first indigenous semi-high-speed trains, are a shining example of the success of the 'Make in India' initiative.

Featuring state-of-the-art coaches, these trains offer passengers a modern and enhanced travel experience.

As of now, more than 100 Vande Bharat train services are operational across Indian Railways, connecting states with a Broad-Gauge electrified network and showcasing India's growing capability in advanced rail technology.

India is achieving remarkable milestones in defence production, exemplified by the launch of INS Vikrant, the country's first domestically made aircraft carrier,

This initiative is part of India's broader goal to reduce imports and become self-reliant (Atmanirbhar) in the defence sector,

In 2023-24, defence production has soared to ₹1.27 lakh crore, with exports reaching over 90 countries, showcasing India's growing strength and capability in this critical area.

India's electronics sector has experienced rapid growth, reaching USD 155 billion in FY23

Production nearly doubled from USD 48 billion in FY17 to USD 100 billion in FY23, driven primarily by mobile phones, which, now constitute 43% of total electronics production.

India is the second-largest mobile manufacturer in the world and has significantly reduced its reliance on smartphone imports, now manufacturing 99% domestically.

India recorded merchandise exports worth \$437.06 billion. FY 2023-24, reflecting the country's growing role in global trade.

Indian bicycles have gained international acclaim, with exports, to the UK, Germany, and the Netherlands soaring. This surge highlights the global recognition of Indian engineering and design.

'Made in Bihar' boots are now part of the Russian Army's equipment, marking a significant milestone for Indian products in the global defence market and showcasing the country's high manufacturing standards.

Kashmir willow bats have become a global favorite. Their popularity underscores India's exceptional craftsmanship and influence in international cricket.

Indian dairy brands like Nandini and Amul have expanded their presence by launching its dairy products in the countries like US

The textile industry has created a staggering 14.5 crore jobs across the country, significantly contributing to India's employment landscape.

India produces an impressive 400 million toys annually, with 10 new toys being created every second.

Opposition leader said that PM Modi bowed to constitution after the 2024 Lok Sabha results and opposition parties are the reason for this.

Let me remind them.

In 2010, as the then Gujarat CM, Shri ji had organised 'Samvidhan Gaurav Yatra' to mark 60 years of our Constitution, during which a replica of the Constitution was placed on an elephant for procession and Modiji too walked in that procession.

In 2015, PM Modiji declared that every year 26th November will be observed as the Constitution Day to express gratitude to the makers of our Constitution and to reiterate our commitment to building the India of their dreams.

PM Modi Ji respectfully touched the Constitution of India with his forehead as he arrived for the NDA Parliamentary Party meeting at Central Hall of the Samvidhan Sadan (Old Parliament) after the 2024 Lok Sabha election results.

PM Modi ji has always been sincerely committed to upholding the principles of our constitution and it is clearly evident in his actions.

SHRI ESWARASAMY K. (POLLACHI): I would like to express my views on the Union Budget 2025-26, a budget that was expected to provide relief, growth, and progress for all. However, what we have received instead is yet another document filled with contradictions, misplaced priorities, and step-motherly treatment towards certain states, particularly Tamil Nadu. The people of India were looking forward to a budget that would address economic inequality, job creation, inflation control, and support for states that contribute significantly to the national exchequer. But, unfortunately, this budget does the exact opposite.

This budget, like its predecessors under the current regime, continues to neglect Tamil Nadu, a state that has consistently been a beacon of progress in India. While the Union Government showers favours upon some states, Tamil Nadu, despite its substantial contribution to the nation's economy, is met with apathy and discrimination.

The Economic Survey itself acknowledges Tamil Nadu's stellar performance in multiple sectors. Our state's Gross State Domestic Product (GSDP) has grown at an impressive rate, and our per capita income is 56% higher than the national average. Tamil Nadu is a leader in industrial output, a top performer in higher education, and a pioneer in welfare schemes. And yet, when it comes to financial devolution and budgetary support, the Union Government deliberately sidelines our state.

Let me draw the attention of this House to the glaring disparity in tax devolution. Tamil Nadu contributes nearly 9% to the nation's GDP, yet receives a meagre 4.08% of tax devolution. Over the last three decades, Tamil Nadu has lost nearly Rs. 3.57 lakh crore due to this skewed devolution policy. Are we being punished for our economic success? Is this the 'cooperative federalism' that the Union Government preaches?

The bias is evident not only in tax devolution but also in centrally sponsored schemes. Take the Samagra Shiksha Abhiyan (SSA), a crucial initiative for education. Despite Tamil Nadu's stellar performance in literacy and education, the Centre has withheld more than Two Thousand (2,000) crores allocated to the state under SSA. This delay threatens the payment of salaries for over 30,000 teachers and the continuation of critical education programs. The reason? Our government's refusal to blindly implement the National Education Policy (NEP), which disregards our regional aspirations. Education is in the Concurrent List, and yet, the Centre behaves as if states have no say in shaping their educational policies.

The irony is that Tamil Nadu has consistently outperformed other states in educational achievements. Our Gross Enrollment Ratio (GER) stands at 47%, for exceeding the national average of 28.4%. Yet, we face funding disparities compared to states with lower educational performance. This is not just a failure of policy, it is a failure of justice. A massive failure by the Union validated by its own budget.

Let us talk about disaster relief. Tamil Nadu is one of the most disaster-prone states in the country, Cyclones Michaeng and Fengal caused severe devastation, leading to a financial burden of thousands of crores. Our government requested Six Thousand (6,000) crores from the National Disaster Response Fund (NDRF). The amount released? A paltry Nine Hundred (900) crores. Meanwhile, states

favoured by the ruling party receive generous allocations. Is disaster relief now a tool for political vendetta?

Let me turn to infrastructure. Tamil Nadu's demand for metro rail projects in Madurai and Coimbatore remains stuck in bureaucratic limbo. Despite submitting all necessary documents and approvals, the Centre refuses to allocate funds. Compare this to Maharashtra, where the Centre has sanctioned about Thrity Nine Thousand (39,000) crores for metro projects. Is Tamil Nadu not part of India? Are our people second-class citizens in the eyes of this government?

Tamil Nadu has been recognized as a leader in the footwear and leather industry, contributing 38% of India's total output in this sector and 47% of total leather exports, generating over two lakh jobs. The Tamil Nadu government has strategically developed industrial estates in rural areas, ensuring employment opportunities, particularly for women. Our state has also successfully integrated the industrial and service sectors, fostering high-value manufacturing and global competitiveness. Even the Economic Survey praises Tamil Nadu's approach to "servicification" of industrial output, ensuring that our manufacturing sector remains robust and competitive on a global scale. However, unfortunately, Tamil Nadu's industrial growth has been systematically undermined by the Union Government's discriminatory policies. Our MSME sector, the backbone of our economy, has been left to fend for itself. The Production-Linked Incentive (PLI) scheme, which claims to promote manufacturing, has disproportionately benefited states aligned with the ruling party. Tamil Nadu, with its robust manufacturing sector, has been largely ignored. Is this the Centre's version of 'Make in India'- one where Tamil Nadu is deliberately excluded? Furthermore, the announcement of an 'Investment Friendliness Index of States' raises concerns about yet another tool that the Union government may use to interfere in state affairs rather than empowering them.

The injustice extends to GST compensation. The abrupt end of GST compensation in 2022 has cost Tamil Nadu dearly. Our state has demanded an extension of GST compensation until 2026, given the revenue loss incurred. But the Centre remains unmoved. We are expected to contribute billions to the national exchequer but are denied our rightful share. This government treats Tamil Nadu like an ATM - always withdrawing, never depositing. This year's budget too, went eerily silent.

Even in the field of cultural preservation, Tamil Nadu faces step-motherly treatment. Our demand for central support to promote Tamil language and heritage is met with silence. The Centre generously funds Sanskrit promotion but ignores Tamil, a language older and richer in literature. The discriminatory attitude towards our language and heritage is yet another insult to our identity. Tamil Nadu has always stood for progressive policies and inclusive development. We have pioneered welfare schemes, such as the Illam Thedi Kalvi initiative, recognized in the Economic Survey for its role in bridging the post-pandemic learning gap. This scheme, along with the Pudhumai Penn scheme, which provides financial support to girls pursuing higher education, and the Naan Mudhalvan program, which enhances employability through skill development, are all testament to our state's dedication to inclusive education. Tamil Nadu has been a leader in integrating Children with Special Needs (CwSN) into mainstream education. The initiative includes assistive devices, accessible infrastructure, teacher training, and personalized learning approaches to ensure inclusivity. The state has developed barrier-free school environments, making education more accessible to children with disabilities. The Tamil Mudhalvan scheme and initiatives for children with special needs further strengthen our commitment to ensuring education for all, yet the Centre continues to undermine our efforts through funding delays and discrimination.

The Union Budget's neglect of Tamil Nadu's demands is not just a failure of policy; it's a failure of leadership. Tamil Nadu, a state that has consistently contributed to the nation's growth, deserves better. The Union Government must recognize our state's contributions and address our demands with the urgency they deserve. The numbers do not lie. The discrimination is not accidental - it is deliberate, political, and vindictive. But let me make it clear: Tamil Nadu will not be silenced. We will continue to demand our rightful share, our due respect, and our fair treatment in this Union. The people of Tamil Nadu are watching, and history will remember the injustice meted out by this government.

On the national front, the contradictions, empty promises, and misplaced priorities of this Union Budget expose the Union Government's neglect. The government calls this a blueprint for 'Viksit Bharat', yet every page of this document reeks of betrayal, neglect, and an utter disregard for the real concerns of the people. This is not a budget for growth-it is a budget for illusion, built on half-truths and diversionary tactics to mask systemic failures.

The Finance Minister speaks of fiscal prudence, but what does that mean when social sector spending is slashed, welfare schemes are underfunded, and states are continuously deprived of their rightful resources? The Centre boasts of 'record capital expenditure' but what good is infrastructure if the people who build it are left hungry and jobless? The fiscal deficit may be projected at 4.4% of GDP, but the real deficit is in credibility, governance, and trust. Meanwhile, transfers to states continue to lag behind, impacting their ability to execute essential development programs.

Let us talk about employment. The government claims that job creation is robust, yet this budget quietly slashes allocations for MGNREGA, the very lifeline for crores of unemployed rural workers. The Economic Survey boasts of an expanding economy, but where are the jobs? The person-days generated under MGNREGA have fallen sharply from 389 crore in 2020-21 to just 220 crore in 2024-25. Reports highlight that real wages under MGNREGA have failed to keep up with inflation, making survival even more difficult for millions dependent on it. Youth across India are battling record-high unemployment while this government continues its empty rhetoric, offering no real solutions, no new employment guarantees, and no safety net for those losing their livelihoods to automation and corporate greed. The service sector, a key driver of employment, remains ignored, with no meaningful policy interventions to address skill gaps and rising underemployment.

The agriculture sector, the backbone of our economy, has been once again sidelined in this budget. The government's emphasis on high-yielding seeds under the 'Atmanirbhar Oilseeds Abhiyan' raises severe concerns over crop diversity and sustainability. The push for monoculture threatens India's rich agricultural biodiversity and could make our farmers more vulnerable to climate change. While lip service is paid to farmers' welfare, actual budgetary support remains insufficient. Where is the long-term vision for sustainable agriculture, farmer incomes, and resilience against erratic weather patterns? Instead of strengthening procurement mechanisms and ensuring MSP guarantees, the government continues to prioritize corporate-friendly policies that leave small and marginal farmers at the mercy of market fluctuations. While this budget claims to empower farmers, it has failed to provide direct income support, increased procurement prices, or genuine relief from agrarian distress.

Ease of doing business remains a hollow promise. Businesses, especially MSMEs, are drowning in over-regulation, bureaucratic red tape, and a tax regime that favors big corporations over small

entrepreneurs. The government claims India is climbing the 'Ease of Doing Business' rankings, but on the ground, corruption, high compliance costs, and delayed approvals strangle small businesses. The MSME credit guarantee scheme has been reduced from Fourteen Thousand (Rs. 14,000) crore in 2023-24 to just Nine Thousand (Rs. 9,000) crore in 2025-26. Where is the policy support for real trade expansion? Our trade deficit is widening, our exports are stagnating, and instead of fixing structural inefficiencies, this government hides behind misleading statistics.

Inflation is another burden that the common man carries while the government sits idle. Prices of essential commodities continue to skyrocket, yet this budget provides no relief to the middle class and poor households struggling to put food on the table. Instead of tackling rising costs, this government hides behind manipulated CPI numbers, failing to acknowledge the distress of ordinary citizens. The Economic Survey notes that food inflation, particularly in vegetables and pulses, remains persistently high, yet the government refuses to take corrective measures.

Education, the foundation of our future, has been reduced to a casualty of budget cuts and centralization. The National Education Policy (NEP) promised a revolution, yet school funding remains stagnant. In the Union Budget 2025-26, the government allocated ₹1.28 lakh crore to the education sector; however, this increase has not translated into equitable support across all states. For instance, states, having opted out of implementing the NEP, stands to lose substantial central funding for vital school education schemes. Further, universities are being run not by scholars, but by political appointees who serve ideological interests rather than academic excellence. The Vice-Chancellor appointments across central universities reflect this dangerous trend of eroding autonomy in higher education.

Let me tell you the story of an ASHA worker. For years, she has been the backbone of her community's healthcare, delivering essential services to mothers and children, conducting immunization drives, and battling malnutrition. Yet, despite her tireless work, she is paid a pittance, often not even receiving minimum wages. Thousands like her have been protesting for fair compensation, but this budget ignores their plight. Instead of recognizing ASHA workers as formal employees and ensuring dignified wages, the government continues to exploit their labor in the name of 'volunteerism?'. Their struggle for justice is a stark reminder of the government's apathy towards the very people who hold our healthcare system together.

Additionally, healthcare remains a broken promise. The Ayushman Bharat scheme is paraded as a success, yet hospitals are underfunded, rural health centres lack doctors, and public hospitals remain overwhelmed. AIIIMS projects face delays and underfunding, while the government's commitment to 'universal healthcare' remains an empty slogan. Despite allocating Ninety-eight thousand three hundred eleven (Rs. 98,311) crore in the Union Budget 2025-26, experts criticize it as a short-term fix rather than a long-term solution. The budget fails to address key issues such as the shortage of healthcare professionals and safety of existing ones, lack of infrastructure, and insufficient investment in public healthcare. Rural areas continue to suffer, forcing millions to rely on an overstretched system.

The absence of tax incentives, GST rationalization on medical devices, and cuts in customs duties on essential equipment make the budget inadequate. Public health spending remains below 4% of GDP-far lower than other emerging economies-while nearly 60% of healthcare costs are still borne out-of-pocket. Private hospitals and insurance-based models flourish, but the public sector remains neglected. If the government truly prioritizes healthcare, it must strengthen primary healthcare, incentivize private-public partnerships, invest in medical education, and ensure affordable healthcare for all. Without real reforms, 'universal healthcare' will remain a distant dream, and the nation will bear the cost of neglecting public health.

Federalism has been reduced to a mere afterthought in this budget. The Finance Commission's recommendations are manipulated to ensure states get less and the Centre tightens its grip over resources. The increasing reliance on cess and surcharges means that while the Centre hoards revenue, states are left scrambling to fund essential programs. The so-called 'cooperative federalism' is a myth, replaced by a model of control, coercion, and deliberate financial strangulation of states.

MSMEs, the backbone of our economy, have been betrayed once again. The government claims to support small businesses, yet credit access remains limited, loan approvals are delayed, and tax reliefs are minimal. The new credit guarantee scheme is a mere eyewash when industries are shutting down due to rising costs and lack of real policy support. The very businesses that sustain millions of livelihoods are being crushed under the weight of bureaucratic apathy and corporate favoritism.

Climate transition and the power sector remain neglected, with no concrete roadmap for ensuring sustainability while keeping energy costs affordable. Power sector reforms are conveniently left half-

baked, leaving consumers to pay for inefficiencies and corporate mismanagement. Instead of investing in green energy, this government continues to favor a model that benefits a few industrial conglomerates at the expense of the people. The renewable energy sector remains heavily dependent on imports, further exposing the failure of 'Aatmanirbhar Bharat'. The government's handling of climate change and the power sector is a stark reminder of its prioritization of corporate interests over the welfare of the people. The lack of concrete roadmap for sustainable energy and the continued reliance on outdated, polluting technologies are indicative of a government that is out of touch with the urgent need for action. The people of India deserve a government that is committed to equitable and sustainable development, not one that perpetuates the status quo.

The budget proposes additional borrowing capacity for states contingent upon power sector reforms. This is coercion disguised as incentive. Tamil Nadu has repeatedly urged the Centre to increase its share of power subsidies, yet the burden is now shifted entirely onto states. The Centre is using financial leverage to dictate policies that should be state prerogatives.

Transportation infrastructure is yet another sector where the government's claims fall flat. Railways are underfunded, metro projects delayed, and critical road networks ignored while the Centre prioritizes vanity projects for political mileage. Urban infrastructure remains a mess-housing remains unaffordable, homelessness is rising, and rental prices are soaring while the government turns a blind eye. According to a recent report, the supply of homes priced below Rs. 1 crore in the top nine cities has fallen by 36% in just two years, making homeownership an unattainable dream for many middle-class Indians. Meanwhile, large-scale redevelopment projects continue to displace low-income families, pushing them into homelessness rather than providing them with affordable alternatives. The crisis is even more pronounced for marginalized communities, including the LGBTQ+ population, who face systemic discrimination in housing, adding to an estimated annual economic loss of up to Rs. 1.7 trillion due to homophobia and exclusion. Where is the affordable housing that was promised?

Cybersecurity and cyber scams are on the rise, yet this budget offers no serious intervention. Citizens are losing their hard-earned money to financial frauds, and yet regulatory mechanisms remain weak, outdated, and ineffective. Digital India cannot thrive if trust in digital transactions is eroded due to inaction and lack of robust policies.

Social justice has been sidelined. Minority institutions face funding cuts, scholarships for marginalized communities are reduced, and welfare programs that uplift the oppressed are being diluted. Dalits, Adivasis, women, persons with disabilities, and the LGBTQ community find no mention in the government's economic vision. The government's indifference towards social welfare has once again been laid bare in this bulge. Social sector spending as a proportion of GDP remains stagnant despite rising inequalities and economic hardships. Programs targeting women, children, and marginalized communities have seen either negligible increases, or outright cuts. Allocations for schemes like the National Health Mission and Integrated Child Development Services have not kept pace with inflation, reducing their real impact. Further, the continued underfunding of critical social programs exacerbates systemic injustices, keeping the most vulnerable trapped in cycles of poverty and deprivation.

Further, the government has cut the allocation for pre-matric and post-matric scholarships for minority students by nearly 50%, directly impacting lakhs of underprivileged students who rely on these funds for their education. Despite grand promises, the budget fails to provide any substantive increase in funding for higher education institutions catering to marginalized groups, further entrenching social inequality. The Union Budget 2025 has enacted severe cuts to educational schemes that support minority and tribal students, exacerbating social inequality and undermining the principles of social justice. The National Fellowship and Scholarship for Higher Education of Scheduled Tribe (ST) students has seen its allocation plummet by 99.99%, from Rs. 240 crore in the Revised Estimates (RE) for 2024 to a mere Rs. 0.02 crore in the Budget Estimates (BE) for 2025. These drastic reductions directly impact lakhs of underprivileged students who rely on these funds to pursue higher education and improve their socio-economic status.

Further, the Pre-Matric Scholarship for Minorities has been slashed by 72.4%, from over Rs. 300 crore in Revised Estimates for 2024 to Rs. 90 crore in Budget Estimates in 2025. Other critical programs, such as the Maulana Azad National Fellowship for minority students and the Scheme of Interest Subsidy on Educational Loans for Overseas Studies, have experienced cuts of 4.9%, and 46.6%, respectively. These funding cuts not only betray the government's commitment to education and social justice but also systematically erode the rights of the underprivileged, instead of uplifting them. Moreover, the budget has once again ignored pressing issues like unemployment, inflation, and growing economic disparities. Reports indicate that unemployment remains a severe challenge, particularly among the youth and

marginalized communities, while inflation continues to push essential goods out of reach for many households. Despite tall claims, the government has failed to allocate sufficient funds to address these concerns, exacerbating existing inequalities and social distress. This budget is a 'brutal betrayal' of education and social justice, as it systematically erodes the rights of the underprivileged instead of uplifting them. The labour market remains in crisis, yet skill development remains an afterthought. Over-regulation continues to crush economic dynamism while the government obsesses over controlling every aspect of public life. The budget once again ignored real issues like unemployment, inflation, and growing economic disparities. Reports indicate that unemployment remains a severe challenge, particularly among the youth and marginalized communities, while inflation continues to push essential goods out of reach for many households. The Union government's plan to monetize assets worth Rs. 10 lakh crore under the new Asset Monetization Plan 2025-30 is nothing but a systematic selling all of national assets. Instead of strengthening public sector undertakings, the government continues to prioritize privatization, benefiting a few corporate giants while leaving common citizens vulnerable.

Artificial Intelligence is being pushed as the next frontier, but where is the roadmap for workers who will be displaced? Where is the policy framework, to ensure job security and skill development in an AI-driven economy? The budget speaks of innovation but does not invest in protecting the workforce from the disruptions AI will bring. Instead of preparing for the future, this government remains fixated on hollow rhetoric and unplanned technological adoption. When we compare India's budget with global practices, we see how far behind we are. Countries such as Germany and Canada allocate a significant portion of their budgets toward social security and skill development, India, on the other hand, continues to reduce spending on social welfare programs while increasing subsidies for large corporations. Countries worldwide are adopting inclusive, sustainable, and innovative budgeting to improve governance and public finance management. Brazil's participatory budgeting allows citizens to vote on municipal spending priorities, ensuring grassroots involvement. Similarly, New Zealand's Wellbeing Budget prioritizes social indicators like mental health and child welfare over traditional economic growth, Norway incorporates sustainability performance-based budgeting, linking government funding to measurable environmental outcomes. The Netherlands' outcome-based budgeting model ties funding to performance metrics, ensuring accountability. The OECD recommends that national budgets prioritize sustainable growth,

innovation, and equitable taxation. Yet, Union Government's focus remains on short-term election-driven pooling rather than long-term economic planning.

This budget is not just a document of misplaced priorities-it is a testament to the Union Government's blatant disregard for equity, justice, and the federal structure of this nation. Tamil Nadu, a pillar of India's economic and social progress, has been systematically sidelined, penalized for its efficiency, and deprived of its rightful share. The numbers do not lie: from skewed tax devolution to discriminatory funding for education, from withholding disaster relief to sabotaging industrial growth- this government has treated Tamil Nadu not as an equal partner but as an adversary. But let me make one thing abundantly clear: Tamil Nadu will not kneel. We will not be silenced by step-motherly treatment, nor will we accept economic discrimination as the new normal. We have built our progress despite the Centre's hostility, and we will continue to rise, defying every stock placed in our path.

Beyond Tamil Nadu, this budget is a betrayal of the nation. It prioritizes illusion over reality, cronyism over justice, and propaganda over governance. While the common citizen struggles with inflation, unemployment, and a crumbling welfare state, this government continues to peddle empty slogans. But history will remember-when the people asked for relief, this government gave them rhetoric. And in democracy, rhetoric alone cannot buy votes forever. Thank you.

***m21 श्रीमती भारती पारधी (बालाघाट) :**

मोदी जी के हाथ में राष्ट्र का विश्वास,
उनका बजट ला रहा है समृद्धि का आकाश ?

आज मुझे यह गर्व का अवसर मिला है कि मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट 2025-26 पर अपनी बात रख सकूँ। यह बजट सिर्फ संख्याओं और आँकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि यह हमारे देश के हर नागरिक की समृद्धि, उनकी खुशहाली और विकास की दिशा में एक ठोस कदम है। इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने देश की आर्थिक स्थिरता को और सशक्त बनाने का संकल्प लिया है।

सबसे पहले, मैं हमारे माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की सराहना करना चाहूँगी, जिन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेहनत और दूरदृष्टि ने इस बजट को आकार दिया है। वित्त मंत्री जी ने इस बजट में जो व्यापक और संरचनात्मक सुधार पेश किए हैं, वह देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए सक्षम हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" के मंत्र को अपनाते हुए अपने बजट को इस तरह से तैयार किया है कि इसका लाभ हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर नागरिक तक पहुंचे। हमारी सरकार ने हमेशा भारत को "विकसित भारत" की दिशा में अग्रसर करने का लक्ष्य रखा है, और यह बजट उस दिशा में एक मजबूत कदम है। प्रस्तुत बजट में सबसे महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र में सुधार है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा किसानों के कल्याण को अपनी प्राथमिकता दी है, और इस बजट में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। जैसे प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को चुना गया है, जिससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी और हमारे किसान अधिक समृद्ध होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे किसानों को और अधिक वित्तीय सहायता मिल सकेगी। इसके अलावा, दलहनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार ने छह वर्षीय मिशन शुरू किया है, जिससे जलवायु अनुकूल बीज और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाएंगे।

MSME क्षेत्र को भी विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा मध्यम, छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहन देने का कार्य किया है। इस बार सरकार ने ऋण गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है, जिससे इन उद्योगों के लिए ऋण तक पहुंच बढ़ सकेगी, जिससे वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। इन्फ्रास्ट्रक्चर में सरकार ने एक बड़ी पहल की है। प्रधानमंत्री मोदी जी की उड़ान योजना को संशोधित करते हुए 120 नए गंतव्यों को जोड़ा गया है, जिससे अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा मिल सकेगी। साथ ही समुद्री विकास निधि के तहत 25,000 करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया गया है, जो जहाज निर्माण, बंदरगाहों और रसद बुनियादी ढांचे के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करेगा।

अब अगर हम इस बजट का तुलनात्मक अध्ययन पिछले वर्ष के बजट से करें, तो हमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि यह बजट पहले से कहीं अधिक समावेशी और व्यापक दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। 2025-26 में कुल व्यय 50,65,345 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से 7.4% अधिक है। साथ ही, कुल प्राप्ति (उधारी को छोड़कर) 34,96,409 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से 11.1% अधिक है। इससे यह साफ है कि सरकार की कोशिश है कि प्राप्ति बढ़े और व्यय का संतुलन बना रहे, जिससे हम आर्थिक समृद्धि की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ सकें।

आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 2025-26 के लिए राजस्व घाटा जीडीपी का 1.5% और राजकोषीय घाटा 4.4% रखने का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले साल के मुकाबले कम है। यह दर्शाता है कि हमारी सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और आर्थिक विकास को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। राज्यों के लिए हस्तांतरण में 12.5% की वृद्धि की गई है, और कुल 25,59,764 करोड़ रुपये राज्यों को हस्तांतरित किए जाएंगे। यह कदम संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करता है और राज्यों को उनके विकास में सहारा देता है।

हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्यात संवर्द्धन के लिए एक नई नीति शुरू की है, जिससे भारत का वैश्विक व्यापार बढ़ सकेगा। निर्यात संवर्द्धन मिशन के तहत वाणिज्य मंत्रालय, MSME मंत्रालय और वित्त मंत्रालय एक साथ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा, Global Capability Centers के लिए नीतिगत प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे भारत को वैश्विक सेवा प्रदाता के

रूप में और अधिक सशक्त किया जा सकेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से यह बजट हमारे देश के प्रत्येक नागरिक की उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री जी का विश्वास है कि भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है और हमारे देश को पूरी दुनिया में एक अग्रणी शक्ति के रूप में स्थापित करना है। इस बजट में आर्थिक सुधारों, समावेशी विकास, और सामाजिक कल्याण की दिशा में उठाए गए कदम हमारे देश की उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इस बजट के जरिए देश के हर नागरिक के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को और भी मजबूत किया है। धन्यवाद।

श्री विनोद लखमशी चावड़ा (कच्छ) : मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीता रमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूँ।, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2025-26 का आम बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले सभी बजट की तरह ही आम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप है। हमारे देश का सौभाग्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी हाल में ही हमने देश के संविधान की 75 वी वर्षगांठ मनाई है और उससे कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये लोकतंत्र का अमृतकाल है ये बजट फिर से भारत वर्ष को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाला बजट है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के तीसरे कार्यकाल में भारत वर्ष आगामी पञ्चवर्षीय में, विकासशील भारत से विकसित भारत की ओर जाने वाली गाडी और भी सुपर फास्ट स्पीड से दौड़ने लगी है। वर्ष 2047 का जो विकसित भारत लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री की सरकार का विकास को देखते हुए लगता है कि वो पहले ही प्राप्त हो जाएगा।

यह बजट करोड़ों भारतीय नागरिकों की आशाओं और सपनों को ध्यान में रखकर बताया गया है और इसका उद्देश्य उन सपनों को सभी के लिए वास्तविकता बताता है। हमने युवाओं के लिए रोमांचक अवसर खोले हैं। जो वास्तव में विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा का दिल है। इस बजट को एक शक्तिशाली वढावा के रूप में सोचें जो हमें अधिक बचत करने, बुद्धिमानी से निवेश करने, बेहतर उपभोग करने और एक साथ बढ़ने में मदद करेगा।

सम्पूर्ण भारत के लिए, आधुनिकता की दिशा में, पिछले दस सालों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं पिछले वर्षों में जो फैसले लिए गए, नीतियां बनी, उसकी वजह से आज अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार होगा।

अमृतकाल के इस बजट से विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण हुआ है इसमें नौकरी पेशा नागरिकों को और वंचितों को वरीयता दी गई है ये बजट आज की आकांक्षा समाज - गांव गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में ये बजट, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए, अनेक नए अवसर पैदा करने वाला ऐतिहासिक बजट है। ये बजट देश में अधिक तेज विकास, तेजी से बढ़ता नया बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश के नए स्रोत, अधिक नौकरियों की संभावनाओं से भरा हुआ है।

यह बजट युवा, गरीब, महिला व किसान को सुदृढ़ करने वाला बजट है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इन चारों को विकसित भारत का स्तंभ माना है। यह वजट विकसित भारत की नींव को मजबूत करने वाला बजट है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने अंतरिम बजट 2024-25 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कि 2023-24 वर्ष के बजट आवंटन से 70 प्रतिशत अधिक था। और अब जनजातीय कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है उसके चलते बजट आबंटन 2014-15 में 4,497.96 करोड़ रुपये से 231.83 प्रतिशत बढ़कर 2025-26 में 14,925.81 करोड़ रुपये हो गया है।

भारत में 10.45 करोड़ से ज्यादा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोग रहते हैं। जो कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत है। यह एक समृद्ध और विविधतापूर्ण आदिवासी विरासत का दावा करता है। दूरदराज और अक्सर दुर्गम क्षेत्रों में फैले ये समुदाय लंबे समय से सरकार के विकास एजेंडे का केंद्र बिंदु रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्रीय बजट 2025-26 जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए बजटीय आबंटन में पर्याप्त वृद्धि के साथ इस प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जिससे देश भर में आदिवासी समुदायों का समय और सतत विकास सुनिश्चित होता है।

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी की कृपा से आप अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समय बजट आबंटन 2024-25 में 10,237.33 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 14,925.81 करोड़ रुपये हो गया है, जो 45.79 प्रतिशत अधिक है।

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) का विस्तार किया गया है और इसे पांच वर्षों में 80,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए बजट लागत में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, जो 2023-24 में 7,511.64 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 10,237.33 करोड़ रुपये हो गया है और अब 2025-26 में 14,925.81 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिलती है: 2014-15 में 4,497.96 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 7,411 करोड़ रुपये हो गई है और अब 2014-15 से 231.83 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो जनजातीय कल्याण पर सरकार के लगातार फोकस को दर्शाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव, श्री विभु नायर: 'बढ़ा हुआ बजट हमें पीएम-जनमन, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, ईएमआरएस और अन्य कार्यक्रमों जैसे परिवर्तनकारी कार्यक्रमों को लागू करने में सक्षम करेगा, जो पूरे भारत में जनजातीय समुदायों के लिए दीर्घकालिक, टिकाऊ प्रभाव पैदा करेंगे।'

केंद्रीय बजट 2025 आदिवासी विकास में एक बड़ा बदलाव है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तीकरण पर जोर दिया गया है। विभिन्न मंत्रालयों में लक्षित हस्तक्षेपों को एकीकृत करके, सरकार समावेशी विकास को बढ़ावा

दे रही है और एक ऐसे विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त कर रही है, जहां आदिवासी समुदाय न केवल लाभार्थी हैं, बल्कि राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदानकर्ता भी हैं।

यह बजट में देश के युवाओं नए जोश से भर देता है एक नई दिशा देने की बात करता है। युवाओं की इनकम बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद इस बजट में दिखती है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है। साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बन जाएगा और जिसकी बुनियाद आज युवा ही होंगे। अभी देश में 3 हजार नए आई.टी.आई खोले गए। इसका फायदा युवाओं को मिला है।

पिछले दशक से ही माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये सरकार युवाओं की आस पर खरी उतर रही है और इस बार हर बार से बेहतर बजट भारत युवाओं को मिला है जब वित्त मंत्री जी ने बजट का पिटारा खोला तो उन्होंने युवाओं और छात्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए। बजट में बड़े ऐलान करते हुए कहा कि सभी MSMEs के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया गया है। इससे उन्हें आगे बढ़ने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का आत्मविश्वास मिलेगा।

सरकार वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। पांच आईआईटी संस्थानों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने बताया कि बीते 10 वर्षों में आईआईटी संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 65 हजार से बढ़कर 1.35 लाख हो गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में बेहतर शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से एक कॉलेज स्थापित किया जाएगा। अगले साल मेडिकल कोलेजों और अस्पतालों में 10 हजार से ज्यादा अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले पांच वर्षों में 75 हजार सीटें जोड़ने का लक्ष्य है। अगले पांच वर्षों में पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के अनुसार, आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10 हजार फेलोशिप प्रदान की जाएंगी।

उभरते युवा उद्यमियों के वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए 'फंड ऑफ फंड्स' योजना के एक और दौर की घोषणा की। एलान इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार स्टार्टअप के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

सरकार ने बजट में युवाओं को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप्स के लिए ऋण सीमा को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किया गया है। साथ ही 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण गारंटी को घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पांच लाख रुपये की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। पहले वर्ष में ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। फंड ऑफ फंड्स का एलान किया है। सरकार ने फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की है, जिसके तहत सरकार स्टार्टअप्स के लिए 10 हजार करोड़ की मदद देगी इस बजट में उन्होंने साफ कर दिया कि महिलाओं की विरोध पर उनका पूरा फोकस है अपनी 'विकसित भारत' की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बजट के सभी विकास की योजनाओं को गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी को केंद्र में रखकर बनाया है। इस बार के बजट में वित्त मंत्री से लोगों की कई उम्मीदें थी और टैक्स में 12 लाख तक की छूट दे कर उन्होंने

कई लोगों को राहत दी है। टैक्स स्लैब की खुशखबरी के अलावा आइए आपको बताते हैं कि महिलाओं को इस बजट में क्या खास मिला है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इस बात का जिक्र किया कि यह उम्मीद करती है कि भारत की इकनोमी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ और लगभग 70% महिलाएं आर्थिक गतिविधियों से जुड़ें वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट में उन्होंने महिलाओं के लिए बड़ा एलान किया है। भाषण के दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दो नई योजनाओं की घोषणा की है। पहली योजना के तहत, अगले पांच सालों में 5 लाख SC/ST महिला एंटीप्रेन्योर को 5 साल की अवधि के लिए टर्म लोन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत अगले 5 सालों में इन उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन (ऋण) दिया जाएगा। यह योजना "Stand-Up India योजना के सफल अनुभवों से सीखी गई बातों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी।

वहीं दूसरी योजना में, पहली बार बिजनेस की दुनिया में कदम रखने वाली 5 लाख SC/ST महिलाओं को अगले पांच सालों में सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, उद्यमिता और प्रबंधकीय कौशल (मैनेजमेंट स्किल्स) को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य इन समूहों को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे सफल बनाने में मदद करना है महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाई गई है, जो पहली बार उद्यमी (एटरप्रेन्योर) बनने जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इन महिलाओं को वित्तीय सहायता, ट्रेनिंग मेंटरशिप प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सरकार पहली बार उद्यम शुरू करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये का लोन शुरू करेगी। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए खास स्कीम लाई गई है जिसमें एसएमई और बड़े उद्योगों के लिए एक विनिर्माण मिशन स्थापित करने सरकार श्रम-प्रधान क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुविधाजनक करने का कार्य भी किया जाएगा, लोन गारंटी कवर को दोगुना करके 20 करोड़ रुपये किया जाएगा तथा गारंटी शुल्क को घटाकर एक प्रतिशत किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के पोषण को मजबूत बनाने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और POSHAN 210 स्कीम की भी शुरुआत की जाना है।

गुजरात में रेलवे के लिए 17.155 करोड़ रुपए का प्रावधान रखने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का विशेष आभार प्रकट करता हूँ।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के साथ-साथ गुजरात का रेलवे नेटवर्क भी विकास और विस्तार के स्वर्णिम कालखंड का साक्षी बन रहा है और विकसित भारत बजट-2025 से इस विकास यात्रा को और अधिक गति मिलने वाली है।

गुजरात में रेलवे के लिए मात्र ₹589 करोड़ की राशि दी गई थी, वहीं मोदी सरकार ने वर्ष 2025-26 में इसे 29 गुना बढ़ाकर ₹17,155 करोड़ करने की ऐतिहासिक घोषणा की है। बीते एक दशक में गुजरात में रेलवे ट्रैक्स के इलेक्ट्रिफिकेशन में भी 22 गुना वृद्धि हुई है और अब गुजरात के 97% रेलवे ट्रैक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ₹799 करोड़ की लागत से स्टेशन पुनर्विकास

के कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे नेटवर्क के इस कायाकल्प से गुजरात में व्यापार, उद्योग, यातायात और रोजगार को और भी अधिक बढ़ावा मिलेगा।

आने वाले दिनों में ₹6,303 करोड़ की लागत से गुजरात के 87 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें अहमदाबाद, आणंद, अंकलेश्वर, जामनगर, जूनागढ़ जंक्शन, महेसाणा जंक्शन, नवसारी, पोरबंदर, राजकोट जंक्शन, वडोदरा और वापी प्रमुख हैं। इसके साथ-साथ ₹5,572 करोड़ की लागत से 7 प्रमुख स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य भी प्रगति पर है, जिनमें गांधीनगर राजधानी, साबरमती, सोमनाथ, उधना, सूरत, न्यू भुज और अहमदाबाद शामिल हैं।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना कृषि जिला विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि विकास का पहला इंजन होगा। प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा।

आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम की तर्ज पर कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाएं और ऋण की उपलब्धता से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। इस योजना में फसल विविधीकरण को अपनाया जाएगा, फसल कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाया जाएगा।

यह कार्यक्रम राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा, जिसमें कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।

कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के माध्यम से कृषि में अल्प रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित करते हुए 6 साल का दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करेगी। नैफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से इन दालों की खरीद करेंगे।

राज्यों के साथ साझेदारी में किसानों के लिए उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना एक अच्छा कदम है जो किसानों को लाभ पहुंचाएगा। यह बोर्ड किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करने में मदद करेगा, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकेंगे।

मैं बजट 2025 की सराहना करता हूं और इसे संसद में पारित करने का समर्थन करता हूं। यह बजट हमारी सरकार की आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, और मध्यम वर्ग के लिए राहत प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है धन्यवाद। जय हिन्द जय भारत।

DR. C. N. MANJUNATH (BANGALORE RURAL): The Hon'ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman ji has presented an inspiring and impactful budget for the year 2025-2026. I congratulate Hon'ble Prime Minister and Finance Minister for presenting a budget of Rs 50,65,345 crore for the current financial year. It is an important step in the direction of making India a 'developed nation. Economic strength, tax reforms, agricultural development, promoting start-ups, job creation, and technological self-reliance are the key pillars of this budget. In the true sense this budget is a transformative and growth-oriented Budget.

So, I express my wholehearted support to the union budget as the Honorable Finance Minister presented the budget keeping in her mind the welfare of the poor, middle class, youth, farmers, and food producers.

The Union budget infused a strong self-confidence in the people of the country. The middle class and salaried class are immensely happy with the relaxation in the income limit up to Rs. 12 lakh. An increase in TDS on interest from the present Rs. 50,000 to Rs 1 lakh for senior citizens, as well as an increase in the TDS exemption threshold on rental income from the present Rs. 2.40 lakh to Rs 6 lakh will benefit the common man. The budget also gives us a Mantra "Sabka Saath, Sabka Vikas". It is a collective responsibility of all of us to join hands to uphold the principle of "Sabka Saath, Sabka Vikas. It will certainly help us to build a developed India.

The hon'ble Finance Minister has highlighted the achievements of our NDA government, and also outlined the future direction for the country and also the global expectations from our nation. With the aim of making the country developed and ensuring widespread welfare, the government has made generous allocations for all schemes related to every sector. Housing for all, water for all, education for all, healthcare for all, ration for all, and electricity for all are unprecedented.

The first announcement in this budget is the Dhan-Dhanya Krishi Yojana for the betterment of the lives of farmers. 100 districts with low crop sowing have been selected as aspirational districts, which has brought a new light into the lives of 1.7 crore farmers. Special focus has been given to pulses like tur, urad, and masoor. The plan has considered vegetables, fruits, millets, and their processing.

The income limit is set at Rs. 12 lakh which will lead to 80 per cent spending i.e. Rs. 80,000 crore in the market. The Kisan Credit Cards offer short-term loans to 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. For micro enterprises, customized Credit Cards with a Rs. 5 lakh limit are available via the Udyam portal. This budget indicates that 75,000 MBBS seats will be increased over the next five years.

India aims to end its urea imports by 2025, which is highly desirable as it is one of the largest importers of urea.

The Budget places a strong emphasis on empowering marginalized and vulnerable communities, particularly focusing on women, children, and Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Term loans of up to Rs. 2 crore will be provided over the next five years for building on the successful framework of the Stand-Up India scheme. The Budget for the Department of Social Justice for the financial year 2025 has seen a remarkable increase of 35.76 per cent compared to the revised estimates. The Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 programme which provides nutritional support to more than eight crore children, one crore pregnant women and lactating mothers and about 20 lakh adolescent girls all over the country. The allocation for Samagra Shiksha is set to rise from Rs. 37,499 crore in 2024-25 to 41,249 crore in 2025-26. Similarly, PM-SHRI's budget increases from Rs. 6,050 crore to Rs. 7,500 crore facilitating better infrastructure, resources, and quality education, setting a strong foundation for the future of our children and enabling them to contribute meaningfully to the nation's growth. The National Rural Livelihood Mission Budget will rise from Rs. 15,047 crore to Rs. 19,005 crore. The Viksit Bharat Budget is a remarkable testament to the perfect harmony between wealth creation and welfare, paving the way for inclusive and sustainable growth.

I would like to draw the kind attention of the hon'ble finance minister for some of the major demands of my constituency that there is a need for allocation of adequate funds for the prevention of elephant menace in the villages adjacent to the forests. Hundreds of people have lost the precious lives due to man-animal conflict. Standing crops worth thousands of crores rupees are destroyed by the wild animals. There is an urgent need to tackle the problems with adequate funds and infrastructure.

Another long pending issues is that Hejjala-Chamarajanagar railway line has been pending for more than three decades. It will be a lifeline for the people of Ramanagara, Kanakapura Malavalli Kollegala talukas. So this needs to be taken up without further delay. And there is also a need for

construction of second Airport in Karnataka near Bangalore as the BIAL has reached the saturation level. In order to ease the congestion of the existing airport the Union government should come forward to construct the 2nd Airport in Bangalore, which is one of the fastest growing city in the world.

I am one of the senior most Cardiologist having an experience of 35 years in the medical field and also worked for 18 years as Director of India's largest public heart Institute in Bengaluru. Based on my vast experience gained so far in the field of medical sciences, I thought of bringing some of my following views to your benign self for due consideration as you deem fit.

(1) Management of Heart Attack and Brain Stroke at the door steps of Taluk Hospitals - Heart Attack and Brain Stroke management to be rolled out as National Scheme under Ayushman Bharat as Hub-and-spoke model. Annually, 30 lakhs people are succumbing to heart attack and related issues in India. Unfortunately, 35% heart attack occur below 45 years of age, young and middle-aged Indians are vulnerable to this disease. Unquestionably this is number one killer accounting for 28-30% deaths both in urban and rural sector. Treatment has to be given in Golden hours preferably with less than six hours to save maximum number of patients and to prevent deaths. Treatment has to be taken to doorsteps of Taluk hospitals on Spoke and Hub model. Otherwise, time delay will result in more deaths.

SPOKE (Taluk Hospitals): Taluk hospitals where initial treatment has to be given in the form of clot dissolving Tenecteplase just one minute injection which cost above Rs.18,000/-, this treatment will stabilize 90% of patients. After few hours of stabilization, he / she shall be shifted to nearest city where angioplasty and stent procedure can be performed. Presently, the cost of Tenecteplase medicine (Thrombolysis) is not covered under Ayushman Bharat scheme for BPL patients. Present death rate in rural hospitals from heart attack is 20-25%, Tier-2 city-15%, & Tier-1 city-5-8%. This Hub and Spoke strategy shall be coordinated by regional agencies in their respective States. These agencies provide training, coordination between Spoke and Hub hospitals analyses the data and provide basic management kits, such specialized agencies can be hired.

HUB (City Hospitals): Super Specialty / Multi Specialty Hospitals located in nearby cities empaneled under 'Ayushman Bharat scheme will perform Angioplasty and stent procedure for such patients referred from Spoke hospital who have already received Thrombolytic treatment (Tenecteplase) there. Angioplasty and Stent procedure have already covered under Ayushman Bharat Scheme for BPL

patients. This HUB-SPOKE model of treating heart attack is implemented partially in 45 taluk hospitals in Karnataka and in few hospitals in Goa, Odisha and Telangana. After implementation of this model, more lives have been saved, death rate is in single digit. If this Hub and Spoke model is rolled out by Hon'ble Prime Minister under a suitable nomenclature through Ayushman Bharat to the entire country, we can save lakhs of patients, so that it will sensitize the stake holders and create awareness among the people and becomes popular. Ultimately, we can save lakhs of people. There will be no significant financial implications, since procedure cost is already covered. However, the medicine cost (Tenecteplase) to be covered. It is better to implement the Hub and Spoke model for management of Heart Attack and Brain Stroke.

(2) Overcoming the manpower issues in Rural Hospitals: - Under National Health Mission (NHM), the consolidated salary of MBBS doctors on contract basis at present is Rs.50,000/- to 60,000/- per month. This salary has to be enhanced at least to Rs.90,000/- per month. There will be no significant financial implication. This enhancement can be managed within the available NHM funds. Only permission is required to enhance the salary. This will attract more and more doctors to work in rural hospitals such as PHCs, CHCs and Taluk Hospitals. The incentive that can be considered is to give additional weightage at the time of NEET-PG selection depending on the number of years of rural service or separate rural service quota for PG seat allotment can also be considered.

Outsource Staff Nurses Issues in PHSS, CHCs and Taluks Hospital:- Rural hospitals such as PHCs, CHCs and Taluk hospitals are facing shortage of Staff Nurses. Presently, under National Health Mission (NHM), outsource Staff Nurses are getting a consolidated salary of Rs. 13,000/- per month which is less than the Daily Wages Act. This is the main reason that the Staff Nurses are not willing to come forward to work. If this can be enhanced at least to Rs.20,000/-per month, then they might be willing to join the rural services. Only way we can improve the Health Care services in public hospitals is by addressing the shortage of man power.

(3)HPV vaccination to prevent Cervical Cancer in women is to be Included under "National immunization Protocol":- Cervical Cancer is one of the common cancers in women. HPV vaccination can reduce the occurrence of cancer by 80-90%. Ideal age group is 10-16 years. Hence, the best strategy is to vaccinate high school studying girls as part of National Immunization Programme.

(4) To encourage the opening of multi-specialty private hospitals in tier three cities / Rural areas. Five-year tax holiday can be considered for such hospitals.

(5) To enhance the honorarium of Asha and Anganwadi workers from time to time: They play an important role in the health care services of pregnant mothers and children. Because of their hard work, the infant mortality and maternal mortality is declining. As the cost of living is steadily increasing, it is becoming difficult for them to support their family with the present honorarium. Hence, the increase of their honorarium is justifiable.

DR. AMOL RAMSING KOLHE (SHIRUR): This Budget is a classic example of the difference in what they preach and what they practice. I will try to explain through two examples.

The philosophy of governance should follow the great principles of Buddhism. i.e "Madhyam Marg" (Middle Path). It is our collective responsibility, especially that of the government, to ensure that the idea of a welfare economy does not devolve into a mere tool for electioneering. We have all witnessed how the Hon'ble Prime Minister used to criticize the provision of free services by certain states, calling it the "Rewadi culture" However, with each passing election, we have observed the Bharatiya Janata Party (BJP) adopting similar trends in states such as Maharashtra, Madhya Pradesh, Haryana, and now Delhi.

Second example is ONOE. The same party that advocates for "One Nation, One Election to enable seamless policy-making is, because governments can take decision without keeping in consideration the election Calendar, unfortunately majority of announcements in this budget are made keeping the election Callender in mind.

It was expected that this budget would present a long-term economic roadmap for the nation, aiming to bring the economy back on track. Instead, what we received was nothing more than a selective and repeated focus on one state, to the point where it may confuse the common people as to whether this is the Union Budget or simply the Budget for Bihar. This selective mention of states deserves careful scrutiny. We saw a similar trend in the previous speech when the Finance Minister sought to woo two of the NDA's allies-Chandra Babu Naidu and Nitish Kumar-but this time, political opportunism led to the omission of Mr. Naidu. In such situations, Mr. Naidu's likely response to this budget finds apt expression in the words of the great poet Ahmad Faraz:

"चला था जिक्र जमाने की बेवफ़ाई का,
सो आ गया है तुम्हारा खयाल वैसे ही."

-Ahmad Faraz

The government is expected to explain to this august House the progress of announcements made regarding Bihar in the last budget. If not, this repeated and selective naming of states signals nothing but an attempt to balance political equations. In her speech, the Finance Minister outlined ten priorities. To my mind, following the "Middle Path," the government should prioritize three things: education, health, and agriculture. I would now like to examine these three areas in greater detail.

Agriculture was pegged as the first engine by the Finance Minister, but the reality is that farmers have received nothing but empty promises in the past 10 years under this government. The biggest promise was the doubling of farmers' incomes. However, real wage growth for agricultural labourers has been just 0.8% since 2014. Additionally, the growth of the agricultural economy has been slowing, with growth falling from 4.7% in 2022-23 to an eight-year low of just 1.4% in 2023-24. After a decade in power, the government has little to show for its efforts, except for the Kisan Samman Nidhi scheme, which, without inflation indexation, is becoming less helpful day by day. Despite a decade of disappointment, our farmers remained hopeful that this year's budget would offer something concrete for them. Unfortunately, what they received was a 2.5% decrease in the Budget Estimates (BE) for 2025-26 compared to the Revised Estimates (RE) for 2024-25 from the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Furthermore, a new scheme, the PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, is aimed at benefiting only 1.2 crore farmers based on their own targets. Given the dire situation of 70 crore farmers-where at least 112,000 individuals working in the agricultural sector have committed suicide over the past decade, according to data from the National Crime Records Bureau-schemes targeting such a small population are simply insufficient. The suffering of the majority of farmers requires a far more comprehensive and meaningful approach. As the poet Dushyant Kumar wrote

"कहाँ तो तय था चरागों हर एक घर के लिए,
कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए."

-Dushyant Kumar

India's healthcare system faces significant challenges, with public healthcare expenditure standing at just over 2% of the country's GDP in 2022, one of the lowest globally. Cuba, ranked 62nd in the world GDP ranking, spent 10.1% of its GDP on healthcare in 2019, according to the CSEP report. Similarly, India's neighbours like Sri Lanka, Malaysia, Thailand, and China spend more on healthcare than India.

In 2019, China spent 3%, Thailand 2.7%, Malaysia 2%, and Sri Lanka 1.9% of their GDPs on healthcare, while India spent only 1%. This low investment is reflected in the state of healthcare infrastructure, as nearly 80% of public health facilities under the National Health Mission fail to meet minimum essential standards for infrastructure, workforce, and equipment. This underinvestment has also contributed to India having one of the highest out-of-pocket healthcare expenses in the world, placing a heavy financial burden on citizens.

Further compounding these challenges is India's growing issue with antimicrobial resistance, with the country being recognized by the World Health Organization (WHO) as a hotspot for such resistance. This has led to a rising number of deaths from infections that no longer respond to treatment, further straining an already overburdened healthcare system.

Moreover, environmental factors such as air pollution exacerbate public health issues. Cities like Delhi are frequently ranked among the most polluted in the world, contributing to widespread respiratory problems such as asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and even premature deaths. Air pollution represents a significant public health threat, underscoring the urgent need for comprehensive reform and investment in both healthcare and environmental policies.

In the words of IMF Managing Director Kristalina Georgieva, artificial intelligence is hitting the global labour market "like a tsunami Millions of jobs are at risk, and we need to overhaul our education system to address this challenge. Unfortunately, no specific vision in this direction was presented in the Budget speech.

Since education is a subject under the Concurrent List, we need coordinated efforts to address such issues. However, the opposite is happening. The UGC Draft Regulations 2025 further undermine state autonomy by centralizing the process of appointing Vice Chancellors (VCs) in state universities. The

new regulations override existing state laws governing university appointments and mandate a central role in the selection process, disregarding the authority of state governments and university bodies.

The biggest point of self-congratulation in the Budget speech was the announcement of a tax foregone amounting to 21 lakh crore. What is particularly interesting is that despite this 21 lakh crore being foregone, income tax collections are expected to increase by 14.4% compared to the Revised Estimate (RE) for 2024-25. The Budget Estimate (BE) for 2025-26 is 14,38,000 crore, up from 12,86,885 crore. This increase in income tax revenue, despite exemptions for those earning below 12 lakh, can only come from a significant increase in income for the higher-income category. This indicates a growing income inequality in the economy.

To sum up the following lines from the famous Hindi poet Adam Gondvi come to mind:

"तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा चुनवी/किताबी है."

SHRI C. N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): The Union Budget 2025-26 is comprehensively biased as the budget completely ignores the needs of Tamil Nadu and betrayed the expectations of the people, therefore, the budget is totally anti-poor, anti-women, anti-youth and anti-farmer. Under PM-KISAN, the Budgetary Allocation in BE 2025-26 is to the tune of Rs. 63,500 crore i.e. the same as in RE 2024-25. Moreover, the Budgetary provisions and its implications are imbalanced, non-progressive and non-inclusive. The Union Budget is prejudiced as it completely ignored the demands of Tamil Nadu for numerous projects viz. Highways and Railways Projects, Coimbatore and Madurai Metro Rail Projects and despite the fact the economic survey, ranking of higher Education Institutions and the NITI Aayog Reports praised the State's activities. Needless to say, reduction in central funding increase the financial burden on the State Government. Sad to say, that schemes and funds are announced only for election bound States or BJP allied ruled States. The Budget does not address the key economic challenges like poverty, inflation and unemployment etc.

- (i) The Budget estimate for MGNREGA Schemes is stagnant at Rs. 86,000 Crores in BE 2025-26, which is same as the budget allocation for 2024-25. despite the fact that it is one of the important schemes for rural poor's livelihood.

- (ii) Although Tamil Nadu has received allocation of Rs. 6,626 Crores for railway projects which is a merely 4% increase over allocation of Rs. 6,331 Crores for 2024-25, however, railway infrastructure projects in Tamil Nadu is not effectively implemented so as to avoid time & cost overruns. The Budgetary allocation is not adequate as per requirement of railway infrastructure of the State.
- (iii) Tamil Nadu is one of the highest revenue contributors in the form of income tax and corporate taxes but unfortunately, Tamil Nadu does not get the corresponding State share, thereby limiting the fiscal space for supporting welfare schemes by State Government. The Union Government could not allocate adequate compensatory fund for the State of Tamil Nadu for Cyclone Michaung, for rescuing and rehabilitation of affected people.
- (iv) The Union Budget is a huge disappointment to the middle class as the few relaxations announced do not apply to those in the old income tax regime.
- (v) High fertilizer prices led to declining in average farmer income and thus the promise of Union Government for doubling farmer's income remained a distant dream and election slogan.
- (vi) The allocation for health and education are also not adequate and the execution of the National Health Mission, SSA, PMGSY, PMKSY have not benefited to the people of Tamil Nadu on the expected line.
- (vii) Everybody knows how the prices of essential commodities including petrol, diesel and cooking gas are reaching to the sky.
- (viii) Although the State Government is making all out efforts for road infrastructure development of Tamil Nadu, however, the allocation by the Union Government for Road Projects remained insufficient especially for highways, Metro rail projects during last 10 years.
- (ix) Tamil Nadu has 1076 Km coastal line but Union Government has not allocated sufficient fund for development of these coast line for transportation and tourism.
- (x) Reportedly, diversion of Educational Fund to the tune of Rs. 2152 crores meant for Tamil Nadu is a case against prudent budgeting.
- (xi) Considering that Tamil Nadu is a water-deficit State, no scheme has been proposed for the diversion of excess water to the State and improvement of agricultural resources.
- (xii) Unemployed youth are running from pillar to post in search of jobs, making the promise of the Government to generate two crore employment each year, only an election plank. And, Alas! the

Government is cherishing 'Viksit Bharat' by 2047, a long term drawn plan and aspiring to rule the country till that period without serving the people's interest.

- (xiii) Paradoxically, Government is claiming for alleviating 25 crore people from poverty, however, Government has to give 5 kg free grains to 80 crore people under PMGKY.
- (xiv) Our, Hon'ble and visionary Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, the embodiment of progress and champion of welfarism, is taking lots of initiatives for all round development of the State and fulfilling the aspiration of the people. He is inviting huge investments for economic growth and development of the State and creating vast opportunities for employment generation.
- (xv) I appeal the Union Government to allocate sufficient fund to build social and physical infrastructure in terms of food security, education, development of railways, airports, roads, ports, MSMEs and tourism in Tamil Nadu in general and my constituency Tiruvannamalai in particular.

CAPTAIN BRIJESH CHOWTA (DAKSHINA KANNADA): From the snow-capped Himalayas to the sun-kissed shores of Kanyakumari, from the fertile plains of the Ganga to the arid deserts of Thar, our homeland is not just a landmass-Bharat is more than geography; it is a living soul, an immortal civilisation, a story of resilience and enterprise.

As the wheel of time turns and a new fiscal dawn breaks, the one promise that must never change is the one we make to our people-that governance is for everyone, not just a privileged few. The wisdom of our ancestors, Sarve **Bhavantu Sukhinaah**-may all be happy, may all be prosperous, may none be left bereft of opportunity- guides our vision and our efforts.

History has shown us that when India dares to dream, it achieves the impossible. From the visionary infrastructure initiatives under Sri Atal Bihari Vajpayee ji's leadership, such as the Golden Quadrilateral, which revolutionized connectivity across the nation, our nation has repeatedly overcome challenges with determination and innovation. The Golden Quadrilateral not only connected major cities but also laid the foundation for rapid economic growth by improving logistics and reducing travel time.

Today, under the leadership of Prime Minister Sri Narendra Modi ji, we have built upon this foundation with the Bharatmala and Sagarmala projects, expanding connectivity even further. A testament to this progress is the recently inaugurated Sonmarg Tunnel, which provides all-weather connectivity to the Kashmir Valley, ensuring seamless movement and strengthening our national security.

This remarkable feat of engineering is yet another milestone in India's infrastructural journey, tracing its roots back to Vajpayee Ji's vision of connecting Kashmir to Kanyakumari through the Golden Quadrilateral. The transformation from laying these first highways to constructing tunnels in some of the most challenging terrains highlights how far we have come as a nation in realizing our infrastructural aspirations.

As we stand at another crucial juncture, this Budget reflects our unwavering commitment to a self-reliant India-one that prioritizes growth, inclusivity, and opportunity for every citizen. It is a Budget that speaks to the dreams of young entrepreneurs, the aspirations of farmers, the resilience of our middle class, and the indomitable spirit of our people.

This Budget strengthens India's economic resilience and prioritizes sectors that will drive growth in the coming years. The emphasis on Make in India, Atmanirbhar Bharat, and digital transformation reaffirms our resolve to create employment opportunities and enhance productivity across industries.

One of the most celebrated aspects of this Budget is the raising of the Nil tax slab to ₹12 lakh, providing significant relief to the middle class. Over the years, our government has steadily increased this threshold, ensuring greater savings and enhanced economic participation from hardworking families. This move alone puts ₹80,000 per person back into the hands of our middle class, fostering consumption, investment, and economic growth.

However, while we welcome the Budget's broad vision, I must take this opportunity to highlight the needs and aspirations of my constituency, Dakshina Kannada. As a coastal region with immense economic and strategic potential, we seek greater attention in specific areas to maximize our growth trajectory.

The government's push for infrastructure development is commendable, but coastal districts like Dakshina Kannada require focused investment in road, rail, and port connectivity. The expansion of the Mangalore Port and the development of multimodal logistics parks will strengthen our position as a key trade hub. We urge the government to expedite ongoing projects like the four-laning of NH-75 and NH-66, as well as the modernization of Mangalore International Airport. Karnataka must leverage the Laid on the Table allocated for infrastructure development

With the potential to emerge as a Blue Economy powerhouse, Dakshina Kannada needs tailored policies for fisheries, marine industries, and coastal tourism. The Budget's allocation for the fisheries sector has been increased to ₹2,703.67 crore, but we need enhanced funding for deep-sea fishing infrastructure, modern cold storage facilities, and direct export corridors. The Tourism Infrastructure Development scheme has seen an allocation of ₹90 crore, which should be directed towards developing coastal tourism circuits in our region. Additionally, the MUDRA loans for homestays and performance-linked incentives for states will boost Dakshina Kannada's tourism sector.

Dakshina Kannada is home to industries in oil refining, petrochemicals, and manufacturing. The Budget's provisions for ease of doing business and MSME support will aid local entrepreneurs. However, we seek specific incentives for industries in the Mangalore SEZ, particularly in renewable energy and sustainable manufacturing. The Shipbuilding Clusters initiative, which has been allocated ₹365 crore, and the ₹25,000 crore Maritime Development Fund must be leveraged to reinstate Mangalore's position as a key shipbuilding hub. The revised classification criteria and doubling of the credit guarantee for MSMEs and startups will further strengthen local industries.

As a coastal region, Dakshina Kannada is vulnerable to natural disasters like cyclones and coastal erosion. While the Budget's outlay for disaster management is appreciated, we need dedicated funds for coastal erosion prevention, construction of sea walls, and disaster-resilient infrastructure. Strengthening coastal security through modern surveillance systems will also enhance national security and safeguard our fishermen.

Mangalore has emerged as an educational hub, attracting students from across the country. I welcome the government's push for skill development and higher education reforms. However, I request the establishment of a Centre for Maritime Studies in Mangalore to leverage our coastal resources and train the next generation in marine sciences, shipping, and fisheries management. The National Programme for Youth and Adolescent Development, with an allocation of ₹25 crore, should include initiatives to skill youth in these sectors. The announcement of a national framework for Global Capability Centres (GCCs) in emerging tier - II cities, including Mangalore, is a major opportunity that we must actively pursue.

This Budget paves the way for a stronger India-one that embraces progress while remaining firmly rooted in its values. As we look towards the future, let us remember that true development is not measured only in GDP growth or infrastructure but in the empowerment of every Indian, in every corner of this vast and diverse land.

At this moment in history, we are not just witnesses to change- we are the architects of India's destiny. As representatives of the people, it is our duty to ensure that no Indian is left behind. With targeted investments and policy support, we can transform Dakshina Kannada into a hub of sustainable growth and economic prosperity. Jai Hind!

DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM): I would like to draw the attention of the Union Finance Minister, to an issue of profound significance to India's democratic ethos and commitment to social justice-the urgent necessity for the Union Government to conduct a census.

In this budget, no allocation has been made for conducting the already delayed decennial census. reflecting the government's decision to postpone this crucial exercise indefinitely.

The decennial census is not merely a statistical exercise, it is the foundation of equitable governance. The Constitution mandates that the Union Government conduct a census every ten years, with the last one held in 2011. However, the 2021 census remains indefinitely postponed a delay that severely hampers our ability to formulate policies based on current realities. How can we address inequality, allocate resources, or measure progress without updated data?

The prolonged postponement of India's 2021 census has caused significant concern. exacerbated by the abrupt dissolution of the 14-member Standing Committee on Statistics (SCOS), led by economist Pronab Sen. This committee, instrumental in overseeing the census process, was disbanded without any clear justification from the central government. The move has intensified scrutiny over the government's handling of the census, leading many to suspect political motivations. More importantly, this delay will have a severe impact on social welfare programs, particularly for marginalized communities that rely on government support for their survival and advancement.

The census is much more than a mere population count; it is an essential tool that enables the government to assess the evolving needs of the people and implement policies that promote social

welfare and inclusive growth. It provides vital data on housing conditions, employment trends, household compositions, literacy rates, and other key factors that shape social welfare initiatives. The effective implementation of programs such as the Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), the National Food Security Act (NFSA), and the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) depends heavily on accurate and updated census data. These initiatives aim to uplift the most disadvantaged sections of society by ensuring access to essential services and economic opportunities.

The delay in conducting the census is already disrupting several welfare programs. For instance, the Public Distribution System (PDS) relies on census data to determine eligibility and allocate food supplies nationwide. The PDS plays a crucial role in India's food security framework, ensuring that millions of low-income families receive subsidized food grains. However, in the absence of updated census data, the system continues to operate based on 2011 estimates, which are now grossly outdated. This means that newly impoverished families or those that have expanded since the last census may be excluded. Such inefficiencies undermine the effectiveness of the PDS, depriving crores of deserving families of their right to food security.

Beyond food security, the lack of recent census data also affects critical sectors like health and education. Public health policies depend on demographic data to plan immunization programs, allocate healthcare personnel, and develop medical infrastructure in underserved areas. The COVID-19 pandemic underscored the urgent need for up-to-date census data in managing public health crises. Without it, the government struggled to ensure the equitable distribution of vaccines and medical care, particularly in remote and vulnerable regions.

Similarly, educational programs like Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) and the Mid-Day Meal Scheme rely on census data to determine the number of children requiring schooling and to allocate resources accordingly. Outdated information leads to inadequate funding, teacher shortages, and a lack of essential supplies, disproportionately affecting children from rural and low-income backgrounds who depend on government support for education.

Perhaps most concerning is the impact of the census delay on vulnerable communities, including Scheduled Castes (SC), Scheduled Tribes (ST), and Other Backward Classes (OBC). These historically marginalized groups rely on government interventions to bridge socio-economic disparities. The census is

crucial in assessing their progress and formulating policies that enhance their participation in the nation's development.

Across India-from villages to universities, civil society to political forums-there is a resounding call for a caste-wise census. Why? Because caste remains a fundamental determinant of access to education, employment, and healthcare. It has been nearly 85 years since the last comprehensive caste census in 1931. In a country where caste shapes socio-economic realities, updated data is not a luxury-it is a moral and policy imperative.

States like Bihar and Telangana have demonstrated remarkable initiative by conducting caste surveys. Bihar's recent survey, for instance, provided critical insights into the socio-economic conditions of marginalized communities. Yet, these efforts have faced legal challenges. On August 28, 2023, the Ministry of Home Affairs (MHA) informed the Supreme Court that only the Union Government has the constitutional authority to conduct a census under Entry 69 of the Union List and the Census Act of 1948. While states can collect socio-economic data through surveys, a formal census-with its legal sanctity and uniform methodology-remains the exclusive prerogative of the Union Government.

The MHA's affidavit highlights a stark reality: unless the Constitution is amended to empower states under the Seventh Schedule, and unless the Census Act of 1948 is revised, states cannot independently conduct caste censuses

The Union Government must act without delay by:

1. Conducting the 2021 Census (now overdue by three years) with caste enumeration
2. Collaborating with states and integrating their findings into a national framework.
3. Amending the Census Act and Constitution to empower the states to conduct population census.

India's strength lies in its diversity, but our policies must reflect this diversity to foster true unity. We cannot allow procedural inertia to eclipse justice. The Union Government must heed the people's call, uphold constitutional morality, and conduct a caste-wise census without further delay. Thank You

श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर) : मैं आम बजट वित्तीय वर्ष 2025-2026 का समर्थन करता हूँ। इस दूरदर्शी बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आपने नये भारत के निर्माण के लिए एक बड़ा कार्य

योजना को अंतिम रूप दिया है। इसमें देश के सभी वर्गों के हितों को ध्यान रखा गया है।

मैं वाल्मीकि नगर लोकसभा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। यह क्षेत्र नेपाल के सीमा से लगा है। आप इसको भारत का द्वार भी कह सकते हैं। इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की बहुत जरूरत है।

बजट में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की योजना है। बिहार के पश्चिम चम्पारण जिला और वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र दर्जनों छोटी-बड़ी और पहाड़ी नदियों से अच्छादित है, जहाँ हर वर्ष बाढ़ व कटाव से फ़सल की क्षति होती है। यहाँ सिंचाई की सुविधा और भंडारण व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। मेरी माँग है कि बिहार के पश्चिम चम्पारण जिले को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में चयनित किये जाने वाले 100 जिलों में शामिल किया जाए। साथ ही साथ कम उत्पादकता, कम फ़सल बुआई, फ़सल विविधता, जिला व प्रखंड स्तर पर भंडारण क्षमता, सिंचाई की सुविधा में सुधार के साथ दीर्घ कालीन व लघु कालीन ऋण उपलब्धता के आधार पर इनके संवर्द्धन हेतु देश के 100 जिलों को चुना जायेगा।

मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन और विपन्न में सुधार लाने के लिए बिहार के दरभंगा में मखाना बोर्ड की स्थापना सरकार का स्वागत योग्य कदम है। यह बोर्ड मखाना उत्पादक किसानों का पथ-प्रदर्शन और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें सभी संगत सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इससे बिहार को काफी लाभ पहुंचेगा। मैं इसके लिये केंद्रीय वित्त मंत्री और भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रयास किया जा रहा। मेरी माँग होगी कि सभी ग्रामीण डाक सेवकों की तनख्वाह बढ़ाई जाये और उन्हें स्थायी कर्मचारी की मान्यता दी जाये।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ऋण राशि 05 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य है। उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 10 लाख विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा भी सराहनीय है। इससे सूक्ष्म उद्योग जगत को बढ़ावा मिलेगा। मेरा आग्रह होगा कि सरकार अपने स्तर से मेरे संसदीय क्षेत्र बाल्मीकिनगर में लघु और सूक्ष्म उद्योग विकसित करने पर विचार करे। 05 लाख महिला, अनुसूचित जाति व जनजाति से आने वाले पहली बार के उद्यमियों के लिए सरकार नई योजना लाने जा रही है, जिससे स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करने की घोषणा से बिहार के लोगों को काफी खुशी हुई है।

इस संस्थान से पूरे राज्य में खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों को पुरजोर बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्द्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी और युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता तथा रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

बजट में बिहार को काफी कुछ दिया गया है। पटना आईआईटी के विस्तार के साथ मेडिकल और इंजिनियरिंग कॉलेजों में सीटें बढ़ने से विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा। देश के 200 जिला अस्पतालों में 'डे-केयर कैंसर केंद्र' खोलने का फैसला इस बीमारी से निजात के लिए अच्छा फैसला है। पश्चिम चम्पारण जिला अस्पताल को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इधर से सैंकड़ों मरीज कैंसर के बेहतर इलाज के लिए पटना, बनारस, गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली जाते हैं और 12 लाख तक की

आय को कर मुक्त करने की घोषणा से मध्यम वर्ग में काफी खुशी है। इस बचे हुए टैक्स की राशि को वे अपने बच्चों की पढ़ाई, माता-पिता की दवाई और निवेश आदि पर खर्च कर सकेंगे।

बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि राज्य की हवाई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इसमें बाल्मीकिनगर भी शामिल है। प्रथम चरण में ही यहाँ के हवाई अड्डा को विकसित कर उड़ान योजना के तहत हवाई यात्रा शुरू करने की मैं पुरजोर माँग रखता हूँ।

पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने से 50,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन पर खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। हमारे संसदीय क्षेत्र में मसान नदी से सैकड़ों हेक्टेयर फसलें प्रभावित होती हैं। उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार ने 28 हजार करोड़ रुपये के निवेश से 12 इंडस्ट्रियल जोन और 100 औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है, जो प्रशंसनीय है। मेरा सरकार से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र बाल्मीकिनगर अंतर्गत बगहा अनुमंडल के रतवल-नैनाहा क्षेत्र में 1700 एकड़ सरकारी जमीन चिन्हित है, जिसमें एक औद्योगिक पार्क की स्वीकृति दी जाये। यह जमीन पहले टेक्सटाइल पार्क के लिए अधिग्रहित की गयी थी, जिसे स्वीकृति नहीं मिली। सरकार ने 08 हजार करोड़ रुपये की राशि से देश भर में 52 हजार इलेक्ट्रिक बस चलाने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार से माँग होगी कि भारत-नेपाल सीमा पर महर्षि बाल्मीकि की तपोभूमि बाल्मीकिनगर से, महात्मा बुद्ध की निर्वाणस्थली कुशीनगर वाया बाँसी-धनहा चौतरवा-लौरिया-बेतिया होते और राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की कर्मभूमि भीतिहरवा, गौनाहा से प्रदेश की राजधानी पटना तक के लिए इलेक्ट्रिक बस की सेवा शुरू की जाये।

देशभर में स्थापित 470 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के जरिये सरकार आदिवासी बच्चों का शैक्षणिक स्तर बढ़ाने का उत्कृष्ट काम कर रही है। मेरा सुझाव होगा कि बाल्मीकिनगर संसदीय क्षेत्र में थारू और उरांव आदिवासी समाज के लोग काफी बड़ी संख्या में रहते हैं, इसलिए दोन क्षेत्र की तरह थरुहट की राजधानी हरनाटांड में भी एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की जाये।

छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा दस लाख से बढ़ाकर बीस लाख रुपये करना सरकार का बहुत ही कल्याणकारी कदम है। देश में 71 वन्दे भारत ट्रेन चलना खुशी की बात है। मेरा अनुरोध होगा कि एक वन्दे भारत ट्रेन गोरखपुर से पटना तक वाया नरकटियागंज -मुजफ्फरपुर होकर चलाई जाये।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 करोड़ शौचालय, उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन और 80 करोड़ उपभोक्ताओं को राशन स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में सरकार का बहुत बड़ा कदम है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन और पेंशनरों के लिए यूनिफाईड पेंशन स्कीम लागू कर सरकार ने जता दिया है कि यह हर वर्ग की हितैषी है। ये दोनों योजनाएं सरकार की तरफ से नौकरी पेशा मिडिल क्लास लोगों के लिए एक अनुपम उपहार है।

जन औषधि केंद्र के खुलने से बीमार लोगों को 80 प्रतिशत रियायत पर दवाओं के मिलने से मरीजों को काफी राहत मिली है। अधिक से अधिक जन औषधि केंद्र खोलने से लोगों को काफी फायदा होगा। देश में 03 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य के साथ मिलिट्री स्कूलों और नेशनल डिफेन्स एकेडमी में महिला कैडेट्स की नियुक्ति महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। महोदय, मेडिकल व इंजिनियरिंग कॉलेजों सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में सीटों की संख्या में वृद्धि युवा कल्याण की दिशा में सरकार का क्रान्तिकारी कदम है। पटना आईआईटी में सीटों की संख्या बढ़ाकर दुगुनी करने और बिहार के मेडिकल कॉलेजों में 200 से 250 सीटों की वृद्धि बिहार के छात्रों के लिए सरकार का तोहफा एक सराहनीय कदम है। मेरा सरकार से यह अनुरोध होगा कि अनिसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र बाल्मीकिनगर में एक केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की जाये।

यह बजट देश के सभी वर्गों के विकास के लिए है। मैं पुनः इस बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू) : मैं 2025-26 के आम बजट पर अपने विचार रखता हूँ। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का भी आभारी हूँ जिन्होंने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को पूर्ण करने वाला बजट पेश किया

यह बजट सर्व स्पर्शी और सर्व समावेशी तथा गरीब, महिला, युवा, एससी, एसटी, ओबीसी एवं अन्नदाता वर्ग के कल्याण के साथ-साथ उद्योगों एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती देने वाला दूरदर्शी बजट है।

कृषि विकास एवं किसानों की खुशहाली के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा से ओतप्रोत और रोजगार सृजन के प्रति समर्पित है।

मैं एक ही बातों को बार-बार दोहराने में विश्वास नहीं रखता और मेरे पूर्व के माननीय वक्ताओं ने बजट के करीब-करीब सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा की है। अतः उन्हीं बातों को दुहरा कर मैं महत्वपूर्ण समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए सरकार का ध्यान एक खास विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर सदन में दिए गए भाषण जिसमें उन्होंने कहा था कि "हम संविधान को जीते हैं" उसको बजट के माध्यम से कैसे परिलक्षित किया गया है इस बात पर टिप्पणी करना चाहता हूँ।

संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि प्रसिद्ध शायर जॉन एलिया का एक शेर आपके समक्ष रख दूँ 'ये वार कर गया है पहलू से कौन मुझ पर, था मैं ही दाएं बाएं और दरमियां भी मैं था। मैं दलित समाज से आता हूँ और मुझे यह लगता है कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का आचरण वर्तमान के विपक्षी दलों का दलित समाज के प्रति रहता है कि हमारे समाज को आज तक समझ ही नहीं आया कि उनके हक पर, उनकी जमीनों पर एवं उनके संसाधनों पर कब्जा कौन कर रहा है। कुछ दल हितैषी बनने का ढोंग तो करते हैं परंतु ढेले भर का काम दलित, आदिवासी एवं ओबीसी समाज के पक्ष में नहीं करते यह मैं बजट के माध्यम से समझाना चाहता हूँ।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1999 में जनजातीय कार्य मंत्रालय को अलग मंत्रालय बनाने वाले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। लेकिन इस बात को भी बताना बहुत जरूरी है कि 1998 में SC & ST वेलफेयर जैसे आवश्यक विषयों को गृह मंत्रालय से समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में लाने वाले भी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ही थे। गृह मंत्रालय के कार्यभार के दौरान SC/ST वेलफेयर को कहीं पर पीछे की सीट मिल जाती थी, यह कोई मामूली घटना नहीं थी अब समझते हैं इसके वजह क्या थे ?

2025-26 के बजट में समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को 13,611 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं जिसका एक मुख्य हिस्सा SC वेलफेयर, SC स्कॉलरशिप, SC एजुकेशनल प्रोग्राम एंड इकोनामिक एंपावरमेंट स्कीम पर खर्च होगा। वर्ष 2014 में यह करीब 6700 करोड़ रुपए होता था जो आज दोगुना से ज्यादा हो गया है।

(VCF-SC) जो एक गवर्नमेंट आफ इंडिया इनीशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट है, उसका कॉरपस 330 करोड़ है और इससे अनुसूचित जातियों के उद्यमियों को बढ़ावा मिल रहा है। उन्हें मात्र 4 प्रतिशत के ब्याज दर पर अपने व्यवसाय के लिए लोन मिल सकता है।

Development Action Plan for Scheduled Castes (DAPSC) के लिए 2023-24 1,59,147.79 में करोड़ आवंटित किए गए थे उसे 2024-25 में लगभग 4 प्रतिशत बढ़ाकर 1,65,500.05 करोड़ रुपए दिए गए थे। इस बजट 2025-26 में आवंटन राशि की 1.80 प्रतिशत बढ़ाकर 1,60,478.38 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत लगभग 7,72,000 किलोमीटर की सड़कें बन गई हैं। आपको क्या लगता है मुख्यतः इसके लाभुक कौन होंगे। लगभग 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों में बड़ी संख्या SC लाभुकों की है क्योंकि उन्हें आवास आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है। यहां मैं बताना चाहता हूँ कि पूर्व में अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आवास प्रदान करने के लिए योजना बनायी गयी थी, कांग्रेस के शासन काल में, पर आज के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और तत्कालीन इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में अंतर को जानकर आप आश्चर्यचकित रह जायेंगे। तब तक अनुसूचित जातियों के सदस्यों के आवास का निर्माण गाँव के बाहर किया जाता था, जहाँ न रोजी रोजगार का कोई साधन था नहीं बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए कोई स्कूल। एक तरह से आवास की तथाकथित सुविधा देकर उन्हें गाँव से बाहर निकाल दिया जाता था। तथाकथित आवास मैंने इसलिए कहा कि वह रहने लायक नहीं था, वस्तुतः वह सुअर के खोभार जैसा था जिसमें सुअर ही रह सकते थे आदमी नहीं और यही कारण है कि अधिकांश आवास खंडहर में तब्दील हो गए।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 2022-23 में 5,660 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था, जिससे 66 लाख छात्र लाभान्वित हुए। अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राएँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके इसके लिए हमारी सरकार ने कक्षा 9वीं एवं 10वीं के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत इस बजट के अंतर्गत 6360.00 करोड़ रुपए आवंटित किया है जिससे छात्र

लाभावान्त होंगे। इतना ही नहीं जो छात्र विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनको भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। National Fellowship for Scheduled Caste Students (NFSC) scheme के अंतर्गत Mphil and PHD Condicates को Stipend प्रदान करती है।

वर्ष 2014-15 के केंद्रीय बजट में अनुसूचित जातियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना Credit Enhancement Guarantee Scheme for SC (CEGSSC) की घोषणा की गई थी। CEGSSC योजना 200 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि के साथ शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, इसके लिए ऋण देने वाली संस्थाओं को ऋण वृद्धि गारंटी प्रदान की जाती है, जो अनुसूचित जाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।

माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने देश के समग्र विकास के लिए आकाशी जिलों एवं ब्लॉकों को चिन्हित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि आकाशी जिलों में विकास का कार्य तेज गति से चले ताकि कि वे आकांक्षी जिलों की सूची से निकलकर विकसित जिलों की श्रेणी में आ खड़े हों। नीति आयोग ने स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास तथा बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के समग्र संकेतकों के आधार पर 27 राज्यों में कुल 112 आकांक्षी जिलों की पहचान की गयी है। उक्त आकांक्षी जिलों की सूची में मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू के दोनों जिलें कमशः पलामू एवं गढ़वा भी शामिल हैं। इन दोनों जिलों के समग्र विकास के लिए मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण परियोजनाएँ अधर में लटकी हुयी है। उक्त परियोजनाओं को पूर्ण कराने की मांग करता हूँ ये योजनाएँ हैं:-उत्तरी कोयल जलाशय (मंडल डैम) परियोजना, मेदिनीनगर स्थित चियांकी एयरपोर्ट का परिचालन, पलामू एवं गढ़वा जिला में 20-20 मेगावाट का सोलर पार्क, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कॉर्पोरेशन (NICDC) के तहत झारखंड राज्य के भवनाथपुर में इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) की स्थापना, सोन कनहर पाइप लाइन सिंचाई परियोजना, रजहरा कोलियरी में कोयला उत्खनन का कार्य प्रारम्भ करना।

बजट 2025-26 में रेलवे के विकास के लिए 2,52,000 करोड़ रूपए की बड़ी राशि आवंटित किया गया है। उक्त राशि से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में रेलवे के इफास्ट्रक्चर, नई ट्रेनें और आधुनिक कोच, निम्न एवं मध्यम वर्ग के लोगों की सेवा करने में बहुत मददगार साबित होगी। माननीय रेल मंत्री जी ने रेलवे का तेज गति से यात्री सुविधाओं में विस्तार एवं रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन किया है इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। रेलवे मंत्रालय से पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण मांगों को पूर्ण कराने की कृपा की जाय, जो निम्नलिखित हैं:-

1. त्रिवेणी लिंक एक्सप्रेस को पुनः प्रारंभ किया जाय अथवा उसके स्थान पर एक ऐसी ट्रेन चलायी जाय जो लखनऊ तक जाये।
2. हावड़ा जबलपुर शक्तिपुज एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 11447/11448 का विस्तार मुंबई तक किया जाये।

3. रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 18635/18636 में यात्रियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण लोगों को यात्रा करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की संख्या को देखते हुए 1 Ac Chair Car एवं 3G.S कोच की संख्या में बढ़ोतरी की जाये।

पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर Unmanned Railway Crossing को बंद कर दिये जाने से एक ही गांव दो भागों में विभक्त हो गये है। वहां के निवासियों को आवागमन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त स्थानों पर RUB/LHS का बनाने से जनता को कठिनाइयों से निजात मिल सकेगी। वैसे स्थान निम्नलिखित है:-

- (1) डाली-हैदरनगर प्रखण्ड, पलामू जिला।
- (2) सोनपुरवा-गढ़वा जिला।
- (3) अहिरपुरवा-नगर उंटारी, गढ़वा जिला।
- (4) कजरात नावाडीह-हुसैनाबाद प्रखण्ड, पलामू जिला।
- (5) बुढवापीपर-डालटनगंज सदर, पलामू जिला।
- (6) बखारी-डालटनगंज सदर, पलामू जिला।
- (7) कुम्भी-मेराल ब्लॉक, गढ़वा जिला।
- (8) लहरबंजारी-उंटारी रोड प्रखण्ड, पलामू जिला।
- (9) बेगमपुरा-मोहम्मदगंज प्रखण्ड, पलामू जिला।
- (10) सतबहिनी रेलवे स्टेशन एवं मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन के बीच में खंभा संख्या 340/33 के समीप और गेट नं0-58 के पास, उंटारी रोड प्रखण्ड, पलामू जिला।

अंत में मैं माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस बजट में अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। उनका निर्णय न केवल उनके सपनों को साकार करने में सहायक होगा बल्कि समाज को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। अंत में इन दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि "तालीम की रोशनी हर दलित के घर में जलती रहे, ख्वाब हर नजर में नए रंग भरती रहे, जो बढ़ाए कदम आगे सबके भले के लिए, उस रहनुमा को सदा दुनियां दुआ देती रहे।"

SHRI AGA SYED RUHULLAH MEHDI (SRINAGAR): I would like to express my views on Union Budget 2025-26 and its implications for the progress of Jammu and Kashmir. While the budget aims to propel

India's growth, it is imperative to critically assess its provisions concerning Jammu and Kashmir to ensure that the region's unique challenges are adequately addressed.

The Union Budget 2025-26 allocates 41,000.07 crore to Jammu and Kashmir, a slight decrease from the previous year's 42,277.74 crore. This reduction is concerning, especially given the region's pressing needs in infrastructure, healthcare, and education. The Kashmir Chamber of Commerce and Industry (KCCI) expressed disappointment over the reduced allocation, emphasizing concerns about funding for development projects.

Tourism is a cornerstone of Jammu and Kashmir's economy, providing livelihoods to thousands. Despite this, the budget lacks a dedicated revival package for the region's tourism industry. While there is a general emphasis on tourism infrastructure across India, specific initiatives tailored to rejuvenate Jammu and Kashmir's tourism sector are conspicuously absent. This oversight could impede efforts to attract visitors and revitalize the local economy.

Jammu and Kashmir grapples with one of the highest unemployment rates in the country. The budget maintains the allocation for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) at 860 billion nationwide. While this scheme provides rural employment opportunities, its effectiveness in significantly reducing unemployment in Jammu and Kashmir remains uncertain. The absence of targeted employment schemes for the region's youth is a glaring omission.

The budget allocates 9,325.73 crore to the Jammu and Kashmir Police, an increase from the previous year's 8,665.94 crore. While maintaining security is essential, the disproportionate emphasis on security expenditure raises concerns. Balancing security needs with developmental initiatives is crucial for fostering long-term peace and prosperity.

Lack of Industrial Incentives

The budget does not introduce significant industrial incentives specific to Jammu and Kashmir. The region's industrial sector, particularly textiles, handicrafts, and food processing, requires targeted support to thrive. The absence of a special economic revival package further disappointed local stakeholders.

Conclusion.

In conclusion, while the Union Budget 2025-26 outlines several initiatives that could impact various sectors in Jammu and Kashmir, the reduction in overall allocation has raised concerns about the potential impact on development initiatives in the region. It is imperative for policymakers to recognize and address these gaps to ensure inclusive and sustainable development for Jammu and Kashmir.

Thank you.

श्री छोटेलाल (राबर्ट्सगंज) : सरकार लाख हवा हवाई बजट पास कर ले, मगर SC/ST/OBC व्यापारी, किसान के लिए यह बजट खोखला है। सरकार यह बताये कि 12 लाख टैक्स में छूट पैसा वालों के लिए हो गया, परन्तु 12 लाख रुपए गरीब, मजदूर, व्यापारी, किसान, युवा इत्यादि लोग कहां से पाएंगे? 12 लाख कैसे कमाएंगे, यह सरकार बताये? क्या कोई ऐसा बजट 10 सालों में आया है? इस बजट में भी ऐसा कुछ नहीं आया जिसमें कि कोई गरीब 12 लाख तक साल में कमायेगा। सबका साथ, सबका विकास कहाँ है? सरकार स्पष्ट करे किस हिसाब से 12 लाख फ्री में टैक्स मुक्त है जबकि पुरानी कर प्रणाली यथावत है। देश की जनता भ्रम में है। 80 से 82 करोड़ तक लोग राशन पाते हैं और अधिकतर लोग 12 लाख से भी ज्यादा लोग देश में टैक्स भरते हैं। क्या लाल कार्ड पाने वाले राशन वालों को अब राशन नहीं मिलेगा, गैस सिलेंडर फ्री में जो मिलता है वह अब नहीं मिलेगा, सब गरीब व मजदूर अमीर हो गये हैं। यह बजट खोखला है। SC/ST/OBC बालक अथवा बालिकाओं के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा फ्री, सब्सिडी पर शिक्षा लोन फ्री, चिकित्सा फ्री, किसानों को व्यापारियों को सब्सिडी पर लोन देकर विकास किया जाना चाहिए। अभी तक गरीब, किसान व व्यापारी इत्यादि लोग जमीन बेचकर बेटी की शादी करते हैं। ये लोग जमीन बेचकर अपनी बेटी की शादी ना करें। ऐसी सुविधा या बजट सरकार सुनिश्चित करे। दलित सांसद, विधायक, मंत्री बने हैं, मगर पॉवर किसके हाथ में है समझ जाइए। भाजपा सरकार में एक कर्मचारी, चपरासी को नहीं बदल सकते।

सोनभद्र दुद्धी में कनहर परियोजना - बँधी तैयार है मगर नहर नहीं बनी है। माननीय नेता जी के समय की परियोजना थी, लेकिन जान बूझकर कोई बजट नहीं दिया गया। वहाँ लोगों को मुआवजा नहीं मिला। ऐसे देसवली परियोजना व नगवा बांध से करही बँधी, बलियारी बँधी, देवरी बँधी, भेलाही बँधी, घोरावल के लिए इत्यादि जगहों पर पानी देने के लिए कोई बजट नहीं है। बाणसागर परियोजना सोनभद्र तक हो जाएगी तो चकिया, नौगढ़, पूरा सोनभद्र आबाद हो जाएगा, लेकिन कोई बजट नहीं है।

उपरोक्त सभी के लिए यह बजट खोखला है। इसमें सभी के लिए कुछ नहीं है, बल्कि 12 लाख लोन फ्री में देकर 5 साल तक ब्याज मुक्त रोजगार का अवसर गरीब लोगों को देना चाहिए था। उपरोक्त सभी के लिए बकरी लोन, गाय लोन, भैंस लोन, भेड़ लोन, सुअर लोन, व्यापारी लोन, किसान लोन, महिला लोन, युवा शिक्षा लोन इत्यादि लोन से पैसा देकर उपरोक्त सभी लोगों का उत्थान करना चाहिए, ताकि 12 लाख कम से कम साल में सभी लोग कमाई कर सकें, तब गरीब का फायदा होगा।

? गरीबों को बजट दिलवाना पड़ेगा,

हवा हवाई बजट भगाना पड़ेगा

अगर चाहिए सच्चा न्याय तो..

गरीबों को सब्सिडी पर लोन देकर व्यापारी,

किसान, गरीब, महिलाओं व युवाओं का कर्ज माफ कराना पड़ेगा।"

अडानी जैसे बड़े-बड़े लोगों को महज 3% पर लोन मिलता है और उनका सैकड़ों करोड़ों का लोन आसानी से माफ भी हो जाता है तो किसानों, व्यापारियों, गरीबों, युवाओं व महिलाओं का कर्ज माफ क्यों नहीं? 15 लाख रुपये नहीं मिले। देश के एक-एक व्यक्ति पर लगभग डेढ़ लाख रुपये का कर्ज है। किसान सम्मान निधि 12 हजार महीना एमएसपी गारंटी क्यों नहीं? किसानों की दोगुनी आय नहीं हुई? मनरेगा की ऐसी योजना है कि कोई मजदूर कार्य करने को तैयार नहीं है।

स्कूल में खाना बनाने वाली रसोईया महिलाओं का वेतन/मानदेय बढ़ाना चाहिए। उसी प्रकार आशा, आंगनबाड़ी, शिक्षामित्रों, आपदा समूह सखियों का भी वेतन/ मानदेय बढ़ाना चाहिए। मगर इस बजट में इन सभी के लिए कुछ नहीं है। देश के मान्यता प्राप्त मीडिया के लोगों को यात्रा में रेलवे विभाग द्वारा 50% छूट मिलती थी। यह सुविधा 5 सालों से बंद है। इस पर सरकार ने विचार नहीं किया। दलितों को मसीहा बताने वाले, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कांसीराम आवास योजना पर नज़र नहीं गई। कई वर्षों से वहाँ साधन-सुविधा, पानी, चिकित्सा, शिक्षा व बने हुए सरकारी आवासों की कोई खबर लेने वाला नहीं है। केवल दलितों का वोट लेने के लिए ये मायाजाल रचते हैं। उन आवासों की रंगाई-पुताई होगी या नहीं, इसकी किसी को चिंता नहीं है।

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): Everyone had hoped that the Union Budget for the upcoming financial year would include provisions to help revive the Indian economy. The budget was expected to include both short-term and long-term projects aimed at economic recovery. However, the Union Government's Budget has proven to be disappointing for all sectors of society.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has failed to propose solutions to the pressing issues facing the economy today. Economic planners, experts, and the business community remain sceptical about the country's economic outlook. The Economic Survey 2024-25, tabled in Parliament by the Union Finance Minister ahead of the Budget, highlights this concern. According to the report, the projected economic growth rate for the current financial year is 6.4%. The survey suggests that next year's growth will not exceed a range of 6.3% to 6.8%. To achieve a "developed India" by 2047, as envisioned by the Prime Minister, an annual growth rate of at least 8% is required. The Economic Survey for 2023-24 had projected a growth rate of 8.2%. The growth rates for the past few years were 8.2% in 2023-24, 7.2% in 2022-23, and 8.7% in 2021-22, according to government figures. Clearly, the economic situation remains critical.

A 12.3% decline in capital expenditure this year has raised significant concerns. Data compiled up to November shows food price inflation at 8.4%, up from 7.5% in the same period last year. Export growth has stagnated at just 1.6%, compared to 5.2% last year. Bank credit growth has also slowed, dropping from 15.2% last year to just 11.8%. Additionally, Rs 3.4 lakh crore in foreign exchange reserves have been withdrawn. In this context, it is imperative for the budget to include measures to boost credit availability and stimulate the economy. Yet, the central government appears to be using elections as a political tool, continuing its approach of prioritizing short-term gains over real solutions.

It is widely agreed that boosting the economy requires increased spending, greater capital investment, and policies that attract more investment while raising the income and purchasing power of the people. This necessitates high growth rates across all sectors, including manufacturing, agriculture, and services. The state must ensure that growth benefits are distributed throughout the country, necessitating a unified policy approach. Unfortunately, such a policy is absent in this year's Union Budget.

The vision for a developed India by 2047 a country celebrating 100 years of independence emphasizes infrastructure development, job creation, and quality education. This "Developed India" vision has been a central theme in every Union Budget since Prime Minister Narendra Modi introduced it in 2022. However, while the roadmap is clear, the government will face numerous challenges in turning this vision into reality. The current economic slowdown, driven by insufficient investment, a lack of capital, and limited private sector participation, is impeding the pace of transformation.

According to the National Statistical Office (NSO), India's GDP growth rate has slowed from 8.2% in 2023-24 to 6.4% in 2024-25. These "Advance Estimates" are forward-looking projections based on available data and will be revised as more information becomes available. This figure is below the 6.5-7% range projected by the Economic Survey. The growth rate of monthly GDP is projected at just 9.7%, down from 10.5% projected in last year's Union Budget. Efforts to improve infrastructure are underway, but the pace has been slower than expected due to challenges in road development, energy production, and technology advancement. Additionally, regional disparities continue to complicate the situation.

The growth of job opportunities is not keeping pace with the increasing demand for employment. Unemployment is projected to be 7.7% by 2024, a significant improvement compared to previous years but still far from ideal. The self-employment sector is growing, but income levels for self-employed

individuals have not seen comparable growth, partly due to the increasing number of self-employed individuals and the lack of skilled workers. A study by the National Skill Development Corporation (NSDC) reveals that a significant portion of the unemployed population consists of graduates and youth from rural areas. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS), which supported rural economies during the pandemic, has not seen any substantial budgetary impact. The budget allocation for the Rural Livelihoods Development Scheme has remained stagnant at Rs 86,000 crore for the past two years. There is also a significant gap between the demand and supply of trained nurses in India, with a deficit of 29 million nurses.

The Finance Minister stated in her Budget speech that the 2025-26 Budget would focus on increasing consumption, particularly among the poor and middle class, and expanding the tax base. The government expects a Rs 1 lakh crore revenue loss, which it believes will result in greater income for the middle class, thereby boosting consumption, savings, and investment. However, the reality is that the real income of many people is declining, making it increasingly difficult for them to afford tax payments. While tax breaks may benefit higher-income urban taxpayers, they will not have a significant impact on the larger middle class. Although these measures may create political gains, the government will still face considerable challenges in achieving the goal of a developed India and securing the necessary capital.

The Union Budget attempts to present a sense of relief through income tax reforms. While individuals with annual incomes up to Rs 12 lakh are eligible for income tax exemptions, those in higher income brackets will not see significant changes. However, these exemptions will benefit only lower-income groups. To access these benefits, taxpayers must choose the new scheme, which includes deductions for housing loan repayments, children's tuition fees, savings under the Simple Savings Scheme, contributions to the Distress Relief Fund, and life and health insurance premiums.

The announcement by Finance Minister Nirmala Sitharaman that middle-class individuals with annual incomes up to Rs 12 lakh will not be taxed has generated much discussion. However, detailed budget figures suggest that the middle class is expected to bear a larger tax burden in the next financial year. Government projections indicate that the increase in personal income tax will outpace increases in corporate tax, GST, and customs duties.

The question remains: are taxpayers truly receiving more money in the broader economic context? The Finance Minister claims that the Rs 1 lakh crore loss in tax revenue will serve as an economic stimulus. However, the receipts budget reveals that the bulk of the tax burden in the coming year will fall on individuals. India's income tax system includes both personal and corporate income taxes, with personal income tax contributing a significant portion to the total revenue. Projections indicate that personal income tax will account for one-third of the total tax revenue for the current financial year.

Let's examine whether middle-class incomes will rise in the next financial year. Personal income in the middle class is expected to increase by 14%, reaching Rs 14.38 lakh crore. However, the growth in corporate tax, GST, and excise duties, which reflect industrial and economic growth, has not kept pace with income tax growth. Corporate tax is expected to increase by only 10%, while GST collection is projected to grow by 11%, Inflation, as estimated by the Reserve Bank, will be 4.5% in 2025-26.

Given these figures, the Economic Survey's projected GDP growth rate of 6.3-6.8% for industry and business suggests that the government does not anticipate significant economic growth. In short, the central government is not even expecting the 8% growth needed to achieve the "Developed India" goal for 2047. The question is: where will the additional tax revenue come from? The projected Rs 42.70 lakh crore in tax revenue for 2025-26 will primarily come from personal income tax, with the middle class shouldering a larger share of the burden.

Whatever the Finance Minister claims, the figures suggest that the government's primary tax source is personal income. The middle class is the one paying these taxes. So, can we truly expect that more money will flow to the middle class for their economic upliftment through the new tax guidelines? The overall economic figures do not seem to support this claim.

Anti-Kerala Budget

The central government has once again ignored Kerala's fundamental needs in this Budget. Despite repeated calls for a special economic package to address significant cuts in central financial allocations, the government has not listened. Kerala's issues, including the Vizhinjam International Airport Project, the largest export promotion project in India in the last two decades, have not received adequate support. The government's continued neglect of the people of Wayanad, who have suffered severe hardships, is

concerning. Once again, the budget presented appears to be against Kerala, overlooking critical issues like rubber production.

There is no approach that treats all states equally. Many announcements have focused on specific states, such as Bihar, with little effort to address the needs of other regions. The Delhi Assembly elections have also created the impression that the government's efforts do not align with their intended goals.

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): I thank the hon. Union Finance Minister, Nirmala Sitharaman ji for presenting a blockbuster budget.

- This budget paves the way for a "Viksit Bharat - Developed India"
- The main focus of this budget has been tax reforms, agriculture, tourism, and strengthening infrastructure, development rural and mountain regions.
- The budget not only continues with the highest Capital Expenditure (CapEx) ever
- But also takes radical steps towards energizing domestic demands
- I also take time to congratulate Hon^{ble} Finance Minister
- As she created a historic milestone by becoming the only Finance Minister in the History of Independent India
- To present eight consecutive Union Budgets
- This remarkable feat not only highlights her adept stewardship of our economy.
- But it also celebrates the empowering force of "Nari Shakti" in our nation.
- In the FY 2014-15 the Capital Expenditure (CapEx) incurred by the Central Govt was **only ₹2.5 Lakh crore**
- The CapEx for Budget this year, including support to State CapEx has been pegged at ₹15.5Lakh Crore
- This is nearly 7 times or 700% increase in investment by the government
- This is also 15% above the YoY FY25 revised estimates
- In percentage of GDP terms, the FY26 budget capex is at 4.3% of GDP, the highest ever.
- As I mentioned, this budget will have tremendous impact in boosting and energizing domestic demand

- The budget offers substantial income tax relief to the middle class.
- There is tax on income up to ₹12 lakh under the new regime, and up to ₹12.75 lakh for salaried individuals due to the standard deduction
- This provides greater disposable income to our middle class families.
- Which will have direct impact on the domestic demands
- On behalf of all the citizens of our nation, I thank the Finance Minister for this
- The budget sets a forward-looking agenda for tourism development
- Especially in rural and underdeveloped mountain regions.
- The proposal includes the development of 50 key tourism sites
- The government will introduce a modified UDAAN regional connectivity scheme.
- This will help enhance air travel to 120 new destinations
- Focus will be on smaller airports, helipads, and infrastructure improvements in hilly and aspirational districts.
- Furthermore, the budget is emphasizing on the development of Buddhist Tourism Circuit and Homestay tourism
- This will not only spur tourism, but it will also generate employment, benefiting local economies.
- This will be greatly beneficial for mountain regions like our Darjeeling hills, Terai and Dooars region
- The budget includes several new initiatives to boost agricultural productivity and sustainability:
 - The **Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana** will extend its benefits to 100 districts, covering 1.7 crore farmers.
 - **Mission for Aatmanirbharta in Pulses**
 - **Mission for Cotton Productivity**
 - **New urea plant in Assam**
- All will ensure the sustainability of our Agricultural Sector
- Under their leadership, the financial security of people in our nation, especially in rural regions have increased manifold.
- In 2013-14, for the farmers:

- **Formal institutional credit:** 64%
- **Non-institutional credit:** 36%
- In past 10 years
 - **Formal institutional credit:** 75%
 - **Non-institutional credit:** 25%
- Today, more and more farmers are getting connected with formal financial sector
- Thanks to the Jandhan, Aadhar and Mobile (**JAM**) **trinity** initiated by PM Modi ji
- Today, less and less farmers are getting exploited by money lenders ? thanks to the inclusive policies of our government
- In this budget the Kisan Credit Card (KCC) loan limit has increased from ₹3L to ₹5L
- This will **benefit 7.7 Cr farmers** with better access to working capital.
- This will result in higher rural spending & economic growth.

Infrastructure Development

- Investment in infrastructure will see a boost, with significant increase in capital expenditure allocation.
- ₹1 lakh crore has been allocated to the Urban Challenge Fund, which will redevelop cities and improve water and sanitation systems.
- In rural areas, the Jal Jeevan Mission will ensure 100% potable water access by 2028.
- ₹1.5 lakh crore has been allocated for infrastructure spending in states through interest-free loans.
- This will help boost state-level infrastructure projects, providing a key financial push for long-term regional growth.
- Region like Darjeeling hills, Terai and Dooars are set to benefit from this.
- Support for MSMEs and startups is enhanced through improved credit facilities and a new Fund of Funds for Startups will be set up.
- There are more than **1 Cr registered MSMEs** in India today
- They **employ** around **7.5?8 Cr people**
- Together they contribute **36% of manufacturing & 45% of exports** of our country.

- In this budget, **credit limits** for MSMEs is being **increased** from **₹5 Cr** to **₹10 Cr**
- This will add ₹1.5L Cr in credit over 5 years.
- The Govt is also introducing customized credit cards with a ₹5L limit for micro enterprises registered on the Udyam portal
- Higher working capital will boost MSME productivity.
- This will help increase domestic demand for raw materials, goods & services will increase
- Collectively it will lead to greater employment generation for our youths.
- The government continues to prioritize education and innovation as vital engines of growth.
- Budget allocation for the Ministry of Education has reached **₹1.28lakh crore**
 - School Education & Literacy highest-ever allocation of **₹78,572 crore**
 - Higher Education **₹50,077.95**
 - Research development and innovation **₹20,000**
 - **50,000 Atal Tinkering Labs** will be established
 - **10,000 PM Research Fellowships**
 - **National Centres of Excellence for Skilling**
 - **Centre of Excellence for Artificial Intelligence for Education ₹500 crore**
- The overall healthcare allocation, including revenue and capital components **₹123 Lakh crore**
- Healthcare for Rural and Urban Poor
 - Day-care Cancer centres to be established in district hospitals across India, with 200 centres set to open in 2025-26 alone.
- Saksham Anganwadi and Poshan 2.0:
 - Enhanced nutrition support through Saksham Anganwadi and Poshan 2.0
 - Covering over 8 crore children and 1 crore pregnant women, as well as 20 lakh adolescent girls
- Expansion of Medical Education
 - An additional 10,000 UG and PG medical seats will be added in FY25-26
 - 75000 new seats over the next 5 years to be added

- Over the past 10 years, 1.1 lakh new medical seats have been created
- Exempting life-saving medicines
 - 36 life-saving medicines from basic customs duty (BCD)
- Healthcare for Gig Workers
 - Extend healthcare benefits to nearly 1 crore gig workers through PM-Jan Arogya Yojana (PM-JAY)
- Atmanirbhar Healthcare Initiatives will focus on increasing access to medical services for rural and underserved areas.
- Strengthening Healthcare Infrastructure
 - Investment in public health systems will be bolstered, particularly in rural regions, through the expansion of healthcare facilities and services.
- India's medical tourism market is projected to reach \$13 billion by 2026

Darjeeling

- Resource rich region
- Leaders of Tourism in the world
- Hub of best tea in the world ? Darjeeling tea
- Immense potential for cross border trade and commerce
- Produces millions of rupees? worth of hydroelectricity
- Famous for its oranges, cardamom, floriculture, fruits and vegetables
- Sir, the WB Govt had kept our region so deprived that majority of our villages did not have access roads
- People had to walk for hours to access schooling, health care, colleges
- There was no provision for drinking water
- No efforts at improving the life and living standards of the people
- However, I say this with pride, in the past 5-years the Central Govt is helping transform our region
- Our Govt is spending nearly Rs 50000 crores in various infrastructure projects in Darjeeling hills, Terai, Dooars and NB region

- **1100mtrs long Atal Setu** connecting Darjeeling to Sikkim at **₹133.49 crores** complete
- **Kalimpong to Damdim Alternative Highway** at **₹350 crores** complete
- Rapid progress on the **National Highway 717A** project at **₹2408 crores** underway
- **NH10** getting refurbished and upgradation work at **₹2000 crores** underway
- **Balason, Sevoke Elevated Highway Corridor** project worth **₹1000 crores** underway
- Allocation of **₹1400 crore** for **Sevoke to Teesta Elevated Corridor**
- **₹3500 crore** for **Bagdogra Airport Expansion**
- **Sevoke-Rangpo Rail Line** at **Rs 12000 crores** underway.
- **Historic Tindharey Railway Workshop** being upgraded
- **2 Vande Bharat** train connecting **Siliguri to Howrah & Siliguri to Guwahati** introduced
- **NJP Railway Station Modernization** project at **Rs 350 crore** underway
- **714 projects** worth around **₹2450.34 crores** for **Har Ghar Jal** schemes
- **₹1985 crore** worth projects in Municipalities of Darjeeling, Siliguri, Mirik, Kalimpong
- Total Road Sanctioned: **6972kms under PMGSY since 2019**
- Total funds allocated: **₹4053 crores**
- **Upgradation** of All India Radio Kurseong Station to **Hub of Nepali Language Programs**
- **Bagdogra Airport** being upgraded with new terminals worth **₹3000 crores**.
- Central Govt has allocated around **₹211 crores** for augmenting health care facilities
 - Upgradation of Block Health Centre, Primary Health Centre across Darjeeling, Kalimpong, Siliguri region
- **₹150 crore** for the development of **Critical Care Unit** at NBMCH
- While the Central Govt is working
- WB Govt has stopped working for our region
- Sir, every year, a revenue over **₹25000-30000 crores** are **drained out** of our Darjeeling hills, Terai, Dooars region by WB Govt
- Only a fraction of this is returned as investment for development

- Most of the money is used to pay interest on the Debt accrued by TMC Govt ? around **₹7 Lakh crores**
- Under the succeeding WB Governments, Darjeeling hills, Terai and Dooars has suffered
- 1988-2010 ? Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC)
- 2011 ? Gorkhaland Territorial Administration (GTA)
- Both supposed to be autonomous ? but has been made to fail by WB Govt
- Because of this, there has been massive deprivation
- Zero investment was made towards augmenting infrastructure in the region
- Internet, Mobile, Communication and Transport Connectivity was severely lacking
- Schools and Colleges infrastructure crumbling ? Lack of qualified teachers
- We don't have proper medical facilities
 - **AIIMS North Bengal was taken to South Bengal by TMC Govt**
- We don't have technical colleges ? No IITs, NITs, IIMS in the entire North Bengal region
- Existing State Universities not able to cater to the needs of modern education
 - Universities running without buildings or permanent faculty
- The Gorkha contribution to nation building is immense
- Freedom Fighters
 - Helen Lepcha, Dal Bahadur Giri, Sahid Durga Malla,
 - INA Capt Ram Singh Thakuri, Dalbir Singh Lohar, Bhakta Bahadur Pradhan, and hundreds of others
- But we are labelled as Foreigners
- Recently even a Supreme Court judge called Gorkhas ?foreign origin?
- We did not immigrate ? our borders changed
- We were part of Sikkim, then Bhutan, then Nepal, then British
- People remained, borders changed
- How can we be considered foreigners in our own country?
- We are indigenous to these land

- But every time we ask for our constitutional rights we are labelled as 'foreigners'?
- It is this 'crisis of identity' which needs to be addressed
- Darjeeling ? in the constituency, there is mass influx of illegal Rohingys and Bangladeshi immigrants
- Majority of our border districts are seeing massive demographic changes
- This is causing the indigenous people ? Gorkha, Rajbangshi, Adivasi, Bengali, Hindi Bhasi and others to become marginalised in our land
- This is the reason why, people in Darjeeling hills, Terai and Dooars have been demanding a separate state Gorkhaland
- Our Govt has assured the people, a Permanent Political Solution will be arrived at, they are waiting
- They have been patient ? further delay will only aggravate the situation
- Darjeeling hills, Terai, and Dooars people eagerly await justice for the 11 left-out Gorkha sub-tribes
- These sub-tribes are ? Bhujel, Gurung, Mangar, Newar, Jogi, Khas, Rai, Sunwar, Thami, Yakha (Dewan) and Dhimal.
- Until 1947, these communities were considered Hill Tribes, as per the census of 1931 and 1941.
- The region was governed as a Scheduled District and Excluded Area, a form of governance applied only to Tribal regions.
- However, after Independence, their Scheduled Tribe (ST) status was revoked without consultation, depriving them of their tribal heritage.
- I want to ask the Government, have the Gorkhas not sacrificed enough for our nation?
- The indigenous Gorkhas are suffering, compromising their language, culture, and traditions.
- Protection of the Gorkha community is vital for national security, achievable by promptly reinstating ST status for the 11 sub-tribes.
- It is because of this systematic deprivation and 'crisis of identity'?
- The people from our region have struggled for a state of our own called Gorkhaland
- They believe in the leadership of Hon'ble PM Modi ji

- Our party has committed to Permanent Political Solution for the Darjeeling hills, Terai and Dooars region
- Our constitution guarantees equality for all and justice for all
- But people from Darjeeling hills, Terai and Dooars are waiting for justice for the past 77-years since Independence.
- Hence, I request the Union Government to fulfil these commitments
- Gorkhas are awaiting justice ? time has come to fulfil ?Gorkhaon ka Sapna?
- I therefore request the Govt for re-inclusion of 11 left-out Gorkha sub-tribes as ST, and
- Constitutional Solution for Darjeeling Hills, Terai and Dooars
- I request the Hon?ble Finance Minister to kindly allocate funds for our Darjeeling hills, Terai and Dooars region,
- Darjeeling hub of school education, but no University

Establishment of Central University Can attract international students from Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam, Thailand

- Over 3 crore people of North Bengal don?t have a central medical facility
- Acute lack of doctors, nurses, equipment, facilities
- AIIMS North Bengal is needed
- In Oct 2023, massive flood engulfed river Teesta ? over 500 families have been severely impacted
- But, till date WB Govt has refused to declare it as a disaster till date
- Official designation of "disaster" would enable the WB Govt to spend up to 10% of the annual allocation under the State Disaster Response Fund (SDRF) to provide support to the victims of this Natural Disaster.
- For WB, the SDRF allocation for the Financial Year 2023-24 is Rs 1189.60 crores
 - Out of which Rs 892 crores is Central Contribution
 - And Rs 297.60 is the WB State Contribution.
 - 10% of Rs 1189.60 crores is Rs 118.96 crores, which the WB Govt can use to help the Teesta Flood victims.

- But they haven't done so till date
- Victims of same Teesta tragedy are deprived of financial support, which people in Sikkim are getting, but Darjeeling and Kalimpong citizens are not
- Requesting Hon?ble Finance Minister to allocate financial support to Teesta Victims
- North Bengal is home to the most diverse socio-cultural and linguistic heritage in our nation.
- Among the various sub-groups one of the largest groups are the Rajbangshi people whose proud history, culture and socio-linguistic identity is gradually vanishing,
- This is happening, because their mother tongue Rajbagshi/Kamtapuri bhasa is yet to be recognized under the 8th Schedule of our Constitution.
- Despite their language being recognized as one of the official state languages of West Bengal
- No effort has been undertaken by the WB Govt to promote their language
- The Rajbangshis are indigenous to our North Bengal and Assam region
- Today, sadly their culture is under threat, due to increasing illegal immigration ? especially Rohingyas being settled in their areas for ?Vote Bank?
- Their language needs to be protected
- I therefore request the Hon?ble Home Minister to kindly ensure the protection of Rajbangshi/Kamtapuri language, heritage and culture by including Rajbagshi/Kamtapuri in the 8th Schedule of our Constitution.
- I also request the Hon?ble Minister of Information and Broadcasting to kindly initiate All India Radio and Dooardarshan programs in Rajbangshi/Kamtapuri languages
- Rural roads in hilly areas usually don?t get approved under PMGSY due to discrimination by the WB Govt
- Construction costs in mountainous regions are substantially higher compared to plains due to increased transportation expenses.
- Frequent road disruptions, and limited availability of local construction materials is a hinderance
- Because of this, a hundreds of villages in our region are not connected

- I am requesting for a Special Allocation for the development of Rural Roads in Darjeeling and Kalimpong districts
- The famed Darjeeling Tea Industry is facing existential crisis
- Due to the lack of support from the Tea Board, and the State Govt
- Darjeeling Tea Industry has seen multiple disruptions
- But despite that, no support or subsidy has been provided to the industry
- TMC wants the tea gardens to shut down
- They are only using the tea industry as a 'land bank' for real-estate developers
- Many of the gardens are running in loss
- There is a legitimate fear that Darjeeling Tea may cease to exist, if proper steps are not taken to correct the situation
- **A special one-time special financial package in the form of PLI or Subsidy should be given to the Darjeeling Tea Industry to resurrect the industry**
- **Small tea growers** today account for over 50% of the total tea production in North Bengal
- However, they are yet to get the same level of benefits and support as the established big tea companies
- There is a need to embrace change. Small growers need to be made a part of the system and not kept outside the system
- Financial Support for Small growers
- **Distribution of Welfare Funds directly to Tea Garden Workers**
- Funds for improvement of infrastructure
- Our region shares four international border
- Also our region is gateway to N.E States
- There is immense potential of trade, commerce and tourism
- But we severely lack infrastructure
- Hence, request for additional funds for Highway and Roads in Darjeeling hills, Terai and Dooars
- Especially fund for expediting

- Siliguri Ring Road Project
- Alternative to Coronation bridge project
- Alternative Highway to Darjeeling project
- Building Bridges in various rivers across Darjeeling and Kalimpong region
- Darjeeling, Kalimpong, Sikkim, and Bodhgaya in Bihar are home to the most important Buddhist pilgrimages in the country
- Sikkim is headquarters of the Black-Hat Karmakagyu sect, Darjeeling is headquarters of the Drukpa Kagyu sect, and Bodh Gaya is strongly associated with Buddha Bhagwan
- Buddhist Circuit has been identified as one of the fifteen thematic circuits for development under Swadesh Darshan Scheme under the Ministry.
- Initiating projects under the Buddhist Tourism Circuit connecting, Darjeeling, Kalimpong, Sikkim and Bodh Gaya- including starting to new trains, will benefit BJP
- There are many villages in our region, that are yet to be connected by road
- Given mountain region, making road will be high cost venture
- Also, fragile geography will make roads construction difficult
- Hence, I am requesting funds for construction of Ropeways to connect these places, through the Parvatmala Project
- In Darjeeling and Kalimpong, Cinchona Plantation have played historic role in curbing malaria
- However, under WB Govt the cinchona plantations are suffering
- I am requesting for funds to convert the Cinchona Plantations to Medicinal Plants Hub
- So that we can use the manpower, land and knowledge of the people to grow medicinal plants, which can be exported internationally
 - The ICDS and Aganwadi workers are some of the most hard working
 - Because of them, rural health matrixes are improving across the country
 - However, their salaries have remained stagnant
 - Especially in the mountains, these hard working ICDS and Aganwadi Workers have to talk in difficult terrain for hours

- I am therefore requesting you to kindly increase their salaries and emoluments
- In the Darjeeling hills, Terai and Dooars region, there is still acute shortage of doctors, nurses and other medical staff.
- Hospitals have shortage of equipment and infrastructure
- Being mountain region, transportation is difficult, especially during Monsoon
- Health being a primary necessity, I am requesting for additional funds for improving Primary and Block Level Health Facilities in our region.
- Many sportspersons from my constituency have represented our nation in different National/International events.
- Despite the lack of sports infrastructure, training facilities, or any institutional support, they have brought laurels for our country
- Youths from the region are naturally athletic, with a little support and training facilities, they can bring Olympic Medals for India
- Request to establish Khelo India centres in Siliguri Darjeeling, and Kalimpong
- We also need development of world class stadiums in Siliguri, Darjeeling and Kalimpong
- In the recent Budget placed by the Hon?ble Finance Minister, she has mentioned that the government will introduce a modified UDAAN regional connectivity scheme
- Including focusing on the development of smaller airports, helipads, and infrastructure improvements in hilly and aspirational districts.
- Given that Darjeeling and Kalimpong region attract the largest number of tourists in the eastern Himalayan region
- I feel that starting daily helicopter services to the hills in the above mentioned places in the districts of Darjeeling and Kalimpong, will further strengthen air connectivity on our region, and
- It will also act as a catalyst for boosting tourism in our region.
- Hence, I request a daily helicopter service between Bagdogra, Darjeeling, Mirik, Bijanbari, Kurseong and Kalimpong

- This will help boost tourism and also help locals in emergency situation by saving commuting time

In the past 10-years, the West Bengal Govt under Chief Minister Mamata Banerjee has incurred huge debt. This has been a result of their faulty economic policies and priorities. Instead of deploying productive capital for the development of infrastructure, educational institutes, health facilities, and other employment generating and growth inducing efforts, the West Bengal Govt has indulged in wasteful spending of capital. As a result, the burden of debt on the state and its people has been steadily rising.

The state has been struggling with both fiscal and revenue deficits.

Revenue Deficit happens when the Govt spends more than it earns, and in the past five years the revenue deficit for West Bengal has been over ₹1.08 Lakh crores. In the same period the Fiscal Deficit, which measures the difference between government's total expenditure and its total revenue, has increased by ₹2.41 Lakh crores. The overall debt burden on the state has grown up to over ₹7 lakh crores, and in the past fiscal year alone, over ₹42000 crores was spent by the TMC Govt towards servicing this debt. For a revenue deprived state, one can imagine the immense pressure the debt burden puts on the people.

Source: WB Budget documents and PRS

West Bengal Budget Summarized		
Financial Year	Fiscal Deficit	Revenue Deficit
2019-20	₹36831 crore	₹19661 crore
2020-21	₹44688 crore	₹29527 crore
2021-22	₹50528 crore	₹32000 crore
2022-23	₹49966 crore	₹27295 crore
2023-24	₹59306 crore (revised estimate)	₹28253 crore (revised estimate)
Total	₹241310 crore	₹108483 crores

In the past five years alone the revenue shortfall was ₹1.08 Lakh crores, and the WB govt overspent Rs 2.42 lakh crore, most of it borrowed from the market. Unable to meet their financial obligations, the West Bengal government introduced a policy of converting the status of commercial land from leasehold to freehold, for a fees.

This is being done by a highly inefficient and corrupt government to shore up their revenue to meet their financial obligations.

Under the leasehold system, the government remained the owner and commercial properties were leased out for a period ranging from 30-years to 99-years, and those land could be used for the specific purposes for which they were handed out. But the WB Govt is now handing over land to corporations on a freehold basis.

A freehold property means the owner has complete and absolute ownership of the land, which means the corporations can do whatever they want to with the land, and the government will have no say in it. In short, the WB Govt is selling off the public land to private companies for generating revenue, as all other sources of revenue have dried up in the state.

In this background, the announcement by the WB Chief Minister Mamata Banerjee in the recent edition of Bengal Business Summit of allowing 30% land in the tea gardens to be diverted to non-tea purposes presents a clear and present danger to the indigenous Gorkhas, Adivasis, Rajbangshis, Bengali, Rabha, Koche, Meche, Toto, and other communities of Darjeeling hills, Terai and Dooars.

For generations the tea garden and cinchona garden workers from our region have been denied and deprived rights to their ancestral land by succeeding West Bengal government. Majority of the tea garden workers have lived in these tea gardens since ancestral times, and well before our region was made a part of West Bengal state, which happened only in 1954.

Before its merger with West Bengal, the Darjeeling hills, Terai and Dooars were governed under a separate and unique administrative framework, on the virtue of the region being leased land governed by various treaties like the Deed of Grant between the British Crown and the Kingdom of Sikkim, and the Treaty of Sinchula with Bhutan.

From 1861 until 1870, the region was governed as a 'Non-Regulated Area,' from 1870-74 as a Regulated Area, from 1874-1919 as a Scheduled District, from 1919-1935 as a Backward Tract, and from 1935-47 as a Partially Excluded Area. As the British had leased Darjeeling from the Kingdom of Sikkim, the region was not directly part of British India. As a result, the laws and regulations applied to the rest of West Bengal were not automatically applicable to Darjeeling. Instead, the Governor of Bengal would have to specifically extend these laws to the region on a case-by-case basis, further contributing to its distinctive administrative history.

It is pertinent to note here that till 1954, the land laws of West Bengal were not applicable in Darjeeling tracts. It was only following the passing of The Absorbed Areas (Laws) Act, 1954, that rules and laws governing West Bengal were extended to Darjeeling also.

In 1955, when the West Bengal Estates Acquisition (Amendment) Act was passed, an amendment was made to the West Bengal Estates Acquisition (Amendment) Act, 1953 and the following amendment was made, *'Provided that in such portions of the district of Darjeeling as may be **declared by notification by the State Government to be hilly portions, an intermediary shall be entitled to retain all agricultural land in his khas possession, or any part thereof as may be chosen by him.**'*

Here, it is important to note that the 'intermediary' happen to be tenants/individuals who had been in possession of such agricultural land. Because of the limited wages granted by the Tea Companies under the British, almost all tea garden workers were allocated land for their personal agricultural purposes.

So going by the Act of 1955, all the people of Darjeeling District, which till 1970s comprised the Dooars region too, should have been allocated Parja Patta to the land they were using for their personal purposes, but this was not done. Instead, the Govt of WB has continued to deny the tea garden, and cinchona garden workers, those living in DI Fund land and Forest Villages in Darjeeling hills, Terai and Dooars right to Parja Patta of their ancestral land.

The threat of displacement faced by the indigenous people of the Darjeeling hills, Terai and Dooars following the diversion of 30% tea-garden to non-tea purposes cannot be overstated. Already the indigenous population has been diluted following unabated settlement of Rohingyas and illegal

Bangladeshi immigrants, who are being allowed to settle in the region by the State Government as their ? vote bank?.

The diversion of land from tea industry began at 15% in 2019 has already reached 30% in the 2025. The rate at which the TMC Government is going, it may soon permit entire tea gardens to be diverted. This is where the real threat to indigenous people of the region comes in. 99% of them have been kept deprived of Parja Patta to their ancestral lands, since the land are now being handed on ?freehold? basis, those corporations who have bought the land from the government will require the landless workers to evict from their land.

This is not a far-fetched conspiracy, we have witnessed this play out in Chandmuni tea garden near Darjeeling More in Matigara, where over 1500 workers, and their families (around 15000 individuals) were evicted to make way for the development of a gated housing society and a shopping mall. The workers were forcefully evicted and even shot at by the WB Police, with a former chief minister justifying the killing of the workers as being ?necessary?. I am fearful that such a scenario will unfold in the future, if due care is not taken today.

Since 2005, Foreign Direct Investment (FDI) in India's real estate and tourism sector has grown significantly. A critical geography like Darjeeling hills, Terai and Dooars that lie in the heart of India?s ? Chicken Neck? will attract immense interests, especially from the nations that are inimical to India?s interests. A freehold land system here, will give immense leverage to those interested in harming India.

As such, the WB Govt has completely failed to check the growing influences of foreign agencies or foreign funded terrorist organisations in the state. The National Investigation Agency (NIA) have busted several ISI agents, even Al Qaeda and JeM Bangladesh terrorist modules and networks from the state. The threat posing our nation by this dangerous policy proposed by TMC Govt in West Bengal is real.

The West Bengal government can demonstrate its commitment to the region by immediately initiating the process to grant Parja Patta to all the ancestral land of the tea garden workers, cinchona garden workers, DI Fund and Forest Villages. This would not only protect the land rights of the indigenous communities, but also ensure that the resources and benefits generated from these land are also accrued to the local people.

Darjeeling and Dooars tea are renowned globally, and they carry immense potential to generate employment and revenue, if given proper focus. Instead of using the tea garden land as land banks for the real-estate sector and short-term revenue generation sources, the WB Govt would be better served by transforming these gardens into sustainable profitable units. This can be achieved by either incentivising corporations to invest in these gardens through Production Linked Incentives (PLI) and better marketing for their tea internationally, or by empowering the tea garden workers to run the gardens as cooperatives.

The tea gardens in Darjeeling and Dooars are not just economic enterprises, rather they are the very thread that binds the people of our region together, and we will not allow this thread to be severed at any cost.

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर) : मैं बजट 2025- 26 पर अपने विचार रखता हूँ। यह सरकार दावे तो बड़े-बड़े करती है लेकिन जब गरीबों किसानों युवाओं तथा महिलाओं के लिए तथा विकसित भारत बनाने के लिए आर्थिक संसाधन मुहैया कराने की बारी आती है तो यह सरकार पूरी तरह असफल नजर आती है। कारण यही है कि इस सरकार का ध्यान जनहितकारी नीतियां बनाने की ओर न होकर बड़े पूंजीपतियों तथा धन-धान्य वर्ग की ओर अधिक केंद्रित है। उदाहरण के लिए केंद्रीय बजट 2025 - 26 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत 100 जिलों को शामिल किया गया है जिसमें 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, इस तरह की घोषणा कर देने मात्र से किसान लाभान्वित हो जाएगा क्या? क्योंकि पहले भी इस सरकार ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लोक लुभावना नारा दे चुकी है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज किसान महंगे खाद तथा किसानों पर उच्च लागत आने के कारण विषम आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं द्वारा खेती किसानों को इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वहां की सरकार हाथ पर हाथ रखी बैठी है, और किसान पूरी तरह बेसहारा और लाचार महसूस कर रहा है। इसी तरह बजट 2025-26 में यह घोषणा की गई है कि किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण की सीमा को तीन लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। जिन किसानों किसानों की जमीन नदी में विलीन हो गई, वह ऋण कैसे देगा। लेकिन बुनियादी सरकार सवाल यह है कि किसानों का ऋण सरकार माफ करे, किसानों की आय लगातार घटती जा रही है, क्योंकि खाद अत्यधिक महंगी है और कृषि में लागत ज्यादा तथा आय लगातार घटती जा रही है। कृषि में लागत ज्यादा तथा आय बहुत कम हो गई है। इस बुनियादी समस्या से निपटने के लिए इस बजट में एक भी ठोस कदम की झलक नहीं मिलती है। सरकार केवल हवा हवाई बातें करके किसानों का ध्यान भटकाने में लगी है जिसके कारण आज हमारे देश में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है और आज कोई भी किसान यह नहीं चाहता है कि उसके बच्चे खेती किसानों करें।

आज भी हमारे देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा वर्ग गांव में रहता है जिनमें अधिकतर लोग गरीब हैं और जीवन यापन के लिए विषम परिस्थितियों की सामना कर रहे हैं लेकिन उनके उत्थान के लिए तथा ग्रामीण भारत की चुनौतियों से निपटने के लिए इस बजट में कोई विजन नहीं है इस बजट में शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास तथा जल एवं स्वच्छता को समर्थन देने के लिए 2025-26 के लिए 10,000 (दस हजार) करोड़ रुपए आवंटित किया गया है परंतु आज हमारे शहरों की जो हालात हैं तथा गांव की अपेक्षा के कारण शहरों पर जो दबाव बढ़ा है। उसे देखते हुए 10,000 करोड़ रुपए की यह धनराशि ऊंट के मुंह में जीरा की तरह है।

हमारे देश में स्वास्थ्य तथा रोगों के महंगे इलाज पर आम आदमी जो पैसा खर्च करता है उससे उसकी आर्थिक स्थिति डाँवाडोल हो जाती है। नीति आयोग ने भी अपनी एक रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है की रोगों के इलाज पर होने वाले खर्च के चलते हमारे देश की लगभग 10 करोड़ जनता हर साल गरीबों की रेखा के नीचे चली जाती है। इसको रोकने के लिए जरूरी है स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च बढ़ाया जाए ताकि जनता को अपने पाकेट से रोगों के इलाज पर खर्च न करना पड़े। जब जेटली जी वित्त मंत्री थे तब सरकार ने यह घोषणा की थी कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च को सन् 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद (अर्थात् जीडीपी) के 2.5 प्रतिशत तक किया जाएगा। 2025 आ भी गया सरकार द्वारा नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट (NATIONAL HEALTH ACCOUNT ESTIMATE) 2021-2022 अभी हाल ही में जारी किया गया है। इसमें दिए गए आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च अभी भी जीडीपी अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.8 प्रतिशत है। जाहिर है कि यह सरकार पूँजीपतियों तथा धन्ना सेठों को करोड़ों रुपए के कर्ज माफ कर रही है लेकिन स्वास्थ्य जैसे बुनियादी सेवाओं पर पर्याप्त बजट आवंटित नहीं कर रही है।

ग्रामीण भारत गरीब, दलित, पिछड़े तथा अल्पसंख्यक इस सरकार के लिए प्राथमिकता में कहीं है ही नहीं। इस बजट में महंगाई को कम करने तथा रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है कुल मिलाकर यह बजट जन विरोधी, महंगाई बढ़ाने वाला तथा पूँजीपतियों के हित में है तथा आम जनता के लिए इसमें कुछ भी नहीं है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह लोक लुभावन नारों को छोड़कर गरीबों के हित के लिए ठोस नीतियां बनाये तथा युवाओं को रोजगार मुहैया कराये तभी हमारा देश विकसित भारत के पथ पर अग्रसर हो सकेगा।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर (दाहोद) : माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक ऐतिहासिक बजट जोकि अमृतकाल का मैं महत्वपूर्ण बजट भी है, को पेश करने के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीता रमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूँ।

हमारे देश का सौभाग्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अभी हाल में ही हमने देश के संविधान की 75 वीं वर्षगांठ मनाई है और उससे कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये लोकतंत्र का अमृतकाल है जिसमें भारत की

विकास की गंगा बिना किसी बाधा के तीसरे कार्यकाल में तीन गुना तेजी से निरंतर बह रही है

ये बजट फिर से भारत वर्ष को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने वाला बजट है जिससे स्पष्ट होजाता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के तीसरे कार्यकाल में भारत वर्ष आगामी पञ्चवर्षीय में, विकाशील भारत से विकसित भारत की ओर जाने वाली गाडी और भी सुपर फ़ास्ट स्पीड से दौड़ने लगी है । वर्ष 2047 का जो विकसित भारत लक्ष है माननीय प्रधानमंत्री की सरकार का विकास को देखते हुए लगता है कि वो पहले ही प्राप्त हो जाएगा ।

यह बजट करोड़ों भारतीय नागरिकों की आशाओं और सपनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसका उद्देश्य उन सपनों को सभी के लिए वास्तविकता बनाना है । हमने युवाओं के लिए रोमांचक अवसर खोले हैं, जो वास्तव में विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा का दिल हैं । इस बजट को एक शक्तिशाली बढ़ावा के रूप में सोचें जो हमें अधिक बचत करने, बुद्धिमानी से निवेश करने, बेहतर उपभोग करने और एक साथ बढ़ने में मदद करेगा ।

सम्पूर्ण भारत के लिए, आधुनिकता की दिशा में, पिछले दस सालों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं पिछले वर्षों में जो फैसले लिए गए, नीतियां बनीं, उसकी वजह से आज अर्थव्यवस्था का निरंतर विस्तार होगा ।

अमृतकाल के इस बजट से विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण हुआ है इसमें नौकरी पेशा नागरिकों को और वंचितों को वरीयता दी गई है ये बजट आज की आकांक्षा समाज - गांव-गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में ये बजट, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए, अनेक नए अवसर पैदा करने वाला ऐतिहासिक बजट है । ये बजट देश में अधिक तेज विकास, तेजी से बढ़ता नया बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश के नए स्रोत, अधिक नौकरियों की संभावनाओं से भरा हुआ है । सच में ये देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को भी सुनिश्चित करने वाला बजट है । विकसित भारत की आकांक्षाओं और संकल्पों को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण किया है । यह बजट वंचितों को वरीयता देता है और आकांक्षी समाज, गरीबों, गांवों और मध्यम वर्ग के सपनों को साकार करने का प्रयास करता है ।

यह बजट युवा, गरीब, महिला व किसान को सुदृढ़ करने वाला बजट है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने इन चारों को विकसित भारत का स्तंभ माना है । यह बजट विकसित भारत की नींव को मजबूत करने वाला बजट है ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अंतरिम बजट 2024-25 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कि 2023- 24 वर्ष के बजट आवंटन से 70 प्रतिशत अधिक था । और अब जनजातीय कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता है उसके चलते बजट आबंटन 2014-15 में 4,497.96 करोड़ रुपये से 231.83 प्रतिशत बढ़कर 2025-26 में 14,925.81 करोड़ रुपये हो गया है ।

भारत में 10.45 करोड़ से ज्यादा अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोग रहते हैं, जो कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत है। यह एक समृद्ध और विविधतापूर्ण आदिवासी विरासत का दावा करता है। दूरदराज और अक्सर दुर्गम क्षेत्रों में फैले ये समुदाय लंबे समय से सरकार के विकास एजेंडे का केंद्र बिंदु रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, केंद्रीय बजट 2025-26 जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए बजटीय आबंटन में पर्याप्त वृद्धि के साथ इस प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है, जिससे देश भर में आदिवासी समुदायों का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित होता है।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी कृपा से आप अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समग्र बजट आबंटन 2024-25 में 10,237.33 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 14,925.81 करोड़ रुपये हो गया है, जो 45.79 प्रतिशत अधिक है।

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) का विस्तार किया गया है और इसे पांच वर्षों में 80,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए बजट लागत में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, जो 2023-24 में 7,511.64 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 10,237.33 करोड़ रुपये हो गया है और अब 2025-26 में 14,925.81 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिलती है: 2014-15 में 4,497.96 करोड़ रुपये से बढ़कर 2021-22 में 7,411 करोड़ रुपये हो गई है, और अब 2014-15 से 231.83 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो जनजातीय कल्याण पर सरकार के लगातार फोकस को दर्शाता है।

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) : दूरदराज के क्षेत्रों में आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 7,088.60 करोड़ रुपये, जो विगत वर्ष के 4,748 करोड़ रुपये से लगभग दोगुना है।

प्रधानमंत्री जन जातीय विकास मिशन के अंतर्गत 152.32 करोड़ रुपये से बढ़कर 380.40 करोड़ रुपये, जिससे जनजातीय समुदायों के लिए वर्ष भर आय सृजन के अवसर सृजित करने के प्रयासों को बल मिलेगा।

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) के अंतर्गत आबंटन 163 प्रतिशत बढ़कर 335.97 करोड़ रुपये हुआ, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार में बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करना है।

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत बहुउद्देश्यीय केंद्र (एमपीसी), वित्त पोषण को 150 करोड़ रुपये से दोगुना कर 300 करोड़ रुपये किया गया, जिससे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) बहुल बस्तियों में सामाजिक-आर्थिक सहायता में वृद्धि हुई।

पीएम-जनमन की सफलता के आधार पर, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) का लक्ष्य पांच वर्षों में 79,156 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करना है (केंद्रीय हिस्सा: 56,333 करोड़ रुपये, राज्य हिस्सा: 22,823 करोड़ रुपये)। यह पहल 25 लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से 17 मंत्रालयों को एक

साथ लाती है, जिससे स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका और कौशल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एकीकृत आदिवासी विकास सुनिश्चित होता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत डीएजेजीयूए के लिए आबंटन 2025-26 में 500 करोड़ रुपये से चार गुना बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो जमीनी स्तर पर जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

"यह बजट जनजातीय कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसमें शिक्षा, आजीविका और बुनियादी ढांचे में केंद्रित निवेश के साथ उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया गया है। हमारी सरकार जनजातीय सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है।"

"प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, केंद्रीय बजट 2025-26 एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए समर्पित है। यह परिवर्तनकारी बजट गांवों, गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के समग्र विकास को प्राथमिकता देता है। इस ऐतिहासिक बजट को प्रस्तुत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार।"

जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव, श्री विभु नायर: "बढ़ा हुआ बजट हमें पीएम- जनमन, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान, ईएमआरएस और अन्य कार्यक्रमों जैसे परिवर्तनकारी कार्यक्रमों को लागू करने में सक्षम करेगा, जो पूरे भारत में जनजातीय समुदायों के लिए दीर्घकालिक, टिकाऊ प्रभाव पैदा करेंगे।"

केंद्रीय बजट 2025 आदिवासी विकास में एक बड़ा बदलाव है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। विभिन्न मंत्रालयों में लक्षित हस्तक्षेपों को एकीकृत करके, सरकार समावेशी विकास को बढ़ावा दे रही है और एक ऐसे विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त कर रही है, जहां आदिवासी समुदाय न केवल लाभार्थी हैं, बल्कि राष्ट्र की प्रगति में सक्रिय योगदानकर्ता भी हैं।

यह बजट देश के युवाओं को नए जोश से भर देता है एक नई दिशा देने की बात करता है। युवाओं की इनकम बढ़ने की पूरी पूरी उम्मित इस बजट में दिखती है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की लगातार युवाओं के लिए काम कर रही है। साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बन जाएगा और जिसकी बुनियाद आज युवा ही होंगे। अभी देश में 3 हजार नए आई.टी.आई खोले गए। इसका फायदा युवाओं को मिला है।

पिछले दशक से ही माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये सरकार युवाओं आस पर खरी उतर रही है और इस बार हर बार से बेहतर बजट भारत युवाओं को मिला है जब वित्त मंत्री जी ने बजट का पिटारा खोला तो उन्होंने युवाओं और छात्रों के लिए कई बड़े ऐलान किए। बजट में बड़े ऐलान करते हुए कहा कि सभी MSMEs के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया गया है। इससे उन्हें आगे बढ़ने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का आत्मविश्वास मिलेगा।

सरकार वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ कौशल विकास के लिए पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। पांच आईआईटी संस्थानों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। सरकार ने बताया कि बीते 10 वर्षों में आईआईटी संस्थानों में

पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 65 हजार से बढ़कर 1.35 लाख हो गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में बेहतर शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से एक कॉलेज स्थापित किया जाएगा। अगले साल मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10 हजार से ज्यादा अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले पांच वर्षों में 75 हजार सीटें जोड़ने का लक्ष्य है। अगले पांच वर्षों में पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना के अनुसार, आईआईटी और आईआईएससी में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10 हजार फेलोशिप प्रदान की जाएंगी।

उभरते युवा उद्यमियों के वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप के लिए 'फंड ऑफ फंड्स' योजना के एक और दौर की घोषणा की। एलान इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार स्टार्टअप के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

सरकार ने बजट में युवाओं को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप्स के लिए ऋण सीमा को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किया गया है। साथ ही 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण गारंटी को घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए पांच लाख रुपये की सीमा वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। पहले वर्ष में ऐसे 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। फंड ऑफ फंड्स का एलान किया है। सरकार ने फंड ऑफ फंड्स की स्थापना की है, जिसके तहत सरकार स्टार्टअप्स के लिए 10 हजार करोड़ की मदद देगी।

इस बजट में उन्होंने साफ कर दिया कि महिलाओं की ग्रोथ पर उनका पूरा फोकस है। अपनी 'विकसित भारत' की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बजट के सभी विकास की योजनाओं को गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी को केंद्र में रखकर बनाया है। इस बार के बजट में लोगों की कई उम्मीदें थीं और टैक्स में 12 लाख तक की छूट दे कर उन्होंने कई लोगों को राहत दी है। टैक्स स्लैब की खुशखबरी के अलावा आइए आपको बताते हैं कि महिलाओं को इस बजट में क्या खास मिला है।

भारत की इकनॉमी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ और लगभग 70% महिलाएं आर्थिक गतिविधियों से जुड़ें। वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट में उन्होंने महिलाओं के लिए बड़ा एलान किया है। भाषण के दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दो नई योजनाओं की घोषणा की है। पहली योजना के तहत, अगले पांच सालों में 5 लाख SC/ST महिला एंटरप्रेन्योर को 5 साल की अवधि के लिए टर्म लोन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत, अगले 5 सालों में इन उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन (ऋण) दिया जाएगा। यह योजना "Stand-Up India" योजना के सफल अनुभवों से सीखी गई बातों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी।

वहीं दूसरी योजना में, पहली बार बिजनेस की दुनिया में कदम रखने वाली 5 लाख SC/ST महिलाओं को अगले पांच सालों में सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, उद्यमिता और प्रबंधकीय कौशल (मैनेजमेंट स्किल्स) को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य इन समूहों को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे सफल बनाने में मदद करना है।

महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाई गई है, जो पहली बार उद्यमी (एंटरप्रेन्योर) बनने जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि इन महिलाओं को वित्तीय सहायता, ट्रेनिंग मेंटरशिप प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। सरकार पहली बार उद्यम शुरू करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये का लोन शुरू करेगी। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए खास स्कीम लाई गई है जिसमें एसएमई और बड़े उद्योगों के लिए एक विनिर्माण मिशन स्थापित करने, सरकार श्रम-प्रधान क्षेत्रों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सुविधाजनक करने कार्य भी किया जाएगा, लोन गारंटी 'कवर' को दोगुना करके 20 करोड़ रुपये किया जाएगा तथा गारंटी शुल्क को घटाकर एक प्रतिशत किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के पोषण को मजबूत बनाने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और POSHAN 210 स्कीम की भी शुरुआत की जाना है।

गुजरात में रेलवे के लिए 17,155 करोड़ रुपए का प्रावधान रखने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का विशेष आभार प्रकट करता हूँ।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के साथ-साथ गुजरात का रेलवे नेटवर्क भी विकास और विस्तार के स्वर्णिम कालखंड का साक्षी बन रहा है और विकसित भारत बजट-2025 से इस विकास यात्रा को और अधिक गति मिलने वाली है।

गुजरात में रेलवे के लिए मात्र ₹589 करोड़ की राशि दी गई थी, वहीं मोदी सरकार ने वर्ष 2025-26 में इसे 29 गुना बढ़ाकर ₹17,155 करोड़ करने की ऐतिहासिक घोषणा की है। बीते एक दशक में गुजरात में रेलवे ट्रैक्स के इलेक्ट्रिफिकेशन में भी 22 गुना वृद्धि हुई है और अब गुजरात के 97% रेलवे ट्रैक्स का इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ₹799 करोड़ की लागत से स्टेशन पुनर्विकास के कार्य किये जा रहे हैं। रेलवे नेटवर्क के इस कायाकल्प से गुजरात में व्यापार, उद्योग, यातायात और रोजगार को और भी अधिक बढ़ावा मिलेगा।

आने वाले दिनों में ₹6,303 करोड़ की लागत से गुजरात के 87 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इनमें अहमदाबाद, आणंद, अंकलेश्वर जामनगर, जूनागढ़ जंक्शन, महेसाणा जंक्शन, नवसारी, पोरबंदर, राजकोट जंक्शन वडोदरा और वापी प्रमुख हैं। इसके साथ-साथ ₹5,572 करोड़ की लागत से 7 प्रमुख स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य भी प्रगति पर है, जिनमें गांधीनगर राजधानी, साबरमती सोमनाथ, उधना, सूरत, न्यू भुज और अहमदाबाद शामिल हैं।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना कृषि जिला विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि विकास का पहला इंजन होगा। प्रथम चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा।

आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम की तर्ज पर कृषि जिलों का विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाएं और ऋण की उपलब्धता से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। इस योजना में फसल विविधीकरण को अपनाया जाएगा, फसल कटाई के बाद भंडारण को बढ़ाया जाएगा।

यह कार्यक्रम राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा, जिसमें कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।

कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के माध्यम से कृषि में अल्प-रोजगार की समस्या को दूर करने के लिए राज्यों के साथ साझेदारी में एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

सरकार तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित करते हुए 6 साल का "दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन" शुरू करेगी। नैफेड और एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों के दौरान किसानों से इन दालों की खरीद करेंगे।

राज्यों के साथ साझेदारी में किसानों के लिए उत्पादन, कुशल आपूर्ति, प्रसंस्करण और लाभकारी मूल्य को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

उच्च उपज वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा जिसका उद्देश्य अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, उच्च उपज वाले बीजों का लक्षित विकास और प्रसार तथा 100 से अधिक बीज किस्मों की व्यावसायिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

सरकार भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागरों से मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए एक रूपरेखा लाएगी, जिसमें अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कपास की खेती की उत्पादकता और स्थिरता में महत्वपूर्ण सुधार लाने तथा अतिरिक्त लंबे रेशे वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा देने के लिए 5-वर्षीय मिशन की घोषणा की गई।

केसीसी के माध्यम से लिए गए ऋणों के लिए संशोधित ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की जाएगी।

असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा।

इस बजट में reform की दिशा में अहम कदम उठाए गए हैं। Nuclear Energy में Private Sector को बढ़ावा देने का फैसला बहुत ऐतिहासिक है। इससे आने वाले समय में देश के विकास में Civil Nuclear Energy का बड़ा योगदान सुनिश्चित होगा। बजट में हर तरह से रोजगार के सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं दो बातों जो आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। एक- Infrastructure को दर्जा मिलने से भारत में बड़े जहाजों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी और हम सब जानते हैं कि जहाज निर्माण ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख 'सूर्योदय क्षेत्रों' में से एक के रूप में जाना जाने वाला भारतीय मत्स्य पालन क्षेत्र अपनी पहचान बनाना जारी रखता है और बहुत ही स्वस्थ गति से बढ़ता है, जो कृषि के तहत संबद्ध क्षेत्रों में उत्पादन के मूल्य (वित्त वर्ष 2014-15 से 2022-23) में 9.08% की उच्चतम औसत वार्षिक दशकीय वृद्धि दर्ज करता है (नीति आयोग रिपोर्ट 2024)। इस विकास की कहानी भारत की वैश्विक रैंकिंग द्वारा चिह्नित है, जो वैश्विक मछली उत्पादन में ~ 8% हिस्सेदारी और 184.02 लाख टन (2023-24) के रिकॉर्ड उच्च मछली उत्पादन के साथ दूसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक देश के रूप में है। भारत 2023-24 में 139.07 लाख टन के साथ जलीय कृषि उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है और 60,524 करोड़ रुपये (2023-24) के कुल निर्यात मूल्य के साथ दुनिया में शीर्ष झींगा उत्पादक और समुद्री भोजन निर्यातक देशों में से एक है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के आदर्श वाक्य के साथ, भारत सरकार 2047 तक विकसित भारत की दिशा में एक प्रमुख चालक के रूप में मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दे रही है। इसी तरह देश में पर्यटन की भी बहुत संभावनाएं हैं। पहली बार 50 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर बनने वाले होटलों को इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर पर्यटन पर बहुत जोर दिया गया है। ये हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और पर्यटन जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, उसे एक तरह से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करके ऊर्जा देने का काम करेगा। आज देश विकास और विरासत के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। इस बजट में इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। एक करोड़ पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन शुरू किया गया है। इसके साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी भी बनाई जाएगी। यानी तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा और हमारे पारंपरिक ज्ञान से अमृत निकालने का काम भी किया जाएगा।

बजट में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए 2,703.67 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे अधिक कुल वार्षिक बजटीय समर्थन प्रस्तावित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह समग्र आवंटन पिछले वर्ष 2024-25 के दौरान किए गए 2,616.44 करोड़ रुपये (बीई) के आवंटन की तुलना में 3.3% अधिक है। इसमें वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 2,465 करोड़ रुपये का आवंटन शामिल है, जो वर्ष 2024-25 (2,352 करोड़ रुपये) के दौरान इस योजना के लिए किए गए आवंटन की तुलना में 4.8% अधिक है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में जलीय कृषि और समुद्री खाद्य निर्यात में अग्रणी के रूप में भारत की उपलब्धि पर प्रकाश डाला। बजट घोषणा रणनीतिक रूप से वित्तीय समावेशन को बढ़ाने, सीमा शुल्क में कमी करके किसानों पर वित्तीय बोझ कम करने और समुद्री मत्स्य पालन के विकास को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।

बजट में लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह पर विशेष ध्यान देने के साथ विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और उच्च समुद्र से मत्स्य पालन के सतत दोहन के लिए एक ढांचे को सक्षम करने पर प्रकाश डाला गया है। यह समुद्री क्षेत्र में विकास के लिए भारतीय ईईजेड और आसपास के उच्च समुद्र में समुद्री मछली संसाधनों की अप्रयुक्त क्षमता का सतत दोहन सुनिश्चित करेगा। चूंकि भारत में 20 लाख वर्ग किमी का ईईजेड और 8,118 किमी लंबी तटरेखा है, जिसमें अनुमानित समुद्री क्षमता 53 लाख टन (2018) है और 50 लाख लोग अपनी आजीविका के लिए समुद्री मत्स्य क्षेत्र पर निर्भर हैं। यह भारतीय ईईजेड में विशेष रूप से अंडमान

और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपसमूह के आसपास उच्च मूल्य वाली टूना और टूना जैसी प्रजातियों के दोहन की व्यापक गुंजाइश और क्षमता प्रदान करता है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में मत्स्य पालन के विकास का लक्ष्य 6.60 लाख वर्ग किलोमीटर (भारतीय ईईजेड का 1/3) के अपने ईईजेड क्षेत्र का उपयोग करना होगा, जिसमें 1.48 लाख टन की समुद्री मत्स्य पालन क्षमता शामिल है, जिसमें टूना मत्स्य पालन की 60,000 टन क्षमता शामिल है। इस उद्देश्य के लिए, टूना क्लस्टर के विकास को अधिसूचित किया गया है और टूना मछली पकड़ने वाले जहाजों में ऑन-बोर्ड प्रसंस्करण और फ्रीजिंग सुविधाओं की स्थापना, गहरे समुद्र में टूना मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए लाइसेंसिंग और अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा एकल खिड़की मंजूरी, समुद्री पिंजरा संस्कृति, समुद्री शैवाल, सजावटी और मोती की खेती में अवसरों का उपयोग करना जैसी गतिविधियां शुरू की गई हैं। लक्षद्वीप द्वीपसमूह में मत्स्य पालन के विकास का लक्ष्य 4 लाख वर्ग किलोमीटर (भारतीय ईईजेड का 17%) के ईईजेड क्षेत्र और 4200 वर्ग मीटर के लैगून क्षेत्र का उपयोग करना होगा, इस प्रयोजन के लिए, समुद्री शैवाल क्लस्टर के विकास को अधिसूचित किया गया है और लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा एंड-टू-एंड मूल्य श्रृंखला के साथ द्वीप-वार क्षेत्र आवंटन और पट्टे नीति, महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का गठन और निजी उद्यमियों और लक्षद्वीप प्रशासन के सहयोग से आईसीएआर संस्थान के माध्यम से क्षमता निर्माण, टूना मछली पकड़ने और सजावटी मछली पालन में अवसरों का दोहन जैसी गतिविधियां शुरू की गई हैं।

बजट में, भारत सरकार ने मछुआरों, किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और अन्य मत्स्यपालन हितधारकों के लिए ऋण सुलभता बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण सीमा को ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया। इस कदम का उद्देश्य वित्तीय संसाधनों के प्रवाह को सुव्यवस्थित करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षेत्र की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक धनराशि आसानी से उपलब्ध हो। बढ़ी हुई ऋण उपलब्धता आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में सहायता करेगी और ग्रामीण विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करेगी, जिससे संस्थागत ऋण को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा।

वैश्विक समुद्री खाद्य बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और हमारे निर्यात बास्केट में मूल्यवर्धित उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य उत्पादों जैसे नकली केकड़ा मांस स्टिक, सुरीमी केकड़ा पंजा उत्पाद, झींगा एनालॉग, लॉबस्टर एनालॉग और अन्य सुरीमी एनालॉग या नकली उत्पाद आदि के विनिर्माण और निर्यात के लिए जमे हुए मछली पेस्ट (सुरीमी) पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) को 30% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर भारतीय झींगा पालन उद्योग को मजबूत करने के लिए, एक्वाफीड के विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट मछली हाइड्रोलाइजेट पर आयात शुल्क 15% से घटाकर 5% करने की घोषणा की गई है। इससे उत्पादन लागत कम होने और किसानों के लिए राजस्व और लाभ मार्जिन में वृद्धि होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री शास्त्री ने 'जय जवान जय किसान' का नारा दिया। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने बताया कि 'जय जवान जय किसान जय विज्ञान', प्रधानमंत्री मोदी ने यह आगे बढ़ाया है कि "जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान", क्योंकि इनोवेशन

विकास की नींव है।

हमारे टेक सेवी युवाओं के लिए यह एक सुनहरा युग होगा, पचास वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के साथ एक लाख करोड़ रुपये का कोष स्थापित किया जाएगा। कॉर्पस लंबी अवधि और कम या शून्य ब्याज दरों के साथ दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्तपोषण प्रदान करेगा, इससे निजी क्षेत्र को सूर्योदय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रूप से अनुसंधान और नवान्वेषण बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हमारे पास ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जो हमारे युवाओं और प्रौद्योगिकी की शक्तियों को संयोजित करते हैं।

रक्षा के उद्देश्यों के लिए डीप-टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाने और 'आत्मनिर्भरता' को तेज करने के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की जाएगी', मूल संरचना विकास, उच्च यातायात घनत्व गलियारे,

मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है। वे लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करेंगे और लागत को कम करेंगे। हाई-ट्रैफिक कॉरिडोर का परिणामी डिक्जेशन यात्री ट्रेनों के संचालन में भी मदद करेगा, जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों की सुरक्षा और उच्च यात्रा गति होगी। समर्पित माल गलियारों के साथ, इन तीन आर्थिक गलियारे कार्यक्रमों से हमारे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में तेजी लाएगी और तर्कसंगत लागतों को कम किया जाएगा। चालीस हजार सामान्य रेल बाँगी को यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और आराम को बढ़ाने के लिए वंदे भारत मानकों में बदला जाएगा।

विमानन क्षेत्र को पिछले दस वर्षों में बढ़ाया गया है। हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हो गई है। उड़ान योजना के तहत स्तर-दो और तीन स्तर के शहरों में वायु संयोजकता से बाहर निकलना व्यापक रहा है। पांच सौ और सत्रह नए मार्ग 1.3 करोड़ यात्रियों को ले जा रहे हैं, भारतीय वाहकों ने 1000 से अधिक नए विमानों के लिए सक्रिय रूप से ऑर्डर दिए हैं। मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का विकास तेजी से जारी रहेगा।

मेट्रो रेल और नमो भारत आवश्यक शहरी परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक हो सकते हैं। इन सिस्टमों का विस्तार बड़े शहरों में समर्थित होगा जो ट्रांजिट-ओरिएंटेड विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

'नेट-जीरो' के लिए 2070 तक हमारी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे।

एक गिगा-वॉट की प्रारंभिक क्षमता के लिए ऑफशोर पवन ऊर्जा क्षमता के उपयोग के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि उपलब्ध कराई जाएगी। कोयला गैसीफिकेशन और 100 मीटर की लिक्वेफैक्शन क्षमता 2030 तक सेटअप की जाएगी।

यह प्राकृतिक गैस, मेथनॉल और अमोनिया के आयात को कम करने में भी मदद करेगा। घरेलू उद्देश्यों के लिए परिवहन और पाइपड प्राकृतिक गैस (PNG) के लिए कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस (CNG) में कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) का चरणबद्ध अनिवार्य मिश्रण अनिवार्य किया जाएगा। संग्रहण को समर्थन देने के लिए बायोमास एग्रीगेशन मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम पर मोदी सरकार निर्माण और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का समर्थन करके ई-वाहन इकोसिस्टम

को बढ़ाएगी और मजबूत करेगी। भुगतान सुरक्षा तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई-बसों को अधिक अपनाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। बायो-मैन्युफैक्चरिंग और बायो-फाउंड्री।

हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव-विनिर्माण और जैव-फाउंड्री की एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, बायो-प्लास्टिक, बायो-फार्मास्यूटिकल और बायो-एग्री-इनपुट जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्राप्त होंगे। यह स्कीम पुनरुत्पादक सिद्धांतों के आधार पर आज के उपयोगी विनिर्माण मानदंड को एक में बदलने में भी मदद करेगी।

ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत जलवायु लचीली गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नीली अर्थव्यवस्था 2.0 के लिए, पुनर्स्थापन और अनुकूलन उपायों के लिए एक योजना, और एकीकृत और मल्टी-सेक्टरल दृष्टिकोण के साथ तटीय जल कृषि और मैरीकल्चर शुरू किया जाएगा।

भारत की विविधता को वैश्विक दर्शकों को साठ स्थानों पर जी 20 बैठकों का आयोजन करने की सफलता। हमारी आर्थिक शक्ति ने देश को व्यापार और सम्मेलन पर्यटन के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है। हमारा मध्यम वर्ग भी अब यात्रा और खोजने की आकांक्षा रखता है।

आध्यात्मिक पर्यटन सहित पर्यटन में स्थानीय उद्यमिता के लिए अपार अवसर हैं। राज्यों को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों, ब्रांडिंग और विपणन के व्यापक विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर केंद्रों की रेटिंग के लिए एक ढांचा स्थापित किया जाएगा। इस तरह के विकास को मैचिंग के आधार पर फाइनेंस करने के लिए राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त लोन प्रदान किए जाएंगे।

घरेलू पर्यटन के लिए उभरते हुए उत्साह को संबोधित करने के लिए, पर्यटन मूल संरचना के लिए परियोजनाएं, और लक्षद्वीप सहित हमारे द्वीपों पर सुविधाएं उठाई जाएंगी। इससे रोजगार पैदा करने में भी मदद मिलेगी। 2014-23 के दौरान एफडीआई का प्रवाह 596 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो एक सुनहरे युग को चिह्नित करता था। यह 2005-14 के दौरान दो बार इन्फ्लो है। निरंतर विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, हम 'पहले विकास भारत' की भावना में अपने विदेशी भागीदारों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं।

विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार विकसित भारत के दृष्टिकोण को समझने के लिए राज्यों में कई विकास और विकास सक्षम सुधारों की आवश्यकता होती है। राज्य सरकारों द्वारा माइलस्टोन से जुड़े सुधारों का समर्थन करने के लिए इस वर्ष पचास हजार करोड़ रुपये का प्रावधान इस साल प्रस्तावित किया जाता है।

सरकार तेजी से आबादी की वृद्धि और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से उत्पन्न चुनौतियों पर व्यापक विचार करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाएगी। 'विकसित भारत' के लक्ष्य के संबंध में इन चुनौतियों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए सुझाव देने के लिए समिति को अनिवार्य किया जाएगा।

कर्तव्य काल के रूप में अमृत काल । मोदी सरकार उच्च विकास के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है और लोगों के लिए अपनी आकांक्षाओं को समझने के लिए शर्तें बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ।

नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं वेतनभोगी करदाताओं के लिए सीमा 12.75 लाख रुपये होगी, जिसमें 75,000 रुपये की मानक कटौती होगी ।

केंद्रीय बजट 2025-26 सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव लाएगा । कर स्लैब दर में कमी और छूट के परिणामस्वरूप मध्यम वर्ग को पर्याप्त कर राहत मिलेगी, जिससे घरेलू उपभोग व्यय और निवेश को बढ़ावा मिलेगा ।

"पहले भरोसा करो, बाद में जांच करो" के दर्शन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए, केंद्रीय बजट 2025-26 ने मध्यम वर्ग में विश्वास जगाया है और आम करदाता को कर के बोझ में राहत देने की प्रवृत्ति को जारी रखा है । सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए कर स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव रखा ।

करदाताओं को सबसे बड़ी खुशखबरी, "नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये (यानी पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर आय को छोड़कर प्रति माह 1 लाख रुपये की औसत आय) तक कोई आयकर देय नहीं होगा । वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपये होगी ।" स्लैब दर में कमी के कारण लाभ के अलावा कर छूट इस तरह से प्रदान की जा रही है कि उन्हें कोई कर देय नहीं है । "नए ढांचे से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आएगी और उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा ।" नई कर व्यवस्था में, वित्त मंत्री ने कर दर संरचना को इस प्रकार संशोधित करने का प्रस्ताव दिया:

0-4 लाख रुपए	शून्य
4-8 लाख रुपए	5 प्रतिशत
8-12 लाख रुपए	10 प्रतिशत
12-16 लाख रुपए	15 प्रतिशत
16-20 लाख रुपए	इसे स्वीकार करो
20-24 लाख रुपए	25 प्रतिशत
24 लाख रुपये से अधिक	30 प्रतिशत

कराधान सुधारों को विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए प्रमुख सुधारों में से ये एक नया आयकर विधेयक 'न्याय' की भावना को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था करदाताओं और कर प्रशासन के लिए समझने में आसान होगी, जिससे कर निश्चितता होगी और मुकदमेबाजी कम होगी।

"जिस तरह से जीव बारिश की उम्मीद में जीते हैं, उसी तरह नागरिक अच्छे शासन की उम्मीद में जीते हैं।" सुधार लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए सुशासन प्राप्त करने का एक साधन है। सुशासन प्रदान करने में मुख्य रूप से उत्तरदायी होना शामिल है। कर प्रस्तावों में विस्तार से बताया गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार ने हमारे नागरिकों की जरूरतों को समझने और उन्हें संबोधित करने के लिए कैसे कदम उठाए हैं।

2014 में जब मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को कदम से सुधारने और शासन प्रणालियों को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी बहुत अधिक थी। समय की आवश्यकता थी जनता को आशा देना, निवेश आकर्षित करना और अत्यधिक आवश्यक सुधारों के लिए समर्थन बनाना। सरकार ने सफलतापूर्वक 'राष्ट्र-प्रथम' के हमारे मजबूत विश्वास का पालन किया।

उन वर्षों की संकट दूर हो गई है और अर्थव्यवस्था को सर्वांगीण विकास के साथ उच्च स्थायी विकास पथ पर दृढ़ता से लगाया गया है। अब यह देखना उचित है कि हम 2014 तक कहां थे और जहां हम अब, केवल उन वर्षों के गलत प्रबंधन से सबक लिखने के उद्देश्य से हैं। सरकार घर की तालिका पर एक सफेद कागज रखेगी।

अगले 25 वर्षों की योजनाओं को धरातल पर लाकर उन्हें कार्यान्वित करने का बजट पेश किया है, जिसमें इज आफ लिविंग पर विशेष ध्यान दिया है भारत के प्रत्येक कोने से, दुर्गम पहाड़ों पे निवास करने वाले या मैदानी क्षेत्र में, किसान या स्टार्टअप करने वाले युवा उद्यमी या फिर औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो, इस बजट में हर परिप्रेक्ष्य को शामिल किया गया है।

इस अमृतकाल के दुसरे बजट में भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है, सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है और साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बन जाने के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा है।

देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले, अमृत काल का एक और बेहतरीन बजट पेश करने के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ।

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): I would like to express my views on Union Budget for the year 2025-2025. From the out look of this Budget, it is amply clear that the hon'ble Finance Minister took time and put a lot of efforts to craft or create this Budget that will boost the prospects of her party to win the forthcoming elections as well as the election which concluded in Delhi. The hon'ble Finance Minister has reversed her party's slogan or that of the hon'ble Prime Minister that NATION FIRST into ELECTION FIRST and of course this must be done with the consent of the hon'ble Prime Minister.

This Budget lacks clear vision how to tackle the serious issues the country is facing such as the increasing unemployment problem, unaffordable level of inflation, unprecedented decline of the strength of Indian rupee to a US dollar, huge widening gap of trade deficit, especially with China, sluggish growth of manufacturing, implications arising out of implementation of Goods and Services Tax and the government's main concern and focus was on how to win elections.

The steady falling of value of rupee against U.S. dollar is a serious concern as it will affect the growth of the nation. The value of Indian rupee fell from Rs.58 to a dollar a decade ago to about Rs.89 a dollar now. The hon'ble Prime Minister during his Chief Minister-ship of Gujarat linked the rupee's value with the then Hon'ble Prime Minister, Dr. Manmohan Singh's age when there was a slight decline in the strength of the rupee. When we hear the word century our mind goes to the cricket field as cricket is quite popular in the country, and our rupee is also heading to a century to a U.S. dollar and the government has no answer how to prevent the declining strength of Indian rupee.

The farmers in the country have been demanding legally guaranteed a Minimum Support Price for their produce for a long time as agricultural activities have become unbearable due to escalating cost of all input materials. The one who produces is not gaining, but the one who sells. This must be stopped and the farmers should get remunerative price for their produce. and for the hard work they are putting in. However, there has been no mention on this in this Budget. It is guaranteed that if we give guaranteed Minimum Support Price to the farmers, the suicides by farmers in the country can prevent to a great extend.

It has been a long pending demand to support the farmers in the district of Palakkad as a special package to them as the farmers in the district face many difficulties such as unpredictable climate change, non-procurement of their produce by the agencies on time, cost escalation towards farming as cost of all input materials has gone up and the cost of labour charges, but yet there has been no decision in this regard by the Union government.

It has been a long pending demand of the pensioners under the Employees Pension Scheme of the Employees Provident Fund Organisation. Currently these pensioners are getting pension of Rs.1,000/- which is not even sufficient to meet a part of their medical needs. The pensioners and most of all the

central trade unions have been demanding a suitable enhancement in the pension amount being paid by Employees Provident Fund Organization.

The card holders under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme are not getting the wages incommensurate with the increasing inflation. The wages which they are getting is stagnant since the launch of the scheme way back in the year 2005. There are reports that the cardholders are not even getting the guaranteed 100 days of work and it is now below the mark of 50 days in a year. Therefore, the wages need to be revised in consultation with the States and also provide the guaranteed number of days of work under the said scheme. It is very ironic that when the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, is running on a deficit of Rs.9.754 core, there has been no hike in the fund allocation in the 2025-26 Budget. A sum of Rs.86,000 crore has been allocated for the scheme, which is the same as in the Budget allocation for 2024-25 While the Centre insist that the MGNREGS is a demand driven scheme and additional funds are given when required, no upward revision was made in the ongoing financial year. If the dues of the MGNREGS are resolved, the allocation will likely decrease further. Therefore, the government should provide more funds to this Scheme.

The Budget kept totally a blind eye towards Kerala and neglected it. The demands of the Kerala have been ignored. Man animal conflicts is an serious issue that the country is facing especially in the State of Kerala. Many people have lost their lives on this account. The most of the victims of such attacks by wild animals are the people who live in and around our forest areas. Not only that we suffer loss of lives due to attack by wild animals, our farmers are also suffering loss of their standing crops as wild animals enter into human habitats and agricultural areas and cause damages and this has become a routine affair, especially in the State of Kerala. Why the wild animals enter into human habitats and cause damages to agriculture, is because of growing eclipse of flora and fauna in the forest and the scarcity of water thee for them. Therefore, we must need to look into this serious issue with proper directions and the Budget lacks support to State to deal with the issue of man animal conflict and the farmers suffering from losses on account of wild animals damaging their crops or the agricultural fields.

Many States in the country especially the State of Kerala are facing acute financial crisis, this is especially with regard to opposition ruled States. The States were not able to implement many of the

welfare schemes of both the States and the schemes shared by both the States and the Union government. The case is with the State of Kerala is that it has to borrow money to share its part in Central schemes. The States were also not allowed to make additional borrowing. The solution to this serious financial crisis is to provide more share of Goods and Services Tax to the State government and its timely release. The States were also not able to receive aid from abroad due to restrictions imposed by the Union government. As far as Kerala is concerned, during the flood in the year 2018 and in recent landslides in Wayanad, the State could not obtain foreign aid due to unfavourable steps taken by the Union government. Therefore, it is urged that the Centre should come forward to ailing States to recover from their pathetic financial conditions. The Budget did not even consider the demand made by the Kerala government for the rehabilitation of people affected by landslides in Wayanad.

The demands of the Kerala government for a Rs.24,000 crore economic package and a Rs.5,000 crore special assistance for the Vizhinjam port project and Rs.2,000 crore prop up for rehabilitation of the landside survivors of the landslides survivors in Wayanad have not found a place in the Budget and it is an act of injustice towards a growing State.

The railways had acquired 236 acres of land for a coach factory and a sum of nearly Rs.7 crore was also spent for construction of boundary wall. The acquired 236 acres of land is lying unutilised. This proposed project was also found in PRAGATI and this was debated in the 38th meeting of the PRAGATI. Therefore, it is urged that the said proposed project be brought under Gati Shakti scheme to expedite it or make use of the said land and infrastructure for any other project of railways or suitable to any other projects of national interest.

The people of Kerala were hoping that an All India Institute of Medical Sciences will become a reality in the State. I had suggested Palakkad for the said purpose due to its demand for an institution like All India Institute of Medical Sciences. But the hopes of the people of Kerala have been dashed as yet again as the issue of setting up of an All India Institute of Medical Sciences in Kerala was not found in the Budget under discussion.

As regards railway projects demanded by the Kerala, the same have been totally ignored. The lion's share of the outlay will go for station redevelopment, track doubling and other supporting infrastructure. The State has been demanding third and fourth rail lines between Thiruvananthapuram and Mangaluru,

Namo Bharat Rapid Rail connecting Thiruvananthapuram with Mangaluru on the lines of similar projects in Delhi and Bengaluru, unfreezing of the Sabari rail project, regular Vande Bharat services between Ernakulam and Bengaluru, Nilambur-Nanjangud rail project, Thalassery-Mysuru project and a new line in the Kanhangad-Panathur-Kaniyur section. However, no funds have been earmarked for any of these projects. This is a total discrimination towards Kerala.

Finally, I would like to mention about the Indian Institute of Technology (IIT), Palakkad. The IIT at Palakkad was started way back in 2015 with 120 students. Now it has 1,400 students now and it hopes to have additional 1,300 students in the next five years. The construction of the buildings has not yet been completed and it was supposed to be completed by the year 2022. However, the expansion suggested in the Budget was usual and not according to the demand of IIT, Palakkad. Therefore, expansion should be carried out at IIT, Palakkad in commensurate with its demand and according to above facts.

With this I conclude and oppose the Budget.

डॉ. लता वानखेड़े (सागर) : मैं अपने हृदय की गहराइयों से देश के यशस्वी, ओजस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करती हूँ। जिनकी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता, अटूट संकल्प और अकल्पनीय दूरदृष्टि के कारण भारत आज एक नए स्वर्णिम युग की ओर बढ़ रहा है।

यह सिर्फ एक बजट नहीं है, यह भारत के भविष्य की रूपरेखा है। यह बजट मोदी जी के उस संकल्प का प्रतिबिंब है, जो उन्होंने इस देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए लिया था। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम इस महायुग के साक्षी बने हैं, जब भारत अपनी विजय गाथा और विकास गाथा लिख रहा है। मैं बिंदुवार यह स्पष्ट करूंगी कि यह बजट अब तक का सर्वश्रेष्ठ बजट क्यों है!

यह एक ऐसा बजट है जो भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यह बजट केवल एक संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि हर किसान, हर मध्यम वर्गीय परिवार, हर युवा, हर महिला, और हर छोटे व्यापारी की उम्मीदों का प्रतिबिंब है।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पहले की सरकारों के समय देश की स्थिति क्या थी। वर्षों तक चली सरकारों ने केवल वादे किए, लेकिन उन वादों को हकीकत में बदलने की इच्छाशक्ति नहीं दिखाई। किसान केवल कर्जमाफी की राजनीति में उलझे रहे, मध्यम वर्ग पर करों का भारी बोझ था, MSME और स्टार्टअप्स की अनदेखी होती रही, महिलाओं और युवाओं केवल घोषणाओं में लुभाया गया, और स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे मूलभूत क्षेत्रों की स्थिति दयनीय थी। लेकिन हमारी मोदी सरकार ने देश की दिशा बदली है। हमारी सरकार ने जो कहा, वह करके दिखाया।

1. किसानों के लिए ऐतिहासिक सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है किसान अब अन्नदाता से उन्नतदाता का सफर तय कर रहा है। पहले की सरकारों ने किसानों को सिर्फ चुनावी मुद्दा बनाया, लेकिन उनकी आय दोगुनी करने या उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोई ठोस नीति नहीं बनाई। हमारी मोदी सरकार ने यहाँ बेड़ा उठाया है और किसानों की समस्याओं को अपनी समस्या माना है। हमारे कृषि मंत्री भी एक किसान परिवार से ही हैं वो जानते हैं कि किसान की दुख तकलीफ क्या होती है हमारी वित्त मंत्री Nirmala Seetharaman जी ने इस बजट में किसानों के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है।

1. 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा किसानों को सीधा लाभ देने के लिए प्रधानमंत्रीधन-धान्य कृषि योजना बनाई गई है।
2. 100 जिलों में आधुनिक कृषि तकनीक लागू की जा रही है।
3. MSP को ऐतिहासिक रूप से बढ़ाया गया है जिससे किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलेगा।
4. किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की ऋण सीमा रुपये 3 लाख से बढ़ाकर रुपये 5 लाख कर दी गई है
5. अब किसान न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे, बल्कि बिचौलियों से मुक्त होकर सीधा मुनाफा कमाएँगे।
6. हमारी वित्त मंत्री जी ने मध्यम वर्ग के लिए सबसे बड़ी राहत दी है करों का बोझ घटाया गया है जो आज के मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी माँग थी। पहले की सरकारों ने मध्यम वर्ग को हमेशा करों के जाल में फंसाकर रखा। टैक्स स्लैब को 10-15 साल तक बदला ही नहीं गया।

हमारी सरकार हमेशा से ही मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर काम करती आई है फिर चाहे नई टैक्स रेजिम हो यह कर में छूट हमारी दूरगामी नीति हमेशा हर वर्ग को ध्यान में रखती है।

इसीलिए इस बार के बजट में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि ;

- 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं नहीं देना होगा यह आज से पहले एक सपना ही था जिसे मोदी सरकार ने साकार किया है।
- वरिष्ठ नागरिकों को ₹1 लाख तक की अतिरिक्त कर छूट दी गई है।
- घर खरीदने और निवेश करने पर विशेष कर प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।
- कराधान प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
- अब हर मध्यम वर्गीय परिवार के पास अधिक बचत होगी और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी।

MSME और स्टार्टअप के लिए भी यहाँ बजट एक सुनहरा अवसर बन के आया है।

पहले की सरकारों ने छोटे व्यापारियों की अनदेखी की। न तो उन्हें सही वित्तीय सहायता मिली, न ही कोई अनुकूल नीति बनाई गई।

हमारी सरकार के इस बजट में

- MSME क्रेडिट गारंटी कवर ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ किया गया है।
- MSME की टर्नओवर और निवेश सीमा को 2.5 गुना तक बढ़ाया गया है।
- 5 लाख नए कारीगर क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप हब' को बढ़ावा देने के लिए ₹50,000 करोड़ का इनोवेशन फंड बनाया गया है।
- अब भारत छोटे उद्योगों को भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा!
- महिलाओं और युवाओं के लिए भी यह बजट स्वर्णिम अवसर बन के आया है।

पहले की सरकारों ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान नहीं दिया और युवाओं के लिए कौशल विकास योजनाएँ सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहीं। अब हमारी सरकार में इस बजट के माध्यम से :

- 50,000 अटल टिकरिंग लैब, स्कूलों में स्थापित की जाएँगी।
- 5 नए राष्ट्रीय कौशल हब, युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से तैयार किए जाएँगे।
- महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के लिए विशेष अनुदान मिलेगा।
- अब महिलाएँ और युवा आत्मनिर्भर बनेंगे और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे!

इस बजट के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा में ऐतिहासिक सुधार लाए जाएँगे।

पहले की सरकारों ने सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। गरीबों को महंगी दवाएँ खरीदनी पड़ती थीं, और सरकारी स्कूलों की हालत खराब थी उसे अनदेखा किया गया।

मोदी सरकार हर उस अनदेखी का जवाब है इस बजट के माध्यम से

- 36 जीवनरक्षक दवाओं पर टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है।
- 10,000 नई मेडिकल सीटें और 200 कैंसर केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं।
- सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई योजनाएँ लागू की गई हैं
- अब भारत स्वस्थ और शिक्षित नागरिकों का देश बनेगा!

बुनियादी ढांचे और परिवहन क्षेत्र में भी क्रांति आए ऐसा बजट इस बार हमारी वित्त मंत्री जी ने लाया है। इस बजट के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा में ऐतिहासिक सुधार लाए जाएँगे।

अध्यक्ष महोदय, पहले की सरकारों ने सरकारी अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। गरीबों को महंगी दवाएँ खरीदनी पड़ती थीं, और सरकारी स्कूलों की हालत खराब थी उसे अनदेखा किया गया।

मोदी सरकार हर उस अनदेखी का जवाब है इस बजट के मध्यम से 36 जीवनरक्षक दवाओं पर टैक्स पूरी तरह हटा दिया गया है; 10,000 नई मेडिकल सीटें और 200 कैंसर केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं ; सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नई योजनाएँ लागू की गई हैं ; अब भारत स्वस्थ और शिक्षित नागरिकों का देश बनेगा! बुनियादी ढांचे और परिवहन क्षेत्र में भी क्रांति आए ऐसा बजट इस बार हमारी वित्त मंत्री जी ने लाया है । पहले की सरकारों ने सड़क, रेलवे और हवाई अड्डों की परियोजनाओं को पूरा करने में हमेशा सुस्ती दिखाई ।

लेकिन मोदी सरकार एक इतिहास बना रही है इस बजट में 500 वंदे भारत ट्रेनें, 100 नए एक्सप्रेसवे और 50 नए एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा गया है जो आज तक ना किसी ने सोचा था ना किया था । रेलवे विद्युतीकरण से भारत में स्वच्छ और आधुनिक परिवहन बने इस बजट में इसका विशेष ख्याल रखा गया है ।

अब भारत का हर शहर महानगरों से और एक दूसरे से बेहतर कनेक्टेड रहेगा । आज हमारे देश में जो सड़को और हाईवेज का जो निर्माण हो रहा है वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है भारत का बच्चा बच्चा इस विकास यात्रा को देख रहा है हमारा मध्य प्रदेश और मेरा संसदीय क्षेत्र सागर भी सड़क और परिवहन में बेहतर हो रहा है हमने माननीय नितिन गडकरी जी से मध्यप्रदेश में मेरे संसदीय क्षेत्र सागर से होते हुए इंदौर के लिए एक विशेष एक्सप्रेस हाईवे मांगा है जिस पर उन्होंने हमें आश्चस्त किया है

से पहले की सरकारों में काम करने में ऐसा तालमेल कभी नहीं देखा गया, उस समय किसी विभाग से कुछ मांगना और उस काम का होना केवल सपना लगता था लेकिन मोदी सरकार का हर मंत्रालय विकास की गाथा लिखने की मिसाल बन रहा है। मैं यह दावे के साथ कह सकती हूँ यह बजट भारत को सुपरपावर बनाने की ओर अब तक का सबसे बड़ा कदम है ।

आज जब हम इस ऐतिहासिक बजट पर चर्चा कर रहे हैं, तो यह याद रखना आवश्यक है कि यह बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है-यह नए भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप है, और विकसित भारत की नींव है ।

लेकिन यह भी सच है कि यदि कांग्रेस की सरकारें अपनी ज़िम्मेदारी निभातीं, यदि उन्होंने सही नीतियाँ बनाई होतीं, यदि उन्होंने भारत की जनता की वास्तविक परेशानियों को समझा होता, तो हमें आज यह सुधार करने की जरूरत न पड़ती ।

हमारी MODI सरकार ने जो कहा, वह किया । 2014 के बाद से हमारे नेतृत्व ने इस देश के विकास के लिए जो संकल्प लिया, उसे पूरा भी किया । हमने हर मोर्चे पर परिणाम दिए हैं, सिर्फ वादे नहीं किए ! आज जो लोग इस बजट की आलोचना कर रहे हैं, वे वही लोग हैं जिन्होंने दशकों तक इस देश को सिर्फ झूठे वादों से ठगा है । ये वही कांग्रेस पार्टी है जो किसानों की कर्जमाफी के नाम पर चुनाव जीतती थी, लेकिन कभी किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया । ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने मध्यम वर्ग को सिर्फ करों के जाल में फँसाया, लेकिन उनके लिए कोई राहत नहीं दी । ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ भ्रष्टाचार किया और गरीबों को उनके हाल पर छोड़ दिया । जो लोग आज हमारे बजट पर सवाल उठा रहे हैं, वे पहले जवाब दें कि उनकी सरकारों ने इतने सालों तक यह काम क्यों नहीं किया? यह बजट कांग्रेस के लिए एक आईना भी है-एक ऐसा आईना

जिसमें वे अपनी नाकामियाँ और खोए हुए अवसरों की कहानी साफ़ देख सकते हैं। अब भारत न केवल एक उभरती हुई शक्ति है, बल्कि एक सशक्त, आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ता राष्ट्र है!

धन्यवाद! जय हिंद !

DR. MALLU RAVI (NAGARKURNOOL): Deeply disappointed, yet determined, to voice the concerns of the people of Telangana and the citizens of this nation who have once again been let down by this Union Budget 2025-26.

This budget was an opportunity an opportunity to uplift farmers, students, workers, small businesses, and the unemployed youth. It was a chance to ensure real urban and rural development, invest in education, and tackle climate change with sincerity, लेकिन इसके बजाय हमें क्या मिला: एक और दिखावटी बजट, जिसमें झूठे आंकड़ों का खेल दिखाया गया, लेकिन जनता के असली मुद्दों का कोई हल नहीं निकला।

Year after year, legitimate demands are ignored, promises remain unfulfilled, and states like Telangana continue to be neglected. जब किसान मदद मांगते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। जब छात्र बेहतर शिक्षा की मांग करते हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है। जब राज्य अपना हक मांगते हैं, उन्हें बहाने बना कर टाल दिया जाता है।

This budget is not about progress it is about politics. And we will not remain silent while the people of this country continue to be betrayed.

Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji has often claimed that the Government is constantly working for value addition in agriculture. But the reality is far from it. They boast about increasing the agriculture budget from 21.52 lakh crore to ₹1.71 lakh crore, but let's not be fooled this mere adjustment does not even come close to what is needed.

Tell me, how can we expect real progress when agriculture gets only 3.38% of the total budget, while a massive Rs. 22.74 lakh crore is set aside for pensions and salaries of central government employees?

What about Telangana's farmers?

- We demanded 65.26 crore to complete the Horticulture University's infrastructure-Ignored!
- We requested a Regional Research Centre for Oil Palm in Telangana Ignored!
- We sought a regional office for coconut farmers in Bhadrachalam district-Ignored!

- We urged the Centre to empanel certified seed suppliers for oil palm to ensure quality seedlings-Ignored!

This Government imposes schemes on us-PM Dhan Dhanya Krishi Yojana, High-Yielding Seeds Mission, Cotton Productivity Mission-but when Telangana demands basic agricultural infrastructure, we are left unheard!

2. Telangana's Rights Under the AP Reorganization Act - Denied Again

Hon'ble Speaker, for the past 10 years, Telangana has been demanding what was promised to us under the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014. But this Government refuses to fulfill its legal commitments.

(A) ₹450 Crore Per Year for Telangana's Backward Districts - Not Given!

- Telangana has 9 backward districts that are entitled to 450 crore annually for development.
- For 5 years, this amount has not been released.
- This budget also ignores it. Where is the justice?

(B) No Bayyaram Integrated Steel Plant - A Broken Promise

- The Centre promised a steel plant at Bayyaram as part of AP Reorganization Act.
- Not a single rupee has been allocated for this in the budget!

(C) Tribal University - No Funds, No Progress

- Telangana was supposed to get a Tribal University, like Andhra Pradesh.
- Funds were initially allocated, but now, it has vanished from the budget.

when will this government stop betraying Telangana?

3. Infrastructure and Urban Development Telangana Ignored Again

(A) Palamuru-Hangareddy Lin Irrigation Scheme No National Status

- Telangana demanded "National Project status for this crucial irrigation scheme. which provides water security to farmers in Nagarkurnool, Mahbubnagar, and Ranga Reddy districts.

- The Centre has denied this status while granting similar benefits to projects in other States!

(B) No National Highway Projects for Telangana

- Telangana proposed several key highways for NH upgradation, including

1. Pullur (Alampur Cross Road) to Nalgonda via Nagarkurnool, Kollapur, Achampet.
2. Four-laning of Hyderabad-Kalwakurthy NH-766.
3. Bix-laning of Hyderabad-Vijayawada NH-65.

- Not a single one of these was approved. Why this discrimination?

(C) Hyderabad Metro Expansion-No Funds Given

- Phase-II expansion of Hyderabad Metro needed central funding-but this budget has ignored it.

4. Pending Financial Dues to Telangana - Why This Injustice?

While this government boasts about fiscal discipline, it owes Telangana thousands of crores in unpaid dues that were not included in this budget.

- 1468.94 crore food subsidy from 2014-15-Still unpaid!
- ₹343.27 crore PMGKAY subsidy from 2022-23-Not released!
- ₹79.09 crore differential cost for non-NFSA scheme - Pending!
- ₹408.49 crore for common institutions expenditure under APRA - Ignored!

Telangana contributes Rs.3.75 lakh crore in tax revenue to the Centre annually, yet when we ask for our rightful share, we get nothing! This is financial injustice.

5. Education and Employment - Telangana's Youth Left Behind

Education is the foundation of any nation, but this Government has completely neglected it.

- No Polytechnic Colleges approved for Telangana.
- No Indian Institute of Management (IIM) for Telangana. No new Kendriya Vidyalayas approved.
- No Skill Development Funds for Telangana's youth.

While the budget speaks of "Viksit Bharat 2047," it has ignored investment in Telangana's education sector. If our students are denied opportunities, how will we build a strong future?

6. A Budget That Favors Fossil Fuels Over Sustainability

- This budget only increased environmental spending by 2.5%, while the Coal Ministry's budget saw a 160% jump.
- The ₹19.81 crore water cess reimbursement for Telangana remains unpaid since 2014!
- The RG coal mine penalty waiver is still pending.

This government talks about climate action, but its budget tells a different story-it supports fossil fuels while ignoring Telangana's green initiatives.

7. Conclusion: A Budget That Fails Telangana and India

Hon'ble Speaker, this budget does not uplift farmers, does not support youth, does not fulfill promises, and does not ensure equitable growth. It is a budget of political discrimination, empty announcements, and financial injustice towards Telangana.

The people of Telangana will not remain silent.

- We demand our rightful share of development funds!
- We demand that the Centre stop treating Telangana unfairly!
- We demand the fulfillment of every promise made in the AP Reorganization Act!

Jai Telangana! Jai Hind!

श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल) : मैं मेरी पार्टी शिव सेना की ओर से माननीय वित्त मंत्री को एक सशक्त, दूरदर्शी और ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूँ और इस बजट का समर्थन करता हूँ। यह बजट केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सरकार सुधार, वित्तीय अनुशासन और सामाजिक सशक्तिकरण में विश्वास रखती है। इस बजट के माध्यम से हम आत्मनिर्भर भारत, तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और जनकल्याण के अपने संकल्प को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा देश विश्व में सातवें स्थान पर है, हमारा देश आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक तेज़ी से बढ़ती हुई शक्ति है और यह बजट इस विकास को और मजबूत बनाएगा। हमारी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। देश में लगभग 50% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, लेकिन इसका

जीडीपी में योगदान लगभग 18% ही है। भारत ने तेजी से आर्थिक विकास किया है। वर्तमान में, सरकार की विभिन्न योजनाएँ मेक इन इंडिया स्टार्टअप इंडिया डिजिटल इंडिया PM Gati Shakti योजना हमारी अर्थव्यवस्था को लगातार आगे बाधा रही हैं।

मोदी सरकार द्वारा पिछले 10 वर्षों में किए गए ऐतिहासिक कार्यों का उल्लेख करना चाहता हूँ, जिन्होंने देश के बुनियादी ढांचे और जनकल्याण के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई है। रेलवे, सड़क परिवहन, चिकित्सा और ग्रामीण विकास इन चारों क्षेत्रों में सरकार की दूरदर्शी नीतियों ने न केवल तेजी से विकास को संभव बनाया, बल्कि देश के नागरिकों के जीवन को भी आसान किया है। महोदय, रेलवे जो देश की जीवन रेखा है, उसे आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत मुंबई-अहमदाबाद के बीच भारत की पहली हाई-स्पीड ट्रेन का निर्माण कार्य जारी है, जो देश को तेज परिवहन के नए युग में प्रवेश कराएगी। वहीं, वंदे भारत एक्सप्रेस और तेजस एक्सप्रेस जैसी आधुनिक और सेमी हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत से यात्रियों को सुविधा और गति दोनों मिली है। सुरक्षा की दृष्टि से, रेलवे ने कवच तकनीक को अपनाया है, जिससे ट्रेनों की टकराव जैसी दुर्घटनाओं में भारी कमी आई है। रेलवे विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी सरकार ने तेजी दिखाई है, वर्ष 2014-15 के बीच हर दिन करीब 1.42 किलोमीटर विद्युतीकरण किया जाता था। इस अवधि में भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क पर लगभग 45,200 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण पूरा किया। वहीं 2023-24 के दौरान प्रतिदिन करीब 19.7 किलोमीटर विद्युतीकरण का रिकॉर्ड बना है कुल ब्रॉड गेज नेटवर्क का लगभग 97 प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। इससे ईंधन की खपत में कमी आई है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। जिससे यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के योगदान में परिवहन का प्रमुख साधन है। माल और यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के अलावा, सड़क परिवहन देश के सभी क्षेत्रों में समान सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह देश के सामाजिक और आर्थिक एकीकरण और विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की अर्थव्यवस्था और विकास को गति देने के लिए सड़क परिवहन का सशक्त होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से मोदी सरकार ने भारतमाला परियोजना की शुरुआत की, जिसके तहत 34,800 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण किया गया। आज भारत में राजमार्ग निर्माण की गति 2014 के मुकाबले लगभग दोगुनी हो चुकी है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाएँ न केवल यात्रा को सुगम बना रही हैं, बल्कि व्यापार और उद्योगों को भी बढ़ावा दे रही हैं। साल 2014 में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण 12.1 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से हो रहा था, जबकि साल 2023-24 के बाद देश में प्रतिदिन 36 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। बजट में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को नजरअंदाज किए बिना कर सुधारों, नवाचार को बढ़ावा देने और कौशल विकास पर जोर देकर आर्थिक प्रगति को प्राथमिकता दी गई है। बजट में स्वास्थ्य सेवा और एमएसएमई दोनों के प्रमुख क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। अगले पांच वर्षों में 10,000 मेडिकल सीटें जोड़ने और 75,000 सीटें बनाने का प्रस्ताव स्वास्थ्य पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगा।

कैंसर भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य चिंता का विषय है। पिछले एक दशक में, इसके मामलों में लगातार वृद्धि हुई है और आने वाले वर्षों में इसके और बढ़ने का अनुमान है। यह अनुमान लगाया गया है कि देश में हर नौवें व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी समय कैंसर होने की संभावना है। भारत में कैंसर के वार्षिक मामलों की संख्या वर्ष 1990 और 2013 के बीच दोगुनी हो गई। वर्ष 2020 में, भारत में कैंसर के अनुमानित 1.39 मिलियन मामले सामने आए, जो वर्ष 2021 और 2022 में क्रमशः 1.42 मिलियन और 1.46 मिलियन हो गए। अध्ययनों ने वर्ष 2025 तक वार्षिक कैंसर के मामलों की संख्या में 12.8% की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो लगभग 1.57 मिलियन होगा। तीन साल की जिला अस्पताल रोलआउट योजना के साथ 200 डेकेयर कैंसर केंद्रों की स्थापना एक स्वागतयोग्य कदम है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा क्षेत्र में सुधार को लेकर माननीय मोदी सरकार के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना जैसी क्रांतिकारी पहल हुई है और इसके तहत 50 करोड़ से अधिक गरीब और मध्यमवर्गीय नागरिकों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिससे गरीब वर्ग को चिकित्सा सुविधाएँ सुलभ हुई हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करने के लिए 300 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज खोले गए और AIIMS की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई। गांवों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले गए हैं, जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं लोगों के घर-घर तक पहुँची हैं। कोरोना महामारी के समय सरकार ने तेजी से वैक्सीन निर्माण और मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया, जिससे भारत ने पूरी दुनिया को एक मजबूत स्वास्थ्य मॉडल प्रस्तुत किया। यह सरकार की कुशल नीति का ही परिणाम था कि भारत ने न केवल अपने नागरिकों को सुरक्षित किया, बल्कि अन्य देशों को भी वैक्सीन की आपूर्ति कर वैश्विक नेतृत्व दिखाया।

भारत की आत्मा गाँवों में बसती है। इसलिए मोदी सरकार ने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्के मकान दिए गए हैं, जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। हर घर जल योजना के अंतर्गत 14 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों तक स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कर भारत को खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित किया गया। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां लाखों किसान परिवार अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। किसानों की आय और उनकी आर्थिक स्थिति देश के विकास के लिए बहुत अहम है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए PM-KISAN योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है। इससे किसानों को आर्थिक संबल मिला है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है।

मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में रेलवे, सड़क परिवहन, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। इन योजनाओं और विकास कार्यों का प्रभाव सीधे देश के नागरिकों के जीवन पर पड़ा है। तेज़गति से बढ़ता बुनियादी ढांचा, मजबूत स्वास्थ्य सेवाएँ ग्रामीण उत्थान और डिजिटल इंडिया के संकल्पों ने देश को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है। आने वाले वर्षों में भी यह सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति के साथ देश को और आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें विश्वास है कि इस विकास यात्रा में हर नागरिक का योगदान रहेगा और भारत एक विश्वगुरु बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ेगा। इस बजट से विकसित भारत का निर्माण होगा और देश लगातार समृद्धि की ओर बढ़ेगा। इसी के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI MUKESHKUMAR CHANDRAKAANT DALAL (SURAT): I would like to express my views on the Budget 2025-26 presented by Finance Minister Shri Nirmla Sitharamanji. It serves as a representation of a significant milestone in our nation's journey, it is a visionary blueprint, steering India toward its goal of becoming a fully developed nation, in line with Prime Minister Narendra Modi's transformative vision of "Viksit Bharat." This budget is more than a financial plan and embodies India's determination to achieve greater progress and strengthen its global standing.

The Union Budget provided a major boost to India's textile, apparel, footwear, and leather sectors by launching a Mission on Cotton alongside a dedicated focus product scheme for the footwear and leather industries. The scheme is designed to enhance productivity, quality, and competitiveness by supporting design capacity, component manufacturing, and machinery for both leather and non-leather footwear. It is projected to generate a turnover of 4 lakh crore, spur exports of over 1.1 lakh crore, and create employment opportunities for 22 lakh people

A series of government Initiatives have been unveiled by the Union Government for the Textile industry in the Union Budget 2025-26 like the revision of tariff items on knitted fabric categories to boost domestic industry, exemption of two more shuttle-less looms from basic customs duty to support technical textile industry to create \$350-billion market size by the year 2030, I also welcome setting up of an Export Promotion Mission with an allocation of Rs 2,250 crore to enhance India's export competitiveness in the backdrop of rising protectionism and global uncertainty at the global level.

The budget has prima facie introduced various reliefs for the domestic diamond industry including the Surat industrial complex, ensuring its long-term sustainability. Responsive interventions like reduced import duties, GST revisions, and financial support are expected to drive growth of the diamond industry in the coming years. However, the industry's resilience to global economic changes and technological advancements to maintain its leadership in the diamond trade will be subjected to tests in the years to come. In the run up to this year's budget, the government also announced the Diamond Imprest Authorization Scheme to enhance the competitiveness of India's diamond exporters

The pace of economy could also be witnessed from the growth of country's Infrastructure sector. Expanding road networks, construction of overbridges, new railway lines & substantial public sector spending's are fuelling this growth. India has emerged as the global player in steel production with

producing over 140 million tons of steel in 2024, alloy & non-alloy both, making it a second largest producer of steel in the world. Per capita consumption of steel increased from only 50 kg in 2013-14 to 110 kg in 2022-23. By 2031 the country is expected to achieve a crude steel capacity of 300 million tonnes. Steel consumption is likely to cross over 450 million tons by 2027.

Similarly India's cement production is expected to grow by 10% to over 320 million tonnes in 2024. Sir, it would be interesting to know that approx. 20000 cubic meters of cement is consumed daily in constructing Ahmedabad Mumbai (which is equivalent to ten story building) bullet train project which is likely to be fully completed by the end of 2028.

We need to produce critical goods at the scale and quality required to serve the infrastructure and investments needs of aspiring economy. This budget will further attract, promote and facilitate domestic and foreign investments that the country needs to become a competitive and innovative economy. I have no doubt that people of India will overcome the challenges and turn them into opportunities on the way to Viksit Bharat by 2047. The year 2024 witnessed unprecedented electoral activity with more than half of the global population went for voting across countries. Also adverse developments like Russia-Ukraine war and Israel-Hamas war increased regional instability. These events have had severe adverse impact upon energy and food security leading towards higher prices and rising inflation globally.

With a firm focus on agriculture, MSMEs, Investments and Exports, India is being steered in a direction of growth. India currently holds 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people, and generating 36% of our manufacturing. These MSMEs have positioned India as a global manufacturing hub, with 45% of our exports coming from them. MSME's will be further facilitated by customised credit cards with a 15 lakh limit for micro-enterprises registered on the Udyam portal.

In addition, the Union Budget 2025-26 introduces a new initiative aimed at supporting women entrepreneurs, particularly first-time business owners from Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST). This marks a significant and progressive shift, as the number of women-led small businesses is growing, yet women from SC and ST communities often struggle to access financial resources. By easing access to capital, this scheme seeks to empower those who have historically faced difficulties in securing credit.

To mark India's global presence and increased hold on soft power, the budget has given the "Make in India" toy industry a boost by seeking to develop toy clusters, skills and manufacturing ecosystems. These toys will not only be sustainable but also promote indigenous culture and Innovation.

This budget is much more than a collection of financial figures, it is a holistic comprehensive strategy that addresses India's challenges by employing both traditional and innovative methods. While our nation is vast and diverse, the struggles of our people remain common, and this budget weaves together a series of complementary policies-from supporting farmers through both agricultural and rural development measures to giving an edge to MSMEs and textile industry, demonstrating that giving up is not in the BJP-led government's nature. Sir, with such grand steps I am sure that the day is not far when India is going to be called as a developed nation.

With regards.

श्री दिलीप शङ्कीया (दारंग-उदालगुड़ी) : मैं केन्द्रीय बजट 2025-26 पर अपने विचार रखता हूँ।

वित्त मंत्री महोदया द्वारा 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया है, जबकि वर्ष 2013-14 में यह केवल 16 लाख 65 हजार करोड़ रुपए था। इस बजट के माध्यम से देश और दुनिया के समक्ष एक मजबूत, श्रेष्ठ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की विस्तृत रूप-रेखा को रखा गया है।

भारत की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार के विकास ट्रैक रिकॉर्ड और महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधारों ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है।

इस बजट में देश के युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति समेत देश के गरीब, पिछड़े और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं।

इस बजट में असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित किये जाने का निर्णय पूर्वोत्तर भारत के लिए एक सराहनीय कदम है। इससे असम राज्य में रोजगार सृजन और देश को रसायन एवं उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने में भी मदद मिलेगी।

इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं, समस्त असम वासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को हार्दिक आभार व धन्यवाद देता हूँ।

कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख 37 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करके देश के अन्नदाताओं को बड़े पैमाने पर सशक्त बनाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया गया है। इसके साथ ही दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत एक सराहनीय कदम

है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण सीमा को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया है, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा।

स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपये तक, आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण के लिए गारंटी शुल्क को घटाकर 1 प्रतिशत किया गया, जो कि देश के युवाओं को इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। वर्ष 2016 से अक्टूबर, 2024 तक कुल 73,151 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हो गए हैं, जिनमें कम से कम एक महिला निदेशक शामिल हैं। इन 9 सालों में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स ने 16 लाख 67 हजार नौकरियां उपलब्ध करवाई हैं, जो रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

रोगियों, विशेषकर कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने 36 जीवन रक्षक औषधियों को मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) से पूर्ण छूट वाली औषधियों की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव किया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है, जो कि वर्ष 2013-14 में 37 हजार करोड़ रुपये था। अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने का लक्ष्य है। हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में लगभग 1.1 लाख यूजी और पीजी मेडिकल शिक्षा सीटें जोड़ी हैं, जिसमें इस दौरान 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

जो काम कांग्रेस सरकार पिछले 60 वर्षों में नहीं कर पाई थी, वे काम मोदी सरकार ने केवल 10 वर्षों के भीतर ही कर दिखाए। 2014 में देश में 16 IIT थी, जो अब 23 हो गई हैं, 13 IIM थे, जो अब 21 हो गए हैं, 7 AIIMS थे, जो अब बढ़कर 24 हो गए हैं, 308 मेडिकल कॉलेज थे, जो 760 हो गए हैं और 740 यूनिवर्सिटीज़ थीं, जो कि अब 1,200 से अधिक हो गई हैं।

हमारी सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

वर्ष 2025-26 में रेल मंत्रालय के लिए 2 लाख 65 हजार करोड़ रुपये हैं, जिनका उपयोग रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण, अपग्रेडेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, रेल लाइनों के दोहरीकरण और अन्य बुनियादी ढांचे के कार्यों में किया जाएगा। असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10 हजार 440 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। वर्ष 2013-14 में रेलवे का बजटीय आवंटन केवल 63 हजार करोड़ रुपये था।

जल शक्ति मंत्रालय के अधीन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के लिए 74 हजार करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया गया है। इसमें करीब 90 प्रतिशत राशि जल जीवन मिशन के लिए खर्च की जाएगी और इस योजना का वर्ष 2028 तक विस्तार किया

जाएगा। जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं के बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और रख-रखाव के लिए कुल परिव्यय में भी वृद्धि की गई है।

अगले 10 वर्ष में 120 नए गंतव्यों और 4 करोड़ यात्रियों को लाने-ले-जाने के लिए क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने की संशोधित उड़ान स्कीम की घोषणा भी की गई है। पर्वतीय, आकांक्षी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी निर्माण किया जाएगा। 2014 तक भारत में 74 हवाई अड्डे थे, अब 160 हवाई अड्डे हैं। एयरपोर्ट की संख्या में वृद्धि से रोजगार के नए अवसर भी खुले हैं।

केंद्रीय बजट 2025-26 में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के लिए 5 हजार 915 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो चालू वित्त वर्ष के आवंटन से 47 प्रतिशत अधिक है। बजट 2024-25 में DoNER मंत्रालय के लिए 4,006 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जबकि वर्ष 2013-14 में यह आवंटन केवल 2 हजार करोड़ रुपए था।

देश को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इस बार रक्षा बजट हेतु 6 लाख 81 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। वर्ष 2013-14 में देश का रक्षा बजट 2 लाख 3 हजार करोड़ रुपए था, जिसमें पिछले 10 वर्षों के दौरान ऐतिहासिक वृद्धि देखने को मिली है।

सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय का बजटीय आवंटन 2013-14 में लगभग 31,130 करोड़ रुपये था, जो कि वर्ष 2025-26 में 2 लाख 87 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई मार्च, 2014 में 91,287 किलोमीटर से 1.6 गुना बढ़कर वर्तमान में 1,46,145 किलोमीटर हो गई है। अप्रैल, 2014 से बजटीय आवंटन में वृद्धि के साथ, सड़कों की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। 4 लेन और उससे अधिक के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई 2014 में 18,371 किलोमीटर से 2.5 गुना से अधिक बढ़कर 46,720 किलोमीटर हो गई है।

माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा पेश किया गया यह बजट नए भारत की नई उम्मीदों को साकार करने वाला है। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, साथ ही देश का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा।

कांग्रेस के शासनकाल में हम दुनिया की 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, जबकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में केवल पिछले 10 वर्षों के दौरान दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं और जल्द ही दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम होगा।

मैं, वित्त मंत्री महोदया को इस ऐतिहासिक, साहसिक और दूरगामी लक्ष्यों को साधने वाले बजट के लिए धन्यवाद करता हूँ।

श्री सुरेश कुमार कश्यप (शिमला) : मैं हमारी माननीय वित्त मंत्री महोदया द्वारा प्रस्तुत दूरदर्शी केंद्रीय बजट 2025-26 की सराहना करता हूँ। यह बजट 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के

गतिशील नेतृत्व में हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। सबका साथ-सबका विकास के सिद्धांत पर आधारित, यह बजट समावेशी विकास, शिक्षा, नवाचार और आर्थिक सशक्तिकरण का एक खाका है।

- इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक पैसा देने पर केंद्रित है। यह सुनिश्चित करके कि ₹12 लाख तक की आय वाले करदाताओं पर कोई कर देनदारी नहीं है, इस सरकार ने वेतनभोगी और निम्न मध्यम वर्ग के नागरिकों के कल्याण के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। इस कदम से बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच बहुत जरूरी राहत मिलने और उच्च खपत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- यह बजट सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उचित ध्यान दिया जाए। यह एमएसएमई क्षेत्र के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता बढ़े हुए क्रेडिट गारंटी कवर और स्टार्टअप, फुटवियर, चमड़ा, खिलौना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए बढ़ी हुई वित्तीय सहायता से स्पष्ट है।
- ग्रामीण विकास इस बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है, बजट ने श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे उनकी पंजीकरण को ई-श्रम पोर्टल पर सुविधाजनक बनाना और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत उन्हें स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। यह एक महत्वपूर्ण श्रमिक वर्ग की पहचान है और यह बदलती अर्थव्यवस्था में श्रमिक कल्याण की दिशा में एक प्रगतिकारक कदम है।
- मुझे गर्व के साथ यह उल्लेख करना है कि इस बजट में हमारे सरकार की भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण मिलता है, जिसमें ₹2.65 लाख करोड़ की भारी पूंजी आवंटित की गई है। यह निवेश हमारे रेल बुनियादी ढांचे और यात्रियों के अनुभव को बदलने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रेलवे का 100 अमृत भारत ट्रेनों, 50 NAMO भारत ट्रेनों और 200 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करने का महत्वाकांक्षी योजना आधुनिक, आरामदायक और प्रभावी रेल यात्रा की दिशा में हमारी कोशिशों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। 17,500 गैर-AC जनरल कोचों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना हमारे समाज के सभी वर्गों की सेवा करने की हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त, ₹1,16,514 करोड़ की सुरक्षा पहलों के लिए आवंटन, जिसमें ट्रैक नवीकरण और सिग्नलिंग उन्नयन शामिल हैं, यात्री सुरक्षा के प्रति हमारी प्राथमिकता को दर्शाता है। यह बजट भारत की आकांक्षाओं को जोड़ने, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और बेहतर गतिशीलता और कनेक्टिविटी के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को प्रेरित करने के हमारे दृष्टिकोण का प्रतीक है।
- इस बजट की एक प्रमुख विशेषता शिक्षा और कौशल विकास पर अभूतपूर्व ध्यान केंद्रित करना है। मंत्रालय को ₹1,28,650 करोड़ का आवंटन, जो पिछले वर्ष से 6.22% अधिक है, हमारे देश में कौशल अंतर को कम करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। यह हमारे सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि हम अपनी युवा शक्ति को उस ज्ञान से सशक्त करें, जो उन्हें एक तेजी से बदलती दुनिया में सफलता दिलाने में सक्षम बनाएगा।
- इस आवंटन में, ₹78,572 करोड़ को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए निर्धारित किया गया है, जो इस क्षेत्र के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। इसके अलावा, ₹50,078 करोड़ उच्च शिक्षा के लिए समर्पित किए गए हैं, जो प्रभावी

ढंग से बुनियादी ढांचे और अनुसंधान समर्थन को सुनिश्चित करेंगे।

- भारत नेट परियोजना के तहत सरकारी माध्यमिक स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की व्यवस्था एक क्रांतिकारी कदम होगा। आज के डिजिटल युग में, उच्च गति इंटरनेट तक पहुँच कोई विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता बन गई है। यह पहल यह सुनिश्चित करेगी कि ग्रामीण भारत के छात्र भी अपने शहरी समकक्षों के समान अवसर प्राप्त करें, डिजिटल विभाजन को समाप्त करें और समान शैक्षिक अवसर प्रदान करें।
- मुझे विशेष रूप से गर्व है कि सरकार ने 50,000 अटल टिकरिंग लैब (ATL) स्थापित करने का महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। हमारे 24.8 करोड़ छात्रों में से 50% छात्र सरकारी संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं, यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, क्योंकि इससे छात्रों में 21वीं सदी के कौशल जैसे कंप्यूटेशनल थिंकिंग, अनुकूली शिक्षा और डिज़ाइन माइंडसेट को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम भारत के युवा मनो को नवाचार और प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता बनने के मार्ग पर अग्रसर करेगा।
- हमारी सरकार ने गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुँच को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। इस वर्ष 10,000 चिकित्सा सीटों के अतिरिक्त करने का प्रस्ताव, और पांच वर्षों में 75,000 सीटों तक विस्तार करने का दीर्घकालिक दृष्टिकोण, हमारे देश में स्वास्थ्य पेशेवरों के गंभीर कमी को दूर करने में मदद करेगा।²
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के भविष्य निर्माण में भूमिका को पहचानते हुए, इस बजट में शिक्षा के लिए AI में उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है, जिसके लिए ₹500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह पहल 2023 में शुरू किए गए तीन AI केंद्रों पर आधारित है और हमारे छात्रों को AI-प्रेरित वैश्विक अर्थव्यवस्था में नेतृत्व करने के लिए तैयार करेगी।
- शोध और विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए, बजट में प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना के तहत 10,000 फेलोशिप प्रदान करने और निजी क्षेत्र-प्रेरित शोध एवं नवाचार में ₹20,000 करोड़ का निवेश करने का प्रस्ताव किया गया है। यह साहसिक कदम नवाचार को प्रोत्साहित करेगा, उच्च-मूल्य वाली नौकरियों का सृजन करेगा, और भारत को एक वैश्विक ज्ञान शक्ति में बदलने में मदद करेगा।
- मुझे यह कहना पड़ता है कि जो लोग इस बजट की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें न तो इसकी रूपरेखा का समझ है और न ही इसके कार्यान्वयन का। उनके तर्क आधारहीन हैं, जो उधारी की बातों से प्रेरित हैं, न कि विवेक से। देखिए उन राज्यों की स्थिति, जैसे कि मेरा राज्य, जहां शासन को एक चक्रीय अक्षमता, भ्रष्टाचार और गलत प्राथमिकताओं में बदल दिया गया है। उनके गलत शासन ने मेरे लोगों को दुखों के एक चक्र में फंसा दिया है-इतना कि उनकी अपनी पार्टी के सदस्य तक इस सदन में अपनी पहली भाषणों में इसे स्वीकार चुके हैं। मैं एक बात से सहमत हूँ-हां, मेरे राज्य के लोग कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन वे कांग्रेस के शासन, कांग्रेस की नीतियों, कांग्रेस की उपेक्षा के कारण कष्ट भोग रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस सरकार की साड़ी गारंटियाँ फेल हो चुकी है कांग्रेस सरकार पूर्ण रूपेण हिमाचल प्रदेश को सुसाशन प्रदान करने में विफल हो गयी है और फिर

भी, विपक्ष इस बजट पर सवाल उठाने की हिम्मत रखते हैं जो सशक्त बनाने, उन्नति करने और रूपांतरित करने का लक्ष्य रखता है? इस सरकार पर उंगली उठाने से पहले, शायद आपको अपनी असफलताओं पर गहरी नजर डालनी चाहिए !

- यह बजट केवल आंकड़ों का मामला नहीं है-यह आकांक्षाओं, सशक्तिकरण और प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे शिक्षा तंत्र को सशक्त बनाने, सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने और हमारे युवाओं को उज्ज्वल भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। लोगों, अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करने की यह सोच हमारी सरकार की समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः प्रमाणित करती है।
- हिमाचल प्रदेश के दृष्टिकोण में इस बजट में
- 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं हिमाचल के लाखों परिवारों को मिलेगा फ़ायदा।
- विकसित भारत का बजट हिमाचलवासियों के लिए भी खास है
- उड़ान योजना के तहत 120 नए स्थानों तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी पहाड़ी रीजन में यातायात सुविधा सुधारने तथा मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी प्रावधान है।
- किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख पी एम धान्य कृषि योजना 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ हिमाचल के किसानों को मिलेगा पूरा लाभ
- राज्य सरकार के साथ मिलकर 50 पर्यटक स्थलों को किया जायेगा विकसित
- हिमाचल प्रदेश के 22 स्थलों को राज्य सरकार के सहयोग से विकसित किया जायेगा इससे प्रदेश के टूरिज्म को भी विशेष बढ़ावा मि
- रेलवे की ओर से हिमाचल प्रदेश में होगा विस्तार इसके लिए को मिला 2716 करोड़ का बजट और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के 4 स्टेशनों का होगा पुनर्विकास
- इस बजट के साथ, हम एक आत्मनिर्भर, ज्ञान-आधारित, और समृद्ध भारत की नींव रख रहे हैं। हम भारत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर, और समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। मैं इस बजट की पूरी तरह सराहना करता हूँ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। तथा बजट का समर्थन करता हूँ।

SHRI ANUP SANJAY DHOTRE (AKOLA): I wholeheartedly appreciate the Budget 2025-2026, presented to this House. As a representative of the people of Akola, I am delighted to see that this Budget has taken into account the needs and aspirations of our citizens.

Our government has introduced a significant tax relief for the middle class, aiming to boost household savings and consumption. Under the new tax regime, individuals with an average monthly income of up to Rs. 1 lakh will be exempt from paying income tax. Furthermore, salaried individuals will

pay nil income tax up to Rs.12.75 lakh per annum, providing substantial relief to the working class. This move is expected to increase disposable income, stimulate economic growth, and alleviate financial burdens on middle-class households.

AGRICULTURE

Our government has announced several initiatives to boost agricultural productivity and rural development. Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana aims to enhance agricultural productivity in 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below-average credit parameters, benefiting 1.7 crore farmers across the country. Additionally, the Building Rural Prosperity and Resilience program will address under-employment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy, covering 100 developing agri-districts in its first phase.

To promote self-sufficiency in pulses, the government has launched a 6-year mission, Aatmanirbharta in Pulses, focusing on Tur, Urad, and Masoor. NAFED and NCCF will procure pulses from farmers during the next 4 years. Furthermore, a comprehensive program will be launched to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for vegetables and fruits, in partnership with States.

Other initiatives include the establishment of a Makhana Board Bihar to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. A National Mission on High Yielding Seeds will be launched to strengthen the research ecosystem, target development, and propagation of seeds with high yield, aiming to make more than 100 seed varieties commercially available.

The government will also bring a framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian Exclusive Economic Zone and High Seas, with a special focus on the Andaman & Nicobar and Lakshadweep Islands. A 5-year mission will be launched to facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming, promoting extra-long staple cotton varieties.

To support farmers, the loan limit under the Modified Interest Subvention Scheme will be enhanced from Rs. 3 lakh to Rs. 5 lakh loans taken through the Kisan Credit Card (KCC). Additionally, a urea plant with an annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up in Namrup, Assam.

As part of our government's commitment to protecting the rights and well-being of gig workers (amazon, zomato, swiggy,etc), we are proud to announce the introduction of identity cards and registration on the E-Shram portal for this vital segment of our workforce. This initiative will not only provide gig workers with a formal recognition of their employment but also enable them to access a range of benefits and social security schemes. Furthermore, we are pleased to extend healthcare benefits to gig workers under the PM Jan Arogya Yojana, ensuring that they and their families receive quality medical care and financial protection in times of need.

As part of our government's efforts to empower street vendors, we are revamping the PM SVANIDHI scheme to provide enhanced financial support. Under this revamped scheme, street vendors will have access to increased loans from banks, as well as UPI-linked credit cards with a limit of ₹30,000. This move aims to provide street vendors with the necessary financial resources to grow their businesses and improve their livelihoods.

As part of our government's efforts to rationalize TDS/TCS, we are pleased to announce several key changes. Firstly, we are doubling the limit for tax deduction on interest earned by senior citizens from the present Rs.50,000 to Rs. 1 Lakh, providing them with a significant reduction in their tax liability. Additionally, we are increasing the TDS threshold on rent from Rs. 2.4 Lakh to Rs. 6 Lakh per annum, which will benefit individuals who rent out properties.

Making healthcare more accessible and affordable, we are pleased to announce significant relief on the import of drugs and medicines. We have fully exempted 36 lifesaving drugs and medicines, used to treat cancer, rare diseases, and chronic diseases, from Basic Customs Duty (BCD). This exemption will help reduce the cost of these essential medicines, making them more affordable for those who need them.

The Increased education budget of ₹1.48 lakh crore will provide vital support to our educational institutions. I also welcome the announcement of new scholarships for students, including a ₹10,000 crore scholarship fund for SC/ST students.

Our government is committed to supporting domestic manufacturing and value addition, and we've taken significant steps to achieve this goal. In July 2024, we exempted 25 critical minerals, which were

not domestically available, from Basic Customs Duty (BCD). Building on this momentum, the Budget 2025-26 fully exempts cobalt powder and waste, scrap of lithium-ion battery, Lead, Zinc, and 12 more critical minerals from BCD. This move will help secure the domestic supply chain and reduce dependence on imports.

To promote domestic textile production, we've also added two more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. Furthermore, we've revised the BCD on knitted fabrics covering nine tariff lines from "10% to 20%" to "20%". These measures will not only boost domestic manufacturing but also make Indian products more competitive in the global.

To boost manufacturing of Lithion-ion battery in the country, 35 additional capital goods for EV battery manufacturing, and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing added to the list of exempted capital goods. Union Budget 2025-26 also continues exemption on BCD on raw materials, components, consumables or parts for ship building for another ten years. Budget also reduced BCD from 20% to 10% on Carrier Grade ethernet switches to make it at par with Non-Carrier Grade ethernet switches.

The healthcare budget increase to ₹89,155 crore will strengthen our healthcare system. The plans to expand the Ayushman Bharat scheme will benefit many poor families.

I also appreciate the government's focus on infrastructure development. The increased infrastructure budget of ₹10.25 lakh crore will support the development of roads, highways, railways, and other critical infrastructure. The plans to build 12,000 km of new roads and highways will provide vital connectivity to many rural areas.

Furthermore, I commend the government's efforts to promote digital India, with Initiatives such as the expansion of broadband connectivity to all villages and the development of digital infrastructure. This will bridge the digital divide and provide opportunities for rural India.

I also appreciate the government's focus on skill development and vocational training. The allocation of funds for initiatives such as the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) will equip our youth with the skills required for the modern workforce.

In addition, I welcome the government's efforts to promote entrepreneurship and job creation. The allocation of funds for Initiatives such as the Startup India program and the Mudra Yojana will provide support to startups and small businesses.

Lastly, I appreciate the government's commitment to environmental sustainability. The allocation of funds for initiatives such as the National Clean Energy and Environment Policy will promote the use of renewable energy and reduce our carbon footprint.

In conclusion, this Budget has taken many positive steps towards addressing the needs and aspirations of our citizens. I applaud the Government's efforts and look forward to seeing the impact of these initiatives.

श्रीमती स्मिता उदय वाघ (जलगांव) : मैं वर्ष 2025-26 के बजट का पूर्ण समर्थन और सराहना करती हूँ, जिसे हमारे देश की माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। यह बजट भारत को एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश के हर वर्ग के विकास को प्राथमिकता दी है, और यह बजट उसी दिशा में एक मजबूत पहल है।

यह बजट विकास की गति को और तेज करने वाला, समावेशी विकास को सुनिश्चित करने वाला, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने वाला, आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने वाला, और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की आर्थिक शक्ति को मजबूत करने वाला है। कृषि क्षेत्र भारत की रीढ़ है, और इस बजट में किसानों की बेहतरी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत 100 कृषि जिलों का विकास किया जाएगा, जिससे किसानों को उन्नत तकनीक, फसल विविधता और सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही, दलहन और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय विशेष मिशन शुरू किया गया है, जो किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा। कपास उत्पादकता मिशन से कपास किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। भारत के भविष्य को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा दिया गया है। 50,000 अटल टिकरिंग लैब्स स्थापित की जाएंगी, जिससे छात्रों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलेगा। 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे, और आईआईटी में क्षमता विस्तार के लिए 6,500 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। साथ ही, मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ गिग कामगारों को स्वास्थ्य सुरक्षा दी जाएगी। सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे कैंसर मरीजों को त्वरित और सुलभ उपचार मिल सकेगा। चिकित्सा शिक्षा में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। बुनियादी

ढांचे को मजबूत करने के लिए 71 वंदे भारत, अमृत भारत और नामो भारत ट्रेनों का संचालन किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरियों के विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे भारत ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। 3 लाख एमएसएमई को क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा, जिससे छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा।

मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए नई कर व्यवस्था में 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार किया जाएगा, जिससे 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से संवर्धित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की जाएगी, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस जी और हमारे दो उप-मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार इस बजट की योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचे के विकास, उद्योगों के विस्तार, किसानों की बेहतरी और सामाजिक कल्याण के लिए बेहतरीन योजनाएं बनाई जा रही हैं। यह राज्य देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और आने वाले वर्षों में और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचेगा।

जलगांव जिले में 25 वर्षों से लंबित लोअर तापी सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता है। यह परियोजना 6 तालुकों में 32,328 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी और लाखों लोगों को पेयजल उपलब्ध कराएगी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा अब तक ₹874.05 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन ₹2,014 करोड़ की शेष राशि के अभाव में यह अधूरी है। केंद्र सरकार द्वारा इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY-AIBP) के तहत शीघ्र शामिल कर आवश्यक वित्तीय सहायता दी जाए।

जलगांव जिला मुख्यालय होने के कारण यहां कई सरकारी और व्यावसायिक कार्यालय स्थित हैं। जलगांव RMS कार्यालय में प्रतिदिन 3,000-3,500 रजिस्टर्ड पत्रों का प्रसंस्करण होता है, और यदि इसे स्पीड पोस्ट हब (ICH) बनाया जाए तो यह संख्या 4,000-4,500 हो सकती है। भुसावल RMS से विलय किए जाने से डाक वितरण में 24 से 48 घंटे की अनावश्यक देरी हो रही है। जलगांव की सड़क, रेलवे और हवाई कनेक्टिविटी इसे एक उपयुक्त डाक हब बनाने के लिए आदर्श स्थान बनाती है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करती हूँ कि जलगांव RMS को एक स्वतंत्र स्पीड पोस्ट हब के रूप में विकसित किया जाए। यह बजट एक दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ बनाया गया है, जो सभी नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण को भी सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के संकल्प के साथ विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आइए, हम सभी मिलकर इस बजट के माध्यम से देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दें।

जय हिंद। जय महाराष्ट्र।

डॉ. हेमंत विष्णु सवरा (पालघर) : मैं केंद्रीय बजट पर अपने विचार रखता हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और आदरणीय वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 2025-26 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया, जो देश के विकास

और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करता है। इस बजट में अनेक क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है, जो न केवल देश के समग्र विकास को गति देंगे, बल्कि हमारे समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करेंगे। यह बजट देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना में बदलाव लाने का एक मजबूत प्रयास है। वित्त मंत्री महोदया ने इस बजट में कई ऐतिहासिक और विकासात्मक घोषणाएँ की हैं इसके लिए मैं और देश की पूरी जनता उनके इस दूरदर्शी बजट के लिए आभारी हैं।

वित्त मंत्री महोदया ने इस बजट में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कई अहम योजनाओं का ऐलान किया है। खासकर मध्यम और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कर में राहत दी गई है। साथ ही, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए निवेश को सरल बनाने की योजना बनाई गई है। सरकार ने नौकरी सृजन पर भी ध्यान केंद्रित किया है, और युवा वर्ग के लिए कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाओं का ऐलान किया है। यह कदम हमारे पालघर के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे और छोटे व मझोले उद्योगों को एक नया जीवन देंगे।

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि नए टैक्स सिस्टम के तहत ₹12 लाख तक की इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है।

महाराष्ट्र के लिए रेलवे बजट 2025-26 में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं, जो राज्य में रेलवे नेटवर्क के विस्तार और सुविधाओं में सुधार करेगा।

* 2009-14 के औसत बजट आवंटन ₹1,171 करोड़ था, जबकि 2025-26 में यह ₹23,778 करोड़ तक बढ़कर 20 गुना हो गया है।

* 2014 के बाद से महाराष्ट्र में 2,105 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं, जो मलेशिया के पूरे रेल नेटवर्क से भी ज्यादा हैं।

3,586 किलोमीटर रेलवे लाइनें विद्युतीकरण की गई हैं, और राज्य अब 100% विद्युत संचालित है। 47 रेल परियोजनाएँ प्रगति पर हैं, जिनकी कुल लंबाई 6,985 किमी और कुल लागत 1,58,866 करोड़ है। इसमें 4 नई परियोजनाएँ और बुलेट ट्रेन परियोजना भी शामिल हैं।

132 अमृत स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं, जिन पर 5,587 करोड़ रुपये खर्च होंगे। (पाल अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र पालघर में रेलवे के विकास के लिए माननीय रेल मंत्री से कुछ अनुरोध करना चाहता हूँ।

माननीय रेल मंत्री ने पहले ही नासिक-दहानु नई ब्रॉड गेज रेल लाइन परियोजना के लिए अंतिम स्थान सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी थी। मैं माननीय रेल मंत्री से इसे जल्दी से जल्दी पूरा करने का आग्रह करता हूँ। साथ ही मेरा निवेदन है कि इस रेलवे मार्ग में दहानु, मोखाडा जैसे लच्छार, विक्रममड

जनजातीय क्षेत्र को जरूरी शामिल किया जाए क्योंकि इन जनजातीय क्षेत्र में भी परिवहन की समस्या का समाधान हो सके और ये क्षेत्र भी विकसित हो सके।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि नई लोकल ट्रेन शुरू करने के लिए दिवा-भिवंडी-अनगांव-अम्बाडी-कुदुस-वाडा-विक्रमगढ़ स्ट पर नई लोकल लाइन (ट्रैक) की शुरुआत की आवश्यकता के संबंध में जल्दी फैसला लेंगे और पालघर के लोगो को एक लोकल ट्रेन की सौगात देंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। नीचे उन प्रमुख बिंदुओं का विवरण प्रस्तुत है:

1. कैंसर दवाएं - कस्टम ड्यूटी मुक्त 36 दवाएं: कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में उपयोग होने वाली 36 जीवनरक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे इन दवाओं की कीमतों में कमी आएगी, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी।
2. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना 100 जिले / 1.07 करोड़ किसान लाभान्वित: इस योजना के तहत 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा।
3. तूर, मसूर, उरद 6 वर्षों का कार्यक्रम: तूर, मसूर और उरद की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 6 वर्षों का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें राज्य एजेंसियां किसानों से इन दालों की खरीद गारंटीड कीमतों पर करेंगी, जिससे किसानों को समर्थन मिलेगा।
4. किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसान 3 लाख से 5 लाख तक: किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की जाएगी, जिससे 7.7 करोड़ किसानों को अधिक वित्तीय सहायता मिलेगी।
5. डाक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण 2.4 लाख डाक सेवक: डाक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 2.4 लाख डाक सेवकों की नियुक्ति की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी।
6. MSME ऋण - 5 करोड़ से 10 करोड़ तक: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए ऋण सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये की जाएगी, जिससे इन उद्यमों को वित्तीय सहायता मिलेगी।
7. स्टार्टअप 10 करोड़ से 20 करोड़ तक: स्टार्टअप्स के लिए ऋण सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये की जाएगी, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
8. ST/SC महिला ऋण 2 करोड़ की व्यवस्था: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 2 करोड़ रुपये की विशेष ऋण व्यवस्था की जाएगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। SC/ST महिला businessmen बनायेंगी।
9. सक्षम आंगनवाड़ी/पोषण 2.0 8 करोड़ बच्चे / 1 करोड़ गर्भवती महिलाएं: आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम के तहत 8 करोड़ बच्चों और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिससे पोषण स्तर में सुधार होगा। कुपोषण कम होगा।

10. अटल टिकलिंग लैब 50,000: अटल टिकलिंग लैब्स की संख्या 50,000 तक बढ़ाई जाएगी, जिससे छात्रों में तकनीकी कौशल का विकास होगा।
11. PHC/ सरकारी स्कूल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी: प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
12. मेडिकल कॉलेज छात्रों की सीट 10,000 प्रति वर्ष वृद्धि: मेडिकल कॉलेजों में छात्रों की सीटों की संख्या प्रति वर्ष 10,000 बढ़ाई जाएगी, जिससे चिकित्सा शिक्षा में वृद्धि होगी।
13. जल जीवन मिशन 2028 तक विस्तार: जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
14. 50 पर्यटन स्थलों का विकास: 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
15. पर्यटन रोजगार - - स्व रोजगार कुपोषण निवारण: पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और स्व-रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे, जिससे कुपोषण निवारण में सहायता मिलेगी।
16. सिविल अस्पताल / ट्रॉमा सेंटर / जबाहर अस्पताल पालघर में: पालघर में सिविल अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर और जवाहर अस्पताल की स्थापना की जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी।
17. आदिवासी - 7 EMRC, वरनी हाट, आदिवासी खेल अकादमी, सांस्कृतिक केंद्र: आदिवासी क्षेत्रों में 7 EMRC, वरली हाट, आदिवासी खेल अकादमी और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे उनकी संस्कृति और खेलों को बढ़ावा मिलेगा।
18. वडवान में हवाई अड्डा: वडवान में हवाई अड्डे की स्थापना की जाएगी, जिससे परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा।
conneadily बढ़ेगी, रोजगार उपलब्ध लेंगे
19. वडवान बंदरगाह - 10 लाख नौकरियां: वडवान बंदरगाह के निर्माण से 10 लाख नौकरियों का सृजन होगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
20. कौशल विकास: कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा।
21. PMJAY - 5 लाख आवास 64,259/55,498: प्रधानमंत्री जन आवास योजना के तहत 5 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा, जिससे 64,259/55,498 परिवारों को लाभ मिलेगा।

धन्यवाद। जय हिंद।

श्री छत्रपाल सिंह गंगवार (बरेली) : मैं सर्वप्रथम चहुँमुखी, समावेशी विकास तथा व्यापक दूर दृष्टि वाले इस आम बजट - 2025 के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ।

यह प्रगतिशील, विकास उन्मुख बजट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का रोड मैप है, अर्थात् ऐसा विकास जिससे भारतवर्ष आत्मनिर्भर तथा विकसित बन सके, जिसका फायदा उद्यमी से लेकर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी मिल सके। यह क्रांतिकारी बजट महिलाओं, युवाओं तथा मध्यम वर्ग के जीवन में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाने का सार्थक प्रयास है।

यह आम बजट जनता जनार्दन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला बजट है। भारतवर्ष की आबादी का 31 प्रतिशत हिस्सा मध्यम वर्ग का है। अब यह वर्ग अपने सपनों को हकीकत में बदल सकेगा। मध्यम आय वर्ग के लोगों को सरकार ने इस बजट में 12 लाख तक की सालाना आय पर किसी भी प्रकार का आयकर नहीं लगा कर बहुत बड़ा लाभ दिया है। मध्यम वर्ग को आयकर में दी गई यह छूट भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उत्प्रेरक का कार्य करेगी।

इस बजट से देश का किसान खुशहाल होगा तथा गांव समृद्ध होंगे। किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं से खेती किसानों के पारंपरिक तौर तरीकों में बदलाव आया है। फसल का उत्पादन बढ़ाने, उसका उचित मूल्य मिलने और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होना कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए कृषि अब अर्थव्यवस्था का प्रथम इंजन बनता जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण की अधिकतम सीमा 3 लाख से बढ़कर 5 लाख किया जाना कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में एक ठोस कदम है तथा साथ ही में कपास उत्पादकता मिशन से किसानों की आय बढ़ेगी और भारत के परंपरागत वस्त्र क्षेत्र में नई जान आएगी। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना से मखाने के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन व्यवस्था में व्यापक सुधार आएगा इस कारोबार में लगे किसानों की आर्थिक दशा तेजी से सुधरेगी व असम के नामरूप में 12.7 लाख टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला उर्वरक संयंत्र, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना व राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, सभी कृषि विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम हैं। इस बजट में जल जीवन मिशन का 2028 तक विस्तार करने से ग्रामीण घरों में शत प्रतिशत पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध होगा। साथ ही में इस मिशन के द्वारा 2 करोड़ ग्रामीण रोजगार भी सृजित होगा।

विकसित भारत की इस यात्रा में महिलाओं की भागीदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए महिला केंद्रित विकास और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की 70 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य वाला बजट पेश किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा, पोषण और स्वास्थ्य के साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए बजट में नए महिला उद्यमी को दो करोड़ तक के सावधि ऋण का प्रस्ताव किया है। स्त्री शक्ति योजना के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा महिला उद्यमी को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है।

किसान बजट में शहरी गरीबों की मदद के लिए प्रावधान किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी-पटरी वालों को व्यापार के लिए धन उपलब्ध करने के साथ ही निर्धन आबादी और कमजोर समूह की सहायता के लिए भी अभियान चलाया जाएगा जिससे शहरों में रहने वाले गरीबों की आय बढ़ाने, नियमित जीविका अर्जित करने का अवसर प्राप्त होने के साथ ही जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। यह योजना शहरों में गरीबों को काम का अवसर प्रदान करने के साथ ही उन्हें सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों के दायरे में लाने वाली होगी।

इस बजट में कैंसर का इलाज सर्व सुलभ कराने के लिए देश के सभी जिला अस्पतालों में कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए इन अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही 36 जीवन रक्षक दवाओं पर आयात शुल्क खत्म करने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है तथा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा जिससे सुदूर इलाकों में टेली मेडिसिन के मार्फत गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं का पहुंचना आसान हो जाएगा।

इस बजट में भारतवर्ष को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से जुड़े कामों को गति देने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत स्कूलों में 50 हजार अटल टिकरिंग लैब की स्थापना तथा सरकारी माध्यमिक स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना और आईआईटी की क्षमता विस्तार, स्कूली स्तर पर बच्चों को नवाचार से जोड़ना, निश्चय ही यह महत्वपूर्ण कदम शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।

इस बजट में भारतवर्ष के शहरों की आज की जरूरत को समझा है तथा इसकी पूर्ति के लिए एक लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनाने का इस बजट में महत्वपूर्ण प्रस्ताव किया गया है। इसके जरिए शहरो के पुनर्विकास के जरिए बुनियादी ढांचे को विकसित किये जाने का प्रावधान है। प्रथम चरण में 100 शहरों के पुनर्विकास की योजना लाई जाएगी। इसके तहत शहरों के मूल स्वरूप यानी केन्द्रीय इलाके को विकसित किया जाएगा।

इस आम बजट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े एक करोड़ गिग वर्कर्स नए दौर की सेवा अर्थव्यवस्था को काफी गतिशीलता प्रदान करते हैं। इस कारण से, इन सभी गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा इन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा तथा पहचान पत्र देने के साथ ई-श्रम पोर्टल पर भी पंजीकरण की व्यवस्था रहेगी।

इस आम बजट में आदिवासी जनजातियों को भारत की मुख्य धारा में शामिल करने के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट में पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि करते हुए आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में विकास योजनाओं को गति देने का स्पष्ट इरादा है। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी बाहुल्य गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए शिक्षा स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी सुविधाओं को बेहतर करना और कमजोर आदिवासी समूह की आजीविका के अवसरों को बढ़ाना है। आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का बजट बीते वर्षों से बढ़ा दिया गया है।

एमएसएमई देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी परिभाषा का बदलाव इसके विस्तार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम होगा। 500 करोड़ तक की सालाना टर्नओवर वाली कंपनियां अब मीडियम श्रेणी में आएंगी, जिससे वे एमएसएमई से जुड़ी स्कीमों का लाभ उठा सकेंगी। एमएसएमई को लोन मिलने में होने वाले दिक्कतों को इस बजट में दूर करने का प्रावधान किया गया है। माइक्रो एंटरप्राइजेज को किसानों की तरह 5 लाख तक की सीमा वाले क्रेडिट कार्ड जारी करने की व्यवस्था की गई है।

इस बजट में निवेशकों का भरोसा बढ़ाने और ईज-ऑफ-डूइंग बिजनेस की दिशा में व्यापक प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न कानून से जुड़े 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने का व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए केन्द्र सरकार जल्द ही संसद में पेश जन विश्वास विधयेक 2.0 पेश करेगी। इसके अंतर्गत ईज-ऑफ-डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ते हुए कई कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में छूट देने की व्यवस्था की है।

इस बजट में नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के संदर्भ में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने की व्यवस्था की गई है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपये से एक परमाणु ऊर्जा मिशन बनाने की व्यवस्था की जाएगी, जो कि देश में पांच छोटे परमाणु संयंत्र स्थापित करने में सहयोग करेगा। इससे परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता घटेगी।

भारत में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। उतनी ही संगठित व असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस बजट में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने व आर्थिक विकास दर को रफ्तार देने को पर्यटन में भी रोजगार प्रेरित विकास का प्रावधान किया गया है तथा पर्यटन में रोजगार प्रेरक विकास को सुगम बनाने के लिए कई उसे कदम उठाए जाने की व्यवस्था है। इनमें वीजा नियमों को आसान बनाना, ई-वीजा सुविधा देना तथा धार्मिक व मेडिकल पर्यटन को प्रोत्साहन देना शामिल हैं।

इस बजट में जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी बढ़ाने को सरकार ने नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग मिशन की स्थापना की व्यवस्था की है। इसके अंतर्गत मैन्यूफैक्चरिंग को आसान बनाने तथा लागत कम करने, गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने, तकनीकी उपलब्ध कराने जैसी चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। निर्यात को ग्रोथ इंजन का प्रमुख स्तंभ मानते हुए बजट में एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन स्थापित करने का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत निर्यातकों को कर्ज मुहैया करने के साथ विदेश में निर्माण करने जैसी सुविधा बहाल करने में मदद की जाएगी, जिससे वस्तुओं का निर्यात बढ़ेगा व रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

इस बजट में रेलवे को और बेहतर बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए जाने की व्यवस्था है, जिससे 17,500 सामान्य कोच, 200 वन्दे भारत, 100 अमृत भारत ट्रेनों के निर्माण जैसी परियोजनाओं को इस बजट में मंजूरी दी गई है। साथ ही, इसमें नई लाइनें बिछाने, दोहरीकरण, स्टेशनों का पुनर्विकास, फ्लाईओवर निर्माण, अंडरपास सहित कई अन्य परियोजनाओं की भी व्यवस्था है।

इस बजट में जल तटीय आर्थिक गतिविधियों को सम्बल देकर ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने की पूर्ण व्यवस्था है। इसके अंतर्गत समुद्री विकास कोष (मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड) बनाने का प्रावधान है। साथ ही, इसमें जहाज निर्माण को प्रोत्साहन देने के

लिए जहाज निर्माण वित्तीय सहायता नीति का नवीनीकरण किया गया है।

यह प्रगतिशील व समावेशी बजट पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक आर्थिक आवश्यकताओं का सावधानी पूर्ण समन्वय है, जो वंचितों के उत्थान के साथ-साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने का लक्ष्य भी रखता है। यह राष्ट्र की समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम भी है। मुझे सम्पूर्ण विश्वास है कि यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सामाजिक गतिशीलता, और सशक्त वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन ला सकता है तथा यह बजट मध्यम वर्ग, युवा, अन्नदाता और नारी कल्याण के प्रति हमारी सरकार के दृढ़ संकल्प को परिलक्षित करने वाला है।

SHRI SUKANTA KUMAR PANIGRAHI (KANDHAMAL): I would like to convey my sincere thanks for giving me an opportunity to express my views on the budget announcements with respect to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.

I feel myself privileged and express my thanks on the wonderful and effective aspects of the union budget 2025-26.

Under the leadership of our Yashaswi Hon'ble Prime Minister - Shri Narendra Modi ji, the country has identified and emphasized key areas of growth and development in agriculture, rural economy, and allied sectors and expressed its commitment to address ongoing challenges faced by agriculture and rural development.

I convey my heartfelt thanks to our finance minister for announcing a 'Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana' in partnership with states. The states, particularly, Odisha from where I belong to, can strategically position themselves to leverage the benefits for the betterment of agricultural and allied sectors by converging existing schemes and specialized measures and benefiting about 1.7 cr. farmers.

Being a student of Agriculture Science, I salute to the deep revolutionary thoughts behind the initial implementation of such a smart and integrated schematic intervention with a view to enhance agricultural productivity, adopt crop diversification and sustainable agriculture practices, augment post-harvest storage at the panchayat and block level, improve irrigation facilities, and facilitate availability of long-term and short-term credit.

Our government is the government of poor, destitute and downtrodden. Our government is always mindful about bringing in an atmosphere of balanced growth and development. This budget has appropriately conceptualised launching of a comprehensive multi-sectoral Rural Prosperity and

Resilience' programme in partnership with states. There is immense need to address unemployment in rural areas and under-employment in agriculture by ensuring skilling, more investment, adoption of technology, and re-orienting the existing rural economy.

With the change in time and modifications in the tastes and preferences of our citizens, the agrarian States like Odisha requires a comprehensive and multi-dimensional development approach, focusing on infrastructure, employment, agriculture, health, education, and social equity. We should capitalize on government schemes, adopt relevant technology, and ensure local participation to bring about holistic growth in rural areas.

By addressing challenges such as poverty, underemployment, climate vulnerability, and marginalization, we can create a sustainable and thriving rural economy that uplifts all sections of society. I commend the budget for considering all of these this year, sir.

All of us know that our country's need for self-reliance in pulses production is driven by several factors, including food security, economic stability, and sustainable agricultural practices. This budget has rightfully emphasized on the self-reliance aspect of pulses production and urged to reduce dependency on imports by announcing introduction of a 6-year "Mission for Aatmanirbharta in Pulses with a special focus on Tur, Urad and Masoor.

It was heartening to note that the government has given its due to the fruits and vegetable sector this time in the budget. A developed fruit and vegetable sector will not only fulfil citizens' nutritional needs, it will facilitate enhancing income levels. The proposed programme for production, supplies and processing would ensure remunerative prices for farmers.

This year's budget is a farmers' budget. In addition to ensuring enhanced credit flow to the agriculture and rural sectors, the budget has expanded the loan limit under the Modified Interest Subvention Scheme from Rs.3 lakh to 5 lakh for loans taken through the KCC which will facilitate short term loans for 7.7 crore farmers, dairy farmers and fishermen.

Our fishery sector has enormous opportunity of growth. Our government has seen this opportunity and with the Sankalp of Sabka Sath, Sabka Vikas, Sabka Prayas, we are all set to try to ensure Sabka Viswas by assuring adequate and timely coordination with all coastal States/Union. The proposal to

ensure an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian Exclusive Economic Zone and High Seas is a way forward to unlock the untapped potential of our rich and prosperous marine sector.

While extending deep gratitude from the bottom of my heart, I urge the Government to become a friend, philosopher and guide of coastal states like Odisha and support in our strive for attaining a glorious status -Viksit Odisha by 2036.

The time has come to understand and underscore implementation issues and address critical gaps in the value chain, including infrastructure, modernization, traceability. production, productivity, post-harvest management, and quality control.

I sincerely hope that with proper and timely implementation of the budget announcements; these critical issues would be addressed and we would have a smooth journey towards our greater goal i.e. achieving goal of Viksit Bharat by 2047.

Once again, I extend thanks for giving me an opportunity to express a few points on budget announcements in the areas of Agriculture and Allied sector.

ai kisan! Jai Jagannath! Jai Hind!

श्री मितेश पटेल (बकाभाई) (आणंद) : विकसित भारत के लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने की आशाओं को मजबूत करने वाले इस गेमचेंजर एवं ऐतिहासिक बजट के लिए मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, परिश्रमी एवं नारी शक्ति माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूँ। केंद्रीय बजट से एक दिन पूर्व आर्थिक समीक्षा में ही सरकार ने बजट की भावी दिशा बता दिया था। आर्थिक सर्वेक्षण में स्वतंत्रता के 100 साल बाद 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की दृष्टि से काफी बातें कही गई थीं। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का लक्ष्य विरासत के साथ विकास है यानी भारत को अपनी पहचान आध्यात्मिक अंतःशक्ति सभ्यता, संस्कृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए इसे एक मुख्य आधार बनाते हुए विश्व में विकसित देश बनाना है।

यह सच भी है कि भारत की क्षमता और संभावनाओं पर वैश्विक विश्वास और बढ़ा है। वित्त मंत्री ने भविष्य दृष्टि के लिए कहा कि हम अगले 5 वर्षों को सबके विकास को साकार करने और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के एक अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं।

बजट को पांच बिंदुओं पर आधारित बनाया गया है? विकास की गति बढ़ाना, समग्र विकास, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू संवेदनाओं को मजबूत करना तथा मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मेक इन इंडिया, रोजगार और अनुसंधान, ऊर्जा आपूर्ति, खेलों का विकास और एमएसएमई यानी सूक्ष्म व लघु उद्योगों का विकास हमारी विकास यात्रा में शामिल है और इसका ईंधन सुधार है। इन दो पहलुओं को देखने के बाद बजट आसानी से समझा जा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण में चुनौतियों की चर्चा करते हुए कहा गया था कि विकास दर की वांछनीयता निर्विवाद है, लेकिन यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि वैश्विक परिवेश, राजनीतिक और आर्थिक कारण भी भारत के विकास परिणामों को प्रभावित कर रहे हैं यानी चुनौतियां हमारे समक्ष हैं और उनका सामना करना ही पड़ेगा। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट हो, समस्या दिखाई दे रही हो तो रास्ते अपनाने और नीतियों के निर्धारण में आसानी हो जाती है।

वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण उत्पन्न समस्याओं और चिंता के बीच विकास के रास्ते में उत्पन्न बाधाओं का सामना करने के लिए वर्तमान परिस्थितियों में जितना कुछ संभव है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसे पूरा करने की कोशिश की है। सच है कि भूमि, श्रम, कृषि और प्रशासन के क्षेत्र में संभावित साहसिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील सुधारी से सरकार बची है। बावजूद 2025-26 का बजट उस भारत की छवि को मजबूत करता है, जो सुधार के लिए तत्पर है, संभावनाओं से भरा हुआ है तथा विश्व में उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है। प्रधान मंत्री ने देश के लिए चार जातियां बताई थीं? गरीब, युवा, किसान और महिला। कुल मिलाकर 10 क्षेत्रों में बदलाव संबंधी कोशिशों पर फोकस किया गया है। 2024-25 के 48 लाख 21 हजार करोड़ की तुलना में इस बार कुल 50 लाख 65 हजार करोड़ का बजट है। इसका अर्थ है कि सरकार को वित्तीय चुनौतियों का आभास है और खर्च ज्यादा बढ़ाया नहीं गया है, जो व्यवहारिक है। इन परिस्थितियों में वित्तीय घाटे को संपूर्ण अर्थव्यवस्था के 4.4% तक रखना बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5 वर्ष पहले यह 9.02% था।

आयकर में छूट ऐतिहासिक है, नौकरी पेशा वालों के लिए 12 लाख 75 हजार और 12 लाख तक आम कारोबारी के लिए आय कर में छूट की कल्पना किसी को नहीं थी। इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा उसकी हो रही है। इसे हम राजनीतिक रूप से प्रभावी मध्यमवर्ग को खुश करने की योजना बता सकते हैं। लेकिन इसके आर्थिक और वित्तीय महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मध्यम वर्ग का आर्थिक और वित्तीय सशक्तिकरण तथा उसकी क्रय शक्ति बढ़ाने का लक्ष्य शामिल है। मध्यम वर्ग की जेब में धन बचने का अर्थ है कि वे आवश्यकताओं पर ज्यादा खर्च कर सकेंगे, जिससे प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास गति को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अपने जीवन को ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल होने की कल्पना से अंदर सकारात्मकता का विकास होगा और इसका असर हमारे संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण पर पड़ेगा। इसके साथ 95% आयकरदाता अब आयकर देने से मुक्त हो चुके हैं। इस दृष्टि से यह साहसी क्रांतिकारी ऐतिहासिक कदम है।

भारत के मूल यानी विरासत के साथ समाज के नीचे से ऊपर सभी तत्वों के संतुलित विकास के साथ ही देश अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हम देखेंगे कि समाज के सबसे निचले लपके यानी सड़कों पर सामान बेचने वाले, श्रमिकों, असंगठित मजदूरों, किसानों, मत्स्यपालकों, लघु, मध्य व सूक्ष्म उद्योगों, युवा नव उद्यमियों, धार्मिक, आध्यात्मिक केन्द्रों आदि सभी समूहों के विकास

की दौर में गतिशील होने की व्यवस्था इस बजट में है। भारत के प्रमुख धार्मिक, आध्यात्मिक, संस्कृत स्थान पर जिस ढंग से तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, वह हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। इसे ध्यान में रखते हुए 50 ऐसे स्थलों को राज्यों की भागीदारी के साथ विकसित करने की योजना है। रोजगार प्रेरित विकास के लिए आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, यात्रा और संपर्क में सुधार करना, वीजा शुल्क में छूट के साथ ई-वीजा को और बढ़ाना, चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरह के व्यावहारिक सूक्ष्मता स्तरीय सोच का कितना असर होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। भविष्य के एक विशेष पहचान वाले आदर्श महाशक्ति की दृष्टि से आधारभूमि बनाने की कोशिश लगातार मोदी सरकार के बजट में है और इसे इस बार सशक्त और त्वरित करने की कोशिश की गई।

सरकार ने सर्वेक्षण में स्पष्ट किया था कि कृषि, जिसका योगदान कुल अर्थव्यवस्था में 16% के आस-पास है, में काफी क्षमता है और प्रतिवर्ष यह 0.75 प्रतिशत से एक प्रतिशत का योगदान दे सकता है। बजट में कृषि विकास के लिए जबरदस्त कदमों की घोषणा है। प्रधान मंत्री धन-धान्य योजना में ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा, जहां कृषि उत्पादकता कम है। इनसे उत्पादकता बढ़ाने, खेती में विविधता लाने, सिंचाई और उपज के बाद भंडारण की क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। किसान क्रेडिट कार्ड अभी 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के साथ किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए छह वर्ष का मिशन शुरू होगा। खाद्य तेलों के उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। नैफेड और एनसीसीएफ में पंजीकृत किसानों से दालें खरीदेगी। श्रीअन्न, सब्जियां और फलों के लिए भी बड़ी योजना का प्रस्ताव है। ऐसे किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजना राज्यों के साथ साझेदारी के साथ लॉन्च किया जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान शुरू किया जाएगा। इससे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षमताएं मजबूत करने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन के अंतर्गत बीजों की ऐसी 100 से अधिक किस्मों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव कितना महत्वपूर्ण है, यह किसान और कृषि से जुड़े विशेषज्ञों को अच्छी तरह बताएं। मछली पालन में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, इसका बाजार करीब 60 हजार करोड़ का है। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों और गहरे समुद्र में स्थायी मत्स्य पालन पर जोर दिया गया। अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप समूह को मत्स्य पालन के विकास के लिए लक्षित किया गया है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का कर्ज का प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। यही नहीं समुद्री उत्पादों पर सीमा शुल्क सीधे 30% से घटाकर 5% करना बहुत बड़ा कदम है। अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। ध्यान रखिए मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने की घोषणा के बाद एक्वाकल्चर स्टॉक में 12.5% तक की वृद्धि हुई। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा। कपास उत्पादकता मिशन के तहत उत्पादकता में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी और कपास के लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में इन सबसे किसानों की आय व्यापक रूप से बढ़ाने की कल्पना की गई है। यूरिया उत्पादन के बढ़ावे पर फोकस है और असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा।

गांव के साथ शहरों को विकास केन्द्र बनाने के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित करने की योजना इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आर्थिक विकास के साथ शहरों की व्यवस्था कमजोर हो रही है। उस कारण वे क्षमताओं के अनुरूप अर्थव्यवस्था में योगदान देने की जगह अपनी ही चुनौतियों से निपटने में ज्यादा उलझे हुए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। ये एमएसएमई उत्पादकों के साथ निर्माण में 45 प्रतिशत योगदान कर रहे हैं। इसमें वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें आगे बढ़ने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का आत्मविश्वास मिलेगा। कर्ज की सीमा 5 करोड़ से 10 करोड़ कर 1.5 लाख करोड़ के आवंटन से इस क्षेत्र के उद्योगों के लिए उत्पादन और वितरण में निश्चित रूप से आसानी होगी। एमएसएमई को विदेशों में शुल्क में सहायता मिलेगी। स्टार्ट-अप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कमी होगी। भारत को चीन के समानांतर खिलौने का सबसे बड़ा हब बनाने का लक्ष्य पहली बार बजट में है। खिलौना उद्योग के लिए मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना शुरू की जाएगी, नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। इसके बाद स्किल और विनिर्माण के लिए इको सिस्टम बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ? ?भारत ट्रेड नेट? (BTN) की स्थापना की जाएगी, जो व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच होगा, इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाएगा।

स्वाभाविक रूप से बजट में ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों की दृष्टि से भी काफी प्रस्ताव है। विकसित भारत की दृष्टि से 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु नाभिकीय ऊर्जा के विकास के लक्ष्य की दृष्टि से निजी क्षेत्र और साधनी क्षेत्र दोनों के लिए योजनाएं घोषित हैं। परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे।

इस तरह के अनेक पहलू बजट में हैं, जो हमारे अपने देश के प्रति आत्मविश्वास पैदा करने के साथ योगदान देने की आर्थिक वित्तीय ठोस आगीदारी दे सकता है। कोई भी बजट आलोचनाओं से परे नहीं है और इनमें भी ऐसे बिंदु निकाले जा सकते हैं। कुल मिलाकर यह भारत को भारत के अनुरूप सामग्र और प्रेरक विकास की दृष्टि वाले बजट का ही अगला पड़ाव है, जिसमें हमारे, आपके, सबके लिए आर्थिक दृष्टि से योगदान देने की भूमिका निभाने के कदम उठाने की कोशिश है।

विकसित भारत के लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस शानदार बजट के लिए माननीय नरेंद्र मोदी साहब का आभार व्यक्त करता हूँ एवं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूँ।

श्री हंसमुखभाई सोमाभाई पटेल (अहमदाबाद पूर्व) : केंद्रीय बजट से एक दिन पूर्व आर्थिक समीक्षा में ही सरकार ने बजट की भावी दिशा बता दिया था। आर्थिक सर्वेक्षण में स्वतंत्रता के 100 साल बाद 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की दृष्टि से काफी बातें कहीं गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार का लक्ष्य विरासत के साथ विकास है। यानी भारत को अपनी पहचान आध्यात्मिक अंतःशक्ति सभ्यता, संस्कृति के साथ सामंजस्य बिठाते, इसे एक मुख्य आधार बनाते हुए विश्व में विकसित देश बनाना।

माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण का आरंभ इन्हीं बिंदुओं से किया। सर्वेक्षण में कहा गया था कि विकसित भारत बनाने के लिए एक या दो दशक तक, स्थिर कीमतों पर औसत 8 प्रतिशत की विकास दर हासिल करने की जरूरत है। माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। इसके आगे उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया है।

यह सच भी है कि भारत की क्षमता और संभावनाओं पर वैश्विक विश्वास और बढ़ा है। वित्त मंत्री ने भविष्य दृष्टि के लिए कहा कि हम अगले 5 वर्षों को सबके विकास को साकार करने और सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के एक अनूठे अवसर के रूप में देखते हैं।

बजट को पांच बिंदुओं पर आधारित बनाया गया है- विकास की गति बढ़ाना, समग्र विकास, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू संवेदनाओं को मजबूत करना तथा मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि मेक इन इंडिया, रोजगार और अनुसंधान, ऊर्जा आपूर्ति, खेलों का विकास और एमएसएमपी यानी सूक्ष्म व लघु उद्योगों का विकास हमारी विकास यात्रा में शामिल हैं और इसका ईंधन सुधार हैं। इन दो पहलुओं को देखने के बाद बजट आसानी से समझा जा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण में चुनौतियों की चर्चा करते हुए कहा गया था कि विकास दर की वांछनीयता निर्विवाद है, लेकिन यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि वैश्विक परिवेश राजनीतिक और आर्थिक कारण भी भारत के विकास परिणामों को प्रभावित कर रहे हैं। यानी चुनौतियां हमारे समक्ष हैं और उनका सामना करना ही पड़ेगा। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट हो, समस्या दिखाई दे रहे हैं तो रास्ते अपनाने और नीतियों के निर्धारण में आसानी हो जाती है।

वास्तव में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण उत्पन्न समस्याओं और चिंता के बीच विकास के रास्ते में उत्पन्न बाधाओं का सामना करने के लिए वर्तमान परिस्थितियों में जितना कुछ संभव है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उसे पूरा करने की कोशिश की है। सच है कि भूमि, श्रम, कृषि और प्रशासन के क्षेत्र में संभावित साहसिक और राजनीतिक रूप से संवेदनशील सुधारों से सरकार बची है। बावजूद 2025-26 का बजट उस भारत की छवि को मजबूत करता है जो सुधार के लिए तत्पर है, संभावनाओं से भरा हुआ है तथा विश्व में उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है। प्रधानमंत्री ने देश के लिए चार जातियां बताई थी गरीब, युवा, किसान और महिला। कुल मिलाकर 10 क्षेत्रों में बदलाव संबंधी कोशिशें पर फोकस किया गया है। 2024-25 के 48 लाख 21 हजार करोड़ की तुलना में इस बार कुल 50 लाख 65 हजार करोड़ का बजट है। इसका अर्थ है कि सरकार को वित्तीय चुनौतियों का आभास है और खर्च ज्यादा बढ़ाया नहीं गया है जो व्यवहारिक है। इन परिस्थितियों में वित्त घाटे को संपूर्ण अर्थव्यवस्था के 4.4% तक रखना बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5 वर्ष पहले यह 9.02% था।

आयकर में छूट ऐतिहासिक है, नौकरी पेशा वालों के लिए 12 लाख 75 हजार और 12 लाख तक आम कारोबारी के लिए आयकर में छूट की कल्पना किसी को नहीं थी। इसलिए सबसे ज्यादा चर्चा उसकी हो रही है। इसे हम राजनीतिक रूप से प्रभावी मध्यमवर्ग को खुश करने की योजना बता सकते हैं। लेकिन इसके आर्थिक और वित्तीय महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मध्यम

वर्ग का आर्थिक और वित्तीय सशक्तिकरण तथा उसकी क्रय शक्ति बढ़ाने का लक्ष्य शामिल है। मध्यमवर्ग की जेब में धन बचने का अर्थ है कि वे आवश्यकताओं पर ज्यादा खर्च कर सकेंगे, जिससे प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास गति को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही अपने जीवन को ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल होने की कल्पना से अंदर सकारात्मकता का विकास होगा और इसका असर हमारे संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण पर पड़ेगा। इसके साथ 95% आयकर दाता अब आयकर देने से मुक्त हो चुके हैं। इस दृष्टि से यह साहसी क्रांतिकारी ऐतिहासिक कदम है।

भारत के मूल यानी विरासत के साथ समाज के नीचे से ऊपर सभी तत्वों के संतुलित विकास के साथ ही देश अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हम देखेंगे कि समाज के सबसे निचले तपके यानी सड़कों पर सामान बेचने वाले, श्रमिकों, असंगठित मजदूरों, किसानों, मत्स्यपालकों, लघु, मध्य व सूक्ष्म उद्योगों, युव नव उद्यमियों, धार्मिक आध्यात्मिक केन्द्रों आदि सभी समूहों के विकास की दौरे में गतिशील होने की व्यवस्था इस बजट में है। भारत के प्रमुख धार्मिक आध्यात्मिक संस्कृत स्थान पर जिस ढंग से तीर्थ यात्रियों पर्यटकों में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है वह हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। इसे ध्यान में रखते हुए 50 पैसे स्थलों को राज्यों की भागीदारी के साथ विकसित करने की योजना है। रोजगार प्रेरित विकास के लिए आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के साथ होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण, यात्रा और संपर्क में सुधार करना, वीजा शुल्क में छूट के साथ ईवीजा को और बढ़ाना, चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। इस तरह के व्यवहारिक सूक्ष्मता स्तरीय सोच का कितना असर होगा इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो भविष्य के एक विशेष पहचान वाले आदर्श महाशक्ति की दृष्टि से आधारभूमि बनाने की कोशिश लगातार मोदी सरकार के बजट में है और इसे इस बार सशक्त और त्वरित करने की कोशिश की गई।

सरकार ने सर्वेक्षण में स्पष्ट किया था कि कृषि, जिसका योगदान कुल अर्थव्यवस्था में 16% के आसपास है, में काफी क्षमता है और प्रतिवर्ष यह 0.75 प्रतिशत से एक प्रतिशत का योगदान दे सकता है। बजट में कृषि विकास के लिए जबरदस्त कदमों की घोषणा है। प्रधानमंत्री 'धनधान्य योजना' में ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा, जहां कृषि उत्पादकता कम है। इनसे उत्पादकता बढ़ाने, खेती में विविधता लाने, सिंचाई और उपज के बाद भंडारण की क्षमता मजबूत करने में मदद मिलेगी। इससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा। किसान क्रेडिट कार्ड अभी 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के साथ किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये की गई है। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए छह वर्ष का मिशन शुरू होगा। खाद्य तेलों के उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। नैफेड और एनसीसीएफ में पंजीकृत किसानों से दालें खरीदेगी। श्रीअन्न, सब्जियां और फलों के लिए भी बड़ी योजना का प्रस्ताव है। ऐसे किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजना राज्यों के साथ साझेदारी के साथ लॉन्च किया जाएगा। बिहार में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान शुरू किया जाएगा। इससे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षमताएं मजबूत करने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन के अंतर्गत बीजों की ऐसी 100 से अधिक किस्मों को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव कितना महत्वपूर्ण है यह किसने और कृषि से जुड़े विशेषज्ञों को अच्छी तरह बताएं। मछली पालन में भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, इसका बाजार करीब 60 हजार करोड़ का है। भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों और गहरे समुद्र में स्थायी मत्स्य पालन पर जोर दिया

गया। अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह को मत्स्य पालन विकास के लिए लक्षित किया गया है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का कर्ज का प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। यही नहीं समुद्री उत्पादों पर सीमा शुल्क सीधे 30% से घटाकर 5% करना बहुत बड़ा कदम है। अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। ध्यान रखिए मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देने की घोषणा के बाद एक्वाकल्चर स्टॉक में 12.5% तक की वृद्धि हुई। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा। कपास उत्पादकता मिशन के तहत उत्पादकता में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी और कपास के लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा। बजट में इन सबसे किसानों की आए व्यापक रूप से बढ़ाने की कल्पना की गई है। यूरिया उत्पादन के बढ़ावा पर फोकस है और असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा।

गांव के साथ शहरों को विकास केन्द्र बनाने के प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती कोष स्थापित स्थापित करने की योजना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्थिक विकास के साथ शहरों की व्यवस्था कमजोर हो रही है। उस कारण वे क्षमताओं के अनुरूप अर्थव्यवस्था में योगदान देने की जगह अपनी ही चुनौतियों से निपटने में ज्यादा उलझे हुए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। ये एमएसएमई उत्पादकों के साथ निर्माण में 45 प्रतिशत योगदान कर रहे हैं। इसमें वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे उन्हें आगे बढ़ने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने का आत्मविश्वास मिलेगा। कर्ज की सीमा 5 करोड़ से 10 करोड़ कर 1.5 लाख करोड़ के आवंटन से इस क्षेत्र के उद्योगों के लिए उत्पादन और वितरण में निश्चित रूप से आसानी होगी। एमएसएमई को विदेशों में शुल्क में सहायता मिलेगी। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटी फीस में भी कमी होगी। भारत को चीन के समानांतर खिलौने का सबसे बड़ा हब बनाने का लक्ष्य पहली बार बजट में है। खिलौना उद्योग के लिए मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना शुरू की जाएगी, नेशनल एक्शन प्लान बनाया जाएगा। इसके बाद लिए स्किल और विनिर्माण के लिए इको सिस्टम बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना 'भारत ट्रेड नेट' (BTN) की स्थापना की जाएगी, जो व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान के लिए एक एकीकृत मंच होगा इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप बनाया जाएगा।

स्वाभाविक रूप से बजट में ऊर्जा क्षेत्र में सुधारों की दृष्टि से भी काफी प्रस्ताव है। विकसित भारत की दृष्टि से 2047 तक कम से कम 100 गीगावॉट परमाणु नाभिकीय ऊर्जा के विकास का के लक्ष्य की दृष्टि से निजी क्षेत्र और साधनी क्षेत्र दोनों के लिए योजनाएं घोषित हैं। परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे।

इस तरह के अनेक पहलू बजट में हैं जो हमारे आपको अपने देश के प्रति आत्मविश्वास पैदा करने के साथ योगदान देने की आर्थिक वित्तीय ठोस भागीदारी दे सकता है। कोई भी बजट आलोचनाओं से परे नहीं है और इनमें भी ऐसे बिंदु निकाले जा सकते हैं। कुल मिलाकर यह भारत को भारत के अनुरूप सामग्र और प्रेरक विकास की दृष्टि वाले बजट का ही अगला पड़ाव है जिसमें हमारे आपके सबके लिए आर्थिक दृष्टि से योगदान देने की भूमिका निभाने के कदम उठाने की कोशिश है।

विकसित भारत के लक्ष्य को तेजी से प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इस शानदार बजट के लिए माननीय नरेंद्र मोदी साहेब का आभार व्यक्त करता हूँ एवं माननीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूँ।

***m50 श्री रविंद्र दत्ताराम वायकर (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) :** मैं भारत के आम बजट 2015-16 पर अपने विचार रखता हूँ। यह बजट केवल संख्याओं का एक दस्तावेज नहीं बल्कि विकसित भारत की मजबूत नींव रखने वाला रोडमैप है। मैं इस दूरदर्शी और जन-हितैषी बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूँ।

इस बजट में 50,65,345 करोड़ रुपये का फुल व्यय प्रस्तावित किया गया है जिसमें 11,21,000 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के रूप में रखे गए हैं। इससे बुनियादी ढांचे का विकास होगा, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और करोड़ों लोगों को नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

इस बजट में सरकार ने गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग और शहरी गरीबों को प्राथमिकता दी है। यह बजट आर्थिक मजबूती, रोजगार सृजन, उद्यमिता, बुनियादी ढांचे के विस्तार और डिजिटल इंडिया को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प दोहराता है। यह केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आज इस ऐतिहासिक बजट में भारत के समुद्री, हवाई, आवासीय और मध्यम वर्ग के विकास के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं जो हमारे देश को एक विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने वाली हैं।

सरकार ने Maritime Development Fund की स्थापना की घोषणा की है जिसमें 25,000 करोड़ रुपये का फंड होगा। इसमें 49 परसेंट सरकार का योगदान रहेगा और बाकी धनराशि बंदरगाहों और निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी। इससे समुद्री व्यापार, लॉजिस्टिक्स और नौवहन के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और भारत को वैश्विक समुद्री हब बनाने की दिशा में मजबूती मिलेगी।

इसी तरह, UDAN (Regional Connectivity Scheme) में 1.5 करोड़ मध्यमवर्गीय नागरिकों को सस्ता और तेज हवाई सफर प्रदान किया है। अब तक 88 एयरपोर्ट और 619 रूट्स इस योजना के तहत जुड़े हैं। इस सफलता को देखते हुए संशोधित UDAN योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा और अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, सरकार ने सस्ते और मध्यम आय वर्ग के आवास (Affordable & Mid-income Housing) के लिए SWAMIH फंड के तहत 50,000 से अधिक घरों का निर्माण पूरा किया और उनके खरीदारों को चाबी सौंपी। इससे उन मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिली जो एक साथ EMI और किराए का बोझ उठा रहे थे। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए अब SWAMIH Fund-2 लॉन्च किया जाएगा जिसमें 15,000 करोड़ रुपये का फंड होगा। इससे एक लाख और घरों का निर्माण तेजी से पूरा होगा जिससे लाखों परिवारों को उनका अपना घर मिलेगा।

मध्यम वर्ग हमेशा से राष्ट्र निर्माण की रीढ़ रहा है और मोदी सरकार ने हमेशा उनके योगदान को सराहा है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने इनकम टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया है जिससे अब एक लाख प्रति माह तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, सैलरीड क्लास के लिए 75,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह सीमा 12.75 लाख रुपये हो जाएगी। यह निर्णय मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सीधी राहत लेकर आया है और उनकी वित्तीय स्वतंत्रता को और मजबूत करेगा।

शहरों में छोटे व्यापारियों और स्ट्रीट वेंडर्स को सशक्त बनाने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 68 लाख से अधिक स्ट्रीट बैंडर्स को सस्ती दरों पर ऋण की सुविधा दी गई है। इस योजना का विस्तार करते हुए सरकार ने अब UPI लिंकड क्रेडिट कार्ड की घोषणा की है, जिसमें 30,000 रुपये तक की लिमिट होगी। इसके अलावा बैंकों से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा ताकि स्ट्रीट वेंडर्स अपने व्यापार को सुचारु रूप से चला सकें।

इसके साथ ही शहरी विकास को गति देने का कंडा स्थापित किया गया है, जिससे शहरी विकास को गति देने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित किया गया है जिससे शहरों को ग्रोथ हब के रूप में विकसित किया जाएगा, स्वच्छता और जल आपूर्ति में सुधार होगा और नगर सेवाओं को आधुनिक बनाया जाएगा। यह फंड पीपीपी मॉडल और बैंकों से ऋण के माध्यम से 50 परसेंट तक धनराशि जुटाने की सुविधा देगा जिससे शहरी विकास को तेज किया जा सकेगा।

भारत में गिग इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है और लाखों युवा Zomato, Swiggy, Uber, Ola जैसी कंपनियों व माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने गिग वर्कर्स को पहचान देने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने के लिए e-Shram पोर्टल पर पंजीकरण और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देने की घोषणा की है। इससे लगभग 1 करोड़ जिम वर्कर्स को सीधा लाभमिलेगा, जिससे वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बन सकेंगे।

भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने 1.1 लाख से अधिक मेडिकल सीटें जोड़ी हैं और अगले वर्ष 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी, जिससे देश में डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी और स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सक्षम बनाया जाएगा।

इसके अलावा, सभी जिला अस्पतालों में के-केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें वर्ष 2025-26 में 200 नए केंद्र खोले जाएंगे। इससे कैंसर के मरीजों को उन्नत उपचार मिलेगा और उन्हें बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

सरकार ने Heal in India पहल के तहत मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इससे भारत में चिकित्सा सुविधाओं का वैश्विक स्तर पर विस्तार होगा और भारत को मेडिकल हब के रूप में स्थापित किया जाएगा।

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने IITs में छात्रों की संख्या 65,000 से बढ़ाकर 1.35 लाख कर दी है। अब वर्ष 2014 के बाद स्थापित 5 नए IITs में 6,500 और छात्रों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा जिस पर 500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नेशनल जियोस्पेशियल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है, जिससे भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण और शहरी नियोजन को और आधुनिक बनाया जाएगा।

सरकार ने राज्यों को 1.5 लाख करोड़ का 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की है जिससे राज्यों में आधारभूत संरचना का तीव्र विकास होगा।

इसके अलावा, प्रत्येक इंफ्रास्ट्रक्चर मंगलय को PPP मॉडल के तहत तीन साल की परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह योजना देश के बुनियादी ढांचे को आधुनिक और प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

अब मैं अपने राज्य महाराष्ट्र और अपने लोकसभा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

वाढवान बंदरगाह: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 276,200 करोड़ रुपये की लागत से इस बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है। मेरा आग्रह है कि केवल वाढवान तक सीमित न रहते हुए कोंकण के सभी बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया जाए।

छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों का संरक्षण: इन ऐतिहासिक धरोहरों का पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से प्रेरणा मिल सके।

मुंबई में जल संकट: गारगाई और पिंजाल बांध परियोजनाओं को जल्द पूरा करने की जरूरत है ताकि मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति सुचारु हो सके।

वर्सोवा जेट्टी का पुनर्निर्माण: इसे पर्यटन और मछली उद्योग के लिए विकसित करने हेतु विशेष निधि दी जाए।

गोरेगांव फिल्म सिटी: हरो रामजी फिल्म सिटी जिससे यह एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की फिल्म सिटी बन सके पर विकसित किया जाए, जिससे यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फिल्म सिटी बन सके। कोंकण रेलवे का आधुनिकीकरण: सभी रेलवे स्टेशनों उनकी यात्री सुविधाओं में सुधार किया जाए और उनकी यात्री सुविधाओं में सुधार किया जाए। रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी के लिए प्रबंध किया जाए। यात्रियों की भीड़ के लिए उपाय योजना होनी चाहिए।

जोगेश्वरी जंक्शन: इसे अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल कर यहाँ मॉल, यात्री विश्राम गृह और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएँ विकसित की जाएं।

मुंबई उपनगर में एम्स अस्पताल के निर्माण (कैंसर और रिसर्च सेंटर) के लिए निधि की आवश्यकता है। यह बजट एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण करने वाला बजट है। सरकार ने गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और मध्यम वर्ग के कल्याण को प्राथमिकता दी है और बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल इंडिया से ऐतिहासिक निवेश किया है।

मेरे लोकसभा क्षेत्र में अभी भी कई विकास कार्य बाकी हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वे मेरी उपरोक्त मांगों पर गंभीरता से विचार करें।

जय हिंदा जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।

श्री आशीष दुबे (जबलपुर) : आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश की वित्तमंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत वार्षिक बजट-2025-26 बिल का मैं जबलपुर की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, समर्थन करता हूँ।

हम सभी आज गौरवान्वित हैं, कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर है और देश एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। देश सांस्कृतिक समृद्धि के साथ-साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण अंचलों की बात हो, पूरा देश विकास और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। सरकार द्वारा सदन में देश के चहुंमुखी विकास हेतु प्रस्तुत बजट से यह स्पष्ट है, आज भारत, विश्व की सशक्त अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है।

इसलिए मैं वर्ष-2025-26 बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

मुझे यह कहते हुए, अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। माननीय वित्त मंत्री महोदया ने अपने बजट भाषण में बताया कि सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन-धन योजना से देश के कुल 54.40 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। देश में डिजिटल लेन देन का प्रचलन है, कालाबाजारी पर रोक लगी है। पीएम आवास योजना के तहत देश की बड़ी संख्या 3.45 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। पूरे विश्व में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का विश्व कीर्तिमान स्थापित करते हुए "आयुष्मान भारत" योजना के निमित्त देश के 55 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत 15.42 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पीने का पानी मुहैया सरकार द्वारा घर-घर पहुंचाया जा चुका है। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी की संवेदनशीलता को नमन करता हूँ, आपने देश के ग्रामीण अंचलों में पेयजल पहुंचाकर पुण्य का कार्य किया है, समग्र देशवासी आज आपका अभिनंदन कर रहे हैं।

सरकार द्वारा देश निर्माण में किए जा रहे कार्यों को गिनाने लगूंगा तो समय कम पड़ जाएगा, उपलब्धियों का विवरण बहुत ही लंबा है। आज पूरा देश देख ही नहीं रहा अपितु महसूस भी कर रहा है। अतः समय की सीमाओं का ध्यान रखते हुए, मैं यही कहूंगा कि देश की सरकार आज नए भारत का उदय करते हुए, सरकार विकसित भारत के सपने को साकार करने जा रही है, इसमें हर भारतवासी आज माननीय मोदी जी के साथ खड़ा है।

अंत में, मैं मेरे संसदीय क्षेत्र जबलपुर के विभिन्न लोकहित के मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

1. जबलपुर शहर में माँ नर्मदा जी के पावन तट पर तिलवारा घाट से माँ नर्मदा व्यू पॉइंट तक लगभग 11 कि०मी० के भाग पर गुजरात में बने साबरमती रिवर फ्रंट एवं कोटा राजस्थान में बने हेरिटेज चम्बल रिवर फ्रंट की तर्ज पर जबलपुर में "माँ नर्मदा जी रिवर फ्रंट" बनाई जाए।

2. जीवन दायिनी माँ नर्मदा की अविरल धारा को केंद्र में रखकर इस पूरे क्षेत्र में "नर्मदा टूरिस्ट सर्किट" का निर्माण किया जाए ।
3. जबलपुर शहर को स्मार्ट सिटी में सम्मिलित करने हेतु आभार, किन्तु जनता की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं के अनुरूप अभी जबलपुर में बहुत से चरणबद्ध, एक विशेष कार्यनीति के तहत विकास कार्यों का होना अत्यंत आवश्यक है । अतः कृपया जनहित में जबलपुर शहर हेतु "स्मार्ट सिटी फेज-2" के तहत अगले चरण का अनुमोदन करते हुए, 1 हजार करोड़ की धन राशि मुहैया करवाने की कृपा करें ।
4. जबलपुर अपने वन संपदा से समृद्ध है । अतः जबलपुर में प्राणी उद्यान (zoo) का होना अत्यंत आवश्यक है । कृपया जनहित में इस पुनीत कार्य हेतु 100 करोड़ रुपये की अनुसंशा करने का निवेदन है ।

मेरा विनम्र अनुरोध है, मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों को आम बजट 2025-26 में जोड़ा जाए, जिससे कि जबलपुर संसदीय क्षेत्र में अपेक्षित विकास, आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके, जबलपुर संसदीय क्षेत्र जैसे ऐतिहासिक क्षेत्र का समेकित विकास करते हुए शिखर पर लाया जा सके ।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का जबलपुर की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन । मैं सरकार द्वारा सदन में प्रस्तुत बजट 2025-26 (वित्त विधेयक) का समर्थन करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ ।

बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार ।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर) :माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया गया, जिसमें विकास के 4 इंजनों- कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) निवेश और निर्यात को रेखांकित किया गया है ।

बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों एवं महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों को प्रस्तावित किया गया है ।

* प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजनारू इसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया ।

* कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान के लिये राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय 'ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन निर्माण' कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा ।

* दलहनों में आत्मनिर्भरतारू सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिये एक छह वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी । जिससे जलवायु अनुकूल बीज और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होंगे ।

* केन्द्रीय एजेंसियां (नेफेड और एनसीसीएफ) अगले चार वर्षों के दौरान किसानों से मिलने वाली इन तीन दालों को अधिकतम स्तर पर खरीदने के लिये तैयार रहेंगे ।

- * किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की बढ़ी हुई सीमा 7.7 करोड़ किसानों के लिये ऋण की सीमा को सुविधाजनक बनाने के लिये इसे 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया ।
- * उच्च उपज देने वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन अनुसंधान को मजबूत करना, 100 से अधिक उच्च उपज देने वाली और कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- * कपास उत्पादकता मिशन सतत् कृषि को बढ़ावा देने, अतिरिक्त लंबे रेशे वाले कपास का उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये 5 वर्ष की पहल ।
- * बिहार में मखाना बोर्डर्स मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाने हेतु इसकी स्थापना की जाएगी ।
- * फलों और सब्जियों के लिये व्यापक कार्यक्रम कुशल आपूर्ति शृंखला को बढ़ावा देना और किसानों के लिये बेहतर बाजार मूल्य सुनिश्चित करना ।
- * मत्स्य विकासरू भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और उच्च सागर में सतत् मत्स्य पालन के लिये नई रूपरेखा, अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित करना ।
- * असम में यूरिया संयंत्र कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिये ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड (बी वी एफ सी एल) के परिसर में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता का एक नया यूरिया संयंत्र स्थापित किया जाएगा ।
- * संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 और दोगुना बढ़ाया गया है, जिससे लघु उद्यम के लिये ऋण के अवसर बढ़ेंगे ।
- * सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड्स 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिये 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा, वित्तीय समावेशन और आर्थिक भागीदारी को बढ़ावा देना ।
- * एमएसएमई के लिये ऋण कवर गारंटी कवर 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिससे ऋण तक पहुँच बढ़ सकेगी ।
- * चमड़ा और फुटवियर के लिये फोकस प्रोडक्ट स्कीम 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व और 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात होगा ।
- * खिलौना क्षेत्र का विकास: क्लस्टर और नवाचार आधारित विनिर्माण वैश्विक बाजारों में मेड इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा दे रहे हैं ।
- * राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानरू बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिससे खाद्य प्रसंस्करण, कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा ।

- * स्टार्टअप्स के लिये फंड ऑफ QaM-1: विस्तारित दायरे और 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा ।
- * शहरी चुनौती निधि शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने, शहरों के रचनात्मक पुनर्विकास तथा जल एवं स्वच्छता को समर्थन देने के लिये 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिये 10,000 करोड़ आवंटित किये गए ।
- * जल जीवन मिशन कुल बजट परिव्यय को बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है तथा इस मिशन की अवधि वर्ष 2028 तक बढ़ा दी गई है, जिससे ग्रामीण जल परियोजनाओं के लिये अधिक वित्त पोषण के साथ सार्वभौमिक पाइप जलापूर्ति सुनिश्चित होगी ।
- * इस मिशन से 15 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं, जो भारत की ग्रामीण आबादी का 80: हिस्सा हैं ।
- * समुद्री विकास निधि 25,000 करोड़ का कोष (सरकार द्वारा 49: योगदान), जहाज निर्माण, बंदरगाहों और रसद बुनियादी ढाँचे के लिये दीर्घकालिक वित्तपोषण का समर्थन करता है ।
- * IIT का विस्तार 6,500 अतिरिक्त छात्रों के लिये अतिरिक्त बुनियादी ढाँचा, भारत की तकनीकी शिक्षा क्षमता को बढ़ावा देगा ।
- * PM रिसर्च फेलोशिप IIT और IISC में उन्नत अनुसंधान के लिये 10,000 फेलोशिप ।
- * डे केयर कैंसर सेंटर इन्हें अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा । वर्ष 2025-26 तक 200 सेंटर स्थापित किये जाएंगे, जिससे कैंसर उपचार की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित होगी ।
- * भारतीय भाषा पुस्तक योजना इसके तहत स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के क्रम में भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी ।
- * विकसित भारत के लिये परमाणु ऊर्जा मिशन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों के लिये 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इसके तहत वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 का संचालन किया जाना प्रस्तावित है ।
- * परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणुवीय नुकसान के लिये सिविल दायित्व अधिनियम में संशोधन के क्रम में निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी के लिये विचार किया जाएगा ।
- * UDAN और क्षेत्रीय संपर्क योजना: संशोधित उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा, जिसका लक्ष्य अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवा प्रदान करना है ।
- * यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी सहयोग प्रदान करेगी ।
- * पश्चिमी कोशी नहर परियोजना मिथिलांचल, बिहार में सिंचाई अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ।

- * रोजगार आधारित विकास के लिये पर्यटन देशभर के 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को राज्यों के सहयोग से चैलेंज मोड के तहत विकसित किया जाएगा।
 - * निर्यात संवर्धन मिशन: क्षेत्रीय और मंत्रालयी लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन का शुभारंभ किया जाएगा, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा।
 - * भारत ट्रेड नेट BTN एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा।
 - * ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) हेतु राष्ट्रीय ढांचा: उभरते हुए द्वितीय श्रेणी (टियर-2) शहरों में आउटसोर्सिंग केंद्रों (ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स) को बढ़ावा देने के लिये नीतिगत प्रोत्साहन दिये जाएंगे, जिससे भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभर सके।
 - * एयर कार्गो के लिये भंडारण सुविधा उच्च-मूल्य वाले नाशवंत उत्पादों के निर्यात को सक्षम बनाने के लिये उन्नत भंडारण अवसंरचना का विकास किया जाएगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक तेज और कुशल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
- सबका विकास" थीम पर आधारित केंद्रीय बजट 2025-26 समावेशी विकास, गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के साथ विकसित भारत के लिये एक मजबूत आधार तैयार करने पर केंद्रित है।
- युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग को प्राथमिकता देते हुए इस बजट का उद्देश्य सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के साथ सतत विकास एवं निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना है। यह बजट भारत को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी तथा आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में अग्रसर करेगा।
- *m53 श्री अरुण भारती (जमुई) :** मैं इस ऐतिहासिक बजट पर अपने विचार रखता हूँ तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और हमारे नेता, युवा हृदय सम्राट श्री चिराग पासवान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह बजट सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि "बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट" विजन को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम है। यह बजट भारत के भविष्य की रूपरेखा तैयार करता है-एक आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित भारत की दिशा में बढ़ते कदमों का प्रमाण है। वर्षों तक बिहार विकास की दौड़ में पीछे छूट गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज बिहार को वह सम्मान मिल रहा है, जिसका वह सदा से हकदार था। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों ने बिहार को सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, लेकिन पहली बार बिहार को वास्तविक तवज्जो मिली है। इस बजट में हर वर्ग के लिए राहत, हर क्षेत्र के लिए विकास, और हर नागरिक के लिए नए अवसरों का संकल्प है। यह बजट बिहार के कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना और युवा विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। NDA सरकार ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से कहीं अधिक दिया है-वास्तविक निवेश, बड़े प्रोजेक्ट्स और आर्थिक सुधारों के रूप में।

बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के लिए यह बजट क्रांतिकारी निर्णय लेकर आया है। बिहार पूरे देश के 90% मखाने का उत्पादन करता है। लेकिन अब तक इसे वह पहचान नहीं मिली जिसकी यह हकदार थी। सरकार द्वारा "मखाना बोर्ड" की स्थापना से किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज, तकनीकी सहायता और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी। मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूँ कि मखाने पर MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) घोषित किया जाए, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिले। पश्चिमी कोसी परियोजना मिथिलांचल क्षेत्र के 50,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि के लिए संजीवनी साबित होगी। वर्षों से सिंचाई की समस्या झेल रहे किसान अब आत्मनिर्भर बनेंगे, जिससे बिहार की कृषि उत्पादकता को नई ऊँचाइयाँ मिलेंगी।

"प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना" के तहत 100 पिछड़े कृषि जिलों को सुधारने की योजना बनाई गई है, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। Mission for Aatmanirbharta in Pulses के तहत तूर, उड़द और मसूर की फसल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक विशेष मिशन की शुरुआत की है। बिहार दाल उत्पादन का केंद्र बन सकता है और इस योजना से किसानों की आमदनी में कई गुना बढ़ोतरी होगी। Rural Prosperity & Resilience Programme के तहत गाँवों में नए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, जिससे बिहार के युवाओं को बाहरी राज्यों में मजदूरी के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। बिहार की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की गई है, जिससे व्यापार, उद्योग और पर्यटन को बल मिलेगा। इसके साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का विकास राज्य को भविष्य की उड़ान भरने के लिए तैयार कर रहा है।

पीएम आवास योजना के तहत ₹5.36 लाख करोड़ का अतिरिक्त आवंटन-इससे बिहार के लाखों परिवारों को पक्का घर मिलेगा। 1 लाख करोड़ रुपये का Urban Challenge Fund-पटना, मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर जैसे शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलने की दिशा में यह बजट एक ऐतिहासिक कदम है। मेट्रो, रोपवे और इलेक्ट्रिक बसें पटना और अन्य शहरों में स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करने के लिए 52,000 इलेक्ट्रिक बसें तैनात की जाएंगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन में सुधार होगा। बिहार के 157 रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। 14 बंदे भारत ट्रेनों का संचालन 20 जिलों में किया जा रहा है। 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (National Centres of Excellence for Skilling)- युवाओं को Make for India, Make for the World विजन के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ सकें।

IITS और मेडिकल कॉलेजों का विस्तार: बिहार के छात्रों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलें, इसके लिए 75,000 नई मेडिकल सीटों की घोषणा की गई है। Centre of Excellence in AI for Education-पटना को शिक्षा का हब बनाने के लिए ₹500 करोड़ के निवेश से AI Excellence Centre स्थापित किया जाएगा, जिससे नई तकनीकों का लाभ बिहार के छात्रों को मिलेगा। Food Processing Industry का विस्तार बिहार में National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management की स्थापना की जाएगी, जिससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

बिहार में लीची, मखाना, चावल और मकई जैसी उपजों की प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित होंगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। MSME सेक्टर को बढ़ावा ₹1.5 लाख करोड़ की विशेष ऋण योजना से बिहार के लघु और मध्यम उद्योगों को नई ताकत मिलेगी। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों ने बिहार के विकास को रोकने का काम किया। वर्ष 1971 में "गरीबी हटाओ" का नारा दिया गया, लेकिन गरीब हटे नहीं, बल्कि गरीबों को ही हटाने का काम किया गया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात करने वालों ने केवल झूठे वादे किए, लेकिन केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज देकर वास्तविक मदद दी। रेलवे, सड़क, पुल, हवाई अड्डे कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने बिहार को कुछ नहीं दिया, लेकिन मोदी सरकार बिहार को विकास की नई ऊँचाइयों तक ले जा रही है। आज का यह बजट "बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट" के विजन को साकार करने वाला बजट है। "बिहार बढ़ेगा, तो भारत बढ़ेगा।" जय हिंदा जय बिहार।

श्री जनार्दन मिश्रा (रीवा) : माननीया वित्तमंत्री जी ने थिरुक्कुरल के लोक 542 को अपने बजट भाषण में उल्लेखित किया है कि ? जैसे जीवित प्राणी वर्षा की आशा में जीते हैं, वैसे ही नागरिक सुशासन की आशा में जीते हैं।? देखा जाए तो देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी से सुशासन की अपेक्षा के कारण उनके नेतृत्व पर तीसरी बार अपना मत प्रकट किया है। सुशासन की यह उत्प्रेरणा है, जिसमें भारत की आशा टिकी हुई है। जिसे चरितार्थ करने का पूरा प्रयास वित्तमंत्री जी द्वारा किया गया है। आज का भारत सुशासन के ही कारण विकसित भारत की संकल्पना को फली भूत देखना चाहता है। आज दुनिया में भू-निश्चितता का वातावरण है, जिससे सरकार भली भांति समझती है। ऐसी परिस्थिति में निवेश और उपभोग को 41 कर आर्थिक स्थायित्व प्रदान करने वाला बजट पेश किया गया है। ह निजी क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित कर निवेश बढ़ाने का प्रयास गया है। आधार भूत संरचनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता से पूंजीगत निवेश बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। मध्यम वर्ग के 12 लाख तक की आय वालों के कर शून्य हो जाने से लगभग एक लाख करोड़ से अधिक की बचत होगी जिसका अधिकांश हिस्सा बाजार में खरीद दारी के माध्यम से आयेगा तथा कुछ बचत भी की जाएगी। इस नीति से बाजार में मुद्रा का प्रवाह बढ़ेगा।

माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट को तीन समयावधि तात्कालिक, मध्य कालिक और अल्पकालिक नजरिये से विभाजित किया है। तात्कालिक तौर पर देखे तो यह जी.डी.पी को गति देगा, मध्यम अवधि में यह जी.डी.पी को सहारा देगा और दीर्घ अवधि में यह समृद्धि की शिला रखेगा। बजट में कृषि को प्रथम वरीयता दी गई है। जिसे बजट में प्रथम इंजन कहा। प्रधान मंत्री धान्य योजना में 100 जिले जो विशिष्ट उपायों के अभिसरण के उत्पादकता, कम फसलों की बुवाई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले हैं को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। सरकार ने दालों के उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त करली हैं। हर सरकार तुअर, उड़द, मसूर की उत्पादकता बढ़ाने के लिए 6 वर्षीय ?दलहनों में आत्म निर्भरता मिशन? प्रारंभ करने जा रही है तथा इन उत्पादों के शत प्रतिशत खरीदी की व्यवस्था बजट में की गई है। उच्च मूल्य की शीघ्र खराब होने वाली बागवानी उत्पादों सहित एयर कार्गो हेतु अवसरचना और भंडार गृह के उन्नयन की सुविधा प्रदान की जाएगी। जलवायु में परिवर्तन को देखते हुए जलवायु अनुकूल गुणों से सम्पन्न बीज तैयार किए जा रहे हैं, जिससे पैदावार बढ़ेगी ये बीज कीट प्रतिरोधी भी होंगे। 100 से अधिक किस्मों के बीज वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराये जाएँगे। कृषि क्षेत्र में किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। किसान क्रेडिट से 7 करोड़ 70 लाख न को अल्पकालिक ऋण

3 लाख तक मिलता है इस ऋण सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। यूरिया बढ़ावा देने के लिए असम में (2.7 लाख मीट्रिक टन उत्पादन वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा!

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय डाक को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाएगा जिससे विश्वकर्माओ, नए उद्यमियों, महिला स्व-सहायता समूहों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा बड़े कारोबारी संगठनों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।

"मेक इन इंडिया" को आगे बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री जी ने राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन? के स्थापना की घोषणा की है। इससे सूक्ष्म, लघु उद्योगों को काफ़ी सहारा मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ की गई है जिससे अगले पाँच वर्षों में 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। स्टार्ट अप के करोड़-बसे बढ़ाकर 20 करोड़ के ऋणों की गारंटी शुल्क कम के 1% कर दी जाएगी। जिससे प्रमुख क्षेत्रों को प्रोत्साहन मिलेगा। सूक्ष्म 5 लिए 5 लाख सीमा वाले क्रेडिट उपलब्ध कराए जाएंगे। 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए नई योजना प्रारंभ की गई है। जिन्हें अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण आबादी को नल से जल देने की योजना का लक्ष्य 100 प्रतिशत कवरेज करने का संकल्प लिया गया है। जो 2028 तक पूरा होगा इससे ग्रामीण महिलाओं को जल संग्रहण में होने वाले कष्टों से मुक्ति मिलेगी साथ ही पेट संबंधी अनेक बीमारियों से भी राहत मिलेगी। उड़ान योजना का विस्तार कर 10 वर्षों में 120 नये गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी जिससे 4 करोड़ यात्रियों का हवाई परिवहन की सुविधा प्राप्त होगी। गत दस वर्षों में 1.1 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा सीटों को जोड़ा गया है। आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों में दस हजार से अधिक सीटें जोड़ी जाएंगी। आगामी वर्षों में 75 हजार सीटें जोड़ने का लक्ष्य है। आंगनवाड़ी केंद्रों को अधिक सक्षम बनाया जाएगा।

50 हजार अटल टिकरिंग प्रयोगशालाओं के माध्यम से छात्रों में जिज्ञासा व को प्रोत्साहित किया जाएगा। परमाणु ऊर्जा ईमिशन के माध्यम से परमाणु ऊर्जा रियक्टरों को क्रियाशील कि जाएगा। विद्युत के सुधारों के लिए राज्यों को इन सुधारों पर भरने पर जी. की 0.5% अतिरिक्त उधारी दी जाएगी।

विगत तीन वर्षों में सभी जिलों में कैंसर सेंटर स्थापित किये जाएँगे। जिससे इस प्राणघातक बीमारी से लाखों गरीबों को राहत मिलेगी। दवाओं में आयात शुल्क घटाने से उनकी कीमतें कम होगी जिससे रोगियों की हजारों करोड़ रुपये की बचत होगी। गिर वर्कर्स को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जिससे उनके जीवन व व्यवसाय में स्थायित्व आयेगा। नया आय कर विधेयक ?न्याय? की भावना को आगे बढ़ायेगा। यह विधेयक अध्यायो व शब्दों दोनों दृष्टियों से आधे से कम और पाठ रूप में सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा। जिससे मुकदमे बाजी में कमी आयेगी।

सभी स्कूलों को ब्रॉडवेड से जोड़ा जाएगा तथा भारत भाषा योजना के जरिये मातृ भाषाई शिक्षा दी जायेगी। जिससे शिक्षा की दिशा में आमूल चूल परिवर्तन होगा। ज्ञान भारत मिशन के माध्यम से एक करोड़ पांडुलिपियों में उल्लेखित मे भारत का परिचय होगा।

एक ओर मोदी जी की सरकार सांस्कृतिक विरासत को प्रकट कर रही है वहीं 68 लाख गरीब स्ट्रीट वैंडरों को कोरोना से मुक्त करने का असंभव कार्य बैंको से संवर्धित ऋण तीस हजार रुपए कर दिया गया है । और उन्हें नई तकनीक से जोड़ कर आधुनिक बनाया जायेगा । भारत में लेदर क्षेत्र की उत्पादकता गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु छोटे चर्मशोधको द्वारा निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रस्ट लेदर को 20% निर्यात शुल्क से छूट दी गई हैं, वही लेदर फुट वियर और उत्पादों की सहायता के अलावा बिना लेदर वाले फुट वियर के उत्पादन हेतु आवश्यक डिजाइन क्षमता, घटक निर्माण और मशीनों के लिए सहायता दी जाएगी । इससे 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात होने की संभावना है ।

बजट में ?वैश्विक खिलौना केंद्र? बनाया जाएगा जिससे उच्च गुणवत्ता वाले ऐसे अनूठे, नवीन और पर्यावरण अनुकूल खिलौने बनेंगे जो ?मेड इन इंडिया? ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेंगे । देश विदेशी खिलौना व्यापार से मुक्त होगा । जो खनिज घरेलू उपलब्ध नहीं है जैसे लिथियम आयन बैटरी, पारा, कोबाल्ट , जिंक सहित 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अपशिष्ट व अवशिष्ट को वी.सी.डी से पूरी तरह छूट दी गई । बजट के स्वतः रत से स्पष्ट है कि बजट मोदी जी के विकसित भारत कस को साकार करलने वाला बजट है ।

रीवा लोकसभा क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में रीवा में हवाई अड्डे का निर्माण कार्य पूरा हो गया तथा रीवा - भोपात्र हवाई यात्रा प्रारम्भ हो गई है। रीवा रेलवे स्टेशन को सर्व सुविधा युक्त बनाया जा रहा है, रीवा बाई पास के चोड़ी करण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है । हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य प्रारम्भ है, गुणवत्ता पूर्ण बिजली आपूर्ति के लिए RDSS योजना के तहत कार्य किया जा रहा है । इन सारे कार्यों के लिए मैं रीवा के 30 लाख नागरिकों की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी और उनकी सरकार के प्रति कृतलता ज्ञापित करता हूँ ।

परन्तु रीवा के नागरिकों की कुछ मांगों की ओर मैं केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ ।

1. रीवा ? हनुमना रेलवे लाइन. निर्माण को स्वीकृति दी जाये तथा रीवा से मुंबई हेतु । नियमित रेल यात्री गाड़ी संचालन किया जाये ।
 2. मऊगंज में अन्त्योदय विद्यालय व सेन्ट्रल स्कूल की स्थापना की जाये ।
 3. रीवा में प्रपातो की एक श्रृंखला है अतः उन्हें पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किया जाये ।
 4. रीवा के पुराने बस अड्डे से ढेकहा तिराहे तक फ्लाई ओवर का निर्माण कराया जाये ।
 5. सोहागी घाटी जो एक गंभीर दुर्घटना स्थल के रूप में चिन्हित की गई है उसे सुरक्षित यात्रा मार्ग बनाने हेतु राशि का आवंटन किया जाये ।
 6. मानिकपुर प्रयागराज के मध्य चलने वाली यात्री गाड़ी संख्या 22441-42 का डभौरा रेलवे स्टेशन पर ठहराव किया जाये ।
- धन्यवाद !

SHRIMATI MALVIKA DEVI (KALAHANDI): I would like to express my views on the 2025-2026 budget. I would like to congratulate our Prime Minister, Shri Narendra Modi, and Finance Minister, Srimati Nirmala Sitharaman ji on this remarkable budget, her eighth consecutive one, a budget which will forever leave an incredible mark on the pages of Indian history. This budget embodies India's spirit towards achieving not dreams but goals of a visit Bharat by 2047.

This budget is the next stage booster that is going take the Indian economy to stratospheric heights of success. It marks a significant milestone in India's journey towards achieving not just its dreams but concrete goals of a Viksit Bharat by 2047.

This budget emphasizes self-reliance and aims to restore India's reputation as the "Soney Ki Chidiya" a reputation that was systematically tarnished by the opposition over generations in its pursuit of power and self-aggrandizement. But why talk about the dark past when the future is brighter than ever and India has moved out of those shadows under the guidance of our honourable Prime Minister Shri Narendra Modiji.

Looking ahead, we expect a GDP growth of 6.4% under the leadership of Shri Narendra Modi. Our focus is on four key sectors driving the Indian economy: agriculture, micro, small and medium enterprises (MSMEs), investment, and export. We aim to make India a central hub for trade and commerce as well as a significant contributor to the global food supply while remaining committed to providing assistance globally. This budget intends to support 1.7 crore farmers, aid the development of rural women and youth, and assist landless farmers. It will facilitate loans for 7.7 crore farmers with the overall loan allocation significantly increased from 3 to 5 lakh crore, aiming to boost growth in over 100 districts with low productivity. Currently, there are over 1 crore MSMEs employing 7.5 crore people, contributing to 36 per cent of our manufacturing and responsible for 45 per cent of our exports. The credit guarantee cover will increase from 5 crores to 10 crores, and a credit of 1.5 lakh crore is planned over five years, with term loans up to 20 crores available for well-run MSMEs. Additionally, cap ex-investment in daycare centres in all district hospitals is also proposed.

The budget includes export promotion missions, the establishment of warehousing facilities for air cargo, financial sector reforms and development, and the removal of tariffs.

There is a significant allocation for increased investment in infrastructure, including roads, railways, and urban development. This encompasses public- private partnerships within the state, power sector reforms, Udaan, shipbuilding, mining sector reforms, and an allocation of 50 lakh crores for railway investment.

The budget proposes several initiatives to enhance education, including the establishment of National Centres of Excellence for Skilling, investment in Saksham Anganwadi, Atal Tinkering Labs, broadband connectivity to government secondary schools, national centres for skilling, and the expansion of IITs to accommodate an additional 6,500 students. Additionally, there are plans to establish centres of excellence in AI. These efforts aim to equip the young population with the necessary skills to excel and lead the country forward in an ever-changing, technology-driven world. Moreover, there is a goal to increase the number of seats in medical colleges, targeting 75,000 seats within five years.

Taxation Reforms- The budget proposes adjustments to tax brackets and rates, aiming to alleviate the financial burden on individuals, particularly those in the middle class. The objective is to increase disposable income and encourage consumer spending, thereby fostering sustainable economic growth.

The budget proposes several initiatives aimed at improving financial inclusion. These include the introduction of UPI-linked credit cards for street vendors, which will enable easier access to credit facilities and digital payments for small businesses. Additionally, the development of a 'Grameen Credit Score' framework is intended to assess the creditworthiness of rural borrowers, helping them secure loans and financial services that were previously difficult to obtain. These measures are expected to enhance economic participation and growth across diverse segments of society.

The budget includes several significant regulatory reforms aimed at improving governance and efficiency. Key measures include the establishment of a High- Level Committee for Regulatory Reforms, tasked with reviewing existing regulations and recommending necessary changes to enhance business and economic environments. Additionally, the introduction of the Jan Vishwas Act 2.0 is set to streamline various regulatory processes, reduce compliance burdens on businesses, and foster a more transparent and accountable framework. This will further improve our record-breaking GST collection, contributing positively to the development of states and the nation. Purvauday, is a bold and novel scheme that is aimed at developing Odisha, Bihar, and other eastern states that have historically received less attention.

This initiative seeks to enhance economic growth, improve infrastructure, and elevate the standard of living in these regions. By addressing issues such as unemployment, education, healthcare, and transportation, Purvauday aims to create sustainable development and bring these states on par with more developed areas in the country.

In recent years, 4 crore houses have been provided to individuals with low income, with plans to construct an additional 3 crore houses. This initiative aims to address the housing shortage and improve living conditions for millions of people. By offering affordable housing options, the program seeks to uplift marginalized communities and promote economic stability. The new constructions will incorporate sustainable practices and modern amenities to ensure long-term benefits for the residents. Currently, 25 crore Indians are above the poverty line. This significant number indicates an improvement in living standards and economic conditions for a substantial portion of the population. However, it also highlights the ongoing challenges faced by millions who still live below the poverty line, necessitating continued efforts towards poverty alleviation and economic development.

Our vision is not solely that of the BJP or the current government but reflects the aspirations of 1.42 billion Indians who stand united. They perceive Viksit Bharat not merely as a dream, but as a tangible and glorious goal to be realized by 2047 under the esteemed leadership of our Honourable Prime Minister, Narendra Modi. This vision encapsulates the collective ambition of our nation to achieve unparalleled growth and prosperity. It seeks to transform India into a beacon of progress and innovation on the global stage, ensuring that every citizen reaps the benefits of this monumental journey. Together, we march forward with unwavering determination, embracing the challenges and opportunities that lie ahead, committed to building a resplendent future for generations to come.

डॉ. राजेश मिश्रा (सीधी) : मैं बजट - 2025 पर अपने विचार रखता हूँ। देश सिर्फ भूमि नहीं, बल्कि इसके लोग हैं।

विकास के इंजन:- 1. कृषि, 2. MSME, 3. निवेश, 4. निर्यात

माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्तमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विकसित भारत के आकांक्षाओं के बजट को अगर संक्षेप में व्याख्या करने के लिए चिंतन किया जाय तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्रीरामचरित मानस के एक दोहे से की जा सकती है वो दोहा है - नहि दरिद्र कोऊ दुखी न दीना, नहीं कोऊ अबुध न लक्षण हीना। जिसका तात्पर्य यह है कि दरिद्र अर्थात् गरीबी, गरीबों को भोजन, आवास, पानी, सड़क, रोजगार व सम्मान देने का यह बजट है।

दुखी अर्थात रुग्ण बजट में कैंसर व जीवन रक्षक दवाइयों के मूल्य में अल्पता करना, वृद्ध श्रेष्ठों को जो 70 से ऊपर हैं उनको आयुष्मान कवर देना, सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करना, अनुसूचित जनजाति व त्याज्य क्षेत्र में 30 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का संकल्प इस बजट में है। दीन अर्थात कमजोर वर्ग हेतु हमारी सरकार ने समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले जन जिसमें से महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति के उद्यमियों के लिए 2 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराएंगे तो यह दीन नहीं रहेंगे। इन्हीं के लिए पीएम स्वनिधि योजना, शहरी आजीविका सुदृढीकरण की व्यवस्था की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संचालित लखपति दीदी योजना इसका प्रमाण है। अबुध अर्थात अज्ञानी, ज्ञानार्जन हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित बजट में 1.3 लाख करोड़ रुपए का बजट ज्ञान के लिए है, जिसमें स्कूलों में लैब अटल टिकरिंग लैब से लेकर AI तक मेडिकल में 75000 सीटें, आईआईटी में सीट बढ़ाने से लेकर रिसर्च व ग्रन्थ डिजिटलाइजेशन तक शामिल है।

प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप 10 हजार देने की तैयारी, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है। हमारे विरोधी दल के लोग इस तरह हैं - जौ काहू के सुनहिं बडाई। स्वास लेहिं जनु जूडी आई, जौ काहू के देवहि विपदी। सुखी होइ मानहु जग नृपति न लक्षण हीना। अर्थात गरीबी से मुक्ति, शत प्रतिशत स्कूली शिक्षा, कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, किसानों की समृद्धि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना हेतु यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार। स्वास्थ्य के क्षेत्र में वित्तमंत्री जी ने 95 हजार 9 सौ 58 करोड़ यानी लगभग 96 हजार करोड़ की स्वीकृति दी है।

1. मेडिकल उपकरणों को भी सस्ता किया है
2. सभी 792 जिलों में डे केयर कैंसर केंद्र,
3. 75000 मेडिकल सीटें बढ़ाने, बल्कि अगले वर्ष ही 10 हजार सीटें बढ़ाना
4. स्वास्थ्य पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा
5. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 55 करोड़ लोगों को कवर करती है

अब बात करें शिक्षा की तो शिक्षा के क्षेत्र में माननीया वित्तमंत्री जी ने 1 लाख 28 हजार 650 करोड़ का प्रावधान इस बजट में किया है -

1. सभी स्कूल ब्रॉडबैंड कनेक्शन
2. 50 हजार सरकारी स्कूल में अटल टिकरिंग लैब
3. एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन
4. किताबें डिजिटल फॉर्म में होंगी

5. रिसर्च के लिए 10 हजार फेलोशिप
6. भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम
7. राष्ट्रीय उत्कृष्ट कौशल केंद्र
8. आई आई टी में 6500 सीट बढ़ाना
9. स्वास्थ्य, शिक्षा व कृषि के लिए AI शिक्षा हेतु उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना

मेरे लोक सभा क्षेत्र की प्रमुख मांगें निम्नलिखित हैं -

1. मेरे लोकसभा क्षेत्र संजय टाइगर रिजर्व पर्यटन की दृष्टि महत्वपूर्ण व लाभकारक है। वहां पर विस्थापित होने वाले 99% लोग ट्राइबल समुदाय से हैं। उन्हें 15 लाख की जगह 50 लाख या आर.एन्ड.आर. के तहत मुआवजा दिया जाए।
2. यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय रेल मंत्री जी हमारे क्षेत्र में विशेष ध्यान दे रहे हैं इसके लिए धन्यवाद।
3. ललितपुर, सिगरौली रेललाइन जो कई वर्षों से निर्माणधीन है मे विगत कुछ महीनो से कार्य तीव्र गति से चल रहा है।
4. वर्ष 2025 तक सीधी व 2026 तक सिगरौली रेल लाइन पहुंच जाए, ऐसा निवेदन है।
5. जमीन के बदले जो नौकरी पहले दी जा रही थी, बंद कर दी गई है उस पर पुनः विचार किया जाए। युवाओं के भविष्य का प्रश्न है
6. सिगरौली से भोपाल वंदे भारत रेल चलाई जाए। मेरे लोक सभा क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेन नहीं है।
7. सिगरौली से बनारस सुपर फास्ट मेमो ट्रेन दी जाए।
8. कटनी चोपल रेल मार्ग का दौहरीकरण कटनी से जोबा तक का शेष है उसे शीघ्र बनाया जाए। लगभग 30km का रास्ता है।
9. जबलपुर से सिगरौली वाया कटनी ब्योहारी मझौली निवास सरई राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए यहां ट्रेफिक लोड बहुत है।
10. सिगरौली एयरपोर्ट से नियमित व्यावासायिक उड़ान प्रारंभ की जाए।
11. ब्योहारी में बाणसागर डैम के पास प्रयाप्त जमीन है वहां नेवी का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाए।
12. सिगरौली में माइनिंग कॉलेज शीघ्र प्रारंभ किया जाए।
13. सीधी में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए।
14. सीधी में वन एवं वन्य जीव प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र बनाया जाए।

15. बजट में 50 पर्यटन स्थल स्थापित करने की बात कही गई है। मेरे क्षेत्र परसिली में पहले से स्थापित केंद्र को अत्याधुनिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। यह क्षेत्र रही बाणभट्ट की तपस्थली है।
16. हमारे क्षेत्र में महुआ बनोपज की खेती बहुत होती है, उसे कृषि क्षेत्र में मिलने वाले अन्य सभी लाभ मिले।
17. मेरे लोकसभा क्षेत्र सीधी सिंगरौली में बैगा विकास प्रधिकरण लागू किया जाए जिस तरीके के म.प्र. के अन्य जिलों में लागू है।

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): I extend my heartfelt congratulations to Hon'ble Prime Minister Narendra Modi Ji and Hon'ble Finance Minister Nirmala Sitharaman Ji for delivering a progressive, forward-looking, and inclusive Union Budget that sets the stage for a Viksit Bharat by 2047. This is not just another budget; it is a bold vision of economic empowerment, infrastructure development, and social transformation.

- Government has given another bold, visionary, and people-centric Union Budget- a budget that is not just a statement of accounts but a statement of intent.
- This is a budget that understands the aspirations of every Indian-be it the farmer in the fields of Odisha, the youth striving for a brighter future, the entrepreneur taking bold risks, the middle-class family balancing dreams and responsibilities, or the senior citizen looking for security and dignity.
- For too long, the middle class of this country- the backbone of our economy- was taken for granted by previous governments. Their hard work, their savings, their dreams were never prioritized. But under PM Modi's leadership, the middle class is not just seen- it is empowered!
- In 2014, when we took office, the Nil Tax slab was ₹2.5 lakh. In 2019, we raised it to ₹5 lakh. In 2023, we took it even further to ₹7 lakh.
- And today, in this historic budget, we have exempted all income up to ₹12 lakh from tax- ensuring that hard-working Indians can earn more, save more, invest more, and dream bigger.
- For salaried professionals, the exemption now extends to ₹12.75 lakh, thanks to the ₹75,000 standard deduction benefit.
- This is not just a tax relief- this is financial freedom for millions of middle-class families. This is the government saying to its people: We trust you, we believe in you, and we will stand with you.
- And what was the reaction of the opposition? Confusion. Shock. Silence.

- For Odisha, this budget is a milestone, ensuring that our state is not just a participant but a leader in India's growth story. From record investments in railways, highways, education, and healthcare to unprecedented support for MSMEs, farmers, and youth, this budget solidifies Odisha's role as a powerhouse of development.
- ₹10,599 crore allocated for railway infrastructure development in Odisha- a 12.5-fold increase from what was given between 2009-2014. In the last 10 years, 2,046 km of new rail lines have been built, exceeding the total railway network of Malaysia.
- ₹2,379 crore allocated for the modernization of 59 key railway stations, including Bhubaneswar, Cuttack, Puri, Sambalpur, and Rourkela- ensuring world-class facilities for passengers.
- Six Vande Bharat Express trains are now operational, enhancing Odisha's regional and interstate connectivity with West Bengal, Jharkhand, and Andhra Pradesh.
- Since 2014, 4,250 km of National Highways have been built in Odisha, with an investment of ₹33,000 crore. Currently, 1,312 km of NH projects worth ₹22,000 crore are underway, ensuring better logistics, trade efficiency, and rural connectivity.
- A revamped UDAN scheme will connect 120 new destinations, including better air connectivity for Odisha, ensuring faster travel and enhanced trade opportunities.
- Jal Jeevan Mission extended till 2028 with enhanced outlay for quality water infrastructure, ensuring every rural household in Odisha has piped water access.
- 50,000 Atal Tinkering Labs to be set up in Government schools in the next 5 years, fostering innovation and technological excellence among students.
- ₹2 lakh crore investment in skill development will prepare Odisha's youth for a global workforce and leadership in technology-driven industries.
- A Centre of Excellence in Artificial Intelligence for education will be established with a ₹500 crore investment, ensuring Odisha becomes a hub for AI and next-gen technologies.
- 10,000 additional medical seats will be created in the next year, contributing towards the goal of adding 75,000 medical seats in 5 years- ensuring more opportunities for Odia students in medical sciences.

- PM Research Fellowship Scheme will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc, promoting Odisha as a centre for scientific innovation.
- BharatNet Project will provide broadband connectivity to all government secondary schools and primary health centres in rural Odisha, bridging the digital divide.
- ₹1.5 lakh crore allocated for capital expenditure interest-free loans to states, ensuring Odisha gets the necessary funds to invest in critical infrastructure.
- The Maritime Development Fund (₹25,000 crore) will enhance Odisha's port-led development, boosting trade and employment in the maritime sector.
- Shipbuilding Financial Assistance Policy revamped- Odisha's coastal economy and shipbuilding sector will now thrive under new incentives.
- Financial incentives for electricity distribution reforms will enhance Odisha's power infrastructure, ensuring uninterrupted electricity for industries, MSMEs, and households.
- A Nuclear Energy Mission (₹20,000 crore) launched for Small Modular Reactors (SMRs) - paving the way for Odisha to emerge as a hub for clean and nuclear energy development.
- Second Gene Bank (10 lakh germplasm lines) set up for future food security, ensuring Odisha's agricultural heritage is preserved and advanced.
- PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana will uplift small and marginal farmers by enhancing productivity, irrigation, and post-harvest storage, benefiting 1.7 crore farmers across 100 districts.
- Mission for Aatmanirbharta in Pulses launched with a 6-year focus on increasing production of Tur, Urad, and Masoor, ensuring better MSP and sustainable farming.
- Kisan Credit Card (KCC) limit increased from ₹3 lakh to ₹5 lakh, ensuring better financial support for farmers, dairy farmers, and fishermen.
- A Rural Prosperity and Resilience Program launched-focusing on agriculture employment, skilling, investment, and technology, ensuring that migration becomes a choice, not a necessity.
- Incentives for MSMEs and export-driven agriculture, ensuring higher returns for farmers and agribusinesses.
- Saksham Anganwadi & Poshan 2.0 to provide enhanced nutritional support to 8 crore children, 1 crore pregnant women, and 20 lakh adolescent girls- ensuring better maternal and child health in

Odisha.

- ₹676.7 crore allocated under PM-USHA for Odisha's higher education infrastructure, transforming universities into world-class multidisciplinary institutions.
- Ayushman Bharat now covers senior citizens above 70 years with ₹5 lakh health insurance, benefiting thousands of elderly citizens in Odisha.
- 200 Day Care Cancer Centres to be set up in district hospitals by 2025-26, ensuring affordable cancer treatment for Odisha's citizens.
- 36 life-saving medicines fully exempt from customs duty, making treatments for cancer, rare diseases, and chronic illnesses more affordable.
- FDI in Insurance raised to 100%- ensuring higher investment, better coverage, and job creation in Odisha's insurance sector.
- Grameen Credit Score to improve access to finance for rural Odisha, enabling self-help groups and entrepreneurs to receive easy credit.
- Bharat Trade Net (BTN) to streamline international trade, ensuring Odisha's businesses can scale globally.
- Extension of tax compliance reforms, including faceless assessment, self- declaration for exporters, and decriminalization of over 100 legal provisions, making doing business in Odisha easier than ever.
- This budget is not just a financial document; it is a game-changer for Odisha. From railways to roads, MSMEs to maritime, agriculture to AI, healthcare to higher education-every sector has been empowered with record allocations.
- For decades, Odisha was neglected-ignored by governments that saw it as a political afterthought. But under PM Modi's visionary leadership, Odisha is at the forefront of India's growth story. The state is no longer just rich in resources; it is becoming rich in opportunities, infrastructure, and economic prosperity.
- The opposition, which failed Odisha for years, is left clueless. They never invested in Odisha's railways, schools, healthcare, industries, or youth- but today, they sit in shock as this government delivers historic development for the state.

- "Just like the Kalinga Empire once led global trade and knowledge, Odisha is reclaiming its place as a leader of India's future."
- This is not just a budget- it is the foundation of a New Odisha, a Viksit Bharat, and an unstoppable future.

Jai Jagannath! Jai Hind!

***m58 श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) :** मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत जनरल बजट 2025-2026 पर अपने विचार रखती हूँ।

यह बजट संतुलित, समावेशी और दूरदर्शी है। यह गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सभी वर्गों के हितों को साधते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मैं इस बजट का पूर्ण समर्थन करती हूँ और सरकार के इस प्रयास की सराहना करती हूँ।

सबसे पहले, मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय वित्त मंत्री को इस दूरदर्शी और समावेशी बजट के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। यह बजट "विकसित भारत?" के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आत्मनिर्भर भारत, सशक्त ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और तकनीकी विकास को प्राथमिकता देता है।

सरकार द्वारा प्रस्तुत यह बजट भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को और अधिक गति प्रदान करेगा। भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और यह बजट स्थायी विकास, निवेश वृद्धि, और रोजगार सृजन पर केंद्रित है। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश: पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी कर सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी है। सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के विस्तार के लिए बड़ा प्रावधान गया है, जिससे नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत: विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित 5 हन (PLI) योजनाओं को और विस्तारित किया गया है, जिससे घरेलू उद्योगों को पल मिलेगी और विदेशी निवेश को आकर्षित किया जाएगा।

हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए अनेक ठोस कदम उठाए गए हैं: पीएम किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ाया गया है ताकि अधिक किसानों को इसका लाभ मिले। प्राकृतिक खेती और कृषि तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कृषि स्टार्टअप्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज, सिंचाई योजनाओं और ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए विशेष बजट आवंटन किया गया है। रोजगार और उद्योग नीति - सरकार ने स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना के तहत लघु और मध्यम उद्यमों को आर्थिक सहायता देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इससे युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और भारत स्टार्टअप हब के रूप में उभरेगा। MSME

सेक्टर को सशक्त करने के लिए सस्ते ह सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। रोजगार 7 के लिए डिजिटल इंडिया मिशन और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया गया है।

शिक्षा पर विशेष ध्यान - राष्ट्रीय नीति (NEP) के तहत डिजिटल शिक्षा, स्कूली बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा बजट आवंटन किया गया है।

आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर इसे और अधिक परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मेडिकल कॉलेजों और अनुसंधान केंद्रों की स्थापना के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वित्तीय सुधार और टैक्स में राहत - आम नागरिकों को राहत देने के लिए इनकम टैक्स स्लैब्स में बदलाव किया गया है। GST सरलीकरण के माध्यम से व्यापारियों और उद्यमियों के लिए कर प्रणाली को सरल बनाया गया है। डिजिटल भुगतान और यूपीआई को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने नए प्रोत्साहन की घोषणा की है।

जलवायु परिवर्तन और हरित ऊर्जा - हमारी सरकार 2050 तक नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस बजट में: ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और नछलजघा5 फ्यूल टेक्नोलॉजी के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया गया है।

किन्तु कुछ बातें मैं अपने प्रदेश दादरा नगर हवेली के विषय में कहना चाहती हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। के ये 10 साल आम जनता को समर्पित रहे। इन 10 सालों में भारत ने हर क्षेत्र में बहुत ?4 की है। आज भारत स्वावलंबी है, अन्य देश भारत सरकार की ओर देख रहे हैं हमारे पगचिन्हों पर चलने की बात करते हैं। जैसा हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत विकास यात्रा की ओर अग्रसर है हर तरफ विकास की गंगा बह रही है और हमारी सरकार ने विभिन्न पर अभूतपूर्व उपलब्धियों हासिल की है।

हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत में तीन गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है। और इन निर्णयों में देश के गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मित्र रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी ने दिया हुआ मंत्र ?सबका साथ, सबका विकास", ?सबका विश्वास और सबका? प्रयास जैसे मंत्र भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की प्रेरणा देते हैं जिससे हम विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर हैं।

मेरा संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव में आजादी के बाद से ही एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर हर तीन साल के लिए सिनियर आईएस अधिकारी की नियुक्ति होती रही है, और चुने हुए जनप्रतिनिधिओं के आपसी सामंजस्य एवं सहयोग से प्रदेश को भरपूर लाभ मिला, प्रदेश विकास पथ पर तेजी से अग्रसर भी होता रहा है, परंतु 2016 के बाद प्रशासक के पद पर पहली बार किसी

राजनिक व्यक्ति को बिठाया गया, और आज भी पिछले आठ वर्षों से लगातार वही व्यक्ति प्रशासक बने हुए है। जिससे विकास के साथ ही साथ जनमानस भी तानाशाही से परेशान एवं त्राहिमाम करने को मजबूर हो गया है।

सरकार ने पिछड़े राज्यों के हित के लिए तमाम जनहितैसी, कल्याणकारी एवं विकासीय योजनाएं लागू की गई हैं। आदिवासी एवं पिछड़ा क्षेत्र होने के बावजूद भी इन योजनाओं का लाभ सही मायने में हमारे को नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क आदि बुनियादी सुविधाओं से हमारा प्रदेश वंचित है। मैं चाहूंगी कि सरकार को इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जिससे मेरे प्रदेश के लोगों को लाभ मिल सके।

शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण स्कूल तो बने हैं परंतु शिक्षकों की कमी से शिक्षण व्यवस्था बाधित हो रही है। गरीब स्कूली बच्चों को समय पर यूनिफॉर्म, बुक्स, पोषण आहार आदि का लाभ नहीं मिलता है, वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को मनमाने ढंग से निकाला गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अस्पताल तो बने हैं परंतु वहां न तो कुशल चिकित्सक हैं और न ही दवाईयां हैं। गरीब मरीज बाहर से महंगी दवा लेने को मजबूर हैं।

हमारे प्रदेश में भारी भरकम खर्चों से मेडिकल कोलेज बनाया गया है ताकि प्रदेश के गरीब आदिवासी योग्य बच्चे पढ़ लिखकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा प्रदान करें, परंतु यहां स्थानिय बच्चों का कोटा फिक्स होने के बावजूद भी बाहरी बच्चों को वरीयता दी जा रही है जिसके कारण स्थानिय बच्चे निराश एवं हताश हो रहे हैं। फायदे में रहने के बावजूद बिजली का निजिकरण होने से विधुत बिल मनमाने ढंग से दुगुना चौगुना वसुला जा रहा है, लोग मजबूर हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी मेरे प्रदेश में सड़कों की हालत तो बंद से बंदतर हो चुकी है, वर्षों से सड़कों बनाने के नाम पर काम चल रहा है परंतु एक भी सड़क आज तक पूरी तरह नहीं बन पाई है जिससे सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जानें जा रही हैं। विकास के नाम पर गरीब आदिवासियों के घर तोड़े जा रहे हैं, लोग जमीन के अभाव में सड़क पर गुजर-बसर करने को मजबूर हैं, इनमें से कईयों ने तो जैसे आत्म हत्या तक कर ली है।

मेरे प्रदेश में पानी की समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है, पानी के अभाव में प्रदेश की गरीब महिलाओं को कोसों दूर से पानी ताना पड़ता है। आज तक जल की स्थाई सुविधा नहीं हो पाई है। पठे लिखे गरीब आदिवासी जो विभिन्न सरकारी विभागों में वर्षों से कार्यरत थे ऐसे हजारों लोगों को बिना किसी ठोस कारण के निकाल दिया गया है, परिवार चिंतित है, जो बच्चे हैं उन्हें सुदूर क्षेत्रों में पोस्टिंग कर परेशान किया जा रहा है। प्रशासन किसी का सुनने को तैयार नहीं है, उल्टे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा डराने धमकाने से लोग परेशान हैं।

स्मार्ट सीटी योजना मंद पड़ी हुई है, जबकि स्मार्ट सीटी के नाम पर लोगों के घर तोड़ दिए गये हैं, प्रदेश की धरोहर रही ग्रीनरी को खत्म किया जा रहा है। हरेभरे वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से प्रदेश को विरान किया जा रहा है, ऐतिहासिक धरोहर नष्ट हो रही है। जनता से स्मार्ट सीटी परियोजना के तहत जबरदस्ती मनमाना टैक्स वसुला जा रहा है। इतना ही नहीं औद्योगिक विस्तार से

परिपूर्ण हमारे प्रदेश से कंपनिया प्रशासन कि मनमानी से पलायन करने को मजबूर हो चुकी है । काफी कंपनियां बंद हो गई है जिससे बेरोगारी और गरीबी बढ गई है ।

आदिवासी समाज के विकास के लिए हमारे यहां वर्षो पहले आदिवासी भवन बनाया गया था, जिसके जरिए गरीब आदिवासीयो के शादी-ब्याह, सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम, आपातकाल मे आदिवासियों की सुरक्षा, उनकी देखभाल और उनकी समस्याओ के निराकरण का आदिवासी भावन एक प्रमुख केन्द्र रहा, जिसे प्रशासन ने गैर कानूनी ढंग से बिना किसी ठोस कारण के कब्जे मे लेकर ताला जड दिया है और भव्य आदिवासी भवन खंडहर बन गया है प्रशासनिक अधिकारी किसी का सुनने को तैयार नही है ।

हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी ने इन 10 वर्षों में जो कार्य किए है वे आज वैश्विक अस्थिरता के वातावरण में भी भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थिरता का स्तम्भ बनकर विश्व के सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहा है । यह अच्छी बात है जिसका मैं स्वागत करती हूँ ।

हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी की सरकार भारत के अमृतकात्र के दौर में अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से निरंतर सतत विकास की ओर बढ़ते हुए नई ऊर्जा देने का काम कर रहीं है । जिसका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ ।

आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चोथे चरण में पच्चीस हजार बस्तियों को जोड़ने के लिए सत्तर हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं । आज जब हमारा देश अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष मना रहा है, तब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके विजन का पर्याय बनी हुई है । इतना ही नहीं अध्यक्ष जी ?वन नेशन-वन इलेक्शन" और ?वक्फ़ अधिनियम संशोधन? जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए हैं ।

संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव में चुने हुए जन प्रतिनिधियों के जो संविधानिक अधिकार है उससू उनको दूर किया जा रहा है । कई वर्षों से असेंबली की मांग होती आ रही है मेरे पती श्री मोहन डेलकर जी ने भी इसी सदन में दादरा नगर हवेली में असेंबली बने इसलिए इस विषय को कई और इस संबंध में पत्र भी लिखे ।

मेरे प्रदेश में असेंबली ना होने के कारण सही मायने में स्थानिक एवं आदिवासी समाज को अधिकार नहीं मिल पा रहा है उनके साथ ज्यादती होती रहती है परंतु बडे दुःख के साथ मैं कहना चाहूगी कि बार बार संसद में आवाज उठाने के बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है जिसके कारण मेरे प्रदेश में दिन प्रतिदिन लोगों को परेशान करने वाली गतिविधियां बढ़ती जा रही है ।

ऐसे मे मजबूत भारत जहां तेजी से विकास की राह में बढ रहा है वही मेरा प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन दीव मे स्थानिय प्रशासन दवारा मनमानी चल रही है, उसे रोकने की आवश्यकता है । महोदय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से अपेक्षा ही नही बलल्की पूरी उमीद है कि जिस तरह उनके सक्षम नेतृत्व मे भारत का तेजी से विकास हो रहा है दुनिया में भारत का

नाम रोशन हो रहा है उसी तरह उनकी कृपा से हमारे प्रदेश का भी भाग्य उदय हो और प्रदेश में खुशहाली एवं अमनचैन कायम रहे ।
धन्यवाद ।

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख) : मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे 145 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बजट 2025 पर अपनी बात रखने का मौका दिया इसके साथ-साथ मैं वित्त मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दिया है । अब नौकरीपेशा लोगों को 12.75 लाख रुपए तक के तहत कोई टैक्स नहीं लगेगा वहीं अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे । सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है । बजट सरकार की विकास को बढ़ाने सभी के डेवलपमेंट मिडिल क्लास की क्षमता को बढ़ाने के लिए समर्पित हैं । हम इस सदी के 25 साल पूरा करने जा रहे हैं । हमारी विकसित भारत की उम्मीद ने हमें प्रेरणा दी है, हमारी अर्थव्यवस्था सभी बड़ी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है । स्वास्थ्य के क्षेत्र में वित्त मंत्री जी ने 36 जीवन रक्षक दवाओं पर पूरी तरह से ड्यूटी टैक्स खत्म कर दी गई है । सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे कैंसर की इलाज की दवाएं सस्ती होंगी । 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी गई है । कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन रखा गया है । इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत होगा । सरकार ने हमारे किसान भाइयों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है । एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, डेढ़ लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा ।

स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ रुपया किया गया है इसमें गारंटी फीस में भी कमी की गई है । मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि देश में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए उन्होंने 75000 सीटें बढ़ाने का ऐलान किया है । सरकार ने डिजिटल शिक्षण संस्थानों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सेवा शुरू की जा रही है । इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है यह सुविधा उन कंपनियों के लिए होगी जो पूरा प्रीमियम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी ।

मैं सरकार की उपलब्धि को बताना चाहूंगा कि पीएम सम्मान निधि से 68 लाख लोगों को फायदा मिला है । हमारी सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रही है । शहरी कामगारों की आय बढ़ाने के लिए योजना लाया गया है । इनके पहचान पत्रों और ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था मिलेगी एक करोड़ कामगारों को फायदा हुआ है । आरोग्य योजना के तहत इनका लाभ मिलेगा शहरी क्षेत्र के लिए शासन नगर पालिका शहरी भूमि और सुधारों से संबंधित योजनाएं शुरू की गई हैं । सरकार एक लाख करोड़ का बजट रखेगी यह रकम भरोसेमंद परियोजनाओं की लागत के 25% तक की रकम देगी । न्यूक्लियर मिशन में 2047 तक 100 गीगावॉट बिजली चाहिए । लघु मॉडल रिएक्टर के अनुसंधान के लिए 20,000 करोड़ के बजट से परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू किया जाएगा ।

इस बजट में मेक इन इंडिया एम्प्लॉयमेंट और इनोवेशन, एनर्जी सप्लाई, स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट, MSMP का विकास हमारी विकास यात्रा में शामिल है और इसका ईंधन रिफॉर्मर्स है। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद की संभावना है। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण राज्यों की भागीदारी से शुरू किया जाएगा। कौशल, निवेश से कृषि में रोजगार का सुधार होगा इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में विकल्प पैदा करना है। युवा, किसानों, ग्रामीण महिलाओं, किसानों छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

बजट का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि रेलवे के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण गलियारों के लिए एलोकेशन किया गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में क्षेत्र वासियों द्वारा बिल्हौर स्टेशन पर लगातार रेलगाड़ी के स्टॉपेज की मांग की जा रही है। ट्रेन संख्या 14151/14152 कानपुर आनंद विहार एक्सप्रेस, 19409/19410 अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस, 22443/22444 कानपुर बांद्रा एक्सप्रेस और संडीला, मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख के अंतर्गत नगर पालिका व नगर पंचायत कछौना, चौबेपुर और शिवराजपुर क्रॉसिंग संख्या 43 से निकलने वाली रेलवे क्रॉसिंग पर भारी यातायात होने के कारण क्रॉसिंग बंद होने पर सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बजट एलोकेशन में से कछौना, चौबेपुर शिवराजपुर में रेलवे ओवरब्रिज या अंडरपास बनाने के लिए ग्रांट दी जाय, ताकि यहां पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने का कार्य शुरू हो सके।

मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख के अंतर्गत बिलग्राम मल्लावां उन्नाव एक स्टेट हाईवे संख्या 38 है। यह हरदोई जिला होते हुए एक तरफ जिला उन्नाव और दूसरी तरफ जिला शाहजहांपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 (4 लेन) में जुड़ती है। जिला हरदोई और उन्नाव में इस सड़क की चौड़ाई बहुत कम है, जिसके चलते आए दिन भीषण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बजट एलोकेशन में से बिलग्राम मल्लावां स्टेट हाईवे को राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल करने की स्वीकृति एवं सड़क को फोरलेन बनाने के लिए ग्रांट दी जाए ताकि क्षेत्र में होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मल्लावां बिलग्राम विधानसभा क्षेत्र में गंगा नदी से बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहां पर प्रत्येक वर्ष गंगा नदी से बाढ़ आने पर कटरी-परसौला छिबरामऊ सहित कई गांवों की न केवल फसल बर्बाद हो जाती है, बल्कि उनके मकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तथा वे बेघर हो जाते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बजट एलोकेशन में बाढ़ से बचाव के लिए एक बांध मेहंदी घाट से होते हुए राजघाट सडिया पुल तक बनाने के लिए ग्रांट दी जाए ताकि बांध का निर्माण हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

SHRI ARUN KUMAR SAGAR (SHAHJAHANPUR): मैं यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में श्रीमती निर्मला सीतारमन, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2025-26 के जनरल बजट का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह हम सभी के लिए प्रसन्नता और गौरव की बात है कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को सदन में लगातार आठवीं बार वित्त बजट प्रस्तुत करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, जो एक रिकॉर्ड है।

सदन में प्रस्तुत यह बजट सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बजट समावेशी विकास और भविष्य की दृष्टि से तैयार किया गया है, जिसमें सभी क्षेत्रों को प्रगति की राह पर ले जाने का प्रयास किया गया है।

वित्त मंत्री जी द्वारा इस बजट में ग्रामीण और शहरी विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचनाओं, उद्योग, और स्टार्ट-अप सहित सभी क्षेत्रों को संतुलित तरीके से प्राथमिकता दी गई है और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के कई प्रावधान किए गए हैं।

देश को आगे बढ़ाने और वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने की यह एक महत्वपूर्ण आधारशीला है। महिलाओं के लिए जो योजना है, भारत के विकसित भारत होने के मार्ग को और मजबूत करेगा। रोजगार के लिए इसमें जो व्यापक रोड मैप बनाया गया है, वह बहुत ही सुंदर है। इस बजट से रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में यह बजट गरीबों के लिए नये अवसर लेकर आएगा। इस बजट में किसानों पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है। इस प्रकार से यह बजट सभी को शक्ति देने वाला है।

यह बजट न केवल हमारे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि हमारे नागरिकों के जीवन में भी सुधार लाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गनिर्देशन में वित्त मंत्री महोदया ने इस बजट में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए लाभकारी होंगे। इनमें से कुछ प्रमुख घोषणाएं हैं।

टैक्स में छूट : इस टैक्स स्लैब में काफी बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा। वेतनभोगियों के लिए 12 लाख ₹0 की आय को आयकर से मुक्त रखा गया है। सरकार ने 5 लाख रुपये तक की आय पर कर छूट दी है, जिससे 90 प्रतिशत से अधिक करदाताओं को लाभ होगा। इसके अलावा 7.5 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया गया है, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को लाभ होगा तथा टैक्स पेयर्स को 1.5 लाख रुपये तक के होम लोन पर भी ब्याज पर छूट दी है, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों को घर खरीदने में काफी मदद मिलेगी।

किसानों के लिए योजनाएं हमारी लोकप्रिय सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का विस्तार, मखाना बोर्ड का गठन, और किसान क्रेडिट कार्ड के लोन की सीमा बढ़ाना शामिल है। किसानों के लिए कई लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है।

यह भी बहुत ही सुखद है कि सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना का विस्तार किया है, जिससे किसानों को फसल की खराबी के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई मिलेगी। हमने किसानों के लिए सिंचाई योजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के केन्द्रीय नेतृत्व में सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनमें कैंसर और गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए 36 दवाओं पर कस्टम ड्र्यूटी हटाना और नई शिक्षा नीति को लागू करना शामिल है।

हमारी लोकप्रिय सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है तथा आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया गया है। जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। हमने शिक्षा के क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

रोजगार सृजन : सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें स्टार्टअप और एमएसएमई क्षेत्र में निवेश बढ़ाना और क्रेडिट गारंटी स्कीम का कवर बढ़ाना शामिल है। हमने रोजगार सृजन के लिए 10,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिससे नए व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा। हमने एमएसएमई के लिए 5,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, जिससे छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय बजट 2025-26 भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करता है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विस्तार, वित्तीय अनुशासन और समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया है। कुल ₹50.65 लाख करोड़ के व्यय के साथ, यह बजट पूंजी निवेश, सामाजिक क्षेत्र में खर्च और कर सुधारों को प्राथमिकता देता है, जबकि राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.4 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखता है। बजट में रेलवे, राजमार्ग, रक्षा और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण धनराशि आवंटित की गई है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। यह आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण देश में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी।

शिप बिल्डिंग सर्वाधिक रोजगार देने वाला सेक्टर है। उसी तरह से होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर जोर दिया गया है, जिससे इससे रोजगार बढ़ेगा।

हमारा देश "विकास भी, विरासत भी" मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं तथा किसानों के लिए जो घोषणा हुई है, वह कृषि क्षेत्र और समूचल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी।

राष्ट्रीय उच्च उपज बीज मिशन और मखाना बोर्ड जैसी योजनाएं कृषि उत्पादकता में सुधार करेंगी। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अल्पकालिक ऋण की सुविधा बढ़ाई जाएगी। दाल उत्पादन और टिकाऊ कपास खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष मिशन शुरू किए जाएंगे।

MSME की परिभाषा में संशोधन कर निवेश और कारोबार की सीमा बदली जाएगी ताकि अधिक व्यवसाय इसका लाभ ले सकें ।

सूक्ष्म उद्यमों के लिए विशेष क्रेडिट गारंटी और कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड, जिससे 10 लाख छोटे व्यवसायों को सहायता मिलेगी ।

जूता, चमड़ा, खिलौने और खाद्य प्रसंस्करण जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया गया है । शहरी पुनर्विकास और जल प्रबंधन के लिए ₹1 लाख करोड़ का अर्बन चौलेंज फंड स्थापित किया गया है । राज्यों के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय (ब्याज मुक्त ऋण सहित) आवंटित किया गया है ।

चिकित्सा शिक्षा का विस्तार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पहल, और अटल टिकरिंग लैब्स की संख्या बढ़ाई जाएगी । ग्रामीण स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, कौशल विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र, और के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है । कर संरचना को सरलीकरण और युक्तिसंगत बनाने के लिए नए प्रस्ताव लाए गए हैं । मध्यम वर्ग के लिए आयकर सुधार, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त कटौती, और किराए पर TDS सीमा में संशोधन किया गया है । बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई है ।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'ग्रामिण क्रेडिट स्कोर और केवाईसी रजिस्टर को पुनर्गठित किया गया ताकि ऋण प्रक्रिया को तेज किया जा सके ।

यह हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है कि इस बजट में निम्नांकित क्षेत्रों पर भी विशेष रूप से फोकस किया गया है. जो स्वागत योग्य है ।

- वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 12 लाख की आय को आयकर से मुक्त रखा गया है । इससे बचत के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा भी बढ़ेगी ।

- बुजुर्ग नागरिकों के लिए ब्याज से होने वाली आय पर टैक्स डिडक्शन लिमिट बढ़ाई गई । इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी बढ़ाया गया ।

- पांच लाख एससी और एसटी महिलाओं को नई स्कीम को लाभमिलेगा ।

-22 लाख लोगों को लेदर इंडस्ट्री से रोजगार मिलेगा ।

-स्टार्ट-अप के लिए अब 10 करोड़ रुपये तक के लोन की सुविधा । श्रम प्रधान सेक्टर्स जैसे कि जूते, चप्पल, चमड़ा और खिलौने पर विशेष ध्यान, जिससे लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी । स्टार्ट-अप को टैक्स राहत से उद्यमिता को और बढ़ावा मिलेगा ।

- भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें होंगी ।

- आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा ।
- उड़ान योजना से हैलीपेड विकसित किए जाएंगे ।
- उड़ान योजना से 120 नए एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा । मिडिल क्लास को मिलेगा फायदा ।
- चुनिंदा पर्यटकों को वीजा मुफ्त मिल सकेगा ।
- नेशनल जीयो स्पेशल मिशन लागू होगा । म्यूजियम को इस मिशन से जोड़ा जाएगा ।
- निर्यात के लिए एक्पोर्ट प्रमोशन सेंटर खोले जाएंगे ।
- रिसर्च के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की घोषणा ।
- नया इनकम टैक्स बिल अगले सप्ताह पेश होगा ।
- अप्रत्यक्ष कर को कम करने की घोषणा, जिससे आम आदमी को फायदा मिला ।
- 50 हजार सस्ते मकान बनाए जाएंगे ।
- मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे ।
- कैंसर से जुड़ी दवाएं सस्ती होंगे ।
- ईवी बैट्री पर छूट का ऐलान ।
- 82 सामानों से सेस हटाया गया ।
- नवाचार संवर्द्धन के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स ।
- बुनियादी ढांचा विकास के लिए राज्यों को डेढ़ लाख करोड़ रुपये की ऋण सुविधा ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 100 प्रतिशत नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाई गई है ।
- एक करोड़ गिग वर्कर्स को पीएम जल आरोग्य योजना का लाभ
- चमड़े से आयात शुल्क हटाया गया, जिससे बाजार में चमड़ा होगा सस्ता ।
- इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी सस्ती ।
- भारत में बने कपड़े सस्ते होंगे । बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़ों भी सस्ते मिलेंगे ।

- भारत में मोबाइल फोन सस्ते किए जाएंगे ।
- जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होंगी ।
- लीथियम बैट्री पर छूट मिलेगी ।
- कानूनों को आसान बनाया जाएगा ।
- कंप्लाइंस का बोझ कम करने के साथ टैक्स की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है । एएसएमईएस के लिए मंजूरी की प्रक्रिया तेज होगी । एमएसएमईएस के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये के अतिरिक्त ऋण का प्रावधान किया गया है । इससे क्लासिफिकेशन काइटेरिया में सुधार होने का लाभ ज्यादा से ज्यादा व्यवसायों को होगा ।
- सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपये की मिलनमिट के साथ उद्यम क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई है ।
- स्वामी फंड के माध्यम से लंबे समय से अटके हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरे किए जा रहे हैं । इससे मिडिल क्लास के लोगों को घर मिलना आसान होगा ।
- एमएसएमईएस के विकास को बढ़ावा देने के लिये 10 हजार रोड़ के साथ फंड ऑफ फंड्स का विस्तार किया गया है ।
- नया इनकम टैक्स बिल बहुत साफ होगा, जिससे टैक्स भरने में आसानी होगी ।
- टीडीएस को और तार्किक बनाया जाएगा । इसकी सीमा को दोगुना किया जाएगा ।
- खिलौना सैक्टर के लिए भी विशेष स्कीम लाने का प्रावधान किया गया है ।
- होम स्टे बनाने के लिए मुद्रा लोन की घोषणा ।
- पटना एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा ।
- बिहार के लिए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की घोषणा ।

अंत में, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की लंबित रेल परियोजना के बारे में सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि विगत लोक सभा में मेरे द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1806, दिनांक 13-12-2023 के बारे में माननीय रेल मंत्री जी ने यह जानकारी दी थी कि पूर्वोत्तर रेलवे में फर्रुखाबाद-शाहजहांपुर मैनाली (165 किलोमीटर) नई लाइन के निर्माण संबंधी सर्वेक्षण 4168 करोड़ रुपये की अनुमानित परियोजना लागत के साथ 2018-19 में पूरा हो गया था ।

इस रेलवे लाइन के स्थापित किए जाने से जहां शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, लखमीपुर खीरी, बदायूं, पीलीभीत, जो अत्यधिक पिछड़े जिले हैं. इन जनपदों के दूरगामी ग्रामीण अंचल रेलवे नेटवर्क से जुड़ सकेंगे, वहीं सैन्य छावनियों के कारण शाहजहांपुर और

फतेहगढ़ जैसे सुरक्षा की दृष्टि से सामरिक केन्द्रों का जुड़ाव सीधे मथुरा, आगरा, ग्वालियर, झांसी और टनकपुर स्थित छावनियों से होने पर संवेदनशील रहने वाली उत्तरी सीमा को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी।

अतः मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि फर्रुखाबाद-शाहजहांपुर मैलानी रेलवे लाईन परियोजना के शीघ्र निर्माण हेतु धन का प्रावधान करने की कृपा करेंगी। ताकि क्षेत्र के विकास के साथ-साथ देश को सामरिक दृष्टिकोण से भी मजबूती मिल सके।

मुझे अपने संसदीय क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्थानीय जनता के द्वारा लखनऊ से दिल्ली के बीच शाहजहांपुर होते हुए वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने और इस रेलगाड़ी का ठहराव शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर भी दिए जाने की मांग विगत कई माह से की जा रही है। इस संदर्भ में, मैं माननीय रेल मंत्री जी को पत्र लिखकर अनुरोध भी कर चुका हूँ।

मैं सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि उ०प्र० राज्य के लोक सभा क्षेत्र शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं० रामप्रसाद बिस्मिल, ठा० रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां की जन्म स्थली है तथा इन वीर सपूतों ने देश को गुलामी की जंजीरों से आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ऐसे क्रांतिकारों के कारनामों से भरा हुआ है, जिन्होंने अपनी चिंगारी से युगों को रोशन किया है और क्रांति तथा जगचेतना जगाकर देश को एक नई दिशा दी है।

अतः मेरा अनुरोध है कि देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पं० रामप्रसाद बिस्मिल, ठा० रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां की स्मृति और सम्मान में लखनऊ से दिल्ली के बीच शाहजहांपुर होते हुए वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने और इस रेलगाड़ी का ठहराव शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर भी दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ-साथ आपका भी आभार प्रकट करता हूँ कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अन्तर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र के शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया गया है तथा इसके नवीनीकरण हेतु प्रथम चरण में 17 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है। लेकिन, मुझे दुःख है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर रिडेवलेपमेंट से संबंधित प्रक्रिया बहुत ही धीमी गति से चल रही है तथा कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं है और कार्यदायी एजेंसी डी०आर०एम०, मुरादाबाद की मिलीभगत से कार्य को अत्यधिक निम्न स्तर का करवा रही है तथा अब तक केवल 10 प्रतिशत के आसपास ही कार्य को करवाया गया है।

इस संबंध में, मेरे द्वारा मुरादाबाद उत्तर रेलवे के डी०आर०एम० का बार-बार ध्यान आकर्षित किए जाने के पश्चात भी वे इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा प्रारम्भ की गई अमृत भारत स्टेशन योजना शाहजहांपुर में रफ्तार नहीं पकड़ रही है तथा कार्य भी गुणवत्ता के अनुरूप नहीं हो रहा है। इसके लिए डी०आर०एम०, मुरादाबाद मुख्य रूप से जिम्मेवार है। इस संदर्भ में, मैं 07-01-2025, 26-11-2024 एवं जुलाई, 2024 में डी०आर०एम०, उत्तर

रेलवे. मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायत भेज चुका हूं। लेकिन मुझे इस प्रकरण में शिथिलता बरतने वाले अधिकारी के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही ही है और न ही कार्य को गुणवत्ता के अनुरूप करवाया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अन्तर्गत शामिल किए गए शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन, जो देश का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन भी है, का शीघ्र रिडेवलेपमेंट वरीयता के आधार पर अविलम्ब पूरा करवाए जाने और इस संबंध में शिथिलता बरतने तथा कार्यदायी एजेंसी के साथ मिलीभगत करके कार्य को मानक के अनुरूप न करवाए जाने वाले डी०आर०एम०, मुरादाबाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

मेरा यह भी अनुरोध है कि गुणवत्ता के अनुरूप कार्य न करवाए जाने संबंधी प्रकरण में मंत्रालय स्तर पर एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित करके उससे विस्तृत जांच करवाए जाने और जांच अधिकारियों को जांच के दौरान स्थानीय सांसद से भी सम्पर्क किए जाने हेतु निर्देशित किया जाए। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर (उ०प्र०) के अन्तर्गत विकास खंड तिलहर में लखनऊ-दिल्ली मुरादाबाद रेल मार्ग पर निगोही-तिलहर के मध्य रेलवे समपार संख्या 334-बी के स्थान पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के रेलवे भाग के सी०पी०-1 और सी०पी०-2 का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके फाउंडेशन सी०पी०-2 के नीचे रेलवे सिग्नल की केबिलें आ रही है, जिन्हें शिफ्ट करवाए जाने हेतु उ०प्र० राज्य सेतु निगम लि० द्वारा मण्डल रेल प्रबंधक, उत्तर रेलवे, मुरादाबाद एवं अन्य अधिकारियों को 19-11-2024 और 31-12-2024 में पत्र लिखकर अनुरोध किए जा चुके हैं। लेकिन, अब तक इस कार्य को पूरा नहीं करवाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप रेलवे भाग के सी०पी०-2 में पाईलिंग का कार्य अनावश्यक रूप से बाधित हो रहा है। इस संदर्भ में, मैं भी 13-01-2025 में पत्र लिखकर अनुरोध कर चुका हूँ।

मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त सी०पी०-2 के नीचे रेलवे सिग्नल की केबिलों को अविलम्ब अन्यत्र शिफ्ट करवाए जाने हेतु निर्देशित किया जाए। मैं सरकार का ध्यान श्री रूप नारायण सुनकर, सदस्य इन्फ्रास्ट्रक्चर, रेलवे बोर्ड एवं पदेन सचिव, भारत सरकार, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 2023/एलएमएल 11/13/20, दिनांक 29-11-2023 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो मेरे संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर (उ०प्र०) में उत्तर पूर्व रेलवे के नियंत्रणाधीन निष्प्रयोज्य रेलवे भूमि शहबाजनगर से केरुगंज तक तथा उत्तर रेलवे के नियंत्रणाधीन निष्प्रयोज्य रेलवे भूमि इन्द्रानगर से मघईटोला, बहादुरपुरा से बाहदुरगंज तक की भूमि को राज्य सरकार को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में है। इस संबंध में, मैं आपका ध्यान शाहजहांपुर (उ०प्र०) के जिलाधिकारी के पत्रांक 129/ एस०टी०-न०आ० / न०नि०शाह० /2024, दिनांक 27 मई, 2024 की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा, जो उपर्युक्त निष्प्रयोज्य रेलवे लाइन राज्य को हस्तांतरित / उपयोग की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में है। मैं यह भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि केवल अयोध्या रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए अयोध्या में ही रेलवे को भूमि आवंटन संबंधी प्रकरण में कार्य हुआ है तथा मेरे संसदीय जनपद शाहजहांपुर में निष्प्रयोज्य रेलवे लाइन की भूमि को अभी भी हस्तांतरण/उपयोग में लाया जाना बाकि है। जनपद शाहजहांपुर की नगर विधानसभा में गरी फाटक से मोहल्ला ककरा होते हुए शाहबाजनगर तक, मोहल्ला बाला तिराही से मोहल्ला केरुगंज, हुसैनपुरा, बिजलीपुरा, इस्लामिया इण्टर कॉलेज के पीछे से होते हुए इन्द्रानगर कालोनी तक रेल लाइन बिछी हुई थी। जिस पर पिछले 40 वर्षों से रेलगाड़ियों का आवागमन बंद होने के परिणामस्वरूप यह भूमि बेकार पड़ी हुई है तथा इसकी अधिकांश भूमि पर अवैध कब्जा भी हो चुका है। रेलवे की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जे से भूमि को बचाने हेतु वैकल्पिक

योजना के रूप में यदि रेलवे की इस भूमि पर सड़क का निर्माण हो जाता है तो रेलवे की उक्त भूमि को अवैध कब्जे से बचाया जा सकता है। शाहजहांपुर नगर निगम दो नदियों गर्ग एवं खन्नौत के बीच में आता है तथा यह सघन आबादी वाला क्षेत्र है। इसलिए शाहजहांपुर संसदीय जनपद में निष्प्रयोज्य रेलवे लाइन की भूमि को शाहजहांपुर नगर निगम को आवंटित किए जाने में सड़क निर्माण इत्यादि कार्यों में उपयोग में लाया जा सकेगा तथा सड़क निर्माण से स्थानीय लोगों को यातायात अवरुद्ध से भी मुक्ति मिलेगी।

मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि नगर निगम शाहजहांपुर उक्त बंद पड़ी रेलवे लाइनों के दोनों ट्रैक पर सी०सी० मार्ग / कोलतार का मार्ग बनवाना चाहता है। इससे क्षेत्रवासियों को शहर में बढ़ रही जाम की समस्या से निजात मिलेगा तथा रेलवे की भूमि को अवैध कब्जे से बचाया जा सकेगा। अतः उपरोक्त समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त रेलवे लाइन पर रोड़ निर्माण हेतु नगर निगम शाहजहांपुर को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। अतः मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय जनपद शाहजहांपुर में निष्प्रयोज्य रेलवे भूमि को नगर निगम शाहजहांपुर को हस्तांतरण/उपयोग में लाये जाने एवं रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों को राज्य सरकार के साथ तालमेल बैठकर कार्य को शीघ्र सम्पन्न करवाए जाने हेतु निर्देशित किया जाए। यह वास्तविकता है कि सदन में प्रस्तुत यह बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला है। यह बजट बचत को बढ़ाएगा, निवेश को बढ़ाएगा, खपत को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से आगे बढ़ाएगा और हमारे देश के विकास को बढ़ावा देगा तथा हमारे नागरिकों के जीवन में सुधार लाएगा और देश के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अंत में, मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी और उनके सहयोगी राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी का हृदय से आभार प्रकट करते हुए सदन में प्रस्तुत जनरल बजट का हार्दिक समर्थन करता हूँ।

***m61 डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश (धुले) :** मैं अपनी पार्टी नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय, 2025-26 के केंद्रीय बजट पर आपने विचार रखने का अवसर दिया। जैसा कि मेरे पार्टी नेतृत्व राहुल गांधी जी और अन्य कई सदस्यों ने सही रूप से उल्लेख किया है, यह बजट देश के सामने मौजूद अनेक चुनौतियों और समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है।

बजट में गरीबों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोजगार से जुड़ी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए आवंटन नहीं बढ़ाया गया है। सरकार ने 86,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान के बराबर ही है। यदि आप 2023-24 के वास्तविक व्यय को देखें, जो 89,154 करोड़ रुपये था, तो इस साल बजट में वास्तव में कटौती की गई है। 2005 में यूपीए सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लेकर आई थी। इस अधिनियम ने भारत में लाखों लोगों को आजीविका प्रदान की है। हम सभी जानते हैं कि COVID-19 महामारी के दौरान यही योजना थी, जिसने ग्रामीण आबादी को आजीविका सहायता प्रदान की थी। फिर भी अपर्याप्त बजटीय आवंटन, धन जारी करने में देरी या धन जारी न होने जैसी समस्याओं से योजना प्रभावित रहती है। इस विषय पर मैं एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। वर्तमान में दिए जा रहे मजदूरी दर बढ़ती जीवन यापन की लागत को देखते हुए बेहद अपर्याप्त हैं। मैं मंत्रालय से अनुरोध करती हूँ कि

वे वेतन दरों की गणना के लिए 2009-10 के आधार को संशोधित करने पर विचार करें, ताकि मौजूदा मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों को ध्यान में रखा जा सके।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा अपने चरम पर है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराध दर 2012 में 42 थी, जो 2022 में बढ़कर 66 हो गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में हर साल औसतन 30,000 से अधिक बलात्कार के मामले दर्ज किए जाते हैं। इसे स्पष्ट रूप से समझें तो भारत में हर 17 मिनट में एक नया बलात्कार का मामला दर्ज किया जाता है। यह बेहद शर्मनाक है। आप बड़ी-बड़ी झूठी घोषणाएँ करते हैं, लेकिन आपकी ही सरकार के आधिकारिक आंकड़े हमें सच्चाई दिखाते हैं। महिलाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय बनी हुई है। श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी मात्र 32% है, जो बेहद चिंताजनक है। सक्षम आंगनवाड़ी योजना, जो महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और आजीविका दोनों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, उसे लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। आज भी अधिकांश आंगनवाड़ी केंद्र (AWCs) बुनियादी ढांचे से वंचित हैं। कुल आंगनवाड़ी केंद्रों में से केवल आधे ही अपने स्वयं के भवनों में संचालित हो रहे हैं। 30% केंद्रों में अभी भी कार्यशील शौचालय तक नहीं हैं। यह आंकड़े आपके ही POSHAN ट्रैकर से लिए गए हैं। स्थिति सुधारने की बार-बार मांग के बावजूद, आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राथमिकता न देना, मतलब महिलाओं और बच्चों की जरूरतों को पीछे धकेलना है। साथ ही, मैं यह भी उजागर करना चाहती हूँ कि वर्तमान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय केवल ₹4,500 प्रति माह है। यह अत्यधिक कम है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता देश में लाखों लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने की रीढ़ हैं। उन्हें उनके काम के अनुरूप वेतन दिया जाना चाहिए, जिसमें बढ़ती मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत को ध्यान में रखा जाए।

सरकार का लगातार कम स्वास्थ्य बजट, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता और गुणवत्ता को प्रभावित कर रहा है, जिससे लोगों को मंहगे निजी क्षेत्र में इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एनएसएसओ (NSSO) के अनुसार, कुल अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में से लगभग 60% और Out-Patient Services का 70% निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान किया जाता है। महोदय, हर साल भारत की 7% से अधिक आबादी स्वास्थ्य खर्चों के कारण गरीबी रेखा से नीचे चली जाती है, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र।

पानी: जल है तो जीवन है। पानी मानव जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे मूलभूत आवश्यकता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार और मानव अधिकारों का हिस्सा है। महोदय, सरकार गर्व से दावा करती है कि अधिकांश ग्रामीण घरों को जल कनेक्शन प्रदान किया गया है- भारत में 79%, महाराष्ट्र में 88% और मेरी संसदीय क्षेत्र धुले में 99%। लेकिन जमीन पर हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। मेरी संसदीय क्षेत्र ही नहीं, बल्कि पूरे देश में लाखों लोगों की स्थिति अलग है। पाइपलाइन बिछा दी गई हैं, लेकिन बिना जल आपूर्ति के वे सिर्फ शोपीस बनकर रह गई हैं। नल तो लगा दिए गए हैं, लेकिन उनमें पानी नहीं है। सरकार का काम और दावे उतने ही खोखले हैं, जितनी ये सूखी पाइपलाइन। यह योजना गरीबों, कमजोरों और वंचितों की मदद के लिए थी या सिर्फ ठेकेदारों के फायदे के लिए? ऐसा लगता है कि इस सरकार की योजनाएँ केवल

बड़े उद्योगपतियों और कॉरपोरेट मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं, क्योंकि इस सरकार को सिर्फ ठेके देने की चिंता है। काम हो या न हो, निर्माण की गुणवत्ता कैसी है, या ये नई परियोजनाएँ सही ढंग से काम कर रही हैं या नहीं- इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे जल जीवन मिशन हो, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) हो या कोई और योजना, सरकार की प्राथमिकता सिर्फ ठेकेदारों को फायदा पहुँचाना है, न कि जनता की भलाई सुनिश्चित करना।

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की भी यही स्थिति है। एक ऑडिट में यह सामने आया कि *PMAY (U) के तहत AHP वर्टिकल में बने घर अक्सर खाली पड़े रहते हैं क्योंकि उनमें बुनियादी सुविधाएँ-पानी, सीवरेज और बिजली का अभाव है। और मैं यहाँ किसी सामान्य रिपोर्ट की नहीं, बल्कि कैग (CAG) ऑडिट की बात कर रही हूँ। तो हाँ, सरकार ने घर तो बना दिए। लेकिन कितने घर वास्तव में रहने लायक हैं? और कितने घरों में वाकई गरीब लोग रह रहे हैं?

आयुष्मान भारत को ही देख लीजिए। सरकार ने अपनी योजना आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (HWC) बनाने के लिए भारी भरकम रकम खर्च की है। या जैसा कि सरकार इन्हें "आरोग्य मंदिर" कहती है। ऐसा लगता है कि इस सरकार के लिए नामकरण (Naming) ही सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन सच्चाई यह है कि ये केंद्र पूरी तरह से विफल रहे हैं। हाँ, आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बुनियादी स्थान, उपकरण और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। एक बहुत मशहूर अंग्रेजी कविता है: "Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall" यह कविता इस सरकार के काम को बिल्कुल सटीक रूप से दर्शाती है। जैसे ही निर्माण कार्य पूरा होता है, वह गिरने लगता है। पिछले साल अक्टूबर में सिर्फ थोड़ी-सी बारिश हुई और रत्नागिरी स्टेशन की छत की चादरें गिरने की कगार पर आ गई। और अटल सेतु-17,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बना यह पुल उद्घाटन के कुछ ही महीनों में दरारों से भर गया। जो सरकार खुद को "इन्फ्रास्ट्रक्चर केंद्रित" कहती है, यह वो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, जिस पर इस सरकार को गर्व है। इन्होंने तो छत्रपति शिवाजी महाराज तक को नहीं बख्शा। आप भले ही भूल गए हों, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूँगी। जिस किसी के भीतर मराठा रक्त की एक भी बूंद है, वह कभी नहीं भूल सकता कि इस सरकार ने उस वीर योद्धा का अपमान किया।

मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ। मुझे गर्व है कि मुझे महाराष्ट्र से इस संसद में चुने जाने का अवसर मिला। महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है। चाहे जीडीपी हो, टैक्स हो-कॉरपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स या जीएसटी- हम सबसे अधिक योगदान देते हैं। लेकिन फिर भी, आपके बजट भाषण में महाराष्ट्र का कोई जिक्र तक नहीं हुआ। उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा लंबे समय से सूखे जैसी परिस्थितियों के कारण कृषि संकट झेल रहे हैं। महाराष्ट्र में कुल बुवाई वाले क्षेत्र का केवल 18% ही सिंचित है, जबकि राष्ट्रीय औसत 50% है। तो सवाल यह उठता है: महाराष्ट्र का अधिकांश हिस्सा अब भी वर्षा पर निर्भर क्यों है? सरकार ने अब तक महाराष्ट्र के किसानों की स्थिति सुधारने के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? अगर हमारी बात नहीं सुनना चाहते, तो कम से कम अन्नदाता की पुकार तो सुन लीजिए। वहीं किसान, जो सूरज की तपिश, बारिश और कठिन परिस्थितियों में मेहनत करके हमें भोजन देता है, वह आज संकट में है। बार-बार सूखा पीड़ित किसानों के लिए राहत की मांग की गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, किसान आत्महत्याओं के मामले में महाराष्ट्र

सबसे आगे है। सरकार कब इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देगी? महाराष्ट्र में पानी की उपलब्धता और सिंचाई को बेहतर बनाने के लिए ठोस प्रयास कब होंगे?

हम सभी ने वित्त मंत्री का भाषण ध्यान से सुना, इस उम्मीद में कि आम आदमी को कुछ राहत मिलेगी। माननीय वित्त मंत्री ने कहा था- "एक देश सिर्फ उसकी मिट्टी नहीं होता, एक देश उसके लोग होते हैं।" लेकिन सच्चाई यह है कि इस सरकार ने खुद अपने ही भारतीयों को असफल कर दिया है। आप "विकास" के गीत गाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप बुनियादी मुद्दों पर भी विफल रहे हैं। आप पिछले दस वर्षों में असफल रहे। और आज भी इस बजट में इन मुद्दों को सुलझाने में विफल रहे। इस बजट ने अन्याय किया है। इसने अन्याय किया है महिलाओं के साथ। इसने अन्याय किया है किसान के साथ, गरीबों के साथ, देश के साथ। धन्यवाद।

डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले (भंडारा-गोंदिया) : मैं इस महत्वपूर्ण बजट पर अपने विचार रखता हूँ। मैं अपने दिल का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित सदन में जनता की चिंताओं को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी सौंपी। वे लोग जो दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, और जिन्होंने एक ऐसे बजट की उम्मीद की थी जो वास्तव में उनकी जरूरतों को पूरा करता। दुर्भाग्यवश, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। यह एक बार फिर भाजपा सरकार की गलत प्राथमिकताओं और दोषपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण का प्रमाण है। सरकार तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का दावा करती है, लेकिन यह विकास आखिर किसके लिए हो रहा है? अमीर और गरीब के बीच की बढ़ती खाई, हमारे किसानों की समस्याएँ, और छोटे व्यवसायों की कठिनाइयाँ एक अलग ही तस्वीर पेश करती हैं। आइए, इस बजट का विश्लेषण करें और देखें कि क्या यह जनता से किए गए वादों को पूरा करता है, या फिर यह सिर्फ एक और चुनावी दिखावा है, जिससे जनता को एक बार फिर गुमराह किया जा रहा है।

भाजपा सरकार ने 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' और 'दालों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन' की घोषणा की है। ये योजनाएँ सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इनसे किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम कैसे मिलेंगे, इस पर कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। किसानों की वर्षों से चली आ रही MSP की कानूनी गारंटी की माँग को इस बजट में पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। यह सरकार की किसानों के प्रति उदासीनता को दर्शाता है। किसानों के लिए ऋण माफी या ब्याज मुक्त ऋण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जबकि किसान लगातार बढ़ते कर्ज के बोझ से आत्महत्याएँ करने पर मजबूर हो रहे हैं। अरबपतियों का अरबों का कर्ज माफ़ किया जाता है, लेकिन किसानों के लिए एक भी पैसा नहीं दिया जाता।

सरकार सिंचाई और भंडारण की सुविधाएँ बढ़ाने का वादा करती है, लेकिन उर्वरक, डीजल और बिजली की लागत कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। भाजपा सरकार ने हमेशा किसानों पर बोझ डाला है और कृषि क्षेत्र में बड़े कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुँचाया है। इस बजट में किसानों की समस्याओं का कोई वास्तविक समाधान नहीं है। यह सिर्फ कागज़ी योजनाएँ बनाकर दिखावे की राजनीति करने का एक और उदाहरण है। भाजपा सरकार छोटे और मध्यम उद्योगों (MSME) को देश की अर्थव्यवस्था का दूसरा इंजन बताती है, लेकिन ये उद्योग आज गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं। सरकार ने कर्ज की सीमा

बढ़ाई है, लेकिन इससे मांग की कमी और बढ़ती परिचालन लागत जैसी मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होता। मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा किया था, लेकिन इस बजट में रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। युवाओं को सिर्फ दिखावटी योजनाएँ नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण रोजगार चाहिए।

सरकार ने गिग वर्कर्स को मान्यता तो दी है, लेकिन उनके लिए नौकरी की सुरक्षा, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा का कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है। भाजपा की कॉर्पोरेट समर्थक नीतियाँ इन श्रमिकों को असुरक्षित छोड़ रही हैं। 'मेक इन इंडिया' अब सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है। इस बजट में न तो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ किया गया है और न ही नई नौकरियों सृजित करने के लिए। सरकार की असफल नीतियों की वजह से नौकरियाँ बन नहीं रहीं, बल्कि खत्म हो रही हैं। भाजपा सरकार ने आयकर छूट की सीमा 212 लाख तक बढ़ाने की घोषणा की है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा। कर राहत का कोई फायदा नहीं होगा अगर आवश्यक वस्तुओं, ईंधन और स्वास्थ्य सेवाओं की कीमतें आसमान छूती रहें। सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण मध्यम वर्ग पहले से ज्यादा संकट में आ गया है। सामाजिक सुरक्षा की अनदेखी: पेंशन सुधार और मध्यम वर्ग और बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सरकार ने कोई परवाह नहीं की। सरकार एक तरफ प्रत्यक्ष कर कम करने का दिखावा कर रही है। जबकि दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर गरीब और मध्यम वर्ग की आमदनी पर और बोझ डाल रही है। वादे बहुत, पर वास्तविकता कुछ नहीं। सरकार दावा करती है कि वह जनता में निवेश कर रही है, लेकिन स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए अपर्याप्त बजट आवंटन से हकीकत कुछ और ही नजर आती है। सरकार ने डे-केयर केंसर सेंटर खोलने की बात कही है, लेकिन सार्वजनिक स्वास्थ्य ढाँचे को मजबूत करने के लिए बजट बहुत कम रखा गया है।

स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने का वादा किया गया है, लेकिन शिक्षकों की सैलरी, सरकारी स्कूलों का आधुनिकीकरण और ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। भाजपा सरकार निजीकरण को बढ़ावा देकर गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा को और महंगा बना रही है। महाराष्ट्र, जो देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देता है। इस बजट में पूरी तरह उपेक्षित किया गया है। मुंबई, पुणे और नागपुर मेट्रो परियोजनाओं के लिए कोई विशेष निधि नहीं है। रेलवे और राजमार्गों के लिए कोई नई परियोजना नहीं है। ऑटोमोबाइल, फार्मास्युटिकल और आईटी उद्योगों को कोई प्रोत्साहन नहीं है। विदर्भ और मराठवाड़ा के कर्ज में डूबे किसानों के लिए कोई राहत नहीं है। पर्यटन और विरासत स्थलों के विकास की पूरी तरह अनदेखी की गई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में कोई बड़ा निवेश नहीं है। यह स्पष्ट करता है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र को जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है। यह बजट किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करता। रोजगार संकट को हल करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं देता। मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक राहत प्रदान नहीं करता। स्वास्थ्य और शिक्षा को मजबूत करने में विफल है। वित्तीय पारदर्शिता और जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन से कोसों दूर है। यह सिर्फ एक और चुनावी स्टंट है, जिसमें भाजपा सरकार ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। हम, विपक्ष के रूप में, इस सरकार की असफलताओं को उजागर करना जारी रखेंगे और इसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाएँगे। भारत की जनता को एक ऐसा बजट चाहिए, जो सभी को समान रूप से लाभ पहुँचाए सिर्फ कुछ गिने-चुने अमीरों को नहीं।

जय हिंद ।

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर) : मैं वर्ष 2025- 26 के केंद्रीय बजट पर विचार रखता हूँ जो हमारे राष्ट्र की आर्थिक यात्रा को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा । इस बजट में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं । यह बजट न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे देश के विभिन्न वर्गों की भलाई को भी सुनिश्चित करने का कार्य करेगा ।

सबसे पहले, हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है । पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों और विकास कार्यों ने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई है । इस बजट का लक्ष्य भी उसी दिशा में निरंतर प्रगति करने का है, विशेष रूप से हमारे गरीब, किसान, युवा और महिला वर्ग को सशक्त बनाने के लिए ।

आयकर में राहत: सरकार ने देश के मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है । 2014 में आयकर की शून्य स्लैब को ₹2.5 लाख तक बढ़ाया गया था, जिसे अब बढ़ाकर ₹7 लाख कर दिया गया है । अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा । इससे करोड़ों भारतीयों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी ।

कृषि और ग्रामीण विकास: कृषि क्षेत्र को लेकर इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं ।

- 'प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना' के तहत 100 जिलों में सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे, जिससे लगभग 1.7 करोड़ किसानों को लाभ होगा ।
- 'दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन' भी शुरू किया जाएगा, जिससे हमारे किसान आत्मनिर्भर होंगे और उनकी आय में वृद्धि होगी
- एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी के लिए 1 लाख 71 हजार 437 करोड़ रुपये की विशाल राशि दी गई है ।

मैं बजट में प्रमुख योजनाओं पर परीव्यय के बारे में बताना चाहता हूँ :

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 8 हजार 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं ।
- कृषोन्नति योजना के लिए 8 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं ।
- एनएफएस के अंतर्गत खादयान्नों को राज्य के भीतर लाने व ले जाने के लिए 7 हजार 75 करोड़ रुपये दिए गए हैं ।
- प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण के लिए 12 हजार 500 करोड़ रुपये दिए गए हैं ।
- पीएम मत्स्य संपदा योजना के लिए 2 हजार 464 करोड़ रुपये दिए गए हैं ।
- पशुपालन और डेयरी के लिए 1 हजार 50 करोड़ रुपये दिए गए हैं ।

- प्रधान मंत्री सूक्ष्म खादय प्रसंस्करण उद्योगों के लिए 2 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई के लिए 8 हजार 260 रुपये दिए गए हैं।
- नदियों को आपस में जोड़ने के लिए 8 हजार 336 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
- इंटरलिविकिंग रिवर, अद्भुत जल जीवन मिशन के लिए 67 हजार करोड़ रुपये का प्रोविजन है।
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए ये कह रहे थे कि बजट ही नहीं है तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि 86 हजार करोड़ रुपये का प्रोविजन यहाँ स्पष्ट दिख रहा है।

मजदूरों और गिग वर्कर्स के लिए योजना: माननीय प्रधानमंत्री ने गिग वर्कर्स के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान किया है। गिग वर्कर्स की पहचान पत्र और स्वास्थ्य की सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को लाभ होगा। यह कदम हमारे शहरी और ग्रामीण मजदूरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।

ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को भी केंद्रीय बजट में 1.88 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के लिए 86 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। डिफेंस में भारत को मजबूत बनाने का सपना देखने वाले प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ रुपये करना देश की सुरक्षा के लिए हमें आवश्यक करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के आम बजट में रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, तथा जल शक्ति मंत्रालय के लिए महत्वपूर्ण आवंटन और योजनाओं की घोषणा की है:

रेल

- बजट आवंटन: रेल मंत्रालय के लिए 2,52,200 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष के समान है।
- सुरक्षा: सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, 1,16,514 करोड़ का बजट सुरक्षा उपायों के लिए आवंटित किया गया है।
- इलेक्ट्रिफिकेशन: 2025-26 में 100% रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रखा गया है जिसे पूरा करने में हमारी सरकार प्रयासरत है।
- स्टेशन रीडेवलपमेंट: अगले चार वर्षों में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा जिससे यात्रियों को मॉडर्न रेल सुविधाएं प्रदान हो सकेंगी।
- नमो भारत ट्रेनें: इंटरसिटी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए 50 नमो भारत ट्रेनें चलाने की योजना है।
- बजट आवंटन: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2,87,333.16 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जो पिछले बजट से 2.41% अधिक है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI): NHAI के लिए आवंटन 1,693.71 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,878.03 करोड़ रुपये किया गया।

- जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन की अवधि तीन वर्ष बढ़ाकर 2028 तक कर दी गई है, जिससे सभी घरों को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा।
- बजटीय परिव्यय: जल जीवन मिशन के लिए कुल बजटीय परिव्यय बढ़ाकर 67,000 करोड़ रुपये किया गया है।

एमएसएमई सेक्टर के लिए यह बजट क्रांतिकारी कदम लेकर आया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख की गई है, जिससे उद्यमियों को अपने कारोबार को बढ़ाने में आसानी होगी। साथ ही, महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए पहली बार उद्यमी बनने वालों के लिए टर्म लोन की सुविधा दी जाएगी।

खिलौना विनिर्माण, जब हम सिंधु घाटी सभ्यता और भारत की जितनी भी सनातनता है, उसको देखेंगे तो पाएंगे कि उसमें खिलौने का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। माननीय मोदी जी ने भारत में खिलौने के लिए टिकाऊ और वैश्विक केंद्र बनाने की योजना बनाई है। कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जो सूक्ष्म उद्योग के उद्यमों के लिए है, उसको 5 लाख रुपये की सीमा से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का काम किया गया है।

स्वास्थ्य - स्वास्थ्य सेवाओं में वर्ष 2025-26 में 10,000 अतिरिक्त मेडिकल सीट्स और 200 कैंसर केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। कैंसर जैसी गंभीर रोगों का इलाज कराने में काफी दिक्कत आती है।

शिक्षा - देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारी विकास हुआ। पिछले दस सालों में एमबीबीएस की सीट्स 50 हजार से अधिक बढ़ाई गईं तथा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार का अगले पांच वर्ष में 75 हजार मेडिकल सीट्स बढ़ाने का इरादा है। सरकार ने पिछले 10 सालों में आईआईटीज में भी 70 हजार नई सीटें जोड़ी हैं तथा आईआईटीज में 6500 नई सीटें जोड़ने की घोषणा भारत को टेक्नीकल फील्ड में बहुत बड़ा जम्प देगी।

निर्यात को बढ़ावा देना: भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 'भारत ट्रेड नेट' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की जाएगी। इससे भारतीय व्यापारियों को वैश्विक बाजारों में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी।

विमानन क्षेत्र और हवाईअड्डों के बारे में हम सभी जानते हैं कि भारत का विमानन क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विस्तार कर रहा है, और इस बजट में इस क्षेत्र के लिए किए गए प्रयास प्रशंसा के योग्य हैं।

सबसे पहले, हवाईअड्डों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा भारी निवेश की घोषणा की गई है। नए हवाईअड्डों का निर्माण और पुराने हवाईअड्डों के पुनर्निर्माण से न केवल यात्रा क्रो सुविधाजनक बनाया जाएगा, बल्कि इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और पर्यटन उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

हमारे छोटे शहरों और कस्बों में हवाई संपर्क को बढ़ाने के लिए सरकार ने "उड़ान योजना" को और सशक्त बनाने का निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत कम दूरी के मार्गों पर हवाई यात्रा को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे न केवल स्थानीय यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि यह नीति हमारे देश के दूरदराज इलाकों में भी हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे समान विकास होगा।

मैं, एक सांसद के रूप में, इस कदम को स्वागत योग्य मानता हूँ और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारतीय विमानन क्षेत्र के विकास में इतनी दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता दिखाई।

आखिर में, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस बजट के माध्यम से सरकार ने भारतीय जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। हम सब मिलकर, इस बजट की योजनाओं को साकार करेंगे और भारत को एक विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे।

धन्यवाद।

श्री अनन्त नायक (क्योँझर) : मैं केंद्रीय बजट पर अपने विचार रखता हूँ। यह बजट देश के आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के सशक्तिकरण, गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए किस प्रकार सहायक होगा, इस पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें बुनियादी ढांचे, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल इंडिया, उद्योग, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। मैं अपने राज्य - ओडिशा और मेरे कर्मक्षेत्र Kendujhar संसदीय क्षेत्र के विकास के कुछ संदर्भ बिंदुओं के साथ केंद्रीय बजट की दिशा और आयामों पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

हमारी सरकार के इस बजट में 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पहली बार उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, जिसमें term loan शामिल है। मुझे दृढ़ता से लगता है कि यह योजना शिक्षा, वित्त, infrastructure और बाजार नेटवर्क तक पहुंच जैसे मुद्दों को दूर करके ओडिशा में जनजातीय विकास को बढ़ाएगी। सही कौशल सेट, प्रशिक्षण और सहायता प्रणालियों के साथ, ओडिशा निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी के सक्षम नेतृत्व में अन्य राज्यों के साथ आगे बढ़ने में सक्षम होगा।

मैं Minor Minerals सहित बहुप्रतीक्षित Mining Reforms का प्रस्ताव करने के लिए हमारी सरकार की विशेष सराहना करता हूँ। हमारा खनन क्षेत्र उत्कृष्ट रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इसे अधिक पूर्वानुमानित, पारदर्शी और जवाबदेह नियामक वातावरण की आवश्यकता है जहां सभी हितधारकों को भूमि अधिग्रहण, वन अधिकार और स्थानीय सामुदायिक कल्याण से संबंधित दिशानिर्देशों का नियमबद्ध तरीके से पालन करना चाहिए। मैं ओडिशा के खनन क्षेत्र Kendujhar से आता हूँ। Kendujhar जैसे खनन क्षेत्रों के लिए एक बड़ी चिंता भूमि क्षरण और वनों की कटाई बनी हुई है। व्यापक पुनर्वास कार्यक्रम जिसमें भूमि सुधार और afforestation प्रयास शामिल हैं, कानून द्वारा अनिवार्य होना चाहिए। भविष्य कहने वाला रखरखाव (predictive maintenance) के लिए Artificial Intelligence (AI) और संसाधन निष्कर्षण (resources extraction) की निगरानी के लिए डेटा analytics एक और महत्वपूर्ण पहल है। मुझे यकीन है कि इससे एक ही समय में उत्पादकता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। हमारे राज्य ओडिशा ने हाल ही में आयोजित उत्कर्ष ओडिशा कार्यक्रम में बहुत सारे निवेशकों को आकर्षित किया है। JSW ने लगभग 35,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ Kendujhar जिले में 5 MTPA स्टील प्लांट स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की है।

हालाँकि यह राज्य और मेरे जिले के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, मैं यह आग्रह करना चाहूँगा कि Satellite Imagery और GIS Technology का उपयोग करके व्यापक खनिज संसाधन mapping से खनन गतिविधियों की बेहतर योजना बनाई जाए, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि Mines extraction अधिक कुशल और पर्यावरण के लिए लाभदायक है।

मैं गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले 10 व्यापक क्षेत्रों को कवर करने वाली स्थायी योजनाएं शुरू करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी और माननीय वित्त मंत्रीजी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। 100 जिलों में राज्यों के साथ साझेदारी में प्रधानमंत्री धन-धन्य कृषि योजना की घोषणा की गई है, जहाँ कृषि विकास से संबंधित मौजूदा योजनाओं और विशेष उपायों को एकत्रित किया जाएगा। सरकार की प्रतिबद्धता कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाकर फसल सघनता बढ़ाने, सामुदायिक स्तर पर फसल के बाद के भंडारण को बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने और किसानों के लिए आवश्यक कृषि आदानों के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की रही है। इस संदर्भ में, मुझे दृढ़ता से लगता है कि ओडिशा में कृषि क्षेत्र को इस बजट द्वारा अपनाए गए संतुलित दृष्टिकोण से बहुत लाभ मिलेगा जो सिंचाई, जलवायु लचीलापन, वित्तीय समावेशन, infrastructure और किसान कल्याण पर केंद्रित है। मुझे उम्मीद है कि उचित बजटीय प्रावधानों और प्रभावी नीति कार्यान्वयन के साथ, मेरा राज्य ओडिशा एक टिकाऊ और समृद्ध कृषि ecosystem बना सकता है।

बजट में युवाओं के कौशल विकास (Skill Development) और MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि बजट घोषणाएं विशेष प्रोत्साहन साबित होंगी और ओडिशा के आदिवासी जिलों में नई औद्योगिक इकाइयों और start up शुरू करने की सुविधा प्रदान करेंगी, ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।

मैं राज्यों के साथ साझेदारी में देश में पर्यटन के विकास के लिए उपायों की घोषणा करने के लिए हमारे सर्वोच्च नेतृत्व को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि देश में विकसित होने वाले शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों में ओडिशा राज्य और मेरे संसदीय क्षेत्र Kendujhar को अंतर्निहित और अपार पर्यटन संभावनाओं को देखते हुए प्राथमिकता स्थान मिलेगा। यह बजट अनेक सकारात्मक पहलुओं से युक्त है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अद्भुत नेतृत्व में, केंद्रीय बजट में ओडिशा राज्य में विभिन्न परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और मेरे संसदीय क्षेत्र Kendujhar में नई पहल शुरू करने के लिए पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा ताकि लाखों गरीबों, वंचितों और किसानों को अधिकतम लाभ हो, जो हमें विकसित राज्यों और जिलों के साथ एक विकसित भारत सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

धन्यवाद!

SHRI RAMESH AWASTHI (KANPUR):

- I would like to express my views on the budget. I would like to begin by congratulating Hon'ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman for giving us a forward-looking and holistic budget that will take our nation closer to the vision of 'Viksit Bharat. The budget stands as a testament to the

steadfast leadership of our Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji and the steadfast stewardship of the Finance Minister, who have collectively championed 'Aminil Kal?.

- Under Prime Minister Modi Ji's guidance, India has emerged as a front-runner in global policy discussions-be it in championing digital inclusion, bolstering climate action, or consolidating strategic partnerships that showcase India's growing influence on the world stage. His insistence on 'Reform, Perform, Transform has propelled our economy to unprecedented heights, laying strong foundations for innovation-driven growth, and equitable welfare It addresses the diverse aspirations of 1.4 billion Indians while staying rooted in the principles of social justice and equitable development. The budget further builds on the impressive government reforms that have stimulated infrastructural upgrades, elevated social welfare, and given fresh impetus to economic vibrancy across every sector and region of our country
- The words of Mahatma Gandhi. "If you educate a man, you educate an individual, but if you educate a woman, you educate a nation, resonate today more than ever The Modi Government has ushered in a women-led development era, ensuring that Nari Shakti stands empowered at every level of governance, economy, and society. We've come a long way since India's first gender budget in 2005-06 Garib Yuva, Annadata, and Nan-are the four groups that have been consistently highlighted as the government's priority Building on that sentiment, the FY 2025-26 budget witnessed a watershed moment with the gender budget at a record 24.5 lakh crores which is the highest since its inception. The allocation in the total budget has been increased to 8.88% in 2025-26, up from 6.8% in the previous budget 2024-25. This demonstrates the government's genuine resolve to ensure women progress hand-in-hand with the nation by supporting women's entrepreneurship, and rural livelihoods.
- This is not all, there are two groundbreaking initiatives highlighted by the Hon'ble Finance Minister in her budget speech a Scheme for first-time entrepreneurs offering loans of up to 22 crores that target five lakh women over the next five years, as well as a multisector rural prosperity and resilience program that prioritizes job creation for rural women in 100 agri-districts. We are investing in their futures, in their entrepreneurial spirit, and their economic independence And this is exactly what will make New India unstoppable.

- Furthermore, gender budget allocations for existing programs have increased across the board- including the National Rural Livelihoods Mission witnessed a 26% increase):Prime Minister Vishwakarma scheme supporting women craft persons has seen a 28% increase and the Seif Reliance India fund of support for women entrepreneurs witnessed a 22% increase. Additionally, the Ministry of Women and Child Development (WCD) budget has increased significantly to 26,889.69 crore, enabling robust investments in child nutrition under POSHAN 2.0 and improved Anganwadi services which has received Rs 21.960 crore to combat malnutrition and strengthen childcare. With these measures, the government underscores its relentless dedication to empowering women Through education, entrepreneurship, and social welfare, Nan Shakti stands at the helm of our nation's progress I ask this House-can any country truly develop without empowering its women? This Government has answered that question loud and clear-with action, not just words!
- The government has embarked on a transformative infrastructure journey to drive economic growth, enhance connectivity, and improve citizens' quality of life. This has led to advancements at an unprecedented pace across highways, railways, airports, and waterways, fostering inclusive and sustainable development India has achieved significant milestones in the form of the Atal Tunnel (the world's longest highway tunnel) and the Chenab Bridge (the world's highest railway bridge) Since 2014, the road transport and highway budget has surged by 500%, enabling record highway construction at 37 km/day in 2020-21 Rural connectivity has improved under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) And, let me remind you these are not just numbers on paper but these are monuments of progress and monuments that every Indian can take pride in!
- Indian Railways has seen unprecedented growth under the leadership of the Hon'ble Prime Minister as never before was such a large number of railway projects launched at one go. Today, a 4-km rail track per day is being built in the country in the last year alone, we built a 5,300 km rail network, which is equal to Switzerland's entire train network. In the past 10 years, a 31,000 km railway track was added 71 Vande Bharat, Amrit Bharat, and Namo Bharat trains now operate nationwide. Moreover, 44,000 km of railway networks were electrified in the past 10 years as compared to 20,000 km in the past 60 years This is not just it, the BJP-led union government has approved a budget allocation of Rs 2.52 lakh crore for the Railways in the 2025-26 financial year.

which will support the continued development and modernization of India's railway network. Moreover, allocating Re 118 lakh crore for safety-related activities shows government seriousness towards the safety of the citizens who travel continuously in trains. This is not just about trains, this is about national pride. can we deny that PM Modi Ji has completely transformed Indian Railways?

- We all know that air travel was once considered a luxury for the elite. But today, thanks to Modi Ji's vision, it has become a reality for the common man Air travel has expanded with 102 new airports, reaching smaller towns and remote areas. The revamped UDAN scheme aims to add 120 new destinations under the FY 2025-26 budget. further democratizing air travel. The number of air passengers annually has surpassed 350 million, positioning India as the third-largest aviation market globally Over the past ten years, domestic air passenger traffic has been growing at an annual rate of 10-12%. and the number of airports has more than doubled to 159. As the government commits to developing 50 more airports in the next 5 years, I am excited to share that the new terminal in Kanpur airport is operational, laced with modern facilities and enhanced capacity. The new terminal in Kanpur which was once hailed as the "Manchester of the East, speaks directly to PM Modiji's promise of revitalizing legacy industrial hubs. boosting trade and tourism, and placing tier-2 cities firmly on the global map.
- It gives me immense pride to mention that I had met the Hon'ble Minister of Civil Aviation Shri Ram Mohan Naidu Ji and had expressed my requests for the introduction of new flights from Kanpur, emphasizing the city's industrial and commercial significance. I have specifically requested direct flights from Kanpur to Amritsar and Kolkata, Ahmedabad along with an additional morning flight to Delhi to meet the growing travel demand. I must emphasize that the current flight options are insufficient to accommodate passengers' needs, causing inconvenience to traders, entrepreneurs, and general travelers. An additional morning flight would enable passengers to reach their destinations on time and conduct their business efficiently I am very grateful to the Minister Sir for acknowledging my request and for his assurance regarding prompt action to address the issue, which would bring significant relief to Kanpur's citizens and business community" The new announcement regarding expanding the UDAN scheme will help my constituency Kanpur as well.
- Regarded by Prime Minister Modi as the "spine" of the Indian economy, MSMEs have consistently found a place of prominence in every policy discourse Calling this one of the four "powerful engines

driving the economy, Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman announced a series of measures in the Union Budget 2025 aimed at strengthening India's Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME). The government has introduced several reforms to boost the sector, notably, enhancing the credit guarantee scheme, and introducing customized credit cards with a Rs 5 lakh limit for micro-enterprises registered on the Udyam portal. Alternate Investment Funds (AIFs) for startups have received commitments of more than ₹91,000 crore, a dedicated scheme for first-time women entrepreneurs as well as those from Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST) will offer term loans up to 2 crore over the next five years. I am particularly excited about the government's step to enhance productivity in the footwear and leather industries. My constituency Kanpur, which is known for its leather goods, will certainly benefit from the scheme that provides support in design capacity, component manufacturing, and machinery required for the production of leather footwear and products. The Government's targeted support for leather and footwear industries will revive the declining leather industry in Kanpur and provide employment opportunities to millions.

- The youth of India are the cornerstone of Prime Minister Modi's vision for Amrit Kaal-where India emerges as a global innovator, manufacturer, and economic leader. India is now the world's third-largest startup ecosystem, with over 15 lakh registered startups flourishing across sectors." Recognising the immense potential of youth of Bharat, this government has undertaken historic reforms and initiatives to empower young minds, foster entrepreneurship, and ensure that the youth are not just job seekers, but job creators. Startup India Seed Fund Scheme, since 2021 has benefited a total of 2,622 startups from 467.75 crore in funding. Initiatives like National Centres of Excellence for Skilling and a dedicated 20,000 crore outlay for private-sector-driven R&D manifest the Prime Minister's belief that today's youth will champion future technologies, industries, and innovations. Steps such as these will put the youth of India on the world map and advance India towards the path of Vikat Bharat. Our Prime Minister has given them the tools, the platforms, and the ecosystem to take India to new heights. And this budget is proof of that commitment.
- This Union Budget 2025-26 embodies the essence of Prime Minister Modi's leadership-bold, inclusive, and transformative. From empowering Mani Shakti and turbocharging infrastructure development to nurturing MSMEs and catalyzing youth-led innovations, every measure is a huge leap towards a Viksit Bharat by the time we commemorate a century of independence. Under PM

Modi's enduring leadership, we are ready to seize the immense possibilities of Amrit Kaal-an era defined by a globally resonant Indian voice, technological prowess, and the ability to craft our own destiny. Each initiative in this Budget is anchored in the belief that a prosperous India is one where every woman, every village, every entrepreneur, and every youth can confidently say, "We are part of India's growth story."

- Together, we will write a remarkable chapter in India's story, a chapter that the world will read in admiration as we march toward a Viksit Bharat in 2047.

SHRI PUSHPENDRA SAROJ (KAUSHAMBI): I would like to express my views on Union Budget of 2025-26 tabled on the 1st of February 2025. Continuing from the previous year's budget, the government has declared that it will continue to focus on Garib, Youth, Annadata, and Naari.

Article 38 of the Indian Constitution envisions India as a welfare state. It goes as follows: "The State shall strive to ***promote the welfare of the people*** by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life". Therefore, the Union Budget is not merely an accounting exercise; it reflects the government's priorities and commitment to the constitutional ideals of a welfare state. The government is responsible for ensuring that economic policies, including the Union Budget, are designed to reduce inequalities, provide equal opportunities, and uplift the most vulnerable sections of society. The budget is the lifeline of key welfare schemes that democratize access to education, health, water and sanitation, provide social security measures and secure the welfare of tribes, minorities and the poor.

The Union Budget 2025-26, however, seems to prioritise short-term gains over long-term development, leaving behind the very people who need the state's support the most- the farmers struggling with rising input costs, the youth facing unemployment, the women battling systemic barriers, and the poor grappling with inflation.

Unfortunately, the four categories of Garib, Youth, Annadata and Naari have been conveniently kept aside, and the focus of this budget has been completely around the proposed income tax relief. The government has heavily relied on the proposed benefits from changes in the tax system for the 'middle class' and 'salaried' employees, with the FM declaring that "*1 crore more people will pay no tax*",

distracting the public from the fact that this budget has ignored the longstanding demands of the poor and the farmers.

The government proudly raises the income tax exemption to ₹12 lakh, but how many Indians even earn that much to benefit? The long-term sustainability of tax cuts is questionable, especially since this revenue is critical for driving inclusive growth through public investments in infrastructure and social welfare. GST as a sustainable source of revenue is a misguided approach, especially since GST hurts the pockets of the poor more than it does the rich.

Unemployment has reached record highs, jobs are disappearing, and wages are not keeping up with rising prices. The commoner is being crushed under soaring indirect taxes, skyrocketing vegetable prices, and a weakening rupee that makes daily life more expensive. Every year, diesel and petrol prices keep rising, pushing transport costs and making even necessities unaffordable.

The real question is- what is this government doing for those who can't even earn enough to avail these exemptions? How will families survive when their earnings stay the same, but their expenses spiral out of control? The government can celebrate its budget, but for the average Indian struggling with rising costs, there is no relief in sight.

The government keeps discussing education reform, but where's the budget allocation to back up its lofty claims? Education spending is stuck at a dismal 2.7% of GDP, nowhere close to the 6% recommended by the Kothari Commission in 1966. The truth is simple- big speeches, small budgets. They want to build a knowledge economy while refusing to invest in students, teachers, and the future of this country.

The new proposals of this budget in the education sector have catered more towards higher education, with the Department of Higher Education receiving 7.7% more allocations than last year's revised estimates. The funding to the University Grants Commission has seen a slight increase from last year's Revised Estimates of about 10%, which is still low compared to the vast 61% budget cut it underwent in 2024-25. The allocations also largely lean toward specialised education, such as the 500-crore allocated for the Centre of Excellence in AI for Education.

During the last budget, I raised a concern that in constituencies like Kaushambi, women are lagging behind in access to higher education- especially because of the lack of women's colleges and hostels. I had demanded that specific schemes be introduced to improve women's access to higher education. I note that the PM USHA scheme, which provides strategic funding to state higher and technical institutions, has merely increased from 1814.95 in 2024-25 to 1815 crores in 2025-26. Of this, only 635 crores have been allocated towards women-specific schemes according to the gender budget, which is unchanged from the 2024- 25 budget. This allocation is insufficient and cannot bring a real change or provisions increasing access to higher education for women across the country.

While I appreciate the setting up of broadband connection in all government secondary schools and provisions for 50,000 more Atal Tinkering Labs, the truth remains that the needs of government school students are still for **basic facilities**. According to the UDISE+ report of 2023-24, over half of India's schools still do not have functional computer facilities. Only 43.5% of Indian Government schools have functional computer facilities compared to 70.9% of private unaided schools. In my state of Uttar Pradesh, only a meagre 22% of government schools have functional computer facilities, while 49.9% of private unaided schools have such facilities (UDISE+ 2023-24 report).

But all is not dull with government schools. The 2024 ASER Report shows that government schools have shown that learning levels in government schools are improving significantly compared to private schools. To boost this growth, appropriate funds must be allocated to the education sector. In the 2025-26 budget, only 2.5% of the entire budget has been allocated to education. We must focus on improving infrastructure, strengthening teacher training and closing the gaps between students in government and private schools.

The government has allocated INR 95,957.87 crore to the Department of Health and Family Welfare. This is a 9.46 per cent increase from last year's budget estimate, yet the allocation of healthcare has remained below 2% of the total budget. Article 47 provides that improving public health and nutrition is among the primary duties of the State. The 2025-26 budget reflects on this duty poorly, as the focus seems to have been primarily on increasing medical college seats, cancer day care centres and reducing customs duty exemptions for medicines. While these efforts are commendable, there is no answer on how structural inefficiencies will be addressed.

Affordable and accessible healthcare remains a dream for Indians, especially in rural India, who walk into government hospitals only to be met with insufficient beds or a lack of doctors- especially speciality care like gynaecologists. The Health Dynamics of India 2022- 23 report revealed that only 4,413 specialist doctors of the requisite 21,964 needed in Community Health Centres (CHCs) in March 2023 were available- a shortfall of 17,551 or 79.9 per cent. These structural inefficiencies point to the fact that healthcare systems require a major revamp from the bottom up to ensure that grassroots health services are stronger, well-staffed and well-funded and the reliance on major hospitals is restricted to only major healthcare concerns.

We know that many families are forced to resort to private medical facilities where the costs of healthcare services are skyrocketing by the day. While an increase of 75,000 medical seats in the country in the next 5 years has been, we have no answer to the crucial question of how these doctors will trickle down to the most rural parts of India. The government has also not been able to solve the issue of backbreaking fees of medical colleges; private medical colleges still continue to charge exorbitant fees- and all the while quality of medical education continues to decline.

Women or Nari Shakti is a key category mentioned as a target group for development, but this budget merely offers 'symbolic' support for India's women. While the budget introduces schemes for rural women and support for first-time entrepreneurs, the overall financial commitment remains unimpressive.

While the allocation to the Ministry of Women and Child Development has increased by 15% to 26,889 crores from last year's revised budget, this is primarily due to the increased funds allocated to Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0, which amounts to 21,960 crores, which is 81% of all the funds allocated to the Ministry.

Allocation to SAMBAL, which includes initiatives to improve women's safety and protection, remained unchanged at 629 **crores** from the 2024-25 budget estimates. The SAMARTHYA scheme also only saw a minimal increase of 4 crore from the 2024-25 budget estimates. The fact that these schemes have been neglected proves that support for women from this government is purely symbolic. The PM's statement that this budget focuses on making people partners in development are just hollow words because half of the Indian population, who consist of women, is once again reduced to a mere statement in budget speeches.

At first glance, the gender budget for 2025-26 might seem to indicate that women's schemes have received a huge boost in this budget. The share of gender budget allocation in the total Union Budget has increased from 6.8% in 2024-25 to 8.9% in 2025-26. A key reason for this increase has been the addition of 107638.78 crores from Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY) in Part B of the Gender Budget, which deals with schemes providing between 30% to 99% allocations for women. PMGKAY was not previously a part of the gender budget. On the other hand, a key scheme of the Jal Jeevan Mission has seen a 40% cut in allocation. Allocation in Part A of the GB, which deals with programmes with 100% provision to women, saw a decrease of 6%. Schemes like the National Widow pension scheme, which falls under Part A, saw no increase. Therefore, it is questionable whether the increase in the gender budget truly signals a policy shift in empowering women or is just a play with numbers.

While schemes expanding credit are a step in the right direction, systemic barriers in the newly announced and current schemes and on matters like labour force participation, workplace inclusivity, and safety must be addressed. India's position in the Global Gender Gap Index of 129th out of 146 countries indicates that empowering women economically calls for more than just financial assistance but sufficient, timely and targeted financial assistance and real efforts in their empowerment.

Despite repeated claims of inclusive development, the Union Budget 2025-26 has once again failed to acknowledge the needs of minority communities. In both the Hon'ble President's address and the Finance Minister's speech, the word 'minority' was not mentioned even once, reflecting a larger pattern of their erasure in policy discourse. This silence is not just rhetorical- it is mirrored in budgetary allocations, where schemes meant to uplift historically marginalised groups have either been slashed drastically or rendered purely symbolic with token allocations. The government's approach signals a clear deprioritisation of minority welfare, particularly in the realm of education, where financial support serves as a crucial lifeline for many students.

The allocation for the Ministry of Minority Affairs only saw a nominal increase of 5% when compared to the Budget Estimates of 2024-25. There is a hike of around 1000 crore in grants-in-aid to States, which was increased from ₹527.12 crore in 2024-25 to ₹1,518.31 crore in 2025-26.

Unfortunately, the budget allocation to education schemes for minorities has taken a huge hit. From 1575 crores allocated overall to education empowerment schemes in 2024-25 budget estimates, there

has been a sharp cut to 678 crores in 2025-26, almost a 57% decrease. This head contains several schemes such as the pre-matric scholarship for minorities, the post-matric scholarship for minorities. Merit-cum-Means Scholarship for professional and technical courses and the Maulana Azad National Fellowship for Minority Students. The 'Education scheme for madrasas and minorities' was also slashed to just ₹0.01 crore in 2025-26 from ₹2 crore in 2024-25.

Similarly, cuts have been made under the Ministry of Tribal Affairs education sub-schemes under the National Tribal Welfare Program. Schemes such as the National Fellowship and Scholarship for Higher Education of ST students and the National Overseas Scholarship Scheme saw huge cuts. The National Fellowship and Scholarship for higher education of scheduled tribe (ST) students has seen a 99.99% reduction, with its allocation dropping from ₹240 crore in the revised estimates (RE) for 2024 to just ₹0.02 crore in the budget estimates (BE) for 2025. The National Overseas Scholarship Scheme has also been cut by 99.8%, falling from ₹6 crore in RE 2024 to ₹0.01 crore in BE 2025.

Article 39 of the Constitution stresses the state's responsibility to promote the educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections. Public spending through the budget is a key way of promoting these interests- and the government seems to have abdicated all such responsibilities.

India's decadal census, which was to be conducted in 2021, seems to be yet again delayed. Only a sum of 574 crores has been allocated under the head of Census, Survey and Registrar General India, which implies that the delayed census in the country may not be carried out in 2025 either. In 2019, the cost that the Cabinet approved for the census was Rs. 8,754.23 crore. The updation of National Population Register (NPR) was pegged at a cost of Rs. 3,941.35 crore.

It is a shame that key policy decisions are still being implemented based on data that is over 14 years old, which is not reliable anymore and does not reflect the country's current socio-economic realities. To implement key policy decisions of this government the Women's Reservation Act, we need the census to be conducted, and then the delimitation exercise must be completed- undue delays will hamper the "good intentions" behind such a law.

Social justice is also being denied to Indians due to the delays in conducting the census. To guarantee equitable distribution of resources and opportunities, India's reservation laws for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes which are based on demographic statistics that must be updated on a regular basis. This would allow social welfare programs and affirmative action measures to be implemented more successfully. A comprehensive, national Socio-economic Caste Census must also be conducted as soon as possible to determine the demographic data of India's most vulnerable populations. This will also help counteract the systematic marginalisation of these communities.

This Budget is another betrayal of India's farmers and exposes the government's lies. In 2016, the BJP had loudly promised to double farmers' incomes by 2022- it is now 2025, and that promise has been completely abandoned. The demand to remove GST on agricultural inputs such as seeds, manure and pesticides, which could have given farmers immediate relief, has been outrightly ignored. Instead, the focus has been on short-term credits to farmers without focusing on addressing systemic issues like access to agricultural markets or price volatility.

The government has once again refused to implement the National Commission on Farmers' recommendation to ensure MSP at 50% above the comprehensive cost of production. This is not just failure it is deliberate deception. In my parliamentary constituency of Kaushambi in Uttar Pradesh, our farmers are not even being informed of the Fair and Remunerative Price (FRP) for the upcoming season: mill owners have withheld their payments, and the farmers suffer from fertiliser shortages every single year.

This government has fed farmers empty promises for eleven years while crushing them under rising input costs and falling incomes. This Budget once again proves that this government stands with corporate profiteers and not the farmers. The Makhana Board and its allocation of 100 crores also prove that feeding the greed of this government's political allies happy is more important than addressing the woes of the millions of farmers that feed the entire nation.

It is disappointing to note that there has been no increase in allocation to the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS). The allocation has been stagnant, with 86,000 crore rupees being allocated in this year's and last year's budgets. The government claims that

the scheme is a "demand-driven" employment Scheme and that funds being released to States/UTs is a continuous process. The Ministry seeks additional funds from the Ministry of Finance as and when required to meet the demand for work on the ground. Given this, it is surprising that the Budget Estimates and Revised Estimates for 2024-25 and the Budget Estimates for 2025-26 have remained unchanged at 86,000 crores.

The aspirations of rural Indians do not seem to be a priority for this government. Workers are already facing a delay in wages, and a consortium of non-profit organisations, NREGA Sangharsh Morcha, has also found that the average workdays per household under the scheme came down to just 44.62 days in 2024-25 from 52.08 days in 2023-24. The promised 100 days of work seems to be a distant dream, and the rural worker continues to receive no support for their aspirations.

Last year, North India faced one of the worst heatwaves in 15 years, with temperatures crossing 50°C in Prayagraj and power demand hitting a record 89 GW daily. Despite claims of preparedness, blackouts disrupted daily life, power shortages hit industries, and even Delhi airport faced an outage. Now, with summer coming again and heatwaves will return and it is questionable whether the government has done anything to prevent another crisis. On paper, installed capacity looks sufficient, but the reality is different- power shortages persist due to grid failures, transmission bottlenecks, and inefficient distribution. Uttar Pradesh, the most populous state, will be among the worst affected, yet there is no clear roadmap in the budget to ensure stable electricity supply during peak demand.

Instead of waiting for another crisis to strike, the focus should be strengthening grid infrastructure, improving transmission efficiency, and ensuring last-mile power delivery. The 2025-26 budget has completely focused on its long-term goals for Viksit Bharat, with a target of 100 GW nuclear power capacity by 2047. It has completely ignored the short- term energy needs of a growing population.

The government talks big about infrastructure, but when it comes to the railways the backbone of India's transport and economy- there is no increase in capital outlay, leaving it stuck at ₹2.52 lakh crore. With rising costs and inflation, this is effectively a cut. stalling much-needed modernisation and expansion. They showcase Vande Bharat trains as a symbol of progress, yet bullet train projects remain stalled, freight corridors are delayed, and safety concerns persist. Meanwhile, the government boasts about 2,364 Kisan Rail trains since 2020, but in Uttar Pradesh- India's largest agrarian state- there are

just 76 trains. That's the reality behind their big promises- hollow schemes with no real intent to help farmers. Farmers, daily passengers, and businesses all rely on railways, yet fares rise while services stagnate.

The neglect of railways in this budget is yet another example of the government's priorities-headline-grabbing announcements over real investment, PR over progress, and speeches over substance. For several years, my constituents' demand to run trains to MUMBAI AND DELHI has been ignored. Our demands for more intercity trains have also been on deaf ears, and this government once again only seems to prioritise trains that are beyond the means of ordinary citizens in my constituency.

The government has **completely prioritised 'profitability'** when it comes to developing the railways, building new routes, and making travel safe. On the one hand, they dole out political freebies without batting an eye, and on the other, they focus on profitability and remunerativeness, instead of making travel more affordable and accessible for the ordinary citizen.

The Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) allows MPs to **directly address local issues** without waiting for state or central government intervention. By allocating funds for crucial projects, MPLADS empowers MPs to respond to their constituents' immediate needs. However, the current funding limit of 25 crore per year is inadequate, particularly for MPs representing **densely populated constituencies**.

Many constituencies, especially in urban and semi-urban areas, have millions of residents. With rising construction and infrastructure costs, **₹5 crore is spread too thin** to create a meaningful impact. MPs in larger constituencies struggle to equitably distribute resources, leading to many pressing issues being ignored. Increasing the allocation would enable MPs to fund larger projects, improve public services, and ensure more balanced development, making MPLADS a more effective tool for grassroots governance. Furthermore, several states MLA Local Area Development Funds (MLA LAD) provide higher support to MLAs. **In Delhi, for instance, the fund was increased to 15 crore per MLA last year.**

The Union Budget 2025-26 was an opportunity to address the pressing concerns of India's citizens rising unemployment, soaring inflation, crumbling public services, and deepening rural distress. Yet, instead of offering real solutions, the government has focused on optics and half-measures. While tax

relief for the middle class is welcome, it does nothing for the millions who earn too little to benefit from exemptions. Education remains underfunded, rural employment stagnates, and farmers continue to struggle without meaningful support. The delays in conducting the Census and Caste Census further expose the government's disregard for data-driven policymaking and social justice.

India needs a budget that prioritises its people, not just its economic headlines. A budget that invests in human capital strengthens social security and ensures dignity and stability for all. But what we have instead is another missed opportunity- one that fails the poor, the youth, the farmers, and the women of this country.

India's identity as a welfare state is drawn from the Constitution, and it is the government's responsibility to bring these ideals to life through the budget and well-targeted welfare measures.

SHRI VISHWESHWAR HEGDE KAGERI (UTTARA KANNADA): I would like to express my views on this memorable Budget presented by Hon'ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitaraman, under the guide line of our great loving leader and Prime Minister Sh. Narendra Modi ji.

As we unveil a transformative vision for our nation's future through the Union Budget 2025. This budget isn't merely a financial document ? it is our blueprint for an India that leads the world in innovation, sustainability, and inclusive growth.

Our journey towards becoming a global powerhouse begins with six pivotal sectors that will reshape our economy over the next half-decade. We are revolutionizing power generation with an ambitious nuclear energy mission that will harnesses 100 GW of clean, reliable energy through indigenous small modular reactors. This bold step positions India at the forefront of nuclear technology while securing our energy independence.

For our farmers, the backbone of our nation, we're launching the comprehensive Dhan Dhanya Krishi Yojana By raising Kisan Credit Card limits to 5 lakh rupees and implementing a focused six-year mission for pulses we're empowering our agricultural sector to achieve new heights of productivity and prosperity.

The heart of our economic engine ? our 5 7 crore MSMEs - will receive unprecedented support. We're not just providing enhanced credit guarantees up to 5 crores; we're creating an ecosystem where

entrepreneurship can flourish. Our vision of making India a global toy manufacturing hub and revolutionizing the footwear and leather sector will generate employment for 22 lakh people and attract investments worth 4 lakh crores

Education and healthcare, the cornerstones of human development, are op receiving transformative attention. We're bringing broadband connectivity to every secondary school, democratizing knowledge through digital Indian language books, and expanding our medical education capacity by 10,000 seats. Our 500-crore investment in AI for education places India at A the cutting edge of learning technology.

Infrastructure development remains paramount. Through innovative PPP models and a 1.5 lakh crore interest-free loan scheme we're building the foundation for sustainable urban growth. The Urban Challenge Fund of 1 lakh crores will transform our cities into models of efficiency and lability.

Our commitment to connectivity reaches new heights with the UDAN regional connectivity scheme, which will connect 120 new destinations and serve 4 crore additional passengers in the next decade. The maritime sector will receive a boost through a dedicated 20,000 crore development fund, strengthening India?s position in global trade.

Perhaps most importantly, we're ensuring that no one is left behind in this journey of progress. From comprehensive support for gig workers to the extension of the Jal Jeevan Mission until 2028, we're creating a society where prosperity touches every citizen.

This budget represents more than financial allocations ? it embodies our unwavering commitment to building a stronger, more prosperous, and more equitable India. The decisions we make today will echo through generations, creating opportunities, fostering innovation, and establishing India's leadership in the global community.

Let us move forward with conviction and purpose, knowing that together, we are laying the foundation for an India that will not just participate in shaping the future, but lead it.

***m68 ADV. ADOOR PRAKASH (ATTINGAL):** I would like to place my views on the Union Budget 2025-26.

The Government claims the budget to be in cognition of the Garib, Youth, Annadata and Naari, and yet the Budget satisfies neither of the above. It is fortunate howsoever to see the Government accept that plans need to be created for the impoverished citizens as this Government has done an astounding job of doing absolutely nothing while the nation with its shameful 130s rank in Human Development Index and serious categorization in World Hunger Index faces exponential growth of an unemployed, uneducated, hungry populous.

Traditionally, the Budget day is seen by major ripples in the stocks and exchanges market of the nation, and yet the stagnation of the otherwise booming Sensex, banking and rail stocks shows how much inconsequentiality can be reflected in the budget. This budget is an effective reflection of what the Government finds as the most pressing issue in the nation today - sustaining their power on all levels, at the cost of the people. The foremost fiscal tool for ensuring economic growth for the people of the nations has now become a mere political tool addressing BJP's political alliances in check. The budget presents a mere bandage to the wounds of ignorance this very administration has engaged upon our people alongside presenting a lion share of the pie to Bihar which has now become an epicenter of political power.

The rebates on Income Tax for salaried individuals upto Rs. 12 lakh is a welcome initiative while what the Government forgets is income needs to be created for Income Tax. Projects of skill building like Krishi Vikas Kendras are running on an almost Rs. 150 crore lesser budget than 2 years ago. The glorified UDAN-RCS Scheme is said to be expanded in the next 10 years but without addressing any serious concerns of developing the quality of services and infrastructure of the nations. Airports, well visible as of the allotted Rs. 540 crore, which is already a historic low, not a single rupee goes to capital expenditure. The Government presents a terribly half cooked budget of political solutions while it never wishes to address the innate issues of our nation - a testament to which is the reduction of almost Rs. 3000 crore from the previous budget for the Ministry of Consumer Affairs, a Government unable to feed the people of our nation has no right to claim of any success as a democracy.

The India Post received more than Rs. 27000 crore in support through schemes from the Government while the unaddressed fact of it running on an already deficit remains unaddressed and uncared. Shall the dear money of the taxpayers be flushed out on projects that bring no returns? The

plans for India Post to reinvent itself is one of great concerns for the nation but definitely not for this Government.

It is the responsibility of this Government to do better, faster if the nation is to see the economic progress it deserves and not gimmicks of political smog. This budget totally neglects the demands of the State of Kerala.

The landslide that occurred in the Wayanad district of Kerala and claimed the lives of more than 400 people, is one of the biggest natural disasters the country has ever witnessed. It was expected that the Centre would announce a special package for Wayanad following Prime Minister's assurance after his visit to the district. But six months after the landslide, the affected people of Wayanad are still awaiting rightful compensation. There is no justification for not providing Central assistance for relief and rehabilitation of the affected in such a severe calamity.

People of Kerala are facing the issue of escalating human-wildlife conflict. People living in forest fringe areas are concerned about increasing incidents of wild animal attack and loss of lives and their crop properties. Human casualties are being reported every day in Kerala and people are agitated for the delay in implementation of safety measures. The State has submitted a proposal for Central financial assistance, but it is not yet considered.

The traditional fishing sector in the State is facing a crisis, unlike ever before. The traditional fishermen are struggling to survive due to job loss and no other source of income. The coastal areas in the country are the most vulnerable to the adverse effects of climate change. The demand for implementation of schemes for ensuring minimum employment in a year for traditional fishermen has not been considered yet by the Government.

The long pending demand for establishing AIIMS in the State, completion of Sabri Railway line are still remaining as a dream. The works of Railway Over Bridges which were sanctioned long back including many ROB's in my constituency Attingal have not been started yet. The State desperately needs more allocation for the completion of pending Railway projects.

Thank you.

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Initially, this budget felt like a tale of promises and optimism, but upon closer examination, it reveals a stark reality for key sectors and vulnerable communities. While the Government has called it a 'visionary roadmap for India's future,' a deeper look suggests it is nothing more than an 'exercise in optics rather than substance.' The Government claims 'fiscal prudence and inclusive growth,' yet allocations for crucial sectors like healthcare, education, and rural development remain inadequate and insufficient to meet the real challenges on the ground.

This budget is nothing but a well-marketed illusion, offering no real solutions to the economic hardships faced by millions.

The budget speaks of 'empowering farmers,' yet tribal cotton farmers in Rayagada are struggling to survive. Unseasonal rains have devastated their crops, input costs have skyrocketed, and the Cotton Corporation of India (CCI) has refused procurement citing quality issues. As a result, these farmers are forced to sell their produce at distress prices to brokers from Andhra Pradesh, falling deeper into debt and despair. What relief does this budget offer them? Where are the structural reforms needed to ensure fair pricing, proper procurement mechanisms, and access to irrigation and much demanded legal guarantee of MSP as per Swaminathan recommendation?

The much-hyped 'growth-oriented approach' in this budget seems to favour corporate tax incentives while leaving informal workers, MSMEs, and marginalized communities to fend for themselves. This budget was expected to tackle inflation, unemployment, and agrarian distress, but the measures announced appear to be 'too little, too late.' It claims to be 'pro-people,' but in reality, the benefits are skewed toward large industries rather than grassroots development. The need of the hour was 'structural reforms with tangible support for small businesses, MSMEs, and farmers,' but what we received instead is a 'well-packaged but underwhelming financial plan.' The Government says it is 'building a stronger India,' but for millions facing economic hardship, this budget offers little more than 'recycled announcements and unfulfilled assurances.'

While the budget boasts about new railway projects, there is nothing exclusive or region-specific for Odisha. Despite Odisha's massive contribution to railway revenues, the State has been denied its fair share of infrastructure development, further pushing it to the margins. Odisha has the potential to be an industrial and transport hub, but instead of strengthening it, the Government chooses to overlook it. A

national budget should not be dictated by electoral politics. The Government cannot prioritize States based on upcoming elections while ignoring those that genuinely need development. Odisha deserves its rightful share of progress, disaster relief, and infrastructure investments. The Central Government must reassess its priorities and ensure that resources are distributed fairly, not just to States that serve its political interests.

The East Coast Railway (ECoR) issue is another glaring example of this neglect. Odisha, which generates one of the highest freight revenues for Indian Railways, continues to be denied adequate infrastructure development. While other States receive new railway divisions and expanded connectivity, Odisha is ignored despite repeated demands. The jurisdiction of ECoR must be expanded to include key revenue-generating railway sections, yet the budget makes no mention of this critical issue. Instead of strengthening railway connectivity in mineral-rich and tribal-dominated areas like Koraput and Rayagada, the Government has chosen to sideline Odisha yet again. How long will we have to fight for what is rightfully ours?

While the tax exemption up to Rs.12 lakh is being hailed as a major relief, one must ask ? how many people in India actually earn Rs.12 lakh a year? According to Government data, India's per capita income stands at just around Rs.2 lakh per year. This means the vast majority of Indians don't even come close to benefiting from this so-called relief. It's like announcing a luxury tax cut in a country where most people struggle to afford a basic meal.

The old adage ?Na nau man tel hoga, na Radha nachegi? fits this budget perfectly ? neither will there be jobs, nor will salaries increase, nor will people even have to pay taxes, because most of them don't earn enough to qualify for taxation in the first place! This budget completely ignores unemployment and inflation.

The average middle-class Indian is not worried about tax exemptions on Rs.12 lakh income ? they are worried about sky-high rent, spiralling education costs, and stagnant wages. A person living in an urban city now spends 30 to 40 per cent of their income on rent, and in metros, this figure is even higher. Meanwhile, school and college fees have reached astronomical levels, making quality education a privilege rather than a right.

Instead of addressing these pressing issues, the Government has failed to introduce any concrete measures to raise the income of the masses. Where are the policies to increase per capita income? Where is the plan to create well-paying jobs, boost small businesses, and ensure financial security for ordinary citizens?

At the end of the day, a tax cut is only beneficial if people have taxable income to begin with. But with rising unemployment and stagnant wages, this budget is offering a discount to a store where most people can't even afford to shop.

This Government is selling false dreams while the youth of this country are forced to protest against paper leaks, recruitment scams, and job shortages. Students who have spent years preparing for competitive exams find their futures shattered by corrupt and inefficient examination processes. The Government boasts about economic growth, yet fails to even acknowledge the lakhs of unemployed youth and the chaos in public sector recruitments. Does this budget have anything for BPSC students protesting against injustice? Did the Government allocate resources to ensure fair and transparent hiring? The silence speaks volumes.

There is something more than just the Budget ? it is BJP's preparation for the Bihar elections wrapped under the guise of economic planning. The much-anticipated Union Budget has once again failed Odisha, leaving the State neglected while Bihar enjoys special attention, driven purely by political compulsions. This budget is nothing more than a long-term vision document, filled with grand promises but lacking real solutions. It does nothing to address the immediate economic distress faced by millions, especially the youth trapped in generational unemployment.

There is no clear roadmap for job creation, no relief from rising inflation, and no effort to control the soaring prices of essential commodities. Instead of offering direct interventions to tackle unemployment, wage stagnation, and economic disparity, this budget focuses on political calculations rather than economic realities. The Government talks about growth, but where is the income growth for common citizens?

This Budget is not about national development ? it is about electoral arithmetic. It prioritizes vote-bank politics over genuine economic planning, and unfortunately, Odisha once again finds itself on the

losing side of this political game.

Odisha has been facing several pressing issues, including the Polavaram dispute, the Mahanadi water-sharing issue, the Kotia border dispute, and distress migration. However, the budget makes no mention of any targeted intervention to address these long-standing problems. Additionally, the Public Distribution System (PDS) crisis, particularly the issue of rice allocation for Odisha, remains unaddressed, despite repeated appeals by the State.

I want to ask the hon. Finance Minister ? how does this budget address the struggles of the women of Kandhamal? How does it ease the pain of a mother forced to sell her child, knowing she cannot afford to feed her? How does it provide hope to millions of tribals whose land and livelihoods are under constant threat, who are being uprooted in the name of development?

I want the hon. Minister to answer ? how does she plan to increase the purchasing power of the marginalized? What concrete steps is she taking to ensure that social welfare schemes like MGNREGS actually serve the poor, instead of being underfunded and throttled? Why has the budget for MGNREGS not been increased when the demand for rural employment is higher than ever?

This budget speaks of growth and progress, but for whom? Where is the relief for those struggling to secure a meal, a job, or a dignified existence? The Government cannot talk about a Viksit Bharat while leaving behind those who built this nation with their blood, sweat, and labour. I demand answers ? not rhetoric, not vague assurances, but real solutions for the people who need them the most.

Odisha sent 20 BJP MPs to Parliament, a clear sign of the people's trust and strong electoral support for the ruling party. Now, I ask these MPs ? will you stand up for the people who elected you, or will you remain silent while Odisha continues to be sidelined? I want each one of you to speak for the people who placed their faith in you and demand SPECIAL STATUS for Odisha. Let's stand together, let's demand it in one voice.

Your accountability is to the people of Odisha, not to any party. If you fail to raise your voice, Odisha will continue to receive step-motherly treatment, and the people will never forget this betrayal. We have already seen important infrastructure projects, industrial investments, and special financial packages being diverted elsewhere, leaving Odisha neglected and underdeveloped.

For years, Odisha has consistently demanded Special Category Status, knowing that our State faces recurring cyclones, natural disasters, and economic hardships. Yet, this demand has been ignored again. Instead, we see a deliberate political strategy ? the focus of industrial and infrastructural development is being shifted from Odisha to Bihar, not based on need but on electoral calculations.

Enough is enough. Odisha deserves better. Odisha demands better. The question is ? will you fight for your State, or will you bow down to political convenience?

This budget completely turns a blind eye to the struggles of tribals in Koraput and Rayagada. These districts lack even the most basic necessity ? clean drinking water. The much-advertised Har Ghar Nal Yojana has failed miserably. Families are still forced to walk miles just to fetch potable water, while the Government remains silent. Malnutrition and hunger deaths continue to rise, yet no targeted intervention has been announced. In some cases, tribal families ? pushed to the edge of survival ? have been forced to sell their own children. And the government calls this "Viksit Bharat"?

Social welfare schemes are being deliberately strangled. The budget for MGNREGS has been kept low, knowing that it will only be used to clear pending dues rather than create new employment. There is no concrete plan for rural employment, no efforts to empower tribals, and no framework to ensure fair wages and financial security for the poor. Meanwhile, the mining companies continue to extract wealth from these regions, leaving the local population in abject poverty. The Government talks about development, but development for whom?

The reality is this ? Odisha is being ignored, its tribals are being pushed further into poverty, its farmers are drowning in debt, and its youth are struggling to find employment. Yet, this Government wants to sell us the dream of ?development? while ignoring the very foundations of our rural economy. They talk of ?sabka saath, sabka vikas?, but in reality, they only stand with those who serve their political ambitions.

This budget does not reflect the aspirations of ordinary citizens. It caters to corporate interests, ignores the unemployed youth, neglects suffering farmers, and abandons tribal communities. The Government needs to be reminded that real economic growth cannot come at the cost of deepening inequality.

Mulla Nasruddin once tried to sell a donkey for 200 silver coins, even though he had listed it for 100 silver coins the day before. When questioned, he simply said, 'I have tied a golden bell around its neck. The donkey is the same, only the presentation has changed!'

This budget is exactly like that donkey! The schemes are the same, the funding is unchanged, yet the Government has repackaged them with new names and presented them as groundbreaking reforms. But the people of India are not fools.

The Government must answer for these injustices, fulfil its promises, and prioritize the people over propaganda. Until then, this budget remains nothing but a well-marketed illusion ? shiny on the outside, empty within.

Jai Hind.

श्री नवीन जिंदल (कुरुक्षेत्र) : मैं वर्ष 2025-2026 बजट पर अपने विचार रखता हूँ।

मैं बजट के समर्थन में अपने विचार रखूंगा। मैं सर्वप्रथम माननीय वित्त मंत्री जी को आठवीं बार बजट पेश कर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए बधाई देता हूँ। यह बजट हमारे नागरिकों की समृद्धि के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता और हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक मजबूत, समृद्ध, विकसित और समावेशी भारत के निर्माण की गारंटी है।

इस ऐतिहासिक बजट को संसद तो पास करेगी ही। पर भारत की जनता ने, दिल्ली के चुनावों में, मोदी जी के नेतृत्व में, हमें प्रचंड बहुमत देकर, इसे पहले ही 100 में से 100 अंक देकर पास कर दिया है। दिल्ली की जागरूक जनता का दिल से धन्यवाद।

मेरे से पहले कई माननीय सदस्य, बजट के बारे में विस्तृत रूप से, पक्ष और विपक्ष दोनों में बोल चुके हैं। इसलिए, मैं, सिर्फ कुछ प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो हमें विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में, मील के पत्थर साबित होंगे।

इस बार बजट में बहुत ही उद्देश्यपूर्ण ढंग से सोच समझकर कृषि, MSME, निवेश और निर्यात को विकास और वृद्धि के चार इंजन के रूप में चिन्हित किया गया है। मुझे विश्वास है कि हमारी अर्थव्यवस्था के इन चार महत्वपूर्ण पहलुओं पर, नए सिरे से जोर देने से, हम 2047 से पहले ही विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे।

इस बजट की भारत की जनता को सबसे बड़ी सौगात, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा REGULATORY SYSTEM में सुधारों की घोषणा है। हम सब इस बात से सहमत होंगे कि INFORMATION TECHNOLOGY के आने से तंत्र में कुछ सुधार तो हुआ है, पर यदि हम, वर्तमान REGULATORY SYSTEM को अपने विकसित भारत के लक्ष्य के संदर्भ में देखें, तो अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। REGULATORY SYSTEM की कमियों के बारे में, आम आदमी ही नहीं, सरकार के इस बार के ECONOMIC SURVEY में भी कुछ इस प्रकार, दो टूक लिखा गया है। मैं सदन की जानकारी के लिए उसको पढ़ना चाहूंगा:

The Economic Survey says, "Getting out of the way" and allowing businesses to focus on their core mission is a significant contribution that governments around the country can make to foster innovation and enhance competitiveness. The most effective policies that governments, both Union and States - in the country can embrace is to give entrepreneurs and households back their time and mental bandwidth. That means rolling back regulation significantly. That means changing the operating principle of regulations from 'guilty until proven innocent' to 'innocent until proven guilty'.

Notwithstanding the fact that, this has been misinterpreted as a negative connotation, by some learned members of the opposition.

I, congratulate the hon'ble Finance Minister for letting the economists speak their mind so freely and critically.

इकोनामिक सर्वे के इस बहुमूल्य सुझाव पर सरकार जितनी जल्दी कार्रवाई करेगी, विकसित भारत का लक्ष्य हमारे लिए उतना ही सरल और सुलभ हो जाएगा। इस बजट में TAXATION, बिजली, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और REGULATORY POLICIES में सुधारों को प्राथमिकता देना, स्वागत योग्य है। CONSTITUTION OF A TIMEBOUND REGULATORY REFORMS COMMITTEE सही दिशा में एक कदम है। 100 कानूनों के तहत प्रावधानों का गैर-अपराधीकरण एक और स्वागत योग्य कदम है।

हमें 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना ही है, तो हमें उसी हिसाब से कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेरा मानना है कि जो सरकार की अनगिनत योजनाएं चल रही हैं, उन सभी का विश्लेषण किया जाए। जो उपयोगी योजनाएं हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर ज्यादा धन और ध्यान आबंटित किया जाए तथा जो योजनाएं अपनी उपयोगिता खो चुकी हैं उन योजनाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाए। इस संदर्भ में मैं रहीम के एक प्रसिद्ध दोहे की एक पंक्ति दोहराना चाहूंगा।

"एकहि साधे सब सधे, सब साधे सब जाए।"

यानि हम एक एक करके ही सब काम कर सकते हैं।

इस विषय पर बोलते हुए, मेरा एक सुझाव और है कि हमें the one thing नाम की एक अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। इस छोटी सी किताब ने मेरा जीवन बदल दिया। इसमें एक रूसी कहावत है कि, अगर आप दो खरगोशों के पीछे भागोगे, तो एक भी हाथ नहीं लगेगा। मैं आपके साथ इस किताब से कुछ विचार साझा करना चाहूंगा। जिनसे मुझे अपने जीवन में बहुत मदद मिली।

पहली बात हम अक्सर जीवन में जरूरत से ज्यादा करने की सोच से ग्रस्त रहते हैं लेकिन हम सफल होते हैं ज्यादा करने की सोच की वजह से नहीं बल्कि जरूरी चीजों को सही तरीके से सही वक्त पर करने की वजह से ।

दूसरी - हम सोचते हैं कि Everything matters equally यानि हर चीज़, जरूरी है जबकि ऐसा नहीं है हमें वो एक चीज़ खोजनी है जो सबसे जरूरी है, जिसके जरिये बेहतर तरीके से असाधारण नतीजे आ सकते हैं ।

तीसरी - Big is Bad - हम अक्सर मानते हैं कि बड़ी सोच नहीं रखनी चाहिए लेकिन यह किताब कहती है । बड़ा सोचें, बड़े लक्ष्य बनाए, जैसा कि मा. प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का एक बड़ा संकल्प लिया है ।

लेखकों के हिसाब से, सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपने आप से सही प्रश्न पूछने होंगे और वह यह है कि - हम ऐसा कौन सा काम कर सकते हैं जिससे बाकी सब काम आसान हो जाएँ या अनावश्यक हो जाएँ । मेरे विचार से हमें सरकार के हर काम में Extreme Prioritization के सिद्धांत पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिये । हम सब जानते हैं कि सरकार व निजी क्षेत्र में बहुत सी परियोजनाएं देरी से चल रही हैं । उनपर अनुमान से कही अधिक खर्चा भी हो चुका है और कोई लाभ भी नहीं हो रहा है । हम नये नये projects announce करते हैं, लेकिन उनके पूरे होने पर ध्यान कम देते हैं । योजनाओं को समय पर पूरा करने की जवाबदेही होनी चाहिए । इसलिए सरकार में सभी Project Officers को Project Management, Theory of Constraints a Principals of the One Thing में formally train और certified करने की आवश्यकता है ।

इसी संदर्भ में, मैं, यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी लाखों करोड़ रुपये के घाटे पर चलने वाली कई Public Sector Undertakings का Air India की तर्ज पर तुरंत निजीकरण करने की आवश्यकता है । इन सभी Undertakings पर जनता के पैसे का खर्च, इस पैसे का सदुपयोग नहीं है । इसलिए सरकार ने इस वर्ष monetize करने का जो 10 लाख करोड़ रुपए का टारगेट रखा है वह स्वागत योग्य है ।

बजट में, हमारे 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य हेतु दो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिन्हित किया गया है । जो की बहुत स्वागत योग्य है । ये है, 100% गुणवत्ता युक्त स्कूली शिक्षा एवं सार्थक रोजगार युक्त 100% कुशल श्रमिक । ये दोनों बिंदु, पूर्ण रूप से आपस में जुड़े हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । अच्छी शिक्षा और कौशल विकास के बिना हमारी भावी पीढ़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में बने रहना बड़ा कठिन हो जाएगा । इसमें राज्य सरकारों की भूमिका ज्यादा अहम होती है ।

कृषि क्षेत्र के लिए बजट में पिछले बजट के 1 लाख 52K करोड़ रुपये के आबंटन के मुकाबले इस साल 1 लाख 70K करोड़ रुपये से अधिक आबंटित किया गया है, जो एक उल्लेखनीय वृद्धि है । माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के लाभों को ध्यान में रखते हुए, इसका पुरजोर समर्थन किया है । परंतु मैं देखता हूं कि, जमीनी स्तर पर इसको आवश्यकता अनुसार प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है । जैसे कि मेरे संसदीय क्षेत्र, धर्म क्षेत्र-कुरुक्षेत्र में कृषि विज्ञान केंद्र अपनी 40 एकड़ भूमि पर मात्र एक एकड़ में ही प्राकृतिक खेती कर रहा है । बाकी भूमि पर पारंपरिक रासायनिक खेती हो रही है । जब तक हम किसानों को उदाहरण देकर, प्राकृतिक खेती के लाभों से अवगत नहीं कराएंगे, तब तक स्वाभाविक है कि उन्हें पारंपरिक रासायनिक खेती छोड़कर, प्राकृतिक

खेती अपनाने में शंकाएं रहेंगी। इसके लिए हमारे देश भर में फैले हुए कृषि विज्ञान केन्द्रों व कृषि विश्वविद्यालयों को बढ़-चढ़कर पहल करनी पड़ेगी। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि, देश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों को अपनी समस्त भूमि पर केवल प्राकृतिक खेती करने के आदेश जारी किए जाएं। ताकि उनके यहां प्राकृतिक खेती के लाभों को देखकर, हमारे किसान भाई भी प्राकृतिक खेती की पद्धति को बढ़-चढ़कर अपनाएं।

इसी संदर्भ में, मैं सरकार से एक आग्रह और करना चाहूंगा कि, कृषि क्षेत्र में कृषि श्रमिकों के अभाव को देखते हुए, कुछ कृषि कार्यों को, मनरेगा के अंतर्गत अनुमोदित कार्यों की सूची में तुरंत शामिल किया जाना चाहिए। इन कार्यों के लिए श्रमिकों को, किसानों द्वारा 50% अतिरिक्त मानदेय भी दिया जा सकता है। इससे लाभार्थियों को वर्तमान दिहाड़ी के मुकाबले डेढ़ गुना अधिक आमदनी प्राप्त होगी और किसानों का उत्पादन भी बढ़ेगा व आय भी बढ़ेगी।

हमारी वर्तमान WORKFORCE में कौशल का अभाव देखते हुए, मेरा यह भी मानना है कि, हमें मनरेगा और कौशल विकास के कार्यक्रमों को जोड़ने की आवश्यकता है। गांवों का तेजी से विकास करने के लिए 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के विशाल नेटवर्क को ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ना, साथ ही भारतीय डाक को एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन के रूप में बदलना न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि में योगदान देगा, बल्कि लाखों विश्वकर्मा, छोटे उद्यमियों, महिलाओं, SELF HELP GROUPS, MSME की किस्मत बदलने में भी मदद करेगा।

कृषि क्षेत्र के हित में, इस बजट में जो व्यापक प्रावधान किए गए हैं, उनसे मेरे राज्य हरियाणा, जो कि एक कृषि प्रधान प्रदेश है, के किसान बहुत लाभान्वित होंगे। बजट में हरियाणा में रेलवे परियोजनाओं के लिए 3416 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। हरियाणा के 34 रेलवे स्टेशनों को 1149 करोड़ रुपये की लागत से अमृत स्टेशन बनाने की घोषणा की गई है। मेवात को रेल मार्ग से दिल्ली व अलवर से सीधा जोड़ने के लिए रेल परियोजना को मंजूरी भी दी गई है।

माननीय प्रधान मंत्री जी का हरियाणा से विशेष लगाव है, इन सभी सौगातों के लिए मैं हरियाणवियों की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ और आग्रह भी करता हूँ की हरियाणा के युवाओं के लिए धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में एक IIT स्थापित करने की भी कृपा करें।

स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए बजट में करीब एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की घोषणा और 10,000 चिकित्सा शिक्षा सीटों को और जोड़ने से हमारी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार होगा।

स्वास्थ्य के मामले में "स्वास्थ्य ही धन है" अंग्रेजी में Health is wealth and Prevention is better than cure की कहावत के बारे में मेरी व्यक्तिगत धारणा के आधार पर, मैं माननीय वित्त मंत्री से उचित हस्तक्षेप के लिए एक जोरदार अपील करना चाहूंगा। REFINED EDIBLE SEED OILS और ULTRA PROCESSED FOOD PRODUCTS हमारे नागरिकों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डाल रहे हैं।

मैं इस संदर्भ में नवीनतम Economic Survey में से एक महत्वपूर्ण उल्लेख करना चाहूंगा, "इसी तरह, यदि भारत को अपनी युवा आबादी की विशाल क्षमता का एहसास करना है, तो उनके मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को पोषित करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक प्रमाणों से पता चलता है कि ULTRA PROCESSED FOOD PRODUCTS (अधिक FAT, नमक और चीनी युक्त) का सेवन शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को कमजोर करने का एक बड़ा कारक है। बहुत ही कड़े फ्रंट-ऑफ-द-पैक लेबलिंग नियमों की आवश्यकता है और उन्हें लागू किया जाना चाहिए। यह सुझाव देना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि देश की भविष्य की विकास क्षमता, इस उपाय पर बहुत अधिक निर्भर करती है।" इसलिए सरकार को इस सन्दर्भ में तुरंत प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि हमारे अनाज व सब्जियों में अंधाधुंध कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों, WEEDICIDES के उपयोग से भी कैंसर बहुत बढ़ रहा है। वक्त की मांग है की हर जिले में एक आधुनिक टेस्टिंग लैब स्थापित होनी चाहिए। जहां पर अनाज, दूध, घी, खाने पीने के सामान तथा दवा आदि का, जनता स्वयं जाकर जांच करवा सके और उनके द्वारा होने वाले लाभ या हानि पर अपना निर्णय ले सकें।

स्वच्छ भारत मिशन की तरह स्वच्छ वायु मिशन शुरू करने की आवश्यकता है। वायु प्रदूषण का असर, खास कर, हमारे बच्चों पर बहुत गंभीर है। इससे इनके स्वास्थ्य के साथ साथ, आयु पर भी प्रभाव पर रहा है। इसलिए हमें वायु प्रदूषण के खिलाफ तुरंत, युद्ध स्तर पर कारवाई करने की जरूरत है। प्रदूषण कम करने के लिए कुछ आसान उपाय जैसे घरों में एल.पी.जी. का उपयोग बहुत आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के द्वारा लाखों परिवारों को यह फायदा पहुंचाया। मेरा सरकार से आग्रह है कि सस्ते गैस सिलेंडर गरीब परिवारों को देने की जरूरत है ताकि वो बायोमास के बजाय नियमित रूप से गैस का ही इस्तेमाल करें।

इस बजट ने Middle Class के सपनों को साकार किया है। भारत का मध्यम वर्ग हमारी economy का नींव का पत्थर है। उसके हित में किया गया कोई भी काम पूरी economy को फायदा पहुंचाता है। देश की economy में डिमांड बढ़ेगी, बाजार में पैसा आएगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जिससे पूरे देश को फायदा होगा। सरकार के इस कदम का सभी नागरिकों ने पुरजोर स्वागत भी किया है।

देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना, भारत को एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने और दुनिया भर से पर्यटकों की संख्या में कई गुना वृद्धि करने में एक गेम चेंजर होगी।

मैं भगवान बुद्ध के जीवन और समय से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान देने वाली योजना का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। यहां पर मैं माननीय वित्तमंत्री जी, से पिछले बजट पर अपने भाषण में किए गए अनुरोध को भी दोहराना चाहूंगा, कि इसी प्रकार वे गीता स्थली धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के विकास के लिए भी एक विशेष योजना प्रारम्भ करने की कृपा करें।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को खोलना और एक सुविधाजनक रेगुलेटरी वातावरण का आश्वासन, बिजली के इस स्वच्छ स्रोत में निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा। यह एक क्रान्तिकारी और दूरगामी कदम है जो हमारे बिजली उत्पादन के लिए

वरदान सिद्ध होगा ।

अंत में, मैं बजट का भरपूर समर्थन करता हूँ, जो हमारी सरकार के संकल्प स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, समग्र भारत और विकसित भारत को पूरी तरह से दर्शाता है । मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि बजट के प्रावधानों का हमारी अर्थव्यवस्था, नियामक ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण प्रणालियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हमारे नागरिकों, विशेष रूप से वंचितों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण समुदायों का सशक्तिकरण होगा । वस्तुतः यह भारत गणराज्य की सरकार का, भारतीय गणराज्य को समर्पित बजट है, जिससे, हर भारतीय लाभान्वित होगा । धन्यवाद, जय हिन्द ।

SHRIMATI DAGGUBATI PURANDESWARI (RAJAHMUNDRI): I would like to express my views in support of the Budget 2025-26. This is not merely a financial statement; it is a powerful testament to our nation's unwavering resolve to build a new India, a Viksit Bharat by 2047. It is a budget woven with threads of aspiration, ambition, and an unshakeable belief in the potential of every Indian.

Under the visionary leadership of Prime Minister, Narendra Modi ji, India has embarked on a transformative journey, a journey from an era of scams to an era of schemes, from a culture of corruption to a commitment to progress, and from a climate of despair to an ethos of self-reliance.

I extend my warmest congratulations to the Finance Minister, Nirmala Sitharaman ji for presenting her eighth consecutive Budget, a remarkable feat in itself. This Budget is a beacon of hope, prioritising inclusive growth, expanding opportunities, and empowering every citizen to realize their full potential. Ye sirf ek budget nahi, ek viksit Bharat ki neev hai.

This budget arrives at a critical juncture in global history. The world is grappling with economic uncertainties, geopolitical shifts and unprecedented challenges. Yet, amidst this turbulence, India stands tall, a beacon of stability and growth. Our resilience, our dynamism, and our unwavering commitment to reform have enabled us to navigate these challenges effectively. This Budget builds upon our strengths, addresses our vulnerabilities, and charts a course towards a brighter future. The Rs.50,65,345 crore budget for 2025-26, a 7.4 per cent increase from the previous year, is not just a collection of numbers; it is a strategic investment in our nation's future. It is a holistic and inclusive Budget, designed to touch the lives of every Indian, from the farmer in the field to the entrepreneur in the city. Just as a rainbow derives its beauty from the harmonious blend of seven colours, this Budget lays a robust foundation in seven key sectors, ensuring balanced and impactful progress for all.

The middle class is the backbone of our economy, the engine of our consumption, and the driving force behind our aspirations. They are the doctors, engineers, teachers, small business owners, and countless other professionals who contribute tirelessly to our nation's progress. Recognising their immense contribution, this Budget brings historic tax reforms, not just as relief, but as empowerment. The tax-free slab has been progressively increased from Rs.2.5 lakh in 2014 to Rs.25 lakh in 2019, then to Rs.7 lakh in 2023, and now, a significant jump to 12 lakh! For salaried individuals, factoring in standard deductions, the effective tax-free limit extends to Rs.12.75 lakh.

This is not merely about reducing taxes; it is about unleashing the potential of the middle class. It is about empowering them to save more, invest more, and secure their families' futures with greater confidence. It is a bold step towards financial independence, ensuring that the tax burden never stifles their dreams or limits their ambitions. This is about honouring their hard work and recognizing their crucial role in building a prosperous India.

For too long, our farmers, the *annadatas* who feed our nation, were relegated to the margins of policy-making. But under Prime Minister Modi ji's leadership, they are now rightfully placed at the centre. This Budget reflects our unwavering commitment to their welfare and prosperity. We are not just giving them slogans; we are giving them the resources, the technology, and the support they need to thrive. This Budget brings historic agricultural reforms, with a record allocation of Rs.1.90 lakh crore for rural development and Rs.1.38 lakh crore for agriculture. The PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana will revolutionise 100 backward agricultural districts, directly benefiting 1.7 crore farmers and boosting their incomes.

The Atmanirbhar Pulses Mission will ensure self-sufficiency in pulses, reducing our reliance on imports and strengthening our food security. The increase in the Kisan Credit Card (KCC) limit from Rs.23 lakh to Rs.5 lakh will provide farmers with access to crucial credit, empowering them to invest in their farms and adopt modern techniques. Beyond financial support, we are investing in rural infrastructure, building 2 crore new rural homes under PMAY-G and connecting 1,62,742 villages through the PM Gram Sadak Yojana. This is not just about building roads and houses; it is about building a bridge between rural and urban India, empowering our farmers, and ensuring that prosperity reaches every corner of our nation. Kisan khush toh desh khush!

National security is paramount. It is the foundation upon which all other progress is built. Unlike previous Governments that compromised our nation's security, we have prioritised building a strong, self-reliant, and technologically advanced defence sector. The 26.81 lakh crore defence Budget is a historic investment in our nation's security, equipping our armed forces with the resources they need to protect our borders and safeguard our interests. We are not just importing defence equipment; we are building a robust domestic defence industry. Defence production, which stood at a mere Rs.42,000 crore a decade ago, has now surged to Rs.1.27 lakh crore. Our defence exports have witnessed a phenomenal jump, from Rs.686 crore in 2013-14 to Rs.21,083 crore. Our target is to reach Rs.50,000 crore in defence exports by 2029. With over 14,000 MSMEs and 350+ defence startups contributing to this growth, India is not just securing its borders; it is emerging as a global defence powerhouse. Atmanirbhar Rashtra, Shakti ka Adhar!

Our youth are our greatest asset, the architects of our future. This Budget is a testament to our belief in their potential and our commitment to providing them with the opportunities they need to thrive. The 22 lakh crore package for skill development and job creation is a significant investment in our young workforce, ensuring that they are equipped with the skills and knowledge required to succeed in the 21st century economy.

We are not just creating jobs; we are fostering entrepreneurship, innovation, and self-reliance. The internship programs for over one crore youth will provide invaluable industry experience, bridging the gap between education and employment. The 1,000 crore venture capital fund for the space sector will empower young entrepreneurs to reach for the stars, literally! With over 1.5 lakh startups already flourishing in India, we are witnessing a revolution in innovation and entrepreneurship.

A strong and prosperous India cannot be built without the full and equal participation of women. This budget reaffirms our unwavering commitment to empowering women and ensuring their rightful place in shaping our nation's destiny. We are not just talking about women's empowerment; we are taking concrete steps to make it a reality.

5 lakh SC/ST women entrepreneurs will receive loans of up to Rs.22 crore, enabling them to start and grow their businesses. The 91 lakh self-help groups (SHGs), empowering over 10 crore women, are a testament to the power of collective action. The 'Lakhpati Didi' initiative aims to create 3 crore financially

independent women, and already, 1.15 crore women have achieved this milestone. The Drone Didi Yojana is equipping women in rural areas with the skills to use technology for economic empowerment. We are not just celebrating women's achievements; we are creating a level playing field where they can excel in every field, from flying fighter jets to leading corporations. Nari Shakti ka samman, naye Bharat ka nirmaan!

World-class infrastructure is the backbone of a modern and prosperous nation. This budget makes unprecedented investments in building a robust and interconnected infrastructure network. Rs.2.87 lakh crore has been allocated for roads, and Rs.2.65 lakh crore for railways a six-fold increase compared to 2009-14! This will not only improve connectivity but also generate employment and boost economic activity. Rs.1.00 lakh crore has been allocated for healthcare, ensuring that quality healthcare is accessible to all, including 6 crore senior citizens under the 25 lakh Ayushman Bharat health scheme.

Rs.1.28 lakh crore has been allocated for education, investing in the future of our youth. This includes establishing 50,000 Atal Tinkering Labs and an AI Centre of Excellence, preparing our students for the challenges and opportunities of the future. The PM SVANidhi scheme has been expanded to benefit street vendors, providing them with access to affordable credit. The 21 lakh crore Urban Challenge Fund will empower cities to become engines of economic growth, driving innovation and creating opportunities for all. India's future lies in the power of science, research, and innovation. This budget lays a strong foundation for making India a global leader in these critical fields. The 50,000 crore allocation for the National Research Foundation will fuel groundbreaking research and innovation across disciplines, nurturing a culture of scientific inquiry and discovery. The 10,000 crore investment in the Vigyan Dhara Yojana will further boost scientific research and development, supporting cutting-edge projects and fostering collaboration between academia and industry.

The launch of the India AI Mission and the National Quantum Mission demonstrates our commitment to embracing the technologies of the future. These initiatives will position India at the forefront of the global AI and quantum computing revolution, opening up new possibilities in various sectors. The focus on Green Tech, including solar PV cells, EV batteries, and wind energy, underscores our commitment to sustainable development and a cleaner future.

This Budget is not just a document; it is a promise. It is a promise to build a New India, a Viksit Bharat where every citizen has the opportunity to thrive, where every dream is within reach, and where India takes its rightful place on the world stage. It is a budget that reflects our collective aspirations and our unwavering belief in the potential of our nation.

This is not a journey that the government can undertake alone. It requires the active participation and support of every citizen. Let us work together, hand in hand, to build the India of our dreams an India that is strong, prosperous, and inclusive.

I once again congratulate Prime Minister Narendra Modi ji and the Finance Minister Nirmala Sitharaman ji for this visionary and transformative Budget.

SHRI SURESH KUMAR SHETKAR (ZAHIRABAD): I express the deep disappointment of the people of Telangana regarding the Union Budget for 2025-26 India's GDP, generating Rs.26.000 crore in taxes annually, and shocking to note that despite Telangana contributing 5.1 per cent to playing a vital role in the country's economic growth, our state has been completely ignored in this year's Union Budget.

There is not a single mention of Telangana in the Budget ? no provision for the crucial projects that the State Government had requested, and no allocations to address the pressing developmental needs of our people. This is not a mere oversight; this is a clear indication of the Centre's indifference to Telangana, a State that has been at the forefront of contributing to India's economic growth.

Let us examine some of the critical issues that were completely overlooked:

1. Bayyaram Steel Plant and Industrial Development. Telangana had been asking for the establishment of a Steel Plant at Bayyaram, which is crucial for the industrialization of the State. The Bayyaram Steel Plant, if established, would have created thousands of jobs and boosted our industrial base, yet no funds have been allocated for this project. The Singareni Collieries also had a request for new coalfields to enhance coal production, and yet there is no mention of this in the Budget.

2. Railway Integrated Coach Factory - Similarly, the Railway Integrated Coach Factory proposed for Telangana, which would create employment and support the Indian Railways' modernization, is absent from the Budget. This project was expected to generate employment for thousands of youth in the region and support the national railway sector.

3. Musi River Re-development Project - Telangana had submitted a request for the Musi River re-development project, which is essential for the clean-up, preservation, and environmental sustainability of one of Hyderabad's most important rivers. This would have benefited the water supply and sanitation systems, as well as the health of thousands of residents in the area. No funds have been allocated for this crucial project.

4. Hyderabad Metro-2 Project - The Hyderabad Metro-2 project, which would improve urban mobility and address congestion in the capital city, had a request for Rs. 17,212 crore in central funding. Despite its importance in easing traffic and contributing to sustainable public transport, this project has been entirely ignored in the Union Budget.

5. Subsidy for Electric Buses - Telangana had also asked for a subsidy for electric buses, aiming to promote green energy, reduce pollution, and enhance the state's public transport infrastructure. But once again, there is no mention of electric mobility in this Budget. This is a blow to the state's environmental sustainability efforts.

6. Turmeric Board - One of the most disappointing omissions is the Turmeric (Haldi) Board. Telangana is one of the largest producers of turmeric in the country, and the establishment of the Turmeric Board was vital for the welfare of farmers in the State. Yet, the Budget has failed to allocate any funds for this critical demand, leaving our farmers without the support they need.

7. Taxation: Revision of Income Tax Slab - The Centre's tax slab revision proposal was another key request. Telangana had requested that the income tax slab be revised to start from Rs. 15 lakh instead of the current Rs. 12 lakh, in order to provide relief to the middle class and salaried employees who are facing rising costs. Yet, this request has also been ignored.

8. Tribal University - The Tribal University for Telangana, a long-pending demand from the tribal communities, was another key request that was completely overlooked. This university was supposed to address the education needs of our tribal population and create opportunities for them to excel in higher education. However, the allocation in the Budget for this vital institution is minimal, and it does not reflect the scale of support needed for our tribal communities.

9. Education: IIM and Sainik Schools - Telangana had also requested the establishment of an Indian Institute of Management (IIM) to foster world-class education in our state. The establishment of more Sainik Schools was also requested to promote defense education and contribute to national security. Both these proposals have been ignored in the Union Budget, despite the fact that such institutions would significantly benefit the youth of Telangana and the country.

Despite Telangana's significant contribution to India's economy, our state has once again been left in the lurch. Not a single rupee has been allocated for our critical projects. This is not just a Budget for the Union; it is a Budget that fails federalism and undermines the rightful aspirations of states Budget that fails like Telangana. BJP ministers from Telangana, Congress MPs, and Chief Minister A. Revanth Reddy have all failed to secure any meaningful support from the Centre for the people of Telangana.

The Centre's neglect of Telangana is not only disappointing, it is an insult to our state, which contributes significantly to the national exchequer. The Union government has shown a clear bias against our state, preferring to allocate funds to other states while leaving Telangana, despite our contribution, to fend for itself.

The Congress party will continue to stand firm in its commitment to the people of Telangana. We will raise our voices, both in the Assembly and in Parliament, until Telangana receives its rightful share in national development. We demand that the Union government take immediate steps to rectify this injustice and ensure that our state gets the support it needs to thrive.

This Union Budget is a betrayal of Telangana's people and their aspirations. It has failed to address our state's most crucial infrastructure, educational, and welfare needs. The Congress party will continue to fight for the rights of the people of Telangana, and we will not rest until our state is given the attention and funding it deserves.

Thank you. Jai Telangana!

श्री गणेश सिंह (सतना) : देश की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ती जा रही है, दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वर्ष 2025-26 का बजट 50.65 लाख करोड़ का रखा गया है, जिसमें 16.29 लाख करोड़ केंद्रीय योजनाओं के लिए रखा गया है। 25.01 लाख करोड़ रुपये राज्यों के लिए निर्धारित किए हैं। 11.21 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए हैं। सरकार द्वारा इसे विकसित भारत के लिए पीएम गति शक्ति योजना में खर्च किए जाएंगे।

बजट में 12 घोषणाएं हैं - कैंसर में राहत, दवाई सस्ती, हर जिले में खुलेंगे डे केयर सेंटर। 5 साल में 3 करोड़ से अधिक रोजगार। सीनियर सिटीजन एक लाख के बैंक ब्याज पर कटौती नहीं। गिग वर्कर (कॉन्ट्रैक्ट लेबर) को पहचान पत्र, ई-पोर्टल पर दर्ज, 5 लाख के आयुष्मान कार्ड की सुविधा। एससी/एसटी महिलाओं को दो करोड़ तक लोन दिया जाएगा। बीमा सेक्टर में 100 प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी। मकान किराए 6 लाख सालाना आय पर टीडीएस नहीं लगेगा। मेडिकल, इंजीनियरिंग में 82 हजार से अधिक सीटें बढ़ाई जाएंगी। स्टार्टअप 10 हजार करोड़ के फंड की छूट 5 साल बढ़ाई गई। बैटरी निर्माण सामग्री पर कस्टम ड्यूटी खत्म की गई। किसान सब्सिडी वाले कार्ड पर 5 लाख तक कर्ज ले सकेंगे। ज्यादा कमाई पर बचत, एक करोड़ वालों के 1.5 लाख बचेंगे, 5 करोड़ वालों के 1.43 लाख का फायदा होगा।

बजट में पहली बार मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख की आमदनी में कोई आयकर नहीं लगेगा, लगभग 6.3 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही एक लाख करोड़ का टैक्स देने वालों को राहत मिलेगी। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्यों को 50 वर्ष के लिए 1.5 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। एमएसएमई को टर्नओवर का 2 गुना कर्ज की सुविधा मिलेगी, जिससे नए रोजगार और बढ़ेंगे। 200 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कैंसर की 36 दवाइयां तथा अन्य मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे। एलईडी, भारत में बने कपड़े, मोबाइल बैटरी सस्ती होंगी। 82 सामानों से सेस हटाया गया, लेदर जूते, पर्स, बेल्ट, इलेक्ट्रिक वाहन, हैंडलूम कपड़े सस्ते हुए। यह बजट विकास में तेजी लाने, समावेशी विकास सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र के निवेशों को बढ़ाने, परिवारों के मनोभाव में उल्लास भरने, मध्यम वर्ग के खर्च की शक्ति को बढ़ाने के लिए कारगर प्रावधान किए गए हैं।

विकास की इस यात्रा के लिए चार शक्तिशाली इंजन हैं ? कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात और यही लक्ष्य है, विकसित भारत का - किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत 100 जिलों से की जाएगी। दलहन में आत्मनिर्भरता। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। वर्तमान में एमएसएमई 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले 45 प्रतिशत निर्यात को योगदान कर रहे हैं। 2.5 गुना दायरा इनका बढ़ाया जाएगा, ताकि निर्यात में बढ़े और रोजगार भी बढ़े। बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इस बजट की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है, केंद्र सरकार के सभी विभागों के बजट में बढ़ोतरी की गई है। रोड ट्रांसपोर्ट में हमारे मध्य प्रदेश की झांसी, बमीठा सड़क के निर्माण को सतना, सिंगरौली तक तथा सतना शहर में एलिवेटेड रोड के प्रोजेक्ट की स्वीकृति देना अति आवश्यक है।

रामपथगमन में अयोध्या से चित्रकूट की निर्माणाधीन सड़क को सतना तक बढ़ाने की जरूरत है। अंतर प्रांतीय कनेक्टिविटी के तहत सतना, सेमरिया, जवा, शंकरगढ़, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) तक सड़क भारत-माला प्रोजेक्ट में विचाराधीन है, स्वीकृत दी जाए। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक आईआईटी है, जो इंदौर में है। प्रदेश का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के सतना में एक नए आईआईटी की स्थापना की जाए। सतना मेडिकल कॉलेज कैंपस में 700 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की स्थापना की जाए। सतना एयरपोर्ट की लंबाई बढ़ाई जाए एवं नाइट लैंडिंग की भी सुविधा का विस्तार किया जाए तथा हवाई

परिचालन शुरू किया जाए। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा में मिलने वाली मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना की टमस एवं सतना नदियों का संरक्षण तथा संवर्धन अत्यंत जरूरी है। बजट में सिंचाई परियोजनाओं के संवर्धन के लिए प्रावधान किए गए हैं।

उसी के तहत बरगी बांध की दाईं तट नहर, जिसका पानी सतना एवं रीवा जिले के किसानों के खेतों तक आना है, परियोजना अधूरी है, बरगी डैम के ऊपर डिंडोरी जिले में तीन सहायक बांध बनाने का प्रस्ताव अधूरा है। सलीमनाबाद में सुरंग का कार्य भी अधूरा है, इस परियोजना को राष्ट्रीय योजना में शामिल किया जाए। मध्य प्रदेश में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। वैसे मेरा सतना क्षेत्र दर्शन योजना, बौद्ध परिपथ, रामायण सर्किट तथा प्रसाद योजना में आंशिक रूप से जोड़ा गया है। लेकिन जरूरत है, चित्रकूट 84 कोसीय परिक्रमा के तीर्थ स्थल सतना, रामवन, पोंड़ी, खजुरी, मैहर, गिद्धा पर्वत, मारकण्डेय घाट, सरसी रिसार्ट, बाणसागर में ब्रिज निर्माण, बांधवगढ़, अमरकंटक, कान्हा को एक नया सर्किट बनाने की घोषणा की जाए। गुजरात के एकता नगर में जो अंतराष्ट्रीय स्तर का जिओ पार्क बनाया गया है, उसी तरह का पार्क मैहर जिले में स्थित मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी तथा जिओ पार्क को बनाया जाए। सतना के नरोहिल के जंगल को जैव विविधता पार्क घोषित किया गया है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। मेरे लोकसभा क्षेत्र के मैहर लिलजी बांध, धर्म सागर बांध नादन, कोलगढ़ी बांध, गोड़ा बांध, उसरार बांध, अमकुई बांध, अबेर बड़ा तालाब, बेरहना बांध, भैसवार डैम को झील प्रोजेक्ट में लिया जाए तथा इनका संवर्धन किया जाए। नए जिले मैहर में कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय तथा सैनिक स्कूल की स्थापना की जाए।

मैं बजट का पुरजोर स्वागत करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेन्द्र मोदी जी तथा वित्त मंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं।

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): The Government speaks of Aatmanirbhar Bharat, but the true test of self-reliance lies in whether it empowers the poorest of the poor, the small-scale industries, farmers, and workers. Is this self-reliance only for a handful of corporate giants, or does it truly aim to uplift the millions struggling to make ends meet? This budget was an opportunity to lay the foundation for inclusive growth, but unfortunately, it has failed to do so.

Farmers in Bihar, particularly in Kishanganj, are struggling due to the high cost of fertilizers and their unavailability in government supply centres. Instead of ensuring proper distribution, the system is plagued by black marketing, forcing farmers to buy fertilizers at inflated prices. This exploitation is pushing small and marginal farmers into severe distress. The Government must take immediate action to regulate fertilizer distribution and prevent black market hoarding.

Farmers are the backbone of our nation, yet their problems remain unaddressed. Rising input costs, lack of proper irrigation facilities, and the absence of a fair pricing mechanism are pushing them

into debt and despair. While the Government claims to support farmers, there is no substantial increase in funding for Minimum Support Price implementation, nor any major initiatives to provide relief from rising input costs. Where are the measures to ensure that farmers get the rightful price for their produce? The agricultural sector deserved more financial support, but this budget has ignored their needs.

Unemployment remains one of the most pressing issues in our country, especially for the youth. Bihar, in particular, has one of the highest unemployment rates in the country. The pandemic forced lakhs of migrant workers to return home, and yet, even after years, there is no concrete plan to provide them sustainable employment opportunities. This budget should have focused on boosting MSMEs and labor-intensive industries, but instead, we see a lack of job-creating policies. The youth of our nation need opportunities, not empty promises.

One of the biggest injustices to my region, Kishanganj, and to the State of Bihar is the complete neglect of healthcare infrastructure. Even in 2025, Kishanganj does not have a Government medical college. This is a region where people struggle to access basic healthcare, often traveling hundreds of kilometres to get medical attention. I have been raising this demand for years, yet no budget allocation has been made for its establishment. I strongly urge the government to immediately announce the construction of a government medical college in Kishanganj, so that the people of the region can have access to affordable and quality healthcare.

Another major issue I want to highlight is the negligence towards Aligarh Muslim University Kishanganj campus. For the past six years, I have been raising this issue in Parliament, yet the government has failed to allocate sufficient funds for its development. There is no proper infrastructure, no recruitment of teaching and non-teaching staff, and no progress in making it a full-fledged educational institution. This institution was meant to uplift the youth of the region, but due to the government's inaction, thousands of students are deprived of quality higher education. I demand immediate action and proper funding for AMU Kishanganj so that it can function as a premier educational institution, benefiting the entire region.

Another issue of grave concern is the lack of proper railway infrastructure in Bihar, especially in Kishanganj, Aluabari Road Junction (Islampur), Thakurganj, and adjoining areas. Despite repeated demands, there has been no significant improvement in railway connectivity, which is crucial for trade,

commerce, and employment opportunities. The government must prioritize these regions and allocate funds for railway expansion, electrification, and new railway projects to boost connectivity in Bihar.

Every year, Bihar, particularly the Seemanchal region, faces devastating floods, causing massive destruction to lives and livelihoods. However, there is no long-term flood management plan in place. The government must take proactive steps to ensure permanent flood control measures, embankment strengthening, and effective disaster relief management.

Bihar has immense potential for small and medium enterprises, but without government support, these businesses cannot thrive. Kishanganj and Seemanchal are home to hardworking entrepreneurs who need access to credit, better market linkages, and government schemes. The government must focus on skill development programs, financial incentives, and industrial clusters in Bihar to boost employment and entrepreneurship.

This budget is a missed opportunity. It neither provides relief to the common man nor addresses the core issues of employment, education, healthcare, and infrastructure. Bihar, and particularly Kishanganj, has once again been ignored. The lack of a government medical college, no progress in AMU Kishanganj, poor railway infrastructure, and inadequate flood management proves that this government is indifferent to the needs of the people of my region.

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): 'Sabka Saath Sabka Vikas' is the phrase that has been coined by Prime Minister Modi to drive home the point that the Government is working for everyone. This Budget is yet another example of how there is 'Na Kisi Ka Saath and Na Kisi Ka Vikas' during his term. This budget is a pro-corporate, anti-poor and anti-farmer budget.

India is facing the highest rate of joblessness in the last 45 years, however, the budget does not address the aspect of unemployment and inflation at all and does not come up with solutions for the same. Except a few tax exemptions, no roadmap for economic recovery has been provided in the Budget.

There has been very marginal increase in the amount allocated for Dalits, Tribals, Backward Classes and Religious Minorities. Unfortunately, this situation is not shocking as when none other than the Home Minister terms the reliance and quoting of Dr. Ambedkar as 'Fashion' one can easily understand how little this Government cares for the Dalits and Minorities. Recently (on 02.02.2025) a Union Minister (Mr.

Suresh Gopi) said that tribal affairs should be handled by upper castes to ensure progress of tribals, thereby indicating the Brahmanical mindset of the Central Government and its approach of neglect towards tribals. There is no plan for health, education or scholarships for dalits, tribals, backward class, poor and minority children in the Budget.

No steps have been taken in the present budget to improve the condition of the rural economy and the poor. The budgetary allocation for MNREGA, one of the largest and most pivotal rural employment and development programs, has not seen any addition despite there being severe distress in the rural economy at present. This is despite the fact that the Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj in its report on 'Rural Employment through MNREGA' in 2024 emphasized that MNREGA allocation should be increased. The Report has highlighted that only about 3% of the workers received unemployment allowance in the last 5 years.

The Budget does not mention anything for people affected by violence in the Northeastern states. Sixty thousand people are languishing in relief camps in Manipur but the Budget has not mentioned anything for them. It is clear that PM does not want to visit Manipur, but at least some allocation in the budget could have been made for them.

Not just Manipur, the Budget has completely ignored Wayanad's landslides where the deadly landslides resulted in around 400 lives. The Centre has not provided any rehabilitation package for the victims in the Budget despite repeated requests for the same. Narendra Modi, during his visit to Wayanad in August 2024 had promised full support of funds. However, nothing has been provided in the Budget despite State's request for funds.

There has been dip in the allocation for key agricultural schemes despite the wages for agricultural labourers not growing at all during the term of the present government.

- i. Nothing has been mentioned above loan forgiveness of the farmers or the Minimum Support Prices (MSP) which has been a long-standing issue for the farmers.
- ii. The allocation to the Department of Agriculture and Farmers Welfare has come down.
- iii. Additionally, the allocation to schemes such as Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (crop insurance scheme) has also come down substantially.

No steps have been taken to improve healthcare in India. The health sector's share of the budget has fallen from 2.31% in 2019-20 to 1.9% in 2025-26, making the healthcare budget one of the lowest among major economies.

Similar situation can be seen for the education sector as well. Budgetary allocation for school education dropped from 3.16% of total expenditure in 2013-14 to 1.55% in 2025-26; higher education allocations dropped from 1.6% to 0.99%.

Instead of Sabka Saath Sabka Vikas, it appears that this government has followed the strategy of 'Sirf Unka Vikas, Jinka Saath'. Instead of thinking about the welfare of the entire country, the Budget has completely neglected States where the BJP is not in power. The Budget has completely neglected the southern states and the demands of people of South India. This Budget therefore also goes against the basic principles of cooperative federalism in India and it is yet another attempt by the BJP Government to weaken State Governments by not providing them adequate budgetary allocations.

Adequate allocations have not been provided for the State of Kerala. What is even more shocking is that Union Minister George Kurien has now said that Kerala must declare itself 'backward' if it wants more funds from the Centre - this is an insult to the people of Kerala and their ability to develop their State and progress in life. This also clearly shows that the aim of the Central Government is to turn Kerala into a backward and poor State.

During the entire speech, the Finance Minister did not mention Kerala even once.

- i. Nothing has been mentioned about long-pending projects such as AIIMS, Silverline etc.
- ii. The economic package of 24000 crores to tide over the economic stress that Kerala has been facing has also not been provided in the Budget.
- iii. The demand for a special package for Vizhinjam International Seaport has also not been met in the Budget.

Other Southern States where the BJP does not have its government have also been completely ignored. The demands of States such as Karnataka, Tamil Nadu and Telangana have also not been taken note of in the Budget.

I wish to also highlight the unfortunate incident of rape and murder of 22-year-old Dalit women in Ayodhya which has taken place recently. It is really unfortunate and abhorrent that even after so many years of independence, not enough has been done to protect the women in our society, especially those belonging to the backward castes and classes. Much more needs to be done, including in terms of budgetary allocations, for the safety and security of women.

The Government through this Budget has yet again failed to address the pressing issues that the people of India are facing and has merely relied on false promises and catchy rhetoric to deceive the people of this country once again.

SHRI TAMILSELVAN THANGA (THENI): I would like to express my views on the Union Budget for 2025-2026. The Budget fails to focus on growth, development, and welfare of the common and socially downtrodden people, particularly the middle-class people, and also fails to account for the regional disparities, particularly relating to the Tamil Nadu State.

The State's demands for adequate allocation to infrastructure projects, agricultural support, and social welfare have not been met. While there is an attempt to focus on infrastructure development at the national level, there is a lack of specific funding for Tamil Nadu's projects. The hon. Minister has not mentioned even a single word of Tamil Nadu State and not willing to allocate any fund for the infrastructural projects, but Tamil Nadu state has achieved all developments on its own resource. This why Tamil Nadu, which has long been a leader in industrial growth, education, and social welfare, continues to face neglect in this Budget. The Budget fails to address the pressing issues specific to Tamil Nadu.

Similarly, while the Government talks about strengthening the healthcare system, there is a little mention of the urgent need to bolster our public healthcare infrastructure. Tamil Nadu, as a key State in the country, requires more investment in its medical colleges, primary healthcare centers, and general hospital infrastructure.

I would request the Finance Minister that the following demands from my constituency may be considered and necessary fund may be allocated at the earliest to fulfill the demands of the lot of devotees and my constituency people. There has been a very long pending demand for more than 100 years for

laying of a new railway line from Dindigul to Sabarimala which is a very famous pilgrimage city and pilgrims thronged from worldwide. Every year, around one crore devotees are visiting Sabarimala, and every month around five lakh devotees are thronging to Sabarimala from all over the country. If a new railway line is started from this sector, lakhs of devotees will get benefit, that is, their time, money and sufferings will be minimized. Also, road traffic and accidents will be reduced. Also, I would request that a new railway line be laid between Kodaikal road to Theni, that is, around 48 km only so that all the devotees reach Theni conveniently and from there, they will reach Sabarimalai within two hours which is merely 150 km from Theni.

I would like to draw the attention of the hon. Finance Minister to allocate fund to lay new by-pass road for Usilampatti and Andipatti which are in my Theni parliamentary constituency which is a long pending demand from the people of my constituency.

The Tamil Nadu State Government is persistently demanding to allocate necessary fund to execute the Metrorail projects, but the Union Government is not willing to allocate any funds. So, I request the Finance Minister to allocate the necessary fund for ongoing metro projects and for the new metro projects.

Agriculture remains the backbone of Tamil Nadu's economy. Yet, this Budget continues to overlook the plight of our farmers. We demand more direct support for small and medium farmers, as well as for the State's agricultural infrastructure. We strongly believe that the welfare of farmers should be a priority, but sadly this budget offers little to address the challenges faced by farmers in Tamil Nadu and across the country.

The allocation for irrigation, subsidies for seeds and fertilizers, and the development of cold storage facilities are insufficient and inadequate to meet the needs of our farmers. Without a comprehensive policy that addresses the issue of minimum support prices, debt relief, and the promotion of sustainable farming, this Government will continue to leave our agricultural sector in peril.

While the Government claims to have allocated funds for national infrastructure development, Tamil Nadu continues to face a lack of adequate funding for essential regional infrastructure projects. Projects

like the Metro Rail expansion in Chennai, road connectivity improvements in rural areas, and the development of regional airports have been delayed, impacting the overall economic growth of the State.

This Budget presents a facade of progress while failing to address the real issues faced by the people of Tamil Nadu and the broader Indian public. It offers empty promises while neglecting the needs of the marginalized and disadvantaged communities. I call upon the Government to rectify these glaring gaps in the Budget, particularly in areas of regional development, education, healthcare, and agriculture

Finally, I demand a fair share for Tamil Nadu, and also request the Government to take necessary steps to reduce the unemployment problems for both educated and uneducated youths and also to address the real solutions for our farmers. With these words, I conclude my speech. Thank you.

SHRI G. SELVAM (KANCHEEPURAM): I would like to express my views on the Union Budget for 2025. The Budget, as presented, claims to focus on growth, development, and welfare, but in reality, it is clear that it falls short in addressing the fundamental needs of the people and fails to account for the regional disparities that continue to plague our nation.

Tamil Nadu, which has long been a leader in industrial growth, education, and social welfare, continues to face neglect in this Budget. The Budget fails to address the pressing issues specific to Tamil Nadu. The State's demands for adequate allocation to infrastructure projects, agricultural support, and social welfare have not been met. While there is an attempt to focus on infrastructure development at the national level, there is a lack of specific funding for Tamil Nadu's projects.

The Budget does not adequately prioritize education and healthcare, two sectors that are critical to the development of any nation. Tamil Nadu, under the leadership of our leader *Thiru* Stalin, has always valued education and health, with the State consistently investing in these sectors. However, we have seen an alarming reduction in funds for the education sector at the national level. This will lead to a deepening crisis in public education, especially in rural areas where the situation is already dire.

Similarly, while the Government talks about strengthening the healthcare system, but there is little mention of the urgent need to bolster our public healthcare infrastructure. Tamil Nadu, as a key State in the country, requires more investment in its medical colleges, primary healthcare centres, and general hospital infrastructure.

Agriculture remains the backbone of Tamil Nadu's economy. Yet this Budget continues to overlook the plight of our farmers. We demand more direct support for small and medium farmers, as well as for the State's agricultural infrastructure. We strongly believe that the welfare of farmers should be a priority, but sadly this Budget offers little to address the challenges faced by farmers in Tamil Nadu and across the country.

The allocation for irrigation, subsidies for seeds and fertilizers, and the development of cold storage facilities are insufficient and inadequate to meet the needs of our farmers. Without a comprehensive policy that addresses the issue of minimum support prices, debt relief, and the promotion of sustainable farming, this Government will continue to leave our agricultural sector in peril.

While the Government claims to have allocated funds for national infrastructure development, Tamil Nadu continues to face a lack of adequate funding for essential regional infrastructure projects. Projects like the Metro Rail expansion in Chennai, road connectivity improvements in rural areas, and the development of regional airports have been delayed, impacting the overall economic growth of the State. We believe that regional infrastructure development is vital for ensuring equitable growth across the country, and Tamil Nadu's infrastructure needs have been consistently ignored in this Budget.

This Budget presents a façade of progress while failing to address the real issues faced by the people of Tamil Nadu and the broader Indian public. It offers empty promises while neglecting the needs of marginalized and disadvantaged communities. I call upon the Government to rectify these glaring gaps in the Budget, particularly in areas of regional development, education, healthcare, and agriculture.

We demand a fair share for Tamil Nadu, a comprehensive plan to address unemployment, real solutions for our farmers, and a true commitment to social welfare. This Government's Budget is nothing but a blueprint for inequality and inefficiency. As Members of Parliament, we will continue to fight for the rights and dignity of the people of Tamil Nadu and all of India.

Thank you.

डॉ. मन्ना लाल रावत (उदयपुर) : केंद्रीय बजट 2025-26 हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी के VIKSIT BHARAT विकसित भारत@ 2047 की नींव रखने को समर्पित एक विजनरी बजट है, जिसे संक्षिप्त में क्रमशः यूं समझ सकते हैं-

वी - अर्थात विकास, जो सर्वस्पर्शी एवं सर्वव्यापी होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हम सब का प्रयास की राह पर चलते हुए संपूर्ण भारत की समस्याओं का समाधान करने वाले विकास की राह बजट में प्रस्तुत की गई है। कांग्रेस द्वारा अपेक्षित किए गए क्षेत्र के पुराने अनुभव व विगत 10 वर्षों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों की प्रेरणाओं को साथ लेकर वित्त मंत्री जी ने तेजी से बदलते विश्व में हमारी मौलिक रणनीति बजट में प्रस्तुत की है, जो भारत की अपनी सुविचारित रणनीति होगी।

आई - इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसमें एमएसएमई व विनिर्माण के क्षेत्र को साथ लेकर भारत की धाक विश्व में जमाने की रणनीति आकर्षित करती है। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को 5 वर्ष तक अवधि का विस्तार कर स्टार्टअप लाभ प्रदान किए जाने की रणनीति युवाओं को ताकत देती हुई दिखती है। इसके साथ ही व्यवसाय करने की सुगमता को लेकर कई वैधानिक प्रावधान किए हैं और कई कानूनी प्रावधानों को गैर अपराध की सूची में डाला है। एमएसएमई के निवेश एवं कारोबार की सीमा बढ़कर दुगुने से अधिक करना व सूक्ष्म उद्योगों के लिए क्रेडिट कार्ड में 10 लाख तक कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी करने जैसे कई कदम महत्वपूर्ण हैं।

के - अर्थात किसान, कृषि और संबद्ध क्षेत्र। बजट में हमारे अन्नदाताओं के महत्व को समझा है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण है, चाहे रोजगार हो, खाद्य सुरक्षा हो या कृषि भूमि के स्वास्थ्य की रक्षा हो। ये आयाम संबद्ध विषय हैं। इसको लेकर ऑर्गेनिक खेती, दलहन में आत्मनिर्भरता, प्रधानमंत्री। धन-धान्य कृषि योजना, सब्जियों व फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम, राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से तीन की जगह पांच लाख तक ऋण प्राप्त करना जैसे विषयों को बजट में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

एस - अर्थात् सोशल सिक्योरिटी। सोशल सर्विस के साथ ही केंद्रीय बजट में गरीब उपेक्षित युवा मजदूर सभी को सर्वोच्च स्थान देकर गौरव बढ़ाया है। बजट में आदिवासियों के लिए धरती आबा जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना अपने आप में महत्वपूर्ण है। इससे जनजाति क्षेत्र की 63 हजार से अधिक ग्राम ग्रामों की समस्याओं का समाधान होगा। बजट में जनजाति कार्य मंत्रालय को के लिए आवंटित बजट लगभग 15 हजार करोड़ से ग्राम समृद्ध एवं विकसित होंगे। उक्त अतिरिक्त इस योजना के लिए अन्य 16 मंत्रालयों को भी बजट में बड़ी राशि आवंटित की है। सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना एवं अगले 5 वर्षों में 75 हजार मेडिकल शिक्षा में पूंजी की सीटें बढ़ाना अपने आप में बड़ा कदम है। इस बजट में गांव, शहर, गरीब, महिला एवं युवाओं को समुचित स्थान दिया गया है।

आई - अर्थात इनकम टैक्स में राहत व इंप्रोस्ट्रक्चर में बड़ा निवेश। नौकरी वालों को 12 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा एवं इस समूह के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75 हजार तक बढ़ा दिया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए यह सीमा एक लाख होगी। किराया से आय वालों के लिए 6 लाख तक की कर राहत है। इस प्रकार मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी ताकत दी है। इस वर्ग की ताकत को भारतीय इकोनॉमी में महत्वपूर्ण स्थान एवं शक्ति प्रदान की है। इस बचत से अच्छी उपभोक्ता ताकत मिलेगी एवं मध्यम वर्ग के शिक्षा स्वास्थ्य एवं अन्य पारिवारिक बचत व खर्च व्यवस्थाएं सुधरेगी। केंद्रीय बजट में इंप्रोस्ट्रक्चर के लिए राज्यों को

50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के लिए डेढ़ लाख करोड़ के आवंटन सहित सरकारी निजी भागीदारी की कई योजनाएं स्वीकृत की हैं इसमें जल जीवन मिशन और शहरी चुनौती कोष भी महत्वपूर्ण दिखाई देता है।

टी - अर्थात् तकनीकी अनुसंधान, शोध एवं युवाओं को ताकत देता है। आईटी और अन्य तकनीकों को लेकर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एआई के माध्यम से हम विश्व शक्ति बनने जा रहे हैं। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन से 2033 तक पांच स्वदेशी विकसित एसएमआर संचालित करने का प्रस्ताव ऊर्जा क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए बजट में संपूर्ण ताकत दी गई है।

भारत - अर्थात् वैश्विक जिओ पॉलिटिक्स में विपरीत परिस्थितियों होते हुए भी अपनी शक्ति, समृद्धि, अवसर एवं भारत की डेमोग्राफिक ताकत के आधार पर अपनी राह स्वयं बनाने की ताकत श्रीमान प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व व वैश्विक अनुकूलता के निर्माण में निहित है। यह बजट विकसित भारत के लिए है जिससे भारत अपने खोए हुए परम वैभव को प्राप्त करेगा एवं हम सब मन में विश्वास रखें कि स्वतंत्रता के सौवें वर्ष में सन् 1947 में राष्ट्र विकसित भारत की पदवी प्राप्त करेगा। इस हेतु केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण प्रयास किया जा रहे हैं, जिसमें 10 व्यापक क्षेत्र एवं चार ग्रोथ इंजन के माध्यम से संपूर्ण रणनीति बजट में दिखती है। यह तो अभी ट्रेलर है। आगामी समय में रिफॉर्म, परफॉर्म एवं ट्रांसफॉर्म की विस्तृत रणनीतियों की संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते।

माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रणाम, जिन्होंने एक आदिवासी बेटा को इस अमृत कालखंड में राष्ट्रपति बनाया और जनजाति समाज एवं राष्ट्र का गौरव बढ़ाया। साथ ही जनजातियों के सांस्कृतिक आइकॉन एवं राष्ट्र के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस कोशिश किया। कांग्रेस द्वारा अपेक्षित आदिवासियों के, अब विकास के लिए अब तक की बहुत बड़ी योजनाएं 24 हजार करोड़ की पीएम जनमन योजना एवं 80 हजार करोड़ की धरती आबा जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान देकर आदिवासियों के विकास की मजबूत नींव रखी है। इसके लिए सरकार का बहुत-बहुत आभार।

माननीय अटल बिहारी वाजपेई जी जब पीएम थे, तब भारत सरकार में जनजातीय कार्य मंत्रालय व संवैधानिक हक की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कर आदिवासीओं को ताकत दी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ऐतराज रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम साहब जनजातियों व जनजातीय क्षेत्र के समेकित विकास के लिए कई कदम उठा रहे हैं, परन्तु राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र जैसे कई क्षेत्रों में आदिवासी संस्कृति को खत्म कर धर्मांतरण करने, विकास गतिविधियों को रोकने, क्षेत्र में कानून व्यवस्था खराब करने, स्कूलों में अलगाव का विचार फैलाने व युवाओं को पत्थरबाज बनाने के लिए कट्टरपंथी तत्वों के साथ मिलकर हानिकारक इकोसिस्टम सक्रिय है, जिसे जड़ मूल से समाप्त करना भी आवश्यक है।

यह तंत्र अपने राजनीतिक खेती के लिए आदिवासी क्षेत्र को अभाव, गरीब व अराष्ट्रीय विचारों का अविकसित टापू रखना चाहते हैं जो स्पष्टतः असामाजिक, अमानवीय, अनैतिक, असंवैधानिक और अवैधानिक है। यह तंत्र औपनिवेशिक दृष्टिकोण की मार्केटिंग कर रहा है, इसे हतोत्साहित करना सरकार सहित हम सभी का काम है। सारतः केंद्रीय बजट जो कि विकसित भारत

2047 की राह में जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान को क्रमशः जोड़ा है। ताकत दी है। मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।

जय हिंद जय भारत।

डॉ. राजकुमार सांगवान (बागपत) : माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा पेश आम बजट 2025-26 के संबंध में राष्ट्रीय लोक दल की ओर से धन्यवाद ज्ञापन :

(1) आम बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र को विकास का पहला इंजन का दर्जा देकर किसान कल्याण के प्रति सरकार ने प्रतिबद्धता जाहिर की है वह स्वागत योग्य है।

(2) ग्रामीण भारत की आर्थिक तस्वीर बेहतर बनाने में गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी शक्ति को आम बजट से सभी को लाभ मिलेगा।

(3) विकसित भारत का रास्ता चूँकि गाँवों से होकर निकलेगा, इसलिये बजट में ग्रामीण भारत के समृद्ध और रोजगारपरक बनाने का विशेष ख्याल रखा गया है।

(4) इस क्रम में "प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना" के तहत कम पैदावार वाले 100 जिलों में उत्पादन बढ़ाने, फसलों में विविधता लाने के प्रयासों से लेकर किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने, तिलहन / दलहन की पैदावार बढ़ाने, उडान योजना के विस्तार से ग्रामीण उत्पादों को नया बाजार देने, ए.आई. (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) को खेतीबाड़ी से जोड़ने, जैव विविधता को नेशनल जीन बैंक की स्थापना से नया आयाम देने जैसे प्रावधान काफी अहम हैं।

(5) कौशल विकास को तेज गति देने के लिये आम बजट में शिक्षा, कौशल, अनुसंधान और नवाचार में बड़े निवेश की परंपरा जारी रखना कौशल विकास व उद्यमिता को मजबूती प्रदान करेगी। ओ.बी.सी. और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये बजट आवंटन श्रेयस योजना के वास्ते एक सराहनीय कदम है।

(6) इसी क्रम में मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाने के लिये आयकर छूट सीमा 12 लाख तक बढ़ाया जाना, ग्रामीण सड़क योजना / आवास योजना व पीएम स्वनिधि योजना इस बजट ✓ के माध्यम से एक नई ऊँचाई हासिल करेगी। जो हमारे देश की जी.डी.पी. विकास दर बढ़ाने का परिणाम देगी।

(7) राष्ट्रीय लोक दल ने एक ऐसी पार्टी के तौर पर सदैव अपनी पहचान बनाई है जो श्रद्धेय चौ. चरण सिंह व चौ. अजीत सिंह के दिखाये मार्ग व सिद्धांतों पर चलते हुए किसान, कमेरा व समाज के सभी वंचित वर्गों के आत्म-सम्मान व विक्रम की लड़ाई में सघर्षशील है। और आम बजट इन्हीं मूल्यों व लक्ष्यों को प्राप्त करने में कारगर सिद्ध होगा। जिसका हमारी पार्टी स्वागत व सराहना करती है।

श्री जिया उर रहमान (सम्भल) : कहा जाता है कि देश का बजट देश की नई दिशा और दशा तय करता है, मगर जब देश की सियासत में नागरिक को नागरिक की हैसियत नहीं, बल्कि एक खास साम्प्रदायिक चश्मे से देखा जाने लगे तो सब कुछ धुंधला हो जाता है।

शिक्षा किसी भी देश का भविष्य तय करती है। मगर जब कोई सरकार शिक्षा के बजट पर खर्च में ही कटौती करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वह सीधे तौर पर देश के भविष्य को गर्क में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ पूरे देश का एक-एक बच्चा देश के लिए बेहद कीमती है, मगर इस भाजपाई सरकार में, खास तौर पर माइनोंरिटी समुदाय के बच्चों के साथ भेदभाव अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका है।

रंगनाथ मिश्रा आयोग और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने देश में मुसलमानों की बदहाली का एक खाका पेश किया था। सबसे ज्यादा पिछड़ा होने के बावजूद देश की मौजूदा सत्ताधारी भाजपा सरकार मुसलमानों के उत्थान के लिए प्रयास करने की बजाय उस तरक्की के रास्ते में लगातार रुकावट बन रही है।

मदरसों के बजट में लगातार कटौती, मुस्लिम बच्चों की स्कॉलरशिप को कम करना अथवा मुकम्मल तरीके से बंद कर देना, इस सरकार की माइनोंरिटी खास तौर पर मुस्लिम विरोधी नियति में शामिल हो चुका है, जिसका व्यापक असर हमें आए दिन सरकारी सतह पर देखने को भी मिलता है।

आखिर क्या वजह है कि जो मुस्लिम समुदाय शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर बदहाली की पराकाष्ठा पर मौजूद है, उसके उत्थान के लिए इस बजट में कोई भी कदम दिखाई नहीं पड़ता है। रंगनाथ मिश्रा आयोग ने मुसलमानों के शैक्षणिक उत्थान के लिए 10 प्रतिशत और रोजगार के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण का सुझाव दिया था। जिस पर कोई भी अमलीजामा पहनाना तो दूर की बात है, आज की राजनीति में कोई भी उस पर बात करने को भी तैयार नहीं है।

स्कूल ड्रॉप आउट के मामले में मुसलमानों की हालत सबको मालूम है, मगर मजाल है कि सरकार इस मुद्दे पर रती भर भी फिक्रमंद दिखाई दे। अगर आंकड़ों के हिसाब से भी बात करें तो UDISE की रिपोर्ट के मुताबिक 21 लाख से अधिक मुस्लिम बच्चे 2020 से 2022 के दौरान प्राइमरी सतह पर ड्रॉप आउट का शिकार हुए हैं।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसमें से 4 लाख से अधिक बच्चे तो केवल मेरे गृह राज्य यूपी से हैं। मेरा दिल तब और रामगीन हो गया, जब मैंने इन आंकड़ों में 52 प्रतिशत मुस्लिम बच्चियों को शामिल देखा है। मेरे शहर संभल में साक्षरता दर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक केवल 49 प्रतिशत है, मगर सत्ताधारी सरकार उस पर ध्यान देने के बजाय हिन्दू मुसलमान और मंदिर-मस्जिद की राजनीति में व्यस्त होकर मुस्लिम युवाओं को जेल भेजने में व्यस्त है। जब युवाओं की पढ़ाई को आपकी प्राथमिकता हासिल ही नहीं होगी तो देश का भविष्य तो बेरोजगार ही रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखने का दावा करने वाली सरकार मुस्लिम बच्चों को केवल जेलों में देखना पसंद करती है।

एक तरफ तो सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी जी मुस्लिम युवाओं के लिए काफी लच्छेदार भाषण देते हैं, मगर हकीकत ये है कि यही भाजपा सरकार मदरसों की बंद करने तरफ अग्रसर है। अगर एक समय के लिए आपके प्रोपोगेंडा को मान भी लिया जाए तो क्या मोदी सरकार ये बताने का कष्ट करेगी कि मदरसों में तो मुसलमानों के केवल 3 प्रतिशत बच्चे पढ़ते हैं, मगर जो 97 प्रतिशत मुस्लिम बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके उत्थान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? क्या उन 97 प्रतिशत बच्चों को यह सरकार देश का भविष्य नहीं समझती है? आंकड़ें बताते हैं कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 में लगभग 20 लाख बच्चों ने ही मदरसों में दाखिला लिया है, मगर 6.67 करोड़ मुस्लिम बच्चे तो उन्हीं सरकारी अदारों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं, जिसका भाजपा सरकार ने बंटाधार कर रखा है। अगर भाजपा के दिल को तसल्ली नहीं हो रही हो, तो पूर्व प्रोफेसर अरुण सी. मेहता जी की रिपोर्ट 'भारत में मुस्लिम शिक्षा की स्थिति?' को पढ़ सकते हैं।

आज कल मेरा शहर और जिला संभल भाजपाई सरकार की आँखों में खूब खटक रहा है। इस सरकार ने मेरे शहर को प्रोपोगेंडा की नई नर्सरी बना दिया है। यहां स्पष्ट कर दूँ कि हिंदू-मुसलमान के चश्मे के बाहर मेरे संभल में अधिकतर आबादी जनरल श्रेणी में शामिल है। सामान्य श्रेणी के बच्चों के लिए EWS आरक्षण का प्रावधान तो हो चुका है, मगर उसमें उम्र की सीमा और इनकम की पाबंदी अक्सर इन बच्चों के भविष्य को दांव पर लगा देती है।

सरकारी फाइलों में कहने के लिए तो EWS इनकम सर्टिफिकेट आसानी से बन जाता है, मगर हकीकत इससे कोसों दूर है। सामान्य वर्ग के बच्चे तो तहसील ऑफिस में केवल अपने सर्टिफिकेट बनवाने में ही अपनी उम्र का एक बड़ा मरहला गुजार लेते हैं। जब तक उनके हाथों में सर्टिफिकेट बनता है, उनकी उम्र सीमा समाप्त हो चुकी होती है।

अगर सरकार सच में दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी की हितैषी है तो आखिर क्यों वह 90 प्रतिशत पीडीए के बच्चों की स्कॉलरशिप में लगातार कटौती कर रही है? अगर आप ढोंग नहीं कर रहे हैं तो मेरी आपकी सरकार से मांग है कि इन बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए स्कॉलरशिप में कटौती की बजाय प्रति वर्ष 5000 रुपए तक बढ़ाने चाहिए।

जो संभल कल तक अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए पुरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध था, आज उसको हिंदू-मुसलमान की बहस में उलझा दिया गया है। ये इस सरकार की कुनीतियों का ही असर है कि हैंडीक्राफ्ट का उद्योग मेरे शहर में अपनी आखिरी सांसे गिन रहा है। ये कैसी मोदी सरकार की स्वदेशी को प्रमोट करने की नीति है, जिसमें संभल के हैंडीक्राफ्ट और कानपुर के चमड़ा उद्योग को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है।

सोचिए देश की आज़ादी को बरसों बीत चुके हैं, मगर मेरे शहर संभल को आज भी अपनी रेलवे लाइन का शिद्धत से इंतजार है। एक तरफ आप दावा करते हैं कि संभल पुराणिक मान्यताओं वाला शहर है, मगर ट्रांसपोर्ट और रेलवे मार्ग को तरसता मेरा शहर आपसे चीख-चीखकर सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब कल्याण होगा? दिल्ली से पश्चिम बंगाल और असम के मुख्य रूट से अलग अगर संभल से होते हुए एक-एक रेलवे लाइन का प्रावधान किया जाए तो उस व्यस्त मार्ग पर भी थोड़ा लोड कम होगा और मेरे शहर संभल का भी उद्धार हो जाएगा।

आप जितना भी मेड इन इंडिया का दावा कर लीजिए, मगर तल्ख सच्चाई यह है कि भारी इम्पोर्ट ड्यूटी होने की वजह से आज भी विभिन्न शहरों के परंपरागत कारोबार तबाह और बर्बाद होने के कगार पर है। संभल में मौजूदा समय में मेंथा कारोबार बंद होने के मुहाने पर ही खड़ा है। क्या सरकारी बजट इनकी तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित करने का कष्ट करेगा?

जो संभल साक्षरता के मामले में पूरे देश में सबसे पिछड़े पायदानों पर आता है, वहां पर अच्छे स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए सरकार और कितने सालों का इन्तजार करवाएगी? क्या हिन्दू मुसलमान की बहस में संभल में एक विश्वस्तरीय यूनिवर्सिटी का ख्वाब केवल ख्वाब ही रह जाएगा?

संभल में कोई केंद्रीय विद्यालय नहीं होना सरकार की इस इलाके के प्रति प्राथमिकता को उजागर करने के लिए काफी है। आखिर कब संभल की केवल 49 प्रतिशत साक्षरता उचित सरकारी नीतियों के अमल दखल से कम से कम राष्ट्रीय औसत के बराबर तो पहुंचेगी?

कल तक माइनोंरिटी स्टेटस की वजह से विभिन्न समुदाय कहस तौर पर मुसलमान खुद से कुछ शैक्षणिक संस्थानों को खोलने और अच्छे से चलाने की कोशिश करते थे, मगर इस भाजपा सरकार ने उसको भी अपनी साम्प्रदायिक राजनीति के भेंट चढ़ाने का फैसला कर लिया है। एक तरफ आप मुसलमानों और पिछड़ों के शैक्षणिक उत्थान के लिए खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर जब वह समुदाय खुद तरक्की के नए आयाम छूना चाहता है तो भी आप उसमें रुकावट बन रहे हैं।

हर बर्बादी और पिछड़ेपन से निकलने के रास्ते मौजूद होते हैं, बस जरूरत ये है कि उसके लिए ईमानदारी से कोशिश की जाए। जब सरकारी रिपोर्ट इस बात को उजागर कर चुकी है कि देश का मुसलमान तो दलित से भी बदतर हालत में है तो इस सरकार को अपने 'सबका साथ सबका विकास' के कथन को अमलीजामा पहनाकर ईमानदारी से कोशिश करने की जरूरत है।

इसी देश ने देखा है कि आज से 30-40 साल पहले केरल का जो मालाबार का इलाका पिछड़ेपन में एक मिसाल होता तो उचित सरकारी नीतियों और समुदाय की अपनी कोशिशों की वजह से वह अब तरक्की की नयी राहों पर अग्रसर है। याद रखें ये इंकलाब अचानक से नहीं आया है, सबका अपना एक अलग योगदान रहा है।

अभी के समय में केरल में मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकारी जॉब में 12 प्रतिशत आरक्षण और प्रोफेशनल उच्च शिक्षा में 8 प्रतिशत आरक्षण ने वहां के हालात को तब्दील करने में अहम भूमिका निभाई है। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो काम उधर हुआ है कुछ वैसा ही मेरे गृह राज्य उत्तर प्रदेश में भी होगा।

मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम बच्चों की दुश्मनी में पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी भाजपा सरकार तेलंगाना के मॉडल से भी सीख ले सकती है। जहां पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण मुसलमानों को शिक्षा और रोजगार के लिए दिया गया है। ज्ञात रहे ये आरक्षण कहीं भी धर्म की बुनियाद पर नहीं दिया गया है, बल्कि पिछड़ेपन के आधार पर पीडीए की कल्पना के तहत दिया गया है।

आखिर क्या वजह है कि जो पिछड़े, दलित और माइनोरिटी देश की आबादी का 90 प्रतिशत है, वे शिक्षा, रोजगार और कारोबार के मामले में कभी 30 प्रतिशत भी नहीं पहुंच पाते हैं। देश के संसाधनों का ऐसा तुष्टिकरण केवल भाजपाई राज में ही इस चरम सीमा पर पहुंचा है।

मैं उम्मीद करता हूँ कि मोदी सरकार अपने हिंदू मुसलमान के साम्प्रदायिक चश्मे को उतार कर सभी समाजों को एक साथ लेकर उनके उत्थान को यकीनी बनाने का काम करेगी।

SHRI VIJAYAKUMAR ALIAS VIJAY VASANTH (KANYAKUMARI): I would like to express my views on Union Budget for the year 2025-26, presented by the Government. While the Finance Minister's speech was filled with grand promises and statistics, I am deeply concerned that this Budget fails to address the real issues facing the common people of our country, especially in the State of Tamil Nadu. While some allocations appear promising on the surface, it is crucial that we examine whether they translate into meaningful change for the people who need it most. Let us address the urgent concerns, both at the national level and for my constituency that have been ignored or inadequately addressed by this Budget.

Infrastructure concerns in Tamil Nadu, hon. Speaker, one of the most glaring issues is the continued delay in infrastructure projects in Tamil Nadu, particularly in road transport and railways. The National Highways project connecting Kalliyakavilai to Kanyakumari, a crucial link for regional development and economic growth, remains stuck in slow progress despite its immense importance. There is no clear timeline for completion, and this disruption continues to affect local commuting and economic activities. Similarly, our railway infrastructure continues to suffer from delays. Crucial projects such as rail electrification, track doubling, and the expansion of the suburban network are still pending. These delays impede local travel and freight transportation, both of which are critical to the State's economy. Moreover, the coastal erosion problem in Tamil Nadu, especially in districts like Kanyakumari, threatens the livelihoods of fishermen and farmers. Yet, there has been little attention to this matter in the national discourse. Coastal protection measures are urgently needed to protect these vulnerable communities.

Agriculture and fishermen's welfare, the agricultural sector in Tamil Nadu, particularly in coastal areas, remains underdeveloped due to inadequate infrastructure. Farmers and fishermen continue to struggle with poor transportation options for moving their produce to markets. Without improvements in rural and coastal transport infrastructure, the livelihoods of millions of people will continue to suffer. The

fishermen's communities, already threatened by coastal erosion, need immediate support. Their lives and work are under constant threat, and the Government must take swift action to safeguard their communities through coastal protection measures.

Impact of inflation and rising prices, the rising prices of essential goods, including milk, vegetables, cooking oils, and fuel, are severely affecting the common man. The recent rise in the prices of milk and fuel has increased transportation costs and grocery prices. Despite the Government's promises to control inflation, the reality is that little has been done to address this issue. Real wages remain stagnant, and high taxes on essentials are placing an even greater burden on ordinary citizens. The Government must take immediate action to control inflation, regulate the prices of essential goods, and provide relief to middle and low-income families who are struggling to make ends meet.

National fiscal concerns: expenditure and deficits, moving to national concerns, the total expenditure for 2025-26 is projected to be Rs 50,65,345 crore, which represents an increase of 7.4 per cent over the revised estimates of 2024-25. However, a significant portion of this expenditure – 25 per cent is dedicated to servicing interest payments, which alone amount to Rs. 12.66 lakh crore. This heavy reliance on debt is concerning, as it limits the Government's ability to make essential investments in critical sectors such as healthcare, education, and infrastructure. The fiscal deficit target for 2025-26 stands at 4.4 per cent of GDP, which, while lower than last year's 4.8 per cent, still raises alarms about the country's growing debt burden. How long can we continue to rely on borrowing to fund our expenditures?

Revenue receipts and tax proposals, on the revenue front, the Government has projected an 11 per cent growth in tax receipts, but this will place a greater burden on the common people, especially those in the lower and middle-income brackets. The 100 per cent rebate for incomes up to Rs. 12 lakh, while a short-term relief for some, will cost the exchequer nearly Rs. 1 lakh crore in forgone revenue. Meanwhile, the Government continues to rely heavily on indirect taxes, particularly from GST, further burdening the poor and middle class.

Underfunding of welfare schemes, the Budget continues to underfund essential welfare schemes. Programmes such as MGNREGS and PM-KISAN, which provide much-needed support to rural communities, remain inadequately funded. Allocations for critical areas like rural infrastructure, LPG

subsidies, and essential services are insufficient and fail to address the needs of the most vulnerable sections of society. The absence of adequate funding for marginalized communities, such as the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, only exacerbates existing inequalities. While the Government has made some announcements for these communities, the allocations remain far below what is necessary to address systemic poverty and discrimination.

Healthcare and education, the allocations for healthcare, education, and infrastructure also remain insufficient. The healthcare budget of Rs. 99,859 crore for 2025-26 is inadequate to meet the growing demand for services, especially in rural areas. The lack of adequate funding for healthcare leaves millions of rural families without proper medical access, exacerbating their already precarious situation. Similarly, the education sector is underfunded, and much more needs to be done to improve access to quality education, particularly in rural areas. This Budget does not adequately address the long-term needs of our country's future generations.

Request for specific allocations to my Kanyakumari constituency. In light of these challenges, I urge the Government to consider the following funding initiatives for my constituency in Tamil Nadu: Development of tourism in Kanyakumari to boost the local economy; establishment of a Fishermen Welfare Fund to support coastal communities; funding for the Rubber Research Station to assist the agricultural sector; creation of a Cancer Research Institute to strengthen healthcare infrastructure; improvement of railway infrastructure to enhance connectivity; strengthening of road and transport infrastructure; upgrading ESI hospitals to ensure better healthcare access; and establishment of a Greenfield Airport to improve regional connectivity.

While the Government continues to present grand visions for the future, the reality on the ground remains far from ideal. Infrastructure delays, inadequate attention to agriculture and fisheries, rising inflation, and underfunded welfare schemes are real issues affecting millions of people. The Budget presented by the Government fails to provide tangible solutions to these problems.

I urge the Finance Minister to revisit this Budget and ensure that it serves the interests of the people and addresses the critical issues facing the country. We need a Budget that translates into real benefits for every citizen, particularly those who have been left behind in the race for growth and

prosperity. The people of Tamil Nadu and the entire nation deserve better ? a budget that addresses the pressing challenges we face and invests in a future that is equitable, sustainable, and just. Thank you.

CAPTAIN VIRIATO FERNANDES (SOUTH GOA): I would like to submit my views with respect to the Budget 2025-2026 that was presented by the Hon. Minister of Finance on 01 February, 2025.

I place my objections to the provisions in the Budget on only certain subjects like agriculture, education, defence, rural development, etc. and I would also mention the reasons for the same in the succeeding paragraphs.

As regards agriculture, it is very sad that the agricultural sector has been given a raw deal in the present Budget. Despite numerous requests from Opposition Parties as well as organizations across the country to give the farmers their due, the Budget does not give any solace to the hardworking farmers across the country. The repeated promises by the Prime Minister of doubling the income of farmers still remains a hollow promise and the farmers continue to suffer under the prevailing difficult conditions in the country with no legal MSP being granted to the farmers.

As regards education, the allocation for education is far below the National Education Policy's (NEP) recommendation. The Budget also did not adequately address the financial concerns of higher education. The actual expenditure for 2023-2024 was 10 per cent more than the 2025-2026 Budget Estimates. Further, the grand announcement of increasing the medical seats to 10,000 is far-fetched because there is already a shortage of faculty members to teach in various existing medical colleges. It is recommended that the Government instead should focus on improving the existing infrastructure of the medical colleges and improving the availability of faculty.

As regards defence, the capital allocation for the Defence Ministry is a meagre 4.65 per cent increase to Rs. 1.8 lakh crore from the previous estimates, and if one takes into account the inflation and the currency fluctuations, as the armed forces are likely to return Rs. 12,500 crore from the Budget Estimates to the Revised Estimates of 2024-2025. Hence there is an injustice which has been done to the Defence forces, especially considering the fact that we are having hostile neighbours.

As regards rural development, rural India has not been given its due despite the biggest labour workforce to drive the economy comes from the rural areas of the country. The allocation for flagship rural

employment scheme of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) was Rs. 86,000 crore, which is the same as the last year. This allocation in the Budget will not be enough to address the complex challenges faced by rural India, particularly considering factors like infrastructure needs, income disparities, and the scale of poverty in rural areas, improvements in targeted allocation and efficient utilization of funds that are crucial for impactful rural development. This allocation will not be adequate to tackle the wide range of issues in rural areas including inadequate infrastructure, healthcare access, and skill development.

Thank you.

***m83 SHRI CHAMALA KIRAN KUMAR REDDY (BHONGIR):** I would like to place my views on the Union Budget for the year 2025-2026.

First of all, I can proudly say that our Telangana State under the able and dynamic leadership of our hon. Chief Minister of Telangana, Shri Anumula Revanth Reddy garu has registered the Gross State Domestic Product (GSDP) of Telangana for 2024-25 (at current prices) which is estimated to be about Rs.16.5 lakh crore, which is an increase of about 12.5 per cent over 2023-24.

Presently, our Telangana budget proposed Rs.710,000 crore for development of Hyderabad, Rs.73,065 crore to Greater Hyderabad Municipal Corporation, Rs.7500 crore to Hyderabad Metropolitan Development Authority, and Rs.3,385 crore to Metro Water Works, also proposed Rs.7200 crore to HYDRAA, Rs.7100 crore for extension of Metro to Airport, Rs.200 crore for ORR, Rs.500 crore for Hyderabad Metro Rail, Rs.7500 crore for extension of Metro to Old City.

The cost-effective suburban train network of MMTS in Hyderabad to get Rs.750 crore from the Budget. And, for our hon. Chief Minister, A. Revanth Reddy's ambitious Musi Riverfront project, Telangana Budget 2024-25 proposes Rs.1,500 crore for which I request the Union Government to allocate matching grants or one-time grant to the Government of Telangana to take up such above said all important developmental projects particularly in and around Hyderabad to make it World-Class City.

The Government of Telangana with a Vision and Direction also identified some key areas which are like, agriculture - Telangana has allocated 20.2 per cent of its total expenditure towards agriculture, which is higher than the average expenditure on agriculture by States, that is, 5.9 per cent; Urban Development

- Telangana has allocated 4.2 per cent of its expenditure towards urban development. This is higher than the average allocation towards urban development by States, that is, 3.4 per cent; Energy - Telangana has allocated 6.4 per cent of its total expenditure towards energy, which is higher than the average allocation by States, that is, 4.7 per cent; Traffic ? This is one of the major problems in Hyderabad. Strengthening the public transport network and Metro Rail is a solution. Government, post re-examining the second phase of Metro Rail, modified the proposals.

All the above said proposals of the Government of Telangana State require allocation of funds or matching grants from Centre also. It is stated that the Union Government showed an indifferent attitude towards Telangana despite repeated requests, and the Centre should seriously consider the contribution to Telangana while allocating funds. The hon. Finance Minister reduced the Union Budget to an election-centric Delhi and Bihar budget and people are not happy in Telangana State and Telangana people are saying, overall it is a worst and *bekar* Budget.

The BJP should give funds, not just *akshinthalu* from Ayodhya, and the Centre is showing step-motherly treatment and hatred towards Telangana people despite electing eight BJP MPs from Telangana State and among them two are in the Modi Cabinet. We do not know what they are doing at the Centre?

For the second successive year, Telangana got short shrift in the Union Budget for 2025-26 with almost zero allocation for any of the projects for which the State Government had urged central funding many times till date but there is no proper response to the Telangana State. But to our utter surprise, it is seen that though the Telangana State's share in Centre GDP is 5 per cent, funds to Telangana State not allocated proportionately. Telangana is the frontrunner with 88 per cent in own tax revenue (OTR) between April - November last year followed by Karnataka and Haryana at 86 per cent each, as per Economic Survey 2024-25.

The Government of Telangana has set up Skill University in Hyderabad and it needs financial support in the form of grant-in-aid and others which will help in setting up of Start-ups to boost the employment and enterprises which will make ?Make in India? scheme successful. Otherwise, people's talent in all the fields will go waste and in vain.

The Government of India is collecting different types of Cess and Surcharges but it is not sharing with the States including Telangana proportionately. The Government of Telangana has asked the 16th Finance Commission to increase the State's share in Central taxes from 41 per cent to 50 per cent to address the regional disparities and support local developmental projects in Telangana State. But there is no response. I do not know why?

Our hon. Chief Minister of Telangana has met the hon. Prime Minister and other Union Ministers concerned, and pressed the demand to take up and sanction various projects. But there is no proper response from the Centre.

The Government of Telangana requested approval for the Metro Rail Phase-II project, which includes six new corridors, costing Rs.24,269 crore. For Metro Rail Phase-2 project in Telangana State which is identified for 76.4 km expansion in Hyderabad, the Government of Telangana has requested for allocation of Centre's share as Rs.17.212 crore to meet the needs of the City like Hyderabad but it is seen that the Centre has not allocated even a single rupee in the Budget.

The Government of Telangana has requested the Centre to allocate and release funds for underground drainage system but there is no mention of it in Budget.

The Government of Telangana has urged Centre to sanction 20 lakh houses to the State under Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0. But there is no clarity how many houses sanctioned.

Our State also sought financial support of Total Rs.56,139 crore for various projects, including the Metro Rail Phase-II expansion, Musi river rejuvenation, and underground drainage networks for GHMC and surrounding towns.

By bifurcating each proposal, I can say that considering the Telangana's significant urban population, making a strong case for the housing project, the Government of Telangana plans to launch the Indiramma housing scheme targeting 4.5 lakh units in its first phase, offering Rs.5 lakh assistance to eligible beneficiaries for which the funding from the Centre is immediately required.

Additionally, he asked for Rs.10,000 crore for the Musi river project and funding. The hon. Chief Minister of Telangana also sought approvals for the comprehensive sewerage master plan (CSMP), taken

at a cost of Rs.17,212 crore for the sewerage network in Hyderabad city and 27 nearby urban bodies and Rs.4,170 crore for a comprehensive underground drainage network in Warangal.

Further, the Telangana CM pressed for one lakh solar pumps under the PM Kusum scheme for tribal farmers and 2,500 MW of power allocation from the Centre. The Government of Telangana also appealed for the inclusion of Telangana discoms in the revamped distribution sector scheme.

The Centre should acknowledge the Telangana State's contribution to India's goal of becoming a \$5 trillion economy. For this, the Government of Telangana also identified the following programmes in the State which requires financial allocations from the Centre which are most important for the overall growth and development of Telangana State.

With regard to financial assistance to farm labourers, a scheme will be launched to provide Rs.12,000 annually to agricultural labourers. Four housing, assistance will be offered under the Indiramma Housing Scheme. Financial assistance of Rs.5 lakh will be offered for construction. SC and ST beneficiaries will be given Rs.6,00,000. Under this scheme, 4.5 lakh houses will be constructed with at least 3,500 houses per assembly constituency.

In terms of women entrepreneurship, under the Indira Mahila Shakthi Programme, 63 lakh women will be trained in different skills to become entrepreneurs. an amount of Rs.1,00,000 crore will be secured for the scheme.

So far as infrastructure is concerned, about 348 kms of Telangana State roads will be upgraded in order to be declared as national highways. A regional ring road will be developed at the cost of Rs.26,502 crore for which funds need to be allocated and released to complete the project.

As the House is well aware, there is need to develop all States in the country but not happening under the present Government. Due to non-availability of work in North India, all the people are migrating to Southern States including Telangana for their livelihood and we are proud to say that all the people from all over the country are leading a happy and healthy life in Telangana State and we love all of them and treat equally.

All 5 Southern States have expected more allocations but Centre ignored. For Andhra Pradesh, I can say, the Government has allocated some funds which is happy to note as it is our neighbouring State

but, at the same time, I am very much sorry to say that it has completely neglected Telangana State leaving us in lurch.

With regard to inflation, the Central Bank revised its inflation forecast for FY25 to 4.8 per cent, up from the previous estimate of 4.5 per cent but in actuality it is severely facing the challenges in taming inflation, driven by volatile food prices, global geopolitical tensions, and supply-side disruptions, which is a grave concern for all of us.

Recently, we are seeing in the news that Indians are being deported from USA for various reasons. I also want to highlight the plight of the students who hail from Telangana and Andhra Pradesh in USA, and other countries. Hundreds of Telugu students from Andhra Pradesh and Telangana who are undergoing studies in the higher education mainly in the engineering and medical stream are living in fear and there are apprehensions that they have to leave for India particularly from USA due to the various reasons. Now their studies and future plans have been jeopardized because of such an unexpected situation. Hence, I request the hon. Minister of Finance in consultation with hon. Minister of External Affairs and other concerned agencies to kindly intervene in the matter and allocate a special package to bring back them to India or to assist them in every possible manner.

In addition to this, even the job holders in USA and other countries are facing umpteen problems but the Centre is not paying any attention to come to their rescue which is unfortunate. I am also unable to understand why the Centre is not coming forward to set up one school in one district as a policy measure including KV, JNV and Sainik schools in Telangana State thereby denying affordable quality education to the children of Telangana? All parents cannot afford expensive public schools for their children. There is a saying, "A child without education is like a bird without wings." In a way, the Centre is not letting the children of Telangana grow and spread their wings.

As we all know, Gujarat International Finance Tech City (GIFT) has been constructed in Gujarat and the Centre also proposes to set up foreign universities and Arbitration Centre in the GIFT city in Gujarat, which we welcome all. But why the Centre ignored Telangana in setting up such GIFT city to have good courses in finance management, fintech, science, technology, engineering, maths, etc. so that the Telangana students can be benefitted more.

It is a known fact that about 15 lakh vacancies are lying vacant in various Central Government related jobs across the country, but the Centre has not initiated any steps to fill the vacant jobs and provoking innocent job seekers to fight against the State Governments including Telangana.

Since 2014, when PM Modi came to power and also promise of provision of job to 2 crore people per year has not materialized and gone, they are now due to give 20 crore jobs in the last 10 years and there is no answer from the Government to this burning unemployment issue.

The PM Modi Government rolled out 5G services but till now 4G has not properly been implemented in many States and MTNL/BSNL subscribers are suffering heavily. This Government is encouraging only private telecom players neglecting MTNL/BSNL. Why?

In the Budget, the hon. Finance Minister mentions that PM Gatishakti will turn the destiny of the country's financial situation to the fast track in future. But in reality, people have no hopes. It is astonishing to see that we have already celebrated 75 years of 'Azadi ka Amrit Mahotsav' but there is no azadi to live and the Government is suppressing the SCs, STs, BCs and other minority people in the country and they are leading their life in extreme panic.

Now, I would take up the National Express Highways in Telangana. The Government promised to complete various projects including the Hyderabad-Indore Express highway via Nanded-Akola having 713 km by 2025. Solapur to Kurnool Express highway having 318 km to complete by 2025 via Gadwal, Raichur, Gulbarga. Hyderabad to Visakhapatnam Express highway having 221 km - Hyderabad to Suryapet by developing Suryapet to Rajahmundry highway via Sattupally and Khammam by converting it to 4 lane road to Visakhapatnam to complete by 2025.

Hyderabad to Raipur expressway having 330 km via Hyd-Warangal-Dantewada-Raipur to complete by Nagpur-Vijayawada Expressway via Khammam, Warangal, Karimnagar, Chandrapur having 453 km to complete by 2025.

I want to ask how many above said express highway projects and funds sanctioned to Telangana for expanding in 2-4-6-8 lanes as per the traffic demand and how many completed because the above express highway road projects have great demand in passenger and vehicle traffic and these projects are very much essential in the interests of the passengers?

I would also like to remind hereby that the PM Modi Government set the target to double the income of farmers by 2022 which is also a false promise and no sincere efforts have been made by the Government to achieve this goal till date. This Government is not sincere and interested to work for the welfare of farmers who are the backbone of our country.

It seems, the income of the farmers halved instead of making it double. Why? In the Budget, Kisan Drones have been proposed and what is the allocation for Telangana and how many farmers will be benefitted?

Due to improper policies of the Government, banking sector is not coming forward to offer loans generously to the common man and small units, and many companies, Startups and small businesses have closed their units since 2014 and it is increasing every year. I do not know why the Government is not taking proper steps to encourage small businessmen in the country.

In fact, with much constraints, I am to say that many developmental projects pertaining to Telangana have been submitted by our hon. Chief Minister of Telangana, Shri Anumula Revanth Reddy garu to the hon. Prime Minister and also to the Ministers concerned but the Centre has not paid any heed to clear the pending projects and funds.

Overall, the Centre has meted out great injustice and shown utter discrimination to Telangana State and its people which is completely deplorable. We strongly demand the Centre to end discriminatory policy and step-motherly treatment towards Telangana State.

Despite non-cooperation from Centre, I can firmly say that under the able and dynamic leadership of our hon. Chief Minister, we take and assure the people of Telangana that our State will progress rapidly and compete with other States and become No.1 in future.

We also object the proposal of Strong Centre and Weak States which the present Government is adopting. As we complete the first quarter of the 21st Century, and also the Government says our economy is the fastest-growing among all major global economies and the country's development track record of the past 10 years but it seems structural reforms have not drawn global attention and we can confidently say and visible that India's capability and potential has not grown in this period compared to the UPA I and UPA II regime under the Prime Ministership of our beloved Party Leader Dr. Manmohan

Singh Ji. In this prevailing situation, one cannot see the much difference in next five years to realize 'Sabka Vikas', because the engine at the Centre is not working properly and will go for repair to the shed at any time.

The hon. Finance Minister has recalled the words of the great Telugu poet and playwright Gurajada Appa Rao who had said, 'Desamante Matti Kaadoi, Desamante Manushuloi; meaning, 'A country is not just its soil, a country is its people', but it seems Desamante Bihar and this Budget has been prepared keeping in view of Bihar elections which is an irony and making mockery.

Recently, our Deputy CM, Government of Telangana has also sought the Union Minister Kishan Reddy's help to Telangana in securing maximum Central assistance to various projects all estimated at Rs.71.63 lakh crore. But it seems till date there is no response.

In the Budget, I can point out some projects pertaining to Telangana. There is no mention of declaring National Project Status for Palamuru-Ranga Reddy Lift Irrigation Project. The Government of Telangana also demanded the Union Government to clear the pending Special Assistance dues under the Backward Regions Grant Fund (BRGF) and seek an extension of the scheme by five more years.

There are many issues pending including those related to the Andhra Pradesh Reorganisation Act (APRA). The Special Assistance for backward regions was mentioned in Section 94 (2) of the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. The Centre released Rs.2,250 crore for 2015-16 to 2018-19 and 2020-21 at Rs.450 crore per year for the development of nine erstwhile districts of the State. The utilisation certificates were also submitted to the Union Government. Now, as the Congress MP I firmly insist that the Centre should release the pending dues of Rs.1,800 crore for 2019-20, 2021-22, 2022-23 and 2023-24.

Also pending issues of the AP Reorganisation Act like public debt, which has not been settled till date. I can also say -As per Section 54(1) of the AP Reorganisation Act, 'all liabilities on account of public debt and public account of the existing State of Andhra Pradesh, outstanding immediately before the appointed day shall be apportioned based on population ratio of the Successor States unless a different mode of apportionment is provided under the Provision of this Act.

The total amount divisible under public debt is identified as Rs.17,666.66 crore, out of which Rs.8,737.29 crore was apportioned on a population basis and the balance amount of Rs.8,929.37 crore pertaining to 15 externally aided projects (EAPs) are yet to be apportioned. The Government of AP proposed the apportionment of four EAPs on a location basis, nine EAPs on a utilisation basis and the remaining two based on population ratio. The Telangana Government's stand is that the apportionment of all EAPs shall be on the basis of population ratio.

There are other key issues pending with the Union Government as per AP State Re-organisation. Establishment of a tribal university in Mulugu District, establishment of integrated steel plant in Khammam, establishment of a rail coach factory in Kazipet, reimbursement of Rs 408.49 crore by AP Government towards expenditure incurred by Telangana in respect of common institutions, reimbursement of Rs.208.24 crore by AP Government in respect of Commercial Tax department, division of Schedule IX and X institutions, issues related to power dues, expansion and financial assistance for Ramagundam Fertiliser Unit, setting up of Handloom Park in Hanamakonda, Rail Neer production unit in Telangana, setting up of IIM in Telangana.

Some other important issues I would like to raise pertaining to Telangana State. Grants to Central Autonomous Bodies in Telangana State requires Rs.352.81 crore Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad, Rs.28 crore for Indian National Centre for Ocean for Information Services, Rs.10.84 crore for National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, Hyderabad, Rs.86.75 crore for International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials, Hyderabad, Rs.16.78 crore for National Fisheries Development Board, Rs.56 crore for Centre for DNA Finger Printing and Diagnostics, Hyderabad, Rs.56 crore for National Institute of Animal Biotechnology, Hyderabad.

Also, allocation of funds for Public Enterprises in Telangana State is Rs.1,600 crore for Singareni Coal, Rs.60 crore for Mishra Dhatu Nigam Ltd., Rs.122 crore for Support to IIT Hyderabad (EAP), Rs.1 crore for creation of capital assets in Salarjung Museum.

Our Government of Telangana State requested the Central Government to communicate net borrowing ceilings along side tax devolution figures with removal of conditionalities on borrowings will allow a greater fiscal space to take up more and more developmental projects in Telangana.

But the Centre thinks the country means only 18 States where BJP is ruling and not considering the demands of Telangana State. In this Budget, the hon. Minister of Finance proposed development measures on Garib, Youth, Annadata and Nari but here I can say Garib becomes more and more Garib, Majority youth becomes more and more unemployed, Annadata committing suicides and Nari are suffering very much in the society a lot. The budget train derailed and all four compartments have failed and laid on the way side.

First big disappointment is for farmers (kisan). What are farmers asking? They are demanding four answers - 1. MSP as a legal guarantee, 2. Farm loan waiver, 3. Inflation indexation of PM Kisan payouts, and 4. Reforms to PM Fasal Bima Yojana.

In the Budget, the hon. Finance Minister did not give a single sentence response of these four issues. Even recommendations of Parl. Standing Committee on Agriculture was totally ignored. Farmers are happy in Telangana in last 12 months because we gave Loan Waiver of Rs 2 lakhs, giving MSP + Bonus on crops like fine rice, and started Rythu Bharosa, and also giving 24-by-7 free electricity. What does Modi give?

The PM Dhan-Dhaanya Krishi Yojana' they announced and say they will partner with states. Any discussion with states before budget? No. Is there anything for high productivity districts and states - nothing.

They talk of aatma-nirbhar in daal, pulses, tur, masoor, urad. This was the opportunity for complete Aamta-Nirbhar of India in food sector in a big way. We should have connected agriculture thinking in budget with climate change problems, water, power, loans, loan waiver, MSP, bonus, problems of landless labour, problem of protein deficiency, food export opportunities, use of new technology, drones, irrigation.

They have decided to give credit cards so they can put Modi picture and send to farmers. They will charge all hidden interest rate on farmers. Very poor budget for farmers. They do not even understand that fishermen, dairy, horticulture, aqua culture, marine produce, have all unique issues.

Rating of budget for Farmers - 1/10. Poor people hoped they will come out of poverty. But last 10 years, and now 11th year, Modi ji has done nothing for them. Not rural poverty nor urban poverty.

Most amazing thing for rural poor was MNREGA we introduced - Smt Sonia Gandhi and Dr Manmohan Singh. What has been contribution of Modi all these years? Urban poor, including gig workers like Swiggy, Zomato, Uber, drivers and delivery boys - you talk big and will give nothing. Health Insurance to gig workers under (PM Jan Arogya Yojana) will not help them at all. Accident insurance, and other issues of their ignored.

Urban poor also included domestic workers (cooks, cleaners, gardeners, security guards) - not even one word about them. Housing is a big thing for poor people. We have done so much for housing - now we are giving Indiramma illu - Modi ji is not caring for building houses or giving money for poor in villages, towns or cities. So, rating of budget for garib people is 1/10.

Women across India must be in tears because while a woman FM presented Budget, there is nothing, absolutely nothing, for them. Not as girl child, or their education or health, not for girl students, or girl sportsmen, not as young ladies in work force or unemployed, not for women entrepreneurs, not for mothers, not for lady senior citizens.

This is the most disappointing Budget. Compare with how much we in Telangana do. How many programs we have for women - free bus, gas cylinder, power, housing, skills, education. Telangana State is giving a cylinder for Rs.500 for poor people. Why Centre is not giving Rs.500 per cylinder for poor people particularly for BPL families. For this rating of Budget for Poor is 0.5 / 10.

Yuva are still reading the budget to see if there is anything for them. If you want to create employment, you have to do big reforms in MSME (micro, small and medium sector) but they were totally ignored. All she spoke about was simplifying KYR norms on a portal. Number of doctors, medical colleges, nursing colleges, dental colleges we need is very high. But she has put a goal of 75,000 new seats in next 5 years. Is this how we will compete with China. Today, it is age of Robotics, Artificial Intelligence, Machine Learning, Rockets and Satellites. The education and skilling needs for youth are completely changing. This budget will leave our youth of India far behind the world.

We need to create two crore jobs every year. That was Modi ji promise before 2014. Nirmala ji did not even speak one word about jobs and employment creation. So, rating of the Budget for yuva is 1/10.

Biggest disappointment for middle classes. Here they are only looking for headlines. What is inflation rate and how much relief you give? For 10 years middle classes are struggling. For good housing. For good urban infrastructure. For better jobs. For improvement in healthcare facilities. For good transport. For good houses.

The Recent Budget also specified four powerful engines which are: Agriculture-Contribution of agriculture to GDP is around 3 to 4 per cent and steps may be taken to reach at least more than 5 per cent, and MSMEs not getting capital fund to come out from losses, Investment is very much less in every sector, and Exports are miserable.

The present Budget aims to initiate transformative reforms across six domains but I can say - 1) Taxation method is suffering in all the sectors from employees to businessmen and need reforms to protect the common man. 2) Power Sector is not improving. 3) Urban Development is only in the name and actually there is no development in urban areas and most of the cities and towns in urban areas are becoming slum areas. 4) Mining sector is in crises and need reforms.

Agriculture as the 1st Engine - I would like to state Telangana State grows 27 important crops in Kharif and Rabi seasons put together covering an area of about 53.51 lakh hectare. And motivated by the success of the Aspirational Districts Programme, I request the Union Government to undertake a 'Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana' in partnership with Telangana which has large scope with an aim to (1) enhance agricultural productivity, (2) adopt crop diversification and sustainable agriculture practices, (3) augment post-harvest storage at the panchayat and block level, (4) improve irrigation facilities, and (5) facilitate availability of long-term and short-term credit. I am to say that the total farming land in Telangana is 1.43 crore acres and the number of farmers in the state stood at 58.33 lakh. Around 55 per cent of population in Telangana make a living from agriculture and I request the Government to consider Telangana on priority to help Telangana farmers and majority are small and marginal farmers.

I also request the Government to devise various programmes to focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families who requires technical and financial assistance from multilateral development banks.

Centre of Excellence in AI for Education - I am happy to note that the Government had announced setting up of a Centre of Excellence in Artificial Intelligence for education with a total outlay of Rs.500 crore and I request the Government to set up such a Centre in Hyderabad for which I also assure on the floor of the House that the Government of Telangana will cooperate in all manner including land allotment, single window clearances, etc.

Expansion of medical education - in the Budget, I am happy to note that in the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals, towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years and I request the Centre to consider our Telangana for more allocation of seats.

Day Care Cancer Centres in all District Hospitals In the Budget, I am happy to note that the Government will facilitate setting up of Day Care Cancer Centres in all district hospitals in the next 3 years and 200 Centres will be established in 2025-26 and I request the Government to set up such Centres of at least 25 in Telangana in 2025-26.

Urban Challenge Fund, I am happy to note that the Government will set up an Urban Challenge Fund of Rs.1 lakh crore to implement the proposals for 'Cities as Growth Hubs', 'Creative Redevelopment of Cities' and 'Water and Sanitation' I am also happy to note that this fund will finance up to 25 per cent of the cost of bankable projects with a stipulation that at least 50 per cent of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs and an allocation of Rs.10,000 crore is proposed for 2025-26 and I request the Government to consider the proposals of Government of Telangana in developing tier 2 and tier 3 cities like Warangal, Nalgonda, Bhongir, Khammam, which have large scope for setting up of new developmental projects in the State.

UDAN - Regional Connectivity Scheme - From the Budget, I am happy to note that UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel and has connected 88 airports and operationalized 619 routes and inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and North East region districts and I request the Government to consider re-opening of Warangal Airport, setting up of new airport/helipads in Nizamabad, Khammam, and Bhongir so that there will be 12 to 15 per cent growth in civil aviation sector.

I once again state that JD(U) has only 12 seats in Lok Sabha and got more allocations and given bonanza to Bihar by Centre due to coming elections of Bihar State which is not good for the people of this country.

In the Budget, I am happy to note that top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode and Telangana has lot of scope in developing tourism considering the natural and eco beauty of Khammam area for facilitating employment-led growth. Warehousing facility for air cargo I request the Centre to develop Shamshabad area in 33 Hyderabad as the international hub by setting up of air cargo handling unit with warehousing facility as it has large scope for exports.

In the Budget, with deep pain and grief, I am to oppose the proposal of raising FDI limit for the insurance sector from 74 to 100 per cent and with this LIC having the revenue in 2024 as 8 lakh 41 thousand 982 crores will be the worst sufferer and the insurers will lose the confidence and such situation lead to chaos in the country. I think if the LIC collapses, the country will collapse.

In the Budget, I am also happy to see that the services of India Post Payment Bank deepened and expanded in rural areas and there is need to encourage the small saving schemes by offering at least 12 per cent interest per annum with different periods under all the post office schemes.

In the Budget, I am happy to note that an Investment Friendliness Index of States will be launched in 2025 to further the spirit of competitive cooperative federalism but my sincere request to the Government is to help the non-BJP ruled States like Telangana, Karnataka, Delhi, Punjab, etc., without any discrimination to achieve the goal of 'Viksit Bharat 2047'. In the Budget, the Government said Democracy, Demography and Demand are the key support pillars in our journey towards Viksit Bharat. The middle class who consists of about 80 per cent of our total population provides strength for India's growth.

In the new tax regime, I request the Government to revise tax rate structure as follows to benefit lower and middle class employees so that they can spend their income for them only in the market. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment but need further concessions and amendments

in the income tax bracket so that the spending in the market will be further improved and they will be happy and also boost the revenue to the Government indirectly.

Indians - the less than 1 percent of India's population is paying tax. What about others who are not paying tax and what they are doing? It is they who will gain the lion's share of the Rs. 1 lakh crores loss that the Government will suffer because of the income tax concessions. More importantly, the Government has chosen not to increase the rates of taxation at higher income slabs, which could very well have been combined with a reduction in tax burden of the lower middle class. They say Income tax reforms.

How many slabs we have in New Tax Regime:

1. 0-4L Nil
2. 4-8L 5 per cent
3. 8-12 10 per cent
4. 12-16L 16 per cent
5. 16-20L 20 per cent
6. 20-24L 25 per cent
7. Above 24L 30 per cent

How can seven slabs be simple? How much relief they will get? This is only for heading management.

Middle class ? 2/10.

I suggest the income tax brackets as under to benefit the common man also.

0-5 lakh rupees	Nil
5-10 lakh rupees	3 per cent
10-15 lakh rupees	5 per cent

15-20 lakh rupees	10 per cent
20-25 lakh rupees	15 per cent
Above 25 lakh rupees	20 per cent

I want to ask the Government is there any need to tax 30 per cent from the employees. There is no rationale in taxing them at 30 per cent as income tax and out of 12 months, salaried employees are getting only 9 to 10 months? salary and burdening their household expenditure gravely. I can say, on the one hand, the Government is paying salary but on the other hand, the Government is taking their salary in the form of income tax. What is this? I do not understand.

This Government under the leadership of feeble Prime Minister Modi has never believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, the Government has not periodically reduced their tax burden since 2014 and the Government is not trusting on the middle-class tax payers despite their contribution to the GDP is more compared to the businessmen.

Another important issue is constitution of 8th Pay Commission for Central Government employees and others which was taken in hasty manner to win the Delhi elections. But till date, the Government has not constituted the Commission and they have no interest in the welfare of the Government employees.

Another request I want to make to the Railways is to restore the fare concessions for Senior Citizens for railway passengers. I also request Railways to give a halt at Peddapalli Railway Station for Telangana Express because AP Express has a stop at Peddapalli. I also request the Railway Authorities to re-open Rail Yatri Niwas with cheaper rates at New Delhi Railway Station so that our poor passengers from Telangana and AP States can utilize whenever they visit to Delhi for different works especially for one day work and visit to Delhi so that they can arrive at railway station, have their bath in the Yatri Niwas and they can catch the train to their destinations in the evenings. Now, they are unable to pay hotel accommodation rates as the private hotels are looting the money of the general public with hefty charges.

Another important issue pertaining to construction of Foot over Bridge from Ajmer Gate/Kamala Market side to Paharganj side at New Delhi Railway Station. In the absence of Foot over Bridge, the people those who want to come from Ajmer Gate/Kamala Market side to Paharganj side are using the

bridge which is near Shiela Theatre which takes at least half-an-hour and if the Food over Bridge is constructed, they can reach in five minutes. For this purpose, open land space is available with Government authorities. Another worrisome thing for all of us is Dollar is strengthening and Rupee is weakening and affecting the common man and poor people. This Budget is for a 10th time which is a big disappointment for all sections of people and the society. It is completely directionless and shift goalposts. It has no focus on developmental issues.

The lack of understanding of economics in the National Government headed by PM Narendra Modi is clearly visible. Compared with Budgets under the Prime Ministership of our beloved leaders - Shri Jawaharlal Nehru Ji, Smt. Indira Gandhi Ji, Shri Rajiv Gandhi Ji, Shri P.V. Narasimha Rao garu, Dr. Manmohan Singh Ji, this Budget under PM Modi does not help India leap to the next level.

The focus of PM Modi and Smt. Nirmala Sitharaman garu is clearly to confuse people and they themselves confused on how to run the Government and they failed miserably since 2014 in running the Administration and people are laughing. People of this country are saying Union Budget 2025-26 is ?A Cruel Betrayal of the Indian People?. The Union Budget 2025-26 is a cruel betrayal of the requirements of the people of India. Instead of addressing the root cause of the demand problem being faced by so many sectors of the economy, the lack of purchasing power in the hands of large sections of the population because of mass unemployment and shrinking wages, the Modi Government through the budget is seeking to stimulate the economy by giving tax cuts to the small minority with higher incomes even as expenditures are cut.

While the Economic Survey shows the desperate plight of India's labour force, pointing out the decrease in earnings over the last five years, this budget with its emphasis on cutting Government expenditures while giving concessions to the rich will only increase the huge inequalities in India.

Instead of mobilizing resources by taxing the rich and the big corporate houses and pushing up public investment that would help generate employment and ensure a minimum wage for our people, it has chosen to do the opposite. It also seeks to foster greater wealth accumulation by the rich by promoting private investment, even placing public assets and public expenditure at its service. In this Budget the Government proposes 100 per cent entry of FDI in the insurance sector and privatisation of

power sector as well. It is therefore a budget by the rich for the rich only which is shameful to our country under PM Modi.

Expenditure as a percentage of GDP is destined to come down once again, as has been happening every year since 2020-21 - this time from 14.6 per cent in 2024-25 to 14.2 per cent in 2025-26. The budget papers further reveal that the Government in contrast to its tall claims, actually spent in the last year approximately one lakh crores rupees less than what the budget had promised. In other words, going by its past record, even the inadequate allocations made cannot be taken at face value as the Government does not spend the amount it promises it would.

In the last year, the Central Government cut down transfers to the States by Rs. 1,12,000 crore compared to the budgeted figures - it reduced funds for centrally sponsored schemes by Rs. 90,000 crores and Finance Commission and other transfers to the states by 22,000 crores. The budget thus reflects the approach of a dilution of the principle of federalism, and the assaults on the rights of the States. The cuts in 2024-25 also hit capital expenditures which are going to be almost Rs. 93,000 crores less than the budgeted figure. Food subsidies, Agriculture and Allied Activities, Education, Rural Development, Social Welfare, Urban Development - all have faced this cut and the budgeted figures for 2025-26 are almost the same as in 2024-25. The allocations are in fact stagnant if one factors in inflation, and as a percentage of GDP less than last year.

The allocation of food in the last budget was 2.05 lakh crores but in revised estimate of the last year expenditure reduced by Rs. 7830 crores while in this budget the proposed figure is Rs. 2.03 lakh crores which is even less than the last year's budget provision. Similarly in the case of education the budget provision for the last year was Rs. 1.26 lakh crores but the revised estimate shows that they spent Rs. 11,584 crore less while in this budget the allocation is only Rs. 14596 higher over last year's budget estimates. This is only 2.3 per cent increase in nominal terms so considering inflation there has not been any increase in real terms.

Regarding allocation of health, the revised estimates are once again less than last year's budget estimates. In agriculture and allied sector the BE was 1.5 lakh crore and the Government spent 10992 crores less according to the revised estimate. LPG subsidy has been cut down from Rs. 14.7 thousand crore as per last year's revised estimate to Rs. 12 thousand crores in this year's budget. The hypocrisy of

the Government is symbolised by its measly allocations for a right which is a lifeline for the rural poor, the MNREGA. The allocations have stagnated at 86,000 crore rupees even as the demand has grown. This is not only a cruel blow against the rural poor, it is an outright assault on the legal right for 100 days work. The demand for MSP for farmers, a critical issue for addressing agrarian distress and farmer suicides has been given short shrift by the Government. The present budget has separate statements for expenditures on scheduled castes, scheduled tribes and for women. Even at face value, the budget papers show the utter callousness of the Government. In 2024-25 the Allocation of Scheduled Castes has faced a cut of Rs. 27,000 crore, while that for Scheduled Tribes similarly is down by Rs. 17,000 crores - this is despite the shares of such expenditures in total expenditure being significantly lower than what the guidelines prescribe them to be, namely proportionate to the shares of these social groups in the population. For 2025-26, the allocations are only 3.4 per cent and 2.6 per cent of total expenditures for SCs and STs respectively. Allocations for North Eastern Areas have also been reduced by Rs. 13,000 crore in comparison to budgeted figures, while that on Welfare of Children has also been cut. Even the Gender Budget for 2024-25 is smaller than in 2023-24. Allocations under these heads continue to be low even in 2025-26.

Overall, the Union Budget 2025-26 reflects the bankruptcy of the Modi Government, and shows that it is so committed to protecting the interests of the rich and corporate sector that it is not even able to formulate any real policy to address the slowdown in the economy. Neither the magnitude of the crisis, nor its character, seem to be visible to the Government and its Finance Minister - who go on like a stuck record about their great stewardship of the economy, which as the Economic Survey showed has resulted in a situation where wages in India are below pre-pandemic levels and growth is also slowing down because of demand constraints. A mountain of evidence now exists that compressing expenditures and lowering taxes on the rich, and other measures to unleash the so-called animal spirits of private corporate and foreign investors, has not worked to address this problem and generate investment and employment growth. The Union Budget 2025-26 is only the latest instalment of a policy that has abjectly failed. It is very unfortunate that the Government did too little and taking steps too late which are not giving desired results for Viksit Bharat 2047 and this Budget is completely directionless. States and National Development: Only State name mentioned I could hear was Bihar, Bihar, Bihar. What about rest of states.

What about South India? Why no mention of my state of Telangana? What will you give us? Do you want to give Telangana people Empty Plate?

a. **Cities will lead growth:** A special dedicated policy is needed in India for six major cities - Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Kolkata and Hyderabad. If cities do not grow, country cannot grow.

b. **\$5 trillion economy:** Nirmala ji totally forgot to mention \$5 trillion economy. We are talking about \$1 trillion economy in Telangana everyday because we are serious and sincere.

c. **Infrastructure:** We must build world-class standards infrastructure for India. They did not even find time to talk of big projects.

d. **Loans:** Long-term 50 years interest-free loans for states for infra - the budget allocations are so low, it would not be enough for even Telangana.

This is one of the biggest failures of Modi govt and even by bad budgets of last 10 years, this one is a total disappointment. Only some friends of PM Modi like Ambani and Adani will be happy in the NDA Regime. Rest of the Indians got nothing. Only taxes, and multiple problems.

With these few words, I would like to conclude.

Thanking you.

श्री अवधेश प्रसाद (फैजाबाद) : मैं माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार द्वारा लाये गये बजट पर अपने विचार रखता हूँ।

मैंने बहुत ही गंभीरतापूर्वक बजट का अध्ययन किया। बजट बहुत ही निराशाजनक है। इस बजट में देश के गरीबों के लिये, वंचितों के लिये, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिये कोई भी विकास की योजना नहीं है। हमारे देश की बहुमूल्य दौलत हमारे देश के करोड़ों करोड़ युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनको नौकरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। आज देश के नौजवानों के लिये जो बड़ी-बड़ी डिग्रियां लिये हैं उनके पास कोई रोजगार नहीं है। किसान जो कि अन्नदाता है, उनकी आमदनी दुगुनी करना तो दूर रहा, किसानों की फसलों को अवारा जानवर और सांड हमारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में चर रहे हैं, खा रहे हैं। सांड खेत को चरता है और किसान की जान भी लेता है। उत्तर प्रदेश में 5 हजार से ज्यादा किसानों की जान सांडों ने ले ली। हमारे विधान सभा क्षेत्र और अब संसदीय क्षेत्र में आता है, मिल्कीपुर, वहां 60 किसानों को सांडों ने मार कर जान ले ली। यहां का किसान अपनी खेती की रखवाली करने के लिये रात में खेतों में रहता है। आधी से ज्यादा खेत बोये नहीं गये हैं। किसानों को खेती बचाने के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है।

मैं जनपद अयोध्या जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की धरती है। मैं 54 फैजाबाद लोक सभा से चुनकर आता हूँ। योगी सरकार ने वहाँ के किसानों की जमीन कौड़ियों में ले ली है और बाहरी लोगों के हाथों करोड़ों में बेचा है। किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। 84 कुशी परिक्रमा के नाम पर किसानों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। पहले भी किसानों के घरों को उजाड़ा गया है, ढाया गया है यहाँ तक कि गुप्तार घाट में बसे हुए निषादों को उजाड़ा गया है, उन्हें बसाया नहीं गया। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि अयोध्या में जिन किसानों की भूमि ली गयी है उनको उचित मुआवजा दें, जिन्हें उजाड़ा गया है, रहने की लिए मकान की व्यवस्था करे।

हमारे संसदीय क्षेत्र में आचार्य नरेंद्र उद्योग कृषि विश्वविद्यालय है। सरकार से मांग करता हूँ कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का उसे दर्जा दिया जाये। डॉ० राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है, जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाये। हमारे यहाँ जनपद अयोध्या में हवाई अड्डे का निर्माण हुआ है। यहाँ से हवाई जहाज की सेवा, हमारे देश में जितने धार्मिक स्थल हैं उन सभी धार्मिक स्थलों में आने-जाने के लिए जहाज की सेवा उपलब्ध कराई जाए। डेमवा नदी पर पुल का निर्माण फिर से किया जाये जिससे जनपद गोंडा जाने के लिये सुविधा उपलब्ध हो। कोरोना काल में तमाम रेलें बंद कर दी गई थी, उन सब रेलों को लखनऊ, फैजाबाद से होते हुए चलाया जाए। सुहावल रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण किया जाये। रुदौली रेलवे स्टेशन का उच्चीकरण किया जाये। वहाँ से आने वाली फैजाबाद, लखनऊ जाने वाली ट्रेनों की सुविधा दी जाए। जनपद अयोध्या में स्थित मेडिकल कॉलेज, श्रीराम अस्पताल अयोध्या की हालत बहुत खराब है। मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अच्छे डाक्टरों की प्राप्ति और सभी सुविधाएं भारत सरकार द्वारा कराई जायें।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि अयोध्या का ऐसा विकास किया जाये जो दुनिया के नक्शे पर चमकता हुआ दिखाई पड़े। अयोध्या में प्रभु श्रीराम की मर्यादा को कायम रखते हुए सही मायनों में विकास किया जाए एवं जो मिल्कीपुर विधान सभा में मतों को लूटा गया उसे रोका जाए।

इस निराशाजनक बजट जो किसान विरोधी है, युवा विरोधी है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोधी है। मैं इस बजट का विरोध करता हूँ।

*m85 श्रीमती रुचि वीरा (मुरादाबाद) : मैं बजट 2025-26 जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखती हूँ।

नई दिल्ली स्थित एम्स का बजट 677 करोड़ रुपये बढ़ाकर कुल 5200 करोड़ कर दिया गया, परंतु नई दिल्ली एम्स पर बहुत ज्यादा लोड होने के कारण जनप्रतिनिधियों के रिकमेंडेशन के बाद भी लोगों को एडमिशन नहीं मिल पाता है और ऑपरेशन आदि की तारीख कई-कई महीने के बाद मिलती है। इस कारण इलाज के अभाव से लोग दम तोड़ देते हैं।

मेरा निवेदन है सरकार की सस्ती, सुलभ, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को देखते हुए मुरादाबाद जनपद, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई मण्डल एवं उत्तराखण्ड के कुमाऊ क्षेत्र का केन्द्र है एवं रेल व सड़क मार्ग से वैल कनेक्टेड है। यहाँ पर एक एम्स की स्थापना कराई जाये जिससे कि इस क्षेत्र के लोगों को सस्ता सुलभ इलाज मिल सके।

सड़क, परिवहन और राजमार्ग विभाग को वर्ष 2024-25 में 2.78 लाख करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे। वर्ष 2025-26 में इसे बढ़ा कर 2.89 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया परन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 734 में मुरादाबाद से उत्तराखण्ड वाया ठाकुरद्वारा पर जमीन अधिग्रहण हेतु नोटिफिकेशन दिनांक 12.01.2022 में कर दिया गया था परन्तु किसानों को जमीन का मुआवजा वर्ष 2019 के सर्किल रेट के दर से दिया जा रहा है। किसानों के जमीन अधिग्रहण पर मुआवजे के मामले में अधिकारियों के द्वारा घोर लापरवारही की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जनप्रतिनिधियों के कहने के बावजूद एस.एल.ओ. किसानों को चक्कर कटाते हैं और आरबिट्रेशन में जाने पर मजबूर करते हैं जिससे किसानों की जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। मैं सरकार से माँग करती हूँ कि जमीन अधिग्रहण का मुआवजा 12 जनवरी, 2022 के अनुसार दिया जाए।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 पर मौजा उजयाली खुर्द, तहसील जानसठ, जनपद मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है परन्तु किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया। तहसील जानसठ द्वारा रोड एलामेंट में कुछ भू-माफियाओं से हमसाज होकर बिना आधार बताए गलत रिपोर्ट पेश की गयी है। किसानों की जमीनों को 1359 फसली के आधार पर नदी, नालों की बताया जा रहा है, ये इनकी दादालाही जमीन है। इस मौजे में चकबन्दी हुई थी और चकबन्दी के दौरान इनके चक यहाँ लगाये गये थे। मैं सरकार से माँग करती हूँ कि तहसील से दोबारा सर्वे कराकर किसानों की जमीनों के मुआवजे के वितरण के उपरांत ही कार्य शुरू करें।

बजट 2025-26 में सरकार ने हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देने और निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। मेरा संसदीय क्षेत्र मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से मशहूर है। यहाँ पर लाखों की तादात में पीतल के काम में हस्तशिल्पी जुड़े हैं 2014 से पूर्व में राजीव गाँधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई जा रही थी जिससे हस्तशिल्पियों को ईलाज में सुविधा मिलती थी। उस योजना को बंद कर दिया गया है जिससे हस्तशिल्पी भुखमरी के कगार पर पहुँच चुके हैं। हस्तशिल्पी अपना काम छोड़कर रिकशा चलाने व ठेला लगाने पर मजबूर हैं। मैं माननीय मंत्री जी से माँग करती हूँ कि इस तरह की स्वास्थ्य बीमा योजना पुनः चालू की जाए एवं हस्तशिल्पियों को जीएसटी में 40 लाख रुपये तक की वार्षिक छूट को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया जाए जिससे कि हस्तशिल्पी अपने काम पर लौटें और बढ़-चढ़कर हिस्सा ले सकें। इससे निर्यात में बढ़ोत्तरी होगी और देश को फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त होगा।

बजट 2025-26 में नागरिक उड्डयन विभाग की क्षेत्रीय उड्डान योजना के अंतर्गत कनेक्टविटी स्कीम की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कही है। मेरे लोकसभा क्षेत्र मुरादाबाद में एक हवाई अड्डा है जिसमें एक फ्लाइट लखनऊ के लिए चलती थी। दिनांक 5 दिसम्बर, 2024 से कोई उड्डान नहीं भरी गई है। मान्यवर, क्षेत्रीय कनेक्टविटी स्कीम में मुरादाबाद को शामिल कर कम से कम व्यवसायिक पीतल नगरी मुरादाबाद को मेट्रोपोलिटिन सिटीज से जोड़ा जाए।

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने बाद भी जिस तरीके से इसकी उपेक्षा हुई है, यह निराशाजनक है। सरकार ने राज्यों को बजट का एलोकेशन करने में पोलिटिकल हित साधे हैं। इस बजट में देश का नौजवान, किसान, महिला और निम्न, मध्यम वर्ग अपने को ठगा से महसूस कर रहा है।

श्री विजय कुमार दूबे (कुशीनगर) : इस वर्ष का बजट यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री माननीया निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, विकसित भारत के संकल्प को मजबूत कर रहा है। वास्तव में यह बजट देश के मध्यम वर्ग, निर्बल वर्ग के साथ युवा, छोटे किसान, छोटे व्यापारी व देश की महिलाओं के लिए ऐतिहासिक विकास की सौगात और उनके सपनों को साकार रूप देने वाला तो है ही, साथ में जहां गरीबी से मुक्ति, अच्छे स्तर के स्कूली शिक्षा, सस्ती व सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी, कृषि के विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करना, समावेशी पथ पर संबंधों को साथ लेकर चलना, मेक इन इंडिया को और आगे ले जाना, MSME को सहायता देना, रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाना, निर्यात को बढ़ावा देना आदि देश को समर्थ और विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती देने वाला यह बजट है।

इस बजट का उद्देश्य ही दिखाई पड़ रहा है, देश के गरीब मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य को भी पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय बजट में लिया गया है, इसके लिए पाँच लाख छत्तीस हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने की योजना है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में पच्चीस हजार बस्तियों को जोड़ने के लिए सत्तर हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

जब देश के विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े परिवारों को मिलता है, तभी विकास का सार्थक परिणाम भी मिलता है।

(1) 12 लाख तक की आय को कर मुक्त करने से सीधे-सीधे मध्यवर्ग के लोगों के जीवन में खुशहाली, संपन्नता के सपनों को उड़ान देने वाला है।

(2) किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर देने से गरीब वर्ग को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

(3) अगले वर्ष मेडिकल कॉलेज में 10000 सीटें व अगले 5 वर्ष में 75000 सीटें बढ़ेंगी तो निश्चय ही युवाओं के सपने को उड़ान देगा।

(4) 7.5 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों की अल्पकालिक ऋण इनके आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा।

इस ऐतिहासिक ठाजर में

(5) 50 पर्यटन केंद्रों का विकास किया जाएगा, खासकर बुद्ध से जुड़े स्थलों को इससे तो सीधे-सीधे हमारे कुशीनगर के पर्यटन विकास को लाभ मिलते दिख रहा है, क्योंकि कुशीनगर भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल और बौद्ध सर्किट एरिया है।

विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाले इस बजट के अंशदान में हमारे कुशीनगर के लिए भी कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जैसा कि कुशीनगर के बौद्ध सर्किट एरिया के पर्यटन विकास को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर पहचान दिलाने के लिए ही यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण पूरा कराये, वो भी कोविड की विषम परिस्थितियों में।

स्पाइसजेट से उड़ान भी दिल्ली के लिए प्रारंभ हुआ, चार माह नियमित व चार माह अनियमित उड़ान के बाद आज सालों से उड़ान पूर्णतः बंद है, करोड़ों रुपया उक्त एयरपोर्ट पर अधिकारियों के तनख्वाह, राजस्व को भारी क्षति हो रही है। इंडिगो से उड़ान शुरू करने का आश्वासन माननीय उड्डयन मंत्री जी ने दिया है, कुशीनगर जिला ही नहीं बल्कि पश्चिमी चंपारण बिहार के भी कई जिलों के निवासी व कुशीनगर से लगे दर्जनों जिलों के निवासी उड़ान शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।

इसी तरह हमारे कुशीनगर के बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लोगों की सुविधाओं को देखते हुए बंद पड़े छितौनी तमकुही रेल परियोजना को माननीय रेल मंत्री जी ने पिछले सत्र में 10 करोड़ देकर डी फ्रिज किए थे, भूमि अधिग्रहण के भी कार्य शुरू हो चुके हैं, परंतु इस महत्वपूर्ण परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 1500 करोड़ से ज्यादा की आवश्यकता को देखते हुए मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि रेल को मिले भारी बजट में इस परियोजना को भी धन की स्वीकृति देने की कृपा करेंगे।

कुशीनगर क्षेत्र की जनता की पुरानी मांग है कि ट्रेन संख्या 15079 पाटलीपुत्र से गोरखपुर व 15080 गोरखपुर से पाटलीपुत्र का ठहराव कठकुइया रेलवे स्टेशन पर किया जाए, और ट्रेन संख्या 18181 टाटानगर से थावे व 18182 थावे से टाटानगर का मार्ग विस्तार कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के कप्तानगंज रेलवे स्टेशन तक करने की मांग क्षेत्र की जनता लगातार कर रही है।

कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का अकेला ऐसा हवाई अड्डा होगा जो रेल सुविधा से वंचित है, गोरखपुर-कुशीनगर-पडरौना परियोजना सन् 2017 से डीपीआर बनाकर बंद है, मैं माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कुशीनगर के बौद्ध सर्किट एरिया व अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को रेल सुविधा से जोड़ने के लिए उक्त गोरखपुर-कुशीनगर रेल परियोजना का शुरू करने की कृपा करें।

राजमार्ग मंत्रालय ने विगत पिछले सत्र में कुशीनगर के विकास में अपना अहम योगदान किया है, अनेक फ्लाईओवरों में, हाटा के दोनों फ्लाई ओवरों पर बजट देकर दुर्घटना बहुल इस स्थल पर निर्माण पूर्ण कराना जनहित में अति आवश्यक है, ऐतिहासिक मिले बजट का कुल सारांश यही है कि जब कुशल नेतृत्व मिलता है तो देश भी विकास करता है, और समाज का हर वर्ग भी तरक्की करता है। उदाहरण के रूप में मात्र 10 वर्ष पहले तक जो देश बीमार अपाहिज की हालत में दुनिया के मजबूत देश के पिछली कतार में खड़ा था, और देश आजादी के बाद से समाज निर्बल-दुर्बल वर्ग, देश के छोटे किसान, छोटे व्यापारी, देश की महिलाएं अपने बुनियादी आवश्यकताओं की आवाज तो लगाते रहे लेकिन देश के 60 साल के नेतृत्वकर्ताओं ने सुना नहीं, आज महज 10 सालों में, यह माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज वही बीमार देश दुनिया के विकासशील देशों के अग्रणी कतार में

खड़ा है, इतना ही नहीं आज देश के समाज का वही वर्ग आत्मनिर्भर बनने की दिशा में मजबूती से खड़ा होकर राष्ट्र के विकास की धारा से जोड़ने का काम कर रहा है। इसीलिए तो समूचा देश कहता है? मोदी है तो मुमकिन है।?

एडवोकेट प्रिया सरोज (मछलीशहर) : मैं बजट 2025-2026 पर अपने विचार रखती हूँ।

सबसे पहले, मैं माननीय वित्त मंत्री जी को लगातार आठवीं बार BUDGET पेश करने के लिए बधाई देती हूँ। एक महिला के रूप में, उनकी जिम्मेदारी और योगदान को मैं आदर करती हूँ।

बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को भी छाया नहीं फल लागे अति दूर।

सरकार के लम्बे चौड़े लेकिन असली मुद्दों पर बेअसर BUDGET पर यही सबसे सटीक टिपण्णी होगी।

मेरा सवाल यह है कि आखिर हम कब BUDGET के माध्यम से देश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों, गरीबों, दलितों और पिछड़ों को भी बधाई देंगे? यह BUDGET किसके लिए है? क्या यह देश के करोड़ों आम लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए है या सिर्फ कुछ खास लोगों के फायदे के लिए?

सरकार GROWTH और PROSPERITY कि बात करती है, लेकिन सर, यह GROWTH GROUND पर दिखाई क्यों नहीं देती?

आपने सबका साथ, सबका विकास का नारा तो दिया, लेकिन आपने सिर्फ कुछ खास UDYOGPATI का साथ दिया। उन UDYOGPATIYON का विकास किया, और देश की आम जनता के साथ पूरा विश्वासघात किया।

सिर्फ 10 साल में, DOLLAR की exchange rate 62 से गिरकर 87 रुपये प्रति डॉलर हो गई है। रुपया ICU में है, और सरकार निद्रावस्था में। तो बताइए, इसे सरकार ऐतिहासिक सफलता" कहेगी या" RECORD तोड़ नाकामी" जिसका बोझ पूरा देश उठा रहा है?

सबसे ज्यादा हल्ला बस इस बात का रहा है कि middle class के तो दिन फिर गए। सरकार ने ऐसे सपने बेचे जैसे हर मिडिल क्लास व्यक्ति बड़ा सेठ बन गया। 12 लाख तक INCOME TAX FREE बताया, मगर बेरोजगारी के इस दौर में कितने लोग हैं जो 12 लाख रुपये सालाना कमा पा रहे हैं?

सिर्फ TAX छूट से क्या होगा जब रोजगार ही नहीं हैं? कौशल विकास के बिना ये REFORMS अधूरे हैं। INCOME TAX में राहत TEMPORARY है, क्योंकि महंगाई, GST और INDIRECT TAX के बोझ से जनता की SAVINGS भी खतरे में आ ही जाएगी।

जब आप नए OPPORTUNITY, नए JOBS और INCOME में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, तो हमारी ECONOMY में DEMAND कैसे आएगी?

एक बात कोई सरकार से पूछे नाक को सीधे पकड़ो या घुमाके पकड़ो, दोनों बातों में क्या फर्क है भाई? एक तरफ आप कहेंगे की income tax कम कर दिया, पर सच्चाई ये है की गाडी खरीदों तो लम्बा चौड़ा tax, उसी गाडी को चलने के लिए पेट्रोल भरो तो उसकी कीमते आसमान पर, फिर थोड़ी दूर पर आ जाता है आपका toll, और देना होता है अच्छा खासा toll tax.

बात सिर्फ income tax की नहीं है, सोशल मीडिया पर लोग पूछते हैं की क्या आपकी सांस लेने पर भी tax लेने की तयारी है? खैर जो देश की हवा है, उसको सांस लेने लायक छोड़ा नहीं है आपने। एक तरफ pollution तो दूसरी तरफ धार्मिक मन मुटाव का ज़हर, हवा वाकई आपने जानलेवा कर दी है। (हंसते हुए) अब सपनों पर भी TAX मत लगा देना।

मैं खुद एक युवा हूँ, इसलिए अब युवाओं की दुखती रग पर हाथ रखती हूँ।

कहने को बड़ा हसीन है हमारा देश,

फूलों की एक पंखुड़ी है हमारा देश,

पर बेरोजगारी और आपसी मन-मुटाव के इस दौर में,

राख के ढेर पर खड़ा है हमारा देश।

अब बात नौकरी की करते हैं। आपकी सरकार ने हर साल 2 CRORE नौकरियाँ देने का वादा किया था। 10 साल में 20 CRORE JOBS मिल जानी चाहिए थीं। पर न नौकरी आई, ना INCOME बढ़ी। सिर्फ बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच गई। लोन की बात करें तो नए BUDGET में लोन के कुछ SCHEMES का OPTIONS तो है, लेकिन असली सवाल यह है कि सरकार DIRECT JOBS क्यों नहीं CREATE कर रही है? क्या हर कोई BUSINESSMAN बन सकता है? रोजगार देना सरकार की जिम्मेदारी है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए BUDGET में कोई खास जिक्र नहीं है। न WORKING CONDITION सुधारी गई, न ही GENDER-RESPONSIVE POLICIES लाई गई। सिर्फ लोन स्कीम देकर महिलाओं को अपनी रोजगार खुद करने के लिए छोड़ दिया गया।

Talking about education. In 2025-26, the total budget estimate amount for the education sector is 1 LAKH 28 THOUSAND 6 HUNDRED AND 50 CRORE) This increase in nominal terms by 6.22% as compared to the Budget Estimates of 1 LAKH 20 THOUSAND 6 HUNDRED AND 28 CRORE for the year 2024-25. If we consider the average inflation rate to be 5.2%, then the real increase is merely around 2% for the education sector.

The Education has also been neglected. There is no strong policy visible for primary, secondary, secondary and education. higher The persistent issue of high dropout rates at the secondary level, currently at 14.1%, underscores the need for substantial investment in this segment.

अगर घर की बात करें, तो आपकी योजना के अनुसार, 2022 तक हर नागरिक को पक्का मकान मिल जाना चाहिए था ।, लेकिन 2025 आ गया और लोग अब भी इंतज़ार में बैठे हैं । घर मिलने के बजाय, अब तो टूटने लगे हैं । उत्तर प्रदेश सरकार ने घर तोड़ने में रिकॉर्ड बनाया, और ज़्यादातर नुकसान पिछड़े व अल्पसंख्यक समुदायों को हुआ है ।

अब मैं अल्पसंख्यकों और पिछड़ों की बात करती हूँ । MINORITIES और BACKWARDS वर्गों के लिए इस सरकार ने क्या किया? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अनुसूचित जाति से आती हूँ, और मेरे मछलीशहर क्षेत्र के आम नागरिक, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लिए इस BUDGET में मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती । जब सरकार ने जाति जनगणना करवाई ही नहीं है, इनके पास DATA ही नहीं है कि किसकी कितनी भागीदारी है, तो आप उनके लिए FINANCIAL STRATEGY कैसे बना सकते हैं?

आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, बिना यह समझे कि असली ज़रूरत किसकी है । जहाँ तक किसानों की बात है, तो हमारे अन्नदाता हमारे किसानों के साथ खुला धोखा किया गया है । नई योजनाएँ पुरानी नीतियों का ही री-ब्रांडिंग हैं । MSP पर भी कोई गारंटी नहीं दी गई है, और किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन को नज़रअंदाज़ कर दिया गया है ।

मेरी कुछ DEMANDS हैं । मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ । उत्तर प्रदेश एक- सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है । प्रधानमंत्री जी भी यूपी के बनारस से चुनकर आते हैं, लेकिन इस BUDGET में यूपी के किसानों, युवाओं, गरीबों, श्रमिकों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है । या फिर यह सिर्फ़ आंकड़ों की बाजीगरी है? मैं पूर्वांचल से हूँ और प्रधानमंत्री जी भी वहीं से चुनकर आते हैं लेकिन बनारस के अलावा उसके आस पास के जिलों में कहीं अच्छी स्वस्थ सुविधाएँ नहीं हैं । ना ही सरकार ने इस AREA में कोई AIIMS का इस BUDGET में एलान किया है । अच्छी सड़क का वादा आप लोगों की ओर से चुनाव में किया गया था लेकिन उसका क्या हुआ, उसके लिए BUDGET में क्या नया प्रावधान है? मैं APPEAL करते हुए, यह कहना चाहती हूँ कि सरकार को विपक्ष से राय लेने में आखिर दिक्कत क्या है? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ़ एकतरफ़ा फ़ैसला लेना है?

This budget represents a significant lost opportunity foster to inclusive and equitable growth. Once again, the government has overlooked the needs of common citizens. What is the value of grand promises when the poor, farmers, workers, communities, students, marginalized and women experience no tangible benefits?

आखिर में, महाकुंभ में हुई दुखद घटना के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी, और कहना चाहती हूँ कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी असफलता रही । लेकिन सरकार के पास कोई स्पष्ट डेटा न होना, यह आज के दौर में एक बड़ा झूठ है ।

हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष AKHILESH YADAV जी ने अपने भाषण के दौरान जो मांगें रखी थीं, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है ।

सरकार को ज़िम्मेदारी लेनी होगी और आम जनता के साथ न्याय करना होगा ।

अंत में, मैं चार लाइनें बोलना चाहूंगी ।

कभी घमंड मत करना,

तक्रदीर बदलती रहती है,

शीशा वहीं रहता है,

बस तस्वीर बदलती रहती है ।

जय हिंद । जय भीम, जय समाजवाद । धन्यवाद ।

श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल (बांदा) : मेरा विषय बजट को लेकर है, जिसके संदर्भ में भारत सरकार का ध्यान देश के गरीब एवं मध्यम आय वाले परिवारों को कोई विशेष व्यवस्था न दिये जाने के संबंध में है ।

गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास दिये जाने के संबंध में दी जाने वाली राशि, जो कि एक लाख बीस हजार है, उसका प्रावधान है ।

आज की महंगाई के स्तर को देखते हुए इतनी कम धनराशि में रहने योग्य मकान का निर्माण संभव नहीं है । सरकार द्वारा यह धनराशि और बढ़ाई जाये ताकि गरीबों के चेहरे में मुस्कान देखी जा सके ।

देश की अर्थव्यवस्था में अपना अमूल्य योगदान देने वाले किसानों की अगर बात करें तो, सरकार अवलोकन करें, कि किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई है, परन्तु किसानों का कर्जा और अधिक बढ़ गया है ।

इसी वजह से मेरा क्षेत्र, जो की बुन्देलखंड में आता है, उसकी स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है तथा इनके आत्महत्या के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं । ऐसी स्थिति में मैं चाहती हूँ कि किसानों को कर्जमुक्त किया जाए ।

धन्यवाद ।

श्री ज्ञानेश्वर पाटील (खण्डवा) : मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 2025-2026 के बजट पर अपने विचार रखता हूँ ।

हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को सत्ता पर काबिज हुए 10 साल हो गए हैं । इन 10 सालों में भारत ने हर क्षेत्र में बहुत तरक्की की है । आज भारत स्वावलंबी है, अन्य देश भारत सरकार की ओर देख रहे हैं हमारे पगचिन्हों पर चलने की बात करते हैं । जैसा माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री

श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत विकास यात्रा की और अग्रसर हो रहा है हर तरफ विकास की गंगा बह रही है अध्यक्ष जी हमारी सरकार ने विभिन्न स्तर पर अभूतपूर्व उपलब्धियों हासिल की है।

हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत में तीन गुना तेज गति से काम हो रहा है। देश के गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिल रही है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदीजी ने दिया हुआ मंत्र "सबका साथ, सबका विकास", "सबका विश्वास और सबका" प्रयास जैसे मंत्र भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने की प्रेरणा देते हैं जिससे हम विश्वगुरु बनने की दिशा में अग्रसर हैं।

हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई, चाहे मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई विभिन्न योजनाएं जिनसे आम लोगों को बेहद लाभ पहुंचा। जन धन योजना, आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और उज्ज्वला योजना से करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन देखने को मिला।

आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो की हमारे सबके श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी जिसके चौथे चरण में पच्चीस हजार बस्तियों को जोड़ने के लिए सत्तर हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आज जब हमारा देश अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष मना रहा है, तब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके विजन का पर्याय बनी हुई है। देश में अब इकहत्तर वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही हैं। इतना ही नहीं अध्यक्ष जी "वन नेशन-वन इलेक्शन" और "वक्फ़ अधिनियम संशोधन" जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर हमारी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए हैं।

आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत बने 12 करोड़ शौचालय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निशुल्क दिए गए 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन, 90 करोड़ जरूरतमंदों को राशन, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन जैसी अनेक योजनाओं ने गरीब, मध्यम वर्गीय, को ये भरोसा दिया है कि वो सम्मान के साथ जी सकते हैं। ऐसे ही प्रयासों की वजह से देश के 40 करोड़ लोग गरीबी को परास्त करके आज अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं।

आयुष्मान भारत योजना गरीबों के लिए जीवनदान साबित हो रही है। इसके तहत 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष फ्री बीमा की सुविधा दी जा रही है। इसे सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम माना जा सकता है। इस योजना को 2018 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के कारण करोड़ों लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं।

माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य सभी को घर उपलब्ध कराना है। इसी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना को लॉन्च किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए तीन करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पांच लाख छत्तीस हजार करोड़ रुप खर्च किए जाने की योजना है।

हमारी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार गांव में गरीबों को उनकी आवासीय भूमि का हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक दो करोड़ पच्चीस लाख सम्पत्ति कार्ड जारी किए हैं। इनमें से करीब 70 लाख से ज्यादा स्वामित्व कार्ड पिछले साल जारी हुए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीनों में इक्तालीस हजार करोड़ रुपये की राशि का भुगतान हुआ है। इस योजना के तहत होम लोन लेने वाले को लगभग 2 लाख 60 हजार रुपये का लाभ मिलता है। इस स्कीम से लोगों को अपना घर खरीदने में तो मदद मिल ही रही है, वहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही है। नदी से नदी जोड़ योजना एक महत्वपूर्ण पहल हमारी सरकार ने शुरू किया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना हका जिसका उद्देश्य देश की प्रमुख नदियों को आपस में जोड़कर एक जल नेटवर्क तैयार करना है। इस योजना के माध्यम से, जल अधिशेष वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में पानी स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में केन-बेतवा लिंक परियोजना पर काम चल रहा है। यह परियोजना देश की पहली नदी जोड़ परियोजना है, जिसके तहत केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र को लाभ होगा।

भारत में आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य रहा है। हमारी सरकार ने खरीफ और रबी फसलों के एमएसपी में निरंतर बढ़ोतरी की है। पिछले एक दशक में धान, गेहूं, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खरीद पर 3 गुना ज्यादा राशि खर्च की गई है। अध्यक्ष जो देश में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के लिए कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के दायरे का विस्तार किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को और बढ़ावा मिलेगा।

आदरणीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' का लाभलाखों किसानों को मिल रहा है। अध्यक्ष जी आज़ादी के दशकों बाद भी हमारे जिस जनजातीय एवं आदिवासी समाज की उपेक्षा होती रही है, लेकिन आज मुझे इस सदन में बताते हुए गर्व हो रहा है की हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके कल्याण को पहली प्राथमिकता दी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के अत्यन्त पिछड़े इलाकों में आकांक्षी जिला कार्यक्रम प्रारम्भ कर सुशासन का एक अनूठा प्रयोग किया है। इस कार्यक्रम से इन जिलों में स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे विभिन्न मापदंडों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य रहा है की देश में कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए कई पूर्णक उपाये किए गए। अध्यक्ष जी हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने देश में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स वातावरण बनाने की दिशा में खेलो इंडिया स्कीम, राष्ट्रीय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जैसे कई कदम उठाए हैं। अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश राज्य में दिव्यांगों के लिए ग्वालियर में विशेष खेल केंद्र खोला गया है। सरकार ने खिलाड़ियों को वर्ल्ड लेवल की सुविधाएं प्रदान करके उनका मनोबल ऊंचा किया।

हमारे प्रधानमंत्री जी की ये प्राथमिकता रहीं है की समाज के हर वर्ग तक सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचें, और पहुंच भी रही है। अस्पताल, इलाज और दवा की व्यवस्था के कारण एक सामान्य परिवार में स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च निरंतर कम हो रहा है। वित्त मंत्री ने आम आदमी का ध्यान रखते हुए बड़ी छूट दी है कि उनको 12 लाख रुपये पर कोई टैक्स

भरने की जरूरत नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है विकसित भारत! उनके नेतृत्व में आने वाले वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं।

धन्यवाद।

श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर (खीरी) : बजट 2025-26 सिर्फ लोक लुभावन एवं खोखले वादों का ही बजट है। इसमें जन कल्याण के लिए जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं किया गया है। रोजगार, निवेश और आय के स्तर को बढ़ाने के लिए ठोस नीतियों का अभाव है। सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं एवं रोजगार की गारंटी पर कोई बात नहीं की गई है। देश में मंहगाई एवं बेरोजगारी का स्तर लगातार बढ़ रहा है, तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की आर्थिक साख कमजोर हो रही है, डालर के मुकाबले रुपए की वैल्यू लगातार घट रही है। जिसका प्रतिकूल प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। रोजगार के नाम पर सरकार सिर्फ संविदा एवं आउटसोर्सिंग के जरिए विभिन्न विभागों में भर्तियां कर रही है। नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन स्तर को उठाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार बार-बार घोषणा कर रही है कि 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाएगी मुझे भी भारत के विकसित राष्ट्र बनने पर खुशी होगी, परन्तु इस दिशा में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आय तथा रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर अत्यंत बल देने की जरूरत है। विकास के इंडिकेडर पर हम आज भी बहुत पीछे हैं, मानव विकास सूचकांक 2024 में 193 देशों में भारत 132 वें पायदान पर है जो कि अत्यंत चिंताजनक है। विकसित ? देश जहां रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर जी०डी०पी० का एक बड़ा भाग खर्च कर रहे हैं वहीं भारत में जी०डी०पी० का एक प्रतिशत से भी कम रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर खर्च हो रहा है। बजट 2025-26 में रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर आबंटन नगण्य है। राजकोषीय घाटा लगातार - बढ़ रहा है। FRBM Act 2023 के नॉर्म्स को सरकार पूरा नहीं कर पा रही है जो अत्यंत चिंताजनक है। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने की बात सरकार लगातार कर रही है परन्तु इस बजट में इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया है। इन्नोवेशन में भी बजटीय आबंटन को बढ़ाने की जरूरत है। युवाओं के इसके लिए सहज ढंग से लोन की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। बजट आबंटन के साथ ही मॉनेटरिंग और एक्जीक्यूशन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। भारत गांव में बसता है।

गांव एवं कृषि विकास के बिना हम विकसित भारत की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। कृषि एवं किसानों की प्रगति के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को तुरंत लागू करना चाहिए। सरकारी क्रय प्रणाली को पारदर्शी बनाना चाहिए जिससे विचौलियों को खत्म किया जा सके एवं किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके, इसके साथ ही कृषि क्षेत्र में रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए बजट आवंटन बढ़ाने की जरूरत है। सरकार सिर्फ कुछ प्रतिशत लोगों को ध्यान में रखकर ही नीतियां बना रही है, आम जनता का कल्याण बजट से कोसों दूर है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा SH-21 मार्ग पर जनपद लखीमपुर-खीरी में शारदा नदी पचपेड़ी घाट पर अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है जिससे लोगो को आने जाने में लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की तरफ से चलकर मैलानी जक्शन होते हुए दिल्ली तक, लखनऊ जक्शन की तरफ से चलकर मैलानी जक्शन होते हुए हरिद्वार-पंजाब की ओर तक, लखनऊ जक्शन की तरफ से मैलानी जक्शन होते हुए आगरा की ओर तक तथा मैलानी जक्शन की तरफ से पूर्वोत्तर की तरफ की

ट्रेने चलाने की कृपा करें। जिससे छात्रों, व्यापारियों एवं आम जनता को आने जाने के लिए सुविधा मिल सकें। मैलानी जक्शन से पलिया कला, तिकुनिया, बहराइच होते हुए गोण्डा तक मीटरगेज को ब्राण्डगेज में परिवर्तित कर रेल का संचालन कराने का कृपा करें। लखीमपुर रेलवे स्टेशन और गोला रेलवे स्टेशन के मध्य रजागंज स्टेशन के पास बने रेलवे फाटक को बन्द कर दिया गया है। जिससे 60-70 गाँवों को अधिक दूरी तय कर आना जाना पड़ता है तथा फाटक के पार हिन्दुओं का शमशान, मुस्लिमों का कब्रिस्तान व मस्जिद है जिससे लोगों को उक्त स्थान पर शव ले जाने में 3 किमी० की दूरी तय करनी पड़ती है। कृपया रजागंज के पास रेलवे फाटक खुलवाने की कृपा करें। गोला रेलवे स्टेशन के पास ग्राम भवानीगंज ग्रा०पं० पुनर्भूगर्भ में मरघट रोड को रेलवे द्वारा बन्द कर दी गई है। जिससे लगभग 20 हजार की आबादी प्रभावित हो रही है गाँव के बच्चों को स्कूल आने जाने में, बजाज चीनी मिल में कार्यरत कर्मचारियों एवं मजदूरों को आने जाने में, अस्पताल एवं मुक्ति धाम आने जाने में दिक्कत होती है। कृपया भवानीगंज मरघट रोड के पास पुल/ओवर ब्रिज बनवाने की कृपा करें। जनपद लखीमपुर के खीरी टाउन में अरनीखाना रेलवे स्टेशन था जिसे बदलकर हॉल्ट कर दिया गया है जबकि खीरी टाउन की आबादी लगभग 60-70 हजार की है। कृपया पुनः अरनीखाना रेलवे स्टेशन बनाने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर-खीरी में प्रति वर्ष विकास खण्ड पलिया, बिजुआ, निघासन, रमियाबेहड़, फूलबेहड़ एवं नकहा में शारदा नदी की बाढ़ से हजारों गाँव प्रभावित हो जाते हैं और प्रति वर्ष सरकार का करोड़ों रुपया खर्च होता है। फिर भी सैकड़ों मकान और सैकड़ों एकड़ जमीन कटकर नदी में समा जाती है। प्रति वर्ष जन और धन की हानि होती है। प्रति वर्ष करोड़ों रुपया खर्च करने के बजाय इसका स्थाई समाधान बनबसा डेम से शारदा बैराज तक शारदा नदी के उत्तरी एवं दक्षिणी तटबन्ध बनाने की कृपा करें। जिससे लोगों की जन एवं धनहानि न होने पायें तथा शारदा बैराज से NH-730 पर शारदा पुल तक उत्तरी तटबन्ध बना हुआ है। कृपया शारदा बैराज से NH-730 पर शारदा पुल तक का भी दक्षिणी तटबन्ध बनवाने की कृपा करें। जनपद लखीमपुर खीरी में नेपाल से आने वाली महोना, सुहेली नदी भी बाढ़ से मकान एवं जमीनें काटकर नदी में समा लेती है इन नादियों पर जहाँ-जहाँ कटान हो रहा है। वहाँ-वहाँ स्पर बनवाकर नादियों को मूलधारा में भेजने की कृपा करें। जिससे किसानों की बाढ़ से सुरक्षा हो सकें। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के जनपद में हमारी 28-खीरी लोकसभा क्षेत्र में कोई नवोदय विद्यालय नहीं है। हमारा लोकसभा क्षेत्र नेपाल सीमा से लगा हुआ जिसमें शिक्षा का अत्यधिक आभाव है आपसे निवेदन है कि जनहित में विकास खण्ड फूलबेहड़ में एक नवोदय विद्यालय बनवाने की कृपा करें।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद के दुधवा टाईगर प्रोजेक्ट क्षेत्र से वन्य पशु वन्य क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं। जिससे वन्य पशु दर्जनो मानवों का शिकार कर वध कर देते हैं। दुधवा टाईगर प्रोजेक्ट क्षेत्र को चारों तरफ तार से घेरने की कृपा करें। जिससे मानव वध को रोका जा सकें। मानव वध पर मुआवजा कम से कम 10 लाख रुपया किया जाये। उत्तर प्रदेश का जनपद लखीमपुर-खीरी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनपद है और नेपाल सीमा से लगा हुआ है। कई वर्षों से हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर न होने के कारण काफी लोगों की जानें चली जाती हैं। कृपया हृदय रोग डॉक्टर की नियुक्ति कराने की कृपा करें। सरकार हर बार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, परन्तु बजट में समावेशी विकास की अवधारणा नदारद है। पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए कोई ठोस प्रयास बजट में नजर नहीं आता है। सरकार की नीतियों के कारण अमीर और गरीब के बीच आय विषमता लगातार बढ़ रही है। गरीब लगातार और गरीब होता जा रहा है, जो कि गरीबों के प्रति सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाती है। देश

को विकसित बनाने के लिए कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, निवेश, अनुसंधान, एवं रोजगार पर अत्यधिक ध्यान देने की जरूरत है। बजट 2025-26 में इन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार को नारेबाजी एवं जुमलेबाजी से हटकर देश के विकास के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। जिससे लोगों की आय बढ़ सके तथा उनके जीवन में खुशहाली लाई जा सके।

अदम गोंडवी जी की चंद लाइनों के साथ की मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा-

? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी हैं।?

धन्यवाद।

श्री राम शिरोमणि वर्मा (श्रावस्ती) : मैं बजट 2025-2026 पर अपने विचार रखता हूँ। साथ ही, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से और मेरे लोक सभा क्षेत्र श्रावस्ती और बलरामपुर की सम्मानित जनता का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद देकर लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर संसद में भेजा ताकि मैं पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक (पीडीए समाज), शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब, किसान, युवा, महिला और बेरोजगार की आवाज को इस सदन में गंभीरता से उठा सकूँ।

सबसे पहले मैं, मौजूदा सरकार के बदइंतजामी और नाकामी के कारण महाकुंभ में हुई दुखद घटना में अपनी जान गवाने वाले श्रद्धालुओं के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।

हमारे देश में आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर के योगदान तथा प्रयासों के कारण हमें यह प्रजातांत्रिक संविधान मिला है। लेकिन मौजूदा सरकार ने सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं का जिस तरह से सर्वनाश किया है, वह अत्यंत ही दुखद है।

इस बात के वैसे तो अनेकों उदाहरण मौजूद हैं, लेकिन सबसे ताजा उदाहरण प्रयागराज में चल रहे पावन महाकुंभ में स्नान करने आए श्रद्धालुओं की हुई मौतों पर सरकार द्वारा पर्दा डालने की कोशिश करना है। समाज के कई गरीब और असहाय लोगों की जान चली गई। उस पर सरकार की चुप्पी अत्यंत ही दुखद है।

बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बजट भाषण में किसानों का कर्ज माफ करने, एमएसपी (MSP) लागू करने, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने, युवाओं और महिलाओं के लिए नए रोजगार उपलब्ध करने, फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू करने, किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली देने, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की मानदेय बढ़ाने के बारे में, संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, तथा शोषित, पीड़ित और वंचित लोगों के उत्थान के लिए और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है।

देश का अन्नदाता किसान आज बहुत परेशान है। कितने किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का था। आज 2025 चल रहा है। सच्चाई यह कि धरातल पर देखा जाए तो किसानों की आय दोगुनी तो हुई नहीं, उल्टे महंगाई कई गुनी जरूर बढ़ गई है।

किसानों को कृषि कार्य के लिए उपयोग में लायी जाने वाली कृषि उपकरणों पर लगने वाले टैक्स में 100 प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। खाद, यूरिया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैशियम, जिंक, डी.ए.पी. आदि के दाम आसमान छू रहे हैं। यूरिया बैग, जो पहले 50 किलो का आता था, सरकार ने उसे घटाकर 40 किलो कर दिया, लेकिन उसके दाम में कोई कटौती नहीं की गई है, जिससे किसानों की लागत बढ़ गई है।

देश में बच्चों को फ्री शिक्षा दिए जाने के सम्बंध में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए बजट में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। बढ़ती कमरतोड़ महंगाई के दौर में बच्चों की शिक्षा आज बहुत ही महंगी हो गयी है। एक आम गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकता। सरकार को पूरे देश में फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू करना चाहिए। हमारा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती और जनपद बलरामपुर, जो आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आता है, वह शिक्षा के मामले में बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। आज भी यहाँ के बच्चे उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं।

श्रावस्ती जनपद में आज तक कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

बजट भाषण में मनरेगा मजदूरों के विकास के सम्बंध में मैं कहना चाहता हूँ कि वर्तमान बजट में मनरेगा के लिए बजट आवंटन बढ़ने की उम्मीद पूरा देश लगाए बैठा था, लेकिन गरीब मजदूरों के प्रति उदासीन रवैया अपनाते हुए इस सरकार ने मनरेगा का बजट पिछली बार की तरह ही इस बार भी 86,000 करोड़ पर ही स्थिर रखा है।

जिस तरीके से मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 237 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती है। वह आज के कमरतोड़ महंगाई के दौर में ?ऊंट के मुह में जीरा? के समान है।

बजट में मनरेगा मजदूरों की 100 दिन की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 365 दिन किया जाना चाहिए था और उन्हें मिलने वाली दैनिक मजदूरी को 237 रुपए से बढ़ाकर कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन की जानी चाहिए थी, जिसका इस बजट भाषण में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है।

प्रधानों को मनरेगा का पैसा समय पर नहीं मिलता है, जिस कारण ग्राम सभा स्तर पर विकास कार्य बाधित होते हैं। उनको समय पर पैसा देना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

देश में जातिगत जनगणना कराये जाने के सम्बंध में मैं कहना चाहता हूँ कि बजट भाषण में सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। वर्तमान समय में समाज के सबसे निचले तबके और वंचित वर्ग के लोगों को, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और देश से बेरोजगारी को दूर करने के लिए

सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना कराना आवश्यक है। ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वास्तव में जो पात्र लाभार्थी हैं, उनकी पहचान करके, उनके अनुरूप संसाधनों की व्यवस्था, रोजगार और नीति का निर्धारण किया जा सके, जिसका बजट भाषण में कोई जिक्र नहीं है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष राहत पैकेज के देने के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि इस बजट भाषण में देश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोई विशेष पैकेज की व्यवस्था नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश के कई बाढ़ प्रभावित जिलों, जिनमें मेरे संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती के दोनों आकांक्षी जिलों श्रावस्ती और बलरामपुर में लगभग हर साल राप्ती नदी में बाढ़ आती है, जिससे हजारों एकड़ जमीन पानी से जलमग्न हो जाता है, किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है, लोगों के भारी जान-माल का नुकसान होता है। बजट भाषण में बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की जानी चाहिए थी, जिसका बजट भाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं है।

सांसद स्थानीय विकास निधि को बढ़ाने के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि इस बजट भाषण में सांसद निधि बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। हम सब यह जानते हैं कि लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का दायरा विधान सभा से कई गुना ज्यादा होता है। अमूमन एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत करीब 5 से 7 विधान सभा क्षेत्र आते हैं। प्रत्येक सांसद को क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपये सांसद निधि (सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत) मिलती है, जो बहुत ही कम है जबकि उत्तर प्रदेश के विधायक को एक विधान सभा क्षेत्र के विकास के लिए सांसद के बराबर ही 5 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष मिलते हैं। उक्त निधि से सांसद एक विधान सभा में केवल एक किलो मीटर तक ही सड़क बनवा सकता है। इस तरह वह साल भर में केवल 5 किमी ही सड़क बनवा सकता है। ऐसे में इतने बड़े संसदीय क्षेत्र का विकास कैसे हो पायेगा? इसलिए सरकार को सांसद निधि बढ़ा कर 25 करोड़ रुपये करने पर विचार करना चाहिए। साथ ही, इसे जीएसटी मुक्त करना चाहिए।

पुरानी पेंशन को बहाल करने के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि बजट भाषण में सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के लिए कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। करीब 20 वर्षों से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों के करीब 6 करोड़ कर्मचारी और उनके आश्रित इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। सरकार से मेरी मांग है कि कर्मचारियों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा हेतु पुरानी पेंशन व्यवस्था को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए।

वैसे तो यह सरकार अपनी उपलब्धियां का डंका जोर-जोर से पीट रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। आज देश का हर तबका महंगाई की मार झेल रहा है तथा विकास की धीमी गति से आम आदमी की प्रगति पर बेड़ियां पड़ गयी हैं।

सरकार के आर्थिक सर्वे में स्वयं स्वीकार किया गया है कि अर्थव्यवस्था के विकास की गति 6.3 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत के बीच रहने वाली है जबकि करीब 145 करोड़ की जनसंख्या जैसे विशाल देश को विकसित देश बनाने के लिए कम से कम 8 प्रतिशत की आर्थिक विकास की गति जरूरी है। इस बात को सरकार भी स्वीकार करती है, लेकिन यह सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा देने

वाली है, जिसके कारण उसके निर्णय के केन्द्र में आम जनता न होकर सिर्फ पूंजीपति ही होते हैं। इस सरकार की नीतियों के कारण गरीब और गरीब होता जा रहा है, जबकि अमीर और अमीर हो रहा है। आज भी हमारी आबादी का एक बड़ा भाग गांव में रहता है, लेकिन गांवों के विकास पर इस सरकार का बिल्कुल भी फोकस नहीं है। यह सरकार विज्ञापन के माध्यम से अपनी छवि बनाने में जुटी है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि आम जनता को अपना जीवन यापन करने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज भी हमारे अन्नदाता किसान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है।

इस बजट ने समाज के सभी वर्गों को निराश किया है। यह बजट असल में चुनावी बजट है। मैं और हमारी पार्टी इस बजट का विरोध करते हैं।

धन्यवाद।

श्री जयन्त बसुमतारी (कोकराझार) : माननीय सभापति महोदया, सबसे पहले मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को आयकर सीमा 12 लाख रुपए करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं, क्योंकि आपके इस ऐतिहासिक फैसले से देश की बहुत बड़ी आबादी को फायदा होगा। मिडिल क्लास को 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखकर आपने बड़ी राहत दी है। यह बहुत अच्छा कदम है। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। आम बजट वर्ष 2025-2026 भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। यह हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। बजट वर्ष 2025-26 विकसित और हर क्षेत्र में श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। किसान, गरीब, मध्यम वर्ग, महिला और बच्चों की शिक्षा, पोषण, स्टार्टअप, निवेश तक हर क्षेत्र को समाहित करता यह बजट मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का रोडमैप है।

उत्तर पूर्व क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी संभावनाएँ हैं, जिसके लिए सरकार पहले से ही ध्यान दे रही है। मेरी माँग है कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद इलाके में पर्यटन के विकास के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करें और यह राशि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद को भेजी जाए। यह जानकारी बहुत खुशी हो रही है कि देश में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढाँचे का विस्तार होगा और अगले तीन साल में देश के सभी जिलों में कैंसर देखभाल केन्द्र शुरू किए जाएंगे। इनमें से 200 केन्द्र वित्त वर्ष 2025-26 में शुरू हो जाएंगे। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गिग वर्कर्स को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ दी जाएंगी। सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के आधारभूत ढाँचे का विस्तार करने का फैसला भी किया है। अगले 10 वर्षों में चिकित्सा शिक्षा के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, परास्नातक की लगभग 1.1 लाख सीटें बढ़ेंगी यानी 130 प्रतिशत की वृद्धि होगी। 36 जीवन रक्षक दवाओं पर से पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया जायेगा। सभी सरकारी अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। कैंसर के इलाज की दवाएँ सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5 फीसदी कर दी जाएगी। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यह बहुत अच्छा कदम है कि सरकार 5 आईआईटीज में अतिरिक्त बुनियादी ढाँचे का निर्माण करेगी और सरकार स्कूलों और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की

पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करेगी। पिछले 10 वर्षों में 23 आईआईटीज में छात्रों की कुल संख्या 65 हजार से बढ़कर 1.35 लाख तक पहुँच गई है यानी यह संख्या 100 प्रतिशत बढ़ी है। वर्ष 2014 के बाद शुरू किए गए 5 आईआईटीज में अतिरिक्त बुनियादी ढाँचा तैयार किया जाएगा ताकि और 6,500 छात्रों को शिक्षा मिल सके। अगले 5 वर्षों में आईआईटी और आईआईएससी में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10 हजार फेलोशिप प्रदान की जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, उससे हमारी आने वाली पीढ़ी देश की तरक्की को देखेगी।

धन्यवाद।

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर) : महोदया, धन्यवाद।

आज इस ऐतिहासिक दिन में, आज इस ऐतिहासिक स्थान पर मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर चलते हुए एक जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है।

सर्वे भवन्तु सुखिनः।

सर्वे सन्तु निरामयाः।।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।

मा कश्चित दुःख भाग्भवेत्।।?

सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ रहें, सभी मंगलमय घटनाएँ देखें और किसी को भी दुःख का अनुभव न हो।

महोदया, यह बजट न केवल मध्यम वर्ग के लिए है, बल्कि यह बजट किसानों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं और उद्यमियों के लिए भी नए अवसरों के द्वार खोलने वाला है।

महोदया, लोकप्रिय माननीय प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है कि आदरणीय वित्त मंत्री जी ने आय कर स्लैब में बदलाव करके मध्यम वर्ग को अभूतपूर्व राहत दी है। अब 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा और 12 लाख 75 हजार रुपये तक की आय पर स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ने पर भी कोई कर नहीं देना है। कांग्रेस सरकार के समय ढाई लाख रुपये तक की आय पर ही कर में छूट थी लेकिन हमारी सरकार ने इस सीमा को 12 लाख रुपये तक बढ़ा दिया। जब देश के नागरिकों की जेब में अधिक पैसा होगा तो देश की अर्थव्यवस्था और अधिक सशक्त होगी।

महोदया, कांग्रेस का नारा ?कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ? था, मगर इसका उलटा हुआ और कांग्रेस का हाथ, आम आदमी की पॉकेट में चला गया था। कांग्रेस नेता पी. चिदम्बरम जी ने कहा था कि आय कर में कटौती से सरकार का राजस्व घटेगा,

जिससे विकास प्रभावित होगा। आज हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह साबित कर दिया कि करों में कटौती भी विकास को गति दे सकती है इसलिए मैं कहता हूँ कि ?मोदी है तो मुमकिन है।

?चमन में जब बहार आएगी खुशबू से यह फिजा महकेगी,
अब हर जेब में खुशहाली होगी,
हर हाथ को मेहनत की उचित कीमत मिलेगी।?

भारत की जीडीपी वर्ष 2025 में 4.25 ट्रिलियन डालर होने की उम्मीद है, जिससे यह दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत की जीडीपी वर्ष 2025 में पीपीपी के हिसाब से दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है। इसके लिए मैं नरेन्द्र मोदी जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 26 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह से छूट दी गई है। यह निर्णय स्वास्थ्य सेवा को सुलभ और किफायती बनाएगा। कैंसर की दवाइयों को कर मुक्त किया गया है। इसके लिए मैं मोदी जी और वित्त मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आम जनता की स्वास्थ्य व्यवस्था का ध्यान रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने देश की 140 करोड़ जनता के हित में बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं। एमएसएमई सेक्टर में क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के लिए उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत की जाएगी। सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी है। इससे हमारे बुजुर्गों को अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। 100 पिछड़े जिलों में कृषि सुधारों को बढ़ावा दिया जाएगा। 7.7 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए छह वर्षीय मिशन चलाया जाएगा।

सभापति महोदया, बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा। भगवान बुद्ध से जुड़े पर्यटन स्थलों को विकसित किया जाएगा। यह बजट बिहार और पूर्वी भारत के लिए स्वर्णिम युग की शुरुआत करेगा।

महोदया, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार में स्थापित हो रहा है। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, जिससे किसानों को मदद मिलेगी। बिहार के मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। एस.सी., एस.टी. महिलाओं के लिए 2 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन देने की घोषणा की गयी है। महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजनाएं चलायी जाएंगी।

माननीय सभापति महोदया, आदिवासी कल्याण का बजट आवंटन वर्ष 2014-15 के 4,497.96 करोड़ रुपये से बढ़कर 14,295.81 करोड़ रुपये हो गया है, जो 231.83 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

सभापति महोदया, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को पाँच वर्षों के लिए 80,000 करोड़ रुपये का आवंटन दिया गया है। एकलव्य विद्यालय का बजट 4,798 करोड़ रुपये से बढ़ कर 7,088 करोड़ रुपये हो गया है।

?सोच बड़ी हो तो, सपने भी सच होते हैं,

इरादे नेक हों तो, रोशनी हर दिशा में फैलती है।?

सभापति महोदया, यह बजट ?आत्मनिर्भर भारत? की मजबूत नींव रखते हुए विकसित भारत बनाने का संकल्प भी रखता है। यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि यह आम आदमी की जिन्दगी में सुधार का बजट है।

?उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः

दैवेन देयमिति कापुरुषाः वदन्ति॥?

लक्ष्मी और समृद्धि उन्हीं का साथ देती हैं, जो मेहनत करते हैं, जबकि कमजोर लोग भाग्य को दोष देते हैं।

माननीय सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र से संबंधित मेरी कुछ दो-चार मांगें हैं। मेरे लोक सभा संसदीय क्षेत्र की जनता सबसे ज्यादा पीड़ित जिस बात से है, वह गंगा के कटान से पीड़ित है। फुलहर और गंगा नदी से लगे हुए मेरे क्षेत्र के दो ब्लॉक्स हरीशचन्द्रपुर-2 और रतुवा-1 में महानंदा टोला और भिलाईमारी ग्राम पंचायत हैं। वहां के लोग हर वर्ष नदी की बाढ़ के कारण बेघर हो रहे हैं। इससे लोगों को बचाने के लिए इस पर ध्यान देने की मैं मांग करता हूं।

महोदया, मेरी मांग है कि उत्तर बंगाल की जनता के लिए रायगंज में एक एम्स की स्थापना की जाए।? (व्यवधान)

श्री उमेशभाई बाबूभाई पटेल (दमन और दीव) : माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 2025-26 पर अपने विचार साझा करने के लिए खड़ा हूं। मंत्री जी ने विभिन्न मंत्रालयों की कई जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की हैं। मेरा मानना है कि घोषणा की-गई योजनाएं जब तक धरातल पर लागू नहीं होतीं, तब तक योजनाओं का कोई मतलब नहीं होता। हमारे प्रदेश में बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। केन्द्र की बहुत सारी योजनाओं का लाभ हमारे स्थानीय प्रशासन की इच्छा शक्ति के अभाव के चलते लोगों को नहीं मिल पा रहा है।

सरकार अर्बन डेवलपमेंट करने की बात कर रही है, पर यह दुःखद है कि हमारे पूरे प्रदेश में एक बस स्टैंड तक नहीं है। बस स्टैंड तो छोड़ दीजिए, बस स्टैंड के स्थल पर पीने के पानी एवं टॉयलेट की सुविधा तक नहीं है। यह इच्छाशक्ति का अभाव ही है।

महोदया, सरकार समुद्र किनारे से 200 किलोमीटर तक मछली मारने के धंधे का विकास करना चाहती है, पर हमारा प्रशासन तो समुद्र तट से 200 फीट पर भी हमें मछली मारने का धंधा नहीं करने दे रहा है। दमन-दीव में समुद्र किनारे मछली सूखाने की काठियां तोड़ दी गयी हैं। जो मछुआरे समुद्र के किनारे अपने बोट्स की फटी जाली सिला करते थे, उन्हें बंद करा दिया गया है। पुर्तगालियों के समय में जिस स्थल पर बोट्स पार्क होती थीं, वहां से मछुआरों को बिना नोटिस दिए उनकी नावों को तोड़ कर फेंक दिया गया, क्योंकि वहां हमारे प्रशासक जी को अपने मित्रों को गो-कार्टिंग करानी है।

सरकार 200 किलोमीटर की बात करती है और हमारा प्रशासन 200 फीट पर भी काम-धंधा नहीं करने दे रहा है। यह है इच्छाशक्ति का अभाव।

हमारे प्रदेश में दीव के समुद्र में ड्रेजिंग की वर्षों की मांग का भी यही हाल है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, पर काम किन्हीं कारणों से शुरू नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही हाल हमारे हार्बर का भी है। यही हाल हमारे लगभग सारे के सारे प्रोजेक्ट्स का हो रहा है। सालों से पूरे प्रदेश के रोड खोद-खाद के रखे गए हैं, लेकिन काम पूरे ही नहीं करवाए जा रहे हैं। छोटे-छोटे दो-तीन किलोमीटर के रोड के काम भी पांच-छह साल से चलते ही जा रहे हैं। इसे कहते हैं इच्छाशक्ति का अभाव।

एक छोटे से प्रदेश में आईएस, आईपीएस, आईएफएस, दानिक्स, दानिप्स जैसे 42 अधिकारियों की फौज के बावजूद केंद्र की ज्यादातर योजनाएं हमारे प्रदेश में लागू नहीं हो पा रही हैं तो इतने सारे अधिकारी करते क्या हैं? हमारे पड़ोसी गुजरात का एक जिला, जो हमारे पूरे प्रदेश से बड़ा है, उस जिले में केवल एक कलेक्टर और एक पीआई काफी है और हमारे यहां इतने सारे अधिकारी होने के बावजूद स्थिति बद से बदतर हो रही है।

महोदया, जब हमारे संघ प्रदेश दमन और दीव का मर्जर डीएनएच के साथ हुआ था, तब कहा गया था कि इस मर्जर से मानव संसाधनों की बचत होगी तो इतने सारे अधिकारियों की ज़रूरत क्या है और पॉप्युलेशन के हिसाब से भी इतने सारे अधिकारियों ज़रूरत भी नहीं है।

अधिकारी सरकारी नौकर नहीं, वहां के जागीरदार बन गए हैं, जो विकास राशि का दुरुपयोग कर अय्याशी कर रहे हैं। उनके कार्यकाल पूर्ण होने पर भी, उनके तबादले के आदेश आ जाने पर भी वे लोग हमारे प्रदेश से रिलीव नहीं होते हैं। क्या वजह है कि वे रिलीव नहीं होना चाहते हैं? भ्रष्टाचार चरम पर है। मैं नमूने के तौर पर आपको कुछ सबूत दिखाना चाहता हूँ। यह पहला टेंडर है, जो दिनांक 08-10-2020 को निकला था, जो लगभग 23 करोड़ 34 लाख रुपये का, सचिवालय के रेनोवेशन के लिए था। यह दूसरा टेंडर है, जो दिनांक 28-09-2022 का है, जो लगभग चार करोड़ रुपये का था, जो इसी रेनोवेटिड सचिवालय को तोड़ने के लिए था। फिर से तीसरा टेंडर निकाला जाता है, और वह 02-09-2023 का है, जिसकी राशि 12 करोड़ रुपये की थी, जो सचिवालय को फिर से रीस्टोर करने के लिए था। कहने का मतलब है कि दो साल पहले बनाया गया, फिर तोड़ा गया उसके बाद तीसरे साल फिर से बनाया गया।

एक और टेंडर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिल्ली स्थित हमारा डीएनएच और दमन और दीव का एक भवन है, जो 30 सितंबर, 2024 को निजी संस्था जिंजर को सौंप दिया गया। फिर दो महीने के बाद, यानि सितंबर को सौंप दिया गया, नवंबर में उसका तीन करोड़ रुपये का टेंडर निकाला जाता है और उससे किचन बनाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपने दो महीने पहले भवन दे ही दिया है, तो फिर किचन का खर्चा हमारा प्रशासन क्यों कर रहा है, सरकार क्यों कर रही है?

महोदया, हमारे पूरे प्रदेश के विकास कार्य के टेंडरों को देखेंगे तो ज्यादातर विकास कार्य लागत कीमत से 40 से 45 प्रतिशत ऊपर ही होते हैं। साथ ही ज्यादातर विकास कार्य समय पर पूरा न करवा कर फिर से रिवाइज करवाए जाते हैं। जो काम एक करोड़ रुपये में होना चाहिए, वह काम तीन करोड़ रुपये में हो रहा है। यह सब भ्रष्टाचार का खेल खुले आम खेला जा रहा है। यह सबूत तो केवल झांकी है, पक्कर तो अभी पूरी बाकी है।

महोदया, मुझे किसी ने बताया कि कुछ सालों में हमारे प्रदेश में 12,000 करोड़ रुपये के विकास के कार्य हुए। मैं आपको दावे से कहना चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच हो तो 12,000 करोड़ रुपये में से 6,000 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार निकलेगा। हमारे प्रदेश के प्रशासक जी विकास राशि का इस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रशासक के निजी इस्तेमाल के लिए ?गुजसेल? का विमान, जो प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन है, उसके इस्तेमाल करने की बात आ रही है। वे तो आम फ्लाइट से भी जा सकते हैं। ? (व्यवधान)

महोदया, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे प्रदेश की विकास राशि की सीएण्डएजी या सीबीआई से जांच की जाए और हमारे प्रदेश अधिकारियों की समीक्षा कर, आर्थिक बोझ समान अतिरिक्त अधिकारियों को तुरंत कम किया जाए।

मैडम, मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार गरीबों को आवास देना चाहती है और हमारा प्रशासन आवास देने की जगह लोगों के घर-मकान तोड़ रहा है। सरकार मनरेगा के माध्यम से रोजगार देने की बात करती है, परंतु हमारे यहां मनरेगा की स्कीम ही लागू नहीं है। सरकार हेल्थ को लेकर काफी चिंतित है, परंतु दुखद है कि हमारे प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त में इलाज नहीं मिलता है। स्वराज्य संस्थाएं मज़बूत होनी चाहिए। हमारे यहां स्टेट असेंबली नहीं है तो स्वराज्य संस्थाओं को मज़बूत करना चाहिए। हमें सात-सात सालों से वहां पर फंड नहीं दिए जा रहे हैं।

मैडम, सरकार की आय बढ़ानी चाहिए। हमारे यहां विकास राशि से भवन बनाए जाते हैं, सर्किट हाउसेस बनाए जाते हैं, अन्य प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं और उन्हीं भवनों को निजी हाथ में सौंप दिया जाता है।

मैडम, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार इन सारी बातों का संज्ञान ले।? (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर) : सभापति महोदया, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने मुझे वर्ष 2025-26 के बजट पर हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया।

महोदया, जब आम बजट आने वाला था तो राजस्थान को बहुत बड़ी उम्मीद थी। हम किसी राज्य के खिलाफ नहीं हैं। बजट में बिहार को बहुत कुछ दिया गया है। पिछली बार भी जहां-जहां चुनाव था, वहां काफी कुछ दिया गया था। आंध्र प्रदेश के अंदर भी बहुत कुछ दिया गया। चुनावी समय में सरकार उन क्षेत्रों का ध्यान रखती है। राजस्थान के अंदर विशेष बजट का आवंटन और विशेष राज्य का दर्जा की मांग रहती है।

महोदया, हम सब की इच्छा रहती है कि जब देश का बजट आता है तो उस समय प्रत्येक सांसद से बात की जाए, संवाद किया जाए। कोई जरूरी नहीं कि आप सांसद की बात माने, लेकिन अगर उनसे संवाद किया जाए और उसके बाद देश का बजट आए तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा बजट देश के अंदर आ सकता है। मोदी जी को यह एक नई पहली करनी चाहिए थी, क्योंकि वह हर मामले में नई पहल की बात करते हैं। आंकड़ों के मायाजाल के अंदर उलझा कर रख देना अच्छी बात नहीं है। आज उसी तरह की हालात दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है।

महोदया, हाल ही के वर्षों में सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, चक्रवात जैसी आपदाओं की संख्या बढ़ी हैं, लेकिन सरकार ने किसानों को राहत देने के बजाय उनका बीमा कवर घटा दिया। लागत बढ़ने और उचित समर्थन मूल्य नहीं मिलने के कारण किसान पहले से ही संकट में हैं। इस बजट में भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। मेरी मांग है कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए। पीएम फसल बीमा योजना में खरीफ फसलों को सम्मिलित किया जाए। अभी इसको निकाल दिया गया है। कृषि आदान-अनुदान की सीमा राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में 2 हेक्टेयर से बढ़ा कर 5 हेक्टेयर की जाए। इसके साथ ही सूखा विकास कार्यक्रम में आने वाले जिलों में पांच हेक्टेयर भू-धारिता वाले किसानों को भी लघु-सीमांत किसानों की श्रेणी में शामिल किया जाए।

सभापति महोदया, मैं खेती और किसानों की बात करता हूं, क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं और किसान का बेटा हूं। निश्चित रूप से मैंने बड़े किसान आंदोलन भी किए। देश के कुल कृषि बजट से 20 गुना ज्यादा तो किसान पर कर्जा है। 32 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का किसान के ऊपर कर्जा है। आप लोग एक सवाल के जवाब में ऐसा बता रहे थे। कर्ज माफी की योजना बनाने से आपने इंकार किया है। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग को आपने नजरअंदाज किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पिछले सात वर्षों में सबसे कम आवंटन इस बजट में किया गया है। मेरी मांग है कि वित्त मंत्री जी इसका जवाब दें। आपने इसके अंदर फसल बीमा का दायरा बढ़ाया है। प्राकृतिक आपदाओं को आपने फसल बीमा से बाहर निकाल दिया। आपने यह मैसेज दिया कि आप सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। वित्त मंत्री जी किसान, एमएसपी, गारंटी कानून और फसल बीमा के ऊपर निश्चित रूप से पूरे देश को बताएं।

महोदया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अनदेखी की जा रही है। मनरेगा का बजट घटा दिया गया है। आज बेरोजगारी काफी तेजी से बढ़ रही है। लोग मनरेगा के माध्यम से मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे हैं। इस बार आपने मनरेगा का बजट नहीं बढ़ाया है। आप मनरेगा का भी बजट बढ़ाएं, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मनरेगा के ऊपर ही टिकी हुई है।

महोदया, स्वास्थ्य क्षेत्र की भी अनदेखी गई है। कोविड के बाद देश के अंदर जिस तरह के हालात बने थे, वे ठीक नहीं थे। भारत का स्वास्थ्य बजट जीडीपी का मात्र 3.3 परसेंट है, जबकि वैश्विक मानक 5-6 प्रतिशत का होता है।

महोदया, ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति दयनीय है। इस दिशा में कोई नई योजना लाई जाए। मैं सदन के अंदर बताना चाहूंगा कि दिल्ली में स्थित हॉस्पिटल्स में काफी पद खाली हैं। कोविड-19 के बाद भी जब डॉक्टर्स के पद ही खाली हैं तो स्वास्थ्य सेवाएं कैसे ठीक होंगी। मैं दिल्ली के बारे में बता देता हूँ। दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में 172, लेडी हार्डिंग में 89 और आरएमएल में 100 चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। यह स्थिति देश की राजधानी के मुख्य अस्पतालों की है। आखिर हम कब विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप देश की आबादी की तुलना में चिकित्सकों की उपलब्धता करवा पाएंगे। इसके लिए मेरी मांग है कि चिकित्सकों के खाली पदों को भरा जाए। निजी निवेशकों के प्रोत्साहन की जो कमी है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। बजट में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन नहीं दिए गए हैं। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण और उद्योगों की वृद्धि धीमी हो सकती है। इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। एफडीआई को लेकर सरकार के मंत्री बड़े-बड़े भाषण

देते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि भारत की एफडीआई वृद्धि दर पहले ही धीमी पड़ रही है और यह बजट इसे बढ़ावा देने में असफल रहा है।

महोदया, इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए सरकार ने कुछ घोषणाएं की हैं। यह बजट ऊपरी आय वर्ग को ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला बजट है। इसमें कुछ राहत जरूर दी गई है। आप लोग 12 लाख रुपये की सीमा को बढ़ा कर कम से कम 15 लाख रुपये करें। महंगाई की वजह से आम आदमी की वास्तविक आय पहले से ही प्रभावित हो रही है। आप पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटाएं। होम लोन, शिक्षा लोन, स्वास्थ्य खर्चों पर टैक्स कटौती बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

महोदया, सरकार ने इस बजट के अंदर राजकोषीय घाटे के बढ़ते बोझ के बारे में बताया। सरकार ने राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.4 प्रतिशत जीडीपी रखा है, जो वैश्विक मानकों के अनुसार अधिक है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन आपके कार्यकाल में भी सरकार लगातार उधारी बढ़ा रही है। इससे आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ सकता है।

सभापति जी, मैं सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूँ कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74 पर्सेंट से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव घरेलू बीमा कंपनियों के लिए खतरा बन सकता है। इससे विदेशी कंपनियों का वर्चस्व बढ़ेगा और भारतीय कंपनियों को नुकसान होगा, जिससे लाखों नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं।

इस बजट का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 12.76 लाख करोड़ रुपये तो सिर्फ कर्ज के ब्याज के भुगतान में ही चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि सरकार के पास नए विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए सीमित संसाधन बचेंगे। इसलिए मेरे सुझाव पर सरकार को गौर करने की जरूरत है। मैं महंगाई नियंत्रण की बात करूंगा। देश में बढ़ती महंगाई की मार को कैसे कम किया जाए?

मैं अब अपने इलाके की बात पर आऊंगा। लाइम स्टोन प्रचुर मात्रा के अंदर नागौर, जोधपुर और मारवाड़ के अंदर निकलता है। हमारे यहां लाइम स्टोन के छोटे पट्टे किसानों को दिए जाएं और खनिज नीति में बदलाव किया जाए, यह मेरी सरकार से मांग है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जितने गांव बच गए, जितनी ढाणियां बच गईं, उनको जोड़ा जाए। वर्ष 2011 की जनगणना हुई। उसके बाद से अब तक कई नई ढाणियों का विस्तार हुआ है। हम चाहते हैं कि 250 के स्थान पर 50 से 100 की आबादी वाली ढाणियों को भी इस योजना के अंतर्गत डामरीकृत करने का प्रावधान लाया जाए, ताकि ढाणियों में रहने वाले लोगों को भी सुलभ यातायात का लाभ मिल सके। मरुस्थलीय क्षेत्र में 50 की आबादी वाली सैकड़ों ढाणियां मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर तथा हजारों ढाणियां पश्चिमी राजस्थान के अंदर हैं।

मैं इतना ही चाहूंगा कि जब वित्त मंत्री जी बजट पर अपना रिप्लाय दें, तब बताएं कि जो पद खाली हैं, उनमें आप नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं और आप महंगाई किस तरह घटा रहे हैं?

SHRI PHANI BHUSAN CHOUDHURY (BARPETA): Madam Chairperson, at the outset, I thank you for giving me an opportunity to speak in this august House. The Budget presented by the hon. Finance Minister is a reflection of the hon. Prime Minister's dream of "Vikshit Bharat." I must thank the Government under the Prime Ministership of Narendra Modi Ji.

I represent Assam, and I represent a regional political party, Assam Gana Parishad (AGP). We formed this political party after a long agitation. Over the years, I have observed one important thing. In Assam, we don't get anything from the central government without agitation. The people of Assam always carried this perception. But this perception has been proved wrong ever since the government under the leadership of Modi Ji came to power at the Centre.

Our people did not have to resort to any agitation for setting up of an oil refinery. The people of our state didn't have to come to the street demanding a bridge over the river Brahmaputra. Our people have realized this. We, therefore, must thank Hon'ble Modi Ji for his contribution to the development of our state.

Our hon. Chief Minister, Himanta Biswa Sarma Ji, has taken laudable steps so that our state becomes one of the five most developed states in our country. I would like to state that earlier we had UPA government at the Centre, and now the NDA government under the leadership of Modi Ji has come to power. What did we get during the UPA regime, and what are we getting now? If we compare these two governments, we will find that in the past 60 years, we had only four bridges over the river Brahmaputra. But today, under the Prime Ministership of Modi Ji, how many bridges have we got over the river Brahmaputra? Now, people have realized this.

The hon. President of India, in her speech in 2024-25, stated that there had been a fourfold increase in the allocation of funds for the Northeast. Earlier, if we had received one rupee, now it has been increased four times.

If we look at this year's Railway Budget, the total allocation for the Northeast is Rs. 10,440,0000 crore. However, if we look at the Railway Budget for the period from 2009 to 2014, only about Rs. 2,100 crore was allocated. This means that this Government under Modi Ji allocated five times more funds in a

single year than what the UPA had allocated. This shows how much we have gained under the present government led by Modi Ji.

We, the people of Assam, truly thank the Hon'ble Prime Minister and the Hon'ble Finance Minister for their generosity. However, we still have many problems. In this budget, a urea plant with a capacity to produce 27 lakh metric tonnes of urea has been sanctioned. Last year, a semiconductor project amounting to Rs. 27,000 crore was also sanctioned. The Assamese people are really grateful to the Hon'ble Prime Minister Modi Ji.

But still, we have problems. Flood and erosion are two major issues that have severely affected the state. To tackle flood and erosion, in 1980, the National Flood Commission was constituted.

Madam, give me one more minute. To solve the problem of floods, a report outlining short-term and long-term measures was to be prepared.

SHRI SHREYAS M. PATEL (HASSAN): Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity to speak on the General Budget of 2025-26.

I stand here today to highlight the pressing concerns of my constituency and the State of Karnataka. These are not just demands, but urgent needs that the Central Government must address.

First and foremost, the Upper Bhadra Project is crucial for Karnataka's central region including my constituency, covering Kadur taluks in Chikmagalur District. The State was promised Rs. 5,300 crore in the earlier Union Budget along with the status of a national project. Despite repeated requests, the national status has not been granted. The farmers in my State and my constituency are watching this. They must not feel that the Centre is playing with their lives by delaying funds for this critical project.

Beyond this, Karnataka continues to be neglected in financial allocations. The 15th Finance Commission recommended Rs. 5,495 crore as special grants yet the Centre rejected them. Despite repeated demands, Karnataka's flood-prone regions, including my constituency Hassan, have received no dedicated mitigation fund.

The funding under NABARD to Karnataka State has been slashed from Rs. 5,600 crore last year to just Rs. 2,340 crore. It is a shocking 58 per cent cut. This directly hurts the farmers, and rural

development.

In Karnataka, under the leadership of Shri Rahul Gandhiji, the State Government headed by our hon. Chief Minister Shri Siddaramaiahji and Shri D.K. Shivakumarji has implemented five guarantees successfully. Under these guarantees, Rs. 52,000 crore have been on the hands of the millions. Annually each family receives around Rs. 50,000 to Rs. 55,000. The critics claim that these guarantees would harm the economy but the economy of the Karnataka Government is projected to grow by 6.6 per cent. At the same time, we ensured fiscal discipline by keeping the fiscal deficit within 3 per cent of GSDP.

The Government often boasts about increasing the Minimum Support Price, that is, MSP, yet it has failed to implement the Swaminathan Committee recommendations. The copra farmers in my constituency in Karnataka suffered a severe price crash due to delayed procurement and reduced quantity caps by NAFED. Prices fell by 50 per cent in December 2023. It was the worst drop in recent history. I urge the Government to increase MSP to match rising production costs and ensure timely procurement.

Madam, another issue is regarding severe human-animal conflict in hilly districts like Hassan. In the past 21 years, around 75 people have lost their lives, and countless crops have been destroyed in taluks like Sakleshpura, Belur, and Alur. We need a dedicated compensation fund for the affected farmers who have lost their lives. Both Central Government and the State Government should join their hands together to solve this problem.

Madam, the pepper and cardamom plantations in my constituency are facing mounting challenges due to erratic climate conditions, rising labour costs, and frequent animal attacks like elephant attacks. I urge the Centre to provide interest waivers and loan restructuring to support these struggling planters. Despite repeated requests, the Centre has ignored the demand to increase housing assistance under the Pradhan Mantri Awas Yojana for the urban and rural poor. The Anganwadi workers, ASHA workers, and the Mid-Day Meal workers, who play a crucial role in public welfare, have seen no increase in honorariums. This is a grave injustice to those who serve the most vulnerable.

Madam, through you, I would like to make the following requests to the Central Government. I would request the Government to upgrade the Srirangapatna-Channarayapatna-Arsikere road as a National Highway and expedite the finalization of the DPR and fund allocation for the construction of 335 km of Bangalore-Mangalore Expressway via Hassan, which covers the major stretch of my constituency. Also, there is a need to develop a comprehensive tourism circuit connecting Belur, Halebeedu, and Shravanabelagola. There are UNESCO-recognised Hoysala temples to boost Karnataka's tourism industry. Then, I would request the Central Government to sanction funds under the Jawahar Navodaya Vidyalaya Yojana. There is a very old school in my constituency near Mavinakere. It struggles with inadequate infrastructure despite providing quality education to rural students.

HON. CHAIRPERSON: Okay, thank you.

SHRI SHREYAS M. PATEL: Madam, please give me one minute. I promise, I will conclude within one minute. It is my humble request to you.

Madam, through you, I would also request the Government to expedite approvals pending on the part of the Union Government, if any for the completion of the Greenfield Airport, which is essential for improving connectivity.

Madam, there is also a need to modernise and renovate the ESI hospital. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, hon. Member, Shri Amar Sharadrao Kale.

? (*Interruptions*)

SHRI AMAR SHARADRAO KALE (WARDHA): Hon. Madam Chairperson, while discussing this Union Budget, I want to bring certain issues to your kind notice. Our Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman presented this Budget on 1st February, 2025. She has made many declarations in it but she did not take cognizance of the problems faced by farmers. You have given tax exemption upto the income of Rs. 12 lac and I welcome this positive step. It means, you have taken into consideration the person who is earning Rs. 12 lac per annum but you completely forgot about the person who is not earning even 1 lac per annum.

I want to share one news in this connection. I represent the State of Maharashtra and the regions like Vidarbha and Marathwada are recognized for the largest numbers of farmers' suicides. Rajendra Pailwar and Omkar Pailwar, a father-son duo had committed suicide on the next day of Makarsankranti at Minkhi, Teh. Biloli, Distt. Nanded in Maharashtra. The reason behind it was dearth of funds to bear the burden of educational books and stationery. The son was studying in class 10th and his father was unable to provide money to purchase uniform and note books. That 16 year old boy committed suicide out of frustration and his father also committed suicide next morning. This is the tragedy of our farmers' life that he could not provide bare minimum necessities to his family and children. This is the fact and ground reality and this must be kept into mind while framing policies for farmers.

I represent Wardha Lok Sabha Constituency. In the adjoining district of Amravati, around 600 farmers committed suicide during last 2 years.

On 20th March, 2014, our so called successful Prime Minister Shri Narendra Modi had visited Wardha. This is a cotton belt and he propagated a 5F formula during his visit. What is this 5F formula? I will tell you. 1st F is farmer, 2nd F is Fibre, 3rd F is Fabric, 4th F is Fashion and 5th F is Foreign. Modiji had promised us and showed a rosy picture of exporting our textile to foreign countries, but nothing has happened till date. That is why, I would like to ask our so called successful Prime Minister Narendra Modiji about this 5F formula. What went wrong, Modiji? As of now, our cotton is fetching the price of Rs. 7000 per quintal only and this is a matter of grave concern. So, I would like to request the Union Govt. to kindly look into it and take necessary action.

Thank you.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : सभापति महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया है। काफी माननीय सदस्यों ने, चाहे वे सत्तापक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, उन्होंने बजट पर विस्तार से बातें कही हैं। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं तो कहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो प्रस्तुत बजट है, यह केवल देश का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। मैं दो दिन से चर्चा को सुन रहा हूं। पहले पॉलिसी पैरालिसिस कहा जाता था, पहले कहा जाता था कि टॉप फाइव फ्रेजाइल इकोनॉमी है और कहा जाता था कि ? बनाना रिपब्लिक? है, कम से कम आज हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि जहां वर्ष 2014 में हम टॉप फाइव फ्रेजाइल इकोनॉमी

में थे, वहीं अब हम दुनिया के टॉप फाइव इकोनॉमी में आ चुके हैं। यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। यह निश्चित तौर से देश के लिए सौभाग्य की बात है और यह सब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है।

पहले पॉलिसी पैरालिसिस की बात की जाती थी। एफडीआई नहीं आ रहा था। जिन लोगों ने निवेश किया था, वे लोग भी अपना निवेश निकाल रहे थे। आज उस पॉलिसी पैरालिसिस की बात नहीं हो रही है बल्कि आज 'विकसित भारत' की बात हो रही है। रिफॉर्म मोमेंटम की बात हो रही है। Rapid pace of economic reforms, boosting investment and business growth की बात हो रही है।

जब ग्रोथ की बात होती है, तो आज मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूँ कि अगर हम अपने रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखें, तो पूरे देश और दुनिया के सामने साफ तस्वीर नजर आएगी। जहां वर्ष 2023-24 में हमने 9,49,195 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किया था, वहीं आज 11,21,090 करोड़ रुपये का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का तात्पर्य इन्फ्रास्ट्रक्चर और देश के विकास से है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तात्पर्य लोगों की एस्टैब्लिशमेंट और सैलरी से है। निश्चित तौर से आज हमने उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटाने का काम किया है। जहां हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को 10.1 प्रतिशत बढ़ाया है, वहीं आज हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटाकर 6.7 प्रतिशत किया है। यह हमारे देश की सरकार ने वित्तीय समावेशन और नियंत्रण किया है।

मैं कहना चाहता हूँ कि हमने वर्ष 2013-14 में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 14.65 लाख करोड़ रुपये खर्च किए थे, अगर आज 39.44 लाख करोड़ रुपये खर्च हो रहा है, तो 175 प्रतिशत बढ़ा है। देश का विस्तार, देश में नौकरियां और देश के एस्टैब्लिशमेंट पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 175 प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2014 में इस देश की तत्कालीन सरकार ने 2.3 लाख करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपेंडिचर के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए थे, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2.3 लाख करोड़ रुपये के स्थान पर 11.21 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रही है, यानी 387.5 प्रतिशत इन्क्रीज किया है। शायद पूरी दुनिया में इससे बढ़ती हुई कोई इकोनॉमी नहीं है।

आज चाहे हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या हम उसको जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं, आप रेवेन्यू डेफिसिट या फिस्कल डेफिसिट की बात करिए। वर्ष 2023-24 में हमारा रेवेन्यू डेफिसिट 2.6 प्रतिशत था, जो वर्ष 2024-25 में रिवाइज्ड होकर 1.9 प्रतिशत हुआ है। आज हम कह सकते हैं कि वर्ष 2025-26 का जो डेटा है, हम उसको 2.61 से घटाकर अपने रेवेन्यू डेफिसिट को 1.5 प्रतिशत पर लाएंगे। यह हमारी सरकार की उपलब्धि है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। आप फिस्कल डेफिसिट को देखिए। हमने वर्ष 2023-24 में फिस्कल डेफिसिट पर 5.6 प्रतिशत खर्च किया था। आज वह फिस्कल डेफिसिट घटकर 4.8 प्रतिशत हुआ है। इस बार वर्ष 2025-26 में हम फिस्कल डेफिसिट को भी घटाकर 4.4 प्रतिशत करेंगे। आखिर किसी चीज का पैमाना क्या होगा? किसी सरकार के वित्तीय समावेशन का क्या पैमाना होगा? हमने किस तरह से वित्तीय नियंत्रण किया है?

पिछले दो दिनों से बहुत बात हो रही है कि हमारे राज्य को पैसा नहीं दिया जा रहा है। हमारे राज्य के कर का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में जहां सभी राज्यों को 14,22,444 लाख करोड़ रुपये मिलने थे, वह स्टेट के डिवैल्यूएशन में आना था। हमने अपने डिवैल्यूएशन से पश्चिम बंगाल को 1,07,010 करोड़ रुपये दिए हैं। तमिलनाडु को 58,022 करोड़ रुपये दिए हैं। कर्नाटक को 51,877 करोड़ रुपये दिए हैं। तेलंगाना को 29,900 करोड़ रुपये दिए हैं। केरल को 27,382 करोड़ रुपये दिए हैं। पंजाब को 25,704 करोड़ रुपये दिए हैं। आज हम केवल डिवैल्यूएशन में स्टेट को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम मानते हैं, आप सुनिए।

आज इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पहली बार नरेन्द्र मोदी जी की सरकार पॉलिसी लाई है कि केवल हम भारत सरकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ाएंगे। उनका फेडरल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पॉलिसी बनाई गई है। देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जब राज्यों के इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, तभी देश का विकास होगा। मैं आज यह बताना चाहता हूँ। हम लोग एक समय कहाँ खड़े थे? हमारे पड़ोसी देश हमारे बराबर खड़े थे। चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हमारी बराबरी करता था। आज हमारे देश की आबादी 145 करोड़ है। बांग्लादेश की आबादी 17.3 करोड़ है, नेपाल की आबादी 3.09 करोड़ है, श्रीलंका की आबादी 23 करोड़ है और पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। आज चाइना की आबादी 141 करोड़ है। आज आप ग्रोथ रेट देखिए। किसी देश के विकास का पैमाना क्या होगा?

जब पूरी दुनिया कोविड-19 जैसी वैश्विक समस्या से जूझ रही थी, कोविड के दौरान पूरी दुनिया में लोग घरों में कैद थे। पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है, जिसने अपने देश के सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाने का काम किया है। न केवल अपने देश के नागरिकों को वैक्सीन लगाने का काम किया है, बल्कि हमने 150 देशों को वैक्सीन देने का काम किया है। इसके बावजूद जो हमारी ग्रोथ रेट है, भारत की ग्रोथ रेट 7 प्रतिशत है, बांग्लादेश की ग्रोथ रेट 5.54 प्रतिशत है, नेपाल की ग्रोथ रेट 3.1 प्रतिशत है और श्रीलंका की ग्रोथ रेट वर्ष 2024 में 5.3 प्रतिशत है। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 2.4 प्रतिशत है। राहुल गांधी जी रोज चाइना की बात करते हैं। वे रोज चाइना की वकालत करते हैं। आज हमारी जीडीपी 7 प्रतिशत है और उनकी जीडीपी 4.8 प्रतिशत है। वे चाइना के मॉडल की बात करते हैं। वे आज चाइना की वकालत करते हैं। आप क्या बात करते हैं?

17.00 hrs

हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी रैंकिंग को सुधारा है। हमारा विकसित भारत का संकल्प ऐसे ही नहीं है। आप हमारी इकोनामिक ग्रोथ देख लीजिए। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6.4 परसेंट है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, केवल आंकड़े देना चाहता हूँ। इंडिया की इकोनामिक ग्रोथ रेट 6.4 परसेंट है और जापान की केवल 0.3 परसेंट है। जापान की हम बात करते थे, जापान के जूते की बात करते थे। आज हम 6.4 परसेंट इकोनामिक ग्रोथ पर हैं, लेकिन जापान 0.3 परसेंट पर है। ? (व्यवधान) 200 वर्षों की गुलामी की। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 2.8 परसेंट है। जो आंकड़े मैं दे रहा हूँ, अगर वे आंकड़े गलत होंगे तो मैं सदन से माफी मांग लूंगा और इस्तीफा दे दूंगा। आप यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहे हैं। आज हमारी इकोनामिक ग्रोथ रेट 6.4 परसेंट है, वहीं इंग्लैंड की इकोनामिक ग्रोथ रेट 0.6 परसेंट है। आज इकोनामिक ग्रोथ रेट में भी हम दुनिया

के सबसे तेजी से बढ़ते हुए देश हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह दुनिया का रही है कि that India is becoming one of the fastest growing economies.

आज भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है। आज चाहे पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मामला हो या ग्लोबल में दुनिया की तीसरी शक्ति सोलर पावर में बनने की बात हो। हमने पेरिस में समझौता किया था कि हम नॉन फॉसिल एनर्जी लेकर आएं तो उस नॉन फॉसिल एनर्जी को समय से पहले और वर्ष 2030 से पहले अगर किसी ने अचीव किया है तो वह भारत ने किया है। यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। आप क्या बात करते हैं? क्या आपका आलोचना करना ही काम है? आप देखिए हम दुनिया में किस तरीके से आगे जा रहे हैं। ? (व्यवधान) आप अनइंफ्लॉयमेंट की बात करते हैं। आज इंडिया में अनइंफ्लॉयमेंट रेट 4.2 परसेंट है, जापान में 2.6 परसेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स में 4.2 परसेंट है, यूनाइटेड किंगडम में 4.3 परसेंट है। आज आप जिस अनइंफ्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें भी हमने अचीव किया है। हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं, हम विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं। आपका क्या था? वर्ष 2014 में नेशनल हाइवेज कितना था? ? (व्यवधान) वर्ष 2014 में नेशनल हाइवेज 91,287 किलोमीटर था। आप धैर्य से सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। I am not yielding. ? (Interruptions) You should have patience to listen. ? (Interruptions) हमारी लैंग्थ क्या थी? वह 91,287 किलोमीटर थी। वर्ष 2014 में यह इनकी सरकार में थी। वर्ष 2023 में भारत के नेशनल हाइवेज 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 1 लाख 46 हजार 145 किलोमीटर हो गए हैं। यह 60.1 परसेंट बढ़ा है। ? (व्यवधान) मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, केवल अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहा हूं तो आपको मिर्च क्यों लग रही है? अगर मैं आलोचना करता और कोई बात कहता तो अलग बात थी। आप याद कीजिए, जब सीपी जोशी जी हाइवेज मिनिस्टर थे और अगर कोई टेंडर एल-वन हो जाता था तो 6-6 महीने उस पर एमओयू नहीं मिलता था तथा उसका एलओआई जारी नहीं होता था। आज गडकरी जी हैं। अगर आज एल-वन हुआ है तो शाम तक लेटर ऑफ इंडेंट जारी हो जाता है।

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : मैडम, अभी तो मैंने शुरू किया है। हमारा समय है। पहले वर्ष 2014 में 9 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाइवे बनाते थे, लेकिन आज हम 36 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाइवे बना रहे हैं। आपने देखा है कि किस तरीके से हमारी रोड मिनिस्ट्री या रेलवे मिनिस्ट्री को वर्ष 2013 -14 में बजटरी सपोर्ट करते थे। रेल राज्य मंत्री बिट्टू जी बैठे हैं। इनको मालूम है कि वर्ष 2013-14 में रेलवे को कुल 27 हजार 72 करोड़ रुपये का बजटरी सपोर्ट मिलता था। वर्ष 2014-15 में 30 हजार 121 करोड़ रुपये रेलवे का बजटरी सपोर्ट था, जो बजट का 1.8 परसेंट था। आज 2025-26 में भारत के प्रधानमंत्री ने 2 लाख 52 हजार 200 करोड़ रुपये का बजट दिया है। हमने अपने बजट का 5 परसेंट दिया है। आप क्या बात करते हैं? रेल भी इन्फ्रास्ट्रक्चर में है। जब रेल और रोड नहीं बनेगा तो देश का विकास कैसे होगा? मैडम, आप भी सुनिए। I think that it is information for the whole House. ? (Interruptions) Everybody will get enlightened and will welcome it also. ? (Interruptions) वर्ष 2013-14 में नेशनल हाइवे मिनिस्ट्री को 28,400 करोड़ रुपये मिला था।

अब अध्यक्ष जी, सीट पर आ गए हैं तो हमें और समय मिल जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : नहीं। अब समय नहीं मिलेगा।

श्री जगदम्बिका पाल : आज उस मिनिस्ट्री ऑफ हाइवेज को जिसका वर्ष 2013-14 में 28,400 करोड़ रुपये बजट था और वर्ष 2014-15 में 33,048 करोड़ रुपये बजट था, लेकिन 2025-26 में 2 लाख 87 हजार 333 करोड़ रुपये दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष : समय समाप्त।

श्री जगदम्बिका पाल : मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा।

अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि पूरी दुनिया कह रही है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, इकोनॉमिक पावर है। एंगस मेडिसन ने एक किताब लिखी है The World Economy उसमें उन्होंने हाईलाइट किया है कि 17वीं शताब्दी में इंडिया और चीन की इनकम पूरी दुनिया की इनकम के 50 प्रतिशत थी। एक हजार इसवी में इंडिया की पर-कैपिटा इनकम 450 डॉलर थी जो यूरोप के 427 डॉलर से अधिक थी। बीच में इंडिया की इकोनॉमी खराब हुई। आज यह इमर्जिंग नहीं है, आज नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इकोनॉमी रिइमर्जिंग हमारी इकोनॉमी होने जा रही है। यह मैं कहना चाहता हूं- the Reserve Bank of India in its latest 'State of the Economy Report' has stated that India is set to become the second largest economy of the world within this century even at current growth, and, perhaps hold the dominant position in the world economy that was enjoyed in 1780 before the colonial invasion. मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया यह मान रही है कि भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। हमारा देश वर्ष 2047 में विकसित भारत बनेगा और दुनिया की सुपर पावर होगा। धन्यवाद।

श्री सुधाकर सिंह (बक्सर) : मैं राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से सामान्य बजट के विरुद्ध हूँ। सबसे पहले, मैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति है। वे एक प्रखर अर्थशास्त्री और संवेदनशील राजनेता थे, जिन्होंने देश को आर्थिक स्थिरता देने के साथ-साथ बिहार के विकास को भी प्राथमिकता दी।

इसके साथ ही, मैं महाकुंभ के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में अपने प्राण गंवाने वाले श्रद्धालुओं को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यह बेहद दुखद है कि एक ऐसा आयोजन, जो आस्था और विश्वास का प्रतीक होता है, वहां सरकार की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी संख्या में लोग अपनी जान गंवा बैठे। जो सरकार अपनी जनता की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती, वह भला विकास के बड़े-बड़े वादे कैसे निभाएगी? सरकार को इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलना चाहिए।

आजकल मोदी सरकार का अमृत काल चल रहा है। इसमें हम भारत के लोग में हम कहाँ हैं। अमृत के बंटवारे में किसानों, कामगारों, कारीगरों, नौजवानों और छात्रों को अमृत के रूप में क्या मिला, यह देशवासियों को गौर करने का विषय है।

मैं आज यहाँ सिर्फ अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए नहीं बल्कि बिहार के बारे में केन्द्र सरकार के द्वारा बनाए गए सावधानीपूर्वक निर्मित भ्रम को तोड़ने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मेरे राज्य के लोग सच्चाई के हकदार हैं न कि बयानबाजी से लिपटे खोखले वादों को सुनने के लिए।

यह बजट देश के उस 80% आबादी के लिए एक भारी असफलता है, जो मेहनत से देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं लेकिन खुद दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भले ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा हो, लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय नीचे से 141 वें स्थान पर है। यह बजट सिर्फ अमीर और गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा करता है, जिससे गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। बिहार, झारखंड जैसे गरीब राज्यों के लिए यह बजट एक बड़ी निराशा है, जिसमें न तो कोई विशेष सहायता दी गई और न ही बुनियादी ढांचे के सुधार की कोई ठोस योजना बनाई गई। इससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इस बजट के जरिए बिहार को एक खराब छवि में दिखाया गया है, मानो राज्य को बहुत कुछ मिल गया हो। मैं जानता हूँ कि संसद में मेरे कई साथी यह दावा कर रहे हैं कि बिहार को इस बजट में भरपूर लाभ मिला है, लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि यह एक सफेद झूठ है। बिहार को जो मिला, वह दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। देश की आबादी में बिहार का अनुपात करीब 10 प्रतिशत है लेकिन केन्द्रीय योजनाओं में 2 प्रतिशत भी आबंटन नहीं मिला है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों चाहिए और यह बजट हमारी समस्याओं का 1% भी हल क्यों नहीं करता?

बिहार की हालत पर केवल छह बार नाम लेने से हमारी समस्याएँ हल नहीं हो जातीं। असलियत यह है कि बिहार के बुनियादी ढांचे की स्थिति दयनीय है और इसके बिना औद्योगिक विकास संभव ही नहीं है। राष्ट्रीय औसत प्रति लाख जनसंख्या पर 11 किमी हाईवे है, लेकिन बिहार में यह मात्र 5.4 किमी है। यह अंतर हमारी गरीबी के मुख्य कारणों में से एक है। लेकिन वित्त मंत्री के बजट भाषण में एक भी नया हाईवे या एक्सप्रेसवे घोषित नहीं किया गया, जबकि पिछले बजट में किए गए वादों पर भी अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। जैसे कि बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे कागजों से नीचे उतरकर ज़मीन पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है।

शिक्षा की स्थिति और भी चिंताजनक है। पूरे भारत में औसतन 15% लोग ग्रेजुएट हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जनगणना के अनुसार बिहार में यह संख्या सिर्फ 7% है। बिहार की बौद्धिक प्रगति के लिए किसी भी नए केंद्रीय विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान की घोषणा इस बजट में नहीं की गई। जब तक उच्च शिक्षा को मजबूत नहीं किया जाएगा, बिहार के युवाओं को विकास का लाभ नहीं मिलेगा।

इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की हालत और बदतर है। पटना को छोड़कर शायद बिहार के किसी शहर में क्रिटिकल मरीजों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो। जहां तक पटना के भीतर दो अस्पतालों को छोड़ दिया जाए तो PMCH और NMCH की

हालत इंसानों को छोड़ दिया जाए तो जानवरों तक का इलाज प्रभावी तरीके से नहीं हो सकता है। 13 करोड़ आबादी के लिए मात्र 1500 बेड का एम्स दिया गया है। वही दिल्ली जैसे छोटे राज्यों के लिए एम्स, सफदरजंग और राम मनोहर लोहिया जैसे दर्जनों सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मौजूद हैं। जिसका दुष्परिणाम है कि बिहार के लाखों में मरीज इलाज हेतु दिल्ली आते हैं। अगर आप दिल्ली AIIMS के बाहर फुटपाथ पर सोए हुए मरीजों से पूछेंगे कि वे कहाँ से आए हैं, तो उनमें से अधिकतर कहेंगे-बिहार से! इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि केंद्र सरकार देश के सबसे गरीब राज्य में विश्वस्तरीय अस्पताल बनाने में कोई रुचि नहीं रखती? कहीं इससे ज्यादा लोग आर्थिक आभाव में अपना जीवन त्याग देते हैं। भारत सरकार ने आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की, जिससे लाखों गरीब भारतीयों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। लेकिन बिहार की स्थिति इतनी दयनीय है कि कई जिलों में एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जो आयुष्मान कार्ड की शर्तों को पूरा कर सके। जबकि बिहार जैसी बड़ी आबादी वाले राज्य में हर जिले में कम से कम 2-3 अस्पताल होने चाहिए या कम से कम हर उप-मंडल स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। आयुष्मान भारत का फायदा तब ही मिल सकता है जब अस्पताल और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मौजूद हों, लेकिन बिहार को इन बुनियादी सुविधाओं से ही वंचित रखा गया है। इसका निदान यही है कि बिहार में काम से कम 5 एम्स और पांच केंद्रीय विश्वविद्यालय की और स्थापना की जाए। जिससे आने वाले एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच सके। यही कारण है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है। जब तक हमें औद्योगिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेष सहायता नहीं मिलेगी, तब तक बिहार और पूरे देश के बीच विकास की खाई और चौड़ी होती जाएगी। इस बजट ने बिहार को सिर्फ नाम लेकर छलने का काम किया है, असल में बिहार के लिए कुछ नहीं किया गया।

देश के किसानों के खराब माली हालात एवं घटती आमदनी के मद्देनजर अब कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। जिस तरह से आर्थिक उदारीकरण के नाम पर देश के किसानों को, खासतौर से बिहार के किसानों को, बाज़ार के हवाले छोड़ देने से घटती आमदनी के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं, उसी तरह देश के कई हिस्सों में किसानों की आत्महत्या की खबरें लगातार विचलित कर रही हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा लगातार हठधर्मिता का परिचय देते हुए, बीते समय से किसानों की मांग के अनुरूप न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी का कानून नहीं बनाना, देश के किसान और किसानों दोनों को गहरे संकट की ओर ढकेल रहा है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने किसान आंदोलन को समाप्त कराने के लिए वादा किया था कि वह स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार MSP लागू करेगी, लेकिन आज तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया है! कृषि संकट अकेले बाज़ार और मूल्य निर्धारण का नहीं है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बांझ बीज, कीटनाशक एवं उर्वरकों के क्षेत्र में अवैध घुसपैठ ने संकट को और गहरा कर दिया है।

मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ केंद्र की बीजेपी सरकार ने 2020 में तीन काले कृषि कानून लाने की कोशिश की, वहीं बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू और बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने 2006 में उससे भी अधिक दमनकारी और किसान विरोधी कानून

लागू किए। नीतीश कुमार सरकार की सतही सोच और गलत नीतियों के कारण आज बिहार का किसान देश का सबसे गरीब किसान बन गया है, और हालात ऐसे हैं कि कई किसान खेती छोड़कर अन्य परदेशों में मजदूरी व निर्माण कार्य करने को मजबूर हैं।

जैसा कि मैं चर्चा किया इसपर कि जब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता तबतक विशेष पैकेज कि व्यवस्था के जरिये सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के प्रभावी तंत्र को विकसित करने के लिए विशेष प्रबंध कि आवश्यकता है ! जिसमें प्रमुख रूप से कोसी नदी पर नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हाई डैम का निर्माण जिससे केवल सिंचाई कि व्यवस्था सुनिश्चित होगी बल्कि बाढ़ नियंत्रण और हरित ऊर्जा का बड़ा स्रोत भी पैदा होगा, इसके अलावा दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्र के लिए सोन नदी पर कदवन जलाशय योजना और कोयल नदी पर झारखंड सीमा रेखा पर मंडल डैम को तत्काल चालू करने से बिहार के सम्पूर्ण GDP में 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी होना और उन प्रभावित इलाकों में पलायन रोकने में भी कामयाब होगा।

अगर भारत को सुपर पावर बनाना है तो उसके लिए पूर्वी भारत खासतौर से बिहार राज्य को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत तक ले जाने के लिए विशेष बजट का उपबंध करना होगा जो कि वित्त मंत्री के अभिभाषण में दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहा है !

सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत के बीच की गहरी असमानता को कब तक नजरअंदाज किया जाएगा? अगर हम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकता, और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की बात करें, तो यह साफ़ दिखाई देता है कि पूर्वी भारत लगातार पीछे छूट रहा है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ सरकार का सौतेला व्यवहार किसी से छुपा नहीं है। केंद्र सरकार की सभी प्रमुख योजनाएँ और बड़े-बड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट सिर्फ पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों तक सीमित रह गए हैं। केंद्र सरकार के विकास कार्यों की प्राथमिकताएँ स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि बिहार और पूर्वी भारत को योजनाबद्ध तरीके से उपेक्षित किया जा रहा है। जब आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ रुपये का हाइड्रोजन एनर्जी प्रोजेक्ट दिया जाता है, गुजरात को 80,000 करोड़ रुपये की सेमीकंडक्टर फैक्ट्रियाँ 1.5 लाख करोड़ रुपये का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र और गुजरात दोनों को मिला और महाराष्ट्र के पालघर में 76,000 करोड़ रुपये का डीप वाटर पोर्ट मिलता है, तब यह सवाल उठता है कि बिहार को क्या मिला? बिहार को बजट में झुनझुना पकड़ाया गया, जिसमें एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की घोषणा की गई, लेकिन अब तक जमीन पर इसका कोई नाम-ओ-निशान नहीं है। बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे सिर्फ कागजों में बना हुआ है, जबकि सरकार इसका ढोल पीट रही है। ज़मीनी हकीकत यह है कि एक भी ईंट तक नहीं रखी गई। इसी तरह, 2016 में घोषित दरभंगा एम्स आज भी अधर में लटका हुआ है, जबकि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बदतर होती जा रही है। क्या यही है केंद्र सरकार का बिहार के प्रति प्रेम? बिहार को हर बार वादों और घोषणाओं से बहलाया जाता है, लेकिन जब निवेश और बड़े प्रोजेक्ट्स देने की बात आती है, तो बिहार को हाशिए पर डाल दिया जाता है। यह सरकार साफ संदेश दे रही है कि बिहार उनके लिए महज़ एक चुनावी गणित है, विकास की प्राथमिकता नहीं। प्रधानमंत्री जी 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा तो लगाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सबका साथ छूट गया और विकास सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित रह गया।

बिहार और अन्य गरीब राज्यों को केंद्र सरकार की योजनाओं में जानबूझकर अनदेखा किया जाता है। रेलवे की बात करें तो इस भेदभाव का एक और उदाहरण साफ दिखता है। बिहार में रेलवे स्टेशनों की हालत दयनीय है, ट्रेनों का ठहराव कम कर दिया गया है, नए प्रोजेक्ट की स्वीकृति नहीं मिल रही, और जहाँ ट्रेनें चलती भी हैं, वहाँ यात्रियों को अत्यधिक भीड़ और असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्या सरकार यह मान चुकी है कि बिहार के लोग रेलवे में निवेश के लायक नहीं हैं? यह रेलवे, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, उसे लगातार कमजोर किया जा रहा है, और निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है। लंबे समय से घोषित रेलवे परियोजना बिहार में कछुए की गति को भी मात दे रही है। जैसे कि आरा मुंडेश्वरी रेल लाइन अभी फाईलों से बाहर तक नहीं आई। भारत सरकार के श्रम पोर्टल पर बिहार के करीब तीन करोड़ लोग प्रवासी मजदूर के रूप में दर्ज हैं। जो रोजगार के अवसर की तलाश में अभी देश में लगातार यात्राएं करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सबसे कम ट्रेनें बिहार में चलती हैं। इससे ज्यादा क्या दुखद हो सकता है की प्रतिदिन समाचार चैनलों के द्वारा दिखाया जाता है कि, ट्रेन बोगीयों में यात्री जानवरों जैसे लटकर आते जाते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार का कोई ठोस पहल नहीं दिखता है!

देश के भीतर आर्थिक असमानता और भेदभाव केवल परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि टैक्स और शुल्कों में भी दिखाई देता है। "वन नेशन, वन इलेक्शन" की बात कर लोकतंत्र की मूल भावना पर हमला किया जा रहा है, लेकिन इस सरकार को "वन नेशन, वन टैरिफ" की जरूरत क्यों महसूस नहीं होती? देश के अलग-अलग हिस्सों में पेट्रोल-डीजल और अन्य वस्तुओं की कीमतें अलग-अलग हैं। अगर इस सरकार को सच में राष्ट्रीय एकता की चिंता होती, तो पूरे देश में एक समान कर प्रणाली लागू होती, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलती।

शिक्षा की बात करें, तो सरकार "वन नेशन, वन एजुकेशन" की नीति लागू करने में असफल रही है। "शिक्षा का अधिकार" कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए था, लेकिन यह केवल 8वीं कक्षा तक सीमित कर दिया गया, जबकि भारत के करोड़ों गरीब और पिछड़े बच्चों को 12वीं तक की मुफ्त और समान शिक्षा की सख्त जरूरत है। सरकारी स्कूलों की हालत बदहाल है, लेकिन सरकार केवल दिखावे के नए-नए कानून बनाकर अपनी पीठ थपथपा रही है। शिक्षा में यह असमानता सरकार की नीतिगत विफलता का एक और प्रमाण है।

बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं के लिए यह सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। जब सत्ता में आने से पहले 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, तब युवाओं को लगा था कि उनका भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि पूरे देश में सिर्फ 10 लाख सरकारी नौकरियाँ दी गईं, जबकि अकेले बिहार में महागठबंधन सरकार बनने के बाद माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मात्र एक साल में 5 लाख सरकारी नौकरियाँ दी गईं। यह स्पष्ट करता है कि अगर नीयत साफ हो, तो रोजगार सृजन असंभव नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार का ध्यान सिर्फ जुमलों पर है, न कि देश के युवाओं के भविष्य पर।

खेलों में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक होता जा रहा है। वैश्विक स्तर पर देश पिछड़ रहा है, लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में खिलाड़ियों के लिए कोई ठोस नीति नहीं है। भारत के युवा खिलाड़ी संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, और सरकार को सिर्फ इवेंट आयोजित करके फोटो खिंचवाने में रुचि है। इसी तरह, व्यापार में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। निर्यात

घट रहा है, आयात बढ़ रहा है, जिससे व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। रुपया लगातार गिर रहा है, डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत घट रही है, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

प्रधानमंत्री आवास योजना का असफल लक्ष्य भी सरकार की विफलता को उजागर करता है। 2022 तक सभी को मकान देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक आधे मकान भी पूरे नहीं हुए हैं। और अब सरकार योजना का विस्तार कर रही है और इसमें अतिरिक्त 3 करोड़ मकानों की घोषणा कर रही है। सवाल यह है कि अगर सरकार का दावा सही है कि उसने 20 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, तो फिर ये नए गरीब लोग अचानक कहाँ से आ गए? या तो सरकार का दावा झूठा है, या फिर यह योजना सिर्फ कागजों पर चल रही है।

आदिवासी समाज के हितों की अनदेखी लगातार की जा रही है। वन उपज अधिनियम, 2007 (Vanya Upaj Adhiniyam, 2007) को आज तक पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया, जिससे वहाँ गरीबी और असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। यह अधिनियम आदिवासियों को उनके जंगलों पर अधिकार देने और उनके परंपरागत आजीविका साधनों को सुरक्षित करने के लिए लाया गया था, लेकिन सरकारों की उदासीनता के कारण इसका लाभ आदिवासी समुदायों तक नहीं पहुँच पाया। परिणामस्वरूप, उनके जंगल, ज़मीन और संसाधन धीरे-धीरे बड़ी कंपनियों और खनन माफियाओं को सौंपे जा रहे हैं। आदिवासी समुदायों को उनकी ही भूमि से बेदखल किया जा रहा है, और उन्हें आज भी अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार नहीं दिया जा रहा। बड़ी खनन कंपनियाँ और कॉरपोरेट लॉबियाँ जंगलों को उजाड़कर खनिज संपदा का दोहन कर रही हैं, जबकि वहाँ रहने वाले आदिवासी लोग विस्थापन और बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं।

इससे न सिर्फ आदिवासी समाज में गहरा असंतोष बढ़ रहा है, बल्कि उनका सामाजिक और आर्थिक शोषण भी जारी है। अगर सरकारें इस अधिनियम को सख्ती से लागू करतीं, तो आदिवासी समुदाय को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता था, लेकिन आज भी उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं और उन्हें गरीबी में धकेला जा रहा है। यह सरकार की दोहरी नीति को दर्शाता है, जहाँ एक ओर आदिवासियों के विकास की बातें होती हैं, वहीं दूसरी ओर उनके जल, जंगल और ज़मीन को कॉरपोरेट के हवाले किया जा रहा। जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। निष्पक्ष चुनाव कराने की बजाय राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। "ग्रीन एनर्जी" का ढोंग किया जा रहा है, लेकिन बिहार जैसे गरीब राज्यों में पुराने थर्मल पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं क्या यही पर्यावरण नीति है?

सरकार सहकारी संस्थानों पर हमला कर रही है, जो भारत की आर्थिक संरचना का एक मजबूत स्तंभ हैं। देश में सहकारिता आंदोलन को कमजोर करने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, ताकि इसे निजी हाथों में सौंपा जा सके। अगर हम बिहार और झारखंड में बिस्कोमान (BISCOMAUN) का उदाहरण लें, तो यह साफ दिखता है कि कैसे सरकार योजनाबद्ध तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर रही है। बिस्कोमान के निदेशक मंडल के चुनावों को 6 बार स्थगित किया गया, जिससे 15 महीने से अधिक की देरी हो चुकी है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार की मिलीभगत से निर्वाचित निदेशक को जबरन हटा दिया गया और उनकी जगह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 3 निदेशकों को बैठा दिया गया। यह सीधे-सीधे लोकतंत्र की हत्या है। सहकारी संस्थाएँ किसानों, छोटे

व्यापारियों और आम जनता के हितों के लिए बनाई गई थीं, लेकिन सरकार इन्हें कमजोर करके पूंजीपतियों के हित साधने में लगी है। अगर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सहकारी संस्थाओं को इस तरह खत्म किया जाएगा, तो आम लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास कैसे बच पाएगा? यह सरकार लोकतंत्र को खोखला करने की एक-एक ईंट उखाड़ रही है, और सहकारी संस्थाओं को खत्म करने की इस साजिश को देश देख रहा है।

धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन (गोरखपुर) : मैं बजट 2025-26 अपने विचार रखता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब से प्रधानमंत्री का पद संभाला है, तब से उन्होंने अनेक ऐसे कदम उठाए हैं तथा नीतियां लागू की हैं, जिससे गरीबों के जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। कल्याणकारी योजनाएं घर-घर तक पहुंची हैं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से लोगों के खातों में सीधे तौर पर पैसे ट्रांसफर हुए हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जननायक की भूमिका के कारण ही हमारे देश की महान जनता ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्रदान किया है।

सबकी निगाहें टिकी थी और बजट पेश होते ही यह साफ हो गया कि इस बजट में सुधारों पर जोर दिया गया है। यह बजट न केवल किसान और युवाओं का बजट है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में जो विजन प्रस्तुत किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि यह बजट नागरिकों के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन्हें विकास में भागीदारी की भी बात करता है।

वैसे तो यह बजट समाज तथा देश के समग्र विकास की परिकल्पना पर आधारित है, लेकिन मैं आज उस इंजन की बात करना चाहूंगा, जिसे इस बजट में रेखांकित किया गया है। यह चार इंजन हैं - एक कृषि, दूसरा सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग अर्थात् एमएसएमई, निवेश तथा निर्यात विकास के साथ चारों इंजन भारत को विकसित देश बनाने के मार्ग को प्रशस्त करेंगे तथा सभी क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करेंगे।

हमारे देश में आज भी कृषि की प्रधानता है तथा हमारे अन्नदाता किसान ने अपना पसीना बहा कर इस देश को खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। हमारे अन्नदाता किसान के कल्याण को केंद्र बिंदु में रखते हुए बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना का शुभारंभ करने की योजना की गई है, जिसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा और जिससे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। हमारे देश में कृषि में रोजगार की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ग्रामीण समृद्धि और लचीला निर्माण, व्यापक क्षेत्रीय कार्यक्रम आरंभ करने की भी परिकल्पना इस बजट में है, ताकि कृषि के क्षेत्र में कौशल निवेश और प्रौद्योगिकी को बढ़ाया जा सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आ सके। मैं समझता हूँ कि कृषि के क्षेत्र में इन कदमों से हमारी अर्थव्यवस्था के विकास की गति और तीव्र होगी तथा भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने के माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार किया जा सकेगा।

किसानों का योगदान हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए उसे हर प्रकार की सहूलियत मिलनी चाहिए। माननीय मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित के लिए इस बजट में अनेक कदम उठाए हैं। इसी क्रम में मैं किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत किसानों के लिए ऋण की सीमा को तीन लाख रुपये से बढ़कर ₹500000 कर दिया गया है।

किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार की ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को उच्च करदाताओं द्वारा वसूली जाने वाली उच्च ब्याज से बचाना है, जो कि किसानों को क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत केवल दो प्रतिशत की ब्याज दर है तथा फसल बीमा योजना का भी लाभ मिलता है। इसलिए, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा में बढ़ोतरी अत्यंत स्वागत योग्य कदम है।

सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम अर्थात् एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के अनुपूरक है। यह क्षेत्र के समग्र उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एमएसएमई के महत्व को देखते हुए ही इस बजट में एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार की सीमा को बढ़ाकर क्रमशः 2.5 तथा 2 गुना कर दिया गया है। इतना ही नहीं 'मेक इन इंडिया' का जो विजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उससे आगे बढ़ाने के लिए लघु और मध्यम और बड़े उद्योगों का शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिमयन मिशन स्थापित करने का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है।

यह सर्वविदित है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास और पूर्ण रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निवेश बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने वर्ष 2017 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है जिसको पूरा होने में निवेश की बड़ी भूमिका होगी। इसी उद्देश्य से बजट 2025-26 में निवेश को विकास के तीसरे इंजन के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसके लिए सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ब्रांड बैंड कनेक्टिविटी, राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्ट केंद्र, आईआईटी में क्षमता का विस्तार, शिक्षा हेतु उत्कृष्ट केंद्र, चिकित्सा शिक्षाओं का विस्तार, सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र इत्यादि बेहतरीन योजनाओं के लिए प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं अवसंरचना अर्थात् इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की कई बेहतरीन योजनाएं जैसे अवसंरचना में सरकारी निजी भागीदारी अर्थात् पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को विकसित भारत के परमाणु मिशन, समुद्री विकास, मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना इत्यादि का ब्लूप्रिंट भी इस बजट की खास विशेषताएं हैं। विकास के चौथे इंजन के रूप में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी इस बजट में महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की गई है। उदाहरण के लिए बजट में किए गए प्रावधानों के अनुसार एक निर्यात संवर्धन मिशन के शुभारंभ की योजना है, जिसे वाणिज्य चलाया जाएगा। इसके अलावा टियर टू शहरों में ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचे की भी परिकल्पना की गई है जिससे भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में उभर सकेगा।

हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री समावेशी विकास गरीबी उन्मूलन, गुणवत्ता शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण का अपना जो विजन देश के सामने प्रस्तुत किया है, उसे मूर्तिमान बनाने के लिए बजट 2025-26 में मजबूत आधारशिला रखी गई है। इस बजट में गरीबों, महिलाओं, किसानों, मध्यम वर्ग सब के हितों का ध्यान रखते हुए सामाजिक समानता सुनिश्चित करने का विजन भी है और उसके क्रियान्वयन का ब्लूप्रिंट भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में बजट में किए गए

प्रावधान के कारण भारत वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा तथा आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र बनने की दिशा में और भी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा ।

बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री दिलेश्वर कामैत (सुपौल) : मैं वर्ष 2025-26 के बजट पर अपने विचार रखता हूँ ।

समावेशी विकास का यह बजट राष्ट्रहित और जनहित के लिए अमृत एवं संजीवनी के रूप में कार्य करेगा । भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदर्शी एवं प्रगतिशील आर्थिक नीतियों एवं योजनाएं, जो समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ सभी वर्गों को समानांतर एवं सार्थक लाभान्वित करती हैं, इसके लिये मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का एवं माननीय वित्त मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ ।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने योजनबद्ध तरीके से परिवर्तन की शुरुवात करके आर्थिक हित करते हुए लोक हित में रोजगार और उद्यमिता के अधिक से अधिक अवसर प्रदान कर भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का कार्य किया है ।

यह बजट भारत के किसानों, युवाओं, छात्रों एवं महिलाओं तथा सभी वर्गों के उत्थान और विकास के लिए है । यह बजट विकास में तेजी लाने, समावेशी विकास सुनिश्चित करने, निजी क्षेत्र के निवेशों में नई जान डालने, परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरने, और भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार के प्रयासों को जारी रखेगा ।

हम सभी लोग मिलकर भारत को विश्व में मान-सम्मान बढ़ाने तथा सर्वोच्च स्थान बनाकर राष्ट्र की अनंत क्षमता को गति प्रदान करने के लिए अपनी यात्रा कर रहे हैं ।

भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास यात्रा को विकसित भारत के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समावेशिता के मादर्शक प्रेरणा से ईंधन के रूप में हमारे सुधार का उपयोग कर कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात जैसे चार शक्तिशाली इंजन गति प्रदान कर रहे हैं । हमारी अर्थव्यवस्था सबके विकास को साकार करते हुए गरीबी से मुक्ति, शत-प्रतिशत अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवायें, शत-प्रतिशत कुशल कामगार को सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में सत्तर प्रतिशत महिलाएं और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान तथा सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है ।

हमारी सरकार का उद्देश्य कराधान, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार जैसे क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है, जिनसे आगामी पाँच वर्षों में विकास क्षमता के साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी ।

इस बजट में कृषि एवं अन्नदाताओं के हित में प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना, विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जायेगा तथा इस योजना से 1 करोड़ 70 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे । ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों, ग्रामीण महिलाओं, भूमिहीन परिवारों एवं बेरोजगार युवाओं के प्रवास को रोकने के

लिए 'ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन निर्माण' कार्यक्रम को राज्यों की भागीदारी से प्रारंभ किया जायेगा, जिससे, कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि क्षेत्र में रोजगार की कमी का समाधान होगा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार होगा एवं बड़े स्तर पर रोजगार का अवसर प्राप्त होंगे। महोदय, इस बजट में भारत को दलहन तथा खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को कार्यान्वित किया जा रहा है। साथ ही पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं आय के स्तरों के बढ़ाने हेतु सब्जियों, फलों और श्रीअन्न का उपयोग के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी को समस्त बिहार की जनता की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ कि सरकार ने इस बजट में बिहार के विकास के लिए बिहार को विशेष रूप से ध्यान में रखा है जिसमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पटना एयरपोर्ट का विस्तार, वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद, कोसी कनाल से 50 हजार हेक्टेयर में सिंचाई, मिथिलांचल के लिए सिंचाई योजना को बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी स्थापित किया जाएगा, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान तथा आईआईटी पटना को वित्त पोषित किया जाएगा, जैसी योजनाओं को शामिल किया है। भारतीय किसानों के लिए राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, मत्स्य उद्योग, कपास उत्पादकता मिशन, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक तथा सहकारी क्षेत्रों के लिए एनसीडीसी के ऋण कार्यों के लिए सहायता प्रदान करने जैसी चहुमुखी योजनाओं को शामिल किया गया है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमियों के जीर्णोद्धार के लिए इस बजट में 5.7 करोड़ एम.एस.एम.ई. पर ध्यान के साथ विनिर्माण और सेवाएं शामिल हैं। एम.एस.एम.ई. के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन, गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि, सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड, स्टार्ट-अप के लिए निधियों का कोष, पहली बार के उद्यमियों के लिए नई योजना, श्रम-सघन क्षेत्रों के लिए उपाय, फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम, खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय, खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता, विनिर्माण मिशन मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण जैसी लाभकारी योजनाओं को शामिल किया गया है।

माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा इस बजट में राष्ट्रहित, लोकहित एवं आर्थिक हित में सभी वर्गों के विकास हेतु हर क्षेत्र में सकारात्मक पहल की गई है। महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने संसदीय क्षेत्र सुपौल के रेलवे से संबंधित मुख्य अति आवश्यक समस्याओं का समाधान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि:-

(1) ललितग्राम से वाया सरायगढ़-सुपौल-सहरसा-दानापुर होते हुए दिल्ली के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जाय अथवा ललितग्राम से वाया सरायगढ़-सुपौल-सहरसा होते हुए नई दिल्ली तक एक मेल/एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जाये।

(2) कटिहार से फारबिसगंज-दरभंगा होते हुए नई दिल्ली तथा दरभंगा से फारबिसगंज-कटिहार होते हुए गुवाहाटी के लिए एक नई ट्रेन का परिचालन किया जाय। इसी के साथ मैं वर्ष 2025-26 के आम बजट का समर्थन करते हुए बिहार की समस्त जनता एवं

जनतादल (यू) की तरफ से धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): A budget is not just about numbers; it is a reflection of priorities. And today, we must ask?whose priorities does this budget serve? The glaring gaps, the misplaced focus of this year?s Union Budget compel us to question its commitment to inclusivity, equity, and sustainability.

Amidst the global economic slowdown, geopolitical tensions, inflationary pressures, and weakening exports, and domestic challenges, achieving the targets that have been laid out are nothing but false promises.

The Budget talks about India?s rapid economic growth but as usual fails to adequately address structural issues like unemployment or income inequality. The government proudly claims that the economy is thriving, yet unemployment is at a record high, rural wages are stagnant. And small businesses are struggling to survive. Can we really celebrate GDP growth when the majority of citizens are left struggling? GDP is not a comprehensive indicator of development. It does not reflect key issues like income inequality, poverty levels, or environmental degradation. Despite high growth rates, unemployment remains a significant issue.

Many structural reforms, such as GST and Demonetization have been poorly implemented and have negative short-term impacts on small businesses and informal sectors. The budget farce to address the growing income inequality by not introducing measures like wealth taxes or higher taxes on luxury goods. Concerns about GST compliance burdens for small businesses and issues with refund delays remain unaddressed.

Reforms such as high scale Privatization and Labour Law changes create fear of job losses and exploitation of workers. These have largely benefitted the organized sector and high-growth industries, leaving the informal and rural economy behind. Balanced growth remains a myth, with urban areas thriving while rural regions struggle with underdeveloped infrastructure, poor healthcare, and lack of quality education. The Asset Monetization Plan for 2025-26 can lead to undervaluation and short-term resource mobilization at the cost of long-term economic stability.

The Prime Minister Oshan-Dhaanya Krishi Yojana depends on the convergence of existing schemes, which already suffer from inefficiencies, fund shortages, and lack of implementation at the ground level. The policy does not address systemic issues like fragmented landholdings, lack of land rights for tenant farmers, or inadequate market access for small-scale producers. Improving irrigation facilities is important, but the policy does not address the issue of groundwater overuse or the promotion of water-efficient technologies like drip irrigation. Deeper reforms to address farmers' income, land reforms, and market access are clearly missing.

Further, achieving 'Atma Nirbharta' in edible oils or pulses within the given time frame heavily underestimates ground-level challenges like water scarcity, soil degradation, and climate challenges which limit sustainability.

The 'Rural Prosperity and Resilience' programme overlooks deeper systemic issues such as land reform, fair market access, and resolving low agricultural productivity.

Many small and marginal farmers, especially in remote regions, are unaware of the KCC (Kisan Credit Cards) scheme or its benefits due to inadequate outreach and communication. The process of applying for a KCC involves extensive paperwork, which makes it difficult for illiterate or semi-literate farmers to access the scheme.

The government's policies often focus on increasing seafood exports which neglects the needs of small-scale and artisanal fishers who form the backbone of the sector. Export-driven policies may promote practices like overfishing or monoculture in aquaculture, harming marine biodiversity and long-term sustainability.

Merely raising investment and turnover limits does not address the deeper systemic issues faced by the MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises), such as lack of market access, poor infrastructure, and inconsistent regulatory support.

The 'Make In India' policy aimed to increase the manufacturing sector's share of GDP to 25% by 2022, but as of now, it has stagnated around 17%, reflecting a significant gap between ambition and reality. While it promised to create 100 million manufacturing jobs, employment in this sector has remained flat, with automation and capital-intensive industries further limiting job growth. The policy

emphasized foreign direct investment (FDI) to boost manufacturing, but much of the FDI received has gone into non-manufacturing sectors such as IT services, e-commerce, and financial services, undermining the policy's core objective. The policy has not adequately addressed the skills mismatch in the workforce.

While "Skill India" was launched alongside, it has largely failed to provide the technical and vocational training required for advanced manufacturing industries. An insufficient emphasis on strengthening domestic supply chains has led to continued dependence on imports for raw materials and components, especially in electronics and automotive sectors.

The scale of funding for the Saksham Anganwadi scheme remains insufficient for the scale of challenges related to malnutrition, infrastructure, and capacity-building. Many Anganwadi centres operate out of inadequate spaces without proper seating, ventilation, sanitation, or storage facilities for food and educational materials. The scheme's aim to digitise Anganwadi operations has limited impact due to poor digital infrastructure and connectivity in rural areas. The Asha workers, who form the backbone of the Saksham Anganwadi Scheme, remain poorly compensated despite their critical role in service delivery. A You have also provided Rs 1 65 paise and Rs1 35 paise for the Provision of nutritious food to pregnant women and children respectively. I request you to tell me, is it really possible to provide any good quality food using such a meagre amount as it seems that this provision has been included just for the sake of it.

In Kasturba Gandhi schools, non-teaching staff including cooks are getting the salary as per 2007 pay scale. I am requesting the hon. Finance Minister to increase their salary.

The Government has talked about the Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. It places the focus on mainstream Indian languages that may marginalize smaller languages or dialects, further eroding linguistic diversity. The initiative of expansion of educational institutions focuses exclusively on IITs, which cater to a small, elite group of students, while state universities and non-IIT technical institutions, which educate the majority of students, remain underfunded and underserved. The Budget very conveniently overlooks the needs of primary and secondary education, where learning outcomes remain poor.

The Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), aimed at providing "Housing for All" by 2022, has not achieved its original goal of delivering 2 crore houses in urban areas and 2.95 crore houses in rural

areas. The completed houses have been made using low-quality materials, resulting in poor durability and safety concerns.

The Jan Vishwas Bill 2.0, which aims to decriminalize minor offenses such as those related to environmental laws, labour violations, and consumer rights might embolden violators. While easing penalties for businesses, the bill does little to safeguard consumer rights and does not reflect ground realities.

While the Ministry of Environment, Forest, and Climate Change (MoEFCC) received a modest 2.47% increase in its budget allocation, funding for critical sectors such as industrial decarbonization, climate adaptation, and ecosystem conservation remains inadequate. The Nuclear Energy Mission for Viksit Bharat which talks about achieving 100 GW of nuclear capacity by 2047 is highly ambitious, given that India's current installed nuclear capacity is only around 7 GW (2025). The plan would require an unprecedented growth rate. Allocating 220,000 crore for SMRs could divert resources from more cost-effective renewable energy sources like wind and solar, which have already achieved economies of scale and require less upfront investment.

This budget is nothing but a bid to woo the middle class and the Bihar voters while the common people, the poor and the jobless continue to suffer. You have talked about so many new schemes and programmes, but what about the ones that already exist? What is the point of bringing out new policies when the old ones continue to be nothing but empty words? Ten years ago, we were promised transformative growth, inclusive welfare and a sustainable future. Fast forward to today's Union Budget, and we see a clear disconnect between promises made and results delivered. It is so evidently detached from the struggles of everyday Indians. Can a budget truly be successful if it leaves so many behind? Have we forgotten that development is meaningless if it isn't inclusive? As citizens, we look to the Union Budget for hope and solutions. But instead of relief for struggling farmers, jobless youth, and overburdened taxpayers, we see empty rhetoric and misplaced priorities. Is this the future we envision for our nation?

श्री भजन लाल जाटव (करौली-धौलपुर) : केन्द्र सरकार के इस बजट को केवल बिहार का बजट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बजट में जो विशेष प्रावधान बिहार के लिए किए गए हैं वो बिहार की जनता के लिए बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए किए गए हैं। यह केवल सरकार बचाओं बजट प्रतीत होता है।

आज दलितों और आदिवासियों के साथ जो हो रहा है, वह न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह सरकार की संवेदनहीनता और असफल कानून व्यवस्था को भी उजागर करता है। हिन्दू रक्षक SC-ST अत्याचार हिन्दू नहीं है। SC-ST समुदायों पर सबसे अधिक अत्याचार दर्ज किए जाते हैं। बजट में सरकार ने SC-ST और दलित वर्ग के लिए कोई विशेष योजना पेश नहीं की।

किसानों को चाहिए था कि उन्हें अधिक समर्थन मूल्य मिले, लेकिन सरकार ने उन्हें निराश किया। सरकार ने किसानों की समस्याओं को नज़रअंदाज किया है और उनके लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए।

सरकार ने वादा किया था कि 2024 तक किसान की आय दोगुनी कर देंगे लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में वास्तविक मजदूरी में या तो नकारात्मक वृद्धि हुई है या फिर लगभग कोई वृद्धि नहीं हुई है। कृषि मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में केवल 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कोविड समय में भी हमारी अर्थव्यवस्था रही उसका यही कारण है कि भारत कृद्धि प्रधान है।

सरकार ने कृषि को ??पहला विकास इंजन?? बताया है, लेकिन यह दावा वास्तविकता से बहुत दूर है। किसान इस बजट से निराश हैं और उनके पास निराश होने की पूरी वजह है कृषि को कुल बजट का केवल 3.38 प्रतिशत देना इस क्षेत्र की अनदेखी को दर्शाता है। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए।

भारत के कृषि परिवारों का आधा कर्ज में डूबा हुआ है। जिसमें औसत कर्ज 91231 रुपये है। इस सरकार ने तो खेती करने के लिए उपयोग में आने वाले यंत्रों पर भी 12 प्रतिशत जी.एस.टी. लगा दिया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ होना चाहिए।

किसान की आय में कमी वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इस सरकार के कार्यकाल में भारत के अरबपतियों की संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है। 2024 में भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 200 हो गई है, जो 2023 के मुकाबले 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है।

सरकारी स्कूलों की हालत दयनीय है, जहां शिक्षकों और संसाधनों की भारी कमी है। महोदय मेरे स्वयं के गांव के उच्चत माध्यमिक विद्यालय झालाटाल में एक भी वरिष्ठ अध्यापक नहीं है। 2023 की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार राज्य स्तर पर स्वीकृत 62.71 लाख शिक्षक पदों में से 9.9 लाख पद रिक्त है।

सरकार ने 10000 नए मेडिकल सीटें जोड़ने की घोषणा की है, लेकिन बुनियादी ढांचे और डॉक्टरों की कमी को कैसे दूर किया जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। आयुष्मान योजना के राजस्थान में निशुल्क इलाज बंद है। आज देश कैंसर की बीमारी के रोगियों की संख्या 25 लाख तक मुफ्त इलाज बंद है SMS अस्पताल के IPD टॉवर के काम को धीमा कर दिया है।

अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में न तो पर्याप्त डॉक्टर हैं, न ही दवाएं। केंद्रीय बजट 2025 में एक बार फिर स्वास्थ्य क्षेत्र की जरूरतों को अनदेखा कर दिया गया है। स्वास्थ्य बजट रु. 99,858.56 करोड़ आवंटित किया गया है, लेकिन यह किसी भी तरह से पर्याप्त नहीं है। इसका कुल बजट में हिस्सा घटकर मात्र 1.94 प्रतिशत रह गया है।

जल जीवन मिशन- राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जल जीवन मिशन के तहत पानी की सुविधा से वंचित है। राज्य के कई गांवों और शहरों में पानी की आपूर्ति के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे की कमी रही है। पाइपलाइनों, ट्रीटमेंट प्लांट्स और स्टोरेज टैंक की स्थिति बहुत खराब है। जिससे पानी की आपूर्ति में रुकावट आती है।

मनरेगा- इस बजट में सरकार से अपेक्षाएं थी कि मनरेगा को ध्यान में रखते हुए सरकार इसके बजट में वृद्धि करेगी लेकिन यहां भी सरकार ने हम सबको मायूस ही किया है। 2025-26 में इसके बजट में कोई वृद्धि नहीं की गई है। महोदय राजस्थान में मनरेगा के तहत प्रतिव्यक्ति मजदूरी केवल 266 रुपये है। महंगाई बढ़ती के साथ-साथ प्रतिव्यक्ति मजदूरी में भी वृद्धि की जानी चाहिए और दूसरा इस योजना के अंतर्गत खून-पसीने लगाकर मेहनत करने बावजूद भी श्रमिकों को उनकी मजदूरी समय पर नहीं दी जाती।

बेरोजगारी एवं आत्महत्याएं- युवा बेरोजगारी दर 45.4 फीसदी हो गई। देश में हर दूसरा नौजवान बेरोजगार है। सरकार ने युवाओं और बेरोजगारों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया। आज भारत का युवा सड़क पर दर-दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो रहा है।

सरकारी नौकरियों का बुरा हाल केन्द्र सरकार को अपने भीतर ही खाली पड़े पदों को भरने में नाकामियाब रही है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुसार 2014 से अब तक केन्द्रीय सरकार की नौकरियों के लिए 2.22 करोड़ व्यक्तियों ने आवेदन किया लेकिन केवल 7.22 लाख को ही सफलतापूर्वक नियुक्ति किया गया। जो कि बहुत कम है।

वर्तमान में आघे से अधिक पुरुष एवं दो तिहाई से अधिक कामकाजी महिलाएं केवल स्व-नियोजित श्रेणी रोजगार में आती हैं। जिससे साफ है उनको) और अपने रोजगार का इंतजाम खुद को करना पड़ रहा है।

महंगाई- सरकार ने महंगाई पर 'काबू पाने के लिए जितनी भी योजनाएँ बनाई हैं, वे अब तक पूरी तरह से विफल रही हैं। यदि हम पिछले कुछ वर्षों का अवलोकन करें, तो यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने कभी भी महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। ईंधन की बढ़ती कीमतें, रसोई गैस सिलेंडर की दरों में उछाल और अति आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि ने आम जनता की हालत बेहद खराब कर दी है। वर्तमान सरकार ने कभी भी महंगाई को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए, बल्कि इसके बजाय-पेट्रोल-डीजल पर भारी टैक्स लगाकर आम आदमी की परेशानियों को और बढ़ा दिया। इस सरकार औपने, राजनीतिक फायदे के लिए फैसले ले रही है। जिससे महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है।

खाद्य राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से बहुत सारे गरीब परिवारों को वंचित किया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा फेर में नाम भी सीमित कर रखी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना आवेदन स्वीकार किए जावे।

राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनावों को टालने की सरकार की मंशा-यह फैसला ग्रामीण क्षेत्र के विकास में एक रूकावट है। राजस्थान में जब ग्राम पंचायत चुनाव नहीं होंगे, तो सरपंचों को न केवल अधिकार नहीं मिलेंगे, बल्कि विकास के लिए निर्धारित फंड भी नहीं मिलेगा। ग्राम पंचायतों को जो फंड मिलते हैं, उनसे गांवों में सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, जल आपूर्ति, और अन्य आवश्यक सुविधाएँ बनाई जाती हैं। अगर चुनाव नहीं होते, तो इन विकास कार्यों को कौन चलाएगा? कौन सुनिश्चित करेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधरे? इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए विशेष कोर्ट की जरूरत है, लेकिन सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। ना ही सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या में बढ़ोतरी की तरफ काम कर रही है

राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति पिछले दो वर्ष से बजट के अभाव के कारण लंबित है। लोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में चक्कर काटते-काटते परेशान हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनकी छात्रवृत्ति उनको प्राप्त नहीं हुई है।

डांग क्षेत्र का विकास-सरकार की अनदेखी - अब मैं राजस्थान के डांग क्षेत्र की स्थिति की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय मेरा संसदीय क्षेत्र करौली-धौलपुर डांग क्षेत्र की श्रेणी में आता है यह क्षेत्र जो मुख्यतः आदिवासी एवं वंचित समुदायों का है, आज भी बुनियादी "से वंचित है।

डांग क्षेत्र कई गांव आज भी पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा तक पहुंच बाधित होती है। बिजली आपूर्ति बेहद है, जिससे खेती, शिक्षा और व्यवसाय प्रभावित होते हैं। पीने के पानी की भारी किल्लत बनी हुई है, जिससे आम जनजीवन संकट में है।

राष्ट्रीय बाघ अभयारण्य--करौली-धौलपुर में बाघ अभयारण्य की घोषणा के बाद विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए पुनर्वास प्रक्रिया में गहरी खामियाँ हैं। पुनर्वास नीति के अनुसार, राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का वादा किया है। हालाँकि, यह राशि घर बनाने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है, आजीविका चलाना तो दूर की बात है। वन्यजीव संरक्षण मानव पीड़ा की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

मेरे संसदीय क्षेत्र में करौली एक ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण जिला है, जिले में रेल लाईन नहीं होने के कारण यहां का पर्यटन एवं व्यापार को काफी नुकसान हो रहा है। जिले की रेलवे परियोजना का कार्य कछुए से भी धीमी गति से चल रहा है।

अंत में मैं ये कही कहना चाहता हूँ कि,

1. डांग क्षेत्र को विशेष विकास पैकेज दिया जाए और उसे ?आकांक्षी जिला? की तर्ज पर विकसित किया जाए।
2. SC-ST अत्याचार निवारण कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए।
3. करौली जिले की रेल परियोजना का कार्य जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए।
4. सड़कों, बिजली और पानी की आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर सुधारा जाए।
5. विद्यालय एवं अस्पतालों में रिक्त चल रहे शिक्षकों एवं डॉक्टरों के पदों पर जल्द भर जाए।
6. करौली-धौलपुर क्षेत्र में खनन योग्य भूमि वन विभाग के अधीन होने के कारण वहां खनन नहीं किया जा सकता। इस भूमि को वन विभाग से खनिज विभाग भूमि में परिवर्तन किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

जय भीम-जय भारत ? जय संविधान।

श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे (शिर्डी) : मैं लोक सभा में प्रस्तुत 2025-26 के वित्त बजट पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट का मैं अपनी और अपनी शिव सेना पार्टी की ओर से विरोध प्रकट करता हूँ। यह बजट न केवल हमारे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में विफल है, बल्कि यह मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए भी कोई राहत नहीं देता है।

सरकार ने इस बजट में कई ऐसी घोषणाएं की हैं जो केवल कागज पर ही अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविकता में इनका कोई फायदा नहीं होगा। उदाहरण के लिए, सरकार ने टैक्स स्लैब में बदलाव किया है, लेकिन यह बदलाव केवल उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा जिनकी आय 5 लाख रुपये से अधिक है। मध्यम वर्ग के लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होगा। सरकार ने टैक्स पेयर्स को 1.5 लाख रुपये तक के होम लोन पर ब्याज पर छूट दी है, लेकिन यह छूट केवल उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो पहले से ही होम लोन ले रहे हैं।

किसानों के लिए भी यह बजट कोई राहत नहीं देता है। सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन इन योजनाओं का कोई फायदा नहीं होगा अगर किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिलता है। सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा योजना का विस्तार किया है, लेकिन यह योजना केवल उन किसानों के लिए फायदेमंद होगी जो पहले से ही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने किसानों के लिए 16 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है, लेकिन यह राशि केवल कागज पर ही अच्छी लगती है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिलता है।

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी यह बजट कोई राहत नहीं देता है। सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई घोषणाएं की हैं, लेकिन इन घोषणाओं का कोई फायदा नहीं होगा अगर हमारे देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था में सुधार नहीं होता है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया है, लेकिन यह योजना केवल उन लोगों के लिए फायदेमंद होगी जो पहले से ही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है,

लेकिन यह राशि केवल कागज पर ही अच्छी लगती है, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर हमारे देश में स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था में सुधार नहीं होता है।

सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन इन योजनाओं का कोई फायदा नहीं होगा अगर किसानों को उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिलता है। इस मंत्रालय के लिए केवल 1,24,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो बहुत ही कम है।

यह बजट न केवल हमारे देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में विफल है, बल्कि यह मध्यम वर्ग और गरीब तबके के लिए भी कोई राहत नहीं देता है। सरकार ने इस बजट में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। देश में एक बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया है। दुःख की बात है कि इस बजट में मिडिल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट नहीं दी गई है और किसानों के कर्ज माफ करने का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। मनरेगा के लिए भी फंड नहीं बढ़ाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते संयंकट के बावजूद सरकार ने मनरेगा का बजट 86 हजार करोड़ रुपये पर ही स्थिर रखा है। इससे सूखा प्रभावित और गरीब ग्रामीण श्रमिक अधर में ही रह गए हैं।

इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे लेकर लोग खुशी मनाएं। लेकिन बीजेपी समर्थक उछल-कूद कर रहे हैं। यह बजट केवल मध्यम वर्ग को ही खुश करने के लिए बनाया गया है, जिसने हाल के चुनावों में बीजेपी को वोट नहीं दिया। बिहार में चुनाव होने हैं, इसलिए उस पर अधिक ध्यान दिया गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने पर्याप्त आवंटन नहीं किया है। शिक्षा मंत्रालय को 1,12,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 5 प्रतिशत कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय को 86,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 3 प्रतिशत कम है। कृषि क्षेत्र में भी सरकार ने किसानों के लिए पर्याप्त समर्थन नहीं दिया है। कृषि मंत्रालय को केवल 1,24,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। देश में 60 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं।

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी सरकार ने पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। पर्यावरण मंत्रालय को भी केवल 3,100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। देश में पर्यावरण की स्थिति खराब हो रही है। महिलाओं और विकलांगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी सरकार को और अधिक कदम उठाने होंगे। बजट में महिलाओं और विकलांगों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। इस बजट में शहरी गरीबों के लिए भी कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। देश में शहरी गरीबी एक बड़ा मुद्दा है। इस बजट में ग्रामीण विकास के लिए भी पर्याप्त आवंटन नहीं किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,12,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। देश में 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। रोजगार सृजन के लिए भी यह बजट कोई राहत नहीं देता है। सरकार ने रोजगार सृजन के लिए कई घोषणाएं की हैं, लेकिन इन घोषणाओं का कोई फायदा नहीं होगा।

ऐसे लोक जिनकी सैलरी है उन्हें तो छूट मिलेगी लेकिन बेरोजगारों का क्या होगा ? जिनकी सैलरी ही नहीं वे क्या करेंगे? रोजगार के मोर्चे पर कोई ऐलान नहीं किया गया । जब तक रोजगार के लिए निवेश नहीं किया जाता तब तक अर्थव्यवस्था को फायदा नहीं होने वाला है । यह भी दुःखद है कि राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए सरकार अगले वित्त वर्ष में बाजार से 11.54 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगी ।

ऐसा लगता है कि बिहार को तोहफा मिला है । वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में बिहार पर काफी ध्यान दिया गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्य के लिए कई घोषणाएं कीं, जिनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए समर्थन शामिल है । केंद्र बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेगा तथा राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए वहां ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा भी देगा । बिहार को घोषणाओं का खजाना मिल गया है । महाराष्ट्र सहित अन्य दूसरे राज्यों की इस बजट में अनदेखी की गयी है ।

यह दुख की बात है कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है । इसमें केवल बिहार बिहार हो रहा था । जहां भी चुनाव होते हैं वहां का नाम लिया जाता है । यह भारत सरकार का बजट है या फिर बिहार सरकार का बजट है । जब देश के बजट की बात करते हैं तो उसमें सभी राज्यों की बात होनी चाहिए । जिन बैसाखियों पर सरकार चल रही है उनको बचाने के लिए पूरे मुल्क को दांव पर लगा दिया गया । मैं अपने संसदीय क्षेत्र की निम्नांकित विषयों की ओर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिनके बारे में बजट में धन आवंटन के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है :-

भगवान श्री राम की यात्रा के महत्वपूर्ण स्थलों को रामायण सर्किट स्कीम में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है ।

इस संदर्भ में, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि शिरडी संसदीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थलों को रामायण सर्किट स्कीम में शामिल किया जाए ।

जैसा कि पुराणों में उल्लेख है, भगवान श्री राम ने अपनी यात्रा के दौरान अकोला में अगस्त्य आश्रम में आए थे और वहां से पंचवटी की ओर गए थे ।

इसके अलावा, भगवान श्री राम ने कोपरगांव के पास गोदावरी नदी में पूज्य पिताश्री दशरथ का श्राद्ध किया था और सीता हरण के बाद नाशिक में आए थे । जटायु ने उन्हें बताया था कि रावण ने सीता का हरण किया है । इसके बाद, भगवान श्री राम ने अकोला में अगस्त्य ऋषि का आशीर्वाद लेने आये और उन्हें ऋषि महाराज ने उन्हें बान दिया, जिससे उन्होंने रावण का वध किया ।

भगवान श्री राम अयोध्या जाने के दौरान तीसरी बार भी अकोला में अगस्त्य ऋषि के दर्शन और उनका आशीर्वाद लेने हेतु आये थे । इन सभी स्थलों का महत्व रामायण से जुड़े ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के रूप में है ।

प्रभू श्रीराम स्व स्थापित श्री रामेश्वर देवस्थान धांदरफळ तहसील संगमनेर जिला अहिल्यानगर प्रभू श्रीराम अगस्ती ऋषी मिलने के बाद दंडकारण प्रभू श्रीराम सीता माता खोज मे महान तपस्वी धौम्य ऋषि के आश्रम धौम्य नगरी आये थे उसी दिन महान तपस्वी धौम्य ऋषि ने या तपस्या पूजन करके प्रभू श्रीराम को सीतामाता खोज के लिए सहयोग किया उसी समय अमृतवाहिनी प्रवरा नदी के कण से प्रभू श्रीराम ने शिव आराधना केले शिव की पिंडी बनाई पिंडी से शिव का आशीर्वाद प्रकट किया उसी दिन से प्रभू श्रीराम स्थापित शिवलिंग प्रभू श्रीराम श्री क्षेत्र रामेश्वर निर्माण महान तपस्वी धौम्य ऋषि के आश्रम मे धौम्य ऋषि की नगरी धांदर फल प्राचीन तीर्थक्षेत्र के द्वारा महाराष्ट्र के अंदर शिवदर्शन के लिए जाना जाता है ।

इसलिए, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि शिरडी संसदीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थलों को रामायण सर्किट स्कीम में शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और साथ ही इस संदर्भ में एक समिति का गठन किया जाए जो इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थलों का सर्वेक्षण करे और उन्हें रामायण सर्किट स्कीम में शामिल करने के लिए आवश्यक सिफारिशें करे ।

महाराष्ट्र के नासिक शहर में त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के पास गोदावरी नदी के तट पर महाकुंभ मेला आयोजित होना है । इस बार नासिक कुंभ मेला 2027 में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रयागराज महाकुंभ मेले की भांति करोड़ों श्रद्धालु शामिल होंगे ।

नासिक कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालु कॉपरगांव, जहां शुकाचार्य मंदिर और विश्व स्तरीय आश्रम और पुरातन काल के अति प्राचीन मंदिर हैं तथा भगवान श्रीराम ने भी अपने वनवास के दौरान पिताश्री दशरथ का वहां स्थित गोदावरी नदी में पिंडदान किया तथा कुछ ही दूरी पर भगवान श्रीराम का मंदिर भी स्थापित है, वहां तथा शिरडी, जो देश का ही नहीं बल्कि विश्व का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, आयेंगे तथा ये श्रद्धालु शनि शिंगणापुर और शिरडी संसदीय क्षेत्र के अन्य प्रमुख ऐतिहासिक अति प्राचीन धार्मिक स्थलों में भी दर्शनार्थ जाएंगे ।

लेकिन, नासिक कुंभ मेले के दौरान शिरडी संसदीय क्षेत्र के उपरोक्त धार्मिक स्थलों में आने वाले श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाएं प्रदत्त किए जाने हेतु अब तक कोई भी तैयारी नहीं की गई है तथा न ही कॉपरगांव स्थित गोदावरी नदी के तट पर घाटों का निर्माण करवाया गया है ।

अतः मेरा अनुरोध है कि जिस प्रकार से नासिक कुंभ मेला के लिए श्रद्धालुओं की सुविधाएं राशि का आवंटन किया गया है, उसी प्रकार से शिरडी संसदीय क्षेत्र में भी कुंभ मेला के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने हेतु धन का आवंटन अविलम्ब किया जाए, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में किसी भी तरह की कठिनाई न हो ।

अकोले महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की अकोले तहसील में एक जनगणना शहर और तालुका है । अकोले का स्थान अकोले भारत में पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के सह्याद्री पहाड़ों से घिरा हुआ है । अकोले का इतिहास अकोले कई ऐतिहासिक स्थलों का निवास स्थान है जो महाराष्ट्र के मध्यकालीन इतिहास और संस्कृति में इसके योगदान को दर्शाता है । अकोले का भूगोल अकोले

प्रवर नदी जैसी नदी की उपस्थिति के लिए लोकप्रिय है, जो ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भों के साथ गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है।

विल्सन बांध, जिसे भंडारदरा बांध के रूप में भी जाना जाता है, 1910 में समुद्र तल से लगभग 150 मीटर (490 फीट) ऊपर बनाया गया था। यह छाता झरने की तरह बनता है, जो एक छतरी के आकार का झरना है। अकोले में पर्यटन बहते पानी को पनबिजली में परिवर्तित किया जाता है। यह भंडारदरा का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, इस झरने का दृश्य हिंदी फिल्मों जैसे मैंने प्यार किया और राजू चाचा की शूटिंग के लिए पृष्ठभूमि का काम कर चुका है।

निलवंडे बांध निलवंडे बांध पनबिजली उत्पादन के लिए प्रवर नदी पर बनाया गया एक और बांध है। कलसुबाई कलसुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊँची चोटी है 1,646 मीटर (5,400 फीट)। घाटघर घाटघर एक प्रसिद्ध दृश्य बिंदु है जो भंडारदरा से 22 किलोमीटर (14 मील) की दूरी पर स्थित है और सह्याद्री रेंज के उत्कृष्ट दृश्य प्रस्तुत करता है और 250 मेगावाट क्षमता की उडचन जलविद्युत परियोजना की पहली परियोजना का घर है।

कोकन कड़ा हरिश्चंद्रगढ़ के पास स्थित है। यह पहाड़ों की सपाट, तीखी और गहरी धार ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने यहां ऋषि अगस्त्य से मुलाकात की थी। ऋषि ने तब भगवान राम को एक चमत्कारी बाण भेंट किया था जिसका उपयोग उन्होंने रावण को मारने के लिए किया था। अमृतेश्वर मंदिर अमृतेश्वर मंदिर रतनवाड़ी गांव की शुरुआत में स्थित है। इसे 1,200 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है जो मुख्य देवता के रूप में भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण हेमदपंथी स्थापत्य शैली में किया गया है, जिसमें मुख्य मंदिर पर खूबसूरत पत्थर की नक्काशी की गई है।

मेरा अनुरोध है कि अकोले तालुका के ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व को देखते हुए इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित किए जाने हेतु सकारात्मक कार्यवाही की जाए।

मेरे संसदीय क्षेत्र शिरडी के अकोले तालुका में प्रवरा नदी के तट पर एक हजार वर्ष पुराना सिद्धेश्वर मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्रीराम पंचवटी से होते हुए अकोले को अपने श्रीचरणों से पावन किए थे। इसलिए, इस मंदिर की क्षेत्र में काफी मान्यता है। यहां पर एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं और भण्डारा, पालकी का आयोजन गांव के लोग मिलकर करते हैं। लेकिन, यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवागमन और जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है।

महाराष्ट्र राज्य के शिरडी संसदीय क्षेत्र में अकोले तालुका के ग्राम म्हालादेवी में स्थित श्री क्षेत्र खण्डेश्वर देवस्थान, जो भगवान शिव के अवतार हैं और पाण्डव कालीन मंदिर है तथा प्रत्येक वर्ष अप्रैल/मई माह के दौरान आयोजित होने वाले समारोह में 8-10 लाख पर्यटक / श्रद्धालु आते हैं, को प्रसाद योजना में शामिल कर वहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता है।

अतः मेरा अनुरोध है कि शिरडी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित उक्त ऐतिहासिक मंदिरों को प्रसाद योजना के अन्तर्गत शामिल करते हुए इनके सौंदर्यीकरण और यहां आने वाले तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए जल, विद्युत, सड़क, तीर्थ यात्री निवास इत्यादि हेतु धन का आवंटन किया जाए ।

मेरे संसदीय क्षेत्र शिरडी के अकोला तालुका में प्रवरा नदी के तट पर स्थित अगस्त्य ऋषि आश्रम रामायण से जुड़ा हुआ है । ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता ऋषि अगस्त्य से मिलने गए तथा ऋषि अगस्त्य ने भगवान श्रीराम को रावण को मारने के लिए एक चमत्कारी तीर भी प्रदान किया था ।

यह भी मान्यता है कि भगवान श्री राम अयोध्या जाने के दौरान तीसरी बार भी अकोला में अगस्त्य ऋषि के दर्शन और उनका आशीर्वाद लेने हेतु आये थे । इन सभी स्थलों का महत्व रामायण से जुड़े ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के रूप में है । महाशिवरात्रि के दिन यहां पर लगभग 4 लाख श्रद्धालुओं का आवागमन होता है । लेकिन, उनके लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभाव है ।

अतः मेरा अनुरोध है कि अकोले तालुका में स्थित अगस्त्य ऋषि मंदिर, जहां भगवान का वास्तव्य रहा है तथा महाशिवरात्रि के दिन लाखों की संख्या में पर्यटकों / श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, को रामायण सर्किट में शामिल कर वहां पर जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने की नितांत आवश्यकता है ।

मेरे संसदीय क्षेत्र शिरडी के अकोले तालुका में ताहाकारी गाँव के पास "अधाला नदी" बहती है । हजारों वर्ष पुराना श्री जगदम्बा मंदिर इस नदी के तट पर स्थित है । इस मंदिर का निर्माण हेमाडपंथी नामक विशेष प्रणाली का उपयोग करके बनाया गया है इसमें बहत्तर खंभे और पाँच शिखर हैं और मंदिर के बाहरी और भीतरी भाग पर विशेष प्रकार की मूर्तिकला नक्काशी की गई है । इसके आसपास के क्षेत्र को "दंडकारण्य परिसर" कहा जाता है । ऐसी मान्यता है कि यह एक ऐसा स्थान है, जिसे भगवान " श्री राम" ने पवित्र बनाया है ।

जगदंबा मंदिर एक हेमाडपंथी मंदिर है, जो देवी अप्सराओं की लकड़ी की मूर्ति के लिए जाना जाता है । अधाला नदी के तट पर स्थित, यह महाराष्ट्र राज्य के उल्लेखनीय मंदिरों में से एक है । इस मंदिर में साल में दो बार जगदंबा माता उत्सव मनाया जाता है । इस मंदिर में एक बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं तथा प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में हनुमान जयंती के दौरान कई लाख लोग आते हैं । वर्तमान में यह मंदिर जर्जर होता जा रहा है तथा लीकेज भी हो रहा है तथा यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पानी, विद्युत, सड़क, भक्त निवास इत्यादि का भारी अभाव है ।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह ताहाकारी गांव में स्थित जगदम्बा मंदिर के जीर्णोद्धार और यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने हेतु धन का आवंटन करने का कष्ट करें । मैं यह भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि ट्राइबल क्षेत्रों में इको सेंसेटिव जोन की स्थापना की गई है, जिसमें मेरे संसदीय क्षेत्र शिरडी के अन्तर्गत अकोले तालुका भी

शामिल है । अकोले तालुका एक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है । इस तालुका में इको सिन्सेटिव जोन की वजह से विकास कार्य पूरी तरह से अवरुद्ध है ।

यह सही है कि इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना है । लेकिन, वास्तविकता यह है कि इको सेंसेटिव जोन की स्थापना से ट्राइबल क्षेत्रों में विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा स्थानीय आदिवासी समुदाय को अपनी जीविका चलाने और विकास कार्यों में भाग लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

इसलिए, अकोले तालुका को इको सेंसेटिव जोन से विमुक्त किया जाए । इससे ट्राइबल क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय समुदाय को अपनी जीविका चलाने में आसानी होगी । दूसरे, प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत संरक्षित स्थल के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति न होने की वजह से नवीनीकरण, निर्माण और शहरीकरण से संबंधित गतिविधियां अवरुद्ध हो रही हैं और संरक्षित स्थल एवं इनके निकट बने मकान आदि पूरी तरह से ध्वस्त होते जा रहे हैं एवं इस रोक के कारण स्थानीय लोगों को अपने घरों और व्यवसायों के विकास में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । साथ ही, यह रोक स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी बाधा उत्पन्न कर रही है ।

इसलिए, मेरा अनुरोध है कि संरक्षित स्थल के 100 मीटर दायरे के अंदर निर्माण संबंधी रोक को तुरन्त हटाया जाए और संरक्षित स्मारकों के पुनर्निर्माण की स्थानीय लोगो को अनुमति प्रदान की जाए ।

महाराष्ट्र राज्य के शिरडी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत अकोले तालुका के ग्राम बारी में स्थित कलसुबाई बीक महाराष्ट्र राज्य का सबसे ऊंचा शिखर है । इस शिखर को पर्यटनीय दृष्टि से विकसित करने के लिए दो जिलों की आपस में कनक्विटी हेतु पर्यटनीय दृष्टिसे रोपवे बनाए जाने की आवश्यकता है ।

अकोले तालुका के घाटघर में स्थित घाटन देवी प्वाइंट और घाटघर डेम को तथा ग्राम रतनवाड़ी में स्थित अमृतेश्वर मंदिर को पर्यटनीय दृष्टि से विकसित किए जाने की जरूरत है ।

शिरडी संसदीय क्षेत्र में संगमनेर तालुका के गांव प्रेमगिरी में स्थित हनुमान मंदिर और खांडगांव में स्थित भगवान शिव के खंडेश्वर मंदिर, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का पुरातन मंदिर है तथा जहां वर्षभर एक बड़ी संख्या में पर्यटक / श्रद्धालुओं का आवागमन होता है ।

संगमनेर तालुका के ही गांव कोकण में स्थित श्री क्षेत्र निझणेश्वर मंदिर, जिसमें शिवलिंग की स्थापना पाण्डवों ने की थी और ग्राम नीमगांव जाली में जहां एक अति प्राचीन दूधेश्वर मंदिर है और एक बड़ी संख्या में पर्यटक / श्रद्धालुओं का आवागमन होता है । इन सभी धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं / पर्यटकों के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाओं का भारी अभावी है ।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह शिरडी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उपर्युक्त सभी धार्मिक स्थलों को प्रसाद योजना में शामिल करके पर्यटनीय दृष्टि से विकसित किए जाने हेतु सकारात्मक कार्यवाही करें ।

महाराष्ट्र राज्य के शिरडी संसदीय क्षेत्र में कोपरगांव तालुका में स्थित जंगली बाबा आश्रम, जनार्दन स्वामी समाधि मंदिर, गुरु शुकाचार्य मंदिर और कोकमठाण गांव में गोदावरी नदी के तट पर स्थित लक्ष्मी माता मंदिर, कचेश्वर मंदिर, हेमान्द्रिपंत भगवान शिव का पुरातन मंदिर, जहां प्रतिदिन एक बड़ी संख्या में पर्यटक / श्रद्धालुओं का आवागमन होता है, को प्रसाद योजना में शामिल करके पर्यटनीय दृष्टि से विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

महाराष्ट्र राज्य के शिरडी संसदीय क्षेत्र की संगमनेर तालुका के गांव धांदरफळ में स्थित विठ्ठल मंदिर और पीर बाबा दरगाह हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है और शाहगढ़ किला ग्राम में स्थित प्रेमगिरी परिसर अति प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है। इनको प्रसाद योजना में शामिल करके पर्यटनीय दृष्टि से विकसित किए की आवश्यकता है।

मेरा अनुरोध है कि शिरडी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले उपर्युक्त स्थलों के ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इन्हें पर्यटनीय दृष्टि से विकसित किए जाने हेतु सकारात्मक कार्यवाही की जाए।

मेरा संसदीय क्षेत्र शिरडी, जिला अहमदनगर (महाराष्ट्र) एक अनुसूचित बाहुल्य काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की बाहुल्यता है और उनकी गुजर-बसर का कोई सहारा नहीं है। इस क्षेत्र में बकरी, कुक्कुट व मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं। मुझे खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सितम्बर, 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएसवाई) की शुरुआत की है।

मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिरडी के अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की जीविकापार्जन एवं उत्थान हेतु इस समुदाय के लिए क्षेत्र में बकरी व कुक्कुट पालन के साथ-साथ केन्द्र की पीएमएसवाई योजना के अन्तर्गत ब्लॉक स्तर पर अकोला, संगमनेर, कॉपरगांव, राहाता, श्रीरामपुर, नेवासा, राहुरी, करजत व जामखेड़ में मछली पालन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र शिरडी में जागड़े फाटा वडगांव पान फाटा मार्ग (राज्य मार्ग 65) पर श्री साईं बाबा और अन्य निकटवर्ती पवित्र स्थानों के दर्शन के लिए शिरडी आने वाले भक्तों के यातायात वाहनों के कारण भारी भार रहता है। उक्त राज्य मार्ग 65 मेरे निर्वाचन क्षेत्र में संचार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

यह मार्ग संगमनेर-पुणे और संगमनेर-भंडारदरा मार्गों से जुड़ा हुआ है और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। इसलिए, साईं भक्तों के शिरडी और निकटवर्ती क्षेत्रों में अन्य पवित्र स्थानों की यात्रा के लिए इस मार्ग को उन्नत और चौड़ा करने की तत्काल आवश्यकता है। यदि यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तांतरित हो जाता है तो यह उन्नयन करके चार लेन का मार्ग बन जाएगा जो साईं भक्तों के लिए शिरडी और अन्य निकटवर्ती क्षेत्रों की यात्रा के लिए लाभदायक होगा।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस सड़क को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तांतरित कर सड़क का पुनरोद्धार का कार्य यथाशीघ्र पूरा किया जाए।

मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र शिरडी के अन्तर्गत संगमनेर तालुका में पुणे-नासिक (एनएच 50) रोड पर गभानवाड़ी सर्किल के पास फ्लाईओवर के निर्माण की तत्काल आवश्यकता के साथ-साथ जावले वस्ती से गभानवाड़ी, चंदनपुरी घाट तक सर्विस रोड के तुरन्त निर्माण करवाए जाने की ओर आकर्षित करना चाहूंगा ।

वर्तमान में, चंदनपुरी गभानवाड़ी क्षेत्र में एक छोटा सा सर्कल बनाया गया है, जो पुणे-नासिक (एनएच 50) रोड पर पैदल यात्रियों और वाहनों के लिए क्रॉसिंग पॉइंट के रूप में कार्य करता है । यह स्थान, चंदनपुरी घाट की शुरुआत में स्थित है, घाट की खड़ी ढलान के कारण उच्च गति वाले यातायात के लिए कठिन है । दुर्भाग्य से, इसके परिणामस्वरूप समय के साथ कई घातक दुर्घटनाएँ हुई हैं, जिससे यात्रियों और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है ।

अतः मेरा अनुरोध है कि आगे की त्रासदियों को रोकने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, गभानवाड़ी सर्किल के पास एक फ्लाईओवर का निर्माण अविलम्ब करवाया जाए तथा ग्रामीणों, छात्रों और किसानों के दैनिक आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए, सर्किल से जावले वस्ती तक लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली एक सर्विस रोड को भी जनहित में निर्मित किया जाए ।

मैं सरकार का ध्यान राज्य राजमार्ग संख्या 7 के चौड़ीकरण से संबंधित मौजूदा मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सावली विहिर से भरवास तक फैला हुआ है । इस सड़क का निर्माण 2014 में शुरू हुआ था, फिर भी यह काम आज भी अधूरा है । जबकि सिन्नर, शिरडी और देरदे कोरहाले तक का हिस्सा पूरा हो गया है, देरदे फाटा से लासलगांव तक का महत्वपूर्ण हिस्सा चौड़ा नहीं किया गया है ।

यहां की एक प्रमुख समस्या कोलपेवाड़ी सहकारी शक्कर कारखाने के आसपास का क्षेत्र है, जहाँ एक प्रमुख कॉलेज है । इस स्थान पर बड़ी संख्या में छात्र, विशेष रूप से बच्चे और छोटी लड़कियाँ, स्कूल जाते हैं । इस क्षेत्र में उचित सड़क चौड़ीकरण न होने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है । वास्तव में, कोलपेवाड़ी सहकारी चीनी कारखाने के पास पहले ही कई दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं । तथा मानसून के मौसम में बैलगाड़ियों और ट्रकों के कारण सड़क पर अत्यधिक भीड़ हो जाती है, जिससे स्थिति और भी जटिल हो जाती है ।

अतः सुरक्षा संबंधी चिंताओं और स्थानीय समुदाय के लिए इस मार्ग के महत्व को देखते हुए, मेरा अनुरोध है कि डेडें फाटा से कोलपेवाड़ी तक सड़क को चौड़ा करने और इसे चीनी कारखाने तक विस्तारित किए जाने हेतु सकारात्मक कार्यवाही की जाए ।

मैं सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र शिरडी में रेलवे लाइन के दोहरीकरण के कारण एक महत्वपूर्ण सड़क के बंद होने से संबंधित गंभीर मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । यह सड़क जो पहले पढेगांव, लाडगांव, मालुंजा, कन्हेगांव, भेरदापुर के ग्रामीणों, स्कूली छात्रों और किसानों के लिए एक प्रमुख मार्ग के रूप में कार्य करती थी, लाडगांव चौकी में पुराने रेलवे फाटक संख्या 44 (ओएचई एम 70-404/12-14) के पास स्थित थी ।

यह सड़क दैनिक यात्रा के लिए महत्वपूर्ण थी, लेकिन रेलवे लाइन के विस्तार के बाद इसे बंद कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, स्थानीय निवासियों और उपरोक्त गांवों सहित आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को अब बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस समस्या के समाधान के लिए मेरे संसदीय क्षेत्र के लाडगांव-पढ़ेगांव, तालुका श्रीरामपुर में पुराने रेलवे फाटक क्रमांक 44 (ओएचई मास क्रमांक 404/3-4) के पास एक छोटे अंडरपास का निर्माण करवाना सुनिश्चित करें, जिससे ग्रामीणों, छात्रों और किसानों की दैनिक आवाजाही में आसानी हो सके ।

मेरे संसदीय क्षेत्र शिरडी की तालुका कोपरगांव के अन्तर्गत जावलके ग्राम पंचायत की लगभग 1,700 की आबादी और 390 परिवारों वाले इस गांव में लगातार लोड शेडिंग के कारण बिजली की गंभीर और निरंतर कमी का सामना करना पड़ रहा है । वर्तमान बिजली प्रणाली गांव की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है तथा अक्सर कम दबाव की आपूर्ति प्रदान करती है ।

इसका समाधान करने के लिए, ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों के साथ परामर्श करने के बाद निर्णय लिया है कि सौर ऊर्जा सबसे व्यवहार्य और टिकाऊ समाधान है । इस संबंध में व्यक्तिगत घरों के लिए छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली, कृषि, सार्वजनिक संस्थानों और सरकारी भवनों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली मोटरें और सौर स्ट्रीट लाइटें लगाना शामिल है ।

इससे ग्रिड पर निर्भरता कम होगी, लोड शेडिंग के प्रभाव कम होंगे, बिजली के बिल कम होंगे और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा । गांव की योजना कृषि सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए कुसुम योजना और घरेलू प्रतिष्ठानों के लिए रूफटॉप सोलर सब्सिडी योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की है ।

अतः मेरा अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिरडी की ग्राम पंचायत जावलके सहित अन्य ग्राम पंचायतें, जहां विद्युत की भारी किल्लत है, के लिए छत पर सौर संयंत्र और सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना किए जाने हेतु सकारात्मक कार्यवाही की जाए ।

यह हम सभी देशवासियों के लिए प्रसन्नता की बात है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, खेलों ने केंद्र स्तर पर जगह बनाई है, जिसका उदाहरण 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने की महत्वाकांक्षा है । इसी भावना के साथ, मैं उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में रोलर स्केटिंग को पदक स्पर्धा के रूप में शामिल करने के लिए आपके हस्तक्षेप और व्यक्तिगत समर्थन का अनुरोध करता हूँ ।

विश्व खेलों - एशियाई खेलों और ओलंपिक में एक स्थायी पदक स्पर्धा, रोलर स्केटिंग ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई है । यह हमारे राज्य में भी बेहद लोकप्रिय है, जहाँ कई एथलीटों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सफलताएँ हासिल की हैं । इसे राष्ट्रीय खेलों में शामिल करने से न केवल उनकी उपलब्धियों का सम्मान होगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए एक मंच भी मिलेगा ।

अतः मेरा अनुरोध है कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में रोलर स्केटिंग को पदक स्पर्धा के रूप में शामिल किए जाने हेतु सकारात्मक कार्यवाही करें।

मैं शिरडी लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा, जो मुख्य रूप से कृषि प्रधान है, जिसमें डेयरी और पशुपालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यह क्षेत्र पहाड़ी और पठारी हैं, और उचित सड़क संपर्क की कमी क्षेत्र के समग्र विकास में बाधा बन रही है।

शिरडी संसदीय क्षेत्र में अकोले तालुका, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है, एक आदिवासी क्षेत्र है जिसमें पर्यटन की पर्याप्त क्षमता है। स्थानीय सड़कों को मुख्य राजमार्ग से जोड़ने से न केवल गांवों और बस्तियों के लिए बेहतर संपर्क की सुविधा होगी, बल्कि पर्यटन विकास और आदिवासी विकास के अवसर भी पैदा होंगे।

अतः मेरा अनुरोध है कि शिरडी लोकसभा क्षेत्र में इन ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए, जिससे इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में काफी वृद्धि होगी और क्षेत्र के आर्थिक विकास में भी योगदान मिलेगा।

मेरा यह भी अनुरोध है कि शिरडी संसदीय क्षेत्र की 14 सड़कों के बारे में, जिन्हें केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु माननीय सड़क, परिवहन राजमार्ग मंत्री महोदय को 10-12-2024 में पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है, इन सड़कों को केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत शामिल करके सड़कों के निर्माण / सुधार के लिए उचित धनराशि आवंटित की जाए।

मैं सरकार के ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि अहिल्यानगर से शिरडी तक का सड़क मार्ग शिरडी और शनि शिंगणापुर के पवित्र स्थानों को जोड़ने वाला एक प्रमुख यातायात मार्ग है। यह उत्तर को दक्षिण भारत से जोड़ने वाली एक प्रमुख सड़क भी है। यहाँ यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि इस खंड पर रहने योग्य क्षेत्र में, कुल 1.2 किलोमीटर की लंबाई में, सड़क दो लेन वाली है, और सड़क पर चलने वाले लोगों को प्रतिदिन यातायात की भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, अड़चन के कारण, रहने योग्य क्षेत्रों में अक्सर दुर्घटनाएँ हो रही हैं।

इस समस्या को हल करने के लिए, रहने योग्य क्षेत्र में दो लेन वाला फ्लाईओवर, जहाँ भूमि की कमी के कारण सड़क वर्तमान में दो लेन वाली है, की अत्यधिक आवश्यकता है। यह दो लेन वाला फ्लाईओवर और उपलब्ध क्षेत्र के भीतर दो लेन वाली सड़क रहने योग्य क्षेत्र में सुचारु यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से काम करेगी।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिरडी के अन्तर्गत एनएच-160 के खंड पर रहने योग्य क्षेत्र में कुल 1.2 किलोमीटर लंबाई के दो लेन वाले फ्लाईओवर के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए।

मैं सरकार को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे शिरडी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत अकोले नगर पंचायत एक आदिवासी तालुका है और पिछले एक साल से 15वें वित्त आयोग द्वारा पंचायत को धन का आवंटन नहीं किया गया है, इसलिए पानी की

आपूर्ति की समस्या बनी हुई है और साथ ही साथ अपशिष्ट निपटान और अतिरिक्त मशीनरी के लिए भी धनाभाव बना हुआ है। जबकि, 15वें वित्त आयोग द्वारा अकोले नगर पंचायत को अपशिष्ट निपटान और अतिरिक्त मशीनरी के लिए निधि आवंटित की जानी चाहिए। यही स्थिति अकोले नगर पंचायत में स्वास्थ्य सेवाओं की भी है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी इस नगर पंचायत को 15वें वित्त आयोग द्वारा निधि उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह शिरडी संसदीय क्षेत्र में स्थित आदिवासी अकोले नगर पंचायत को उपरोक्त सभी कार्यों के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा निधि उपलब्ध करवाए जाने हेतु सकारात्मक कार्यवाही करें।

मैं सरकार का ध्यान शिरडी निर्वाचन क्षेत्र में देश के प्रसिद्ध साईं नगर (शिरडी) रेलवे स्टेशन की ओर आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहूंगा कि शिरडी रेलवे स्टेशन के पूर्वी तरफ निघोज रुई शिवाय पर मेट्रो है और उसके बगल में पोल नंबर के बीच रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ सर्विस रोड है, इससे स्टेशन तक पहुंच आसान होगी तथा उक्त रेलवे स्टेशन के पूर्वी तरफ मेट्रो तक रेलवे स्टेशन का यार्ड स्पेस है, जहां बड़ी संख्या में कांटे और झाड़ियां हैं। इसलिए वहां फेंसिंग और यार्ड स्पेस विकसित किया जाना चाहिए।

मैं यह भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि मेट्रो के पूर्वी तरफ लगभग आधा किमी जो कि उक्त रेलवे स्टेशन के निघोज रुई शिवाय पर है, चारी नंबर 11 के पास, जो नगर मनमाड हाईवे से रुई गांव तक जाती है, रेलवे ने बड़ा एंगल बनाकर रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया है। इससे उन किसानों को काफी परेशानी हो रही है जिनकी जमीन दो हिस्सों में बंट गई है और रास्ता भी बंद होने से बंद हो गया है। ट्रैक पर लोहे का एंगल लगाकर गेट खुलवाया जाए और वहां पर चौकी की व्यवस्था की जाए।

मेरा यह भी अनुरोध है कि शिरडी रेलवे स्टेशन से पुणतांबा रेलवे स्टेशन तक उक्त रेलवे ट्रैक के दोनों ओर बड़ी संख्या में कंटीली झाड़ियां उगी हुई हैं तथा दोनों ओर खेती की जाती है। इसलिए, चूंकि इन कंटीली झाड़ियों के कारण तेंदुओं की आवाजाही बढ़ रही है, इसलिए रेलवे ट्रैक पर कंटीली झाड़ियों और पेड़ों को हटाया जाना चाहिए तथा उस स्थान को साफ रखने का ध्यान रखा जाना चाहिए।

मैं सरकार का ध्यान शिरडी संसदीय क्षेत्र के अकोले तालुका में प्रमुख सड़कों के विकास की तत्काल और अनिवार्य आवश्यकता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो इस क्षेत्र के पर्यटन, परिवहन और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अकोले में कई उल्लेखनीय पर्यटन स्थल हैं, जिनमें भंडारदरा बांध, निलवंडे बांध, घाटघर बांध, कलसुबाई चोटी (1646 मीटर), सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र गढ़, पट्टाकिला, अलंगगढ़, अजोबा गढ़ और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में कोंकणकाड़ा शामिल हैं। ये प्राकृतिक चमत्कार, विश्व प्रसिद्ध संधान घाटी और रंधा जलप्रपात के साथ, अकोले को एक आकर्षक पर्यटन केंद्र बनाते हैं।

इस क्षेत्र में अमृतेश्वर मंदिर भी है, जो ऋषि अगस्ती की एक प्राचीन मूर्ति का घर है। अपार संभावनाओं के बावजूद, सड़कों की खराब स्थिति ने पर्यटन और समग्र विकास के विकास में बाधा उत्पन्न की है।

अतः मेरा अनुरोध है कि शिरडी संसदीय क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक लाभों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य राजमार्ग संख्या 23 (बोटा से राजूर) और एसएच-54, एसएच-65, एसएच-50 और एसएच-320 सहित अन्य प्रमुख राज्य सड़कों का दोहरीकरण किए जाने हेतु सकारात्मक कार्यवाही की जाए ।

मैं अवगत कराना चाहूंगा कि निम्नलिखित राजमार्गों - पुणे-नासिक-कल्याण - नगर, नासिक-मुंबई, कोल्हार-घोटी के बीच संपर्क में सुधार से यातायात की भीड़भाड़ को काफी हद तक कम किया जा सकेगा और क्षेत्रीय गतिशीलता में सुधार होगा । इन सड़कों के दोहरीकरण के निम्नलिखित लाभ होंगे :-

पुणे-नासिक-कल्याण-नगर, नासिक-मुंबई, कोल्हार-घोटी के बीच संपर्क में सुधार और दोहरीकरण से यातायात की भीड़भाड़ को काफी हद तक कम किया जा सकेगा और क्षेत्रीय गतिशीलता में सुधार होगा और अहमदनगर, ठाणे, मुंबई, पुणे और नासिक जिलों में यात्री और माल परिवहन दोनों के लिए परिवहन लागत को लगभग 30 प्रतिशत कम कर देंगी और साथ ही शिरडी, कोपरगांव तालुका, संगमनेर तालुका, अकोले तालुका से मुंबई और संगमनेर, अकोले से कल्याण की दूरी भी काफी कम हो जाएगी ।

बेहतर कनेक्टिविटी से अधिक पर्यटक आकर्षित होंगे, जिससे पर्यटन से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय राजस्व में वृद्धि होगी । यह परियोजना न केवल आदिवासी बहुल अकोले तालुका में नए रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा करेगी, बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी इसका भरपूर लाभ मिलेगा ।

अतः मेरा अनुरोध है कि पुणे-नासिक-कल्याण-नगर, नासिक-मुंबई, कोल्हार-घोटी राजमार्गों के सुधार एवं दोहरीकरण हेतु सकारात्मक कार्यवाही की जाए ।

महाराष्ट्र राज्य के शिरडी संसदीय क्षेत्र में श्रीरामपुर तालुका में डोमेगांव स्थित है । इस गांव में उत्खनन के दौरान प्राचीन अवशेष मिले हैं । डोमेगांव गांव में प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही आबाद था । इन अवशेषों में प्राचीन मंदिर, सिक्के, मूर्तियां और अन्य पुरातात्विक सामग्री शामिल हैं ।

डोमेगांव गांव के अवशेषों का अध्ययन करने से प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है । महाराष्ट्र सरकार ने इस गांव को अपने अधीन लिया है और इसके पुरातात्विक स्थल के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं । इन योजनाओं में पुरातात्विक स्थल का संरक्षण, संग्रहालय का निर्माण, और पुरातात्विक महत्व के स्थलों का विकास शामिल है ।

चूंकि यह गांव पुरातात्विक महत्व का है, इसलिए सरकार ने इसे संरक्षित करने और इसके पुरातात्विक महत्व को बढ़ावा देने के लिए अपने अधीन लिया है और साथ ही इस गांव को पुरातात्विक स्थल भी घोषित किया है तथा इसके लिए एक विशेष समिति का भी गठन किया है, जिसका कार्य इस गांव के पुरातात्विक महत्व को संरक्षित करना और इसके विकास के लिए योजनाएं बनाना है ।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह डोमेगांव की महत्ता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय स्तर से भी इस पुरातात्विक स्थल के संरक्षण और विकास के लिए केन्द्रीय आवंटन सुनिश्चित करें ।

संसद सदस्यों (एमपी) और विधानसभा सदस्यों (एमएलए) को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत मिलने वाली धनराशि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है । वर्तमान में, सांसद और कुछ राज्यों में विधायकों को 5 करोड़ रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं । लेकिन सवाल यह है कि क्या यह धनराशि संसद सदस्यों के लिए पर्याप्त है ?

संसद सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारियां विधानसभा सदस्यों से अधिक व्यापक हैं । वे न केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, बल्कि वे देश की नीतियों और कानूनों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा विधायक के क्षेत्र की अपेक्षा लोक सभा क्षेत्र कई गुना बड़ा होता है । इसलिए, उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए, उन्हें एक विधायक से अधिक धनराशि मिलनी चाहिए ।

इसके अलावा, संसद सदस्यों को अपने क्षेत्र में विकास संबंधी परियोजनाओं को लागू करने के लिए अधिक धनराशि की आवश्यकता होती है । वे अपने क्षेत्र में सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए धनराशि का आवंटन करते हैं । इसलिए, यदि उन्हें सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत विधायक की अपेक्षा अधिक धनराशि मिलती है, तो वे अपने क्षेत्र में अधिक विकास परियोजनाओं को लागू कर सकते हैं ।

अतः मेरा अनुरोध है कि वह सांसदों को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत जारी की जाने वाली राशि को 5 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ प्रति वर्ष किए जाने और जिस प्रकार से सांसदों को "वेतन" शीर्षक के अन्तर्गत आयकर में छूट दी हुई है, उसी प्रकार से उक्त विकास निधि में भी जी०एस०टी० में छूट प्रदान करें, ताकि जी०एस०टी० राशि की छूट को क्षेत्रों में विकास कार्यों में समायोजित किया जा सके ।

महाराष्ट्र राज्य के शिरडी संसदीय क्षेत्र में जल संकट एक गंभीर और बड़ी समस्या है । इस क्षेत्र में पानी की कमी के कारण लोगों को पीने के पानी के लिए भी संघर्ष करता पड़ता है । इसके साथ ही क्षेत्र में कृषि, जो एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, पानी की कमी के कारण किसानों को अपनी फसलों को उगाने में भी कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है ।

नीति आयोग ने पिछले साल पानी पर जारी रिपोर्ट में कहा था कि देश में करीब 60 करोड़ लोग पानी की गंभीर किल्लत का सामना कर रहे हैं । 2030 तक देश में पानी की मांग उपलब्ध जल वितरण की दोगुनी हो जाएगी और देश की जीडीपी में छह प्रतिशत की कमी देखी जाएगी । देश में करीब 60 करोड़ लोग पानी की गंभीर किल्लत का सामना कर रहे हैं । करीब 2 लाख लोग स्वच्छ पानी न मिलने के चलते हर साल जान गंवा देते हैं ।

शिरडी के साथ-साथ हर वर्ष देश के कई क्षेत्रों को भी गंभीर रूप से सूखे का सामना करना पड़ता है । देश की कुछ नदियों में आवश्यकता से अधिक पानी रहता है तथा अधिकांश नदियाँ ऐसी हैं जो बरसात के मौसम के अलावा वर्षभर सूखी रहती हैं या उनमें पानी की मात्रा बेहद कम रहती है ।

देश में औसतन हर साल 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर के करीब बारिश होती है। लेकिन, इसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं होता है और यह पानी नदियों के माध्यम से समुद्र में बह जाता है, जिससे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी की समस्या और अधिक विकराल रूप ले लती है। इस समस्या के समाधान के लिए नदी जोड़ो योजना एक महत्वपूर्ण कदम है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि नदी जोड़ो योजना के तहत, वर्षा का पानी नदी के माध्यम से समुद्र में बहने के बजाय, उसे अन्य नदियों और जलाशयों में स्थानांतरित करके शिरडी संसदीय क्षेत्र में पानी की समस्या के समाधान हेतु एक कार्य योजना बनाकर उसे शीघ्र कियान्वित किया जाए।

महाराष्ट्र राज्य के शिरडी संसदीय क्षेत्र में शनि शिंगणापुर एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यह लोकप्रिय मंदिर शनि ग्रह से जुड़े लोकप्रिय हिंदू देवता भगवान शनिदेव को समर्पित है। मंदिर पूरे भारत के स्थानीय लोगों और भक्तों के बीच बेहद प्रसिद्ध है। शिंगणापुर इसके लिए भी मशहूर है कि गांव के किसी भी घर में दरवाजे नहीं हैं, सिर्फ चौखटें हैं। इसके बावजूद, आधिकारिक तौर पर गांव में कोई चोरी की घटना नहीं हुई है।

आम तौर पर, इस मंदिर में एक दिन में 30,000-45,000 आगंतुक आते हैं, जो अमावस्या पर लगभग तीन लाख लोगों तक पहुँच जाते हैं, जिसे शनि को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन एक बड़े उत्सव का भी आयोजन किया जाता है।

शनि मंदिर में एक खुले मंच पर स्थापित साढ़े पांच फुट ऊंची काली चट्टान है, जो शनि देवता का प्रतीक है। प्रतिमा के एक तरफ त्रिशूल (त्रिशूल) रखा गया है और दक्षिण की ओर नंदी (बैल) की प्रतिमा है। सामने शिव और हनुमान की छोटी प्रतिमाएँ हैं। भक्त भगवान शनि की छवि को पानी और तेल से नहलाते हैं और उन्हें फूल और उदीद चढ़ाते हैं।

यहां पर भगवान शनि का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो भगवान शनि को समर्पित है। यहां का इतिहास बहुत पुराना है और यह स्थल सदियों से तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल रहा है। यहां पर भगवान शनि की पूजा की जाती है और यहां पर आने वाले तीर्थयात्रियों को भगवान शनि की कृपा प्राप्त होती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि शिरडी संसदीय क्षेत्र में स्थित शनि शिंगणापुर की धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटनीय विशेषता को ध्यान में रखते हुए इसके विकास हेतु केन्द्रीय आवंटन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

महाराष्ट्र राज्य के शिरडी संसदीय क्षेत्र में प्रवर नदी के तट पर स्थित भंडारदरा सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में बसा एक हिल स्टेशन है। एक किंवदंती के अनुसार, ऋषि अगस्त्य ने यहां एक वर्ष तक तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें गंगा नदी की एक धारा प्रदान की, जिसे अब प्रवर नदी के रूप में जाना जाता है। भंडारदरा ट्रैकिंग ट्रेल्स से घिरा हुआ है और किलों से भरा हुआ है।

आर्थर झील और विल्सन बांध, अम्ब्रेला फॉल्स और रंधा फॉल्स यहाँ के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण केन्द्र हैं। इनमें विल्सन बांध एक बहुत ही लोकप्रिय है, जो देश के सबसे पुराने बांधों में से एक है। मानसून के दौरान इस बांध से दो झरने भी गिरते हैं। मानसून के मौसम में पूरा हिल स्टेशन हरा-भरा हो जाता है और पहाड़ियों से कई झरने फूट पड़ते हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के अलावा, भंडारदरा में ऐतिहासिक जगहें भी हैं, जिनमें रतनगढ़ किला, अमृतेश्वर मंदिर और कलसुबाई मंदिर इस पहाड़ी शहर के प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि शिरडी संसदीय क्षेत्र में स्थित भंडारदरा की पर्यटन विशेषता को ध्यान में रखते हुए इसके पर्यटनीय विकास हेतु केन्द्रीय आवंटन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

महाराष्ट्र राज्य के शिरडी संसदीय क्षेत्र की श्रीरामपुर तालुका में डोमेगांव-कमलापुर एक पवित्र और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, जो सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है।

यहां पर गुरुद्वारा श्री बिरध बाबा का निर्माण 25 मई 1968 को नांदेड़ के एक संत के हाथों शुरू हुआ था। करीब 150 साल पहले पंजाब के एक सिख संत, जिनके पास गुरु ग्रंथ साहिब की हस्तलिखित प्रति थी, ने इस स्थान पर एक फूस की झोपड़ी में इसकी स्थापना की थी, जिसे अब गुरुद्वारे में बदल दिया गया है। यह गांव गोदावरी के तट पर बसा है, जो बिरध बाबा के समय से अक्सर बाढ़ की चपेट में आ जाती थी। गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा की गई और सिर पर गोदावरी ले जाकर बाढ़ कम होने के लिए गंगा माई (गोदावरी) से प्रार्थना की गई।

स्थानीय लोगों को गुरु ग्रंथ साहिब और बिरध बाबा पर पूरी आस्था है और उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि प्रार्थना से बाढ़ कम हो जाती है और गांव को नुकसान से बचाया जाता है। यह परंपरा आज भी जारी है। इस साल जब 6 अगस्त 1968 को बाढ़ आई, तो गांव के लोगों ने यही बात दोहराई और बाढ़ के पानी से गांव को कोई नुकसान नहीं हुआ। यहां पर गुरुद्वारा के साथ-साथ चक्रधर मंदिर, हनुमान मंदिर, गणपति मंदिर, और एक मस्जिद भी एक ही परिसर के आसपास आस-पास हैं।

यहां पर हर साल गुरु नानक के जन्मदिन यानी कार्तिक पूर्णिमा पर अखंड पाठ (गुरु ग्रंथ साहिब का निरंतर पाठ) किया जाता है। इस क्षेत्र के ग्रामीण होली और दिवाली जैसे अवसरों पर गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर रखकर गांव के लोगों के साथ जुलूस निकालते हैं। हर साल जनवरी के पहले सप्ताह में एक विशेष समागम का भी आयोजन किया जाता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि डोमेगांव-कमलापुर तीर्थ स्थल के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटनीय विकास हेतु केन्द्रीय आवंटन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

महाराष्ट्र राज्य के शिरडी संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत कोपरगांव में गोदावरी रिवर टनल एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण संरचना है, जो ब्रिटिश काल में बनाई गई थी। यह टनल गोदावरी नदी के नीचे से गुजरती है और कोपरगांव को आसपास के क्षेत्रों से जोड़ती है। लेकिन अब यह टनल जीर्णोद्धार की आवश्यकता है।

गोदावरी रिवर टनल का निर्माण 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। यह टनल उस समय एक महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग थी, जो कोपरगांव को आसपास के क्षेत्रों से जोड़ती थी। लेकिन अब यह टनल जीर्णोद्धार की आवश्यकता है।

टनल की जीर्णोद्धारता के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। टनल की दीवारें और छत दरक रही हैं, जिससे यह खतरनाक हो गई है। इसके अलावा, टनल में पानी भरने की समस्या भी है, जिससे यह और भी खतरनाक हो जाती है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह टनल के जीर्णोद्धार के लिए एक व्यापक योजना बनाकर उसे शीघ्र क्रियान्वित करें।

महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में नेवासा एक पवित्र स्थल है, जो मराठी साहित्य और संस्कृति के महान संत ज्ञानेश्वर की जन्मभूमि है। यह गांव महाराष्ट्र के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र है।

नेवासा गांव में संत ज्ञानेश्वर का जन्म 1275 ईस्वी में हुआ था। वह एक महान संत, कवि और दार्शनिक थे, जिन्होंने मराठी भाषा में भक्ति साहित्य की रचना की। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति 'ज्ञानेश्वरी' है, जो भगवान श्रीकृष्ण के जीवन और उपदेशों पर आधारित है, जो उनके अनुयायियों के लिए एक धार्मिक कृति है। यहां पर ज्ञानेश्वर की मूर्ति स्थापित है, जिसकी पूजा अर्चना की जाती है। गांव में कई अन्य मंदिर और स्मारक भी हैं, जो ज्ञानेश्वर के जीवन और कार्यों से जुड़े हैं।

नेवासा गांव का महत्व सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक नहीं है, बल्कि यहां की प्राकृतिक सुंदरता भी आकर्षक है। गांव के आसपास के क्षेत्र में देवगढ़, शनि शिंगनापुर, महाल्सा खंडोबा मंदिर, मोहिनी मंदिर अनेक महत्वपूर्ण स्थल हैं तथा इनके अलावा वन और नदियां भी हैं, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हैं।

राज्य सरकार ने नेवासा गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। यहां पर संग्रहालय, पुस्तकालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो ज्ञानेश्वर के जीवन और कार्यों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि नेवासा तीर्थ स्थल के सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटनीय विकास हेतु केन्द्रीय आवंटन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

मैं सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि महाराष्ट्र राज्य के शिरडी संसदीय क्षेत्र में टाइगर अटैक के कारण लोगों में भय का माहौल है। इस क्षेत्र में टाइगर के हमलों की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। इससे स्थानीय लोगों में डर और चिंता का माहौल है। क्षेत्र में कई बच्चों को टाइगर खा चुके हैं और कई औरतों एवं आदिमियों को भी मार चुके हैं।

टाइगर के हमले की वजह से क्षेत्र की विशेषतः संगमनेर, राहाता, श्रीरामपुर, अकोला तालुका के किसान रात्रि में अपने खेतीबाड़ी भी नहीं कर पा रहे हैं। टाइगर अटैक के कारण लोगों को अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतित है और वे दिन में भी टाइगर की गतिविधियों को लेकर सावधान रहते हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह शिरडी संसदीय क्षेत्र में टाइगर अटैक की समस्या का समाधान करने के लिए और स्थानीय जनता को टाइगर अटैक से राहत दिलाने के लिए व्यापक जनहित में उनको वहां से पकड़कर राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य अथवा अन्य कहीं भी टाइगर संरक्षित क्षेत्र में भिजवाए जाने हेतु कार्यवाही करें ।

किसान फसल बीमा योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को फसल की खराबी से होने वाले नुकसान की भरपाई करना है । लेकिन इस योजना का पूरा लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है और बीमा कंपनियों का इस योजना में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बनी हुई है ।

किसान फसल बीमा योजना के तहत किसान अपनी फसल का बीमा करवाते हैं और अगर फसल खराब होती है तो बीमा कंपनी उन्हें मुआवजा देती है । लेकिन अधिकतर मामलों में किसानों को यह मुआवजा नहीं मिल पाता है क्योंकि बीमा कंपनियां अपने हितों को ध्यान में रखती हैं और किसानों के दावों को खारिज कर देती हैं ।

इसके अलावा, बीमा कंपनियों का इस योजना में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है । कई बार बीमा कंपनियां किसानों से अधिक प्रीमियम वसूलती हैं और फिर भी उन्हें मुआवजा नहीं देती हैं । इससे किसानों को आर्थिक नुकसान होता है और वे अपनी फसल की देखभाल करने में असमर्थ होते हैं ।

मेरा अनुरोध है कि किसान फसल बीमा योजना का पूरा लाभ किसानों को मिले, इसके लिए सख्त कदम उठाकर बीमा कंपनियों की गतिविधियों पर केन्द्रीय स्तर पर निगरानी रखकर उनके भ्रष्टाचार की जांच करवाई जाये और साथ ही किसान फसल बीमा योजना की शर्तों को और अधिक सरल बनाए, ताकि किसान आसानी से अपना दावा सरलता से कर सकें ।

विगत कुछ वर्षों से दूध का कारोबार किसानों के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो रहा है । इसका प्रमुख कारण यह है कि दूध की कीमत कम और उत्पाद शुल्क में निरंतर वृद्धि हो रही है । आज एक लीटर दूध के उत्पादन में 27 रुपये का खर्च आता है तथा वहीं दुग्ध उत्पादक किसान को एक लीटर दूध की कीमत मात्र 18 से 22 रुपये मिलती है तथा शुरुआती दिनों में जहां गाय अच्छी मात्रा में दूध देती है, वहीं कुछ महीनों बाद दूध कम हो जाता है और 6 या 7 वर्ष बाद गाय पूरी तरह से दूध देना बंद कर देती है ।

ऐसी स्थिति में गो-हत्या पर प्रतिबंध होने की वजह से किसान बांझ गाय को बेच नहीं पाते हैं और साथ ही उसकी देखभाल भी नहीं कर पाते हैं, जिस कारण उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है ।

यही स्थिति प्याज उत्पादकों की भी है । प्याज की खेती की लागत बहुत अधिक है, लेकिन किसानों को इसका सही दाम नहीं मिलता है, जिससे उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है । सरकार द्वारा प्याज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य न तय किए जाने की वजह से भी उनको उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है ।

केन्द्र सरकार किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाए जाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस निमित्त किसानों को गन्ना एवं अन्य फसलों की वाजिब कीमत भी दिलाया जाना सुनिश्चित किया हुआ है। यदि दुग्ध और प्याज उत्पादकों को उनका वाजिब मूल्य नहीं मिलता है तो यह उनके साथ अन्याय होगा।

अतः ऐसी स्थिति में मेरा सरकार से अनुरोध है कि जिस प्रकार से गन्ने एवं अन्य फसलों के लिए गारंटी कीमत किसानों को मुहैया करायी जाती है, उसी प्रकार से दुग्ध और प्याज उत्पादक किसानों को भी गारंटीकृत कीमत दिए जाने हेतु समुचित कदम उठाए जाएं।

मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र शिरडी में संचालित नीलवंडे प्रोजेक्ट की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यह अपर प्रवरा सिंचाई प्रोजेक्ट मेरे क्षेत्र की अकोला तालुका में चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से क्षेत्र की लगभग 64 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी और क्षेत्र में अकाल और पानी की अभाव में किसानों को खेती करने में जो असुविधा होती है, उससे उन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस प्रोजेक्ट का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। केवल केनाल के बचे हुए कुछ कार्यों को पूरा कराए जाने के लिए केन्द्रीय धन के आवंटन की जरूरत है, ताकि प्रोजेक्ट का कार्य शीघ्र पूरा होकर क्षेत्रीय किसानों को इसका लाभ सुनिश्चित हो सके।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मेरे क्षेत्र में संचालित नीलवंडे प्रोजेक्ट के बचे हुए कार्यों को अविलम्ब पूरा कराए जाने हेतु केन्द्रीय धन का आवंटन करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं और क्षेत्र की जनता आभारी होगी।

कीटनाशक कम्पनियों द्वारा केन्द्र सरकार एवं सेट्रल इंसेंटिसाइड बोर्ड से अनुमति के बाद ही किसी भी कीटनाशक का उत्पादन किया जाता है और कीटनाशक अधिनियम के अनुसार उसे पूरे देश में व्यापार करने की अनुमति मिलती है। कंपनी की के मूल पैकिंग का नमूना जब किसी विक्रेता के यहां से लिया जाता है तो उसका सैंपल फेल होने पर सर्वप्रथम लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा संबंधित कंपनी की बजाए विक्रेता का लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए जाने हेतु नोटिस दिया जाता है। जबकि दोष उस निर्माता कंपनी का होता है।

दूसरे, देश में खाद एवं कीटनाशक के अधिनियम में कंप्यूटर के स्टॉक रजिस्टर को मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन बीज अधिनियम में इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। अतः बीज अधिनियम में कंप्यूटराइज्ड स्टॉक रजिस्टर को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु संशोधन किया जाना चाहिए और साथ ही बीज की गुणवत्ता के लिए संपूर्ण जवाबदेही बीज उत्पादक कंपनी एवं निर्माताओं की होनी चाहिए न कि छोटे डीलर या निजी विक्रेता की।

मेरा अनुरोध है कि सरकार इस संबंध में समुचित कार्यवाही करें।

मैं सरकार का ध्यान गुजरात राज्य के जूनागढ़ में स्थित जैन महातीर्थ गिरनार की ओर आकर्षित करना चाहूंगा । इस जैन महातीर्थ के संबंध में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2024 में आदेश पारित किए जाने के बावजूद भी जैन श्रावकों को पूजा अर्चना न करने देकर देश के अल्पसंख्यक जैन समाज के मौलिक अधिकारों का घोर हनन और माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना तथा संविधान को दरकिनार कर लोकतंत्र की हत्या किए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए शोभा नहीं देता है ।

अतः मेरा अनुरोध है कि वह जूनागढ़ के जैन महातीर्थ गिरनार के संबंध में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अमल में लाए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए ।

ईपीएस-95 योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारी अपनी मांगों के समर्थन में विगत एक दशक से ज्यादा समय से देशभर में संघर्ष कर आमरण अनशन कर रहे हैं । लेकिन, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि केन्द्र सरकार उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं कर रही है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिजनों का गुजर बसर करना कठिन हो रहा है ।

कर्मचारी पेंशन योजना 16 नवंबर 1995 को लागू हुई. यह योजना कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है, जिन पर 1952 विविध प्रावधान अधिनियम और कर्मचारी भविष्य निधि लागू होते हैं. ये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा शुरू की गई एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजना है. कर्मचारी पेंशन योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद लाभ पहुंचाना है. मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह ईपीएस-95 की कमियों को दूर करते हुए कर्मचारियों के हित में सकारात्मक कार्यवाही करें, ताकि उन्हें इसका पूरा लाभ मिल सके ।

देश में केन्द्र व राज्य सरकारों की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं । लेकिन, मुझे बड़े ही दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन योजनाओं का समुचित लाभ दबे-कुचले वर्ग को पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है । इसका एक प्रमुख कारण यह है कि केन्द्र व राज्य सरकारों की योजनाओं की नियमावली की पूरी जानकारी निचले स्तर पर न पहुंचने की वजह से लाभार्थी इन योजनाओं से अनभिज्ञ रहता है ।

आज स्थिति यह है कि गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि बनवाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है । ये लोग सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटकर न केवल अपनी रोजी-रोटी कमाने का समय बरबाद करते हैं, बल्कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी उनको सही जानकारी न देकर गुमराह करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ये लोग आज भी सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं । मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सरकारी योजनाओं के संचालन और इनका पूरा लाभ दलित व गरीब परिवार के सभी पात्र लोगों को मिल सके, इसके लिए एक ऐसी नियमावली बनाए, जिससे उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े तथा सरकार इसके संचालन की पूरी जिम्मेवारी सरकारी अधिकारियों के प्रति सुनिश्चित करें । अंत में, मैं अपनी और अपनी पार्टी की ओर से वित्त मंत्री महोदया द्वारा लोक सभा में प्रस्तुत वर्ष 2025-26 के बजट का पूरजोर विरोध करते हुए अनुरोध

करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित उक्त विषयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए धन का आवंटन सुनिश्चित किया जाए।
धन्यवाद।

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : मैं बजट वर्ष 2025-26 पर अपने विचार रखता हूँ।

देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 12वां बजट इस देश ने देखा है, प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बजट में देश के किसानों, मजदूरों, युवाओं, आधारभूत अवसरचरणाओं, आर्थिक सुधारों को शामिल किया गया है।

यह कहा जाता है कि मोदी हैं तो मुमकिन हैं, यह बात विगत 11 वर्षों से देश ने देखा है तथा परखा है। संकल्प से सिद्धि को साकार किया है।

मोदी जी के बजट के करीश्मा हैं कि दिल्ली में दिल्लीवालों ने आपदा को खाना किया है, लूट से दिल्ली को मुक्ति मिली है।

देश की वित्तमंत्री महोदया आदरणीया श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस बार भी बेहतर देश का बजट प्रस्तुत किया है।

इस बार के बजट में कुछ बातें जो कि इस बजट की प्रमुख विशेषताएं हैं : 1 लाख रुपए तक प्रति माह की औसत आय पर कोई आय कर नहीं; इससे मध्यमवर्ग परिवारों की आय व खपत में वृद्धि होगी।

वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 12.75 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना होगा।

केन्द्रीय बजट में विकास के चार इंजनों की पहचान की गई है- कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात।

प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना से 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, इनमें 100 निम्न उत्पादन वाले जिलों को शामिल किया जाएगा।

अरहर, उड़द व मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए "दालों में आत्मनिर्भरता मिशन" शुरू किया जाएगा।

संशोधित ब्याज योजना के तहत केसीसी के माध्यम से पांच लाख तक का लोन दिया जायेगा।

एमएसएमई को गारंटी के साथ दिए जाने वाले ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया।

मेक इन इंडिया को निरंतरता देने के लिए लघु, मध्यम व वृहद उद्योग को शामिल कर राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन का शुभारंभ किया गया।

अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जायेगी।

500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किये जायेंगे

बैंको से ऋण में वृद्धि सहित पीएम स्वनिधि, 30 हजार रुपए की सीमा के साथ यूपीआई लिंकड क्रेडिट कार्ड ।

गिग वर्कर्स को पहचान पत्र दिया जाएगा, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत ई-श्रम पोर्टल और स्वास्थ्य देखभाल में पंजीकरण ।

विकास केन्द्र के रूप में शहरों को एक लाख करोड़ रुपए का शहरी चुनौती निधि ।

20 हजार करोड़ रुपए परिव्यय के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के आरएंडडी के लिए अणु ऊर्जा मिशन ।

संशोधित उड़ान योजना से 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा ।

एक लाख आवासीय ईकाइयों को शीघ्र पूरा करने के लिए 15 हजार करोड़ स्वामिह निधि ।

निजी क्षेत्र द्वारा संचालित शोध विकास व नवाचार पहलों के लिए 20 हजार करोड़ आवंटित ।

पांडुलिपियों के सर्वेक्षण व संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन ।

बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74 से बढ़ाकर 100 प्रतिशत किया गया ।

विभिन्न कानूनों में 100 से ज्यादा प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण रूप देते हुए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाया जाएगा ।

संशोधित आयकर रिटर्न की समयसीमा दो से बढ़ाकर चार साल किया गया ।

टीसीएस भुगतान में देरी अब अपराध नहीं होगा ।

किराया पर टीडीएस 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए किया गया ।

कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों के उपचार के लिए 36 जीवनरक्षक औषधियों को बुनियादी सीमा शुल्क (बी.सी.डी.) से छूट प्रदान की गयी हैं ।

आईएफपीडी पर बीसीडी को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया, ओपन सेल्स पर बीसीडी में 5 प्रतिशत की कमी की गयी हैं ।

घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ ओपन सेल्स पर बीसीडी में छूट ।

बैट्री उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विद्युतीय वाहन और मोबाइल बैट्री उत्पादन के लिए अतिरिक्त पूंजीगत वस्तु में छूट ।

जहाज निर्माण में प्रयोग होने वाले कच्चा सामग्री और घटकों पर 10 साल के लिए बीसीडी में छूट ।

फ्रोजन फिश पेस्ट पर बीसीडी को 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया और फिश हाइड्रोलिसेट पर 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया ।

क) गरीबी से मुक्ति;

ख) शत प्रतिशत अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा;

ग) बेहतरीन, सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच;

घ) शत-प्रतिशत कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार;

ङ) आर्थिक गतिविधियों में सत्तर प्रतिशत महिलाएं; और

च) हमारे देश को 'फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड' बनाने वाले किसान

इस बजट में प्रस्तावित विकास, उपाय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर किया गया है।

SHRI VAMSI KRISHNA GADDAM (PEDDAPALLE): The Prime Minister promised 2 crore jobs per year, but where are they or it just another *jumla*? Unemployment has risen to nearly 10 per cent, meaning 15-20 crore Indians are jobless today. The manufacturing sector which has the potential to generate millions of jobs, has been ignored. This budget lacks a concrete job creation roadmap. Instead, the Government is spending more time on PR campaigns like "Yuva Yuva" rather than addressing real job concerns.

Startups are struggling due to inconsistent policies, while multinational corporations are being given incentives without employment guarantees. The youth of this country deserve better and not only *jumla* of PM Modi.

Telangana has been completely sidelined in this budget. We demand a Rs. 10,000 crore AI & Startup Incubation Hub in Peddapalli to create high-value jobs. The manufacturing and PLI schemes must be directly tied to employment, not just corporate profits. The youth of India deserve real jobs, not empty slogans. Telangana, which contributes significantly to the nation's economy, is being deliberately ignored in infrastructure and industrial allocations.

This Budget is not about "Make in India" it is about "Make for Adani." The Adani Linked Incentives (ALI) scheme has been strategically designed to benefit one group of businesses while ignoring real entrepreneurs and small industries. The Finance Minister talked about Artificial Intelligence, but I think AI is Adani's India and everything surrenders to Double AA (Adani Ambani). The Government is funnelling tax money into corporate giants while providing zero direct incentives to MSMEs and job-creating

industries. While Adani-linked industries receive preferential treatment, tax waivers, and exclusive contracts, real businesses struggle with GST burdens, lack of credit, and bureaucratic roadblocks.

Manufacturing growth has limped along at a mere 5.8 per cent annually, well below the promised 12 to 14 per cent. The share of manufacturing in India's GDP has remained stagnant at 15.8 per cent, falling far short of the Union Government's 25 per cent target set for 2022.

We demand a transparent audit of ALI schemes, equal opportunity for all industries, and increased funding for MSMEs and employment-linked industrial incentives. The Government's favouritism towards select corporate houses at the cost of national interest must be called out and corrected.

Infrastructure development has been skewed in favour of select regions, leaving Telangana ignored. No new railway corridors have been announced for Telangana. There is no mention of the State in the National Infrastructure Pipeline, and Telangana's debt has not been restructured while other States receive financial relief. If Telangana contributes Rs. 1 in tax, it gets back only Rs.0.43, while States like Bihar get Rs. 7.06 and UP gets Rs. 2.73. This is economic discrimination with Telangana and in India other than Bihar and Andhra Pradesh there are other States too and the Government has to look into them and not only Bihar and Andhra Pradesh.

We demand Rs. 15,000 crore for new infrastructure projects, approval of new airports in Warangal and Nizamabad and the expansion of railway lines in Peddapalli and Mancheri for industrial growth. The Government must stop treating Telangana as an afterthought and start recognizing its rightful contributions to the nation.

Let's examine sector-wise allocations:

Education: The Post Matric Scholarship for SCs, a crucial scheme for Dalit students, received Rs. 6,360 crore this year. Compare this with Rs. 1.72 lakh crore for higher education, overall SCs/STs students are left with mere breadcrumbs.

The Stand-Up India scheme, meant to support SC/ST entrepreneurs, has not even spent 20 per cent of its budgetary allocation since its launch. Only 0.5% of bank credit in India goes to Dalit entrepreneurs. Hon. Speaker, Sir, how can Dalits be "Atmanirbhar" when this Government does not provide them with capital, resources or equal opportunities?

Even today, every 15 minutes, a crime is committed against a Dalit in India. Article 17 of the Constitution abolishes untouchability, yet Dalits are forced into manual scavenging. The SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989, demands strict action against crimes against Dalits, yet only Rs. 600 crore was allocated for its implementation, less than what were spent on the Parliament's renovation. Is this "Sabka Vikas" or "Sabka Vinash" for Dalits?

20 per cent Budget share for Dalits and Adivasis. Hon. Speaker, Sir, we do not seek charity. We demand what is rightfully ours. The Dalit community is 16.6 per cent of the population; the ST community is 8.6 per cent. Together, we make up 25.2 per cent of India's population. Then why do we receive less than 6 per cent of the budget? Our demands are simple, constitutional, and just. At least 20 per cent of the total budget must be allocated to SC/ST welfare, proportional to their population. A legally protected Dalit Development Fund must be established to prevent the diversion of SC/ST funds to general schemes. Rs. 50,000 crore must be allocated to Dalit students' education to ensure no SC/ST student drops out due to financial reasons. Banks must be mandated to provide at least 10 per cent of total credit to Dalit entrepreneurs. Land redistribution schemes must be revived to provide agricultural and residential land to SC/ST families. An independent committee must audit SC/ST welfare funds annually to ensure transparency and accountability. An independent Committee must audit SC/ST welfare funds annually to ensure transparency and accountability.

If this Government truly believes in "Sabka Saath, Sabka Vikas," let them prove it in numbers, not just in slogans because slogans do not educate Dalit children. Slogans do not create Dalit jobs. Slogans do not erase the bloodstains of caste-based violence. If this government fails to act, history will not forgive them and neither will we.

This budget is a masterclass in economic injustice. Jobs remain unfulfilled. industries are struggling, inflation is rising, and Telangana and other progressive States are being sidelined. We demand equitable tax distribution, investment in AI, green energy, employment-driven industries, and national infrastructure plans that include Telangana's rightful share. The Adani-linked incentives must be stopped, and a fair industrial policy must be implemented. If the government truly believes in "Sabka Saath, Sabka Vikas," let it prove it through actions, not mere words.

I will end with few words,

"Neeti, kuneeti dekh chup rehna,

chintuon ki majboori hai.

Duryodhan se jo poochhe sawaal,

har sangh mein Vidur zaroori hai.?

Jai Bhim! Jai Bharat!

SHRI RAHUL KASWAN (CHURU): What truly defines a nation's progress? Is it in grand speeches and ambitious promises, or is it seen in the everyday lives of our people? We are not here just to acknowledge achievements; we are here to ask the real question: Are these promises making meaningful difference?

The President's Address lays out a bold vision; economic growth, better infrastructure, and social welfare. But a vision means little without real execution. While the Government highlights milestones, we must ask: Are these policies truly improving life for the common man? Are our farmers, workers, small business owners, and young graduates actually seeing positive change?

Today, I wish to dissect some of these claims and examine their actual impact on the ground.

Neglect of Rajasthan's Agricultural Crisis -- Agriculture is the backbone of our nation, yet our farmers continue to struggle against adversity. As a representative of Rajasthan, particularly the drought-prone Churu constituency, I must highlight the deepening crisis in the agricultural sector.

The Government touts schemes like PM-Kisan Samman Nidhi, which has provided Rs. 41,000 crore to crores of farmers. However, these direct cash transfers are not a substitute for sustainable agricultural policies. There is a little mention of effective water management solutions for drought-prone regions like ours. Groundwater levels are depleting, monsoons remain erratic, and farmers are left without sufficient irrigation support.

Instead of long-term resilience planning, we see stopgap measures that fail to secure the future of our agrarian economy. We must prioritise:

- Investment in drought-resistant crop research and scientific irrigation techniques.

- Increased subsidies for water conservation projects and sustainable farming.
- Expansion of community-led water management programmes.

If we truly wish to transition from 'Make in India' to 'Make for the World', we must first ensure our farmers can survive and thrive. Without urgent reforms the agricultural backbone of India, will continue to weaken.

Inadequate Healthcare Infrastructure -- The Government boasts of establishing 1.75 lakh Arogya Mandirs and extending the Ayushman Bharat scheme to senior citizens. Yet, a closer look reveals significant gaps in healthcare delivery, especially in rural areas. A 2021 NITI Aayog study highlighted severe inadequacies in health and wellness centres across 18 States, citing lack of trained personnel and essential medical supplies. What good is an Ayushman Bharat card if hospitals lack doctors, medicines, or even basic diagnostic tools?

Consider this: The Government claims over 30 crore e-teleconsultations have been provided. But how can telemedicine be effective when rural areas suffer from poor internet connectivity and lack of digital literacy? Health must not be a privilege of the urban elite; it must be a fundamental right accessible to all.

To truly improve healthcare, we must:

- Enhance funding for rural hospitals and ensure full staffing in health centres.
- Expand preventive healthcare programs, including maternal health and nutritional initiatives.
- Address bureaucratic inefficiencies that prevent eligible citizens from accessing their healthcare benefits.

Lack of Focus on Education and Employment -- Education is the foundation of our future, yet foundational gaps persist. The National Education Policy (NEP) 2020 emphasises expansion, but does it address the ground reality?

- Many rural schools still lack basic infrastructure, classrooms, sanitation, and drinking water.
- Recruitment exams have expanded to 13 Indian languages, but exam paper leaks continue to erode trust in the system.

- The Government promises 1 crore internships, but what about those who graduate with degrees yet remain jobless?

We need:

- Greater investment in digital education and teacher training.
- Strengthening of vocational training programs to equip youth with employable skills.
- Expansion of scholarships and student aid beyond financial assistance to include mentorship and career guidance.

Rural Infrastructure: A Persistent Urban Bias -- While we applaud metro expansions and Vande Bharat trains, we cannot ignore the fact that thousands of villages still lack basic road connectivity. Without proper transportation, farmers cannot sell their produce, children cannot attend school, and patients cannot reach hospitals in emergencies. The Government has allocated significant funds for rural development, including:

- Rs. 86,000 crore for MGNREGA, which provides rural employment.
- Rs. 19,000 crore for Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, improving rural connectivity.
- Rs. 19,005 crore for Deendayal Antyodaya Yojana ? National Rural Livelihood Mission to promote self-employment.
- Rs. 54,832 crore for Pradhan Mantri Awas Yojana ? Grameen, supporting rural housing.
- Rs. 67,000 crore for Jal Jeevan Mission, ensuring access to clean drinking water.
- Rs. 7,192 crore for Swachh Bharat Mission - Gramin, promoting sanitation.
- Rs. 2,505 crore for Watershed Development Component Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, for irrigation.
- Rs. 1,064 crore for Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan, strengthening rural governance.

These numbers look impressive on paper, but we must ask a fundamental

question:

- Are these funds being efficiently utilised, or are they getting stuck in bureaucratic bottlenecks?

- Is MGNREGA meeting the rising demand for rural employment? In December 2024, work demand under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) was 8.3% higher than the same period in 2023, reflecting the growing reliance on the scheme. The Government has allocated ₹86,000 crore for MGNREGA in FY25. Rural Development Minister Shivraj Singh Chouhan has stated that the scheme is demand-driven, and additional funds will be requested if needed. However, the key concern remains: Will this allocation be sufficient to meet the increasing demand and ensure timely wage payments to rural workers? Are road and housing projects progressing at the right pace, or do we see delays and cost overruns?
- Is Jal Jeevan Mission actually delivering clean water to every household?
Numbers alone do not ensure rural transformation; accountability and implementation matter.
- About 1 in 5 (18%) of the poorest rural households still do not have access to electricity. Rural electrification must move beyond promises to full-scale implementation.
- Road development must ensure last-mile connectivity for all regions, not just major urban centres.

The Rising Burden of Inflation on the Middle Class -- The Government highlights an 80 per cent discount on medicines through Jan Aushadhi Kendras and the Mudra loan limit increase from Rs. 10 lakh to Rs. 20 lakh. While these measures are commendable, they do not address the larger economic reality:

- Rising fuel and food prices are squeezing household budgets.
- The middle class and small businesses are struggling under mounting economic pressures.

Inflation is eating into the purchasing power of the common citizen. The Government must:

- Take decisive steps to control inflation and stabilise essential commodity prices.
- Provide direct consumer relief through tax reforms and targeted subsidies

No Relief for the Common Citizen: No GST Cuts, No Major Welfare Measures -- At a time when inflation is squeezing household budgets, this Budget should have provided relief. But instead:

- There is no reduction in GST on essential commodities like food, fuel, and medicines.

- There are no new welfare schemes to support the poor and middle-class.
- The Budget allocation for the Department of Food and Public Distribution is lower than last year, which affects food security programmes.

The common citizen is left burdened by high prices, stagnant wages, and economic uncertainty. The Government must recognise that real growth happens when every Indian feels financially secured.

The Digital Divide and Cybersecurity Concerns -- While the Government celebrates the India AI Mission and UPI's success, millions remain excluded from these advancements due to lack of reliable internet access. A recent report showed that over 60 per cent of rural areas lack stable network connectivity. This means:

- Farmers, students, and small businesses cannot fully utilise digital banking or e-learning.
- Many citizens remain vulnerable to cyber fraud due to lack of digital literacy.

We must:

Expand rural broadband infrastructure.

Invest in cybersecurity awareness and consumer protection measures.

Ensure responsible AI governance to safeguard data privacy

Conclusion: From Promises to Accountability -- True leadership is not about grand announcements, it is about real impact. The people of this nation do not need more rhetoric; they need results. They need policies that uplift the vulnerable, create real opportunities, and ensure that every citizen, no matter where they come from, has access to the essentials of a dignified life.

Our job isn't to applaud promises; it's to hold power accountable. We must rise above party lines and focus on what truly matters, turning words into action and aspirations into reality. The people of India deserve more than assurances. They deserve action. They deserve not just plans, but real progress. Not just speeches but meaningful change.

Let us work toward a future where no one is left behind. and every citizen can share in the success of a nation that truly delivers on its promises.Thank you.

SHRIMATI POONAMBEN MAADAM (JAMNAGAR): Progress is built on vision and action, and the Union Budget 2025 reflects this Government's commitment to realizing the vision of a Viksit Bharat. A commitment to every worker who wakes up before dawn, every entrepreneur who dares to dream, and every woman breaking barriers. This budget is a testament to empowering every Indian where growth is not a distant dream but is a reality.

I extend my congratulations to the hon. Finance Minister, Smt. Nirmala Sitharaman ji, for presenting a comprehensive and inclusive budget, and I appreciate this opportunity to express my thoughts on it. The transformative work during this Government's first two terms has laid a strong foundation for this budget to accelerate growth and development. The Union Budget focuses on four key areas to drive the country forward ? Agriculture for rural prosperity, MSMEs for Jobs and businesses, investment for better infrastructure and innovation, and exports to boost India's global growth.

Ten years ago, this Government was set on the path of transforming India. India is the fastest-growing major economy in the world. Today, we stand as the 5th largest economy, and under the visionary leadership of the hon. Prime Minister Narendra Modiji, we are steadily moving towards becoming the 3rd largest. This Government's strong track record and reforms have earned India global recognition, boosted investor confidence, and strengthened its position in the world economy.

Despite inheriting an economy burdened with high non-performing assets and a struggling corporate sector, this Government has steadily improved fiscal management. It has done so through a clear three-part approach encouraging public investment, increasing capital expenditure, and targeted public service delivery. These efforts have helped India stay strong, even as the global economy faces rising inflation. The fiscal deficit for FY 2024-25 has been revised down to 4.8% of the GDP from the earlier estimate of 4.9%. Similarly, the target for FY 2025-26 has been lowered further to 4.4% of the GDP. This decline reflects improving financial management and a move toward greater economic stability.

In addition to focusing on the Garib, Yuva, Annadata, and Nari, this Government has remained committed to India's middle class. The middle class plays a crucial role in driving India's economic growth and shaping the vision of Viksit Bharat@2047. A step in this direction is the Vivad se Vishwas scheme, which prioritises trust in taxpayers before scrutiny by the Income Tax Department. This budget continues in the same direction, bringing tax relief measures. In a major move to support the middle class, the 'nil' tax slab has been expanded, reducing the tax burden and increasing disposable income. Earlier, only income up to Rs. 7 lakh was tax-free, but now, income up to Rs. 12 lakh will have zero tax liability. This means that citizens earning Rs. 1 lakh per month will pay no income tax. These measures reflect the Government's commitment to easing the tax burden and putting more money in the hands of the people. After all, if a budget does not serve the people, then who does it serve?

Apart from taxation reforms, the budget highlights this Government's commitment to affordable housing for urban low and middle-class income groups with the launch of SWAMIH Fund 2. This initiative aims to create over 1 lakh homes, with 40,000 houses set to be delivered in 2025. These reforms reflect this Government's commitment to uplifting the middle class and ensuring them opportunities for a better future.

Farmers have always been at the centre of this Government's development agenda. The Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme provides direct financial support to landholding farmers, where each beneficiary receives Rs. 6,000 annually. In my constituency 1.77 lakh farmers have benefited, with a total amount of Rs. 859.43 crore disbursed to support their agricultural needs. To further boost 'Annadata Shakti', the Prime Minister Dhan-Dhaanya Krishi Yojana was introduced by this budget. In its first phase, this scheme aims to benefit 1.7 crore farmers. Diversifying crops is essential for soil health and food security. To support this, the government is set to launch a six-year 'Mission for Atmanirbharta in Pulses', focusing on tur, urad and masoor pulses. For migration to become a choice, not a necessity, a comprehensive rural prosperity and resilience program will be launched to tackle agricultural underemployment through skilling, investment, and technology. Access to credit will improve as the Kisan Credit Card loan limit increases from Rs. 3 lakh to Rs. 5 lakh, easing the financial strain on farmers. To further secure agricultural growth, a 12.7 lakh metric tonne urea plant will be set up in Namrup, Assam, ensuring a steady supply of fertilizers.

A decade ago, expectations from the Government in terms of public service delivery were significantly lower. But this has drastically changed. With their basic needs met, people are more aspirational, demanding better opportunities and higher living standards. This shift raises expectations from the Government, driving it to deliver more and do better. This budget reflects that commitment, ensuring growth and progress for all. The expansive and holistic reach of development and welfare schemes has ensured irreversible empowerment for various marginalised groups, helping them become self-reliant. Serving the poor and the marginalised has been the promise of this government, a promise that is guided by the principle of Antyodaya, which means that the goal of development isn't complete until it reaches the last person in society.

Building on the success of the PM SVANidhi Scheme, which has benefited 68 lakh street vendors, this budget brings higher loan limits, UPI-linked credit cards with a limit of Rs. 30 thousand, and capacity-building support for street vendors. The Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0 programmes have been strengthened to support children, pregnant and lactating women, and adolescent girls. Additionally, the Jal Jeevan Mission, which has provided safe drinking water to 15 crore households covering 80% of rural India, has been extended till 2028 with an increased budget allocation to ensure nobody is without safe drinking water.

World Cancer Day is celebrated each year on February 4th to raise awareness about cancer, and the Ayushman Bharat scheme has been a game-changer in the fight against the disease. The Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana (AB-PMJAY) scheme has significantly reduced out-of-pocket expenditure from 62.6% to 39.4%. With the help of the Ayushman Card, low-income families can access timely and cashless treatment, ensuring better healthcare without financial strain. In my constituency, over 9 lakh constituents have been availing treatment through the scheme. Now what about gig workers—one of the driving forces of India's digital economy? This budget brings them into the fold by including them under Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana, ensuring healthcare access, identity cards, and e-Shram registration. With nearly 1 crore gig workers set to benefit, this is a major step toward their social security and well-being.

The former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, once said. "Education is the most powerful weapon you can use to change the world." To achieve and give every child the weapon of education to

change the world, this Government has developed and launched various schemes over the past decade to empower the Yuva through world-class education and upskilling.

This Budget has announced plans to establish 50,000 Atal Tinkering Labs in Government schools over the next 5 years to promote scientific thinking among students. To bridge the language gap in education, the Bharatiya Bhasha Pustak Scheme will provide digital forms of Indian language books. In a major step towards equitable learning opportunities, this Government will provide broadband connectivity to all rural Government secondary schools, ensuring children have better access to digital education.

To equip India's youth with world-class skills, five National Centres of Excellence for Skilling will be set up for youth to 'Make in India, Make for the World.' Recognizing that AI-driven education is the future, the Centre of Excellence in AI for Education is a visionary investment that will place India at the forefront of technological advancements. Adding 75,000 new seats in Government medical colleges is a game-changer in medical education, ensuring a more significant number of skilled healthcare workers. Furthermore, 10,000 technological research fellowships in IITs and IISc will fuel innovation under the PM Research Fellowship Scheme.

Building on the hon. Prime Minister Narendra Modi ji's commitment to the Panchamrit environmental goals in 2022, this budget launches the National Manufacturing Mission, focusing on the domestic manufacturing of solar PV cells, EV batteries, motors, and turbines. Recognising the future of nuclear energy, amendments to the Atomic Energy Act and Civil Liability for Nuclear Damage Act will enable the private sector to participate in developing 100 GW of nuclear power by 2047. A Nuclear Energy Mission has also been announced to support research and development for Small Modular Reactors, with at least five indigenous Small Modular Reactors to be operational by 2033.

The Union Budget 2025 has introduced major boost to railway infrastructure with 17,500 general coaches, 200 Vande Bharat, and 100 Amrit Bharat trains. By March 2025, our Railways is on the verge of reaching a 1.6 billion-tonne cargo capacity, making it the world's second-largest railway freight carrier. Furthermore, we are rapidly moving towards achieving 100% electrification of our rail network, reducing carbon footprint and improving energy efficiency.

In my constituency, I am proud to state that we have achieved 100% electrification marking a significant milestone in our commitment to sustainable and efficient railway infrastructure. Moreover, solar power plants have also been installed at Okha and Jamnagar stations, showing our commitment to sustainable energy.

Eight stations are being redeveloped in my constituency under the 'Amrit Station Scheme' which will majorly enhance infrastructure and passenger facilities. The Kanalus-Rajkot doubling project is underway and progressing efficiently. Among trains introduced, the Vande Bharat Express from Jamnagar to Ahmedabad, now extends to Okha. Moreover, the Hapa-Bilaspur Superfast Weekly train has been extended to Okha which has brought a new level of comfort and speed to our rail network.

In road infrastructure, the Kuranga to Kathiveliya State Highway has been upgraded to a National Highway, further strengthening regional connectivity. Additionally, the 1,256 km Amritsar-Jamnagar Economic Corridor will directly link my constituency, providing the people with faster transportation, improved trade opportunities, and better access to other key economic hubs.

The MSME sector has been the backbone of India's economy. A strong MSME sector means a strong India. Over the years, the MSME sector has grown stronger, with exports soaring from Rs. 3.95 lakh crore in 2020-21 to Rs. 12.39 lakh crore in 2024-25, and the number of MSMEs exporting increasing from 52,849 to 1,73,350. Representing the constituency of Jamnagar with a strong MSME presence, I have witnessed firsthand the hard work and resilience of our entrepreneurs. Steps have been taken by this government to enhance this sector. For instance, the Pradhan Mantri MUDRA Yojana has empowered non-corporate, non-farm small and micro enterprises by providing them access to institutional finance. To further strengthen support the Government has previously increased the loan limit from Rs.10 lakh to Rs. 20 lakh, ensuring greater financial inclusion and opportunities for growth. In my constituency, over 9.10 lakh beneficiaries have received MUDRA loans, with Rs. 617.53 crore disbursed under the scheme. This budget continues moving in this direction, with transformative measures introduced to strengthen and expand this sector further. Under this budget, the removal of customs duties on essential minerals like brass scraps will significantly lower costs and benefit numerous manufacturers and MSMEs, including those in my constituency. Jamnagar, famously known as the Brass City is home to over 5,000

manufacturing units which play a crucial role in driving export revenue, creating jobs and enhancing India's global competitiveness in the sector.

To boost credit access, the investment and turnover limits for MSME classification have been raised by 2.5 times and 2 times, respectively, enabling businesses to improve access to capital and technological advancement. The credit guarantee cover for medium and small enterprises has doubled from Rs.5 crore to Rs.10 crore, unlocking an additional Rs.1.5 lakh crore in credit over five years. Startups will also benefit, with guarantee cover increasing from Rs.10 crore to Rs.20 crore, with the guarantee fee being moderated to 1% across 27 sectors. For exporting MSMEs, term loans of up to Rs.20 crore will now come with enhanced guarantee cover, ensuring greater financial security and global competitiveness. Additionally, a new Credit Card scheme will offer Rs.5 lakh in credit to micro enterprises registered on the Udyam portal, with 10 lakh cards to be issued in the first year.

This Government's aim is not limited to financial assistance, it's about empowering our MSMEs, enabling them to grow, innovate, and compete globally. The reforms introduced by this budget will also empower the MSMEs of my constituency to not only drive local growth but also contribute to India's success story.

As I draw to a close, I commend the Government for the forward-thinking initiatives highlighted in this budget. India is thriving, and the world is taking notice. As global economies struggle with uncertainty, India shines as a beacon of stability, innovation, and growth. This budget is our answer to the world. It is a declaration that we are ready, that we are rising, and that we are on our journey to a Viksit Bharat.

श्री लक्ष्मीकान्त पप्पू निषाद (संत कबीर नगर) : यह बजट वर्ष 2025-26 का किसान, नवजवान, मुसलमान एवं पिछड़ा, अनुसूचित विरोधी बजट है जहां आज पढ़ लिखकर नवजवान बेरोजगार है। बजट में किसानों, व्यापारियों, गरीबों के लिए कोई उन्नति का रास्ता नहीं दिया, शिक्षा के क्षेत्र में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, इससे प्रतीत होता है कि शिक्षा विरोधी बजट है। बजट में उत्तर प्रदेश के मछुवारों (फिशर) को कोई जगह नहीं दी गई है, जबकि निषाद (मछुआरा) समाज गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता है मछुआरा को मछुआ आवास इस सरकार में नहीं दिया जा रहा है।

बजट में विश्व में पहचान बनाने वाले सूफी संत महात्मा कबीर दास जी के नाम जिला बनाया गया है इतने बड़े संत के नाम से कोई बजट नहीं दिया गया है। संत कबीर नगर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, न ही पूर्वोत्तर में सेना का स्कूल है, संत कबीर

नगर में मिलिट्री स्कूल बनवाने का कष्ट करें मेरे जिले में नर्सिंग कॉलेज एवं मत्स्य पालन हेतु उच्च स्तर का ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाये ।
धन्यवाद ।

DR. NAMDEO KIRSAN (GADCHIROLI-CHIMUR): I would like to express my views on the budget, India's GDP growth for 2024-25, as per government data, is expected to be 6.4 per cent which is not a cause for celebration.

If India is to encash its historic demographic dividend, sustained GDP growth of at least eight per cent is necessary. But unfortunately, over the last few years India has consistently failed to achieve these targets.

The Modi government is marching India forward into the middle income trap, which will make us uncompetitive, underproductive, and unequal.

GDP growth in the six per cent range is insufficient to create jobs for our growing youth population, especially when rapid technological change is disrupting the future of jobs. It will keep India stuck in a state of high inequality, where two-thirds of our population remains dependent on free grains from the government while the Prime Minister's favored few accumulate wealth rapidly. Such economic underperformance robs millions of the Constitution's promise of a more just, prosperous, and equal future.

But the Modi government appears focused on enriching his circle of corporate supporters. In 2019, it announced a massive tax cut for corporations, but the private sector has not stepped-up investment in return.

Common people and small businesses continue to be burdened with punitive taxes on fuel and an extractive Goods and Services Tax regime.

In every corner of the country, families, workers, farmers, and businesses are feeling the weight of the government's failure to deliver on its core commitments and poll promises.

Youth unemployment stood at a staggering 45.4 per cent in 2022-23. Practically, every second young person is jobless & joblessness is particularly high among the educated youth.

Graduates face a 29.1 per cent unemployment rate. There has been serial job destruction in the formal sector. The share of manufacturing in the workforce has declined from 12.6 per cent in 2011-12 to just 11.4 per cent in 2023-24.

For the first time in decades, the share of workers engaged in agriculture has increased rising from 42.5 per cent in 2018-19 to 46.1 per cent in 2023-24.

Due to lack of quality job creation, over half of men and two-thirds of women are now self-employed, typically in low-productivity and low-income jobs.

Job growth in the non-farm sector has dropped from a high of 75 lakh per year under the UPA to just 29 lakh per year under the Modi government

Since 2014, real wage growth has been abysmal: agricultural labourers have seen an increase of just 0.8 per cent, non-agricultural workers 0.2 per cent, and construction workers have faced negative wage growth.

Salaried workers, too, have seen their wages decline by one per cent annually.

Household savings have plummeted to a 47-year low, while consumption growth has hit a 20-year low, with private consumption growth falling to four per cent in 2023-24.

The poorest 20 per cent of households have faced the harshest income losses, with their earnings dropping by more than 50 per cent by 2021. Household debt has soared, with a record 39 percent of GDP tied up in debt.

Despite the increasing demand for MGNREGA work, the programme's budget share has plummeted from 2.15 per cent in 2019-20 to just 1.33 per cent in 2023-24. The 2024-25 allocation failed to meet the scheme's requirements.

Nearly four crore job cards were deleted between 2019 and 2024. By imposing an Aadhar-based payment system, the government has excluded nearly 50 lakh workers from wage payments. MGNREGA wages have been growing at measly rates despite consistent demands from workers and the Parliamentary Committee on Rural Development to raise them to Rs. 375 per day.

I would like to state that 70 per cent of farmers earn Rs. 11,000 to Rs. 13,500 per month, with barely any surplus after covering their basic consumption.

Post-COVID, 56 lakh workers were absorbed into agriculture, but with stagnant output, these workers face disguised unemployment.

Over 55 per cent of agricultural households are in debt, with an average liability of Rs. 91,231. Despite this, the consistent demand made by farmer organizations for an agricultural loan waiver has been ignored.

Dr Manmohan Singh's government increased the Minimum Support Price (MSP) for wheat by 119 per cent and for rice by 134 per cent, while the current Government has raised it by about 47 per cent for wheat and about 50 per cent for rice. These increases are highly inadequate to cover the comprehensive input costs borne by farmers.

Despite assurances made by the Government to the farmers during the Farm Protests, the Government has refused to make MSP a legal guarantee or set prices according to the Swaminathan Commission's formula.

PM-KISAN has not been indexed to inflation, with farmers continuing to get the flat Rs. 6,000 they received in 2019 despite high inflation in the intervening years.

PM Fasal Bima Yojana has been a flop, with farmers struggling to get adequate insurance payments on time. The tragic consequence of the agrarian crisis is the 1,00,474 farmer suicides between 2014 and 2022.

Excise duties on petrol and diesel have been increased by over 100 per cent (petrol) and 343 per cent (diesel) since 2014. Inflation has eroded the returns on Fixed Deposits (FDs), once considered a reliable investment option for retirees. The rupee has depreciated from Rs. 58 per dollar in 2014 to over Rs. 86 per dollar, increasing the costs of imports and stoking further inflation.

The rapid concentration of wealth has fuelled in the hands of a few billionaires, with the government acting as a facilitator of their corporate empires.

While ordinary Indians face unemployment and rising inequality, these business magnates have thrived, benefiting from lucrative government contracts and favorable policies.

It has been announced in the budget that "A new scheme will be launched for 5 lakh women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes first-time entrepreneurs which will provide term loans up to Rs. 2 crore during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand-Up India scheme."

I would like to state that despite the Government's push for startups, the total number of direct jobs created by DPIIT-recognised startups, as of 31st October 2024, was only 16,67,519.

The funding for Indian startups decreased by a modest 7 per cent in the first nine months of 2024, falling to USD 7.6 billion from USD 8.2 billion during the same period in the previous year.

The government claims that "Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people, and generating 36 percent of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45 percent of our exports."

I would like to state that according to Ministry of Statistics, the share of MSME Gross Value Added (GVA) in India's GDP during 2022-23 was only 30.1 per cent. This is lower than the pre-COVID level of 30.5 per cent in 2019-20.

The share of MSME-specified products in India's total exports showed no actual growth between 2021 and 2023. Due to the government's failure to support MSMEs, 19,828 MSMEs shutdown in 2023-24.

The government also claimed that it will facilitate setting up of Day Care Cancer Centres in all district hospitals in the next 3 years. 200 Centres will be established in 2025-26,"

The Government has completely failed to curb the increasing cases of cancer. India has 13.9 lakh cancer cases, which are estimated to increase by 12 per cent by the year 2025. India reported over eight-lakh cancer-related deaths in 2022, ranking third globally for cancer cases. Seventy per cent of Indian districts lack comprehensive cancer centers, disproportionately impacting rural areas.

Only forty per cent of cancer care centers are situated outside metropolitan zones, widening the urban-rural divide in cancer care in India.

Government has failed to prevent cancer in Northeast India. The region has the highest incidence of cancer in the country, with three times the national average. Around 45,200 new cases are reported every year, and Assam alone accounts for more than 32,000.

Approximately 60 per cent of radiation treatment facilities are concentrated in southern and western India, leaving eastern regions underserved despite a high incidence of cancer.

With these few words, I conclude and request the government to acknowledge what is going wrong as it would be the first step toward fixing the economy instead of staying in a state of denial.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : मैं वर्ष-2025-26 के आम बजट पर अपने विचार रखता हूँ। इसी के साथ माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी को हृदय से बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मन्त्र को केंद्र में रखकर इस आम बजट को बनाया है। इस बजट में सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है कि "सभी धर्मों, जातियों, लिंगों और आयुवर्ग के भारतियों को अपने जीवन के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति करे।

यह बजट भारत के आम जनता के लिए इसलिए भी विशेष है कि इसमें मुख्यतः गरीब, महिलायें, युवा और अन्नदाता किसान पर ध्यान केन्द्रित कर विभिन्न योजनाओं में विशेष रूप से धन आवंटित किया गया है जो भारत को दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाने के साथ एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में है। इस बजट के मुख्य बिंदु निम्न हैं जिसे बताते हुए मुझे अतिप्रसन्नता हो रही है :-

1. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना-विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम ।
2. ग्रामीण सम्पन्नता और अनुकूलन निर्माण ।
3. दलहन में आत्मनिर्भरता ।
4. सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम ।
5. राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन ।
6. कपास उत्पादकता मिशन ।

7. किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण ।
8. सूक्ष्म उधमियों के लिए क्रेडिट कार्ड ।
9. वैश्विक खिलौना केंद्र ।
10. राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र ।
11. सभी जिला अस्पतालों में डे केयर सुविधा केंद्र ।
12. भारत में चिकित्सा पर्यटन केंद्र और स्वास्थ्य लाभ ।
13. ज्ञान भारतम मिशन ।
14. रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन ।
15. मध्यम वर्गों के लिए टैक्स में भारी छूट ।

उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के तहत बजट में की गई व्यवस्था से भारत के आम जनता को काफी लाभ मिलेगा तथा राष्ट्र को मजबूती मिलेगी । इससे मध्यम वर्ग, व्यापारी एवं उधमियों को भी बड़े पैमाने पर लाभ होगा ।

आम बजट में बिहार को विशेष रूप से बड़े स्तर पर अनेकों योजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर राशि का आवंटन हुआ है । इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री, माननीया वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं अपने महाराजगंज संसदीय क्षेत्र सहित पूरे बिहार की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ । बिहार के लिए इस आम बजट में विशेष रूप से प्रावधानित योजनाओं से बिहार में युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार बढ़ेगा एवं किसानों, श्रमिकों, मछुआरों की आय में भी वृद्धि होगी तथा साथ ही बिहार को देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने में काफी मदद मिलेगी । बिहार के लिए बजट में प्रावधानित कार्य निम्न प्रकार है :-

1. बिहार में फूड टेक्नोलॉजी इंस्टिट्यूट की स्थापना ।
2. पटना आईआईटी में छात्रावास का निर्माण, सीटों में इजाफा एवं अन्य अवसंरचना को बढ़ाने की व्यवस्था ।
3. पटना हवाई अड्डा का विस्तार ।
4. बिहार में ग्रीनफील्ड नए हवाई अड्डे का निर्माण ।
5. बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना ।
6. बिहार दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मदद की घोषणा ।

7. मिथलांचल के किसानों के लिए स्पेशल पैकेज के साथ सिचाई की व्यवस्था (वेस्टर्न कोशी प्रोजेक्ट को विस्तारित करना) ।

अंत में इस आम बजट का समर्थन करते हुए माननीया वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा, बिहार अंतर्गत जनहित में निम्न कार्यों को भी कराने की इस बजट में व्यवस्था किया जाये ।

1. एक कृषि/बागवानी महाविद्यालय की स्थापना हेतु ।

2. नई दिल्ली से गोरखपुर, सिवान, एकमा, छपरा होते हुए पटना तक एक जोड़ी वन्देभारत ट्रेन चलाने की व्यवस्था ।

3. एक मेडिकल कॉलेज खोलने की व्यवस्था ।

4. लोकनायक जयप्रकाशनारायण की जन्मस्थली सारण से जलालपुर, बनियापुर, भगवानपुर, डुमरिया घाट होते हुए महात्मा गाँधी की कर्मस्थली चम्पारण के मोतिहारी तक एक नई रेल लाइन बिने हेतु ।

5. मांझी से अयोध्या तक घाघरा/सरयू नदी में पूर्व से घोषित राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 40 में जलीय परिवहन का शुचारू संचालन की व्यवस्था ।

6. मेगा फूड पार्क स्थापित कराने की व्यवस्था ।

7. संसदीय क्षेत्र के सारण जिला अंतर्गत मांझी प्रखंड के मांझी गढ एवं बनियापुर प्रखंड अंतर्गत हरपुर कराह गढ को धरोहर घोषित करते हुए पर्यटकीय एवं सांस्कृतिक दृष्टि से विकसित करने हेतु ।

8. सारण जिला के धुरदह, बहियारा चवरो में मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि की व्यवस्था ।

9. चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना ।

10. पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना ।

11. नाईलिट सेंटर की स्थापना ।

12.आई.टी. पार्क की स्थापना ।

13. टेक्सटाइल पार्क की स्थापना ।

14 एन.एच.331 पर भगवानपुर हाट में ट्रामा सेण्टर की स्थापना ।

15.एन.एच.531 पर एकमा में ट्रामा सेण्टर की स्थापना ।

16. एन.एच.227 अ पर बसंतपुर में ट्रामा सेण्टर की स्थापना ।

17. साईं सेण्टर की स्थापना ।

सधन्यवाद ।

श्री नीरज मौर्य (आंवला) : मैं बजट 2024-25 पर अपने विचार रखता हूँ। इस बजट में शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषकर उ.प्र. में और मेरे क्षेत्र के लिए कोई कार्ययोजना नहीं है हमारा क्षेत्र आँवला लोकसभा जो अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य करने की आवश्यकता है।

अतः मैं सरकार से माँग करता हूँ कि एक सैनिक स्कूल खोलने का प्रावधान आँवला में किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। हमारा लोक सभा क्षेत्र आँवला जो बरेली जनपद के अन्तर्गत आता है। बरेली पश्चिमी उ.प्र. का एक प्रमुख केन्द्र है जिला मुख्यालय के साथ-साथ मण्डल मुख्यालय भी है बड़ी आबादी है और बरेली में कोई भी अच्छा अस्पताल नहीं है आम लोगों को गम्भीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है और गरीब लोग इलाज के अभाव में जीवन भी गवा देते हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जनता की परेशानियों को देखते हुए अविलम्ब बरेली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने संबंधी प्रक्रिया चालू करने की कृपा करें।

हम सबकी पुरानी माँग थी कि आयकर की सीमा बढ़ायी जाए एवं आयकर की दरें भी कम की जाएँ आप द्वारा 12 लाख तक आयकर से मुक्त करने का फैसला सराहनीय है परन्तु जो आयकर की दरें 30% तक है इन्हें और कम किया जाए।

हमारे क्षेत्र के किसान बहुत दुखी व परेशान हैं किसानों को आवारा जानवरों से मुक्ति मिलें व किसान कल्याण हेतु योजना की आवश्यकता है।

बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है युवाओं को काम नहीं मिल रहा ।

इस क्षेत्र में सरकार को ध्यान देने की अति आवश्यकता है ।

अन्त में माँग करता हूँ कि सांसद विकास निधि जो पिछले 15 वर्षों में 5 करोड़ है जबकि स्थानीय विधान मण्डल विकास निधि सांसद की विकास निधि से कहीं अधिक है अतः क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए सांसद विकास निधि कम से कम 25 करोड़ की जाए मैं यह माँग करता हूँ।

धन्यवाद ।

श्रीमती मंजू शर्मा (जयपुर) : मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीया वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को सर्व हितकारी बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत-बहुत बधाई एवं धन्यवाद देती हूँ।

इस नई लोक सभा का यह पहला बजट देश के गरीबों, युवाओं, किसानों, महिलाओं, मध्यम वर्ग और समस्त देशवासियों को समर्पित है और उनके सपनों को साकार करने वाला है इस वर्ष माननीया वित्त मंत्री जी ने 50.65 लाख करोड़ से अधिक के व्यय का बजट प्रस्तुत किया है।

आज विश्व में आर्थिक मंदी का दौर है। पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था मंदी से प्रभावित है जहां बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और माननीया वित्त मंत्री जी की सूझबूझ का नतीजा है कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। जहां हम 2013 में विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में थे और आज हम विश्व की करीब करीब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और बहुत जल्द हम 5 ट्रिलियन इकोनोमी के लक्ष्य को हासिल कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे।

आज भारत धीरे धीरे प्रोडक्शन हब के रूप में उभर रहा है। एप्पल जैसी विश्व की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी भारत में अपने उद्योग स्थापित कर रही है और वैश्विक मंदी के इस दौर में भी भारत की क्रय शक्ति क्षमता विश्व में तीसरे स्थान पर है।

मैं माननीया वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगी कि उन्होंने वैश्विक मंदी के दौर में भी भारत को एक सर्व कल्याणकारी बजट आवंटित किया है। यह बजट मध्यम वर्ग पर भारोसे वाला साहसिक बजट है, मध्यम वर्ग विशेषकर नौकरी पेशे वाले लोग काफी समय से आयकर के बोझ से दबे हुये थे। अबकी बार उनकी इस समस्या का समाधान करते हुये 12 लाख तक कोई आयकर न देने की उनकी घोषणा से मध्यम वर्ग में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब नौकरी पेशे वाले व्यक्ति को 12 लाख 70 हजार रुपये तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

इससे वित्तमंत्री जी ने खपत आधारित वृद्धि का नेतृत्व करने के लिए मध्यम वर्ग पर भारोसा जताया है। इस वर्ग के परिवारों में उपभोग को बढ़ावा देने के लिए एक साहसिक कदम है।

माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के वादों के अनुसार निर्णय लिये गये। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जी का भारोसा माननीया वित्त मंत्री सीतारमन जी पर है। इसीलिए यह उनका 8 वीं बार पेश किया गया बजट है। इस बजट से नए रोजगार और व्यवसायों का सृजन होगा और निर्माण में तेजी आयेगी।

माननीय वित्त मंत्री जी का फोकस गरीब, युवा और अन्नदाता नारी यानी ज्ञान पर रहा। गरीब और वंचित समूह भी आय बढ़ाने सत्त रोजगार ओर बेहतर जीवन यापन के लिए शहरी कामगार उत्थान योजना लागू की जायेगी। युवाओं के लिए अगले चार साल में आई.आई.टी. में 6500 और एम.बी.बी.एस. में 75000 सीटें बढ़ेगी। 50,000 सरकारी स्कूलों में अटल टिकरिंग लैब स्थापित की जायेगी। इससे बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना पैदा होगी। अन्नदाता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लॉन कीमत 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए पी.एम. धन धन्य योजना की घोषणा की गई है जो 100 जिलों को कवर करेगी। अगले 4 साल में किसान जितनी दलहन का उत्पादन करेंगे केन्द्रीय एजेंसिया सारी खरीदेगी। नारी को ध्यान में रखते हुये पहली बार बिजनेस शुरू करने वाली एस. सी/एस.टी. की 5 लाख महिला उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये का टर्म

लोन दिया जायेगा। महिलाओं और बच्चों के पोषण को मजबूत बनाने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 स्कीम की शुरुवात होगी।

माननीया वित्त मंत्री जी ने रेलवे में 2.52 लाख करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है, जो अब तक कि सबसे बड़ी राशि है इससे रेलवे में आधुनिकरण में मदद मिलेगी। 200 बन्दे भारत, 100 अमृत भारत और 50 नमों भारत ट्रेनों का संचालन होगा।

वित्त मंत्री जी ने रक्षा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुये 6.81 लाख करोड़ की धनराशि

आवंटित की है जो हमारी तीनों सेनाओं का एकीकरण में मददगार साबित होगा।

वित्त मंत्री जी के कुछ और सराहनीय कदमों पर प्रकाश डालती हूँ। कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे लोगों को अगले 3 वर्षों में देश के सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर केन्द्र बनाये जायेंगे। स्कूलों में ब्राडबैंड की सुविधा होगी। लघु और मध्यम उद्योगों के लिए ऋण सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ ऋण कर दिया है। मेकइन इंडिया की पहल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन स्थापित किया जायेगा।

अन्त में मैं, यह कहूंगी कि सह बजट भारत को 5 ट्रिलियन इकोनोमी कि ओर ले जाने वाला अच्छा बजट है। इसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री और माननीया वित्त मंत्री जी के अथक प्रयास से वह दिन दूर नहीं जब हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्ताव का स्वागत करते हुये अपनी बात समाप्त करती हूँ।

श्री हरीभाई पटेल (महेशाणा) : मैं बजट 2025-2026 पर अपने विचार रखता हूँ। मैं देश के प्रधान सेवक आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने वर्ष 2014 से पहले रुके हुए विकास के सभी कार्यों को पूर्ण गति प्रदान की और एक मजबूत भारत की छबि दुनिया में बनायी है मैं आपके माध्यम से सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतना मजबूत और स्पष्ट बजट प्रस्तुत किया है इसी के साथ विकसित भारत 2047 के लिए रोडमैप: सुधारों को ईंधन और समावेशिता को मार्गदर्शक भावना के रूप में रखते हुए, वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट विकसित भारत की गति निर्धारित करने का लक्ष्य रखता है। यह बजट स्वीकार करता है कि किसी देश की शक्ति उसकी भूमि में नहीं बल्कि उसके लोगों में होती है, और इस प्रकार, सभी वर्गों में समावेशी विकास के माध्यम से मोदी सरकार की सबका साथ, सबका विकास की प्रतिबद्धता को पुनर्जीवित करती है। केंद्रीय बजट चार प्रमुख इंजनों द्वारा संचालित है ग्रामीण समृद्धि के लिए कृषि, उद्यमिता और रोजगार सृजन के लिए एम.एस.एम.ई (MSME), बुनियादी ढांचे और नवाचार के लिए निवेश, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा व आर्थिक वृद्धि के लिए निर्यात। यह बजट छह प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है, अर्थात् कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, वित्तीय क्षेत्र, नियामक सुधार और खनन। इस बजट का लक्ष्य एक व्यापक छह-आयामी दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसमें विकास को गति देना, समावेशी विकास को सुरक्षित करना, भारत के मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाना, निजी क्षेत्र के निवेश को प्रेरित करना और घरेलू भावना को सशक्त करना शामिल है।

बेहतर भविष्य के लिए मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना ज्ञान (GYAN) के मुख्य सांभी के अतिरिक्त, मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को फिर दोहराया है। ताकि उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य

को सुरक्षित किया जा सके। इस दिशा में, मोदी सरकार ने विवाद से विश्वास की नीति को अपनाया है, जहां आयकर विभाग पहले करदाता पर विश्वास करता है और बाद में उनकी जांच करता है। वर्तमान बजट में इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्याज पर कर कटौती की सीमा को वर्तमान समय में ₹50,000 से दोगुना कर 11 लाख कर दिया गया है। इसी प्रकार, किराए पर टी डी एस (105) की वार्षिक सीमा ₹2.40 लाख से बढ़ाकर 28 लाख कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, विदेशी प्रेषण (remittances) पर कर संग्रह (TCS) की सीमा 27 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान बजट के माध्यम से, मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग पर कर बोझ को कम करने के मार्ग को जारी रखा है और "शून्य" कर श्रेणी को मौजूदा 27 लाख से बढ़ाकर 212 लाख कर दिया गया है, जिससे 1 लाख मासिक आय वाले व्यक्ति की कर देयता शून्य हो जाएगी। ₹12 लाख तक की सामान्य आय वाले करदाताओं को कर छूट दी जा रही है, जो स्लैब दर में कमी के कारण होने वाले लाभ के अतिरिक्त होगी, जिससे उनका कोई कर देय नहीं होगा। नए कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख की आय वाले करदाता को ₹80,000 का कर लाभ मिलेगा, जो मौजूदा दरों के अनुसार 100% कर देयता के बराबर है। इसी प्रकार, ₹18 लाख की आय वाले व्यक्ति को ₹70,000 का कर लाभ प्राप्त होगा। कराधान सुधारों के अलावा, बजट ने शहरी निम्न और मध्यम आय वर्ग के लिए किफायती आवास प्रदान करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया है। इसके लिए 'स्वामी फंड 2' (SWAMIH Fund) लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत ₹15,000 करोड़ की लागत से 1 लाख से अधिक घरों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 2025 में ही 40,000 घरों के वितरण का लक्ष्य रखा गया है। ये सुधार मध्यम वर्ग की क्षमताओं और दृढ़ संकल्प पर मोदी सरकार के विश्वास को दर्शाते हैं।

अन्नदाताओं का समग्र कल्याण: पिछले दशक में, मोदी सरकार के भारतीय विकास एजेंडे के केंद्र में किसान रहे हैं। अन्नदाता शक्ति को और मजबूत करने के लिए, केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के पहले चरण में राज्यों के सहयोग से 100 कम उत्पादकता और कम बीमा कवरेज वाले कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। यह योजना कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने में मदद करेगी। इसके साथ ही, भंडारण और सिंचाई सुविधाओं में सुधार किया जाएगा और किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे 1.7 करोड़ से अधिक अन्नदाताओं को लाभ मिलेगा। कृषि क्षेत्र में रोजगार की कमी को दूर करने के लिए एक व्यापक बहु-क्षेत्रीय ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें कौशल विकास, निवेश और तकनीक के माध्यम से कृषि में रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक ग्रामीण नागरिक के लिए प्रवासन एक आवश्यकता नहीं बल्कि विकल्प हो। खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए दालों में आत्मनिर्भरता के लिए छह वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा। इसे नफेड (NAFED) एन.सी.सी.एफ (NCCF) के साथ मिलकर संचालित किया जाएगा। अगले चार वर्षों में, किसानों से मिलने वाली तूर, उड़द और मसूर दालों की अधिकतम मात्रा की खरीद पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसमें कृषि उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता, प्रसंस्करण और किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने पर जोर दिया जाएगा। इससे भारत को एक स्वस्थ समाज की ओर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। यह मखाना उत्पादकों को संगठित कर उन्हें किसान उत्पादक संगठन (FPO) के रूप में विकसित करने में मदद करेगा। उन्हें प्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे मखाने के

उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में सुधार होगा। उच्च उपज देने वाले बीजों पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा। यह उन्नत अनुसंधान, अधिक उपज देने वाले, कीट-रोधी और जलवायु-प्रतिरोधी बीजों के विकास और प्रचार-प्रसार पर केंद्रित होगा। साथ ही, जुलाई 2024 के बाद जारी 100 बीज किस्मों की व्यावसायिक उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। समुद्री क्षेत्र की असीमित संभावनाओं को विकसित करने के लिए, मोदी सरकार भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र और हाई सीज़ में मत्स्य पालन को सतत रूप से दोहन करने के लिए एक सक्षम ढांचा लाएगी। इसमें अंडमान-निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत के लाखों कपास किसानों की आय बढ़ाने के लिए, कपास उत्पादकता पर पांच वर्षीय राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य कपास की उत्पादकता में वृद्धि और अतिरिक्त लंबा रेशा (extra-long staple) वाली कपास की किस्मों को बढ़ावा देना होगा। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के अंतर्गत लिए जाने वाले ऋण की सीमा 23 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी जाएगी। यूरिया की आपूर्ति को और मजबूत करने के लिए, असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, दूसरा जीन बैंक स्थापित किया जाएगा, जिसमें 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइन का संग्रह किया जाएगा।

विश्वस्तरीय शिक्षा के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना मोदी सरकार इस बात को भली भांति समझती है कि भारत को विश्वगुरु बनाने के लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए देण के युवाओं को उन्नत कौशल (upskilling) से लैस करना आवश्यक है। इस दिशा में केंद्रीय बजट में अगले पांच वर्षों में 50,000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई है। ये प्रयोगशालाएं सरकारी स्कूलों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में मदद करेंगी। इसके अतिरिक्त, भारत नेट परियोजना के अंतर्गत सभी ग्रामीण सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इस बजट में "भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना के तहत, भारतीय भाषाओं की पुस्तकें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि छात्र अपनी शिक्षा में भाषा की कठिनाइयों को दूर कर सकें। जुलाई 2024 के बजट में घोषित पहल को आगे बढ़ाते हुए, सरकार वैश्विक विशेषज्ञता के साथ पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (National Centres of Excellence for Skilling) स्थापित करेगी। यह केंद्र युवाओं को 'मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड' के तहत आवश्यक कौशल से सशक्त बनाएंगे। आई.आई.टी. (IT) में 1.35 लाख छात्रों को सुविधा देने के लिए, मोदी सरकार 2014 के बाद स्थापित पांच आई आई.टी. में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगी। इससे 6,500 और छात्रों को शिक्षा की सुविधा मिलेगी। साथ ही, आई.आई.टी. पटना में हॉस्टल सुविधाओं का विस्तार भी किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को बढ़ावा देने के लिए ₹500 करोड़ की लागत से "ए. आई (AI) फॉर एजुकेशन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। पिछले वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या में 130% वृद्धि हुई है। इसे और आगे बढ़ाते हुए, अगले पांच वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएंगी। जुलाई 2024 के बजट में घोषित निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। अगले पांच वर्षों में, प्रधानमंत्री अनुसंधान छात्रवृत्ति योजना (PM Research Fellowship Scheme) के अंतर्गत, सरकार आईआईटी और आई.आई.एस.सी. में तकनीकी अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप प्रदान करेगी।

सामाजिक न्याय और सभी वर्गों के कल्याण के माध्यम से अमृत काल की अभिव्यक्ति: वर्तमान बजट यह स्वीकार करता है कि मानव संसाधन क्षमता का विकास आर्थिक वृद्धि का तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रमों को सशक्त बनाया गया है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं, तथा किशोरियों का कल्याण सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त, मोदी सरकार ने इस बजट के माध्यम से देशभर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कार्यरत 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स की जरूरतों की भी पहचाना है। इन श्रमिकों को सामाजिक पहचान देने के लिए उन्हें पहचान पत्र जारी किए जाएंगे और उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा, इसके अलावा, बजट में जमीनी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से अगले तीन वर्षों में सभी जिता अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। 2018 से अब तक, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 15 करोड़ परिवारों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा दी जा चुकी है। यह संख्या भारत की ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा कवर करती है। 100% कवरेज प्राप्त करने के लिए जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है, और इसके लिए बजट आवंटन को भी बढ़ाया गया है।

निरंतर आर्थिक वृद्धि और राजकोषीय समेकन मोदी सरकार को एक चरमराई हुई अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी जिसमें उच्च गैर-निष्पादित संपतियाँ (NPA) और संकटग्रस्त कॉर्पोरेट क्षेत्र प्रमुख समस्याएँ थीं। इसके बावजूद, सरकार ने सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने, पूंजीगत व्यय को क्रमिक रूप से बढ़ाने और लक्षित सार्वजनिक सेवा वितरण की तीन स्तरीय नीति अपनाकर राजकोषीय समेकन को सफलतापूर्वक लागू किया है। इन्हीं सक्रिय नीतियों के कारण, वैद्विक अर्थव्यवस्था में बढ़ती महंगाई के बावजूद भारत एक अपवाद बनकर उभरा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान में राजकोषीय घाटा 4.8% है, जो कि बजट अनुमान 4.9% से नीचे आया है। इसी तरह, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी घाटे के लक्ष्य को और घटाकर 4.4% किया गया है।

एम.एस.एम.ई क्षेत्र की अपार क्षमता का दोहन: मोदी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 'डबल इंजन सरकार का दूसरा प्रमुख स्तंभ माना है। वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) 7.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं। ये एम.एस.एम.ई (MSMEs) देश में निर्मित कुल उत्पादों का 36% योगदान देते हैं और कुल निर्यात का 45% से अधिक उत्पन्न करते हैं। इन उद्यमों की दक्षता बढ़ाने के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमाओं को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ाया जाएगा। क्रेडिट की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मध्यम और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये किया गया है। इससे अगले पांच वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण सुविधा उपलब्ध होगी। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये किया जाएगा, और गारंटी शुल्क को 27 क्षेत्रों में 1% तक सीमित किया गया है। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये की क्रेडिट लिमिट के साथ कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। पहले वर्ष में 10 लाख ऐसे कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप्स के लिए, 91,000 करोड़ रुपये की प्रतिबद्धता के साथ 'ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट फंड' पहले ही स्थापित किया जा चुका है। अब, 10,000 करोड़ रुपये के शुरुआती योगदान के साथ एक नया 'फंड ऑफ फंड्स' स्थापित किया जाएगा। ये सभी उपाय भारतीय एम.एस.एम.ई (MSMEs) को वैश्विक

बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद करेंगे। व्यापक और तीव्र गति से विनिर्माण विस्तार: आर्थिक विकास और व्यापार के लिए औद्योगिक विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में उद्योगों और उनके संबद्ध क्षेत्रों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक समग्र रणनीति प्रस्तुत की गई है। उदाहरण के लिए, भारतीय फुटवियर क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत, डिजाइन क्षमता, घटक निर्माण और गैर-चमड़े के जूते के लिए आवश्यक मशीनरी को समर्थन दिया जाएगा। यह योजना फुटवियर उद्योग में 22 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करेगी। इससे अर्थव्यवस्था में 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का योगदान होगा और 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात उत्पन्न होगा। बजट ने भारतीय खिलौना उद्योग को भी पुनर्जीवित करने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय कार्य योजना (National Action Plan) के तहत, भारत को खिलौना उत्पादन में वैश्विक नेता बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए खिलौना निर्माण के क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इससे इस क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRIMATI MAHIMA KUMARI MEWAR (RAJSAMAND): I strongly support and deeply appreciate the judicious and meticulous Union Budget of 2025-26. The Finance Minister, Nirmala Sitharaman ji has articulately highlighted the Government's major achievements. This Budget is a true embodiment of what a renewed and fresh perspective the Modi 3.0 Cabinet can present.

I salute the consideration for the poor, the middle class and the common man of India. Following her address, I would like to reflect on some of the key aspects she emphasised, particularly in the areas of housing and urban development, agriculture, and research and innovation. Our government under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi is working with triple energy and vigour towards our collective dream of a Viksit Bharat by 2047. I am sure our hard work in this Amrit Kaal will culminate in the realization of that dream of ours. The most significant victory for women in the country is the boost in the gender budget allocation from 6.8 per cent to 8.86 per cent for FY 2025-26. Envisioning a Bharat that values every woman - didi, ladki and beti the Budget reflects a strong governmental commitment to addressing gender disparities through proactive policies.

The Union Budget allocates a substantial Rs.21,960 crore to Saksham Anganwadi and POSHAN 2.0, which will offer nutritional support to over eight crore children, one crore pregnant and lactating women, and around 20 lakh adolescent girls in targeted regions. Meanwhile, Mission Vatsalya, focusing on child protection, sees its funding rise to Rs.1,500 crore, while women's empowerment is reinforced through Mission Shakti with a total allocation of Rs.3,150 crore.

To add to it, the Government with the Union Budget 2025-26 is now designing a new scheme to support women entrepreneurs, particularly first-time business owners from Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This is a welcome change and rather revolutionary as small businesses run by women are on the rise, but often women from SC and ST communities are left behind, however, this will facilitate access to capital for those who have historically faced challenges in securing credit.

This Government has decisively empowered India's agricultural sector, demonstrating an unwavering commitment through substantial budget allocations. The funding for agriculture has surged dramatically, increasing from Rs.11,915.22 crore in 2008-09 to a massive Rs.1.37 lakh crore in 2025-26. This significant investment highlights the Government's dedication to advancing agriculture in the country. As a direct result of these strategic efforts, the real Gross Value Added (GVA) in agriculture, forestry, and fishing has reached an impressive 26.42 lakh crore and a growth rate of 2.1 per cent in 2023-24. This progress is not merely coincidental; it is a testament to the effectiveness of improved operational efficiency, increased mechanization of farming practices, and a concerted push towards diversification in agricultural activities.

The turning point for me has been the Pradhan Mantri Dhan-Dhaanya Krishi Yojana which will support agricultural practices in 100 climate-impacted districts, with low productivity by boosting agricultural output, promoting crop diversification, and enhancing post-harvest storage. With approximately 46.1 per cent of the population involved in agriculture and related sectors, ensuring financial stability and easy access to credit for farmers remains a key government priority.

This year's budget reinforces the government's dedication to empowering farmers and increasing agricultural productivity by raising the loan limit under the Kisan Credit Card Scheme from Rs.3 lakh to Rs.25 lakh. It will allow our farmers increased financial flexibility, enabling them to invest in quality inputs, modern machinery, and advanced farming practices. It will further reduce their reliance on expensive informal credit sources and help farmers manage risks better, ultimately leading to improved agricultural productivity and rural development.

The government's flagship Khelo India programme, designed to scout for and nurture athletes at the grassroots level, received a significant boost with an allocation of Rs.1,000 crore for the financial year 2025-26. This marks an increase of Rs.200 crore from the previous year's grant of Rs.800 crore. Overall,

the Ministry for Youth Affairs and Sports has been allocated Rs.3,794.30 crore, reflecting a substantial hike of Rs.351 98 crore. An important contribution of the scheme has been the significant rise in the participation of female athletes and honing in-house talent.

Sports are no longer confined to a select few; they are now accessible to all and actively nurtured by the government to shine on international platforms. It is remarkable to think that 124 out of 644 Indian athletes and 42 out of India's 106 medals, including 9 Gold medals at the 2022 Asian Games in Hangzhou, China as well as 28 out of 117 Indian athletes were from the Khelo India Programme, highlighting the program's ongoing success and the critical role in enhancing India's performance in national and international sports events.

There was a time when families and parents in India expressed concerns if their children aspired to become professional athletes. However, that mindset is changing. Today, investment in sports extends beyond mere encouragement—it encompasses infrastructure development, capacity building, specialized training, and structured platforms to showcase talent. This comprehensive approach has become the new standard, ensuring that aspiring athletes receive the opportunities they need to succeed on both national and global stages.

As Digital India becomes a reality, the union government has pre-emptively equipped Government educational institutions with broadband connectivity for all government secondary schools and primary health centres in rural areas under the BharatNet project. Also commendable is their initiative to focus on the holistic growth of a child, wherein 50,000 Atal Tinkering Labs will be established in government schools to nurture curiosity, innovation, and scientific thinking among students in the next five years. This initiative will ensure that all government secondary school students have access to ATL facilities.

To support it further, five National Centres of Excellence for Skilling with global expertise to equip youth for manufacturing and technology sectors. As AI, technology and the type of jobs available in the market change, our youth must be trained, readied and equipped with necessary skills. It was in fact Mark Twain who had given us the secret to success. He says and I quote, "The secret to getting ahead is getting started." reminding us that India is already on her path, expanding what she started and will finish first.

The Union Budget for FY26 has increased TDS thresholds across various income sources, providing significant relief to senior citizens relying on interest income. The TDS exemption limit on interest earnings for seniors has been doubled from Rs.50,000 to 1 lakh. For other individuals, the exemption limit has been raised from Rs.40,000 to Rs.50,000 on deposit interest. This rise in TDS exemption limits will allow senior citizens and other deposit holders to retain a larger portion of their interest income, reducing tax deductions at the source. This provides financial relief, particularly for retirees who rely on fixed deposits and savings schemes for their livelihood, ensuring better cash flow and lower tax compliance burdens.

The Budget introduces several significant changes for India's elderly: doubling the TDS threshold and tax deduction limit on interest income to 1 lakh, and exempting withdrawals from old National Savings Scheme accounts on and after August 19, 2024. By exempting withdrawals from old NSS accounts after August 19, 2024, the government ensures that long-term savers, especially senior citizens, can access their funds without tax penalties.

This move enhances financial security, promotes continued participation in savings schemes, and provides liquidity without additional tax burdens. Above and beyond, the Union Budget brings notable tax reforms designed to ease the financial burden on the middle class. A major highlight is the increase in the income tax exemption limit to 12 lakh per year, significantly lowering individual tax liabilities and enhancing financial flexibility.

Additionally, the revised tax slabs offer benefits to those earning up to 24 lakh, increasing disposable income and promoting domestic spending. These changes are anticipated to drive consumption, strengthen the middle class, and solar energy got the highest allocation of Rs 26,549 crore, with a clear focus on rooftop solar with the PM Surya Ghar Yojana. This substantial increase is expected to accelerate the adoption of rooftop solar panels across households, reducing dependence on conventional fossil fuels and lowering electricity costs. In the long run, this investment will contribute to achieving renewable energy targets, spur job creation in the solar installation and manufacturing sectors, and promote environmental sustainability by cutting carbon emissions.

Along with that, the Viksit Bharat Nuclear Mission with the aim for 100 GW of non-fossil-based energy by 2047 is a clear push towards harvesting clean energy beyond solar and others presently in focus. This

significant budgetary allocation underscores the government's commitment to diversifying the energy mix and reducing dependency on fossil fuels. By investing in SMR technology and expanding nuclear capacity, the initiative is set to accelerate the development of safer, more scalable nuclear power solutions.

Initiatives like supporting and incentivising electric vehicle manufacturing with custom duty exemptions on 35 capital goods¹ for EV battery manufacturing, supporting domestic manufacturing of motors, controllers and other critical components and integration of EV manufacturing with clean tech manufacturing programmes along with a committed budget for the PM-e-drive with a sizable allocation of Rs 4,000 crore to upscale electrification of the two-wheeler and heavy-duty vehicle segments has led to a tangible wholesome EV eco- systems have come together relatively more cohesively to take an ecosystem approach to localisation of the industry. As the government aims to achieve Net Zero goals by 2070, expansion of localised-Indian manufacturing¹s of EV batteries, solar PV panels, wind turbines, etc, as well as making it a part of daily life eventually to mitigate road transport emissions.

India's medical tourism sector is set to experience robust growth-projected at 14-15 per cent, thanks to the recent easing of visa regulations announced in the Union Budget 2025-26¹⁷ The simplified visa process is expected to not only bolster India's established reputation as a cost-effective destination for medical treatments but also expand the sector beyond major metro cities into tier-2 and tier-3 regions.

In India in 2024, the Medical Tourism market was valued at 7.69 billion dollars, with around 7.3 million foreign patients seeking treatment in the country. India currently ranks 10th on the Medical Tourism Index 2020-21, largely due to the significant cost advantage-medical procedures cost 60-80 per cent less than in developed nations. The recent policy changes, including the introduction of e-visas and short-notice visas, will categorically remove all barriers, ensuring timely treatment for international patients, especially from regions like Africa and neighbouring South Asian countries as the world gears up to celebrate Health Day with Universal Healthcare, the people of India must know and understand that healthcare in India is far ahead of other countries.

As a woman of India and representative of people from an area renowned for courage, I strongly believe that "Bravery is not the absence of fear, but the conquest of it." These words resonate deeply with the essence of this budget, which embodies both courage and foresight in its approach for it is not just a

financial document; it is a declaration of intent—a vision that embraces ambition while ensuring protection, much like a warrior who steps onto the battlefield with both valour and strategy. It acknowledges the challenges ahead but does not retreat from them. Instead, it arms us with policies and mechanisms designed not just for survival, but for growth and prosperity. It does not just offer temporary relief, rather, but lays down a sustainable path for progress, ensuring that we do not merely endure difficulties but emerge stronger, more self-reliant, and future-ready.

The budget resonates with me in its qualities of fortitude, perseverance and foresight - the guiding principles my forefathers and people lived by. The budget is a step towards a future where challenges are met with solutions, where risks are mitigated with foresight, and where every individual is empowered with the means to not just cope but to truly flourish.

This budget is much more than a collection of financial figures, it is a holistic comprehensive strategy that addresses India's challenges by employing both traditional and innovative methods. While our nation is vast and diverse, the struggles of our people remain common, and this budget weaves together a series of complementary policies—from supporting farmers through both agricultural and rural development measures to integrating clean energy with nuclear power, demonstrating that giving up is not in the BJP-led government's nature. I have personally received a lot of emotional responses from my constituency for this budget. At the beginning of my speech, I mentioned how this was a journey that hon. PM Narendra Modi had started alone, but today the numbers say otherwise, it has now evolved into a movement that resonates deeply with the people.

THE MINISTER OF FINANCE; AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, it is indeed very gratifying that 78 hon. Members have spoken on this Budget-related discussion. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी सीट पर बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am very grateful that the hon. Members have chosen to get into the details of the Budget. ? (*Interruptions*) Actually, this Budget has come at a time of immense uncertainties. The change in the global macroeconomic environment makes it challenging. So, if there are

challenges which have actually made the Budget preparation with a lot more uncertainties, I have to at least put in front of the august House that there are issues which are of global concern, which also have an impact on our own Budget-making. There is a continuation of global conflict. The situation in the Middle-East, Russia-Ukraine war, stagnation in global GDP and sticky inflation in the emerging markets are all vitiating the atmosphere in the entire developing economies. ? (*Interruptions*) Actually, what is happening is, where we have ideally a situation which should encourage free trade, we are seeing more restrictions. ? (*Interruptions*) Where we very strongly vouch for globalisation, we see a lot more fragmentation. Where we need fiscal prudence, we are seeing rising debt. ? (*Interruptions*) Where we are seeing market forces which should actually play to make sure economies are going to be absolutely free and fair in its practices, we are seeing many restrictive industrial policies.

We are also seeing that where multilateral forums should be playing a greater role, we are seeing bilateral partnerships and regional forums coming into play. ? (*Interruptions*) So, the world scenario in the last 10 years has turned almost 180 degrees, as a result of which the challenges for any country in making its budget are far more complicated now than ever before.

As the first advanced estimates from the NSO have come in, India's economy is expected to grow by 6.4 per cent in real terms and by 9.7 per cent in nominal terms. ? (*Interruptions*) So, during the current financial year, this is the picture which we want to present before you. The inflation trends, particularly food inflation, appear to be moderate.

Sir, the Union Budget 2025-26 has sought to address these immediate challenges facing the domestic economy in the global context. ? (*Interruptions*) It also rolls out futuristic path for transforming India into Vikasit Bharat. Our main goals in this Budget are to accelerate growth, secure inclusive development, integrate private sector investments and uplift household sentiments. ? (*Interruptions*) So, with a focus on *garib*, youth, *annadata* and *naari*, the Budget likes to reveal new schemes and reforms in the following broad sectors: promotion of agriculture, MSMEs, investments and exports as growth engines in building rural prosperity and resilience. ? (*Interruptions*) We also want to have employment-led development spurring domestic consumption and boosting manufacturing in India, including export promotion.

Continuing public capital expenditure and rekindling the animal spirits in the private sector to step up investments, and most importantly, investing in people, investing in economy and investing for innovation -- these are actually the points on which the Union Budget is focusing so that we balance the national development priorities with fiscal imperatives -- I want to highlight here some of the budgetary outlays so that it covers most of the concerns expressed by many of the Members.

Before I even utter the outlays for each of the schemes, I want to highlight one concept that is, effective capital expenditure. What is effective capital expenditure and why do we need it? I am sure many Members of Parliament will be fully aware of it, but for the records, I would like to describe it for a minute. Effective capital expenditure includes core capital outlays and the grants-in-aid for creation of capital assets. Though the grants-in-aid for creation of capital assets is accounted as revenue expenditure in our Budget, they go for creating capital assets in the States. So, we include them when we talk about effective capital expenditure. In the Budget of 2025-26, the effective capital expenditure is projected at Rs.15.48 lakh crore as against Rs.13.18 lakh crore in the RE of 2024-25. So, the effective capital expenditure in the BE of 2025-26 is about 4.3 per cent of our GDP, that is, only 0.1 per cent of GDP, lower than the fiscal deficit of 2025-26, which is 4.4 per cent of the GDP. So, the effective capital expenditure is 4.3 per cent of GDP and fiscal deficit is 4.4 per cent of GDP. What does it indicate?

It indicates that the Government is using almost the entire borrowed resources for financing effective capital expenditure. So, the borrowings are not going for revenue expenditure or committed expenditure or any of those kinds. It is going only for creating capital assets. So, in effect, the Government intends to use about 99 per cent of borrowed resources to finance effective capital expenditure in the upcoming 2025-26 year.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): What is the outstanding debt? ? (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I will explain it, Professor. I have just begun.

The sectoral outlays in the year 2025-26 include agriculture and allied activities which get Rs. 1.71 lakh crore; rural development gets Rs. 2.67 lakh crore; urban development and transport, Rs. 6.45 lakh crore; health and education, Rs. 2.27 lakh crore, defence which excludes defence pension, Rs. 4.92 lakh crore.

So, I just want to highlight the fact that money is not being denied to any of the capital expenditure accounts because I heard occasionally this argument being put forward saying, 'has the paradigm shifted from capital expenditure because that gives a greater multiplier effect to giving people, the taxpayers, some money in their hands for boosting consumption?? No. These data from the current Budget, which is before us, show that capital expenditure outlays have not come down at all. On the contrary, they have gone up.

So, in this, most importantly, across all schemes, I want to highlight how the transfers to the States, that is, for the year 2025-26 will be to the tune of Rs. 25.01 lakh crore. I am talking about transfers to the States across all schemes, and I just want to go back to listing out how much after COVID-19, the capital expenditure is increasing, at the same time, including tax devolution, the Finance Commission grants and funds for the Centrally- Sponsored Schemes, 50-year interest-free that we give for the States. All put together, the transfer of resources to the States is growing by the year. In 2020-21, it was Rs. 13.44 lakh crore, which is an increase from the previous year, that is, 2019-20, where it was Rs. 13.19 crore. In 2021-22, it rose to Rs. 13.40 lakh crore. It was Rs. 4,000 crore slightly less because of COVID-related issues, although we targeted a higher number. But in 2022-23, it was Rs. 15.56 lakh crore, which is Rs. 2.16 lakh crore more than the previous year. And that is the year when we brought in the 50-year interest-free loans for States. In 2023-24, it was Rs. 17.98 lakh crore, which is again Rs. 2.42 lakh crore more from the previous year. In 2024-25, it was Rs. 22.91 lakh crore, which is Rs. 4.93 lakh crore more. And this year, in the Budget which is before us, it is Rs. 25.01 lakh crore, which is Rs. 2.1 lakh crore more than the previous year. So, the amounts going to the States have not come down at all.

Sir, I will seek your indulgence. I want to highlight the thought and the philosophy behind our Government's Budget-making processes and also how in the last 5-6 years, we have set clearly some practices which are, I would think, very important from the point of view of fiscal management. So, allow me to just go through some of the points. It has been a conscious policy choice because it is part of our governance priorities, its commitment to fiscal discipline. So, India's development story actually presents a stark tale of two opposite approaches to Budget-making and also for fiscal prudence.

There were the global financial crisis of 2008 and once in a century 2020 COVID pandemic. But what happened after 2008 led us to become a 'Fragile Five' country. Whereas what is now happening

is that you see, we continue to remain the fastest growing economy. I want to highlight some of the very critical steps that we have taken in the fiscal prudence approach and also in Budget-making. Under this Government, India transited from the league of 'Fragile Five' to become one of the top five economies of the world. In 2020-21, we had the devastating pandemic. The Union budgeting reveals recurrent claims of transparency. Since that year, you will find that our themes, which are recurring, are transparency in the Budget-making and also credibility of Budget-making, reforms to catalyse growth, targeted social security and use of technology for obtaining value for public money.

I will just give two examples, or sometimes even one example for each year. In 2020-21, we took a giant step of bringing onboard the FCI off-Budget borrowing of Rs.1.2 lakh crore. The Food Corporation of India had continuously maintained off-Budget borrowings. That year, we took a major step of bringing all the off-Budget borrowings of FCI, which totalled to Rs.1.2 lakh crore, onto the Budget. So, that enabled better public understanding and discourse on Government debt and also brought in a sense of credibility to the Budget documentation itself. That year ? another step ? we have also partnered with the States to deepen the multiplier effect on capital spending by providing them with the 50-year interest free loan. From an allocation of Rs.12,000 crore in 2020-21, it has now, in the current Budget, reached Rs.1.50 lakh crore. So, it is not just us believing in multiplier effect by spending on capital asset building, but we have partnered with the States. The States are really, actually, speedily coming up with a lot of proposals, which is very, very good. We are able to give them that kind of a money to support their proposals. In 2021-22, the year after that ? again I would like to highlight two steps ? the Ministry of Housing and Urban Affairs' off-Budget borrowing was also taken on board.

We brought on record the off-Budget borrowing of MoHUA of Rs.33,000 crore on the books of the Government by prepaying it. So, we brought it on books and we prepaid it. That is a major initiative that we have taken to make sure the Budget's transparency, and nothing outside of the Budget will be done. That was the second major step. The first year, it was FCI. The second year, it was MoHUA. That year again, for just in time release and transparency in flow of funds to the States, the Single Nodal Agency model was introduced. So, the taxpayers' money goes to the States just in time for them to use the money. There is no difficulty in that kind of a quick disbursal of resources. That is the second major step for 2021-22.

In 2022-23, there was debt consolidation of agencies for better fiscal planning on borrowings. Professor was very worried about the borrowing, the debt and everything else. This is one of the points which I want Professor to consider as to why consistently between 2020 and 2021 we are taking measures to reduce debt and at the same time, make public money go for productive asset building activities. We commenced financing of capital outlay of Railways and Highways from the Union Budget that time in 2022-23. This allowed for debt consolidation, particularly, the Railways? debt consolidation began happening from that year of these agencies and helped lower cost of borrowing. As borrowing by the Government is cheaper than borrowing by agencies, so there was efficient use of money. There also we have shown that this kind of a step can actually better utilise the taxpayers? money.

In 2023-24, one big step was recognising the taxpayers by easing tax rates. The New Tax Regime was made the default tax regime with new slab structure and with reduced tax rates. Also, the rebate limit was raised until Rs.7.27 lakh annual earning with marginal relief also given until Rs.7.27 lakh where no tax was payable at all. This year, of course, it has gone to Rs. 12 lakh.

The fifth point which I want to say is this. In 2024-25, we empowered the Ministries with a proposal which was suggested by the PAC, which was very actively looked into by the Public Accounts Committee. And then, we consulted the C&AG, and then, we brought in a revision of new service and new instruments of service limits. This is the fourth time since Independence that a major step of this kind has been brought in with substantially enhanced financial delegation to improve operational efficiency in Ministries. Otherwise, for small amounts, they had to keep coming for permission-seeking and so on. That has been cleared. The Ministries are more empowered now. And therefore, the decisions and disbursements of money happen quickly.

This year proactive disclosures, realistic estimation, and ensuring greater predictability are the steps that we have taken. I draw the attention of the hon. Members to the statement in 4AA ? the expenditure profile. Many Members would have seen it but I still draw their attention to this particular thing which outlines the SNA balances with States in select schemes. It is an important thing on which I want to draw the attention of the hon. Members. This brings to the fore, for the implementation challenges of the States, the need for action to remedy at the State level. What I want to highlight here is that not only the Centre but also the States will have to look at debt consolidation and also rationalise their debt balances.

And therefore, we have outlined a debt consolidation pathway for the Union Government till March, 2031, and this would give some kind of a guidance to the markets with greater predictability also. So, that is an important step I want to highlight. In the last five years, you see certain underlying currents in the Budget preparation, and the contents of the Budget also being transparent, and, therefore, it speaks strongly for the Budget being a very reliable document. It reinforces the sanctity and also the credibility of the Budget process itself. So, I thought that it is important to draw the attention of the hon. Members.

Sir, now, I move to the issues which have been raised by the hon. Members. I have broadly grouped them, and, therefore, instead of going by Member by Member, issues raised by three or four Members have been grouped together and I speak in response to their issues. ? (*Interruptions*)

Sir, there was this concern on rising unemployment, especially among youth. I have got a list of about 11 hon. Members who have spoken on it. I want to highlight the fact that according to the 2023-24 Annual Periodic Labour Force Survey, the Labour Force Participation Rate has increased from 49.8 per cent in 2017-18 to 60 per cent in 2023-24, reflecting a rise of about 10.3 percentage points.

The Worker Population Ratio has increased from 46.8 per cent in 2017-18 to 58.2 per cent in 2023-24, reflecting a rise of 11.4 percentage points.

Unemployment rate has declined from six per cent in 2017-18 to 3.2 per cent in 2023-24.

Sir, about Rozgar Mela, in which the hon. Prime Minister hands over employment letters/appointment letters, over 9.25 lakh appointment letters have been issued for the Central Government jobs in 14 editions which have been held till date from October, 2022.

Sir, now, I come to the concerns about high inflation, especially food inflation. Inflation management, Sir, actually receives the highest priority of this Government. Overall retail inflation is within the notified tolerance band of 2-6 per cent. And, there are very many parameters which we keep monitoring so that at affordable rates, food materials are distributed to people. I have said this before. I will repeat some of them again. I just want to highlight the fact that food inflation which was affected because of adverse weather conditions or supply chain disruptions have all been attended to. We are still continuing to do it.

The water levels in reservoirs are also being monitored. It has improved so that water adequacy for irrigation for Rabi crop production is ensured. As of 23rd January, the reservoir level was 66.1 per cent of the current live storage capacity.

As per RBI's latest meeting of the MPC that they held on 7th February, CPI inflation for 2025-26 is projected lower at 4.2 per cent.

I have just one or two highlights. It is important for us to understand that double digit headline inflation over ten per cent seen during the UPA regime is not the case now. It is a thing of past. I want that to be clear. NDA 1999-2004, food inflation was only 2.2 per cent. UPA ? I 2004-2009, food prices soared to 6.5 per cent creating pressure on household budgets. UPA-II 2009-2014, food inflation reached staggering 11 per cent causing severe hardship for the public. NDA 2014-2024, food inflation was brought down to 5.3 per cent indicating a robust focus on supply chain improvements and agricultural reforms.

Sir, fuel inflation under UPA-II was 8.9 per cent compared to NDA 2014-2024 which is at 4.4 per cent highlighting better management of global price volatility under NDA.

Sir, now I come to LPG cylinders. Before April, 2014, nearly 45 per cent of Indian households did not have access to clean cooking fuels. In contrast, the LPG coverage under NDA has reached near saturation. Total domestic active LPG customers have more than doubled from 14.52 crore in April, 2014 to 32.89 crore as of December, 2024. After a targeted subsidy of Rs. 300 a cylinder for PM Ujjwala Yojana consumers, the Government of India is providing 14.2 kg LPG cylinders at an effective price of Rs. 503 per cylinder in Delhi which is available for more than 10.33 crore Ujjawala beneficiaries across the country. So, under the PM Ujjwala Yojana, Sir, the refill rate about which I think one or two Members mentioned that is per capita consumption is 4.4 cylinders in a year.

Sir, about this, ?oh do you not see it on the ground, prices are going up??, and so on, the measures the Government of India had taken are very important and even in this Budget, I have taken steps to say we should have better productivity in agriculture, we should also have vegetables and fruits grown so that the supply side problems can be better administered.

PM Dhan Dhanya Krishi Yojana Developing Agricultural Districts Programme is a very important one where hundred low productivity agricultural districts are being focussed and we are going to build those

districts. Like the way hon. PM gave attention to aspirational districts for social welfare indicators, so shall we do on agricultural productivity in these hundred districts where the productivity now is very low.

So, we will do this for agricultural productivity in these 100 districts where the productivity now is very low. Atmanirbharata in Pulses, Comprehensive Programme for Vegetables and Fruits, National Mission on High Yielding Seeds ? these are the steps which we have taken in this Budget. We are making efforts. Other than that, there are Bharat Dal brands, and other schemes where we do distribution of onions. Under the Bharat Chana Dal Phase II where three quarters have gone, 76,300 tonnes have already been sold. The total quantity which we want to reach is 13.08 lakh tonnes. Under ? Bharat Atta?, 88,000 tonnes have already been sold, and 16.08 lakh tonnes is what we want to target so that affordable atta and chana dal can reach the common people. Similarly, under Bharat Rice, 45,000 tonnes have already been distributed, and 15.03 lakh tonnes more will be distributed. Under Bharat Chana Whole, 7553 tonnes of have already been sold. Likewise, 6,637 tonnes of moong dal have already been sold, and in Rabi Season of 2024, 85,524 tonnes of onion have already been sold at an affordable price. It means, the onion has been sold at Rs.35 per kilogram, and people are benefiting by these steps.

Sir, I want to come to the third point on which several hon. Members have spoken regarding depreciation of the Indian rupee and I want to respond to that. Various domestic and global factors influence the exchange rate of Indian rupee, such as the movement of dollar index, trend in capital flow, level of interest rates, movement in crude prices, current account deficits, etc.

So the currency volatility across major countries is really extensive and you can get information on that. The US dollar index rose by 6.5 per cent from October, 2024 to January, 2025? (*Interruptions*) मैं उस विषय पर भी आ रही हूँ। ? (व्यवधान)

Major Asian currencies such as South Korean Won, Indonesian Rupiah, and Malaysian Ringgit all were depreciated by 8.1 per cent, 6.4 per cent and 5.9 per cent respectively in this period.

G10 currencies also were depreciated during this period by more than 5.5 per cent. For instance, Japanese Yen was depreciated by 7.0 per cent, British Pound was depreciated by 6.6 per cent, and Euro got depreciated by 5.8 per cent. This is even acknowledged by ? it might be helpful to quote ? the former RBI Governor, Shri Raghuram Rajan who even participated in the Bharat Jodo Yatra. Shri Raghuram

Rajan Sir, former RBI Governor, on 15th January, 2025 said and I quote? (*Interruptions*) yes I quote it. We will quote all of them. Do not worry. Yes, I will quote all of them in the context.

Now, this is the context in which I want to quote it? (*Interruptions*) Sir, have the patience to listen? (*Interruptions*) You can always question me? (*Interruptions*) You questioned almost for three days. I am giving my reply. You should have the patience and endurance to listen. Shri Raghuram Rajan Sir has commented and I quote: ?The fixation, of course, always is with the rupee-dollar exchange rate. The reality is the dollar has been strengthening against many currencies. If you look at the Euro, the dollar could buy 91 cents at the beginning of last year, and now it buys 98 cents.?

??So, that is about a six per cent to seven per cent depreciation in the Euro. That is what happened with Indian rupee, with it becoming 83 to 86, maybe even a little less than what has happened to the Euro, so it is really a dollar issue.?

I really quote. I continue, it means what it says. ? (*Interruptions*) It means what it says, if they refuse to understand it, I cannot help them. ? (*Interruptions*) Every Member seems to understand. They do not want to understand. ? (*Interruptions*) Sir, I am quoting again:

?The dollar is strengthening partly because of the thought that the new administration with applied tariffs the deficit may go down. The trade deficit for the US, that will strengthen the dollar. There is also some potential safe-haven buying at this point into dollar assets. So given all that, I would not be overly worried.?

So, he said about the Indian rupee, and he is not worried, whereas our people here are more worried about rupee depreciating. ? (*Interruptions*) When I said the dollar is appreciating and the rupee is remaining stable, they said: ?Oh! What? This is not an explanation.? Now, when Raghuram Rajan says it, they do not want to hear it. ? (*Interruptions*) Raghuram Rajan continues, and further says: ?If you look at the real effective exchange rate of the rupee, it has not depreciated that much.? So, that is what it means. He summarised it in one sentence. ? (*Interruptions*) ?If you look at the real effective exchange rate of the rupee, it has not depreciated that much. Some nominal depreciation might be useful for exports.? ? (*Interruptions*) They do not want to accept it because it does not suit them. ? (*Interruptions*)

Sir, there are other points like decline in household savings, and increase in household debt. At least, three or four Members have spoken about them. I want to say some facts for them. The household

savings, consist of net financial plus physical savings, increased by a compound average growth rate of 8.9 per cent CAGR from 2019-20 to 2022-23. There is a reallocation of savings by households to real assets. In the post-COVID period, household real estate investments have increased considerably. The share of savings in physical assets in gross household savings has steadily increased from 30.8 per cent in 2015-16 to 42.7 per cent in 2022-23. So, according to the National Accounts Statistics, household savings in physical assets have increased by a compound average growth rate of 15.6 per cent from 2019-20 to 2022-23.

Sir, as far as slash in public spending is concerned, I have addressed this issue a bit earlier, but I want to say this again. The total expenditure of the Union Budget in 2025-26 is to be about Rs. 50.65 lakh crore, which is higher by about Rs. 2.44 lakh crore and Rs. 3.49 lakh crore than 2024-25 BE and RE of 2024-25.

With regard to the capital expenditure, I would reiterate here this point because many people seem to think that capital expenditure has come down. It is not like that. The capital expenditure was Rs. 11.11 lakh crore last time, and now it is Rs. 11.21 lakh crore. ? (*Interruptions*) So, it has only gone higher, and as I said earlier, the effective capital expenditure for 2025-26 is pegged at Rs. 15.48 lakh crore.

Now, I come to the net additional expenditure. This is important, and I would like to seek the attention of the House. The net additional expenditure of Rs. 2.44 lakh crore, which is higher in BE 2025-2026 over 2024-2025, is mainly going to finance three major items, which are, interest payments ? Rs. 1.13 lakh crore; Central sector schemes ? Rs. 1.06 lakh crore; and Centrally sponsored schemes ? Rs.0.35 lakh crore.

Sir, again, with your indulgence, I seek hon. Members' attention on this point. We also had the onerous burden of repayment of oil, fertilizer and FCI bonds raised during the UPA era. The UPA-time oil bonds, UPA-time fertilizer bonds and FCI bonds are being repaid now. ? (*Interruptions*) This year, in the Budget which is before us and in the coming year, we will be paying just the interest and not the principal amount. And, what is the interest? In the current year 2024-2025, Rs. 5,946 crore has just gone for interest on oil and FCI bonds taken during their time. ? (*Interruptions*) Now, Rs. 3,524 crore will go just for the interest in 2025-2026 Budget. Actually, what is the principal? Just for the record, the principal due in 2024-25 is Rs. 44,701 crore. In 2025-2026, the principal is Rs. 40,464 crore. So, let us not forget debt

considerations and worries about debt. Money is going for interest payments, and Professor should take cognisance of the fact.

Sir, also, I just want to highlight this point. For instance, public spending outlays in health, education, social welfare, rural development have increased from Rs. 4.16 lakh crore to Rs. 5.54 lakh crore between 2020-21 and 2025-2026. So, there is no cut in any of these. Repeatedly, we have people asking questions. It is okay to ask questions. I am giving you the answer that nothing has come down there.

Sir, fiscal consolidation was another issue on which many Members were worried, asking whether it is being done at the cost of public spending and social sector spending. It was said that education budget has been reduced, and the budget for PM POSHAN, Jal Jeevan Mission, PM Awas Yojana, and Post Matric Scholarships have come down. I would like to answer all of them.

Sir, with respect to social welfare, the budget has increased from Rs. 56,501 crore in 2024-2025 to Rs. 60,052 crore in 2025-2026. It has not gone down. ? (*Interruptions*) I will come to that also. ? (*Interruptions*)

Sir, coming to education, the budget has increased from Rs. 1.26 lakh crore in 2024-2025 to Rs. 1.29 lakh crore in 2025-2026. एजुकेशन का भी बजट कम नहीं हुआ बल्कि ज़्यादा हुआ है । ? (*व्यवधान*) Talking about health, the budget which was Rs. 89,287 crore in 2024-2025 has gone to Rs. 98,311 crore in 2025-2026.

Sir, I would like to highlight one point at this time. Again, it is the substantive budgetary technicality, but it is important because the technology which has been adopted for Budget and Budget management has today given all of us the advantage of getting facts by looking at the portal or by looking at the documents. Nothing can be hidden in this day and age because of technology. Therefore, I would like to draw the attention of the hon. Members to a statement which has been provided called the Expenditure Profile. It is the Statement 4AA. I want to show how the unspent balances are remaining and how much is the unspent balances totalling to. It is Rupees one lakh crore as of 31st December 2024.

How much unspent balances are remaining, and the Expenditure Profile Statement is here for us to see? This is along with the Budget. It has already been presented. An amount of Rs.1,395.45 crore is

lying either in the SNA account or in the treasury or in an escrow account in the States. This much money is lying there on the Rashtriya Krishi Vikas Yojana head of account. This is yet to be utilised.

An amount of Rs.4,636.55 crore is lying in the States in terms of Assistance to State Agencies for Intrastate Movement of Food Grains and the FPS Dealers Margin under the National Food Security Act (NFSA). Many hon. Members are really, really concerned and I can understand the concern. But if money is lying in the accounts, if you just give the utilisation or show the rates, the bills, you get the money. It is in your SNA account there. Please take it. It is already in your account. But no, you are not giving money for Food Security Act. Why not? We are giving the money. It is there. Would you like to use it? This is a Statement attached to the Budget documents. I would like the hon. Members to see where the money is lying, and despite that, more is being asked. You ask more, there is no problem. The moment you use this, we will give more.

The next head is Samagra Siksha. An amount of Rs.11,516 crore is lying there in the States. Would you please use it?(Interruptions)

There was a lot of concern on Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman, the erstwhile National Programme for Midday Meal in schools. An amount of Rs. 5,205 crore is lying in the State accounts, and this is for Poshan Abhiyan. Here, I hear voices कि ?प्रधान मंत्री जी, बच्चों के न्यूट्रिशन के ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है ।? पैसे आपके अकाउंट्स में हैं, आप यूटीलाइज़ कीजिए ।? (व्यवधान) हमने तो पैसे दे दिए, आप उसे क्यों नहीं यूटीलाइज़ कर रहे हैं?? (व्यवधान) उसके पहले आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं?? (व्यवधान)

So, go use it. This document is available. Have a look at it if I am saying anything abrupt. (Interruptions) These are not *chota-mota* amounts. These are big amounts. I want to ask questions, therefore.

Sir, next one is NRHM-RCH Flexible Pool. I have heard the hon. Health Minister, Shri Jagat Prakash Nadda ji.(Interruptions) No, Supriya ji, you can always ask me all the questions. But I have heard you all, and I want to come up with my answer. Please have patience, and you may ask me again. But if I am telling you anything which is not already available with you, I will be ready to answer. But it is there. (Interruptions)

SHRI RAJEEV RAI (GHOSI): What is the proof?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: What proof? हे भगवान! ? (व्यवधान) यह सब बजट डॉक्यूमेंट में है।? (व्यवधान)

Sir, Flexible Pool for RCH health system, strengthening the National Health Program and the National Urban Health Mission. How much is left in the accounts? An amount of Rs.2,988 crore is lying with the States.(Interruptions)

*m122 श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : माननीय मंत्री जी, आप यू.पी. के बारे में बताएं।? (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण : हाँ, हाँ, बता दूँ? ? (व्यवधान)

Next, I have heard questions being asked of the Health Minister. I have heard the Health Minister trying to respond, ?No, I am giving teachers. No, I am giving paramedical staff. No, we are funding?. Do you know how much money is left there? Under Human Resources for Health and Medical Education, an amount of Rs.7,059 crore is lying in the State account. Would they please use it?(Interruptions)

Sir, next is, Swachh Bharat Mission. Sometimes they raise questions saying, ?Was it necessary for the hon. Prime Minister to speak about Swachh Bharat on the ramparts of Red Fort?? He spoke, and he is carrying the mission forward, and as a result, the World Health Organization has said that health has improved among women and children.

I want to show how much money is left with the States in the Swachh Bharat Mission ? Urban. An amount of Rs. 12,319 crore is with the States. Please spend it. They are very concerned about urban. ? (Interruptions) Do not worry. Hear me out. There is the Urban Rejuvenation Mission which was launched in 500 cities. They are worried about urban unemployment. I want to ask this question. An amount of Rs. 12,377 crore is lying with the States. Will you use it for that? ? (Interruptions) Listen, I will give you answers.

There were a lot of comments about Jal Jeevan Mission. The hon. Minister is sitting here. Patil *sahib* is sitting here. They asked questions saying, ?Why Jal Jeevan Mission gets a small allocation?? It is because we are reaching the saturation level and only for the new leftovers we are giving money. But you will be astonished to hear how much money is left on Jal Jeevan Mission with the States! An amount of Rs. 13,782 crore is lying with the States. ? (Interruptions)

Sir, I am not letting this list go. So, pardon me. They say about many poor people ? *(Interruptions)* We want people to hear. ? *(Interruptions)* They will know this also. They talked about PM Awas Yojana ? Gramin and Urban. They did not have any number. An amount of Rs. 14,000 is left with the States for Gramin. For Mahatma Gandhi National Rural Guarantee Programme, Rs. 4,351 crore are lying with the States. ? *(Interruptions)*

Sir, if you allow me, since there are some points, I would like to point them out. ? *(Interruptions)* Do not worry. I will come to it. I have heard you for three days. I am giving you a reply. You should have the patience to hear, Kanimozhi ji. ? *(Interruptions)* Sir, I respect hon. Member, Kalyan Banerjee. I have a lot of patience hearing whenever he stands to speak. But I also want him to have that patience when I speak. I request him. ? *(Interruptions)*

Sir, Kalyan Banerjee ji is somebody who I listen to patiently because he passionately speaks about West Bengal. I have absolutely all respect for him. But here are some things which I have to speak because his leader who spoke that day mentioned some things. He was here. I was also there listening to his leader. I want to point out some things. ? *(Interruptions)*

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Madam, I know you will only speak against West Bengal. What else can you do? ? *(Interruptions)* You will speak against West Bengal. ? *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाओ, गरिमा बना कर रखो ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी गरिमा बनती है, लेकिन आप फिर बिगाड़ लेते हो । बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी गरिमा बनती है, लेकिन थोड़े दिन बाद आप फिर बिगाड़ लेते हो ।

? (व्यवधान)

17.68 hrs

At this stage, Shri Sudama Prasad and some other hon. Members left the House.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): You give us the details of all the States. ? *(Interruptions)*

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am giving the details. ? (*Interruptions*) Very well said. ? (*Interruptions*) I am going to say that. ? (*Interruptions*)

18.00 hrs

SHRI KALYAN BANERJEE: What about West Bengal? ? (*Interruptions*) Why West Bengal has been targeted by you? ? (*Interruptions*) Why are you targeting West Bengal all the time? ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रेशर थोड़ा कम करें।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: थोड़े दिन रेप्यूटेशन बनती है, फिर आप बिगाड़ लेते हैं।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, आप बैठिए।

? (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: Why are you biased against West Bengal? ? (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am biased against West Bengal! ? (*Interruptions*) Please, that is not right. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। प्लीज, नो डिबेट।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, अगर सभा की सहमति हो तो सभा की कार्यवाही माननीय वित्त मंत्री जी के उत्तर तक बढ़ा दी जाए।

अनेक माननीय सदस्य: जी हाँ।

? (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: It was said, ?Tell me about my State, it is a biased Budget, etc.?. I will come back to speaking also specifically, as was requested by hon. Member, Shri Kalyan Banerjee. ? (*Interruptions*) But before that, Dr. Dharamvira Gandhi ji, who started the debate, raised a lot of points,

and he was followed by many other Members. I would like to answer some of them. I have already mentioned that the amount for capital expenditure, being given, is increasing steadily every year. It is not as if the projects are not happening in the States.

Sir, 38 National Highway projects were sanctioned for Punjab in three years for development of 825 kms. amounting to Rs. 22,160 crore? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए।

? (व्यवधान)

श्रीमती निर्मला सीतारमण: आप जरा सुनिए।? (व्यवधान) पिछले हम तीन साल से 22 हजार करोड़ रुपये पंजाब में सड़क बनाने के लिए ही दे रहे हैं। 38 National Highways were sanctioned for Punjab with Rs. 22,160 crore? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आप वकालत करना छोड़ दीजिए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप किसी माननीय सदस्य का नाम ही मत लीजिए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इनका आप कोई जवाब मत दीजिए।

? (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: No, I am not giving him any response. ? (*Interruptions*) I am telling you. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, आप बैठिए।

? (व्यवधान)

SHRI KALYAN BANERJEE: Why should I hear the reply? ? (*Interruptions*) Let her speak in front of her own Treasury Bench. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: आपने भाषण दे दिया है। अब आप मंत्री जी का जवाब सुनिए।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप सुनना नहीं चाहते हैं?

? (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी : हाँ, मैं सुनना चाहता हूँ।? (व्यवधान)

HON. SPEAKER: No.

? (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, as regards Telangana, the Kakatiya Mega Textile Park in Warangal was announced as PM Mitra Mega Textile Park in August, 2024. The Union Cabinet approved the industrial node. There is also an industrial node in Zahirabad under the National Industrial Corridor Development Programme. So, that is one of the examples that I can give.

For Kerala, the Union Cabinet approved an industrial node in Palakkad in August, 2024. Sir, 1,300 kms. of National Highways were constructed in Kerala since 2014. Then, 1,126 kms. of National Highway corridors are being developed under the Bharat Mala Pariyojana in Kerala. I have just given an example.

As regards Karnataka, 5,213 kms. of National Highways were constructed in Karnataka since 2014. Seven airports have been operationalised in Karnataka since 2014. We have constructed 1,652 kms. of new railway tracks in Karnataka since 2014.

As regards Tamil Nadu, the Chennai Metro Rail Project Phase ? II was approved under the Central-sector project with a total of Rs. 63,246 crore, of which 65 per cent is by the Central Government.

I have given you some examples of Kerala. ? (*Interruptions*) I read that first. 4,100 kms of National Highways have been constructed in Tamil Nadu since 2014. The PM Mitra Mega Textiles Park has been announced in aspirational district, Virudhunagar. I have few examples of Tamil Nadu and Himachal Pradesh. The world's longest highway tunnel, Atal Tunnel, in Rohtang was constructed in 2020. The AIIMS Bilaspur was inaugurated in 2022. 1,247 kms of National Highways were constructed in Himachal Pradesh since 2014. The Union Budget 2024-25 said, ?Himachal Pradesh suffered extensive losses due to floods last year. Our Government will provide assistance to the State for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance.

Jharkhand Purvodaya Initiative was announced in the Union Budget 2024-25 for all-round development of the eastern region of the country. In October 2023, the Union Cabinet sanctioned the completion of the North Koel Reservoir Project at a revised cost of Rs. 2,430.76 crore. Sir, 2,444 kms of National Highways were constructed in Jharkhand since 2014. ? (*Interruptions*)

Again, there is a lot of concern about debt. I partly addressed it. I will address it even more. ? (*Interruptions*) I am coming to West Bengal. Please wait patiently. About high debt, there is a lot of worry. I want to say that, on account of pandemic, the Central Government fiscal deficit reached 9.2 per cent, 61.4 per cent was the debt level to the percentage of GDP. But we have made strides and efforts to bring down both fiscal deficit and also the debt to GDP. Since then, the fiscal deficit and debt percentage have been brought down. Now we have 4.4 per cent of the fiscal deficit number, which is already put in place for 2025-2026. And for debt to GDP, we have said that we will bring it down to 50 per cent plus minus one per cent by 2030-31, clearly showing that the debt of the country will come down. The Central Government's debt will come down and come down to the level which has been suggested by the Committee which went into debt management, both of the Centre and States. What has been suggested is what we are indicating. ? (*Interruptions*)

I want the hon. Members to appreciate the fact that the liabilities of the Central Government are mostly domestic liabilities in nature with a small portion, which is 3.4 per cent of the total liabilities at book value, which are external sector-related. So, it is a downside risk because if a big number is attributed to external debt, then there will be a concern but our external debt is not big. I want that to be appreciated by the hon. Members.

माननीय अध्यक्ष : आपने कहा है कि सब सदस्य सराहना करें।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I want to highlight the fact that the amount being given at different stages for different support for public sector undertakings are kindly to be recalled. If huge amounts are going from the Central exchequer, they are going for valid causes. One example I want to give for the hon. Members. During the UPA regime, the BSNL's market share had fallen from 19 per cent in 2005 to just 7.96 per cent in 2015. Repeatedly, questions are being asked about public sector undertakings like BSNL. I want to show what BSNL was like when they left and what has happened to it today. I will show with money. ? (*Interruptions*) Due to delay in tenders, BSNL was forced to pay

Rs.18,499 crore for spectrum. When they were in no position to pay at all, they were compelled to pay. As a result, they went into deep debt themselves. ? (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE: Why do you keep comparing with UPA? ? (*Interruptions*) You tell us what was the tax collection in 2024 and what it is now. ? (*Interruptions*) What are those figures?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am telling for now. Mr. Kalyan Banerjee, give me an opportunity. I am showing what I have done in numbers. ? (*Interruptions*) In 2019, Rs.69,000 crore were given and the debt was restructured via sovereign guarantee bonds. There was administrative allotment of spectrum for 4G; they could not even make the BSNL have 4G. They went away. I am not talking about them. What have I done? Rs. 69,000 crore were given in 2019. In 2022, how much did I give for the second revival? Please listen, Mr. Kalyan Banerjee. ? (*Interruptions*) Rs.1.64 lakh crore were given to BSNL. Rs. 69,000 crore, Rs. 1.64 lakh crore, and capital formation through capital infusion were given. Merger of the Bharat Broadband Nigam Limited with BSNL was done. ? (*Interruptions*) So, with the merger of the Bharat Broadband Nigam Limited with the BSNL, we have strengthened their hands, resulting in operating profits from 2021-22 and reduction of BSNL, debt from Rs.32,944 crore to Rs.22,289 crore. In the third package for BSNL in July 2023, Rs.89,047 crore were approved for BSNL capacity for pan-India 4G and 5G. Sir, 50,000 indigenous 4G sites nationwide have been launched by the BSNL. That is the capacity of the BSNL today. For the first time in India, India has developed her own 4G technology stock that will be rolled out by the middle of this year.

The Members said, I have reduced the allocation for the Ministry of Minority Affairs. The budget for Ministry of Minority Affairs has increased from Rs. 3,183 crore in 2024-25 to Rs.3,350 crore in 2025-25. There is no reduction in the budget for the Ministry of Minority Affairs.

The Members said the subsidy for food and fertilizers has been reduced. I want to highlight that major subsidies for food, fertilizers, and petroleum have increased from Rs.3.81 lakh crore in 2024-25 to Rs.3.83 lakh crore in 2025-26.

Sir, I seek your permission for the hon. Members to know that in 2023-24, the Government had infused Rs.11,000 crore equity in the Food Corporation of India so that they have the capacity to run the institution, and if anything is borrowed from market, it will help.

With regard to fertilizer subsidy, in 2024-25, Rs. 1.64 lakh crore fertilizer subsidy was given, which has been increased to Rs. 1.68 lakh crore in 2025-26. In addition, I have announced that Atmanirbharta and urea production will happen. The Government had reopened three dormant urea plants in the Eastern region, and now a 12.7 lakh metric tonnes annual capacity urea plant has been opened in Namrup in Assam. ? (*Interruptions*)

PROF. SOUGATA RAY : Madam, please come to West Bengal. ? (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Yes, Professor. ? (*Interruptions*) Sir, before I go to the specific points on West Bengal, which were raised, I want to list out the things that we have done for West Bengal, like I did for Kerala, like I did for Jharkhand, like I mentioned about Punjab, since hon. Member Kalyan Banerjee is very keen. ? (*Interruptions*) The AIIMS in Kalyani was inaugurated in West Bengal in February, 2024. ? (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE: Kalyani is tagged as a sub-divisional hospital. ? (*Interruptions*)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: You asked me and I am reading out the whole list. ? (*Interruptions*) After I finished, you can speak. ? (*Interruptions*) Sir, for railways, West Bengal received a record allocation of Rs. 13,955 crore for rail infrastructure. ? (*Interruptions*) 1,293 kilometres of new railway tracks were constructed since 2014 in West Bengal. ? (*Interruptions*) Nine Vande Bharat trains got operationalised for West Bengal. ? (*Interruptions*) 101 railway stations were being redeveloped under the Amrit Bharat Station Scheme for West Bengal. ? (*Interruptions*) The first Gati Shakti cargo terminal was commissioned in Asansol division. ? (*Interruptions*) In June 2024, the Union Cabinet approved Jamshedpur- Purulia-Asansol third line. ? (*Interruptions*) Sir, if this is for Railways, we will go to Metro. ? (*Interruptions*)

Sir, 38-kilometre metro line was constructed since 2014 at a cost of Rs. 23,050 crore for West Bengal. ? (*Interruptions*) Coming to roadways, over 2,309 kilometres of National Highways were constructed in West Bengal since 2014. ? (*Interruptions*) In August 2024, the CCEA approved four lanes, Kharagpur-Moregram National High-Speed Corridor, 231 kilometres, at a capital total cost of Rs. 10,247 crore in West Bengal. ? (*Interruptions*) Regarding airways, in August 2024, the CCEA approved the development of a new civil enclave at Bagdogra airport, Siliguri, West Bengal at an estimated cost of Rs.

1549 crore. Operationalisation of Durgapur airport in 2019 and Cooch Behar airport in 2023 was done under the RCS-UDAN Scheme. Revamping of Bagdogra and Barrackpore airfields was done at a cost of Rs. 500 crore in West Bengal. In regard to social infrastructure and efforts for West Bengal, in that direction, 38 lakh houses were built for the poor under the PM Awas Yojana. ? (*Interruptions*) 93 lakh tap water connections were provided under the Jal Jeevan Mission in West Bengal. ? (*Interruptions*) 83 lakh household toilets were built under the Swachh Bharat Mission in West Bengal. ? (*Interruptions*) 494 Jan Aushadhi Kendras were operationalised in West Bengal. ? (*Interruptions*) 5.3 crore Jan Dhan accounts were opened in West Bengal. ? (*Interruptions*) Five crore mudra accounts have been sanctioned for West Bengal. ? (*Interruptions*)

Sir, I want them to be a bit more patient. I have more things to say for West Bengal. ? (*Interruptions*) Please wait. I have more things to say about West Bengal. ? (*Interruptions*) I was listening to the speaker from West Bengal. He said that it is West Bengal *virodhi* Budget. I want to address that. ? (*Interruptions*)

West Bengal MPs spoke about financial blockade. ? (*Interruptions*) They charged us with the financial blockade allegation. Like every other State, the PM Awas Yojana ? Gramin is being implemented in West Bengal since 2016-17. ? (*Interruptions*) The Government has released Rs.25,798 crore as Central share to the States since 2016-17. It is gone. However, complaints of irregularities in the implementation of the PM Awas Yojana ? Gramin, including a selection of ineligible households from 2018 Awas Plus, removal of eligible households and branding violations were received. ? (*Interruptions*) There have been similar complaints about MGNREGA. The Ministry of Rural Development is engaging with West Bengal. ? (*Interruptions*)

Now, I come to the specific data. It is ironical that ?Trinamool? ? which means grassroots, the Trinamool Congress prides itself on being rooted in the grassroots ? now symbolises harassment and denial of rights to the common people at the grassroots. ? (*Interruptions*) I will give you examples for that. Sir, 25 lakh fake job cards are there in MGNREGA. Funds meant for people at the grassroots have been looted by the cadres. ? (*Interruptions*) There is Rs.100 crore Mid-Day Meal fraud. ? (*Interruptions*) Ration mafia is thriving in the State at the grassroot level. ? (*Interruptions*) Ayushman Bharat was

blocked, and they denied healthcare for the poor living in the grassroot. ? (Interruptions) There is 43 per cent tap water coverage in West Bengal as opposed to the 74 per cent national average. ? (Interruptions)

Sir, it is important. Capital formation crashed from 6.7 per cent in 2010 to 2.9 per cent in the recent years. ? (Interruptions) There are no jobs, no factories and no mission. That is West Bengal for you. ? (Interruptions) West Bengal was the industrial powerhouse with 24 per cent share. In 1947, during Independence, West Bengal had 24 per cent share in manufacturing. ? (Interruptions) Today, it has a share of 3.5 per cent. ? (Interruptions)

West Bengal's per capita income growth lags behind the national average. For the last 20 years, the per capita income of West Bengal lags behind the national average. ? (Interruptions) It is right. It is 23rd. In 2021-22, it was 23rd among all the States of India.

Sir, Trinamool Congress has institutionalised corruption, gutted institutions, and Trinamool has become a byword for exploitation. Now, can I then suggest one thing क्योंकि बजट बंगाल विरोधी बोला गया है? मैं अभी पूछना चाहती हूँ कि क्या तृणमूल विरोधी टीएमसी हो गई है? टीएमसी तृणमूल विरोधी है, तृणमूल जनता विरोधी है।? (व्यवधान)

Sir, I am coming to the last few things. ? (Interruptions)

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): She cannot make a political speech. ? (Interruptions)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: You accuse me politically. ? (Interruptions)

Sir, the MSME sector is ignored and is not in a good health. It is an allegation which very many Members have mentioned about. Dr. Dharamvira Gandhi, Shri Benny Behanan and Shri Pradyut Bordoloi have mentioned that the MSME sector is being ignored. ? (Interruptions) I want to say that in this Budget itself, we have mentioned ? (Interruptions) I am coming on it. ? (Interruptions)

The MSME is the backbone of the Indian economy. It is among the four most engines for driving the Indian economy. ? (Interruptions) The MSME is providing employment to over 25 crore people during the same period. We have increased their classification so that they can benefit both from being in the MSME and also raising more funds. So, with regard to micro enterprises, currently, it is Rs. 1 crore and the revised is Rs. 2.5 crore. The current turnover of micro enterprises is Rs. 5 crore and we have revised

it to Rs. 10 crore. About small enterprises, the current investment is Rs. 10 crore, and now, we have revised it to Rs. 25 crore, and the current turnover is at Rs. 50 crore and we have revised it to Rs. 100 crore. Similarly, for medium enterprises, we have revised it from Rs. 50 crore to 125 crore, and for turnover, we have revised it from Rs. 250 crore to 500 crore.

The Credit Guarantee Cover will be enhanced from Rs. 5 crore to Rs. 10 crore leading to additional credit of Rs. 1.5 lakh crore in the next five years. The customized credit card is being given Rs. 5 lakh limit for micro enterprises registered on Udyam portal.

Sir, now, I come to this point of KCC which is being provided to farmers. Many hon. Members thought that if I increase the loan ceiling from Rs. 3 lakh to Rs. 5 lakh, would it not become a reason why the farmers will be more indebted and more getting into a debt? I want to highlight the fact. Today, this amount of Rs. 3 lakh being increased to Rs. 5 lakh, is purely done because otherwise they will fall a prey to the middle man who charges huge amounts. And this amount through KCC is more guaranteed by the Government and they do not need to give any collateral, and also for timely servicing, they get interest subvention. And therefore, it is better that they borrow through the banks rather than be left alone to borrow from the middle man. That is the intention with which we have brought in the KCC. Nearly, eight crore farmers will be benefiting from this short-term lending which will begin from 1st April, 2025-26. ?
(Interruptions)

Sir, the Budget document very clearly speaks on the various skills through which we want to increase the liquidity which will be available for people. In three years prior to 2024-25, the country's GDP growth rate averaged at about eight per cent.

Only in two out of last twelve quarters, has the growth rate touched 5.4 per cent or remained below it.

I want to inform the Members that on account of strong economic foundation, a speedy rebound is happening and we shall take measures which will going forward help in keeping our economy growing fastest as in the last few years. We will continue to remain the fastest growing economy.

I wish to state that private final consumption expenditure is expected to grow by 7.3 per cent in 2024-25 driven by good rural demand. So, the private final consumption expenditure is estimated to be

61.8 per cent of the nominal GDP which is the highest since 2002-2003.

So, with these words, I would like to thank all the hon. Members who have participated and in the Budget Discussion.

I thank you for your indulgence.

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 13 फरवरी, 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.31 hrs

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Thursday, February 13, 2025/Magha 24, 1946 (Saka).*

* Expunged as ordered by the Chair.

?.. English translation of this part of speech was originally delivered in Marathi..

?.. English translation of this par of speech was originally delivered in Tamil.

** Not recorded.

* Expunged as ordered by the Chair.

* Expunged as ordered by the Chair.

?.. English translation of this part of speech was originally delivered in Marathii.

* Expunged as ordered by the Chair.

* Treated as laid on the Table.

** Expunged as ordered by the Chair.

* Expunged as ordered by the Chair.

** Not recorded

* Not recorded.

* Expunged as ordered by the Chair.